



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 1973/फाल्गुन 5, 1894
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 1973/PHALGUNA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

NOTICE

With effect from 17th February 1973.

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were Published up to the 18th January, 1973.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
	का० आ० दिनांक 1 जनवरी, 1973 ।	औद्योगिक विकास मंत्रालय	मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (संशोधन) आदेश 1973 ।
1.	S.O.2.(E). dated 1st January, 1973.	Ministry of Industrial Development.	The Motor Cars (Distribution & Sale) Control (Amendment) Order 1973.
	का० आ० 2(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1973 ।	कम्पनी कार्य विभाग	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और ज्यन्ती शिपिंग कम्पनी सम्मेलन आदेश 1973 ।
2.	S.O.2 (E) dated 1st January, 1973.	Department of Company Affairs.	The Shipping Corporation of India and Jyanti Shipping Company Amalgamation Order 1973
	का० आ० 3(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1973 ।	शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय	कापी राईट बोर्ड में और सदस्य नियुक्त करना ।
3.	S.O.3(E) dated 1st January, 1973.	Ministry of Education and Social Affairs.	Appointment of More Members on the copy Right Board.
	का० आ० 4(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1973 ।	वित्त मंत्रालय	भारतीय बीमा कम्पनियों के शेयर अनुसूची के स्तम्भ (4) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अन्तर्गत और निहित करना ।
4.	S.O.4.(E) dated 1st January, 1973.	Ministry of Finance.	Transferring and visiting of shares of the Indian Insurance Companies to persons under column (4) of the Schedule.
	का० आ० 5(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1973 ।	तदैव	निर्देश देता है कि प्रत्येक विद्यमान बीमा कर्ता, कम्पनी, जो भारतीय बीमा कम्पनी नहीं है का उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट भारतीय बीमा कम्पनी को अन्तर्गत तथा निहित कर दिया जाय ।
5.	S.O.5.(E), dated 1st January, 1973.	Do	Direction that the undertaking of every existing insurer, who is not an Indian Insurance Company shall be transferred to and vested in the Indian insurance company specified in column (3) of the Schedule.
	का० आ० 6(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1973 ।	तदैव	वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए उपक्रम अन्तर्गत और निहित किया जाता है ।
6.	S.O.6.(E) dated 1st January, 1973	Do	Manuer in which and the candition subject to which the undertaking transferred and vested.

का० आ० 7(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1973 ।	कृषि मंत्रालय	अधिकतम कीमते, जिन पर बनस्पति तेल उत्पादों की विभिन्न जोनों में विक्रय किया जा सकेगा । नियत करना ।
7. S.O. 7. (U) dated 1st January, 1973	Ministry of Agriculture.	Fixing the maximum prices at which vegetable oil product may be sold in the various zones.
का० आ० 8(अ), दिनांक 2 जनवरी 1973 ।	वित्त मंत्रालय	भारतीय विविध बीमा निगम का भारतीय पुनः बीमा कर्ता के रूप में अनुमोदन करना ।
8. S.O. 8.(E) dated 2-1-73	Ministry of Finance.	Approval of the general Insurance Corporation of India as an Indian reinsurer.
का० आ० 9(अ), दिनांक 4 जनवरी, 1973 ।	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	निर्देश देना कि राष्ट्रीय राज मार्गों में से प्रत्येक से सम्बन्धित कामों के निष्पादन के सम्बन्ध में कार्य, अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा भी नियमों का पालन करना होगा ।
9. S.O. 9. (E) dated 4-1-73	M of Shipping and Transport.	Direction that the function in relation to the execution of works pertaining each of the National Highways shall be exerciseable by the State Govt. concerned specified in col (3) of the Schedule.
का० आ० 10(अ), दिनांक 4 जनवरी, 1973 ।	तदैव	निर्देशक राष्ट्रीय राजमार्गों में से प्रत्येक से सम्बन्धित कामों के निष्पादन के सम्बन्ध में कार्य ञ्छोयड़ विल्ली और गोवा के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा भी अपने अतिरिक्तों में नियम का पालन करना ।
S.O. 10(E) Dated 4th January, 1973	Do	Direction that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways shall be exerciseable by the administrators of the Union territories of Chandigarh, Delhi and Goa within their respective jurisdiction.
10. S.O. 11. (E) dated 5th January, 1973	Election Commission of India	Amendment in the delimitation of Parliamentary and assembly Constituencies order 1966.
का० आ० 12(अ), दिनांक 5 जनवरी, 1973 ।	भारत निर्वाचन आयोग	5-मंजरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिये उपनिर्वाचन ।
11. S.O. 12. (E) dated 5th January, 1973	Do.	Byc-election to the House of the people from 5 Manjeri constituency.
का० आ० 13(अ), दिनांक 8 जनवरी, 1973 ।	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली में किसी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित किसी हड़ताल या ताला बन्दी को प्रतिबिद्ध करना ।
12. S.O. 13. (E) dated 8th January, 1973	Ministry of Labour and Rehabilitation.	Prohibiting any strike or lock-out in connection with any industrial dispute in the Neyveli Lignite Corporation limited Neyveli
का० आ० 14(अ), दिनांक 10 जनवरी, 1973 ।	विदेश व्यापार मंत्रालय	सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकारी (संशोधन) नियम, 1972 ।
13. S.O. 14.(E) Dated 10th January, 1973	Ministry of Foreign Trade	The marine products export development authority (Amendment) rules, 1972
का० आ० 15(अ), दिनांक 10 जनवरी, 1973 ।	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	द्वितीय अनुसूची में दी गई फिल्म को स्वीकृत करना ।
14. S.O. 15. (E), dated 10th January, 1973	Ministry of Information and Broadcasting	Approval of the film as specified in the second schedule therein.
का० आ० 16(अ), दिनांक 10 जनवरी, 1973 ।	तदैव	अनुसूची में दी गई फिल्म को स्वीकृत करना ।
S.O. 16. (E) dated 10th January, 1973	Do.	Approval of the film as specified in the schedule therein.
का० आ० 17(अ), दिनांक 10 जनवरी, 1973 ।	तदैव	अनुसूची में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
S.O. 17. (E) dated 10th January, 1973	Do.	Approval of the film as specified in the schedule therein.
का० आ० 18(अ), दिनांक 11 जनवरी, 1973 ।	तदैव	अनुसूची में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
S.O. 18. (E) dated 11th January, 1973	Do.	Approval of the film as specified in the schedule therein.

का० आ० 19(अ), दिनांक 15 जनवरी, 1973 ।	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय	कुछ व्यक्तियों को विश्व विद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त करना ।
16. S.O. 19. (E), dated 15th January, 1973	Ministry of Education and Social Welfare	Appointing certain persons to be the members of the University grants Commission.
17. S.O. 20. (E), dated 15th January, 1973	Ministry of Home Affairs.	Election of the members of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee.
का० आ० 21(अ), दिनांक 15 जनवरी, 1973 ।	विदेश व्यापार मंत्रालय	म्यूर मिल्स लिमिटेड, कानपुर का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम को प्राधिकृत करना ।
18. S.O. 21. (E), dated 15th January, 1973	Ministry of Foreign Trade.	Authorising the Uttar Pradesh state textile corporation to take over the management of the Miuer Mills Limited, Kanpur in place of the National textile corporation Limited.
का० आ० 22(अ), 18 ए० ए०/आई० डी० आर० ए०/73 दिनांक 15 जनवरी, 1973 ।	औद्योगिक विकास मंत्रालय	श्री जानकी शगर मिल्स एन्ड कंपनी, दोईवाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) का प्रबन्धग्रहण करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य शगर कार्पोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत करना ।
19. S.O. 22. (E)/18AA/ 1DRA/73 dated 15th January, 1973	Ministry of Industrial Development	Authorising the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited to take over the management of Shri Janki Sugar Mills and company Doiwalla District Dehra Dun (Uttar Pradesh)
का० आ० 23(अ), दिनांक 17 जनवरी, 1973 ।	गृह मंत्रालय	अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) संशोधन नियम, 1973
20. S.O. 23.(E) dated 17th January, 1973	Ministry of Home Affairs	The Authentication (orders and other Instruments) Amendment Rules, 1973.
का० आ० 24(अ), दिनांक 17 जनवरी, 1973 ।	औद्योगिक विकास मंत्रालय	पेपर एन्ड जिजर मर्चेंट एसोसिएशन लिमिटेड मुम्बई को बृहत्तर मुम्बई की सीमाओं के भीतर काली मिर्च की अग्रिम संविदाओं की बाबत; 18 जनवरी 1974 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिय मान्यता प्रदान करना ।
21. S.O. 24.(E), dated 17th January, 1973	Ministry of Industrial Development	Granting recognition to the Pepper and Ginger Merchants Association Ltd., Bombay for a further period of one year ending the 18th January 1974 in respect of forward contracts in pepper within the limits of greater Bombay.
का० आ० 25(अ), दिनांक 18 जनवरी, 1973 ।	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना ।
22. S.O. 25(E), dated 18th January, 1973	Ministry of Information and Broadcasting.	Approval of the films as specified in the Schedule therein.
का० आ० 26(अ), दिनांक 18 जनवरी, 1973 ।	तदैव	द्वितीय अनुसूची में दी गई फिल्म को स्वीकृत करना ।
S.O. 26(E), dated 18th January, 1973.	Do.	Approval of the film as specified in the second schedule therein.
का० आ० 27(अ), दिनांक 18 जनवरी, 1973 ।	तदैव	अनुसूची में दी गई फिल्म को स्वीकृत करना
S.O. 27.(E), dated 18th January, 1973.	Do.	Approval of the film as specified in the Schedule therein.
का० आ० 28(अ), दिनांक 18 जनवरी, 1973 ।	तदैव	अनुसूची में दी गई फिल्म को स्वीकृत करना ।
S.O. 28.(E), dated 18th January, 1973.	Do.	Approval of the film as specified in the Schedule therein.
का० आ० 29(अ), दिनांक 18 जनवरी, 1973 ।	तदैव	द्वितीय अनुसूची में दी गई फिल्म को स्वीकृत करना ।
S.O. 29.(E) dated 18th January, 1973	Do.	Approval of the films as specified in the second Schedule.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
 कन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

**Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
 (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
 (other than the Administration of Union Territories)**

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1973

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1973

आवृत्ति

आवृत्ति

का. आ. 497.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 को हुए आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 276-टुंगतुर्थी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी. प्रसंगी, मिशन कम्पाउंड, सुर्यपेट, जिला नालगोंडा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वांछित करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पी. प्रसंगी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आवृत्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरिहित घोषित करता है ।

[सं. आ. प्र.-वि. स./276/72]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 5th January, 1973

ORDER

S.O. 497.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P. Prasangi, Mission Compound, Suryapet, District Nalgonda, a contesting candidate for the general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in March, 1972 from 276-Tungaturthi constituency, has failed to lodge and account of his election expenses at all as required by the Representation of the People, Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P. Prasangi to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/276/72]

का. आ. 498.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 को हुए आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 245-मेवाराम (अजा) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री देवी राजलिंगू धर्मराम, निवासी बोमारेड्डीपल्ली (गांव), पेड्डापल्ली तालुक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वांछित करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री देवी राजलिंगू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आवृत्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरिहित घोषित करता है ।

[सं. आ. प्र.-वि. स./245/72]

ORDER

New Delhi, the 10th February, 1973

S.O. 498.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Devi Rajalingu, Dharmaram, H/o Bommarreddipalli (V), Peddapalli taluk, a contesting candidate for the general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in March 1972 from 245. Mydaram (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Devi Rajalingu to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/245/72]

आवृत्ति

New Delhi, the 1st February, 1973

का. आ. 499.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 को हुए आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 249-नस्थुलापुर (अज) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उपुलाटे दुर्गाचंदाह, डाकघर वचनूर, तालुक तथा जिला करीम नगर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री उपुलाटे दुर्गाचंदाह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. आ. प्र.-वि. सा./249/72]

ORDER

S.O. 499.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Uppulate Durgaiyah, Post Vachnur Village Taluk and District Karimnagar, a contesting candidate for the general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in March, 1972 from 249. Nusthulapur (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Uppulate Durgaiyah to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/249/72]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1973

का. आ. 500.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के परामर्श से, श्री आर. के. अहूजा के स्थान पर, श्री के. सेथुरामन, अपर जिला मैजिस्ट्रेट अन्डमान और निकोबार द्वीप को 28 नवम्बर, 1972 से 18 दिसम्बर, 1972 तक अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्वारा नाम निर्देश करता है।

[सं. 154/अ. नि. द्वी./73]

S.O. 500.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission, in consultation with the Andaman and Nicobar Islands Administration, hereby nominates Shri K. Sethuraman, Additional District Magistrate, Andaman and Nicobar Islands, as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands from 28th November, 1972 to 18th December, 1972 vice Shri R. K. Ahuja,

[No. 154/ANI/73]

का. आ. 501.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के परामर्श से, श्री के. सेथुरामन के स्थान पर, श्री रमेश चन्द्र, उपायुक्त, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह को 18 दिसम्बर, 1972 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्वारा नाम निर्देशित करता है।

[सं. 154/अ. नि. द्वी./73(1)]

श्री. एन. भारद्वाज, सचिव

S.O. 501.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission, in consultation with the Andaman and Nicobar Islands Administration, hereby nominates Shri Ramesh Chandra, Deputy Commissioner, Andaman and Nicobar Islands, as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands from the 18th December, 1972 (afternoon) and until further orders vice Shri K. Sethuraman.

[No. 154/ANI/73(1)]

B. N. BHARDWAJ, Secy.

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1973

आवृत्ति

का. आ. 502.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 को हुए पं. बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 152 हबड़ा नार्थ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जवाहरलाल खन्ना, 9/1/बी., महात्मा गान्धी रोड, कलकत्ता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित

अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री जवाहर लाल खन्ना को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प. बं. वि. सा./152/71(18)]

ए. एन. सैन, सचिव

New Delhi, the 1st February, 1973

ORDER

S.O. 502.—WHEREAS the Election Commission is satisfied that Shri Jawahar Lal Khanna, 9/1/B, Mahatma Gandhi Road, Calcutta a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 152-Howrah North constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder:

AND WHEREAS, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jawahar Lal Khanna to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By Order.

[No. WB-LA/152/71(18)]

A. N. SEN, Secy.

वित्त मंत्रालय

राजस्व और बीमा विभाग

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1973

आयकर

का. आ. 503.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संख्या को, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

मानेकलाल साइन्टिफिक रिसर्च फाउन्डेशन, मुम्बई।

[सं. 260 (फा. सं. 203/42/71-आई टी ए 2)]

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue & Insurance

New Delhi, the 10th January, 1973

INCOME TAX

S.O. 503.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Council of Scientific and Industrial Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

MANEKLAL SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION, BOMBAY.

[No. 260 (F. No. 203/42/71-ITA. II)]

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1973

का. आ. 504.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित करने वाली अधिसूचना, सं. 166 (फा. सं. 11/11/69-आई. टी. ए. 11), तारीख 1 जून, 1971, 1 अप्रैल, 1969 से प्रभावी होगी।

[सं. 265 (फा. सं. 203/11/72-आई टी. ए-2)]

New Delhi, the 11th January, 1973

S.O. 504.—It is hereby notified for general information that notification No. 166 [F. No. 11/11/69-ITA. II] dated 1st June, 1971 approving the Vasaspati Manufacturers Association of India, Bombay for the purposes of clause (a) of sub-section (1) of Section 35C of the Income-tax Act, 1961 shall have effect from 1st April, 1969.

[No. 265 (F. No. 203/11/72-ITA. II)]

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1973

का. आ. 505.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था को, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

कम्पनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बम्बई

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1972 से प्रभावी होगी।

[सं. 267 (फा. सं. 203/14/72-आई. टी. ए-2)]

टी. पी. भुनभुनवाला, उप सचिव

New Delhi, the 15th January, 1973

S.O. 505.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Council of Scientific and Industrial Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act 1961.

INSTITUTION

KAMANI RESEARCH INSTITUTE, BOMBAY

This Notification will take effect from 1st April, 1972.

[No. 267 (F. No. 203/14/72-ITA. II)]

T. P. JHUNJHUNWALA. Dy. Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1973

का. आ. 506.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का. सं. 53) की धारा 53 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध, जहाँ तक उनका संबंध कलकत्ता स्टीप नेविगेशन कम्पनी लि. में नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड के शेयरों से हैं, उक्त बैंक पर 5 नवम्बर, 1973 तक लागू नहीं होंगे।

[सं. 15(10)-बी. सी./72]

कै. येसुरत्नम, अवर सचिव

(Department of Banking)

New Delhi, 9th February, 1973

S.O. 506.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the National and Grindlays Bank Ltd. till the 5th November, 1973 in so far as they relate to its holdings in the shares of Calcutta Steam Navigation Co. Ltd.

[No. 15(10)-BC/72]

K. YESURATNAM, Under Secy.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

नई दिल्ली, 8 फरवरी 1973

का. प्रा. 507.—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में फरवरी 1973 की 2 तारीख का समाप्त हुए गणना के लिए लेखा
दृष्टि विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	20,40,14,000		माने का सिक्का और बुलियन :—		
संचलन में नोट	4939,60,59,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां	171,65,38,000	
जारी किये गये कुल नोट		4960,00,73,000	जोड़		354,18,49,000
			रुपये का सिक्का		16,48,09,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		4589,34,15,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे		
			वाणिज्य-पत्र		..
कुल देयताएं		4960,00,73,000	कुल आस्तियां		4960,00,73,000
तारीख : 7 फरवरी, 1973					एस० जगन्नाथन, गवर्नर

2 फरवरी, 1973 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
शुद्धता पूंजी	5,00,00,000	नोट	20,40,14,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	4,63,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	209,00,00,000	छोटा सिक्का	3,16,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	45,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल :	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	175,00,00,000	(क) देशी	1,09,55,000
जमा राशियां :—		(ख) विदेशी	—
(क) सरकारी :		(ग) सरकारी खजाना बिल	219,24,15,000
(i) केन्द्रीय सरकार	53,22,67,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	168,85,78,000
(ii) राज्य सरकारें	9,99,91,000	निवेश**	420,81,20,000
(ख) बैंक :		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	305,14,14,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	—
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	12,76,00,000	(ii) राज्य सरकारों को @	114,02,52,000
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,04,20,000	ऋण और अग्रिम :	
(iv) अन्य बैंक	55,95,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	6,37,50,000
(ग) अन्य	70,79,72,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	299,03,22,000
देय बिल	78,81,40,000	(iii) दूसरों को	2,95,27,000
अन्य देयताएं	407,29,58,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :	
		(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को	54,69,81,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	24,38,12,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	—
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	10,00,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	11,23,62,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	29,26,85,000
		अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	93,26,94,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	—
		अन्य आस्तियां	47,91,10,000
	रुपये 1523,63,57,000		रुपये 1523,63,57,000

*नकदी, आबधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग)के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सीमादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 10,00,000 रुपये शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 7 फरवरी, 1973

एस० जगन्नाथन, गवर्नर
[सं० का० 1(1)73/बी० ओ०—I]
व० व० भीरबन्धानी, अवर सचिव, I

RESERVE BANK OF INDIA

Now Delhi, the 1st February, 1973

S.O. 507.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 2nd day of February 1973

ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	20,40,14,000		Gold Coin and Bullion :		
Notes in circulation	4939,60,59,000		(a) Held in India	182,53,11,000	
Total Notes issued		4960,00,73,000	(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	171,65,38,000	
			Total		354,18,49,000
			Rupee Coin		16,48,09,000
			Government of India		
			Rupee Securities		4589,34,15,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		4960,00,73,000	Total assets		4960,00,73,000

S. JAGANNATHAN, Governor,

Dated the 7th day of February 1973

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 2nd February 1973

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	20,40,14,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	4,63,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	209,00,00,000	Small Coin	3,16,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	45,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	175,00,00,000	(a) Internal	1,09,55,000
		(b) External	
		(c) Government Treasury Bills	219,24,15,000
		Balances Held Abroad*	168,85,78,000
		Investments**	420,81,20,000
		Loans and Advances to :	
		(i) Central Government	
		(ii) State Governments@	114,02,52,000
		Loans and Advances to :	
		(i) Scheduled Commercial Banks†	6,37,50,000
		(ii) State Co-operative Banks††	299,03,22,000
		(iii) Others	2,95,27,000
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to :	
		(i) State Governments	54,69,81,000
		(ii) State Co-operative Banks	24,38,12,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	10,00,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank	11,23,62,000
		Debentures Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	29,26,86,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	93,26,94,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		Other Assets	47,91,10,000
Rupees	1523,63,57,000	Rupees	1523,63,57,000

*Includes Cash, Fixed Deposit and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 49,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

S. JAGANNATHAN, Governor.

[No. F. 1(1)/73-B.O.]

Dated the 7th day of February 1973.

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 1972

30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के काम काज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट

का. आ. 508.—भारतीय रिजर्व बैंक ऐक्ट, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार केन्द्रीय निदेशालय बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के कामकाज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है।

1. अर्थव्यवस्था की समग्र प्रवृत्तियाँ

जुलाई 1970 से जून 1971 तक के बैंक के लेखे वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधि प्रायः असमान थी। फिर भी समग्र विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था काफी संतोषजनक परि-लक्षित हुई। विशेष रूप से जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता गया, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होने लगीं। यह अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष स्थिर मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय में 1969-70 की अपेक्षा 5 से 5.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यह क्रमशः दूसरा वर्ष था जब राष्ट्रीय आय चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए परिकल्पित समग्र वृद्धि के लक्ष्य तक पहुँची। काफी हद तक यह वृद्धि कृषि क्षेत्र में हुई 6 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के कारण हुई। इस क्षेत्र का प्रमुख वर्ग अनाजों पायी गयी। यह वृद्धि 8.0 प्रतिशत से अधिक थी। इसके विप-का उत्पादन था जिसमें लगातार दूसरे वर्ष भी वृद्धि की प्रवृत्ति रीत औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि-दर में कमी पायी गयी। मूल्यों की स्थिति वर्षभर तनावपूर्ण रही। विविधी लेंद्वन में क्षेत्रों में एक ओर जहाँ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपनी रूपा-मुद्राओं को पुनः खरीदने का कार्यक्रम समाप्त कर प्रारक्षित निधियों के अपने दूसरे क्षेत्र को मजबूत बनाया वहाँ दूसरी ओर चालू खाते के भुगतान शेष में घाटा बढ़ गया। इस वर्ष के दौरान निर्यातों में वृद्धि हुई, किन्तु आयातों के संवर्ध में अव-मूल्यन के बाद से पायी गयी कमी की प्रवृत्ति के विपरीत स्थिति परिलक्षित हुई। मार्च 1971 के सैनिक विस्फोट के बाद पूर्व बंगाल में जो दुःख घटनाएँ हुईं उन से हमारे देश में रक्षा के लिए आनेवाले लाखों शरणार्थियों की गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई। इन अभागों लोगों के लिए अन्न और आवास की जो व्यवस्था करनी पड़ती है उस से देश की वित्तीय साधनों को भारी तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ा है और इस प्रकार लगातार आनेवाले असंख्य शरणार्थियों के कारण आर्थिक विकास की गतिविधि पर गंभीर दबाव पड़ना अवश्यभावी है।

2. अर्थव्यवस्था के निवेश-क्षेत्र में पर्याप्त स्तर तक सुधार होने का कोई लक्षण अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की निवेश-मात्रा यद्यपि पिछले वर्ष से अधिक थी फिर भी उक्त मात्रा बजट में परिकल्पित मात्रा की अपेक्षा बहुत कम थी। निजी कंपनी क्षेत्र के संवर्ध में नये शेरों के प्रति जनता की सख संतोषजनक थी। इस वर्ष मीठावी ऋण देनेवाली संस्थाओं ने जो वित्तीय सहायता मंजूर की और पहले ही मंजूर की गयी सहायता में से जो वितरण किया वह पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक था। इस वर्ष के प्रारंभिक महीनों में स्टाक बाजार में सुधार की प्रवृत्ति पायी गयी, किन्तु बाद में उस में ह्रास की प्रवृत्ति पायी जाने लगी। समग्र रूप से संगठित उद्योग-क्षेत्र में इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कम मात्रा में पूंजीगत भंडारियों विये जाने और पूंजीगत शेर जारी किये जाने के कारण मंदी विद्यमान थी। लघु,

उद्योग क्षेत्र के निवेश-कार्य के संवर्ध में यह प्रतीत होता है कि उस में सुधार हुआ है। कृषि में निवेश किये जाने के लिए संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले वित्त की मात्रा में पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में वृद्धि दिखाई पड़ी।

3. 1970-71 के बजट संबंधी कार्यकलापों से यह लक्षित हुआ है कि प्राप्तिओं और वितरणों के बीच, विशेषकर राज्य सरकारों के संवर्ध में अपेक्षा से अधिक व्यापक खाई विद्यमान थी, इस कारण बैंकों द्वारा घाटे की जो वित्त पूर्ति की जाती है उस में पर्याप्त वृद्धि हुई। केन्द्रीय सरकार की 1971-72 की बजट नीति आर्थिक स्थिति के सामान्य सुधार की संभावनाओं और विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता की पृष्ठभूमि में बनायी गयी है। बजट में योजना परियोजनाओं में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की व्यवस्था की गयी है ताकि विकास-कार्यों को आवश्यक शक्ति मिल सके। उस में कुछ ऐसे अन्य उपाय भी किये गये हैं जिनसे प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने और एक समतल्युक्त समाज का निर्माण करने के सामाजिक लक्ष्यों के निकट पहुँचा जा सके। उस में ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन प्रधान निर्माण कार्यों और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 75 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गयी है। बजट में शरणार्थियों से संबंधित व्यय के लिए भी 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। किन्तु आनेवाले शरणार्थियों की संख्या प्रत्याशा से बहुत अधिक रही है, अतः बजट संबंधी वित्तीय साधनों पर पड़नेवाला दबाव उसके अनु-रूप बढ़ेगा ही।

4. मूल्यों पर बराबर दबाव पड़ने और वर्ष के पूर्वार्ध में बैंकिंग संघटन द्वारा किये जानेवाले ऋण में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण निरंतर मुद्रा नीति को अर्थव्यवस्था में पायी जानेवाली मुद्रा-स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य के अनुकूल बनाया जाता रहा। इस संवर्ध में जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये वे इस प्रकार हैं : बैंकों की ब्याज दर में एक प्रतिशत की वृद्धि कर उसे 6 प्रतिशत किया गया, बैंकों के सार्वजनिक और वास्तविक चल मुद्रा अनुपातों को बढ़ाया गया, अग्रतावाले क्षेत्रों को और अनाजों की उगाही के लिए दिये गये अग्रिमों के संबंध में प्रदान किये जानेवाले पुनर्वित्त की मात्रा के आधार में पर्याप्त परिवर्तन किये गये और बैंकों को सलाह दी गयी कि वे विशिष्ट रूप से निर्धारित पण्यों पर सर्वाधिक नियंत्रण लगाएँ तथा जुने हुए पण्यों पर लगाये गये ऋण नियंत्रणों को कठोर बना दें। इसके साथ ही, बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे जमा-राशि जुटाने से संबंधित अपने कार्य की गति में सीवता लायें। बैंकों को उनके अपने साधन-स्रोतों को बढ़ाने में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से जमा-राशियों की विभिन्न ब्याज-दरों को बढ़ाने की अनुमति दी गयी। उसके बाद ऋण-विस्तार की मात्रा में काफी कमी हुई और मूल्यों पर पड़ा दबाव कम हुआ।

5. सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपने शाखा विस्तार कार्यक्रम को सीवता के साथ जारी रखा और अपनी ऋण-नीतियों को अग्रता वाले क्षेत्रों के अनुकूल बनाया तथा पिछड़े क्षेत्रों और समुदाय के कमजोर वर्गों को सहायता पहुँचाने के लिए विशेष योजनाएँ बनायीं। इसके साथ साथ बैंकों को यह भी समझाया गया है कि अग्रता वाले क्षेत्रों को ऋण देते समय गुणवत्ता के एक न्यूनतम मानक का पालन किया जाना चाहिए और साथ ही इस बात का हतमीनान कर लेना चाहिए कि निधियों का सही उपयोग हो और उनकी बराबर वापसी अदायगी होती रहे।

*पूर्व बंगाल से आनेवाले शरणार्थियों पर दिसंबर 1971 के अंत तक होनेवाले खर्च के लिए 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्य-वस्था की गयी है।

उत्पादन, मूल्य और नीति संबंधी उपाय

कृषि उत्पादन

6. 1970-71 दूसरा वर्ष था जब कृषि उत्पादन में लगातार पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होती रही। यद्यपि अनुकूल मौसमी परिस्थितियों ने विशेष रूप से खरीफ मौसम के दौरान इस वृद्धि में अवश्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है फिर भी सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार और जल-प्रबन्ध संबंधी अच्छी तकनीकों का उपयोग किये जाने, अधिक उपजवाली किस्मों के कार्यक्रम के अधीन अधिक भूमि के लाये जाने और व्यापक पैमाने पर आधुनिक ट्रैक्टरों/लाजी के अपनाने जाने के कारण भी यह वृद्धि हुई। इस वृद्धि के अधिकांश भाग का कारण अनाजों का उत्पादन था जिसकी मात्रा 1078 लाख मी. टन थी। यह उत्पादनमात्रा पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 83 लाख मी. टन अधिक थी। वृद्धि का

शेष भाग ज्वार का छोड़कर अन्य सभी महत्वपूर्ण अनाजों में पाया गया। दालों के उत्पादन में सामान्य कमी पायी गयी। किन्तु प्रमुख नकदी फसलों का उत्पादन असमान था। 1970-71 के दौरान रुई और पटसन के उत्पादन के संबंध में यह आशा की जाती है कि यह 1969-70 के उत्पादन की अपेक्षा कम थी। एक ओर जहाँ रुई के उत्पादन पर कीतिपथ रुई-उत्पादक भूभागों में असामयिक रूप से भारी वर्षा और कीड़ों का आक्रमण हो जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा वहाँ दूसरी ओर पटसन के उत्पादन में जो कमी हुई वह अंशतः बुवाई की अवधि में पायी गयी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण और अंशतः उत्पादन-क्षेत्र के विस्तार में कमी हो जाने के कारण हुई। प्रमुख तिलहनों में से भूगफली के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई अर्थात् उसकी उत्पादन-मात्रा 51 लाख मी. टन से बढ़कर 61 लाख मी. टन हो गयी। गन्ने (गुड़ के रूप में) का उत्पादन संभवतः लगभग 134 लाख मी. टन के पिछले वर्ष के स्तर पर ही रहा।

सारणी 1—कृषि उत्पादन की प्रवृत्तियाँ

	माला	1969-70 (अंतिम अनुमान)	1970-71 (अनुमानित)
1. धान	दस लाख मी० टन	99.5	107.8*
(i) बाबल	—वही—	40.4	42.5†
(ii) गेहूँ	—वही—	20.1	23.3†
2. रुई*	दस लाख गांठें@	6.1	5.4
3. पटसन और मेस्ता@@	—वही—	6.8	6.1
4. भूगफली@@	दस लाख मी० टन	5.1	6.1
5. गन्ना (गुड़ के रूप में)	—वही—	13.4	13.4

*व्यापार अनुमान।

†अंतिम अनुमान।

@ 180 कि०घा० की गांठ।

@ @ 1970-71 के लिए अंतिम अनुमान और 1969-70 के लिए अंशतः परिशोधित अनुमान।

औद्योगिक उत्पादन

7. आलोच्य अवधि में औद्योगिक विकास की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय रूप से मंदी पायी गयी। औद्योगिक उत्पादन से संबंधित केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के सूचकांक (आधार : 1960-100) में जहाँ 1968 और 1969 में क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई वहीं 1970 में उसमें केवल 4.5 प्रतिशत* की वृद्धि पायी गयी। यह कमी इस वर्ष के उत्तरार्ध में अधिक स्पष्ट रूप से पायी गयी जब 1969 की तदनुसूची अवधि की अपेक्षा केवल 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी-मार्च 1971 में 1970 के तदनुसूची महीनों की अपेक्षा सूचकांक में जो वृद्धि हुई वह केवल 1.5 प्रतिशत थी। औद्योगिक विकास की गतिविधि में जो मंदी पायी गयी उसके लिए रुई, तिलहन और मूल धातु जैसी महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री की कमी, बिजली और परिवहन संबंधी कठिनाइयाँ, तनावपूर्ण औद्योगिक संबंध तथा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश की वृद्धि-दर का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें हुई कमी आदि के अनेक प्रतिकूल कारण थे।

*वृद्धि में हुई यह कमी अंशतः सांख्यिकीय कारणों से हुई। कीतिपथ यूनिटों के तकनीकी विकास के महानिदेशक की बहियों से हटाकर पिछले वर्षों के लिए तदनुसूची समायोजन किये बिना ही लघु उद्योग क्षेत्रों में अंतर्गत कर दिया गया है।

8. प्रायः सभी महत्वपूर्ण औद्योगिक वर्गों में चाहे वे उद्योगों के अनुसार वर्गीकृत हों अथवा मूल वस्तुओं के अनुसार भिन्न भिन्न मात्राओं में यह कमी पायी गयी। इस प्रकार मूल उद्योगों में 1970 के दौरान केवल 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि 1969 में उनमें 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मध्यवर्ती माल उद्योगों में हुई वृद्धि का प्रतिशत जहाँ 1969 में 4.2 था वहाँ इस वर्ष केवल 2.7 था। उपभोक्ता माल उद्योगों में इस वर्ष 6.3 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी जबकि 1969 में उन में हुई वृद्धि का प्रतिशत 10.2 था। विशेष रूप से यह कमी उपवर्ग 'टिकाऊ उपभोक्ता माल उद्योगों' में बहुत अधिक थी। केवल पूंजीगत माल उद्योगों के वर्ग में अधिक वृद्धि दिखाई पड़ी। उन में हुई वृद्धि का प्रतिशत जहाँ 1969 में 1.8 था वहाँ यह 1970 में बढ़कर 4.7 हो गया।

9. मूल वस्तुओं के आधार पर देखा जाए तो जहाँ कृषि आधारित उद्योगों और धातु आधारित उद्योगों की वृद्धि दर 1969 में क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत थी, वहाँ 1970 में उस में मामूली कमी हुई अर्थात् वह क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत हो गयी। किन्तु रासायनिक पदार्थों पर आधारित उद्योगों की वृद्धि-दर में तेजी से कमी हुई अर्थात् उक्त वृद्धि-दर जहाँ 1969 में 10.3 प्रतिशत थी वहाँ इस वर्ष घट कर 7.5 प्रतिशत हो गयी।

10. क्षेत्रगत निवेशकों से यह प्रतीत होता है कि 'परिवहन उपकरण और संबद्ध उद्योगों' का उत्पादन 1970 में 1969 के समान बिल्कुल ही गतिहीन रहा। 'विजली और संबद्ध उद्योगों' में उच्च स्तर की वृद्धि (लगभग 11 प्रतिशत) बनी रही यद्यपि वह वृद्धि पिछले वर्ष की वृद्धि (14.2 प्रतिशत) से कम ही थी। कृषिपथ महत्वपूर्ण उद्योगों से संबंधित आंकड़े उन उद्योगों के उत्पादन में हुई भारी कमी को दर्शाते हुए सारणी 3 में दिये गये हैं और सारणी 4 में ऐसे उद्योगों के आंकड़े दिये गये हैं जिनके उत्पादन में ऊंची दरों पर वृद्धि होती रही।

क्षमता का उपयोग

11. इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि-दर में कमी होने के साथ ही विशेष रूप से लोहे और इस्पात, भारी यांत्रिक इंजीनियरी और औद्योगिक मशीनों तथा रेल सड़क उपकरणों आदि के उद्योगों में विद्यमान क्षमता का न्यून मात्रा में उपयोग होने की समस्या बढ़ गयी। तैयार इस्पात के संदर्भ में उस क्षेत्र की क्षमता के उपयोग का अनुपात 1970 के उत्तरार्ध में 68 प्रतिशत था जब कि 1939 की तदनुसूची अवधि में उक्त अनुपात 70 प्रतिशत था। सीमेंट की मिलों के लिए मशीनों का निर्माण करनेवाले तथा चाय, छपाई, चमड़े

और रबड़ के उत्पादों के उद्योगों के क्षेत्र में विद्यमान क्षमता का उपयोग किये जाने में 1969 की तुलना में 1970 में कमी हुई। रेल बंगनों के संदर्भ में रेलों से प्राप्त होनेवाले आदर्शों में निरंतर कमी होती रहने से उस क्षेत्र में स्थापित क्षमता के 39 प्रतिशत का महसूस से उपयोग किया गया। 1970 के दौरान जिन अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों की क्षमता के उपयोग के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति पायी गयी उन में अन्यान्य उद्योगों के साथ सीमेंट, इस्पात की ढलाई, इस्पात के नलों और ट्यूबों, संचायक बैटरियों और सूखे सेलों के उद्योग शामिल हैं। प्रायः इन सभी उद्योगों की क्षमता के उपयोग का अनुपात न केवल 1970 के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध में कम था, बल्कि 1970 के कैलेंडर वर्ष में भी 1969 की अपेक्षा कम ही था।

12. फिर भी कुल उद्योगों में उनकी अपनी निर्धारित क्षमता के उपयोग में थोड़ा सा सुधार हुआ। उन में पावर ट्रांसफार्मरों, विजली के मोटरों, विजली के कैबलों और तारों के उद्योग महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों पर अधिक परीक्ष्य किया गया। मोटर यानों, मशीन औजारों और कास्टिक सोडा जैसे कुछ मूल रसायनिक पदार्थों के उद्योगों की उत्पादन क्षमता के उपयोग में उन वस्तुओं की भारी मांग की स्थिति के बने रहने के कारण सुधार हुआ।

सारणी 2—औद्योगिक उत्पादन के प्रवृत्तियाँ
पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में उतार चढ़ाव (%)

वर्णन	1969	1970	जनवरी—जून		जुलाई—दिसंबर	
			1969	1970	1969	1970
सामान्य सूचकांक (प्रशोधित)	100.00	+7.1	+4.5	+8.0	+6.2	+3.0
उपयोग के आधार पर वर्गीकरण						
मूल उद्योग	25.11	+8.9	+4.2	+9.6	+5.9	+2.6
पूँजीगत माल उद्योग	11.76	+1.8	+4.7	+4.1	+7.4	+2.5
मध्यवर्ती माल उद्योग	25.88	+4.2	+2.7	+3.0	+5.1	+0.6
उपभोक्ता माल उद्योग	37.35	+10.2	+6.3	+12.6	+6.8	+5.5
(क) टिकाऊ उपभोक्ता माल उद्योग	5.88	+12.9	+3.2	+17.0	+2.7	+3.1
(ख) गैर टिकाऊ उपभोक्ता माल उद्योग	31.57	+9.3	+7.3	+11.2	+8.2	+6.3
मूल वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण						
कृषि आधारित उद्योग	44.08	+5.5	+4.5	+5.8	+6.0	+2.9
धातु आधारित उद्योग	16.55	+5.8	+5.2	+8.5	+6.9	+3.7
रासायनिक पदार्थों पर आधारित उद्योग	8.94	+10.3	+7.5	+13.2	+10.7	+4.6
क्षेत्रगत निवेशक						
(1) परिवहन उपकरण और संबद्ध उद्योग	10.90	+0.4	+0.1	+5.4	+1.8	+1.4
(2) विजली और संबद्ध उद्योग	8.42	+14.2	+11.1	+15.4	+12.1	+10.4

नोट :—यह सारणी औद्योगिक उत्पादन संबंधी केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के सूचकांक (आधार : 1960—100) पर आधारित है। वर्गों के सूचकांक निकासे गये हैं।

सारणी 3—1970 के दौरान उत्पादन में
भारी कमी बराने वाले उद्योग

(प्रतिशत में)

उद्योग	वृद्धि-दरें	
	1969 के दौरान	170 के दौरान
लोहा और इस्पात (मूल उद्योग)	+ 8.5	— 6.9
पीतल निर्माण	+ 28.5	— 4.6
प्रथम चालक, बायलर तथा भाप उत्पादक संयंत्र	+ 0.5	— 2.7
रेल-सड़क उपकरण	—10.6	—19.8
रंग सामग्री और रंग	+ 9.6	— 1.4

सारणी 4—1970 के दौरान उत्पादन में ऊंची दरों पर वृद्धि
बराने वाले उद्योग

(प्रतिशत में)

उद्योग	वृद्धि-दरें	
	1969 के दौरान	1970 के दौरान
मूल उद्योग		
भारी प्रकाशनिक रासायनिक पदार्थ	+ 14.0	+ 6.5
उर्वरक	+ 22.1	+ 21.3
एल्युमीनियम	+ 5.9	+ 19.6
बिजली	+ 12.9	+ 10.3
पूँजीगत माल उद्योग		
उत्पादन, भाषि के लिए मशीनी साधन और उपकरण (पावर ट्रांसफार्मर)	+ 4.6	+ 40.6
बिजली के मोटर और मट्रियां	+ 8.7	+ 34.5
बिजली के केबल और इन्सुलेट किये हुए तार	+ 5.4	+ 9.0
मध्यवर्ती माल उद्योग		
जूट से बनी वस्तुएं	—19.3	+ 9.4
उपभोक्ता माल उद्योग		
चीनी (परिष्कृत)	+ 76.4	+ 10.9
चाय	+ 3.1	+ 18.8
वस्त्र	+ 1.6	+ 8.2
वाणिज्यिक, कार्यालयीन और घरेलू मशीनें	—14.1	+ 14.3
मोटर साइकिलें और साइकिलें	+ 10.4	+ 9.8

करणमूलक तथ्य

13. औद्योगिक विकास में हुई कमी के कारण अनेक हैं और वे प्रत्येक उद्योग के संदर्भ में भिन्न-भिन्न हैं। लोहे और इस्पात के उत्पादन पर तनावपूर्ण औद्योगिक संबंधों और अन्य संगठनात्मक समस्याओं, तापसह साधनों और तार जैसी कच्ची सामग्री की कमी तथा यांत्रिक खराबियों और मशीनों की मरम्मतों के कारण कारखानों के बन्द हो जाने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लोहे और इस्पात के उत्पादन में समग्र रूप से जो कमी हुई उसके कारण इस्पात पर आधारित अनेक इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन में बाधा पड़ी। कोयले के उत्पादन पर मांग की कमी, विशेष रूप से रेलवे की कम मांगों और परिवहन संबंधी अड़चनों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस वर्ष समग्र औद्योगिक कार्यक्षमता में सामान्य रूप से जो मंदी पायी

गयी उसके कारण वेगन-सदानों में कमी होने और पूर्वी क्षेत्र की कानून और व्यवस्था की असन्तोषजनक स्थिति के कारण वेगनों के बंदार पड़े रहने से रेल-विवत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके कारण रेलवे को अपने निवेश कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ी। इस से कई प्रकार के इंजीनियरी उद्योगों, विशेषकर रेल-सड़क उपकरणों के उद्योगों के लिए होने वाली मांग में भी अधिक बाधा पड़ी। इसके अलावा रेलवे और बांकारों इस्पात कारखाने, पेट्रो-रासायनिक पदार्थों तथा उर्वरकों के कारखानों जैसी सरकारी क्षेत्र की अन्य अनेक प्रमुख औद्योगिक प्रायोजनाएं भी अपने निवेश परिवर्धनों में निर्धारित वृद्धि-दर तक न पहुँच सकीं। इस से इंजीनियरी क्षेत्र के उत्पादन में बाधा पड़ी; किन्तु बिजली से संबंधित भारी उद्योग-यंत्र के उत्पादन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उक्त उद्योग वर्ग द्वारा बिजली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिये जनिशों, पावर ट्रांसफार्मरों और अन्य उपकरणों का जो उत्पादन किया जाता है उस में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हाल ही में प्रारम्भ किया गया ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम इस वृद्धि का अतिरिक्त कारण है।

14. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पूर्ति में सुधार हो जाने के साथ-साथ हाल ही के महीनों में डीजल इंजनों की मांग संतुलित हो गयी है। उपभोक्ता माल उद्योगों में से सूती वस्त्र उद्योग रुई की कमी के कारण विषम परिस्थिति से गुजरता रहा है।

15. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सामान्य रूप से औद्योगिक विकास में मंदी की जो स्थिति आयी वह पावर और परिवहन संबंधी अड़चनों के अलावा अंशत रुई, तिलहन, इस्पात जैसी महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री की कमी के कारण आयी। सरकारी क्षेत्र के निवेश में जो कमी हुई उसका प्रभाव अनेक यांत्रिक इंजीनियरी उद्योगों पर पड़ा जिन में सरकारी क्षेत्र के निवेश की क्रमिक वृद्धि की आशा करते हुए पहले ही अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया गया था। साथ ही, निवेश कार्यक्रमों का हाल ही में कृषि संबंधी और नियोजन प्रधान योजनाओं के लिए लागू कर दिया गया है। इन योजनाओं में कम-से-कम प्रारम्भ में भारी यांत्रिक इंजीनियरी उद्योग के उत्पादों के लिए अतिरिक्त मांग पैदा करने की सीमित क्षमता रहती है। इस वर्ष श्रमिक सम्बन्ध चिन्ताजनक ही रहा। 1970 में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण लगभग 1969 के समान ही 190 लाख श्रमीदन नष्ट हुए।

16. जहाँ हाल ही के वर्षों में संगठित उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि-दर में कमी हुई वहाँ उसके विपरीत लघु उद्योगों और विकेंद्रीकृत उद्योगों के क्षेत्रों के उत्पादन कार्य में सुधार हुआ। उदाहरणार्थ विकेंद्रीकृत क्षेत्र के वस्त्र-उत्पादन में 1970 में लगभग 4.4 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी।

रोजगार की स्थिति

17. पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण, 1970-71 के दौरान रोजगार की जो स्थिति रही उसका मूल्यांकन करना कठिन है। जहाँ 1966-67 और 1967-68 में 'संगठित क्षेत्र' में रोजगार की समग्र स्थिति के संदर्भ में गतिरोध आ गया था वहाँ उस में 1968-69 और 1969-70 में क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी। इन दोनों वर्षों में सरकारी क्षेत्र में रोजगार के संदर्भ में जो वृद्धि हुई वह गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक थी। रोजगार संबंधी 1970-71 की स्थिति के संदर्भ में अप्रैल-सितम्बर 1970 की अवधि के लिए उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि 'संगठित क्षेत्र' की कुल रोजगार स्थिति में पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की अपेक्षा लगभग 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र करीब-करीब रोजगार स्थिति में क्रमशः 2.9 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्ररों से उपलब्ध 1970-71 अप्रैल मार्च के आँकड़ों से भी यह विदित होता है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के मामले में प्रगति की प्रतीति विद्यमान थी। वास्तविक 'नियुक्तियों' के संदर्भ में जहाँ 1969-70 में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ 1970-71 में 5.1 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। साथ ही, 'अधिसूचित रिक्त स्थानों' के संदर्भ में जहाँ 1969-70 में 0.6 प्रतिशत की वास्तविक कमी हुई थी वहाँ 1970-71 में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

18. अभी कुछ समय से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रधान योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इस से यह आशा की जा सकती कि असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। केन्द्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रधान निर्माण कार्यों की व्यवस्था करने और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए क्रमशः 50 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा सामान्य कृषकों, सूखी खेती के क्षेत्रों के कृषकों और कृषि मजदूरों की सुविधा के लिए बनाये गये कीलपय विशेष कार्यक्रम भी उपयोगी होंगे। 41 चुने गये जिलों में प्रारम्भ की जाने वाली सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजनाओं के जिन में से प्रत्येक पर एक-एक करोड़ रुपये का परिव्यय होगा, (मार्च 1971 तक उक्त प्रायोजनाओं में से 30 प्रायोजनाओं के अनुमोदित किया जा चुका है और 22 प्रायोजनाओं के विस्तीय

सहायता दी जा चुकी है)। विशेष रूप से इस प्रकार बनाया गया है कि उन से मुर्गी पालन और डेरी उद्योग जैसे सहायक व्यवसायों का विकास हो। विभिन्न राज्यों के काफी समय से सूखे से पीड़ित 54 जिलों में प्रारम्भ किये जाने वाले ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए चौथी योजना के दौरान 100 करोड़ रुपये का परिव्यय होने की परिकल्पना की गयी है और उन कार्यक्रमों से यह आशा की जाती है कि उन क्षेत्रों के किसानों के रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे।

19. बाणिज्य बैंकों ने भी रोजगार कीपर्याप्त क्षमतायुक्त कार्यों के निमित्त छोटे कृषक, छोटे पैमाने के निर्माता, फुटकर व्यापारी, सड़क परिवहन चालक, छोटे व्यापारी, व्यावसायिक और स्वनिर्वाहित व्यक्ति जैसे कम साधन वाले अनेक ऋणकर्ताओं के लिए उचित ब्याज-दरों पर दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को लागू कर दिया है।

मूल स्थिति

20 आलांच्य वर्ष में सामान्य मूल्य-स्तर में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी जब कि पिछले वर्ष उसमें 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मूल्य-स्थिति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तत्व यह था कि उन पर बराबर दबाव पड़ता गया यद्यपि सितम्बर 1970 और मई 1971 के बीच उन में बहुत कम घटबढ़ हुई।

21. आर्थिक सलाहकार का थोक मूल्य संबंधी सूचक अंक (आधार-1961-62 = 100) जहाँ जून 1970 के अन्त तक 180.5 था वहाँ वह

सारणी 5—थोक मूल्यों के सूचकांकों की प्रवृत्तियाँ

(आधार : 1961-62 = 100)

वजन*	जून 1969 के अन्त में	जून 1970 के अन्त में	जून 1971 के अन्त में	प्रतिशत अंतर		
				जून 1969 के अन्त में	जून 1970 के अन्त में	
				सुलना में जून 1970 के अन्त में	सुलना में जून 1971 के अन्त में	
1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य 3	1000	173.5	180.5	186.1	+4.0	+3.1
खाद्य वस्तुयें	413	201.9	204.3	206.8	+1.2	+1.2
अनाज	(35.8)	210.8	212.1	207.0	+0.6	—2.4
(1) चावल	(16.2)	202.4	209.2	204.8	+3.4	—2.1
(2) गेहूँ	(7.8)	207.8	205.9	199.9	+0.9	—2.9
(3) ज्वार	(2.2)	198.3	188.8	191.9	—4.8	+1.6
(4) बाजरा	(1.1)	207.2	187.6	139.5	—9.5	—25.6
दालें	(6.5)	241.6	240.0	247.8	—0.7	—3.3
खाद्य	(13.0)	211.1	239.5	198.1	+13.5	—17.3
शराब और तमाकू	25	202.2	184.5	194.4	—8.8	+5.4
तमाकू से बनी वस्तुयें	(47.5)	199.5	212.1	245.6	+6.3	+15.8
ईंधन, पावर, बिजली और जिकनाई पदार्थ	61	153.4	160.3	170.5	+4.5	+6.4
औद्योगिक कच्ची सामग्री	121	185.7	201.3	191.0	+8.4	—5.1
रूई	(18.5)	169.7	191.0	229.8	+12.6	+20.3
पटसन	(9.6)	189.3	159.6	152.0	—15.7	—4.8
तिलहन	(43.3)	215.1	144.3	204.0	+13.6	—16.5
मूंगफली	(20.8)	216.9	240.1	192.9	+10.7	—19.7
रासायनिक पदार्थ	7	179.1	185.1	195.0	+3.4	+5.3
मशीनें और परिवहन उपकरण	79	133.7	145.7	156.1	+9.0	+7.1
मिश्रित वस्तुयें	294	140.9	151.7	165.4	+7.7	+9.0
(1) मध्यवर्ती उत्पाद	(19.5)	155.3	174.9	193.0	+12.6	+10.3
(2) तैयार उत्पाद	(80.5)	137.4	146.0	158.7	+6.3	+8.7
सूत से बनी वस्तुयें	(26.8)	131.1	140.0	159.4	+6.8	+13.4
जूट से बनी वस्तुयें	(8.1)	148.1	166.5	191.2	+12.4	+14.8
रसायन से बनी वस्तुयें	(9.2)	135.6	143.9	149.5	+6.1	+3.9
लोहे और इस्पात से बनी वस्तुयें	(12.2)	149.7	160.8	177.6	+7.4	+10.4
कागज से बनी वस्तुयें	(3.3)	120.4	121.3	124.7	+0.7	+2.8

*कोष्ठकों में दिये हुए आंकड़े सम्बन्धित मुख्य वर्ग के लिये निर्धारित वजन सम्बन्धी प्रतिशत को दर्शाते हैं।

बढ़कर 12 सितम्बर 1970 को 183.8 हो गया। इसके बाद कटाई का मौसम शुरू होने के साथ साथ उस में थोड़ी सी घट-बढ़ होती रही। किन्तु, चीनी मूलभूत प्रवृत्ति निरंतर द्वावपूर्ण थी अतः सूचकांक पुनः 9 जनवरी 1971 को अपने पहले के उच्चतम स्तर अर्थात् 183.8 पर पहुँच गया और महीने के अन्त तक इसी स्तर के आसपास रहा। इस अवधि के दौरान मूल्यों पर पड़े दबाव का प्रमुख कारण यह था कि इस वर्ष के प्रारम्भ में रूई और तिलहन जैसी महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्ची सामग्री की पूर्ति में उसकी बढ़ती हुई मांग की तुलना में कम पाई गयी। अधिकतर मात्रा में आयात, सामान वितरण, सामान्य और चयनात्मक ऋण नियंत्रण जैसे साधारणतम उपायों के अपनाये जाने के कारण मूल्यों पर पड़ने वाला दबाव कम हुआ और मूल्य सूचकांक कम होकर 27 फरवरी 1971 को 180.6 तक पहुँचा। उसके बाद वह मई 1971 के तीसरे सप्ताह तक 180 और 183 के बीच घटता-बढ़ता रहा। कृषि-पण्यों में मंदी का समय जब आया तब पुनः मूल्यों पर दबाव पड़ने लगा। थोक मूल्यों के सूचकांक में पिछले दो लेखा वर्षों में जो घट-बढ़ हुई उसे सारणी 5 में दिखाया गया है।

22. वर्गिकार देखने पर खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अपेक्षाकृत अधिक स्थायिता पायी गयी जब कि औद्योगिक कच्ची सामग्री के मूल्यों में कमी हुई, क्योंकि मूँगफली के तेल और अन्य खाद्य तेलों के मूल्यों में पिछले वर्ष के उच्च स्तर की तुलना में इस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से भारी कमी हो गयी थी। प्रायः अन्य सभी वर्गों के मूल्यों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि हुई।

23. खाद्य पदार्थों के मूल्य सूचकांक की सापेक्ष स्थायिता उनका सप्ताह स्थिति की अपेक्षाकृत अधिक सहजता की परिचायक है। क्रमशः चौथे वर्ष अच्छी कटाई होने के कारण 'अनाजों' के मूल्यों में 2.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी हुई जब कि पिछले वर्ष उन में वृद्धि पायी गयी थी यद्यपि वह भिन्नात्मक ही थी (0.8 प्रतिशत)। चावल और गेहूँ जैसे दालों से भिन्न अनाजों के मूल्यों में क्रमशः 2.1 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत की कमी हुई। बाजरे के मूल्यों में 25.6 प्रतिशत की गिरावट हो गयी। मूल्यों में हुई इन कमियों के विपरीत 'दालों' के मूल्यों में 3.3 प्रतिशत और ज्वार के मूल्यों में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जहाँ अक्टूबर 1970 के आरम्भ तक 'खाद्य तेलों' के मूल्यों पर भारी दबाव पड़ रहा था वहाँ उसके बाद 1970-71 के मौसम के दौरान अच्छी फसल होने की संभावनाओं, विशेषकर मूँगफली के संवर्ध में ऐसी स्थिति की संभावना के कारण उक्त दबाव कम हुआ। यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो 'खाद्य तेलों' के मूल्यों में आलोच्य वर्ष में 17.3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी हुई जब कि 1969-70 में उन में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

24. तिलहन और पटसन के मूल्यों में हुई कमी (क्रमशः 16.5 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत) के कारण औद्योगिक कच्ची सामग्री वर्ग के मूल्यों में उल्लेखनीय रूप से 5.1 प्रतिशत की कमी हुई (जब कि 1969-70 में उन में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी)। 1969-70 में जहाँ पटसन के मूल्यों में 15.7 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी हुई थी वहाँ तिलहन के मूल्यों में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत रूई के मूल्यों पर आलोच्य वर्ष में पुनः दबाव पड़ने लगा और 1969-70 के दौरान हुई 12.6 प्रतिशत की वृद्धि से भी अधिक 20.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि सितंबर-अक्टूबर 1970 में जब व्यापार अनुमानों के अनुसार यह निर्धारित किया गया कि 1970-71 में होनेवाली रूई की फसल की मात्रा 62 लाख गांठों के उच्च स्तर पर होगी, (बाद में इस में परिवर्तन कर केवल 54 लाख गांठों निर्धारित किया गया) अस्थायी रूप से राहत की स्थिति पायी गयी फिर भी दंशी रूई की भारी कमी और आयातों में विलंब होने के कारण रूई के मूल्यों में 1970 के आरम्भ से बराबर वृद्धि की प्रवृत्ति ही पायी गयी। रूई का थोक

मूल्य सूचकांक 6 फरवरी 1971 तक 257.0 के उच्चतम स्तर तक पहुँच गया था जो 1970 के आरम्भ में विद्यमान स्तर की तुलना में 53 प्रतिशत की वृद्धि का सूचक था। किन्तु, बाद में जब रूई के आयात संघी सरकार के कार्यक्रम में तेजी लायी गयी और ऋण-नियंत्रण संबंधी उपायों को कड़ा किया गया तब रूई के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति पायी जाने लगी और 15 मई 1971 तक उनका सूचकांक 218.1 तक पहुँच गया जो उपर्युक्त उच्चतम स्तर की तुलना में 15.1 प्रतिशत की कमी का परिचायक था। उसके पश्चात् रूई के मूल्यों में आयातित रूई के अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण पुनः वृद्धि होने लगी और सूचकांक वर्ष के अंत में 229.8 पर आकर रुक गया।

25. यद्यपि 1970-71 में पटसन का अनुमानित उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम था फिर भी जूट मिल उद्योग और साथ ही कलकत्ता बंगलाह में पायी गयी श्रमिक अशांति के कारण निर्माण कार्य में मंदी आ जाने से मार्च 1971 के आरंभ तक उसके मूल्यों में क्रमशः कमी की प्रवृत्ति पायी जाती रही। कलकत्ता बंगलाह में पायी गयी श्रमिक अशांति के कारण जूट के निर्यातों में भी बाधा पड़ी। बाद में जब पटसन के संवर्ध में मिलों की मांग बढ़ने लगी तब उसके मूल्यों में वृद्धि होने लगी। इस वृद्धि के मूल में पूर्व बंगाल में हुई धटनाएँ भी कारण बनी रहीं। इसके फलस्वरूप, इस वर्ष के दौरान पटसन के मूल्य सूचकांक में पर्याप्त कमी होने के बावजूद अंतिम तिमाही (अप्रैल-जून) में उस में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

26. 'तिलहन' के मूल्यों में 1969-70 में हुई 13.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 16.5 प्रतिशत तक की जो कमी हुई वह प्रमुख रूप से मूँगफली के मूल्यों में हुई 19.7 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी के कारण हुई। आलोच्य वर्ष भर में बहुत अच्छी फसल की संभावनाओं के कारण उक्त मूल्यों में बराबर कमी होती आयी है। कमी की यह प्रवृत्ति सितंबर-अक्टूबर 1970 के दौरान बाजार में भारी मात्रा में मूँगफली की नई फसल के आ जाने और बाद में अमेरिका से 75,000 मी. टन के सोयाबीन तेल का आयात करने के लिए एक नये पी. एल. 480 करार पर हस्ताक्षर हो जाने की रिपोर्टों के कारण और बढ़ गयी।

27. कृतिपय महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्ची सामग्री की पूर्ति की स्थिति में कमी हो जाने के कारण 1970-71 में उक्त सामग्री से बनी वस्तुओं के मूल्यों में 1969-70 में हुई 7.7 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि स्थानीय रही। निर्मित उत्पादों में से सूत और जूट से बनी वस्तुओं के मूल्यों में अधिक वृद्धि पायी गयी। उनके मूल्यों में जहाँ पिछले वर्ष क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 12.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहाँ इस वर्ष उस से भी अधिक क्रमशः 13.9 प्रतिशत और 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोहे और इस्पात से बनी वस्तुओं के मूल्यों में 1970-71 में 7.4 प्रतिशत और 1970-71 में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, कागज से बनी वस्तुओं और रासायनिक पदार्थों आदि के मूल्यों में बराबर वृद्धि हो रही।

28. शराब और तमाखू के वर्ग के भीतर 'तमाखू' से बनी वस्तुओं के मूल्यों में जहाँ लेखा वर्ष (जुलाई 1970—मई 1971) के पहले ग्याह महीनों के दौरान 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहाँ जून 1971 में 12.2 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप इस वर्ष के दौरान इन मूल्यों में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी जब कि पिछले वर्ष इन में 6.3 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार 'इंधन, पावर, बिजली और चिकनाई पदार्थ' के वर्ग के भीतर खनिज तेलों, मिट्टी के तेल और पेट्रोल के मूल्यों में जहाँ पहले ग्याह महीनों में प्रायः स्थिरता विद्यमान थी वहाँ जून 1971 में तेजी से

वृद्धि हुई। उक्त वृद्धि की दर 6.0 प्रतिशत और 19.0 प्रतिशत के बीच थी।

29. आलोक्य वर्ष में 'अनाजों' के मूल्यों के संदर्भ में सापेक्ष रूप से जो स्थिरता पायी गयी उसका प्रभाव श्रमिक वर्ग के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960-100) में हुए परिवर्तन में परिलक्षित हुआ। उक्त सूचकांक में जुलाई 1970—जून 1971 के दौरान 1.1 प्रतिशत की थोड़ी सी वृद्धि हुई जब कि उस में 1969-70 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

नीति संबंधी उपाय—कृषि पण्य

30. क्रमशः दूसरे वर्ष भी अनाजों के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अनाजों की उगाही में पर्याप्त वृद्धि की गयी। चावल को छोड़कर अन्य सभी अनाजों की आवाजाही पर से नियंत्रणों को हटा दिया गया और सरकार के पास रहने वाले अनाजों के स्टॉक में कम आयात किये जाने के बावजूद इस वर्ष के अंत तक लगभग 30 लाख मी. टन की और वृद्धि हुई।

सारणी 6—अनाज-व्यवस्था से सम्बन्धित मूल आंकड़े

(दस लाख मी० टन)

	1968-69 फसल		1969-70 फसल		1970-71 फसल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
उगाही						
कुल अनाज	7.9	6.1	9.2	6.6	9.5	8.1*
इसमें से :						
चावल (नवंबर—प्रस्तूबर)	3.6	3.3	4.5	3.0	4.7	3.1*
गेहूँ (अप्रैल—मार्च)	3.6	2.3	3.7	3.2	4.0	4.5*
आयात @		5.7		3.9		3.6
अनाजों का सार्वजनिक वितरण @		10.4		9.5		8.9
वर्ष के अंत में अनाजों के स्टॉक		5.5		5.8		8.5

*अनन्तिम

@ये क्रमशः 1968, 1969 और 1970 के फेल्लेयर वर्ष के आंकड़े हैं।

31. अनाजों के देशी उत्पादन में निरंतर वृद्धि होने के साथ-साथ उनके आयातों की मात्रा को 1968 और 1969 के क्रमशः 57 लाख मी. टन और 39 लाख मी. टन से घटाकर 1970 में 36 लाख मी. टन कर दिया गया है। यह संभव है कि 1971 के दौरान आयातों की मात्रा 30 लाख मी. टन से कम हो जाए। वास्तव में 1971 की पहली छमाही में केवल 7 लाख मी. टन के अनाजों का आयात किया गया जब कि 1970 की तदनुकूपी अवधि में 18 लाख मी. टन के अनाजों का आयात किया गया था। सरकार ने भी 1972 तक अनाजों के सभी रियायती आयातों को बन्द कर देने का विचार किया है।

32. कम आयातों के बावजूद केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के स्टॉकों की मात्रा जून 1971 के अन्त में 85 लाख मी. टन थी जो एक वर्ष पहले विद्यमान स्तर से 27 लाख मी. टन अधिक थी। तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 20 लाख मी. टन के अनाजों को अलग कर देने पर भी अनाजों के समीकरण भंडार की मात्रा 65 लाख मी. टन होगी। बहुत अधिक मात्रा में स्टॉक का यह संचयन इसलिए संभव हो सका कि उगाही के कार्यक्रमों में तीव्रता लायी गयी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा अनाजों की कम खरीद की गयी।

33. 1969-70 की फसल से कुल 66 लाख मी. टन के अनाजों की उगाही की गयी। 1970-71 की फसल से जून 1971 के अंत तक की गयी कुल उगाही की मात्रा 81 लाख मी. टन थी जब की समूचे फसल वर्ष के लिए 95 लाख मी. टन का लक्ष्य निर्धारित किया

गया था। भारतीय खाद्य निगम अनाज व्यापार में क्रमशः महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता आ रहा है। निगम ने जून 1971 के अन्त तक 1970-71 की फसल से लगभग 74 लाख मी. टन के अनाजों की उगाही की जब कि 1969-70 की पूरी फसल से उगाही की गयी मात्रा 54 लाख मी. टन थी।

34. खुले बाजार में अनाजों के मिलाने में सुधार हो जाने के कारण उचित मूल्यों की दुकानों/राशन की दुकानों से वितरित किये जाने वाले अनाजों की मात्रा पिछले दो वर्षों से कम होती आ रही है। 1970 के दौरान वितरित किये गये अनाजों की कुल मात्रा 89 लाख मी. टन थी जब कि 1969 में उक्त मात्रा 95 लाख मी. टन थी। उचित मूल्यों की दुकानों/राशन की दुकानों की संख्या भी जहाँ 1969 के अंत में 1.39 लाख थी वहाँ 1970 के अंत तक कम होकर 1.22 लाख हो गयी।

35. अनाजों की आवाजाही से संबंधित प्रतिबंधों का जहाँ तक संबंध है, अप्रैल 1970 से विधिक राशन व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले बम्बई, कलकत्ता और आसनसोल-दुर्गापुर के संयुक्त प्रदेश के क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में गेहूँ और गेहूँ की दस्तूओं की आवाजाही को मुक्त बना दिया गया। उसके बाद मई 1971 में विधिक राशन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले बम्बई क्षेत्र में गेहूँ की आवाजाही पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा दिया गया।

36. कृषि संबंधी प्रमुख कच्ची सामग्री के संबंध में, जिसके मूल्यों की स्थिति इस वर्ष के दौरान चिंताजनक थी, सरकार ने अपने

आयात कार्यक्रम में वृद्धि की। रूई के मामले में सरकार ने 1970-71 के मौसम में लगभग 13.3 लाख गांठों का आयात करने का निश्चय किया जब कि 1969-70 में 9.1 लाख गांठों का आयात किया गया था (सारणी 7)। फिर भी, वास्तव में आयातित रूई के प्राप्त होने में काफी विलंब हो गया था और अतः रूई के मूल्यों में तेजी से वृद्धि पायी गयी जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 1970 के मध्य में बैंकों द्वारा रूई पर दिये जाने वाले अग्रिमों से सम्बन्धित नियंत्रण को कड़ा करना आवश्यक हो गया था। वस्त्र आधुक्त ने 9 दिसंबर 1970 को मिलों के पास रूई के जो स्टॉक रह सकते थे उनकी मात्रा में और कटौती कर दी। इसके अलावा वायदा बाजार आयोग ने कपास के वायदा व्यापारों को रद्द कर दिया और रूई के गैर-अंतरणीय विशिष्ट दाति ठेकों की अर्वाध को दिसंबर 1970 में छः महीनों से कम कर तीन महीने और फरवरी 1971 में उसे और कम कर एक महीना कर दिया। तिलहन के संबंध में सरकार ने पी. एल. 480 के अधीन अधिक मात्रा में सोयाबीन तेल का आयात करने की अनुमति दी और तोरिया के बीजों के आयात के लिए व्यवस्था की। मूंगफली के उत्पादन में सूचित वृद्धि के बावजूद इस वर्ष सट्टेबाजी के उद्देश्य से तिलहन और तेलों के स्टॉक बनाये जाने के कारण उनके मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गये थे, अतः रिजर्व बैंक को तिलहन, वनस्पति तेलों और वनस्पति पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों के संबंध में अपने ऋण नियंत्रणों को जनवरी 1971 के अंत में कड़ा करना पड़ा।

37. कृषि के उत्पादक आधार को मजबूत करने के उद्देश्य से बनायी गयी नयी कृषि प्रणाली के अधीन कार्यक्रमों को आलोच्य

अर्वाध में विस्तारित किया गया और उनमें सीवृत्ता लायी गयी। कृषि-विकास के कार्यक्रमों का क्षेत्रीय विस्तार किया गया ताकि सूखी खेती के क्षेत्रों को भी उनके अधीन लाया जा सके और ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की जा सकें, जिससे उन्हें भी विकास के लाभ प्राप्त हो सकें। प्रारंभ में अन्न-उत्पादन-नीति को इस प्रकार कार्यान्वित किया गया कि नये तकनीकों का समग्र उपयोग कर क्षेत्रों की वर्तमान उत्पादन क्षमता को पूर्ण रूप से काम में लाया जाए तथा उन क्षेत्रों को निश्चित जल पूर्ति तथा अन्य अनुकूल सुविधाएँ प्राप्त हों। यद्यपि उक्त प्रणाली से लाभकारी परिणाम प्राप्त हुए हैं फिर भी उस से सूखे क्षेत्रों और कृषक समुदाय के कमजोर वर्गों को अब तक कोई सुविधा नहीं मिली है। अतः सूखी खेती के क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने और अधिकांश छोटे परन्तु सक्षम और समर्थ कृषकों, सामान्य कृषकों और कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम बनाये गये।

38. यह आशा की जाती है कि वर्तमान कार्यक्रमों में से अधिक उपजवाली किस्मों के कार्यक्रम के अंतर्गत 1970-71 में 140 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र आया जब कि पिछले वर्ष उसके अंतर्गत वास्तव में 114 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र आया था। इसके अलावा आलौच्य वर्ष में चावल और गेहूँ दोनों की नयी सुधरीकृत किस्मों का निर्धारण करने की दिशा में और प्रगति की गयी है और उनके उत्पादन के क्षेत्रों में भी काफी विस्तार हुआ है। चावल की अधिक उपजवाली किस्मों के उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है अर्थात् जहाँ 44.5 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में उक्त

सारणी 7—उद्योगों के लिये कच्ची सामग्री की उपलब्धि¹

	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71 (अनुमानित)
1	2	3	4	5
रूई (प्रति गांठ 180 किलोग्राम के हिसाब से लाख गांठें) (सितम्बर-मार्गस)				
उत्पादन ²	65.4@	59.2	60.7	54.0
आयात	7.8	4.3	9.1	13.3
उपलब्धि	92.4	84.7	86.9	83.8
मिलों के उपभोग की मात्रा	61.7	62.0	63.7	59.3
पटसन और मेस्ता (प्रतिगांठ 180 किलोग्राम के हिसाब से लाख गांठें) (जुलाई-जून)				
उत्पादन	75.9	38.4	67.9	61.4*
आयात	—	6.1	—	—
उपलब्धि	94.6	64.5	75.9	75.4
मिलों के उपभोग की मात्रा	71.3	58.5	62.0	60.0
प्रमुख तिलहन ³ (बस लाख मी० टन) (जुलाई-जून)				
उत्पादन	8.3	6.8	7.6	8.4

1. उपलब्धि से उत्पादन, आयात और प्रारंभिक स्टॉक अभिप्रेत हैं।

2. बाणिज्येतर, उत्पादन सहित व्यापार-अनुमान।

3. मूंगफली, तोरिया, सरसों, भलसी, तिल और एरण्ड।

@वास्तविक गांठें।

*अन्तिम अनुमान।

किस्मों का उत्पादन करने का लक्ष्य था वहाँ 1970-71 में 55 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में उत्पादन किया गया। मोटे अनाजों में से बाजरे को संकर किस्मों का उत्पादन उत्पादक रहा है। विविध फसल, पौधों के संरक्षण, और लघु तथा मझौली सिंचाई जैसे अन्य कार्यक्रमों में परिणाम की दृष्टि से पर्याप्त वृद्धि हुई। महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों की उत्पादन दरों में वृद्धि लाने के लिए गये तकनीकों का निर्धारण करने की दिशा में किये जाने वाले प्रयत्नों को भी आलोच्य वर्ष में तेजी से आगे बढ़ाया गया।

39. यद्यपि उर्वरकों के उपभोग की मात्रा में वृद्धि हुई है, फिर भी 1969-70 और 1970-71 दोनों वर्षों में उनके उत्पादन की वृद्धिदर में कमी पायी गयी है। आंशिक रूप से इसका कारण यह था कि विक्रेताओं तथा कृषकों के पास पहले ही बड़ी मात्रा में उर्वरकों के स्टॉक विद्यमान थे। जिन क्षेत्रों में जल की पर्याप्त पूर्ति की स्थिति है और जिन क्षेत्रों में अधिक उपजवाली किस्मों के उत्पादन की भूमि में विस्तार हुआ है, उन क्षेत्रों में उर्वरकों के उपभोग की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, अन्य क्षेत्रों में उपयुक्त प्रकार से उत्पादन-भूमि का विस्तार करना अभी शेष है। ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीयकरण कार्यक्रम का महत्व मिल जाने के

कारण जिन गाँवों में बिजली की पूर्ति की गयी है और कृषि संघों पंप सेटों को बिजलीचालित कर दिया गया है, उन गाँवों और पंप सेटों की संख्या में वृद्धि हुई है। निजी नल कूप लगाये जाने और ट्रैक्टरों का उपयोग किये जाने की दिशा में और प्रगति पायी गयी है (सारणी 8)। "विविध एजेंसी प्रोविज़न" अपनाये जाने के कारण विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषि को दिये जानेवाले ऋणों की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई। सहकारी समितियों द्वारा 1969-70 में इस क्षेत्र को दिये गये ऋणों की कुल राशि 682 करोड़ रुपये थी जब कि इस वर्ष के लिए 640 करोड़ रुपयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और पिछले वर्ष वास्तव में 816 करोड़ रुपयों के ऋण प्रदान किये गये थे। 1970-71 में प्रदान किये गये अल्पावधि ऋणों की राशि 615 करोड़ रुपये थी; भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किये जानेवाले दीर्घावधि ऋणों की राशि में भी इस वर्ष के दौरान और वृद्धि होने की आशा की जाती है। वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को दिये जानेवाले ऋणों में 1970-71 में अभूत-पूर्व वृद्धि हुई, प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व जून 1969 में 188 करोड़ रुपयों के ऋण बकाया था, किंतु उक्त बकाया ऋणों की राशि मार्च 1971 के अंत में बढ़कर 379 करोड़ रुपये हो गयी।

सारणी 8—नयी कृषि प्रणाली की प्रगति

कार्यक्रम	यूनिट	1968-69	1969-70	1970-71 (लक्ष्य)
कार्यक्रम के अधीन प्राप्त वाला कुल क्षेत्र				
1. अधिक उपजवाली किस्में	10 लाख हेक्टेयर	9.3	11.4	15.1 (14.0)
2. विविध फसल	"	6.1	8.0	10.2 (9.5)
3. पौधों का संरक्षण	"	40.0	48.0	52.0@ (52.0)
उर्वरकों का उपभोग	1000 मी. टन (पोषक)	1760	2009	2540 (2113)
1. नाइट्रोजनयुक्त (एन)	"	1208	1398	1730 (1426)
2. फास्फेटयुक्त (पी ₂ ओ ₅)	"	382	435	560 (461)
3. पोटेशियुक्त (के ₂ ओ)	"	170	176	250 (226)
कुल क्षेत्र जहाँ सिंचाई की गयी				
बड़ा और मझौला*	10 लाख हेक्टेयर	18.6	19.4	20.0 (20.7)
लघु	"	19.0	20.4	21.9 (21.9)
लघु सिंचाई के सम्बंध में संस्थाओं का विवेक	(करोड़ रुपये) †	106	120	— (30)
बिजली-चालित कृषि सम्बन्धी पंप	(हजार में)	1069	1329	1609 (1594)
लगाये गये निजी नलकूप	"	67	90	— (100)
ट्रैक्टरों का देशी उत्पादन	"	15.5+	17.1++	25.0 (20.1)

नोट: संभाव्य उपलब्धि के आंकड़े कोष्ठकों में दिये गये हैं।

*क्षमता।

+ इनके अलावा 15,500 ट्रैक्टरों का आयात किया गया।

++ इनके अलावा 1969-70 की आवश्यकताओं के लिये 33,500 ट्रैक्टरों का आयात करने के सम्बन्ध में किये गये ठेके के संदर्भ में 31 मार्च, 1971 तक 14,888 ट्रैक्टरों का लदान हो चुका है।

@मूल लक्ष्य 423 लाख हेक्टेयर था।

40. 45 षुनं हए जिलों में छोटें कृषक-विकास एजेंसियों को अनुमोदित किया गया है जब कि चौथी योजना के शेष वर्षों के लिए 46 जिलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और मार्च 1971 तक 43 एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी गयी। उक्त एजेंसियों को छोटे परंतु सक्षम और समर्थ कृषकों का पता लगायेंगी, उनकी समस्याओं का अध्ययन करेंगी और उनके लिए संस्थागत ऋण, खेती में काम आनेवाली मूलभूत सामग्री, आदि की व्यवस्था करने में सहायता देंगी। सामान्य कृषकों और कृषि-श्रमिकों के लिये पूरक व्यवसाय और नियोजन-प्रधान कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए एजेंसियों का गठन किया गया है। नागालैंड और मेघालय को छोड़कर शेष सभी राज्यों में पहले से ही स्थापित किये गये कृषि उद्योग निगमों ने खेती में काम आनेवाली अत्यावश्यक मूलभूत सामग्री और कृषि संबंधी मशीनों को उपलब्ध कराने में और प्रगति की है। केन्द्रीय सरकार के 1971-72 के बजट में 50 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन-प्रधान योजनाएं प्रारम्भ करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए खर्च किया जाएगा। परंपरागत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण कार्य करने के लिए अनुदान प्रदान करने के निमित्त 1971-72 के बजट में 18.5 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

41. रूई और पटसन के संबंध में सरकार ने सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से उनके आयातों/सप्लाई का कार्य कराने के लिए भी कदम उठाये हैं, इस उद्देश्य के लिए विशेष नियमों की स्थापना की गयी है। भारतीय रूई निगम 15 सितंबर 1970 से अपना कार्य करने लगा; उसे रूई के आयात-कार्य के अलावा आधार-मूल्य संबंधी कार्य, अतिरिक्त लंबे रेशेवाली रूई खरीदने और सरकार के प्रबंध के अधीन कार्य करनेवाली मिलों को रूई की सप्लाई करने का कार्य सौंपा गया है। निगम ने मुख्यतः सरकारी क्षेत्र की मिलों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से वंशी रूई खरीदने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जूट के मामले में 2 अप्रैल 1971 को पटसन खरीदने के लिए भारतीय जूट निगम की स्थापना की गयी ताकि उसके उत्पादकों को न्यूनतम आधार-मूल्य प्राप्त हो सकें और देश के भीतर से ही जूट खरीदकर या आवश्यकता पड़ने पर उसके आयात कर समीकरण भण्डार बनाये जा सकें।

औद्योगिक वस्तुएं

42. औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की जो प्रवृत्ति पायी जाती थी उस में चौथी योजना के पहले दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र के निवेशों में कमी हो जाने से आंशिक रूप में बाधा पड़ी। 1971-72 के लिए सरकारी क्षेत्र के योजनागत परिव्यय की राशि को 3024 करोड़ रुपयों तक बढ़ाकर अर्थात् 1970-71 के संभाव्य योजनागत व्यय की राशि में लगभग 600 करोड़ रुपयों की वृद्धि कर इस स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। प्राथमिकतावाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं के संदर्भ में 1971-72 की आयात नीति को काफी उदार बनाया गया। इसके अतिरिक्त आयात नीति में कच्ची सामग्री के आयातों के लिये भी विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है जिससे बंद इंजीनियरी यूनिटों को, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के ऐसे यूनिटों को पुनः संचालित करने में सुविधा हो। बंद यूनिटों या बंद होने की स्थिति में रहनेवाले यूनिटों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के ऐसे यूनिटों का पुनर्निर्माण करने की दिशा में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से अप्रैल 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम नामक एक नये निगम की स्थापना की गयी जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है।

43. औद्योगिक विकास नीति के संदर्भ में जहाँ फरवरी 1970 में सरकार द्वारा घोषित की गयी नयी लाइसेंसनीति औद्योगिक

प्रगति के लिए आधार प्रस्तुत करती रही वहाँ आलोच्य वर्ष के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में प्रारंभ किये गये उद्योगों और लघु उद्योगों और साथ ही, युवा तकनीशनों, इंजीनियरों और अन्य स्वनिर्वाहित व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किये गये उद्योगों के अनुकूल स्पष्ट रूप से उक्त नीति में संशोधन किया गया ताकि उद्योगों को अधिक व्यापक क्षेत्र में विस्तारित और विकसित किया जा सके। इन उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के निमित्त कई कदम उठाये गये हैं। केंद्रीय सरकार के 1971-72 के बजट में छोटे यूनिटों द्वारा आयात की जानेवाली मशीनों के संदर्भ में आयात शुल्क में कटौती तथा विशेष रूप से उत्पादक वस्तुओं के संबंध में विभेदक उत्पादन शुल्कों की व्यवस्था की गयी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं ने पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जानेवाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नयी नीतियां बनायी हैं। 1971-72 की आयात नीति में छोटे यूनिटों, युवा तकनीशनों, इंजीनियरों और अन्य स्वनिर्वाहित व्यक्तियों तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को कच्ची सामग्री की आवश्यकताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।

44. औद्योगिक लाइसेंसिकरण नीति संबंधी जांचसमिति (इत समिति) जिसके संबंध में इस रिपोर्ट में बाद में उल्लेख किया गया है, की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने भारतीय उद्योग के "संयुक्त क्षेत्र" के विकास के लिए कुछ ठोस कदम उठाये।

45. लाइसेंस नीति के क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मर्दानों की संख्या में वृद्धि की गयी है और इस से आरक्षित मर्दानों की कुल संख्या 128 हो गई है। औद्योगिक लाइसेंसिकरण के उद्देश्य के लिए 'प्रतिबन्धित' सूची को, जिसे मार्च 1970 से प्रायोगिक रूप से स्थापित किया गया था, रद्द कर दिया गया है।

46. इसके अलावा अलग-अलग उद्योगों की आकीस्मकताओं के अनुरूप विशिष्ट नीति संबंधी उपाय भी किये गये। बिजली के केबलों, तारों तथा एल्यूमिनियम और उसके उत्पादों जैसे कीतपय उद्योगों के मामले में बाजार की स्थितियों को देखकर सरकार को विधिक मूल्य नियंत्रण लगाना पड़ा। इसके अलावा बिजली के केबलों और तारों के उत्पादन में, तांबे का उपयोग किये जाने पर सिवाय उस संदर्भ के जहाँ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन निर्यात के उद्देश्य से किया जाता हो अन्यत्र रोक लगायी गयी। जहाँ उद्योगों के लागत स्वरूप के कारण मूल्यों में कटौती करने की आवश्यकता थी वहाँ ऐसी कटौती या तो विधिक कटौती के द्वारा, जैसे कि रेंयन टायर तांगे, डोरी या वस्त्र के मूल्यों में (शुल्क दर आयोग की सलाह पर) कटौती की गयी है, या सम्बन्धित उद्योगों के साथ की गयी अनौपचारिक व्यवस्थाओं द्वारा जैसे कि मोटर के टायरों और ट्यूबों के फुटकर व्यापार के मूल्यों संबंध में ऐसी व्यवस्था की गयी है, औषधियों और दवाइयों के मूल्यों को एक व्यापक नियंत्रण प्रणाली के अधीन लाया गया। उन मामलों में मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति दी गयी जहाँ मजदूरी, कच्ची सामग्री या दूसरे व्यय में हाल ही के वर्षों में वृद्धि हुई हो। इत्याद के मूल्यों में हुई वृद्धियों के कारण साइकिलों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी गयी। सीमेंट के मामले में मालभाड़ा समीकरण लेख में विद्यमान बकायों की पुनः पूर्ति करने के उद्देश्य से मूल्य-वृद्धियों को अनुमति दी गयी।

47. इत्याद की भारी कमी को कम करने के उद्देश्य से उसके आयातों को काफी उदार बना दिया गया इसके परिणामस्वरूप 1970-71 के वित्तीय वर्ष में इत्याद के संबंध में जारी किये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य 1969-70 के दौरान जारी किये गये लाइसेंसों के मूल्य के दुगुने से अधिक था। सरकार ने इत्याद के निर्यातों को विनिर्धारित करना, मुख्य उत्पादनों द्वारा

मिश्रित उत्पादन किये जाने के संदर्भ में आवश्यक परिवर्तन लागू करना आदि कई अन्य उपाय भी किये। वितरण की प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया और वितरण संबंधी नियंत्रण को सामान्यतः लोह और इस्पात के सभी उत्पादों पर, उनके दुर्लभ और सुलभ वर्गों के बीच कोई विभेद किये बिना लागू किया गया। नियंत्रित मूल्यों में पुनर्वर्तनों (Re-rollers) के लिए बिलेट की पूर्ति की जाती है; अतः अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण को पुनः इस्पात लपेट कर बनायी गयी वस्तुओं के लिए भी लागू किया गया ताकि अधिक मार्जिन पाने के लिए उनको अलग रख देने की प्रवृत्ति को रोका जाए।

48. मूल्य नियंत्रण के अधीन रहनेवाले कृषि पण्यों और कृषि आधारित उद्योगों में से प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में इस उद्देश्य से वृद्धि करने की अनुमति दी गयी कि छोटे उत्पादकों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। चीनी की संतोषजनक सप्लाई स्थिति को देखते हुए उसके मूल्य, वितरण और आवाजाही से सम्बन्धित नियंत्रणों को हटा दिया गया, परंतु मासिक पूर्ति की पद्धति को जारी रखा गया।

बजट संबंधी गतिविधियाँ @

49. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 1970-71 के बजट की गतिविधियाँ समग्र स्थिति के बहुत अधिक बिगड़ जाने का संकेत करती हैं। 1969-70 (वास्तविक) के 37 करोड़ रूपयों के सामान्य सभ्य घाटे के मुकाबले में 1970-71 के परिशोधित अनुमानों से 455 करोड़ रूपयों के घाटे का पता चलता है। कुल प्राप्तियों की वृद्धि दर में पर्याप्त मात्रा में कमी होने के परिणामस्वरूप यद्यपि कुल वितरणों की वृद्धि दर में कमी हुई फिर भी स्थिति में यह खराबी आ गयी है। 1971-72 के लिए 387 करोड़ रूपयों की राशि के घाटे का अनुमान लगाया गया है।

परिव्यय की प्रवृत्तियाँ

50. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कुल वितरणों (राजस्व और पूँजी) की वृद्धि-दर में 1970-71 @@ में संयुक्त रूप से 10 प्रतिशत की कमी हुई जब कि 1969-70 में उसमें 11.4 प्रतिशत की कमी हुई थी। 1971-72 के लिए यह अनुमान किया जाता है कि ऐसे वितरणों में 8 प्रतिशत की वृद्धि होगी (सारणी 9)। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त राजस्व व्यय में 1968-69 और 1969-70 में जहाँ क्रमशः 11 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ 1970-71 में उसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1971-72 के बजट अनुमानों में राजस्व व्यय में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त पूँजीगत वितरणों की राशि में 1970-71 में 10 प्रतिशत से थोड़ी कम वृद्धि हुई जब कि 1969-70 में उसमें 10 प्रतिशत से थोड़ी अधिक वृद्धि हुई थी। 1971-72 के लिए ऐसे वितरणों में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि होने की प्रत्याशा है जो पिछले दो वर्षों में हुई वृद्धियों से कम है।

51. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त विकास परिव्यय की राशि में (अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में अभिदान जैसे अनावर्ती व्यय की ऐसी विशेष मदों को छोड़कर जिनके लिए 1970-71 के परिशोधित बजट में व्यवस्था की गई) 1969-70 में हुई 18 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1970-71 में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1971-72 के संयुक्त विकास परिव्यय में 1970-71 में हुए ऐसे व्यय (विशेष मदों को छोड़कर) की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त विकास परिव्यय में 1969-70 में जहाँ (1968-69 की 14 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में) 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ 1970-71 में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई (अनावर्ती व्यय की विशेष मद अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षतिपूर्ति के लिए की गई उस व्यवस्था को छोड़कर जो 1970-71 के परिशोधित बजट में शामिल की गयी) 1971-72 के बजट में सम्मिलित किये गये विकास परिव्यय में 1970-71 की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि गयी (राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षतिपूर्ति के लिये की गयी व्यवस्था को छोड़कर)। यह अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 1971-72 के योजनागत परिव्यय की राशि 3024 करोड़ रूपयें होंगी अर्थात् 1970-71 (बजट) के लिए निर्धारित राशि से करीब 400 करोड़ रूपयें अधिक होंगी।

प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ*

52. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की 1970-71 की कुल प्राप्तियाँ (राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित क्षतिपूर्त बांडों और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि के कारण उत्पन्न कल्पित प्राप्तियों को छोड़कर) की वृद्धि दर 3 प्रतिशत थी जब कि 1969-70 में यह दर 15 प्रतिशत थी। 1971-72 के बजट के अनुसार कुल प्राप्तियों में 1970-71 की तुलना में (कल्पित प्राप्तियों को छोड़कर) लगभग 12 प्रतिशत वृद्धि होगी। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में, जहाँ 1969-70 में 11 प्रतिशत से थोड़ी सी अधिक वृद्धि हुई थी वहाँ 1970-71 में भी लगभग उतनी ही वृद्धि हुई परन्तु 1971-72 में राजस्व प्राप्तियों में 11 प्रतिशत अर्थात् पिछले दो वर्षों की वृद्धि दर से थोड़ी सी कम वृद्धि होने का अनुमान है। कर राजस्व की वृद्धि दर 1968-69 में लगभग 9 प्रतिशत थी, वह 1969-70 में बढ़कर लगभग 12 प्रतिशत हो गयी थी 1970-71 में भी वही दर जारी रही, किन्तु 1971-72 में कर राजस्व की वृद्धि-दर पिछले वर्ष की अपेक्षा आंशिक रूप से कम होगी। पण्यों और सेवाओं के करों से प्राप्त होनेवाले राजस्व में 1969-70 में हुई 12 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1970-71 में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस प्रकार कुल कर राजस्व में उसका अनुपात 1969-70 के 74.4 प्रतिशत से बढ़कर 1970-71 में 76.3 प्रतिशत हो गया। 1971-72 में इस स्त्रोत से मिलने वाले कर राजस्व में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है, कुल कर राजस्व में ऐसे करों से मिलनेवाले राजस्व का अंश 77 प्रतिशत होगा।

@यदि अन्यथा उल्लेख किया गया हो तो इस खण्ड में जीर्णोद्धार राशियाँ राजकांषीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से संबंधित हैं।

*इसमें केन्द्रीय सरकार के संवर्धन में बकाया खजाना बिलों और नकदी बकायों से किये गये आहरण और राज्य सरकारों के संवर्धन में नकदी बकायों से किये गये आहरण में हुई वृद्धि और राज्य सरकारों के नकदी बकाया निवेश लेखों में रखी गयी प्रतिभूतियों की वास्तविक विक्रियाँ और राज्यों की राजस्व आरीक्षित निधियों से किये गये वास्तविक अंतरण शामिल हैं।

* 5 अगस्त 1971 को लोकसभा में अनुदानों की जो पूरक मांगें पेश की गयीं उनमें पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को राहत प्रदान करने के संबंध में दिसम्बर 1971 के अंत तक की अवधि के लिए 200 करोड़ रूपयों के अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था की गयी है। उक्त मांगें इसमें शामिल नहीं हैं। चूंकि विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होनेवाले 50 करोड़ रूपयों की राशि को भी हिसाब में ले लिया गया है अतः शरणार्थियों के संवर्धन में केन्द्रीय सरकार बजट पर 150 करोड़ रूपयों का वास्तविक प्रभाव पड़ता है।

@ @यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो 1970-71 के संवर्धन में दिये हुए सभी आंकड़े परिशोधित अनुमान हैं।

सारणी 9—केंद्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और बिबरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1969-70 (लेखे)		1970-71 (बजट अनुमान) (क)	
	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
	1	2	3	4
I. कुल प्राप्तियाँ (अ+आ)	8179	+ 15.2	8229	+ 0.6
(अ) राजस्व प्राप्तियाँ	5392	+ 11.3	5813	+ 7.8-
उनमें से :				
कर प्राप्तियाँ	4182	+ 12.2	4564	+ 9.1
(आ) पूँजीगत प्राप्तियाँ	2787	+ 23.7	2416	- - 13.3
II. कुल बितरण	8216	+ 11.4	8590	+ 4.6
उनमें से:				
विकास परिषद (क+ख)	3140	+ 8.4	3620	+ 15.3
(क) राजस्व	2105	+ 11.9	2323	+ 10.4
(ख) पूँजीगत	1035	+ 2.0	1297	+ 25.3
विकासोत्तर परिषद (क+ख)	3279	+ 17.5	3328	+ 1.5
(क) राजस्व	3157	+ 12.0	3210	+ 1.7
(ख) पूँजीगत	122		118	- - 3.3
III. समग्र अधिशेष (+) या घाटा (—) (I—II)	—37(ख)		—361(ख)	

नोट: आंकड़े अन्तर सरकारी अन्तरणों के लिए समायोजित किये गये हैं और अतः वे बजट दस्तावेजों और सारणियों में दिये गये आंकड़ों से भिन्न हैं। परन्तु समग्र रूप से संयुक्त स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(क) बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के बकाया खजाना धिलों, तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के नकदी बकायों के आहरण में हुई वृद्धि, राज्य सरकारों के नकदी बकाया निवेश लेखों में रखी गयी प्रतिभूतियों की वास्तविक बिक्री और राज्यों की राजस्व आरक्षित निधियों से किये गये वास्तविक अन्तरण के आधार पर।

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1970-71 (परिशीलित अनुमान)		197-172 (बजट अनुमान) (क)	
	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
	5	6	7	8
I. कुल प्राप्तियाँ (अ+आ)	8579	+ 4.9	9436	+ 10.0
(अ) राजस्व प्राप्तियाँ	6004	+ 11.4	6666	+ 11.0
उनमें से:				
कर प्राप्तियाँ	4700	+ 12.4	5259	+ 11.9
(आ) पूँजीगत प्राप्तियाँ	2575	- - 7.6	2770	+ 7.6
II. कुल बितरण	9034	+ 10.0	9823	+ 8.7
उनमें से:				
विकास परिषद (क+ख)	3647	+ 16.1	4128	+ 13.2
(क) राजस्व	2417	+ 14.8	2741	+ 13.4
(ख) पूँजीगत	1230	+ 18.8	1387	+ 12.8
विकासोत्तर परिषद (क+ख)	3697	+ 12.7	3723	+ 0.7
(क) राजस्व	3377	+ 7.0	3574	+ 5.8
(ख) पूँजीगत	320	+ 162.3	149	- - 53.4
III. समग्र अधिशेष (+) या घाटा (—) (I—II)	—455(ख)		—387(ख) (ग)	

(ग) पूर्व बंगाल के शरणार्थियों को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में अनुदानों की पूरक मांगों में 150 करोड़ रुपयों के वास्तविक व्यय की व्यवस्था की गयी है। बजट स्थिति पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर यहाँ विचार नहीं किया गया है।

1970-71 के बजट में घाटा

53. केन्द्रीय सरकार के समग्र घाटे की राशि 1970-71 में 230 करोड़ रुपये थी जो मूलतः परीक्षीय राशि (227 करोड़ रुपये)* से सामान्य रूप से अधिक थी। राज्य सरकारों के मामले में परीक्षीय अनुमानों के अनुसार 1970-71 के समग्र घाटे की राशि 225 करोड़ रुपये थी जो बजट अनुमान से 91 करोड़ रुपये अधिक थी। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 1970-71 के वास्तविक समग्र घाटे की राशि अभी ज्ञात नहीं हुई है। परन्तु रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र को दिये गये ऋणों के परिणाम से संभाव्य घाटे का अनुमान लगाया जा सकता है; रिजर्व बैंक से सरकारी क्षेत्र को प्राप्त ऋणों की राशि में जहाँ 1969-70 के राजकोषीय वर्ष में 13 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। थी वहाँ 1970-71 के राजकोषीय वर्ष में 332 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक से दिये गये वास्तविक ऋणों की राशि में 1969-70 में जहाँ 81 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी वहाँ 1970-71 में 107 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। राज्य सरकारों के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिये गये वास्तविक ऋणों की राशि में 225 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जब कि 1969-70 में उस में 68 करोड़ रुपये की कमी हुई थी।

54. वर्तमान राजकोषीय वर्ष में अब तक की अवधि में (1 अप्रैल से 25 जून 1971 तक) रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र को दिये गये ऋणों की वास्तविक राशि में 468.0 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जब कि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में उक्त राशि में 65.5 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिये गये ऋणों की राशि में 375.2 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है (जब कि 1970 की उसी अवधि में 56.1 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी)। और राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों की राशि में 92.8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई (जब कि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 9.4 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी)।

राज्य सरकारों द्वारा लिये गये आवरड्राफ्ट

55. पिछले कुछ वर्षों से कीतपय राज्य सरकारें रिजर्व बैंक से बराबर आवरड्राफ्ट लेती रही हैं। 11 राज्य सरकारों के कुल वकाला आवरड्राफ्टों की राशि (28 जून 1971 को) 371.29 करोड़ रुपये थी जब कि 27 जून, 1970 को 82.74 करोड़ रुपये (8 राज्यों के मामले में) थी। सारणी 10 में सभी राज्यों की 1965-66 से लेकर 1970-71 तक की समग्र बजट स्थिति दिखायी है। उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से राज्य सरकारों द्वारा लिये गये आवरड्राफ्टों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में विद्यमान स्थिति और राजस्व और पूंजीगत लेखों पर संयुक्त रूप से किये गये कुल वितरण के विवरण दिये गये हैं। उक्त श्रेणी से पता चलता है कि पिछले 5 या 6 वर्षों में राज्य सरकारों के समग्र घाटे तथा उनके वितरणों की राशि बजट अनुमानों की अपेक्षा परीक्षीय अनुमानों में बहुत बढ़ गयी है। कुछ राज्य सरकारों के आवरड्राफ्टों के वास्तविक कारण अभी स्पष्ट मालूम नहीं हुए हैं। फिर भी, वितरणों की प्रवृत्तियों और बजट अनुमान तथा परीक्षीय अनुमानों के बीच उनमें हुई घट-बढ़ का अध्ययन करना उपयोगी सिद्ध होगा।

* केन्द्रीय वित्त मंत्री ने यह संकेत दिया है कि 1970-71 में केन्द्रीय सरकार के समग्र घाटे की राशि 270 करोड़ रुपये होगी।

56. 1970-71 के कुल वितरणों में से योजनागत और योजनांतर मदों के लिये किये गये वितरणों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध हैं। उन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बजट अनुमानों की तुलना में परीक्षीय अनुमानों में कुल वितरणों की राशि में वृद्धि हुई है, यह वृद्धि योजनागत और योजनांतर दोनों व्ययों में हुई है और योजनांतर व्यय में हुई वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक रही है। 1970-71 में जहाँ बजट अनुमानों के घाटे की अपेक्षा परीक्षीय अनुमानों के घाटे में 320.4 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई देती है वहाँ योजनागत व्यय में 104.6 करोड़ रुपये और योजनांतर व्यय में 295.0 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है (सारणी 11)। (10 राज्यों के) आवरड्राफ्टों की राशि मार्च 1971 के अन्त में 268.2 करोड़ रुपये थी।

57. राज्य सरकारें रिजर्व बैंक से लिये गये अपने आवरड्राफ्टों की अदायगी करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार से अल्पावधि तदर्थ ऋण लेती आ रही हैं। 1965-66 से 1968-69 तक की अवधि में लिये गये ऐसे संचय ऋणों की राशि 378 करोड़ रुपये थी। योजनांतर व्यय के संदर्भ में समग्र रूप से कुछ राज्यों को धन की कमी का जो सामना करना पड़ता है उसे दूर करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 1969-70 से विशेष वित्त-पोषण की एक योजना प्रारम्भ की है। इस उद्देश्य के लिए 1969-70 में 279 करोड़ रुपये, 1970-71 में 195 करोड़ रुपये (परीक्षीय अनुमान) और 1971-72 में 120 करोड़ रुपये (बजट अनुमान की व्यवस्था की गयी)।

58. इन आवरड्राफ्टों की समस्या की ओर रिजर्व बैंक बराबर ध्यान देता आ रहा है। पांचवें वित्त आयोग (1968) ने कीतपय राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये गये अनधिकृत आवरड्राफ्टों की समस्या का अध्ययन कर उन्हें समाप्त करने और ऐसे आवरड्राफ्टों के संबंध में कार्रवाई करने की प्रणाली के बारे में सिफारिशें की हैं, केन्द्रीय सरकार ने उक्त सिफारिशों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है।

1971-72 की समग्र स्थिति

59. कराधान की वर्तमान वृत्ति के अनुसार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 1971-72 के समग्र घाटे की अनुमानित राशि क्रमशः 397 करोड़ रुपये और 240 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित अतिरिक्त करों को हिसाब में लिया जाए तो केन्द्रीय सरकार के 1971-72 के घाटे की राशि कम होकर 233 करोड़ रुपये** रह जायेगी जबकि उक्त राशि 1970-71 में 230 करोड़ रुपये थी। यह आशा की जाती है कि राज्यों द्वारा जुटाए गये अतिरिक्त वित्त केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कराधान में राज्यों के हिस्सों और केन्द्रीय सरकारों से राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाले अंतरणों की वास्तविक अतिरिक्त राशि को हिसाब में लेने पर राज्य सरकारों के पास इस वर्ष के अन्त में 39 करोड़ रुपये का अधिशेष रह जायेगा जबकि 1970-71 में 225 करोड़ रुपये का घाटा था। कुछ राज्य सरकारें रिजर्व बैंक से आवरड्राफ्ट लेने लग गई हैं। 13 अगस्त, 1971 को वकाला आवरड्राफ्टों (8 राज्यों के संदर्भ में) की राशि 108.0 करोड़ रुपये थी जब कि 14 अगस्त 1970 को उक्त राशि (6 राज्यों के संदर्भ में) 52.5 करोड़ रुपये थी।

** पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के राहत प्रदान करने के संबंध में अनुदानों की पूरक मांगों में 150 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय की व्यवस्था की गयी है। बजट स्थिति पर पड़नेवाले उसके प्रभाव पर यहां विचार नहीं किया गया है।

इनमें राज्य सरकारों को दिये जानेवाले 100 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान शामिल हैं जिनकी व्यवस्था 1971-72 के लिए प्रस्तुत अनुदानों की पूरक मांगों में पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के कारण होनेवाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए की गयी।

सारणी 10—1965-66 से 1970-71 तक की अवधि में राज्य सरकारों की समग्र बजट स्थिति,

कुल वितरण और रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिये गये ओवरड्राफ्ट

(करोड़ रुपये)

	समग्र घाटा (—)/ अधिशेष (+)	राजस्व और पूँजीगत लेखे पर कुल संयुक्त वितरण**	बजट अनुमानों की तुलना में परि- शोधित अनुमानों में समग्र घाटे में हुई घट-बढ़ [वृद्धि (+) कमी (—)]	बजट अनुमानों की तुलना में परि- शोधित अनुमानों में कुल वितरणों में हुई घट-बढ़ [वृद्धि (+) कमी (—)]	रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिये गये ओवरड्राफ्ट 31 मार्च की स्थिति
	1	2	3	4	5
1965-66 (बजट अनुमान)*	—45.6	2965.3			
(परिशोधित अनुमान)	—188.9	3269.7	+ 143.3	+ 304.4	120.2
(लेखे)	—66.8	3216.5			
1966-67 (बजट अनुमान)*	+ 170.6	3204.1			
(परिशोधित अनुमान)	—76.2	3431.0	+ 246.8	+ 226.9	15.8
(लेखे)	—6.5	3339.7			
1967-68 (बजट अनुमान)*	—49.7	3784.5			
(परिशोधित अनुमान)	—102.6	3882.1	+ 52.9	+ 97.6	31.5
(लेखे)	—38.2	3835.6			
1968-69 (बजट अनुमान)*	+ 138.2	3847.9			
(परिशोधित अनुमान)	—152.7	4314.2	+ 290.7	+ 466.3	144.7
(लेखे)	—11.8	4461.5			
1969-70 (बजट अनुमान)*	—88.9	4797.3			
(परिशोधित अनुमान)	—145.8	4935.1	+ 56.9	+ 137.8	91.7
(लेखे)	+ 8.9	4907.6			
1970-71 (बजट अनुमान)*	+ 95.7 ^(a)	5033.3 ^(a)			
(परिशोधित अनुमान)	—224.7 ^(a)	5432.9 ^(a)	+ 320.4	+ 399.6	268.2

** प्रेषणों (वास्तविक) को छोड़कर ।

* इसमें राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों से प्राप्त आय और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अन्तरित किये जाने वाले वित्तीय स्रोतों अर्थात् केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से, सहायक अनुदान और वास्तविक ऋण में हुई वृद्धि शामिल है । उक्त वृद्धि राज्य सरकारों के बजट अनुमानों की अपेक्षा परिशोधित अनुमानों में हुई वृद्धि की छोटक है ।

(a) हिमाचलप्रदेश को छोड़कर, क्योंकि उस राज्य के परिशोधित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

सारणी 11—1970-71 और 1971-72 के दौरान राज्य सरकारों की समग्र बजट स्थिति और कुल वितरण

(करोड़ रुपये)

	1970-71		1971-72	
	बजट अनुमान	परिशोधित अनुमान	बजट अनुमानों की तुलना में परिशोधित अनुमानों में घट-बढ़ स्तम्भ (1) की तुलना में स्तम्भ (2) [वृद्धि (+) कमी (--)]	बजट अनुमान
	1	2	3	4
सभी राज्यों का समग्र अधिशेष (+) या घाटा (—)	+ 95.7 @†	—224.7†	+ 320.4	—153.8‡
31 मार्च, 1971 को उन राज्यों का समग्र अधिशेष (+) या घाटा (—)	+ 66.7 @	—169.6	+ 236.3	
जिन्होंने ओवर ड्राफ्ट लिये हैं				
सभी राज्यों के कुल वितरण* (क+ख)	5033.3† (100.0)	5432.9† (100.0)	+ 399.6	5700.1 (100.0)
(क) योजनागत	1142.2 (22.7)	1246.8 (22.9)	+ 104.6	1489.3 (26.1)
(ख) योजनाेतर	3891.1 (77.3)	4186.1 (77.1)	+ 295.0	4210.8 (73.9)
उन राज्यों के कुल वितरण* जिनके 31 मार्च, 1971 को ओवर- ड्राफ्ट थे (क+ख)	3095.5 (100.0)	3371.2 (100.0)	+ 275.7	
(क) योजनागत	655.3 (21.2)	748.1 (22.2)	+ 92.8	
(ख) योजनाेतर	2440.2 (78.8)	2623.1 (77.8)	+ 182.9	

नोट: 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल वितरणों के प्रतिशत हैं।

2. योजनागत व्यय में राज्यों की योजनाओं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं पर किया गया व्यय शामिल है।

3. गुजरात राज्य ने केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के व्यय को योजनाेतर व्यय माना है। आंकड़े प्रस्तुत करने में समानता लाने की दृष्टि से इसे योजनागत परिच्यय मान लिया गया है।

@ इसमें राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों से प्राप्त आय और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अन्तरित किये जाने वाले वित्तीय स्रोतों अर्थात् केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से, सहायक अनुदान और वास्तविक ऋण में हुई वृद्धि शामिल है; उक्त वृद्धि राज्य सरकारों के बजट अनुमानों की अपेक्षा परिशोधित अनुमानों में हुई वृद्धि की ओर है।

‡ राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों से प्राप्त होने वाली राशि (45.3 करोड़ रुपये) और केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कराधान में राज्य सरकारों के हिस्से की राशि (लगभग 41 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

† हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, क्योंकि इस राज्य के परिशोधित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

* यह राजस्व और पूंजीगत लेखों पर संयुक्त रूप से किये गये कुल वितरणों से सम्बन्धित है परन्तु इसमें प्रेषण (वास्तविक) शामिल नहीं है।

सारणी 12—केंद्रीय सरकार की समग्र बजट स्थिति

	(करोड़ रुपये)			
	1969-70 (लेखे)	1970-71 (बजट अनुमान)	1970-71 (परिशोधित अनुमान)	1971-72 (बजट अनुमान)
	1	2	3	4
I कुल प्राप्तियाँ (ग्र + ग्रा)	5677	5573	5923	6080 (6244)
(ग्र) राजस्व प्राप्तियाँ	3027	3341	3340	3503 (3667)
उनमें से :				
कर राजस्व	2201	2390	2442	2553 (2717)
(ग्रा) पूँजीगत प्राप्तियाँ	2640	2332	2583	2577
उनमें से :				
देशी बाजार ऋण (कुल)	536	455	427	500
विदेशी ऋण* (कुल)	633	719	681	666
II कुल बितरण	5713	5800	6153	6477
उनमें से :				
(क) विकास परियोजनाएँ	889	1152	1047	1178
(ख) विकासेतर परियोजनाएँ	2073	2158	2435	2409
(ग) देशी ऋणों का भुगतान	393	291	291	332
(घ) विदेशी ऋणों का भुगतान	179	200	196	216
III समग्र घाटा (I—II)	(—46)	(—) 227	(—) 230	(—) 397 [(—) 233**])

नोट : (1) कोष्ठकों के आंकड़े अतिरिक्त कर संबंधी उपायों से अनुमानित प्राप्त होने वाली राशि की हिसाब में लेने के बाद निकाले गये हैं।

(2) यहाँ के आंकड़े बजट वस्तावेजों के आंकड़ों से मेल नहीं खाते क्योंकि कतिपय समायोजन कर दिये गये हैं।

* पी०एल० 480 ऋणों को मिलाकर

** इसमें पूर्व बंगाल के जरणार्थियों को राहत प्रदान करने के निमित्त अनुदानों (150 करोड़ रुपये) के लिए की गयी पूरक मांगों का प्रभाव शामिल नहीं है।

1971-72 के लिए केंद्रीय सरकार का बजट

60. आर्थिक स्थिति की सामान्य रूप से सुधरी हुई संभावनाओं और लगातार चारों वर्षों में केंद्रीय सरकार के योजनागत परियोजनाओं में हुई कमियों के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय सरकार का 1971-72 का बजट बनाया गया। वित्त मंत्री ने योजनागत प्रायोजनाओं का समय पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे आर्थिक कार्यकलाप को अधिक गतिशील बनाया जा सके और उसके जरिये नियोजन के क्षेत्र को अधिक विकसित किया जा सके। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के योजनागत परियोजनाओं में 1970-71 के बजट की अपेक्षा 13 प्रतिशत की वृद्धि करने के अलावा केंद्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन के अवसर प्रदान करनेवाले कार्यों के लिए (50 करोड़ रुपये) और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए नियोजन के अवसर प्रदान करने के निमित्त (25 करोड़ रुपये) 75 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

61. यह अनुमान लगाया गया है कि केंद्रीय सरकार का राजस्व और पूँजीगत लेखों पर 1971-72 में (अतिरिक्त कर उपायों से प्राप्त होनेवाली राशि को मिलाकर) 6,244 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, उक्त राशि 1970-71 की तुलना में 5.4 प्रतिशत अधिक है (सारणी 12)। कर संबंधी नये उपायों से प्राप्त होनेवाली राशि सहित कर राजस्वों से यह पता चलता है कि 1970-71 की तुलना में उनमें 11.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 1970-71 की अपेक्षा इस वर्ष के बजट में देशी बाजार से लिये जानेवाले वास्तविक उधारों और अल्प बचतों की अधिक राशि की व्यवस्था की गयी है जहाँ इस वर्ष के बजट में निर्धारित वास्तविक विदेशी ऋणों की राशि 1964-65 से लेकर अब तक के किसी भी वर्ष की तुलना में कम होगी। कुल वितरणों की 6,477 करोड़ रुपयों की राशि 1970-71 की अपेक्षा 5.3 प्रतिशत (324 करोड़ रुपये) अधिक है। वृद्धि पूर्णतः राजस्व

व्यय के अंतर्गत हुई है, उक्त व्यय की 3,527 करोड़ रुपयों की राशि 1970-71 की अंश 385 करोड़ रुपये अधिक है, पूर्व बंगाल के शरणार्थियों की राहत के लिए की गयी 'अस्थायी' व्यवस्था के कारण 60 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है*। राजस्व व्यय में हुई वृद्धि के एक अंश का पूंजीगत वितरणों में 61 करोड़ रुपयों की कटौती कर समायोजित किया जाएगा। चूंकि कुल प्राप्तियों और वितरणों में उतनी वृद्धि होने की आशा की जाती है अतः 233 करोड़ रुपयों की समग्र घाटे की राशि 1970-71 के समग्र घाटे की राशि (230 करोड़ रुपये) से केवल थोड़ी सी अधिक है। समग्र घाटे को मात्रा कुल वितरणों का 3.6 प्रतिशत होगी, जबकि 1970-71 में यह मात्रा 3.7 प्रतिशत थी।

योजनागत परिव्यय

62. 1971-72 में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के योजनागत परिव्यय की अनुमानित राशि 3024 करोड़ रुपये हैं; यह राशि 1970-71 में की गयी तदनुसूची व्यवस्था से 400 करोड़ रुपये और 1970-71 के संभाव्य योजनागत व्यय की राशि से 600 करोड़ रुपये अधिक है। केन्द्रीय सरकार के बजट में योजनागत परिव्यय के लिए 2135 करोड़ रुपयों की राशि की व्यवस्था की गयी है जो 1970-71 (बजट अनुमानों) की तुलना में 229 करोड़ रुपयों (12 प्रतिशत की) वृद्धि की शक्ति है। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि बजट में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए की गयी वित्त व्यवस्था में 155 करोड़ रुपयों की वृद्धि की गयी (कुल 1350 करोड़ रुपये) और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों की योजनाओं को दी जानेवाली सहायता में 67 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी। यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो कृषि और तत्संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित केन्द्रीय सरकार की योजना के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था में 1970-71 के बजट में की गयी तदनुसूची व्यवस्था के मुकाबले में 60 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है। 'परिवहन संचार' के अधीन बजट में की गयी व्यवस्था में भी लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है। उद्योग के संदर्भ में सामान्य वृद्धि हुई है; कायले और पेट्रोलियम स्तयनों के लिए की गयी व्यवस्था में जहाज वृद्धि की गयी है वहां उर्वरकों के लिए कम व्यवस्था की गयी है।

केन्द्रीय सरकार के कर संबंधी उपाय

63. 1971-72 के बजट में कर संबंधी नये प्रस्ताव किये गये जिनका अन्य बातों के साथ यह उद्देश्य था कि कर की अलायगी से बचने के मौके कम किए जायें और आय तथा संपत्ति की असमानताओं को कम किया जाए। यह अनुमान है कि अतिरिक्त कराधान के प्रस्तावों से 1971-72 में 205 करोड़ रुपयों (राज्य सरकारों के 41 करोड़ रुपयों के अंशदान को मिलाकर) की राशि प्राप्त होगी। इनके अलावा डाक संबंधी शुल्क दरों में परिवर्तन किये जाने के कारण जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा उसके संबंध

* चूंकि शरणार्थियों की राहत प्रदान करने के संदर्भ में राजस्व लेखों में 'फिलहाल' विदेशी सहायता के 20 करोड़ रुपयों के हिसाब में लिया गया है अतः इस संदर्भ में बजट व्यवस्था की राशि 40 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा, अनुदानों की पूरक मांगों में पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के राहत प्रदान करने के लिए दिसंबर 1971 के अंत तक की अवधि के लिए 200 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है। उन में विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त 50 करोड़ रुपयों की राशि भी हिसाब में ली गयी है। इस प्रकार बजट के अनुसार इस उद्देश्य के लिए होनेवाले वास्तविक व्यय की राशि 150 करोड़ रुपये होगी।

में यह अनुमान है कि पूरे वर्ष में 10.8 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और रेलवे द्वारा माल भाड़े की दरों और यात्री-किरायों में वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि 1971-72 में 26 करोड़ रुपये (पूरे वर्ष में 35 करोड़ रुपये) प्राप्त होंगे, परंतु यह राशि केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं होगी।

64. 1971-72 में प्राप्त होनेवाले कुल अनुमानित अतिरिक्त राजस्व में से पण्यों और सेवाओं के करों (विदेशी यात्रा के कर को मिलाकर) से प्राप्त होनेवाली राशि 86.8 प्रतिशत होगी। उप-भोक्ता वस्तुओं तथा उत्पादक वस्तुओं को मिलाकर कुल ऐसी 24 नयी वस्तुएं हैं जिन पर पहली बार **वथामूल्य** दरों पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है। आयात शुल्क की दर के स्वरूप को आयात शुल्क की सात दरों के स्थान पर चार **वथामूल्य** दरें निर्धारित कर सरल बना दिया गया है। यदि आय-राशि 15,000 रुपयों से अधिक हो जाय तो व्यक्तिगत आय कर पर लिये जानेवाले औधभार की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। 15 लाख रुपयों से अधिक की वास्तविक संपत्ति पर लगाये जानेवाले कर की दर को बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है जब कि फिलहाल 15 और 20 लाख रुपयों के बीच की और 20 लाख रुपयों से अधिक की वास्तविक संपत्ति के वर्गों के लिए क्रमशः 4 और 5 प्रतिशत की दरों पर कर लिया जाता है। कंपनी के लाभों पर लिये जानेवाले अतिरिक्त की दर में कोई परिवर्तन किये बिना उसे पूंजी के 15 प्रतिशत तक के लाभों के लिए 25 प्रतिशत ही रखा गया है। किन्तु यदि लाभ इस सीमा से अधिक हों तो कर की दर को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। दीर्घावधि पूंजीगत लाभों पर लिये जानेवाले कर को भी बढ़ाया गया है।

65. 31 मार्च 1954 के बाद स्थापित किये गये संयंत्रों या मशीनों में किये गये नये निवेशों या खरीदे गये नये जहाजों के संबंध में 1955-56 में विकास छूट की व्यवस्था की गयी। 31 मई, 1974 के पश्चात् खरीदे जानेवाले जहाजों या स्थापित की जानेवाली मशीनों या संयंत्रों के संबंध में कोई विकास छूट नहीं दी जायेगी। प्राथमिकतावाले उद्योगों की सूची में से कतिपय उद्योगों को हटाकर उस सूची में कमी कर दी गयी है और प्राथमिकतावाले उद्योगों के लाभों के संबंध में दी जानेवाली कर संबंधी विशेष छूट की मात्रा को कम कर दिया गया है। 'कर भुक्ता' की व्यवस्थाओं के अधीन कर मुक्त लाभों का हिसाब लगाने के लिए डिग्रेडरों और दीर्घावधि ऋणों के 'उपयोग में लायी गयी पूंजी' की सूची से हटा दिया जायेगा। अनुमान लगाया जाता है कि इन उपायों से पूरे वर्ष में 22 करोड़ रुपयों की आय प्राप्त होगी। व्यक्तिगत दत्तों के दी जानेवाली रियायतों के संदर्भ में जीवन बीमा किश्तों भविष्य निधि के अंशदानों आदि के माध्यम से की जानेवाली बचतों, जिन्हें कर योग्य आय से हटा दिया जाता है, की उच्चतम सीमा को अलग-अलग व्यक्तियों के मामले में 15,000 रुपयों से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है और इस संदर्भ में कर-राहत का हिसाब लगाने की प्रणाली में कुछ संशोधन किये गये हैं। विशिष्ट वित्तीय आस्तियों से प्राप्त होनेवाली 3,000 रुपयों तक की आय को जो छूट दी गयी है उसे सहकारी समितियों में सदस्यों द्वारा रखी गयी जमा-राशियों पर मिलने वाले ब्याज के लिए भी लागू किया जाएगा; यह छूट अब अलग अलग व्यक्तियों और औपभक्त हिन्दू परिवारों तक ही सीमित रहेगी। जिनके पास मोटोर्गाइया हैं उनको छोड़कर अन्य कर्वाताओं के मामले में की जानेवाली मानक कटौतियों में भी वृद्धि की गयी है।

1971-72 के लिए राज्य सरकारों के बजट

66. राज्य सरकारों ने 1971-72 के लिए बजट में राजस्व (कराधान की 1970-71 की दरों के अनुसार) और पूंजीगत लेखों के

अंतर्गत 5464 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों की व्यवस्था की है जो 1970-71 की तुलना में 4.9 प्रतिशत (256 करोड़ रुपये) अधिक है (सारणी 13)। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्यों के अपने ही कर राजस्वों में 6.8 की वृद्धि होगी और उनकी राशि 1971-72 में बढ़कर 1607 करोड़ रुपये होगी। 1971-72 के लिए कुल वितरणों की राशि 5704 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है जो 1970-71 की तुलना में 5.0 प्रतिशत (271 करोड़ रुपये) अधिक होगी वितरणों के लिए निर्धारित राशि में हुई वृद्धि मुख्यतः विकास व्यय के लिए अधिक मात्रा में की गयी व्यवस्था के कारण हुई। विकास व्यय के लिए 2950 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी जो 1970-71 की तुलना में 13.5 प्रतिशत अधिक है और 1971-72 के कुल वितरणों की राशि के आधे अंश से थोड़ी अधिक है जब कि 1970-71 में उसकी मात्रा 47.9 प्रतिशत थी। विकासोत्तर व्यय के लिए बजट में व्यवस्था की गयी राशि (1632 करोड़ रुपये) में 1970-71 की तुलना में 67 करोड़ रुपये की वृद्धि परिलक्षित होती है और अन्य वितरणों, जिनमें मुख्यतः राज्यों द्वारा प्रदान किये गये ऋण और अग्रिम, केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों, बाजार ऋणों की वापसी अदायगी शामिल है, की राशि में 1970-71 के स्तर से 11 प्रतिशत से अधिक कमी होने की आशा की जाती है।

67. 1971-72 में यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारों के बजट संबंधी लेन-देनों में (नये वित्तीय खातों के प्रस्तावों से प्राप्त होनेवाली राशि को हिसाब में न लेनेपर) अंत में 240 करोड़ रुपये का समग्र घाटा होगा; यह घाटा पूंजीगत लेखों के 287 करोड़ रुपये के घाटे और राजस्व लेखों के 27 करोड़ रुपये के अधिशेष का वास्तविक परिणाम है। कोतपय राज्य सरकारों ने अतिरिक्त वित्त जुटाने के जो प्रस्ताव किये हैं उनसे 45 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सरकार के नये करों में से राज्य सरकारों को उनके हिस्से की राशि के रूप में 41 करोड़ रुपये के मिलने की जो आशा की जाती है उससे समग्र घाटे की राशि कम हो कर 154 करोड़ रुपये रह जाती है। इसके अलावा राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होनेवाली वास्तविक अतिरिक्त राशि (193 करोड़ रुपये*) के लिए समाधान किया जाये तो राज्य सरकारों के पास 39 करोड़ रुपये ** का अधिशेष रहेगा जब कि 1970-71 में 225 करोड़ रुपये का समग्र घाटा हुआ था।

68. सात राज्य सरकारों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, नागालैंड और उड़ीसा ने अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के उपाय प्रस्तावित किये हैं, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु ने भी ऐसे उपाय प्रस्तावित किये हैं और उन राज्यों ने राजकोषीय खियायतों भी प्रदान की हैं। कुल मिलाकर इन अतिरिक्त उपायों से (प्रशासन व्यवस्था तथा बकाया राशियों की वसूली के सरल बनाने के लिए किये गये उपायों के भित्ताकर)

* राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के बजट की तुलना में अपने बजटों में अनुदानों और वास्तविक ऋणों के संबंध में अपेक्षाकृत थोड़ी सी राशि और करों में अपने हिस्से के संबंध में थोड़ी अधिक राशि की व्यवस्था की है। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वास्तविक अतिरिक्त राशि में राज्य सरकारों को दिये सहायता अनुदानों की 100 करोड़ रुपये की बहु राशि भी शामिल है जिसकी व्यवस्था पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के कारण होनेवाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के निमित्त 1971-72 के लिए अनुदानों की एक मांग में की गयी है।

** यदि बिहार और महाराष्ट्र द्वारा जारी किये गये उन बाजार ऋणों (27 करोड़ रुपये) से प्राप्त होनेवाली वास्तविक राशि को, जिनके उनके बजटों में सम्मिलित नहीं किया गया है, हिसाब में लिया जाए, तो 1971-72 की स्थिति और सुधार हो सकता है।

1971-72 में 45.3 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की आशा है परन्तु हरियाणा ने कर संबंधी केवल सामान्य खियायत की घोषणा की है, किन्तु उससे कर राजस्व में होनेवाली हानि नगण्य है।

बाजार ऋण

69. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 1970-71 में लिये गये बाजार ऋणों से प्राप्त वास्तविक राशि संयुक्त रूप से 235 करोड़ रुपये थी, जो 1969-70 की राशि की अपेक्षा 11 करोड़ रुपये अधिक थी। राज्य सरकारों द्वारा 1970-71 में लिये गये ऋणों की वास्तविक राशि 1969-70 की अपेक्षा 17 करोड़ रुपये अधिक थी जब कि केन्द्रीय सरकार के मामले में उक्त राशि 1969-70 की अपेक्षा 8 करोड़ रुपये कम थी।

7. पहले की तरह केन्द्रीय सरकार के 1970-71 का ऋण कार्यक्रम दो चरणों में समाप्त किया गया। कुल 275 करोड़ रुपये के लिये 11 अप्रैल, 1970 को जारी किये गये 5½ प्रतिशत 2000 ऋण के संबंध में किये गये कुल अभिदानों की राशि 290 करोड़ रुपये थी। उक्त राशि में नकदी के रूप में प्राप्त 150 करोड़ रुपये और अवधि-पूर्ण ऋणों का नये ऋणों के रूप में परिवर्तित करने के द्वारा प्राप्त 140 करोड़ रुपये शामिल हैं। 125 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिये 15 अक्टूबर 1970 को जारी किये गये 4.1/2 प्रतिशत ऋण 1977 और 5.1/2 प्रतिशत ऋण 2000 (पुनर्निर्गम) के संदर्भ में कुल 138 करोड़ रुपये (76 करोड़ रुपये नकदी में और 62 करोड़ रुपये अवधिपूर्ण ऋणों के परिवर्तन के द्वारा) प्राप्त हुए। अवधि-पूर्ण ऋणों की कुल 293 करोड़ रुपये की राशि में से परिवर्तन के लिए प्रस्तुत की गयी राशि 202 करोड़ रुपये थी। जिन ऋणों की अवधि समाप्त हो गई थी, पर जिन्हें परिवर्तन के लिए पेश नहीं किया गया था, उनके संबंध में नकदी अदायगी (91 करोड़ रुपये) की व्यवस्था करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार से लिये गये ऋणों की कुल राशि 1970-71 में 135 करोड़ रुपये थी जो मूलतः बजट में व्यवस्था की गयी राशि (162 करोड़ रुपये) से 27 करोड़ रुपये कम थी।

71. 1971-72 के केन्द्रीय सरकार के बजट में बाजार ऋणों से 500 करोड़ रुपये (कुल) प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋण कार्यक्रम का पहला चरण 1 जुलाई 1971 को समाप्त हुआ जब 375 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए तीन ऋण जारी किए गए; उनमें किये गये अभिदानों की कुल राशि 405 करोड़ रुपये (298 करोड़ रुपये अवधिपूर्ण ऋणों के परिवर्तन के रूप में और 107 करोड़ रुपये नकदी में) थी।

72. 15 जुलाई, 1970 को 15 राज्य सरकारों ने 142.50 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए 5½ प्रतिशत विकास ऋण जारी किए उन ऋणों की अवधि 12 वर्षों के बाद समाप्त होगी। सभी ऋण सममूल्य पर जारी किए गए। 12 राज्यों के कुल 57 करोड़ रुपये के जिन ऋणों की अवधि समाप्त हुई थी उन्हें उन राज्यों के संबंधित ऋणों में परिवर्तन के लिए पेश किया गया। सभी ऋणों में पिछले वर्ष की तरह अधिक अभिदान किया गया। अधिक अभिदान की राशि अधिसूचित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक थी। अतः आंशिक रूप से ऋण-राशि स्वीकार की गयी, इस प्रकार स्वीकृत अभिदानों की राशि 157 करोड़ रुपये थी। उक्त राशि में से 125 करोड़ रुपये नकदी अभिदानों के रूप में और 22 करोड़ रुपये अवधि पूर्ण ऋणों के परिवर्तन के द्वारा प्राप्त हुए। परन्तु, जिन ऋणों की अवधि समाप्त हो चुकी थी, किन्तु जिन्हें नये ऋणों में परिवर्तन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया उनके लिए नकदी अदायगी की (25 करोड़ रुपये) व्यवस्था करने के पश्चात् वास्तविक उधारों की राशि 1970-71 में 100 करोड़ रुपये थी जब कि 1969-70 में उक्त राशि 83 करोड़ रुपये थी।

सारणी 13—राज्यों की समग्र बजट स्थिति

	(करोड़ रुपये)			
	1969-70 (लेखे)	1970-71 (बजट अनुमान) +	1970-71 (परिशोधित) अनुमान	1971-72 (बजट अनुमान)*
	(1)	(2)	(3)	(4)
I. कुल प्राप्तियां (अ + आ)	4957	4918	5208	5464 (5550)
(अ) राजस्व प्राप्तियां (i + ii)	3172	3430	3535	3916 (3992)
(i) राज्यों की निजी राजस्व प्राप्तियां	2015	2144	2216	2381 (2416)
उनमें से:				
कर प्राप्तियां	1356	1446	1507	1607 (1641)
(ii) केन्द्रीय सरकार से अंतरित किये गये वित्तीय साधन (क + ख)	1157	1286	1319	1535 (1576)
(क) करों का हिस्सा	625	728	751	860 (901)
(ख) केन्द्रीय सरकार से अनुदान	532	558	568	675
(आ) पूंजीगत प्राप्तियां (i + ii)	1785	1488	1673	1548 (1558)
(i) राज्य सरकारों की निजी पूंजीगत प्राप्तियां	755	694	651	745 (755)
उनमें से:				
बाजार ऋण (कुल)	173	152@	157	152@
(ii) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण (कुल)	1030	794	1022	803
II. कुल वितरण	4948	5025	5433	5704
उनमें से :				
(क) विकास परियोजनाएँ	2251	2468	2600	2950
(ख) विकासोत्तर परियोजनाएँ	1481	1470	1565	1632
(ग) केन्द्रीय सरकार के ऋणों का भुगतान	608	610	659	562
(घ) अन्य पार्टियों को ऋण और भुगतान	432	394	497	436
(ङ) बाजार ऋणों का भुगतान	85	62	63	75
III. समग्र अधिशेष (+) या घाटा (-) (i-ii)	+ 9	-134	-225	-240 (-154)

नोट: यहां दिये गये आंकड़े बजट वस्तुवर्गों में दिये गये आंकड़ों से मेल नहीं खाते; क्योंकि यहां कृषिपय समायोजन किये गये हैं।
इसमें बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है।

*कोष्ठकों के आंकड़े बजट-प्रस्तावों से अनुमानित प्राप्त होनेवाली राशि को हिसाब में लेने के बाद निकाले गये हैं।

@बिहार और महाराष्ट्र द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों से प्राप्त होनेवाली राशियां (27 करोड़ रुपये) इसमें शामिल नहीं हैं।

अल्प बचतों से प्राप्त राशियाँ

73. अल्प बचतों से 1970-71 में 188 करोड़ रूपयों की वास्तविक राशि प्राप्त होने की आशा है जब की 1969-70 में 129 करोड़ रूपयों की राशि प्राप्त हुई थी। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार कुल (वास्तविक) प्राप्त राशियाँ 1970-71 के परिशोधित अनुमानों से 43 करोड़ रूपयें अधिक थीं। 188 करोड़ रूपयों की जो कुल वास्तविक राशि प्राप्त हुई उसकी दो तिहाई से थोड़ी सी कम राशि (लगभग 65 प्रतिशत) बचत के दो नये माध्यमों अर्थात् डाकघर सावधि जमा योजना (73 करोड़ रूपयें) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र 2 निर्गम (50 करोड़ रूपयें) से प्राप्त हुई। केन्द्रीय सरकार ने इस स्रोत से 1971-72 में 180 करोड़ रूपयें प्राप्त होने का अनुमान लगाया है। अल्प बचत के वर्तमान माध्यमों को आलोच्य वर्ष में बढ़ाया नहीं गया किन्तु बैंक दर में परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप सभी वर्तमान माध्यमों की ब्याज दरों को 15 जनवरी, 1971 से बढ़ाया गया। इस प्रकार विभिन्न अल्प बचत प्रमाणपत्रों के संबंध में ब्याज दरों में 1 प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत तक के परिवर्तन किये गये। इसके अलावा 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों (2 और 3 निर्गमों को मिलाकर) में जमा की जानेवाली राशिओं की सीमाओं को 1 अगस्त, 1971 से अलग अलग व्यक्तियों के संदर्भ में 25,000 रूपयों से बढ़ाकर 50,000 रूपयें तथा संयुक्त रूप से की जानेवाली जमा राशिओं के संदर्भ में 50,000 रूपयों से बढ़ाकर 1,00,000 रूपयें कर दिया गया है।

74. 1970-71 के बजट में सार्वजनिक भविष्य निधि योजना से 5 करोड़ रूपयों की वास्तविक राशि प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था, किन्तु परिशोधित अनुमानों के अनुसार उक्त राशि 2.5 करोड़ रूपयें रह जाती है। फिर भी वास्तव में 4.6 करोड़ रूपयें प्राप्त हुए जब कि 1969-70 में प्राप्त राशि 2.5 करोड़ रूपयें थी। 1971-72 में इस मद के अधीन 4 करोड़ रूपयें प्राप्त होने का अनुमान है।

श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार

75. आलोच्य वर्ष के पूर्वार्ध में श्रेष्ठ प्रतिभूतियों के बाजार के मूल्यों में सामान्यतः काट्टे विशेष घट-बढ़ नहीं हुई जब कि उत्तरार्ध में बैंक दर में की गयी वृद्धि के परिणामस्वरूप उक्त मूल्यों में कमी की प्रतीति आयी। सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रतिभूतियों (आधार : 1961-62-100) से संबंधित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आँखल भारतीय सूचकांक नवंबर 1970 के पहले सप्ताह तक जून 1970 के अंत में स्थित 99.3 के स्तर पर ही रहा, और विसंबर 1970 के अंत में थोड़ा कम होकर 98.9 रह गया। 9 जनवरी 1971 में बैंक दर में पूरे एक प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के कारण श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के मूल्यों में और कमी हुई और सूचकांक कम होकर जनवरी और जून 1971 के अंत में क्रमशः 98.2 और 97.6 रह गया। केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के सूचकांक में जहाँ समूचे वर्ष में 2.1 अंकों की कमी हुई और वह 96.9 हो गया वहाँ राज्य सरकारों की तथा अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों के सूचकांकों में क्रमशः 0.2 अंक और 0.1 अंक की कमी हुई और वह क्रमशः 100.3 और 101.2 हो गये। बाजार में सुव्यवस्थित स्थिति बनाये रखने और उसकी क्रय और विक्रय दरों में समायोजन कर वर्तमान ब्याज दरों के अनुरूप आय स्वरूप को बनाने की दिशा में रिजर्व बैंक के खुले बाजार के कार्यकलाप पहले की तरह जारी रहे। इस लेखा वर्ष में रिजर्व बैंक द्वारा खरीदी और बेची गयी प्रतिभूतियों की कुल राशि क्रमशः 275.7 करोड़ रूपयें और 359.8 करोड़ रूपयें थी और इसके परिणामस्वरूप वास्तविक बिक्री की राशि 84.1 करोड़ रूपयें थी जब कि उक्त राशि पिछले वर्ष 30.0 करोड़ रूपयें थी।

गैर-सरकारी निगम क्षेत्र

76. आलोच्य वर्ष में गैर-सरकारी निगम क्षेत्र के नये निवेश संबंधी कार्यकलापों में वृद्धि होने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला।

ऐसा प्रतीत हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश-क्षेत्र में धीरे-धीरे वृद्धि होने के कारण गैर-सरकारी निगम क्षेत्र के नये निवेश कार्य में कुछ सीमा तक मंदी आ गयी है। निवेशों के वित्त पोषण के संबंध में 1969-70 की तुलना में इस वर्ष ऋण से प्राप्त होनेवाले वित्त पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति अधिक पायी गयी जिसके परिणाम-स्वरूप मीयादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता स्वीकृत और वितरित की गयी किन्तु नये सिरों से जारी किये गये पूंजीगत शेयर काफी कम थे। जुटायी गयी वास्तविक पूंजी का जहाँ तक संबंध है, इक्विटी और अधिमान शेयरों के भागले में वृद्धि हुई जब कि डिबेंचरों के माध्यम से जुटायी गयी पूंजी में तेजी से कमी हुई। नये शेयरों के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक थी। लाभांश-संबंधी घोषणाओं के प्रारंभिक अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि निगम के कार्य-कलापों में कुछ सुधार हुआ है। इक्विटी शेयरों के मूल्य अक्टूबर 1970 में बढ़कर और अधिक हो गये, परन्तु उसके बाद उनमें परिवर्तन आया और वर्ष के अधिकांश भाग में वे कम ही रहे।

पूँजी शेयर संबंधी सहमतिगत

77. शेयरों (बोनस शेयरों को छोड़कर) और डिबेंचरों के रूप में नये पूंजीगत शेयर जारी किये जाने के प्रस्तावों के संदर्भ में गैर-सरकारी सार्वजनिक सीमित कंपनियों को दी गयी सह-मतिता/स्वीकृतियों में इस वर्ष कमी हुई। 1970-71 (जुलाई-जून) में 52.5 करोड़ रूपयों की राशि के लिए जो सहमतिता दी गयीं वे 1969-70 में दी गयी सहमतिताओं की 89.0 करोड़ रूपयों की राशि से काफी कम थी। इस संबंध में अधिकांश कमी 'अतिरिक्त' शेयर जारी किये जाने के लिए दी गयी सहमतिताओं के संदर्भ में हुई, क्योंकि उनकी राशि जहाँ 1969-70 में 69.6 करोड़ रूपयें थी वहाँ इस वर्ष केवल 31.9 करोड़ रूपयें थी। 'प्रारंभिक' शेयर जारी करने के लिये दी गई सहमतिताओं की राशि पिछले वर्ष के 19.5 करोड़ रूपयों से थोड़ी सी अधिक अर्थात् 20.5 करोड़ रूपयें थी। यदि जमानतदार देखा जाये तो 1970-71 में 32.5 करोड़ रूपयों के इक्विटी शेयर और 11.6 करोड़ रूपयों के डिबेंचर जारी करने के लिए सहमतिता प्रदान की गयीं जब कि 1969-70 में उनकी राशियाँ क्रमशः 43.4 करोड़ रूपयें और 37.8 करोड़ रूपयें थीं। 8.3 करोड़ रूपयों की राशि के अधिमान्य शेयर जारी करने की जो सहमतिता दी गयीं वे पिछले वर्ष के 7.9 करोड़ रूपयों से थोड़ी सी अधिक थीं।

78. बोनस शेयरों के संबंध में यह स्मरण होगा कि सरकार ने अप्रैल 1970 से किये गये प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे। 1970-71 (जुलाई-जून) में गैर-सरकारी सार्वजनिक सीमित कंपनियों को बोनस शेयर जारी करने के संबंध में दी गयी सहमतिताओं की राशि पिछले वर्ष के 45.4 करोड़ रूपयों से घटकर 34.1 करोड़ रूपयें हो गयी। सामान्य निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मई 1971 में बोनस शेयर जारी किये जाने के संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में और संशोधन किया गया। पिछले संशोधनों के अनुसार प्रस्तावित पूंजीकरण के पश्चात् अवशिष्ट प्रारक्षित निधियों का जो अनुपात बनाये रखना है उसे कंपनी की बढ़ायी गयी चुकता पूंजी के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 22-1/3 प्रतिशत कर दिया गया है। यह भी निर्धारित किया गया है कि बोनस शेयर जारी करने के लिये दिये जानेवाले प्रस्ताव के साथ ही प्रबंधकों को चाहिए कि वे कंपनी की बढ़ायी गयी पूंजी पर दिये प्रथम वार्षिक लाभांश के बारे में अपने आशय की स्पष्ट सूचना दें और उसके लिए शंकरधारियों का अनुमोदन प्राप्त कर लें।

*अब यह अनुमान लगाया गया है कि 1970-71 में अल्प बचतों से प्राप्त होने वाली राशि 197 करोड़ रूपयें होगी, परन्तु उसके लिये अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

† अनन्तिम

नये शेर शर्तों की कार्यकलाप

79. नये पूंजीगत शेर जारी करने के कार्य में जुलाई 1970—जून 1971 के दौरान मंदी पायी गयी। विवरणपत्रों द्वारा तथा शेरधारियों के अधिकार के रूप में जारी किये गये शेरों की कुल राशि 1969-70 (जुलाई-जून) के 81.5 करोड़ रूपयों से घटकर 50.7 करोड़ रूपयों हो गयी। प्रतिभूतिवार देखा जाए तो डिबेंचरों में मुख्यतः कमी हुई यद्यपि इक्विटी और अधिमान शेरों की राशि भी कुछ सीमा तक कम ही थी। इसके अलावा केवल 'अतिरिक्त' शेरों की राशि में भारी कमी पायी गयी; उनकी राशि 1969-70 के 54.2 करोड़ रूपयों से घटकर 17.0 करोड़ रूपयों हो गयी। इसके विपरीत 'प्रारंभिक' शेरों में वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही और उनकी राशि 1969-70 के 27.3 करोड़ रूपयों से बढ़कर इस वर्ष 33.7 करोड़ रूपयों हो गयी। इसके परिणामस्वरूप 1970-71 के दौरान जारी किये गये कुल नये शेरों में प्रारंभिक शेरों का अनुपात भारी था पूंजीगत शेरों में जगता ने जो रुचि दिखायी उससे इस विश्वास में और सुधार होने का संकेत मिला और अनेक शेरों में अधिक अभिदान हुआ। हामीदारी के रूप में जो सहायता दी जाती है उसमें अधिकांश भाग विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली हामीदारी का था। परंतु उपलब्ध आँकड़ों से यह पता चलता है कि सार्वजनिक योगदान में सुधार होने के कारण सांस्थानिक हामीदारी के रूप में प्रदान की जानेवाली सहायता की राशि का अनुपात 1970 में कुल हामीदारी की राशि का 23.4 प्रतिशत था जब कि 1969 में उक्त अनुपात 27.6 प्रतिशत था।

मिश्रायी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता

80. 1970-71 (अप्रैल-मार्च) में मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं ने 1969-70 की अपेक्षा काफी अधिक वित्तीय सहायता मंजूर की। इन संस्थाओं द्वारा ऋणों, शेरों और डिबेंचरों की हामीदारी तथा उनमें प्रत्यक्ष अभिदानों के रूप में मंजूर की गई वित्तीय सहायता की कुल राशि 1969-70 (अप्रैल-मार्च) के 153.6 करोड़ रूपयों से बढ़कर इस वर्ष 231.7 करोड़ रूपयों हो गयी। वितरणों @ की राशि 1969-70 के 115.5 करोड़ रूपयों के मुकाबले में इस वर्ष 147.5 करोड़ रूपयों हो गयी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अप्रैल 1970—मार्च 1971 के दौरान काफी अधिक राशि अर्थात् 80.3 करोड़ रूपयों के ऋण मंजूर किये जब कि अप्रैल 1969—मार्च 1970 में उसने 46.9 करोड़ रूपयों के ऋण मंजूर किये थे और उसके वितरणों की राशि भी पिछले वर्ष की उक्त अवधि के 43.3 करोड़ रूपयों की तुलना में अधिक अर्थात् 51.1 करोड़ रूपयों थी।

81. जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट हामीदारी और निवेश संबंधी अपने कार्यकलापों द्वारा गैर-सरकारी निगम क्षेत्र को पर्याप्त सहायता देते रहे। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 1970-71 (अप्रैल-मार्च) में शेरों और डिबेंचरों की हामीदारी तथा उनमें प्रत्यक्ष अभिदानों के रूप में 15.2 करोड़ रूपयों की सहायता प्रदान की जो पिछले वर्ष के 9.9 करोड़ रूपयों की सहायता से अधिक थी। जीवन बीमा निगम ने शेरों और डिबेंचरों की हामीदारी तथा उनमें प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में 1968-69 (अप्रैल-मार्च) के 14.4 करोड़ रूपयों के मुकाबले में 1969-70 (अप्रैल-मार्च) में 10.8 करोड़ रूपयों की राशि मंजूर की थी।

82. भारतीय उद्योग के 'संयुक्त क्षेत्र' के विकास के संबंध में दत्त समिति की रिपोर्ट का इसके पूर्व उल्लेख किया गया था। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने 1 मई 1971 को अखिल भारतीय दीर्घवर्धित वित्तीय संस्थाओं से बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाले औद्योगिक यूनिटों के संदर्भ में ऋणों को पूंजी (पूँजी अर्थात् चुकता पूँजी और गुप्त आरक्षित निधि) के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार

किसी एक कंपनी के लिए 50 लाख रूपयों या उनसे अधिक राशि के रूप-या-ऋण मंजूर करते समय वित्तीय संस्थाएँ ऋण संबंधी प्रतिज्ञापत्र में सामान्यतः इस प्रकार व्यवस्था करेंगी कि अनुपात की दृष्टि से ऋण-पूँजी में सामंजस्य बनाये रखने के लिए उचित मात्रा में ऋण को पूँजी के रूप में परिवर्तित करने का विकल्प प्राप्त हो। 25 लाख रूपयों और 50 लाख रूपयों के बीच के ऋणों के संबंध में वित्तीय संस्थाएँ अपने विवेक का उपयोग कर सकती हैं और जो ऋण 25 लाख रूपयों से अधिक न हों, उनके मामले में संस्थाएँ उन ऋणों को पूँजी के रूप में परिवर्तित करने की शर्त नहीं लगाएँगी।

83. इस प्रकार औद्योगिक विकास के क्षेत्र में यह परिकल्पना की गयी है कि सार्वजनिक क्षेत्र अधिकाधिक क्रियाशील भूमिका अदा करेगा और इस संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों के नाम यह शर्त निर्धारित करते हुए जारी किये गये निदेश का उल्लेख किया जा सकता है कि यदि वे किसी ऋणकर्ता को शेरों की गमानत पर 50,000 रूपयों से अधिक सीमा तक के ऋण प्रदान करें या उन्हें नवीकृत करें, तो इस प्रकार बंधक रखे गये शेर उनका नाम अंतर्गत कर दिये जाएँ और उन शेरों के संबंध में उनका संपूर्ण मताधिकार रहेगा। आगामी वर्ष के अंत में सभी सामान्य श्रेणी कंपनियों को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया।

इक्विटी शेरों के मूल्य :

84. प्रमुख शेर बाजारों में इक्विटी शेरों के मूल्यों में फरवरी 1970 के मध्य से वृद्धि की जो प्रवृत्ति पायी गयी थी वह उसके बाद के महीनों में और तेज हो गयी और अक्टूबर 1970 के पहले सप्ताह में उक्त मूल्य नये शिखर स्तर पर पहुँच गये। केन्द्रीय सरकार के 1970-71 के बजट में निवेशों के लिए जिन प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गयी थी उनके कारण तथा, लोकप्रिय शहरों की कमी, अनुकूल मानसून, सुधरी हुई फसल के उत्पादन की संभावनाओं और निगम क्षेत्र के संतोषजनक कार्यकलापों के कारण शेर बाजारों की प्रवृत्तियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। परिवर्तनीय लाभोपवली औद्योगिक प्रतिभूतियों का रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय सूचकांक (आधार: 1961-62=100) जहाँ 27 जून 1970 को समाप्त हुए सप्ताह में 100.0 था वहाँ 3 अक्टूबर 1970 को बढ़कर 110.1 के नये शिखर पर पहुँच गया। फिर भी, उसके बाद मूल्य जनवरी 1971 के पहले सप्ताह तक घटते रहे और तब इक्विटी सूचकांक 101.4 के स्तर पर पहुँच गया। यद्यपि बैंक दर में 9 जनवरी 1971 से वृद्धि की गयी फिर भी निगम क्षेत्र के संतोषजनक कारोबार के कारण जनवरी 1971 के शेष सप्ताहों में इक्विटी शेरों के मूल्यों में कुछ सीमा तक स्थायिता आयी। उसके पश्चात् मूल्यों में फिर से कमी होने लगी। इक्विटी शेर मूल्य सूचकांक 3 अक्टूबर 1970 के शिखर स्तर से घटकर 20 जून 1971 को 97.5 हो गये, अर्थात् उनमें 11.4 प्रतिशत की कमी हो गयी। लेखा वर्ष में भी, उक्त सूचकांक में 2.5 प्रतिशत की कमी हुई, जहाँ 1969-70 (जुलाई-जून) में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। शेर बाजार के मूल्यों की प्रवृत्ति का प्रभावित करनेवाले मुख्य तत्व इस प्रकार थे : कच्ची रूई के मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने के कारण सूती वस्त्र मिलों द्वारा कीठनाइयों अनुभव की गयीं, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा कंपनियों को दिये गये ऋणों को पूँजी के रूप में परिवर्तित करने के संदर्भ में आशंकाएँ उत्पन्न हुईं, सभी बकाया धातु क्रय-विक्रय

*भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम।

@इनमें गारंटियों के संबंध में वितरित की गई राशि शामिल है।

*अन्तिम।

*इनमें पुनर्भोजन और बैंकों को दिया गया पुनर्भित्त शामिल है।

सारणी 14 — मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा 1969-70 और 1970-71 में मंजूर की गयी और वितरित सहायता

(क्रोड़ रुपये)

संस्था का नाम	ऋण			
	1970-71		1969-70	
	मंजूर किये गये	वितरित किये गये	मंजूर किये गये	वितरित किये गये
	1	2	3	4
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	80.3* [17.0]	51.1* [13.7]	46.9* [7.8]	43.3* [5.7]
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	31.1 (5.8)	16.5@ (2.6)	17.2 (1.8)	16.4@ (1.9)
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	37.6 (28.0)	26.1 (21.5)	17.9 (13.7)	16.1 (11.8)
राज्य वित्तीय निगम	48.8	32.7@	32.9	21.4@
राज्य औद्योगिक विकास निगम**	16.3	9.2	20.3	7.5
जोड़	214.1	135.6	135.2	104.7
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	—	—	—	—
भारतीय जीवन बीमा निगम @@@	—	—	2.6	1.7

भेयरो और डिबेंचरो की हमीवारी तथा उनमें प्रत्यक्ष अभिदान

संस्था का नाम	1970-71		1969-70	
	मंजूर किये गये	वितरित किये गये	मंजूर किये गये	वितरित किये गये
	5	6	7	8
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	4.3	4.7	6.2	1.8
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	3.8	0.9	1.4	1.1
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	5.4	3.1	4.9	3.7
राज्य वित्तीय निगम	0.5	0.3	0.5	0.3
राज्य औद्योगिक विकास निगम**	3.5	2.9	5.4	3.9
जोड़	17.5	11.9	18.4	10.8
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	15.2	8.4	9.9	8.1
भारतीय जीवन बीमा निगम @@@	—	—	10.8	10.1

सारणी 14—मिमावो ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा 1969-70 और 1970-71 में मंजूर की गयी और वितरित सहायता

(करोड़ रुपये)

संस्था का नाम	जोड़			
	1970-71		1969-70	
	मंजूर किये गये	वितरित किये गये	मंजूर किये गये	वितरित किये गये
	9	10	11	12
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	84.6 [17.0]	55.8 [13.7]	53.1 [7.8]	45.1 [5.7]
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	35.0 (5.8)	17.4 (2.6)	18.6 (1.8)	17.5 (1.9)
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	43.0 (28.0)	29.2 (21.5)	22.8 (13.7)	19.8 (11.8)
राज्य वित्तीय निगम	49.3	33.0	33.4	21.7
राज्य औद्योगिक विकास निगम**	19.8	12.1	25.7	11.4
जोड़	231.7	147.5	153.6	115.5
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	15.2	8.4	9.9	8.1
भारतीय जीवन बीमा निगम @@@	—	—	13.3	11.8

नोट:— (i) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े विदेशी मुद्रा ऋणों से संबंधित हैं। (ii) 1970-71 के आंकड़े अंतिम हैं।

*इनमें प्रत्यक्ष ऋण, पुनर्भाजन और बैंकों को दिया गया पुनर्वित्त शामिल है; चौकोर कोष्ठकों में राज्य वित्तीय निगमों को दिया गया पुनर्वित्त दर्शाया गया है; उन्हें इनमें इसलिये शामिल नहीं किया गया है कि यह राशि चूंकि राज्य वित्तीय निगमों के ऋणों के अंतर्गत दी गयी है अतः उसे दुबारा हिसाब में न ले लिया जाए।

@इनमें गारंटियों के संबंध में वितरित की गयी राशि शामिल है।

**ये आंकड़े 10 राज्य औद्योगिक विकास निगमों, गुजरात औद्योगिक निवेश निगम और महाराष्ट्र लघु उद्योग और निवेश निगम से संबंधित हैं।

@@@1970-71 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

कारोबार में संतुलन लाने के लिए सरकार ने शहर बाजारों को आर्षेस दिये और शहर बाजार की त्रिष्ट में केन्द्रीय सरकार के 1971-72 के बजट प्रस्ताव गैर सरकारी कंपनी क्षेत्र के संदर्भ में बहुत उत्साह-पूर्ण नहीं थे।

कंपनियों लाभांश

85. सार्वजनिक सीमित कंपनियों द्वारा की गयी लाभांश संबंधी घोषणाओं के प्रारंभिक अध्ययन से यह पता चलता है कि 1969-70 की तुलना में 1970-71 में कंपनी क्षेत्र के कार्य में थोड़ा सा सुधार हुआ। अप्रैल 1970 और मार्च 1971 के बीच जिन 630 सार्वजनिक सीमित कंपनियों ने अपने लेखे बंद किये थे उनमें से 200 या 32 प्रतिशत कंपनियों ने अपनी लाभांश-दरों को बढ़ाया जब कि 1969-70 में 195 या 31 प्रतिशत कंपनियों ने लाभांश दरों को बढ़ाया था। जिन कंपनियों ने उन्ही दरों पर लाभांश अदा किया उनकी संख्या पिछले वर्ष अर्थात् 1969-70 की ही तरह 198 या 31 प्रतिशत थी। शेष 232 कंपनियों में से 100 या 16 प्रतिशत कंपनियों ने अपने लाभांश को कम किया जब कि पिछले वर्ष इस प्रकार लाभांश कम करनेवाली कंपनियों की संख्या 79 या 13 प्रतिशत थी। इसके विपरीत कुछ भी लाभांश अदा न करनेवाली कंपनियों की संख्या 1970-71 में 132 या 21

प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष के 158 या 25 प्रतिशत से कम थी। लाभांशों की वास्तविक दरों के संदर्भ में 11 और 20 प्रतिशत के बीच लाभांशों की अदायगी करनेवाली कंपनियों की संख्या में 1970-71 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई अर्थात् वह 1969-70 के 186 (30 प्रतिशत) से बढ़कर इस वर्ष 216 (34 प्रतिशत) हो गयी। 6 और 10 प्रतिशत के बीच लाभांश अदा करनेवाली कंपनियों की संख्या पिछले वर्ष के 202 (32 प्रतिशत) से कम होकर इस वर्ष 188 (30 प्रतिशत) हो गयी जब कि कंपनियों की कुल संख्या में 20 प्रतिशत से अधिक लाभांश की अदायगी करनेवाली कंपनियों का अनुपात दोनों वर्षों में 3 प्रतिशत था।

कृषि संबंधी निवेश के लिए वित्त

86. विविध सांस्थानिक एजेंसियाँ कृषि संबंधी निवेश की जो वित्तीय सहायता करती हैं उसमें आलोच्य वर्ष में और प्रगति हुई। कृषि पुनर्वित्त निगम, कृषि वित्त निगम और ग्रामीण बिजली निगम द्वारा कृषि संबंधी योजनाओं के लिए संवितरणों के रूप में प्रदान की गयी वित्तीय सहायता और रिजर्व बैंक के मध्यावधि ऋणों से ली गयी राशि और केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों से यह पता चलता है कि 1969-70 के स्तर की तुलना में 1970-71 में कृषि-निवेशों में

पर्याप्त वृद्धि हुई। कृषि वित्त निगम द्वारा किये गये संवितरणों में थोड़ी सी कमी हुई परन्तु कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा किये गये संवितरणों में वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक के मध्यावधि ऋणों से ली गयी राशि पिछले वर्ष के स्तर पर ही रही। इस वर्ष ग्रामीण बिजली निगम ने पहली बार 26.04 करोड़ रूपयों का संवितरण किया। आलांच्य वर्ष में कृषि पुनर्वित्त निगम तथा कृषि वित्त निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या और उनके द्वारा किये गये ऋणों संबंधी वाचदों की राशि अपेक्षाकृत कम थी परन्तु ग्रामीण बिजली निगम की स्वीकृतियों और वाचदों में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हुई (सारणी 15)। वाणिज्य बैंकों द्वारा मध्यावधि उद्देश्यों के लिए कृषि को दिये जानेवाले ऋणों में भी पर्याप्त प्रगति हुई। उसी प्रकार, केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित किये जानेवाले मध्यावधि ऋणों में भी काफी वृद्धि हुई।

मुद्रा की उपलब्ध की प्रवृत्तियाँ

87. पिछले वर्ष की तुलना में (592 करोड़ रूपयें) 1970-71 (जुलाई-जून) में जनता के पास रहनेवाली मुद्रा में उल्लेखनीय रूप से भारी वृद्धि हुई (814 करोड़ रूपयें)। इस वर्ष मुद्रा-वृद्धि की दर 12.3 प्रतिशत थी। जब कि 1969-70 में वह 9.8 प्रतिशत थी। कुल मुद्रागत वित्तीय साधनों में जिनमें मुद्रा की उपलब्धि और बैंकों के पास रहनेवाली मीयादी जमाराशियां शामिल हैं, जहाँ पिछले वर्ष 1,011 करोड़ रूपयों या 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ इस वर्ष 1,363 करोड़ रूपयों या 14.0 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई (सारणी 16)। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल माँग में पर्याप्त वृद्धि हुई। यदि घटकवार देखा जाए तो माँग जमाराशियों में हुई वृद्धि की अपेक्षा समग्र रूप से चलमुद्रा में बराबर अधिक वृद्धि होती गयी; परन्तु वृद्धि की दरों के अनुसार चलमुद्रा की अपेक्षा जमाराशि की वृद्धि की दर काफी ऊँची थी। चलमुद्रा वा माँग जमाराशियों की अपेक्षा मीयादी जमाराशियों में वास्तविक आंकड़ों और वृद्धि की दर, दोनों ही दृष्टियों से अधिक तेजी से वृद्धि हुई। कुल मुद्रागत वित्तीय साधनों में हुई कुल वृद्धि में मीयादी जमाराशियों का प्रतिशत 0.3 था जब कि जनता के पास रहनेवाली चलमुद्रा और जमाराशियों का प्रतिशत क्रमशः 31.3 और 28.4 था।

88. 1970 के दौरान हुए मुद्रा विस्तार के कारणों में बैंक द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण एक महत्वपूर्ण कारण था जिसमें 924 करोड़ रूपयों की अभूतपूर्व वृद्धि हुई; यह वृद्धि सामान्यतः बजट संबंधी कार्यकलापों में बढ़ते हुए असंतुलन और विशेषकर राज्य सरकारों द्वारा लिये गये आवरड्राफ्टों की समस्या की श्रोतक थी। बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये ऋण में वास्तविक आंकड़ों तथा वृद्धि की दर दोनों ही दृष्टियों से अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। मुद्रा विस्तार की दर पूरे वर्ष में एक सी नहीं थी, 1970 के लेखा वर्ष के पूर्वार्ध अर्थात् जुलाई-दिसम्बर

1970 में यह विस्तार (330 करोड़ रूपयें) 1969 के तदनुसूची पूर्वार्ध में हुए विस्तार (153 करोड़ रूपयें) की अपेक्षा बहुत अधिक था, परन्तु उत्तरार्ध में इस प्रवृत्ति का प्रत्यावर्तन हुआ अर्थात् जहाँ जनवरी-जून 1970 में 602 करोड़ रूपयों का मुद्रा विस्तार हुआ था वहाँ जनवरी-जून 1971 में केवल 299 करोड़ रूपयों का मुद्रा विस्तार हुआ। इन कारणों से जो मुद्रा विस्तार हुआ वह कुछ हद तक निम्नलिखित कारणों से कम हुआ : (i) बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा अस्तित्वों में 97 करोड़ रूपयों की कमी हुई जब कि 1969-70 में उनमें 264 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई थी, और (ii) बैंकिंग संघटन की वास्तविक मुद्रांतर देयताओं में 110 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई। वास्तविक विदेशी अस्तित्वों में जो कमी हुई वह अंशतः उदार आयात नीति के फलस्वरूप आयातों में वृद्धि और अंशतः विदेशी सहायता के द्वारा किये गये अनाज के आयातों और प्रायोजनोत्तर सहायता में कमी हो जाने के फलस्वरूप विदेशी सहायता के उपयोग में हुई अपेक्षाकृत अधिक कमी की श्रोतक है। इन पर इसके बाद के पैरा-ग्राफों में चर्चा की गयी है।

माँसमी प्रवृत्तियाँ

89. जहाँ 1969 में कम कामकाज के समय (मई-अक्टूबर) में जनता के पास रहने वाली मुद्रा में 58 करोड़ रूपयों की कमी हुई थी वहाँ 1970 के कम कामकाज के समय में उसमें 143 करोड़ रूपयों की माँसमंतर वृद्धि हुई (सारणी 17)। मुद्रा की उपलब्धि में जो वृद्धि हुई वह मुख्यतः बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक ऋण में हुई 111 करोड़ रूपयों की वृद्धि और बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा अस्तित्वों में हुई 36 करोड़ रूपयों की वृद्धि के फलस्वरूप हुई। मुद्रा विस्तार में बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये ऋण का योगदान भी उल्लेखनीय था।

90. किन्तु 1969-70 के अधिक कामकाज के समय (नवम्बर 1969-अप्रैल 1970) मुद्रा की उपलब्धि में हुई 703 करोड़ रूपयों ((12 प्रतिशत) की माँसमी वृद्धि की तुलना में 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में हुई 572 करोड़ रूपयों (8.5 प्रतिशत) की माँसमी वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी। चलमुद्रा के घटक में 400 करोड़ रूपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई वृद्धि से 117 करोड़ रूपयें कम थी। माँग जमाराशियों में हुई वृद्धि में भी पिछले अधिक कामकाज के समय की तुलना में 14 करोड़ रूपयों की कमी पायी गयी। फिर भी, मीयादी जमाराशियों में जो वृद्धि हुई उसमें 1969-70 के अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा 81 करोड़ रूपयों की अधिकता पायी गयी।

91. बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक ऋण में जहाँ पिछले अधिक कामकाज के समय में 130 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई थी वहाँ 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में 620 करोड़ रूपयों की बड़ी भारी वृद्धि हुई। फिर भी विदेशी मुद्रा अस्तित्वों में 85 करोड़ रूपयों की कमी हुई जब कि पिछले अधिक कामकाज के समय में उनमें 168 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई थी। मीयादी

सारणी 15—कृषि संबंधी निवेश के लिए वित्त
(जुलाई—जून)

(करोड़ रुपये में)

	1960- 61	1961- 62	1962- 63	1963- 64	1964- 65	1965- 66	1966- 67	1967- 68	1968 69	1969- 70	1970- 71
1. केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक/विकास बैंकों द्वारा जारी किए गए डिबेंचर ¹											
(क) सामान्य डिबेंचर	9.97	10.50	19.25	23.34	34.81	43.10	52.05	64.51	103.42	114.82*	119.49
(ख) ग्रामीण डिबेंचर	1.55	2.24*	1.57	1.84	3.23	4.33	2.93	1.57	5.00	1.10	4.78
2. कृषि पुनर्वित्त निगम (कृ.पु.नि.)²											
(क) मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या				3	10	24	15	89	108	142	100
(ख) कुल परिव्यय				2.72	20.60	17.96	10.53	68.16	79.21	92.78	62.15
(ग) कृ.पु.नि. के वायदे				2.45	16.88	14.18	8.53	58.64	69.32	70.92	53.92
(घ) इस वर्ष संबितरित की गयी राशि				—	0.45	4.45	2.08	5.67	17.84	28.60	30.62
3. कृषि वित्त निगम (कृ.वि.नि.)³											
(क) मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या									6	21*	10
(ख) कुल परिव्यय									61.50	45.70*	23.33
(ग) इस वर्ष संबितरित की गयी राशि									0.96*	15.77*	13.24
4. ग्रामीण बिजली निगम (ग्रा.बि.नि.)⁴											
(क) मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या										49*	74
(ख) कुल परिव्यय										32.01*	49.71
(ग) ग्रा.बि.नि. के वायदे										29.79*	49.38
(घ) इस वर्ष संबितरित की गयी राशि										—	26.04
5. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मध्यावधि ऋण											
(क) मंजूर की गयी राशि	4.68	9.56	9.31	14.01	14.39	14.11	15.49	16.57	19.00	8.30	18.76
(ख) उसमें से इस वर्ष ली गयी राशि	5.69	7.39	4.18	7.45	7.91	7.45	8.37*	9.12	8.98*	11.48	11.38

नोट : वाणिज्य बैंकों द्वारा केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक/विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों में किये गये अंशदान के रूप में श्रीर कृषि वित्त निगम के साथ सहभागिता के द्वारा दिये गये वित्त के आंकड़ों को छोड़कर उनके द्वारा प्रदान किये गये अन्य निवेश वित्त के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार, सहकारी ऋण एजेंसियों द्वारा अपनी निजी निधियों से प्रदान किये गये निवेश वित्त के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

1. सहकारी भूमि बंधक/विकास बैंकों ने 1961-62 में 18.00 लाख रुपये, 1963-64 में 5.41 लाख रुपये 1965-66 में 1.45 लाख रुपये, 1966-67 में 1.23 लाख रुपये 1967-68 में 0.32 लाख रुपये और 1968-69 में 0.18 लाख रुपये तक के विशेष विकास डिबेंचर भी जारी किये। विशेष विकास डिबेंचरों की पहली श्रेणी कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना के पहले जारी की गयी थी और शेष श्रेणियाँ कृषि पुनर्वित्त निगम की योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आती।
2. ये कार्यकलाप इस वर्ष के दौरान मंजूर की गयी योजनाओं के द्योतक हैं जिनमें इसी वर्ष के दौरान वापस ले ली गयी योजनाओं को छोड़ दिया गया है। पिछली रिपोर्टों में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष के कार्यकलापों को प्रस्तुत किया जाता था : (i) संबन्धित वर्ष और उसके बाद के वर्षों में वापस ले ली गयी योजनाएँ (ii) उसके बाद के वर्षों में वित्तीय परिव्यय में की गयी कटौतियाँ और (iii) योजनाओं का पुनर्गठन यदि कोई हो। वापस ले ली गयी योजनाओं तथा पुनर्गठित योजनाओं के लिए हिसाब में आवश्यक व्यवस्था करने के बाद मंजूर की गयी योजनाओं की संचयी संख्या 30 जून 1971 को 458 होती है जिनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता की राशि 293.00 करोड़ रुपये थी। उसमें से निगम द्वारा वायदा की गयी राशि 248.66 करोड़ रुपये थी।
3. यहां जो आंकड़े दिये गये हैं वे यदि एक ही वर्ष में कोई योजना वापस ले ली गयी हो/परिव्यय में परिवर्तन किया गया हो, तो उसे हिसाब में लेने के बाद किन्तु बाद में यदि कोई योजना वापस ले ली गयी और परिव्यय में परिवर्तन किया गया हो तो उसे हिसाब में लिये बिना उस वर्ष के दौरान मंजूर की गयी योजनाओं से संबन्धित है। इन बातों पर विचार करने के बाद कृषि वित्त निगम द्वारा अपनी स्थापना से लेकर अर्थात् 1 अप्रैल 1968 से 30 जून 1971 तक मंजूर की गयी योजनाएं 33 रहती हैं जिनके कुल परिव्यय की राशि 128.08 करोड़ रुपये है और इस संवर्ष में निगम ने 29.97 करोड़ रुपये वितरित किये थे।
4. इनमें से 1969-70 में तीन योजनाएं और 1970-71 में दो योजनाएं ग्रामीण सहकारी बिजली समितियों से संबन्धित थीं।

*परिशोधित।

सारणी 10—मुद्रा की उपलब्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियाँ (वार्षिक)

(करोड़ रुपये में)

	जुलाई-जून में घट-बढ़		
	1968-69	1969-70	1970-71
1. जनता के पास चल मुद्रा	+ 341 (+ 9.9)	+ 371 (+ 10.1)	427 (+ 10.2)
2. मांग जमा राशियाँ	+ 225 (+ 11.1)	+ 211 (+ 9.4)	+ 387 (+ 15.7)
3. मुद्रा की उपलब्धि (1+2)	+ 566 (+ 10.3)	+ 592 (+ 9.8)	+ 814 (+ 12.3 ^f)
4. मीयादी जमा राशियाँ	+ 473 (+ 21.5)	+ 419 (+ 15.6)	+ 549 (+ 17.7)
5. कुल मुद्रागत साधन (3+4)	+ 1039 (+ 13.3)	+ 1011 (+ 11.6)	+ 1363 (+ 14.0)
6. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण	+ 433 (+ 9.9)	+ 2 (—)	+ 924 (+ 19.2)
7. बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	+ 153@ (+ 84.6)	+ 264 (+ 66.0)	—97 (+ 14.6)
8. जनता के प्रति सरकार की वास्तविक चलमुद्रा देयताएँ	+ 33 (+ 10.4)	+ 20 (+ 5.6)	+ 18 (+ 4.8)
9. जोड़ (6+7+8)	+ 619@ (+ 12.7)	+ 286 (+ 5.1)	+ 845 (+ 14.4)
10. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण*	+ 641 (+ 17.6)	+ 755 (+ 17.7)	+ 629 (+ 12.5)
(क) बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया वास्तविक ऋण*	+ 167 (+ 11.7)	+ 336 (+ 21.1)	+ 8 (+ 41)
11. रिज़र्व बैंक की वास्तविक मुद्रा देयताएँ (वृद्धि—)	—95@	—60	—177
12. अन्य बैंकों की वास्तविक मुद्रा देयताएँ (वृद्धि—)	—125 + 1260@	+ 29 + 1041	+ 67 + 1474
13. जोड़ (9+10)	(+ 14.8)	(+ 10.6)	(+ 13.5)

नोट : कोष्ठकों में दिये हुए आंकड़े घट-बढ़ के प्रतिशत हैं।

(a) रिज़र्व बैंक के इणू विभाग में रखे हुए सोने के पुनर्मूल्यांकन के कारण 1 फरवरी, 1969 से उत्पन्न परिवर्तनों को छोड़कर।

*इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों की वाणिज्यिक उद्यमों के लिये किये गये ऋण शामिल हैं।

सारणी 17—मुद्रा की उपलब्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियाँ (मौसमी)

निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़

	कम-कामकाज का समय		अधिक कामकाज का समय	
	1969	1970	1969-70	1970-71
1. जनता के पास चल-मुद्रा	—149 (—4.0)	+34 (—0.8)	+517 (+14.3)	+400 (+9.7)
2. बैंकों की मांग जमा राशियाँ	+91 (+4.2)	+177 (+7.3)	+186 (+8.3)	+172 (+6.6)
3. मुद्रा की उपलब्धि (1+2)	—58 (—1.0)	+143 (+2.2)	+703 (+12.0)	+572 (+8.5)
4. मीथादी जमा राशियाँ	+248 (+9.6)	+277 (+9.2)	+163 (+5.7)	+244 (+7.4)
5. मुद्रागत साधन (3+4)	+190 (+2.2)	+420 (+4.4)	+866 (+10.0)	+816 (+8.2)
6. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण	—14 (—0.3)	+111 (+2.3)	+130 (+2.8)	+620 (+12.5)
7. बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	+59 (+15.4)	+36 (+5.9)	+168 (+38.0)	+85 (—13.2)
8. जनता के प्रति सरकार की वास्तविक चल-मुद्रा देयताएँ	— (—)	+6 (+1.6)	+19 (+5.5)	+15 (+4.1)
9. जोड़ (6+7+8)	+45	+153	+317	+550
10. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण*	+136 (+3.3)	+311 (+6.4)	+602 (+14.2)	+448 (+8.7)
(क) बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया वास्तविक ऋण*	—111 (—7.3)	+34 (+1.8)	+438 (+31.1)	+204 (+10.9)
11. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वास्तविक मुद्रा देयताएँ (वृद्धि—)	+15	27	—77	—113
12. अन्य बैंकों की वास्तविक मुद्रा देयताएँ (वृद्धि—)	—6	—71	+25	—69
13. जोड़ (9+10)	+181 (+1.9)	+464 (+4.4)	+919 (+9.4)	+998 (+9.0)

नोट : कोष्ठकों में दिये हुए आंकड़े घट-बढ़ के प्रतिशत हैं।

*इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों की वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दिये गये अग्रिम शामिल हैं।

जमाराशियाँ में हुई वृद्धि का समायोजन करने पर, बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये वास्तविक ऋण में 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में 204 करोड़ रूपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई 438 करोड़ रूपयों की वृद्धि की अपेक्षा कम थी। इस अवधि में बैंकों द्वारा अनाजों की उगाही के लिये दिये जानेवाले ऋण में 70.3 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई। बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण में अधिक कामकाज के समय के पहले दो महीनों (नवम्बर-दिसम्बर 1970) में जो विस्तार (199 करोड़ रूपयों) हुआ था वह बाद के चार महीनों में हुए विस्तार (249 करोड़ रूपयों) से अपेक्षाकृत बहुत अधिक था। बैंकिंग संघटन की वास्तविक मूद्रांतर वैयताओं में भी 182 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई, इसके फलस्वरूप मूद्रा की उपलब्धि में कमी हुई। उपर्युक्त कारण से और साथ ही वास्तविक विदेशी मूद्रा अस्तित्वों में हुई कमी और बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये वास्तविक ऋण में हुई अपेक्षाकृत थोड़ी सी वृद्धि के कारण से भी 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में मूद्रा की उपलब्धि में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई।

92. जिस प्रकार 1970 के कम कामकाज के समय के पहले दो महीनों में (मई-जून 1970) मूद्रा की उपलब्धि में मौसमोत्तर विस्तार हुआ था उसी प्रकार वर्तमान कम कामकाज के समय के तत्पश्चात् दो महीनों में भी मूद्रा की उपलब्धि में मौसमोत्तर विस्तार हुआ। बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक ऋण में इस वर्ष के कम कामकाज के समय में पिछले वर्ष की उसी अवधि में हुई थोड़ी सी कमी तुलना में भारी वृद्धि हुई; किन्तु बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये वास्तविक ऋण में 1970 के उक्त समय में हुई वृद्धि की तुलना में इस वर्ष कमी हुई।

बैंक व्यवसाय की प्रवृत्तियाँ और ऋण नीति

93. आलोक्य वर्ष के पूर्वार्ध में बैंकों की जमाराशियाँ में जिस तेजी से वृद्धि हो रही थी उसकी अपेक्षा और अधिक तेजी से बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में वृद्धि हो रही थी। अतः वाणिज्य बैंकों ने रिजर्व बैंक से अधिकधिक वित्तीय सहायता मांगी। 1 जनवरी 1971 को इस प्रकार की वित्तीय सहायता की राशि बहुत अधिक बढ़कर 351 करोड़ रूपयों के उच्च स्तर पर पहुँच गयी जो अक्टूबर 1970 के अंत में विद्यमान 150 करोड़ रूपयों की तुलना में भारी वृद्धि की परिचायक है। वस्तुतः अक्टूबर 1970 के अंत में परंपरागत कम कामकाज का समय समाप्त होना चाहिए था और इस कारण बैंकों द्वारा लिये जानेवाले ऋणों की राशि अत्यधिक मामूली हो जानी चाहिए थी। ऋणों के इस उच्च स्तर के कारण जो सरकार द्वारा बैंक संघटन से लिये गये ऋणों के अतिरिक्त थे, वस्तुओं की कीमियों से सामान्य मूल्य स्तर पर पड़ा उबाव बढ़ गया। इस अवधि में जो सामान्य मूल्य स्तर था वह एक वर्ष पहले के स्तर से लगभग 5 से 6 प्रतिशत तक उँचा था। अतः रिजर्व बैंक ने 9 जनवरी 1971 से बैंक दर को 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत बनाकर और 29 जनवरी 1971 से 'वास्तविक चलमूद्रा अनुपात' को 33 प्रतिशत से 34 प्रतिशत बनाकर सामान्य ऋण नियंत्रण को कड़ा कर दिया। साथ ही जमाराशियाँ को जटाने में बैंकों की सहायता करने के उद्देश्य से उनसे यह कहा गया कि वे जमाराशियाँ पर दिये व्याज की दरों में $\frac{1}{4}$ से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक की वृद्धि करें। बैंक दर और वास्तविक चलमूद्रा अनुपात में किये गये परिवर्तनों के फलस्वरूप अग्रिमों की व्याज-दरों के संबंध में बैंकों से यह कहा गया कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा अग्रिमों पर परसूत किये जाने वाले व्याज की दरों में औरतन लगभग 1 प्रतिशत की ही वृद्धि हो। रुई, तिलहन और वनस्पति तेलों के मूल्यों पर बढ़ते हुए व्याज को ध्यान में रखते हुए इन नीतियों

पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में लगाये गये चयनात्मक नियंत्रणों को और कड़ा कर दिया गया। यद्यपि उसके बाद इन सब उपायों के तत्काल प्रभाव स्वरूप बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में काफी कम वृद्धि हुई फिर भी वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में हुई वृद्धि की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक ही थी। इस प्रकार स्थिति संतोषजनक नहीं थी। अतः 4 फरवरी 1971 को ऋण स्थिति का मध्यकालीन पुनरीक्षण करते हुए गवर्नर ने बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋणों पर बराबर नियंत्रण रखने और जमाराशियाँ जटाने के लिये अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा बैंकों की ऋण प्रणाली को अधिक उद्देश्यप्रधान बनाने की दृष्टि से, गवर्नर ने बैंकों को यह समझाया कि अधिक व्यापक रूप से ऋण प्रपत्र के रूप में विनिमय बिल का उपयोग कराये जाने के संदर्भ में उन्हें प्रवर्तक की भूमिका अड़ा करनी है और नयी हंडी पुनर्भाजन योजना के अधीन बैंक दर पर पुनर्वित्त सुविधाएँ वर्ष भर में उपलब्ध होंगी। एक अतिरिक्त रियायत के रूप में यह व्यवस्था भी की गयी कि इस योजना के अधीन 30 जून, 1971 के बाद जिन हंडियों का पुनर्भाजन किया जाएगा उनके कारण बैंक दर पुनर्वित्त प्राप्त करने के बैंकों के अधिकार पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी, उनके वास्तविक चलमूद्रा अनुपात की स्थिति कुछ भी क्यों न हो। अन्य वर्गों की हंडियों को भी इस योजना में शामिल कर इस योजना के क्षेत्र को व्यापक बनाने के भी उपाय किये गये।

94. राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से अग्रतावाले और अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋणों की मात्रा को और बढ़ाया गया। राष्ट्रीयकरण से लेकर जून 1971 तक की अवधि में, जमा राशि में से सांख्यिक निवेश करने के पश्चात् शेष रहनेवाली राशि के अनुमानतः तीन चौथाई अंश का उपयोग कृषि, लघु उद्योग, परिवहन, चालकों, फुटकर व्यापार तथा छोटे कारोबार, व्यवसायिकों तथा स्वनिर्वाहित व्यक्तियों और शिक्षा के लिए दिए गए ऋणों के रूप में किया गया है। इस अवधि में बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में जो वृद्धि हुई उसमें इन क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों का अंश 68 प्रतिशत था। कुल अग्रिमों में इन क्षेत्रों को दिये गये ऋणों का हिस्सा जहाँ जून 1969 के अंत में 14.5 प्रतिशत था वहाँ मार्च 1971 के अंत में बढ़कर 23.8 प्रतिशत हो गया।

95. अनाज की उगाही संबंधी कार्यों के लिए दिए जानेवाले अग्रिमों में भी काफी वृद्धि हुई; इन अग्रिमों की राशि जहाँ 26 जून 1970 को 207 करोड़ रूपयों थी वहाँ वह बढ़कर 25 जून 1971 को 379 करोड़ रूपयों हो गयी। इन अग्रिमों में और वृद्धि हुई और उनकी राशि 30 जुलाई 1971 (अंतिम शुक्रवार) को 431 करोड़ रूपयों हो गयी।

वार्षिक घट बट (जुलाई 1970—जून 1971)

96. समग्र वर्ष में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई, परंतु जमाराशियाँ में 1969-70 की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई। अतः बैंक इस स्थिति में थे कि वे अपने निवेशों तथा नकदी बकाया राशियों में वृद्धि कर सकें और रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों के एक अंश की वापसी अदायगी भी कर सकें।

97. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों में जहाँ 1969-70 (जुलाई-जून) में 613.9 करोड़ रूपयों या 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ 1970-71 में 563.1 करोड़ रूपयों या 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विपरीत, जमाराशियाँ में हुई वृद्धि की राशि जहाँ 1969-70 में 628.7 करोड़ रूपयों या 13 प्रतिशत थी वहाँ वह 1970-71 में 915.4 करोड़ रूपयों या 17 प्रतिशत हो गयी। बैंक ऋण में हुई वृद्धि की दर वर्ष के

सारणी 18—बैंक व्यवसाय सम्बंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों में वार्षिक घट-बढ़

(करोड़ रुपये में)

	जून 1968 के अन्त में	जून 1968 में समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़	जून 1969 के अन्त में	जून 1969 में समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़
1. कुल बैंक ऋण	3102.9	+ 471.8	3598.8	+ 495.9
2. कुल निवेश	1160.7	+ 90.8	1358.9	+ 198.2
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में	975.6	+ 53.0	1126.3	+ 150.7
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	185.1	+ 37.8	232.6	+ 47.5
3. नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया	269.5	+ 10.7	380.3	+ 110.8
4. मांग पर प्रतिदेय राशि	50.6	—7.1	88.1	+ 37.5
5. कुल जमा राशियां	3969.0	+ 452.0	4645.8	+ 676.8
(क) मांग	1874.8	+ 210.2	2103.5	+ 228.7
(ख) मीयादी	2094.2	+ 241.8	2542.3	+ 448.1
6. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार	103.5	+ 92.0	172.2	+ 68.7

	जून 1970 के अन्त में	जून 1970 में समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़	जून 1971 के अन्त में*	जून 1971 में समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़
1 कुल बैंक ऋण	4212.7	+ 613.9	4775.8	+ 563.1
2. कुल निवेश	1504.2	+ 145.3	1798.9	+ 294.7
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में	1186.1	+ 59.8	1369.4	+ 183.3
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	318.1	+ 85.5	429.5	+ 111.4
3. नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया	357.6	—22.7	393.5	+ 35.9
4. मांग पर प्रतिदेय राशि	47.9	—40.2	74.8	+ 26.9
5. कुल जमा राशियां	5274.5	+ 628.7	6189.9	+ 915.4
(क) मांग	2328.8	+ 225.3	2725.1	+ 396.3
(ख) मीयादी	2945.7	+ 403.4	3474.8	+ 519.1
6. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार	291.5	+ 119.3	207.2	—84.3

*अनन्तिम (25 जून 1971 को)

स्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) के अधीन भेजी गयी साप्ताहिक विवरणियां ; परन्तु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधारों के आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त उधार सूचनाओं पर आधारित हैं।

सारणी 19—अनुसूचित बाणिज्य बैंकों के आंकड़ों में मौसमी घट-बढ़

(करोड़ रुपये में)

	कम कामकाज का समय 1969	अधिक कामकाज का समय 1969-70	कम कामकाज का समय 1970
	1	2	3
1. बैंक ऋण	+ 31.3	+ 562.9	+ 225.6
2. सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	+ 239.5	- 53.8	+ 187.6
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में	+ 208.3	- 100.9	+ 155.3
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	+ 31.2	+ 47.1	+ 32.3
3. नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया	+ 26.7	+ 7.7	+ 31.2
4. मांग पर प्रतिवेय राशि	- 25.8	- 14.8	- 5.6
5. कुल जमा राशियां	+ 348.1	+ 320.9	+ 448.6
(क) मांग	+ 115.0	+ 171.9	+ 174.3
(ख) भीयादी	+ 233.1	+ 149.0	+ 274.3
6. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार	- 67.5	+ 203.0	+ 86.0

	अधिक कामकाज का समय 1970-71	निम्नलिखित सप्ताह का कामकाज 25 जून 1971*	सप्ताह का कम समय 26 जून 1970
	4	5	6
1. बैंक ऋण	+ 409.2	+ 85.5	+ 157.2
2. सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	+ 128.5	+ 11.5	+ 32.9
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में	+ 53.7	- 4.8	+ 20.9
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	+ 74.8	+ 16.3	+ 12.0
3. नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया	+ 7.9	+ 39.1	42.3
4. मांग पर प्रतिवेय राशि	- 5.8	+ 41.9	+ 3.6
5. कुल जमा राशियां	+ 421.1	+ 211.2	+ 165.5
(क) मांग	+ 186.3	+ 98.2	+ 62.5
(ख) भीयादी	+ 234.8	+ 113.0	+ 103.0
6. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार	+ 40.2	+ 16.5	+ 55.0

*अनतिम

नोट :—(1) ये आंकड़े बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अधीन भेजी गयी साप्ताहिक विवरणियां पर आधारित हैं; परन्तु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधारों के आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त साप्ताहिक उधार सूचनाओं पर आधारित हैं।

(2) घट-बढ़ के आंकड़े अप्रैल और अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार के आंकड़ों पर आधारित हैं।

सारणी 20—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रमुख अनुपातों का मौसमी स्वरूप

(करोड़ रुपया में)

	अक्तूबर 1969		अप्रैल 1970		अक्टूबर 1970	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6
1. बैंक ऋण	3492.6	72.9	4055.5	69.4	4281.1	77.0
2. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	1525.1	31.8	1471.3	28.8	1658.9	29.8
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में	1266.1	26.4	1165.2	22.8	1320.5	23.7
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	259.0	5.4	306.1	6.0	338.4	6.1
3. नकदी और रिजर्व बैंक के पास वकाया	307.6	6.4	315.3	6.2	346.5	6.2
4. बोली और भ्रम्य सूचना पर प्रतिदेय राशि	59.1	—	44.3	—	38.7	—
5. कुल जमा राशियां	4788.1	100.0	5109.0	100.0	5557.6	100.0
(क) मांग	2094.4	43.7	2266.3	44.4	2440.6	43.9
(ख) मीयादी	2693.7	56.3	2842.7	55.6	3117.0	56.1
6. रिजर्व बैंक से लिये गये उधार	33.5	—	236.5	—	150.5	—

	अप्रैल 1971		जून 1971*		जून 1970	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
	7	8	9	10	11	12
1. बैंक ऋण	4690.3	78.5	4775.8	77.2	4212.7	79.9
2. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	1787.4	29.9	1798.9	29.0	1504.2	28.5
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में	1374.2	23.0	1369.4	22.1	1186.1	22.5
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	413.2	6.9	429.5	6.9	318.1	6.0
3. नकदी और रिजर्व बैंक के पास वकाया	354.4	5.9	393.5	6.4	357.6	6.8
4. बोली और भ्रम्य सूचना पर प्रतिदेय राशि	32.9	—	74.8	—	47.9	—
5. कुल जमा राशियां	5978.7	100.0	6189.9	100.0	5274.5	100.0
(क) मांग	2626.9	43.9	2725.1	44.0	2328.8	44.2
(ख) मीयादी	3351.8	56.1	3464.8	56.0	2945.7	55.8
6. रिजर्व बैंक से लिये गये उधार	190.7	—	207.2	—	291.5	—

नोट :—(1) प्रतिशत कुल जमा राशियों के अनुपात हैं।

(2) ये आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अधीन बैंकों द्वारा भेजी गयी साप्ताहिक विवरणियों पर आधारित हैं, परन्तु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधारों के आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त साप्ताहिक उधार सूचनाओं पर आधारित हैं। सभी आंकड़े महीने के अंतिम शुक्रवार के हैं।

* अन्तिम (आंकड़े 25 जून के हैं)।

वॉरान एक-सी नहीं थी, इस वर्ष के पूर्वार्ध में उनमें 239.8 करोड़ रूपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष के तदनुसूची पूर्वार्ध में हुई 17.1 करोड़ रूपयों की वृद्धि की अपेक्षा काफी अधिक थी परंतु जहाँ पिछले वर्ष के उत्तरार्ध में उनमें 596.8 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई थी वहाँ इस वर्ष के तदनुसूची उत्तरार्ध में 323.3 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई। ऋण-जमा अनुपात जून 1971 के अंत में 77.2 प्रतिशत था जो एक वर्ष पहले के अनुपात (79.9 प्रतिशत) से 2.7 प्रतिशत कम था। 1970-71 में जमाराशियाँ में हुई 915.4 करोड़ रूपयों की कुल वृद्धि में मीथादी जमाराशियाँ का अंश 56.7 प्रतिशत था जब कि वह 1969-70 में हुई कुल वृद्धि का 64.1 प्रतिशत था। अनुसूचित बाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गये निर्वेशों की राशि में 1970-71 में 294.7 करोड़ रूपयों की जो वृद्धि हुई वह 1969-70 में हुई वृद्धि (145.3 करोड़ रूपयें) की दृष्टि से भी अधिक थी। निर्वेश-जमा अनुपात जहाँ 26 जून 1970 को 28.5 प्रतिशत था वहाँ 25 जून 1971 को बढ़कर 29.0 प्रतिशत हो गया। नकदी और रिजर्व बैंक के पास रहनेवाली बकाया राशि में जहाँ पिछले वर्ष 22.7 करोड़ रूपयों की कमी हुई थी वहाँ इस वर्ष उनमें 35.9 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई; परंतु जमाराशियाँ में तेजी से वृद्धि होने के कारण नकदी अनुपात में 0.4 प्रतिशत की कमी हुई अर्थात् वह 6.4 प्रतिशत हो गया। रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों की बकाया राशि 25 जून 1971 को 207.2 करोड़ रूपयें थी जो एक वर्ष पहले के स्तर (291.5 करोड़ रूपयें) से 84.3 करोड़ रूपयें कम थी। फिर भी, समग्र वर्ष में, जमाराशियाँ में वृद्धि होने के बावजूद, बाणिज्य बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए गए उधारों की राशि पिछले वर्ष के तदनुसूची सप्ताहों में लिये गये उधारों की राशि की अपेक्षा अप्रैल 1971 तक लगातार उच्चतर होती रही, यह राशि 19 मार्च 1971 को 443 करोड़ रूपयों के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गयी, किन्तु उसके बाद के सप्ताहों में उसमें कमी होती गयी और वह 1970-71 के अधिक कामकाज के समय के अंत में 190.7 करोड़ रूपयें रह गयी। जहाँ यह राशि 26 जून 1970 को 291.5 करोड़ रूपयें थी वहाँ 25 जून 1971 को 207.2 करोड़ रूपयें थी (सारणी 18)।

98. बंबई में बोली जमा दर जुलाई से दिसंबर 1970 तक की अवधि में 4 और 6 प्रतिशत के बीच विद्यमान थी। किन्तु बैंकों की चलमुद्रा संबंधी स्थिति पर तनाव बढ़ जाने के फलस्वरूप 1971 के प्रारम्भ में उसमें वृद्धि होने लगी और वह फरवरी 1971 के प्रथम सप्ताह में बढ़कर 13 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर तक पहुँच गयी, किन्तु उसके बाद उसमें बराबर कमी होती गयी और 30 अप्रैल 1971 को वह 6½ प्रतिशत रह गयी। जहाँ यह दर जून 1970 के अंत में 6½ प्रतिशत थी वहाँ जून 1971 के अंत में 4½ प्रतिशत थी। परंतु पिछले वर्ष यह दर जुलाई 1969 से जनवरी 1970 तक की अवधि में 3½ और 4½ प्रतिशत के बीच बनी रही थी। किन्तु उसके बाद उसमें बराबर वृद्धि होती गयी और 31 मार्च 1970 को वह 9 प्रतिशत तक पहुँच गयी थी; उसके बाद वह कम होकर 30 अप्रैल 1970 को 6½ प्रतिशत हो गयी। फलतः में यह दर नवम्बर 1970 तक 4½ और 5½ प्रतिशत के बीच विद्यमान थी, जुलाई 1970 से उसमें बराबर वृद्धि होती गयी और फरवरी 1971 में 12 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचने के बाद उसमें कमी होती गयी और 30 अप्रैल 1971 को वह 5½ प्रतिशत हो गयी। पिछले वर्ष उक्त दर में जुलाई 1969 से फरवरी 1970 के अंत तक की अवधि में 3 और 5½ प्रतिशत के बीच घटबढ़ होती रही और बाद में वह बढ़कर 31 मार्च को 9½ प्रतिशत हो गयी और उसके बाद वह घटकर 30 अप्रैल 1970 को 7 प्रतिशत रह गयी। उक्त दर जहाँ पिछले वर्ष के जून के अंत में 5½ प्रतिशत थी वहाँ वह 1971 के जून के अंत में 4½ प्रतिशत थी।

मौसमी प्रवृत्तियाँ

99. 1970 के कम कामकाज के समय के दौरान ऋणों में वस्तुतः कमी का अभाव ही था और वास्तव में बैंकों द्वारा विधेय गये, ऋणों में तीव्र मौसमंतर वृद्धि परिलक्षित हुई, और यद्यपि जमाराशियाँ में काफी वृद्धि हुई थी, फिर भी प्रायः पूरे कम कामकाज के समय के दौरान बैंक संघटन की चलमुद्रा संबंधी स्थिति पर तनाव का अनुभव किया गया था। बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋणों में 1969 के कम कामकाज के समय में भी 31.3 करोड़ रूपयों की मौसमंतर वृद्धि हुई थी परंतु 1970 के कम कामकाज के समय में उनमें 225.6 करोड़ रूपयों की जो वृद्धि हुई वह बहुत ही अधिक थी। मौसमी ऋणों पर दिये जानेवाले अग्रिमों में अपेक्षाकृत थोड़ी सी कमी और मौसमंतर ऋणों पर दिये जानेवाले अग्रिमों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होने के कारण उपर्युक्त वृद्धि हुई। यद्यपि समग्रता की दृष्टि से तथा सापेक्ष दृष्टि से भी जमाराशियाँ में अधिक वृद्धि हुई अर्थात् जहाँ 1969 के कम कामकाज के समय में 348.1 करोड़ रूपयों (7.8 प्रतिशत) की जमाराशियाँ जुटायी गयी थीं वहाँ इस वर्ष के कम कामकाज के समय में 448.6 करोड़ रूपयों (8.8 प्रतिशत) की जमाराशियाँ जुटायी गयीं, फिर भी, 1970 के कम कामकाज के समय के अंत में ऋण-जमा अनुपात 77.0 प्रतिशत था जो कि एक वर्ष पहले के ऋण-जमा अनुपात (72.9 प्रतिशत) से लगभग 4 प्रतिशत अधिक था। बैंकों के वित्तीय साधनों पर बराबर दबाव पड़ता रहा, इसके फलस्वरूप निर्वेशों में अपेक्षाकृत कम राशि लगायी जा सकी अर्थात् जहाँ पिछले कम कामकाज के समय में उक्त राशि 240 करोड़ रूपयें थी वहाँ इस वर्ष वह 188 करोड़ रूपयें थी और रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों की वापसी अदायगी की राशि का अनुपात (36 प्रतिशत) भी 1969 के कम कामकाज के समय में वापस अदा की गयी राशि के अनुपात (68 प्रतिशत) की अपेक्षा कम था।

100. ऋण और मूल्यों की स्थिति को देखते हुए और चौथी योजना में बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अतिरिक्त जमाराशियाँ के एक निश्चित अनुपात का निर्वेश किये जाने की परिकल्पित आवश्यकता के संघर्ष में, गवर्नर ने अगस्त 1970 में बैंकों से यह अनुरोध किया कि वे अपनी आस्तियों में वृद्धि कर ताकि अगस्त 1970 के अन्तिम शुक्रवार से साप्ताहिक चलमुद्रा अनुपात 27 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जायें। इसके साथ साथ, जिस न्यूनतम वास्तविक चलमुद्रा अनुपात के आधार पर बैंक दर पर बैंक उधार प्राप्त कर सकते हैं, उसे भी अगस्त 1970 के अन्तिम शुक्रवार से एक प्रतिशत बढ़ा कर 33 प्रतिशत कर दिया गया। (इसके पूर्व इन अनुपातों में से प्रत्येक में अप्रैल 1970 के अन्तिम शुक्रवार से एक प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी अर्थात् उनका क्रमशः 27 प्रतिशत और 32 प्रतिशत कर दिया गया था)। शंखों पर दिये जानेवाले अग्रिमों का विनियमित करने के लिए कतिपय उपायों की भी घोषणा की गयी ताकि सट्टेबाजों के उद्देश्यों के लिए बैंक विस्तार के उपयोग पर रोक लगायी जा सके। 1969-70 के लिए हंडी बाजार योजना के अधीन दी गयी पुनर्वित्त सुविधाएँ जून 1970 के अंत में समाप्त होनेवाली थीं परन्तु बैंकों द्वारा अग्रतवाले क्षेत्रों को और अनाज की उगाही तथा वितरण संबंधी उद्देश्यों के लिये दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में उक्त सुविधाओं को 30 जून 1970 के बाद भी जारी रखा गया।

1970-71 के अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति

101. इस वर्ष के अधिक कामकाज के समय के प्रारम्भ में ही बैंकों ने रिजर्व बैंक से 150 करोड़ रूपयों के भारी उधार लिये। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। 1970-71 के अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति की घोषणा करते हुए 10 नवम्बर 1970 को गवर्नर ने बैंकों से यह अनुरोध किया कि वे ऋणों की, विशेषकर

अग्रतावाले क्षेत्रों के लिए, बढ़नेवाली मांग की पूर्ति करने के निमित्त जमाराशियों को अधिक मात्रा में जुटाये और उन्होंने बैंकों को यह आश्वासन दिया कि सभी उचित उत्पादक कार्यों के लिये रिजर्व बैंक से बैंकदर/रियायती दर पर पुनर्वित्त सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी। ऋण में होनेवाली वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता को पूर्णतया स्वीकार करते हुए भी आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने और अग्रतावाले क्षेत्रों और पिछड़े प्रदेशों के लिए ऋण की व्यवस्था को बराबर जारी रखने की आवश्यकता को देखते हुए यह समझा गया कि पिछले वर्षों की तुलना में 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में ऋणों में उत्तम वृद्धि होना अपेक्षित है। बैंकों से यह कहा गया कि उनका लक्ष्य यह होना चाहिये कि वह कुछ निश्चित समय के दौरान अग्रतावाले क्षेत्रों को वित्त जाननेवाले ऋणों में होने वाली वृद्धि की पूर्ति भी अपनी जमाराशियों से करें और रिजर्व बैंक से केवल अन्तिम उपाय के रूप में और जहां तक संभव हो, अपेक्षाकृत कम अवधिओं के लिए ही सहायता लें। फिर भी रिजर्व बैंक अक्सर या विशेष रूप से उत्पन्न होनेवाली ऋण संबंधी भारी मांगों के कारण बैंकों पर पड़ने वाले चलमूद्रा संबंधी दबाव को कम करने के लिए योग्य मामलों में विवेकाधीन सहायता प्रदान करता रहेगा।

102. बैंकिंग संघटन को अधिक कामकाज के समय में सामान्य मौसमी कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने पुनर्वित्त संबंधी अपनी पद्धति में कुछ परिवर्तन किये। इस प्रकार, यद्यपि निर्धारित आधार अवधि के दौरान अग्रतावाले क्षेत्रों को दिये जानेवाले अग्रिमों में होनेवाली वृद्धि के संबंध में बैंक दर/रियायती दर पर पुनर्वित्त बराबर प्राप्त होता रहेगा, फिर भी आधार अवधि को ही आगे ले जाया गया और 1970-71 में होनेवाली वृद्धि का हिसाब लगाने के लिए आधार अवधि में परिवर्तन कर उसे पिछले वर्ष (अर्थात् 1968-69 के स्थान पर 1969-70) की तदनुसूची तालिका में विद्यमान ऐसे ऋणों का औसत स्तर कर दिया गया।

103. रिजर्व बैंक ने अगस्त 1970 में ही 1 नवम्बर 1970 से नयी हुई पुनर्भाजन योजना को अमल में लाने की घोषणा कर दी थी। इस योजना से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बैंकिंग संघटन के भीतर की चलमूद्रा संबंधी विषमता को दूर करेगी और उसके कारण रिजर्व बैंक के पास सहायता के लिए आने की बैंकों की प्रवृत्ति कम होगी, बैंक सामान्यतः रिजर्व बैंक के पास तभी सहायता के लिए आएंगे जब समग्र बैंकिंग संघटन के पास निधियों की कमी हो और फलहाल निधियों की आवश्यकता के समय केवल कीतपय बैंक सहायता की जो मांग करते हैं वह भी इससे कम हो जाएगी। उक्त योजना की प्रमुख विशेषताओं और बाद में उसमें किये गये संशोधनों की चर्चा इसके बाद के पैराग्राफों में की गयी है।

104. बैंकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और/या उनके द्वारा अधिकृत एजेंसियों को अनाजों की उगाही/संग्रहण/वितरण के उद्देश्यों के लिए वित्त जाननेवाले अग्रिमों के संबंध में रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की कि 30 अक्टूबर 1970 को विद्यमान ऐसे अग्रिम के वास्तविक स्तर से अधिक जो वृद्धि हो उसके 50 प्रतिशत तक बैंक दर पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा। अप्रैल 1971 में इस पुनर्वित्त-सुविधा को 9 अप्रैल से 30 जून 1971 तक की अवधि के लिए बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया और इस सुविधा को बाद में जुलाई 1971 के अंत तक बढ़ा दिया गया। उक्त सुविधा को अगस्त 1971 के लिए घटाकर ऐसे अग्रिमों में निर्विष्ट आधार तारीख (30 अक्टूबर 1970) के स्तर से अधिक होनेवाली वृद्धि का 60 प्रतिशत और उसके बाद 50 प्रतिशत किया

जानेवाला है। रिजर्व बैंक ने यह भी संकेत किया कि वह बैंकों को योग्य मामलों में बैंक दर पर विवेकाधीन सहायता प्रदान करने पर विचार करेगा ताकि अक्सर या विशेष रूप से उत्पन्न होनेवाली ऋण संबंधी भारी मांग के कारण अलग अलग बैंकों पर पड़नेवाले चलमूद्रा संबंधी दबाव को कम किया जा सके।

105. 1970 के अंत तक ऋणों और मूद्राओं की वृद्धि के कारण मूल्यों की स्थिति पर पड़नेवाले दबाव बढ़ते हुए परिलक्षित हुए। इस प्रकार जहां पिछले अधिक कामकाज के समय के पहले दो महीनों में ऋणों में 123.3 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई थी वहां उनमें 1970-71 के अधिक कामकाज के समय के पहले दो महीनों में 147.3 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई। मूद्रा की उपलब्धि में हुई वृद्धि जहां पिछले वर्ष 647 करोड़ रूपयों थी वहां वह 25 दिसंबर 1970 को समाप्त हुए वर्ष में काफी अधिक अर्थात् 755 करोड़ रूपयों (12 प्रतिशत) थी। दिसंबर 1970 में जो मूल्य स्तर था वह 1969 के तदनुसूची महीने के मुख्य स्तर की अपेक्षा 6.5 प्रतिशत ऊंचा था।

106. बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जानेवाले उधारों में भी वृद्धि हुई थी; जहां 1970 के अधिक कामकाज के समय के प्रारम्भ में इन उधारों की बकाया राशि 150 करोड़ रूपयों थी वहां उसमें दिसंबर 1970 के अंत में 152.2 करोड़ रूपयों की और वृद्धि हुई। यह अनुभव किया गया कि जैसे जैसे अधिक कामकाज का समय आगे बढ़ेगा, यह दबाव भी बढ़ता जाएगा। अतः यह आवश्यक समझा गया कि ऋण की वृद्धि की दर को नियंत्रित किया जाए और साथ साथ बचतों को बढ़ावा देने और जमाराशियों को जुटाने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 9 जनवरी 1971 से बैंक दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया। इसके बाद बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जानेवाले अतिरिक्त उधारों पर वसूल किये जानेवाले ब्याज की दंड दर को निर्धारित करने के उद्देश्य के लिये 29 जनवरी 1971 से न्यूनतम वास्तविक चलमूद्रा अनुपात में 1 प्रतिशत की वृद्धि की गयी अर्थात् उसे 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया। परन्तु बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 24 के उद्देश्य और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 42 के अधीन निर्दिष्ट प्रारक्षित नकदी की अपेक्षाओं के लिये निर्धारित चलमूद्रा अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं किया गया अर्थात् वह 31 प्रतिशत ही बना रहा। बैंकों को यह सलाह दी गयी कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उनके द्वारा दिये जानेवाले अग्रिमों पर लिये जानेवाले ब्याज की दरों का समायोजन करते समय उनका चाहिए कि वे इस बात का सुनिश्चय कर लें कि उनके द्वारा दिये जानेवाले ऋणों पर जो ब्याज लिया जाता है उसकी दरों में औसतन लगभग एक प्रतिशत की ही वृद्धि हो। फिर भी, रिजर्व बैंक अग्रतावाले क्षेत्रों के लिए नियन्त्रित वर्तमान आधार पर पुनर्वित्त प्रदान करता रहा : (1) चाहे वास्तविक चलमूद्रा अनुपात कुछ भी हो, निर्यात ऋण में और चुने हुए जिलों में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को निर्धारित उद्देश्य के लिये बनायी गयी योजना के अनुसार वित्त जाननेवाले ऋण में निर्धारित आधार अवधि के स्तर से अधिक होनेवाली वृद्धि के लिए 45 प्रतिशत पर पुनर्वित्त, (2) चाहे वास्तविक चलमूद्रा अनुपात कुछ भी हो, लघु उद्योगों और क्वकों को वित्त जाननेवाले अस्थावधि ऋणों में निर्विष्ट आधार अवधि के स्तर से अधिक होने वाली वृद्धि और नई हुई पुनर्भाजन योजना के अधीन किये जानेवाले पुनर्भाजन में होनेवाली वृद्धि के लिये बैंक दर पर पुनर्वित्त, और (3) बैंकों द्वारा अनाजों की उगाही संबंधी कार्य-कलापों के लिए वित्त जाननेवाले अग्रिमों के संबंध में 30 अक्टूबर 1970 को विद्यमान ऐसे अग्रिमों के स्तर के 60 प्रतिशत तक के लिए बैंक दर पर पुनर्वित्त।

107. बचतों को प्रोत्साहन देने और जमाराशियों को जुटाने में और सहायता देने के उद्देश्य से, विविध वर्गों की जमाराशियों पर दिये गये व्याज की उच्चतम दरों में वृद्धि की गयी। बचत लेखों के व्याज की दर को 3½ प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया। 15 दिनों से 45 दिनों तक की अवधि की जमाराशियों के व्याज की दर को 1.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.00 प्रतिशत और 46 दिनों से 90 दिनों तक की अवधि की जमाराशियों के व्याज की दर को 2.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.00 प्रतिशत कर दिया गया। एक वर्ष तक की अवधिवाले अन्य विभिन्न वर्गों की जमाराशियों के व्याज की दरों में ½ प्रतिशत की वृद्धि और एक वर्ष और उससे अधिक परन्तु पांच वर्षों तक की अवधियों के विविध वर्गों की जमाराशियों के व्याज की दरों में ½ प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गयी। 5 वर्षों से अधिक अवधियों की जमाराशियों के संबंध में व्याज की अधिकतम दर 7½ प्रतिशत निर्धारित की गयी। छोटे बैंकों को पहले की तरह बड़े बैंकों द्वारा प्रकृत व्याज-दरों से अपेक्षाकृत थोड़ी उंची दर पर व्याज की घोषणा करने की अनुमति दी गयी।

108. निर्दिष्ट पण्यों की पूर्ति और मूल्य की स्थिति में हुए परिवर्तन के संदर्भ में, जहाँ आवश्यक था वहाँ उन पण्यों के संदर्भ में चयनात्मक ऋण नियंत्रणों में भी संशोधन किया गया। इन उपायों के विवरण इस रिपोर्ट के भाग 3 में किये गये हैं।

109. 4 फरवरी 1971 को मुद्रा और ऋण की स्थिति का मध्यावधि पुनरीक्षण करते हुए गवर्नर ने इस बात के लिए संतोष प्रकट किया कि ऋण नियंत्रण के उपायों को और कड़ा कर देने के फलस्वरूप बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋण में होनेवाली वृद्धि की दर कम हो गयी, और रिजर्व बैंक से उनके द्वारा लिये जानेवाले उधारों में भी कमी हो गयी, साथ ही, गवर्नर ने ऋणों पर बराबर नियंत्रण रखने और जमाराशियों को जुटाने में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता पर बल दिया। गवर्नर ने बैंकों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें वर्तमान आधार पर पुनर्वित्त सुविधाएँ प्राप्त होती रहेंगी, परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि बैंक दर पर विवेकाधीन सहायता केवल अपवादात्मक मामलों में प्राप्त हो सकेगी। ऐसी सहायता प्रदान करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा : बैंक द्वारा जमाराशियों को जुटाने के लिए किये गये प्रयत्न, उद्देश्यपूर्ण ऋण आयोजना, अनाज की उगाही संबंधी कार्य-कलापों की वित्तीय सहायता करने के लिए बैंक द्वारा किये गये वायव्य और पिछड़े क्षेत्रों में किये जाने वाले कार्यों के संदर्भ में बैंक के समक्ष उपस्थित समस्याएँ। चूंकि बैंक छोटे ऋण कर्ताओं की बढ़ती हुई मात्रा में सीधे ऋण प्रदान करते हैं अतः गवर्नर ने बैंकों को यह सलाह दी कि वे मुस्तानि हंडीयों का पुनर्भाजन करते समय सराफों द्वारा किये गये ऋणों के उद्देश्य तथा शर्तों की कड़ाई से जाँच करें। बैंकों की ऋण प्रणाली को अधिक उद्देश्य प्रधान बनाने और उसे निर्दिष्ट समयावधि के लिए ऋणकर्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं से संबंध करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, गवर्नर ने 4 फरवरी 1971 की बैठक में बैंकों को यह सलाह दी कि वर्तमान नकद ऋण प्रणाली के स्थान पर क्रमशः हंडीयों और ऋणों की प्रणाली को लागू करने की कार्रवाई करें। नयी हंडी पुनर्भाजन योजना को अधिक व्यापक बना दिया गया है ताकि उसके अंतर्गत अन्य वर्गों की हंडीयों को भी शामिल किया जा सके। उक्त योजना के अधीन पुनर्भाजन सुविधाएँ पूरे वर्ष के दौरान प्राप्त होती रहेंगी और बैंकों द्वारा 30 जून 1971 के बाद पुनर्भाजन की जानेवाली हंडीयों के कारण उनके वास्तविक चलमुद्रा अनुपात पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी। यह भी निश्चय किया गया कि वर्तमान हंडी बाजार योजना को, जिसके अधीन बैंकों की हंडीयों की जमानत पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाता था, 30 जून 1971 से बन्द कर दिया जाए, फिर भी, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, उक्त योजना बैंकों द्वारा

अनाजों की उगाही और वितरण के लिये किये जाने वाले अभिमानों के संबंध में जारी रखी गयी।

110. रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा लिये जानेवाले उतिरिक्त उधारों के लिये फरवरी 1971 में व्याज की अधिकतम 15 प्रतिशत की दृढ़ दर निर्धारित की। अब तक किसी बैंक के वास्तविक चलमुद्रा अनुपात में 34 प्रतिशत से कम होनेवाले एक प्रतिशत या उससे अधिक अंश पर रिजर्व बैंक द्वारा लिये जानेवाले व्याज की दृढ़ दर में बैंक दर के ऊपर 1 प्रतिशत की वृद्धि की जाती थी जब बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जानेवाले उधारों की राशि इस सीमा तक बढ़ जाए कि उनका वास्तविक चलमुद्रा अनुपात 28 प्रतिशत से कम हो जाए तब 15 प्रतिशत की उक्त उच्चतम सीमा के कारण बैंकों को राहत मिलेगी। साथ ही, अपवादात्मक मामलों में विवेकाधीन सहायता प्रदान करने के लिये भी कीतिपत्र सुरक्षात्मक व्यवस्थाएँ की गयीं।

111. समग्र वर्ष में 4½ प्रतिशत की दर पर तथा बैंक दर पर उपलब्ध होने वाले पुनर्वित्त की राशि के संबंध में अनिश्चितता की मात्रा को कम करने की दृष्टि से और बैंकों द्वारा मंजूर किये जानेवाले निर्यात ऋणों की व्याज दर पर लागू की गई 6 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के संदर्भ में निर्यात ऋण पर दी जानेवाली पुनर्वित्त सुविधाओं के आधार का पुनरीक्षण फरवरी 1971 में किया गया। परिशीलित व्यवस्था के अनुसार, वास्तविक चलमुद्रा अनुपात पर ध्यान किये बिना, 1970 में किये गये निर्यात ऋण के वार्षिक औसत के 10 प्रतिशत के बराबर की राशि तक 4½ प्रतिशत की रियायती दर पर और साथ ही निर्यात ऋण के वार्षिक औसत के 10 प्रतिशत तक की उतिरिक्त राशि तक बैंक दर पर पुनर्वित्त प्राप्त कराया जा सकता था। फिर भी, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा निर्यात ऋण पर लिये जानेवाले व्याज की दरों के स्वरूप में उचित समानता लाने की दृष्टि से आस्थायित अदायगी की शर्तों पर निर्यात करनेवालों के किये जानेवाले ऋण को छोड़कर अन्य पातल-दानपूर्व (पीएफए ऋण) और पातलदानांतर ऋणों के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने निर्यात ऋण पर लिये जानेवाले व्याज की उच्चतम वार्षिक दर को 17 अप्रैल 1971 से 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया। आस्थायित अदायगी की शर्तों पर किये जानेवाले निर्यातों पर किये जानेवाले निर्यात ऋणों से संबंधित व्याज की अधिकतम दर 6 प्रतिशत ही रही और निर्यात ऋण (व्याज उपदान) योजना के अधीन सभी निर्यात ऋणों पर दिया जानेवाला उपदान पहले की तरह 1.5 प्रतिशत ही रहा।

112. 17 अप्रैल को यह निश्चय किया गया कि हंडी पुनर्भाजन योजना के अधीन पुनर्भाजन के लिये प्रस्तुत की जानेवाली प्रत्येक हंडी की न्यूनतम राशि को 10,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दिया जाए, परन्तु किसी बैंक द्वारा पुनर्भाजन किये जाने के लिए एक समय पर प्रस्तुत की गयी हंडीयों का मूल्य पहले की तरह 50,000 रुपये से कम नहीं होगा।

1970-71 के अधिक कामकाज के समय में बैंक व्यवसाय की प्रवृत्तियाँ

113. जहाँ बैंकों द्वारा किये गये ऋणों में पिछले अधिक कामकाज के समय में 562.9 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी वहाँ 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में 409.2 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में जो कम वृद्धि हुई वह रिजर्व बैंक द्वारा 1971 के प्रारम्भ में किये गये ऋण नियंत्रण संबंधी उपायों के कारण हुई। 30 अक्टूबर 1970 और जनवरी 1971 के पहले सप्ताह (बैंक दर में वृद्धि किये जाने के तमिक पूर्व) के बीच

सारणी 21—बैंक ऋण की मौसमी प्रवृत्तियाँ : प्रतिभूतिवार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये में)

	अधिक कामकाज का समय	कम कामकाज का समय		अप्रैल के मध्य तक अधिक कामकाज का समय	
	1968-69	1969	1970	1969-70	1970-71†
मौसमी अग्रिमः	+ 206.8	—192.0	—172.9	+ 116.3	+ 199.1
धान और चावलः	+ 41.1	—29.0	—31.1	—6.8	+ 20.7
गेहूँ	—33.7	+ 14.4	+ 14.5	—59.5	—6.6
अन्य अनाज	+ 9.0	—3.1	—30.9	+ 2.1	+ 14.1
बीनी	+ 98.9	—44.6	—49.9	+ 85.7	+ 73.6
गुह	+ 3.7	—3.6	—3.8	+ 3.6	+ 6.4
मूंगफली	+ 11.8	—13.7	—10.2	+ 12.2	+ 8.3
अन्य तिलहन	+ 13.9	—17.0	—11.3	+ 9.0	+ 7.3
वनस्पति	+ 1.6	—10.2	—8.9	+ 12.4	+ 15.3
हई और कपास	+ 68.1	—86.9	—53.7	+ 54.9	+ 63.9
पटसन	+ 1.0	—6.1	—9.8	+ 14.4	+ 8.2
चाय	—8.6	+ 7.8	+ 22.2	—11.7	—12.1
मौसमेतर अग्रिमः	+ 131.4	+ 185.0	+ 382.4	+ 318.8	+ 105.2
सूती वस्त्र	+ 0.5	+ 1.0	—4.3	+ 39.2	+ 36.5
जूट के बने वस्त्र	+ 6.1	—0.8	+ 11.0	+ 9.9	—6.0
लोहा, इस्पात और इंजीनियरी सामान*	—12.7	+ 44.9	+ 49.6	+ 83.8	+ 43.1
रासायनिक पदार्थ, रंग, पेंट, दवाइयाँ और औषधियाँ‡	+ 48.2	+ 7.4	—3.5	—14.6	+ 40.4
बिजली के सामान	—6.7	+ 18.4	अनु.	अनु.	अनु.
औद्योगिक संस्थाओं की आस्तियाँ—बल या अचल	+ 4.7	+ 10.3	+ 8.0	+ 19.0	+ 11.9
मिश्रित पूंजी कंपनियों के शेयर ¶	+ 3.0	—1.5	—3.0	+ 2.3	—4.1
सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियाँ	—1.7	+ 0.6	अनु.	अनु.	अनु.
सोने और चांदी के बुलियन और गहने	+ 1.5	+ 8.4	अनु.	अनु.	अनु.
कुल जमानती अग्रिम	+ 338.2	—7.0	+ 209.5	+ 435.1	+ 304.3
नेर जमानती अग्रिम	+ 55.8	+ 25.2	+ 19.0	+ 73.7	+ 120.5
कुल अग्रिम	+ 394.0	+ 18.0	+ 228.5	+ 508.8	+ 424.8

† बैंकों की चुनी हुई शाखाओं से प्राप्त अप्रैल 1971 के मध्य की विवरणियों पर आधारित अनुमान।

‡ इनमें चाय के बागानों से हतर बागान शामिल नहीं हैं।

‡ इनमें चाय के बागानों से हतर बागान शामिल हैं।

* इनमें यातों पर दिये गये अग्रिम शामिल हैं।

‡ इनमें उर्वरकों पर दिये गये अग्रिम शामिल हैं।

अनु.—अनुपलब्ध।

स्रोत : जमानत के अनुसार वर्गीकृत बैंकों के अग्रिमों का पाक्षिक/मासिक सर्वेक्षण। ये आंकड़े केवल रिपोर्ट देनेवासी शाखाओं से संबंधित हैं, अतः वे सारणी 19 में दिये गये आंकड़ों से मेल नहीं खाते।

सारणी 22—अनुसूचित बाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि, लघु क्षेत्र और निर्यातों के लिए दिए गए ऋण

(राशि करोड़ रुपये में)

(लेखों की संख्या हजारों में)

	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंक		14 राष्ट्रीयकृत बैंक		सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक		अन्य अनुसूचित बाणिज्य बैंक		जोड़	
	लेखों की संख्या*		लेखों की संख्या*		लेखों की संख्या*		लेखों की संख्या*		लेखों की संख्या*	
	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम
	संख्या*	रकम	संख्या*	रकम	संख्या*	रकम	संख्या*	रकम	संख्या*	रकम
1. कृषि ऋणों का जोड़										
जून 1970	240	141.91	392	159.73	632	301.64	210	40.13	842	341.77
मार्च 1971	280	142.97	521	194.57	801	337.54	255	40.98	1056	378.52
उनमें से ऋणों को सीधे दी गयी वित्तीय सहायता										
जून 1970	239	55.51	374	104.87	613	160.38	205	23.60	818	183.98
मार्च 1971	279	72.01	505	134.72	784	206.73	247	28.35	1031	235.08
2. लघु क्षेत्र को दिए गए ऋणों का जोड़										
(क+ख+ग)										
जून 1970	42	167.79	45	226.96	87	394.74	9	50.83	96	445.57
मार्च 1971	52	204.83	60	278.13	112	482.96	11	60.81	123	543.77
(क) सड़क और जल परिवहन बालक										
जून 1970	2	4.55	9	19.86	11	24.41	2	6.22	13	30.63
मार्च 1971	4	7.86	16	31.48	20	39.34	3	8.12	23	47.46
(ख) लघु उद्योग										
जून 1970	40	163.24	36	206.32	76	369.56	8	44.49	84	414.05
मार्च 1971	48	196.97	44	243.55	92	440.52	8	52.62	100	493.14
(ग) औद्योगिक आस्थानों की स्थापना										
जून 1970	—	—	—	0.77	—	0.77	—	0.12	—	0.89
मार्च 1971	—	—	—	3.10	—	3.10	—	0.07	—	3.17
3. निर्यात										
जून 1970	—	92.02	—	158.04	—	250.06	—	70.44	—	320.49
मार्च 1971**	—	103.37@]	—	172.58†	—	276.95	—	86.46	—	363.41†

नोट : ये आंकड़े महीने के अन्तिम शुक्रवार के हैं।

* ये आंकड़े मद संख्या 2 (लघु क्षेत्र) के संदर्भ में यूनिटों की संख्या से संबंधित हैं।

** अग्रान्तिम।

@ इनमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अग्रान्तिम आंकड़े शामिल हैं।

† इनमें पंजाब नेशनल बैंक के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत : बैंकों से प्राप्त विशेष विवरणियां।

की अवधि में बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में 285 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 241 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी और उसके बाद की अवधि में 144 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जब कि पिछले अधिक कामकाज के समय की तदनुसूची अवधि में 322 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी।

114. अनाजों की उगाही संबंधी कार्यकलापों के लिये दिये गये अग्रिमों में जहाँ पिछले अधिक कामकाज के समय में 27.3 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी वहाँ उन में इस वर्ष के अधिक कामकाज के समय में 77 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई या उक्त वृद्धि कुल बैंक ऋण में हुई 380 करोड़ रुपयों की वृद्धि का लगभग पाँचवाँ हिस्सा थी। इसके विपरीत, अन्य उद्देश्यों के लिये दिये गये बैंक ऋण में जहाँ पिछले अधिक कामकाज के समय में 590.2 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी वहाँ इस वर्ष अपेक्षाकृत कम अर्थात् 302.9 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई।

115. 1970-71 के अधिक कामकाज के समय (16 अप्रैल 1971 तक) में बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों (अनुमानों के आधार पर) का जमानतवार विश्लेषण करने पर यह पता लगता है कि इस वर्ष अनाजों पर दिये गये अग्रिमों में वृद्धि (28 करोड़ रुपये) हुई जब कि पिछले अधिक कामकाज के समय की तदनुसूची अवधि में उनमें कमी (64 करोड़ रुपये) हुई थी। चीनी, तिलहन और पटसन आदि अन्य मौसमी पण्यों पर दिये गये अग्रिमों में जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक कामकाज के समय में वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। गेहूँ और वनस्पति तेलों पर दिये गये अग्रिमों में भारी वृद्धि हुई और चाय पर दिये गये अग्रिमों में प्रायः उतनी ही कमी हुई जितनी पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई थी। मौसमंतर अग्रिमों में, जहाँ पिछले अधिक कामकाज के समय में रासायनिक पदार्थों, रंग आदि पर दिये गये अग्रिमों में कमी हुई थी वहाँ उनमें इस वर्ष की तदनुसूची अवधि में भारी वृद्धि हुई; सूती वस्त्रों और लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं और औद्योगिक संस्थाओं की आस्तियों पर दिये गये अग्रिमों में जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी और जूट के वस्त्रों पर दिये गये अग्रिमों में जहाँ पिछले अधिक कामकाज के समय में वृद्धि हुई थी वहाँ इस वर्ष उनमें कमी हुई। औद्योगिक संस्थाओं के शायरों पर दिये गये अग्रिमों में इस वर्ष कमी हुई जब कि पिछले अधिक कामकाज के समय में उनमें सामान्य वृद्धि हुई थी। जमानती अग्रिमों में पायी गयी प्रवृत्ति के विपरीत गैर जमानती अग्रिमों में काफी वृद्धि हुई। गैर जमानती अग्रिमों में हुई वृद्धि का अधिकांश भाग अनाजों की उगाही संबंधी कार्य कलापों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्मिलित होने से जुलाई 1970 के बाद अपनायी गयी संगठन प्रणाली के कारण उत्पन्न हुआ। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखे गये मीयादी वचनपत्रों के बदले अग्रिम प्रदान किये थे और इसलिए उन अग्रिमों को गैर जमानती अग्रिमों के अधीन दर्शाया गया। इसके विपरीत, इसके पहले के वर्षों में इन अग्रिमों को द्रष्टव्य रखे गये स्टार्कों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों के रूप में दर्शाया गया था।

116. 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियाँ में 421.1 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई वृद्धि की अपेक्षा 100.2 करोड़ रुपये अधिक थी। इसके फलस्वरूप, अप्रैल 1971 के अन्त में 78.5 प्रतिशत का जो ऋण-जमा

अनुपात था वह एक वर्ष पहले के अनुपात की अपेक्षा 0.9 प्रतिशत कम था। 1970-71 के अधिक कामकाज के समय में मीयादी जमाराशियों में जो वृद्धि (235 करोड़ रुपये) हुई वह पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई वृद्धि की तुलना में काफी अधिक (86 करोड़ रुपये) थी। यह वृद्धि संभवतः जमाराशियों पर दिये गये ऋण की दरों में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक की गयी वृद्धि के कारण हुई। मांग जमाराशियों में भी जो वृद्धि (186 करोड़ रुपये) हुई वह पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई वृद्धि की अपेक्षा 14 करोड़ रुपये अधिक थी। अप्रैल 1971 के अंत में कुल जमाराशियों में इन दो वर्गों का हिस्सा वही था जो अप्रैल 1970 में था अर्थात् कुल जमाराशियों में मांग और मीयादी जमाराशियों के हिस्से क्रमशः 44 और 56 प्रतिशत थे।

117. जमाराशियों में हुई उक्त वृद्धि के बावजूद, 1970-71 के अधिक कामकाज के समय के दौरान वाणिज्य बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ली गयी सहायता की राशि पिछले अधिक कामकाज के समय की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ही रही, फिर भी, इस वर्ष के अधिक कामकाज के समय के अंत में उक्त राशि का स्तर (190.7 करोड़ रुपये) एक वर्ष पहले के स्तर (238.5 करोड़ रुपये) की तुलना में बहुत ही कम था। अधिक कामकाज के समय का प्रारंभ ही रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों की 150.5 करोड़ रुपयों की राशि से हुआ जो बहुत ही अधिक थी। इसके बाद उक्त उधारों की राशि में लगातार वृद्धि होती रही और 19 मार्च, 1971 को वह 443 करोड़ रुपयों के सर्वाधिक स्तर पर पहुँच गयी, किन्तु इसके बाद के सप्ताहों में वह कम होकर 30 अप्रैल 1971 को 191 करोड़ रुपये रह गयी। 1970-71 के अधिक कामकाज के समय के अन्त में उक्त उधारों का जो स्तर था वह अक्टूबर, 1970 के अन्त के स्तर से 40 करोड़ रुपये उँचा था। यह स्तर पिछले अधिक कामकाज के समय में हुई 203 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में काफी अच्छा था। 1970-71 के अधिक कामकाज के समय के दौरान सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों में 114.2 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जब कि 1969-70 के अधिक कामकाज के समय के दौरान 53.8 करोड़ रुपयों के निवेश हटा लिए गए थे; इस कारण जमाराशियों में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों का अनुपात जहाँ अप्रैल, 1970 के अन्त में 28.8 प्रतिशत था जहाँ अब अप्रैल, 1971 में बढ़कर 29.9 प्रतिशत हो गया। चलभद्रा संबंधी अपेक्षाओं में जो वृद्धि की गयी उसके फलस्वरूप अपने वित्तीय साधनों के सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों में से हटाकर बैंक ऋण के रूप में परिवर्तित करने की वाणिज्य बैंकों की क्षमता पर संभवतः अंकुश लग गया था। नकदी और रिजर्व बैंक के पास रहनेवाली बकाया राशि में पिछली अवधि में हुई वृद्धि (7.7 करोड़ रुपये) की तुलना में इस वर्ष सामान्य वृद्धि (7.9 करोड़ रुपये) हुई।

118. जैसे कि पहले चर्चा की गयी है, ऋण के लिए बढ़ती हुई मांग के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त सूविधाओं में की गयी कमी का स्वाभाविक परिणाम बोली जमा बाजार की प्रवृत्ति में देखा गया। रिजर्व बैंक ने बोली जमा बाजार को व्यापक बनाने के लिए नवंबर 1970 में जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट को उनकी अपनी अधिशेष निधियों को बोली और अल्प सूचना पर प्रतिद्वंद्व राशि के रूप में बैंकों में रखने की अनुमति दी। इसके पहले रिजर्व बैंक ने सितंबर, 1970 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोली जमा बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। अब तक ऋणकर्ताओं के रूप में ही कार्य करने वाले स्टेट बैंक के सहायक बैंकों को भी ऋणदाताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गयी ताकि वे अपनी अधिशेष निधियों को अन्तर्-बैंक बोली जमा बाजार में लगा सकें।

निर्धारित विस्तार

119. चाहे बैंकों का वास्तविक चलमुद्रा अनुपात कुछ भी हो, रिजर्व बैंक उनके द्वारा दिये जानेवाले निर्यात ऋण के लिए उन्हें रियायती दर/बैंक दर पर पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करते हुए निर्यातों को जो अधिमान दिया करता था उसे रिजर्व बैंक ने इस वर्ष भी बराबर जारी रखा। जून 1971 के अंतिम शुक्रवार को निर्यातों के लिए दिये जानेवाले बैंकिंग ऋण और पोतलदानोत्तर ऋण के लिए प्रदान किये गये पुनर्वित्त के संदर्भ में क्रमशः 35.5 करोड़ रुपये और 36.6 करोड़ रुपये बकाया थे। यद्यपि पुनर्वित्त का स्तर एक वर्ष पहले के स्तर की अपेक्षा बहुत कम था, फिर भी पुनर्वित्त की कुल राशि में निर्यातों के लिए प्रदान किये गये पुनर्वित्त की राशि का अंश 35 प्रतिशत के आसपास रहा। परंतु इस वर्ष के अधिक कामकाज के समय के दौरान बकाया राशियाँ बराबर पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक रही और 356 करोड़ रुपयों के कुल ऋणों में से निर्यात ऋण के लिए प्रदान किये गये पुनर्वित्त की राशि 2 अप्रैल, 1971 को 134 करोड़ रुपयों के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गयी।

120. अपने द्वारा दिये गये निर्यात ऋण के संबंध में बैंक भी बराबर व्याज उपदान प्राप्त करते रहे। आलोच्य अवधि में 45 योग्य वाणिज्य बैंकों से दावे प्राप्त हुए और उनको कुल 4.09 करोड़ रुपयों की राशि अदा की गयी। इस राशि में से 2.19 करोड़ रुपये और 1.90 करोड़ रुपये क्रमशः पोतलदान-पूर्व ऋण और पोतलदानोत्तर ऋण के सम्बन्ध में उपदान के रूप में दिये गये थे।

121. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा निर्यातों को दिये गये अग्रिमों के उपलब्ध आँकड़ों से यह पता चलता है कि निर्यात ऋण में लगभग वृद्धि होती रही और वह जहाँ मार्च 1970 के अन्त में 321.93 करोड़ रुपये था वहाँ वह बढ़कर मार्च 1971 के अंत में 363.41 करोड़ रुपये हो गया, निर्यात ऋण की इस कुल राशि का लगभग तीन चौथाई अंश 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक समुदाय द्वारा दिया गया था।

122. निर्यात ऋण के संदर्भ में किये गये ऋण-नीति संबंधी प्रमुख उपायों का उल्लेख स्पष्ट रूप से पहले ही किया जा चुका है। क्रियाविधि के संदर्भ में जो छूट दी गयीं उनमें रिजर्व बैंक द्वारा नवम्बर, 1970 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दी गयी सलाह महत्वपूर्ण थी। उक्त सलाह यह भी कि जहाँ तक निर्यात ऋणों का संबंध है, निर्यातक-ऋणकर्ताओं के संदर्भ में ऋण-युंजी (चुक्ता पूँजी-मुक्त प्रारक्षित निधि) अनुपात संबंधी मानक में गुणवत्ता के आधार पर छूट दी जाए और इस अनुपात का हिसाब लगाते समय आस्थगित अदायगी के आधार पर किये जानेवाले निर्यातों के संबंध में लिये गये मीयादी ऋण के अधीन प्राप्य राशि को शामिल न किया जाए।

कृषि और लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम

123.14 प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यह भी था कि अब तक के उप-क्षिप्त क्षेत्रों को बराबर ऋण प्राप्त होने की व्यवस्था की जाए। तदनुसार, वाणिज्य बैंकों की नीतियों का निर्धारण करते समय छोटे ऋणकर्ताओं की सहायता करने के प्रश्न को अत्यंत प्राथमिकता दी गयी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा इस विधा में की गयी प्रगति उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर सारणी 23 में दिखायी गयी है। जून 1970 और मार्च 1971 के बीच कृषि संबंधी उधार खातों की संख्या 8.4 लाख से बढ़कर 10.6 लाख और लघु उद्योगों के संबंध में ऋणकर्ता यूनिटों की संख्या 0.8 लाख से बढ़कर 1.0 लाख और ऋण प्राप्त करनेवाले सड़क तथा जल परिवहन चालकों की संख्या 18,000 से बढ़कर 23,000 हो गयी। इसी अवधि में अग्रिमों की बकाया राशि कृषि के मामले में 342 करोड़ रुपयों से बढ़कर 379 करोड़ रुपये, लघु उद्योगों के मामले में 414 करोड़ रुपयों से बढ़कर 493 करोड़ रुपये और सड़क परिवहन चालकों के मामले में 31 करोड़ रुपयों से बढ़कर 47 करोड़ रुपये हो गयी। जून 1970 के अंत से मार्च 1971 के अंत तक की अवधि के बीच सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों में कृषि को दिये गये अग्रिमों का अनुपात 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 8.2 प्रतिशत, लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों का अनुपात 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 10.6 प्रतिशत और निर्यातों के मामले में दिये गये अग्रिमों का अनुपात 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गया।

124. समाज के कमजोर क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जो प्रगति की है वह उधार खातों की संख्या और फुटकर व्यापार तथा छोटे कारोबार, स्वनिर्वाह तथा व्यावसायिक व्यक्तियों को और शिक्षा के लिए दिये गये बैंक अग्रिमों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि से परिलक्षित होती है। जून 1970 से मार्च 1971 तक की अवधि के बीच फुटकर व्यापारियों और छोटे कारोबार से संबंधित उधार खातों की संख्या 0.9 लाख से बढ़कर 1.1 लाख, व्यावसायिक और स्वनिर्वाह व्यक्तियों के उधार खातों की संख्या 28,000 से बढ़कर 38,000 और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिये गये उधारों के खातों की संख्या 5,000 से बढ़कर 7,000 हो गयी। उसी अवधि में फुटकर व्यापार और छोटे कारोबार को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि 43 करोड़ रुपयों से बढ़कर 53 करोड़ रुपये हो गयी। व्यावसायिक और स्वनिर्वाह व्यक्तियों के कुल 8 करोड़ रुपयों के अग्रिम दिये गये जब कि जून, 1970 में उक्त अग्रिमों की राशि केवल 6 करोड़ रुपये थी। शिक्षा के लिए दिये गये अग्रिमों की राशि जहाँ जून 1970 में 2.1 करोड़ रुपये थी वहाँ वह मार्च 1971 में 3.7 करोड़ रुपये थी। (सारणी 23)।

सारणी 23-14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 'ग्रन्थ क्षेत्र' को दिये गये अग्रिम

	जून 1970		मार्च 1971	
	लेखों की संख्या (हजारों में)	रकम (लाख रुपयों में)	लेखों की संख्या (हजारों में)	रकम (लाख रुपयों में)
फुटकर व्यापार और छोटे कारोबार	88	4282	107	5279
व्यावसायिक और स्वनिर्वाह व्यक्तियों	28	617	38	818
शिक्षा	5	205	7	372

125. बैंकों की विशेष ऋण योजनाओं का, उनकी नियोजन-क्षमता के विशेष संदर्भ में पुनरीक्षण करने के लिए श्री. पी. डी. ठक्कर की अध्यक्षता में जुलाई 1970 में एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, रिजर्व बैंक ने मार्च 1971 में सभी वाणिज्य बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे (उनके विवरण इस रिपोर्ट के भाग 3 में किये गये हैं)। साथ ही, ऋणों की गुणवत्ता में सुधार लाने और छोटे तथा संभाव्य रूप से सक्षम कृषकों को उत्तुल्य ढंग से विकास करने के निमित्त सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों के नाम दिसंबर 1970 में कृषि विकास के पितृपाषण के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रदान करते हुए एक परिपत्र भेजा। विरोधक व्याज वृत्तों के प्रश्न का परीक्षण करने के लिए सितम्बर 1970 में गठित की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट जून 1971 में प्रस्तुत की। (विवरण के लिए भाग 3 देखें) अप्रत्याशित और अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण किये जाने के लिए एक व्यापक ऋण गारंटी योजना को कार्यान्वित करने के निमित्त ऋण गारंटी निगम की स्थापना की गयी। उक्त योजना अप्रैल 1971 में अमल में आयी और उसके अंतर्गत परिवहन चालकों, व्यापारियों, स्वनिर्धारित व्यक्तियों, कारोबारी उद्यमों के नातिकाओं और कृषकरी में लगे हुए कृषकों आदि को प्रदान की जानेवाली ऋण सुविधाएँ (कुछ सीमाओं तक) आती हैं।

हुंडी पुनर्भाजन योजना

126. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने फरवरी 1970 में ऋण प्रपत्र के रूप में विनियम बिल के उपयोग को व्यापक बनाने और भारत में एक हुंडी बाजार का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया था। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट जून 1970 में प्रस्तुत की। उक्त दल ने यह सिफारिश की कि रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह ऋण-प्रपत्र के रूप में विनियम बिल के उपयोग को प्रोत्साहित कर भारत में हुंडी बाजार के निर्माण की दिशा में कदम उठाये। अध्ययन दल के अनुसार, वास्तविक हुंडी बाजार का निर्माण किये जाने से मुद्रा बाजार में लचीलापन आयेगा, बैंक संगठन के भीतर की चल-मुद्रा की स्थिति में समानता आयेगी और रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार पर अधिक प्रभावशाली नियंत्रण रख सकेगा।

127. रिजर्व बैंक ने अध्ययन दल की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार किया और नवम्बर 1970 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(2) (क) के अनुसार एक नयी हुंडी पुनर्भाजन योजना अमल में लायी गयी। योजना की प्रमुख विशेषतायें उसमें किये गये संशोधनों के साथ नीचे दी गयी हैं :

- (1) सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी लाइसेंसीकृत अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक के पास विनियम बिलों के पुनर्भाजन के लिए प्रस्तुत करने के पात्र होंगे ;
- (2) उक्त योजना के अधीन केवल वे वास्तविक व्यापारिक बिल आधे जो माल की बिक्री के प्रमाण हों ,
- (3) बिल खरीदार के बैंक के नाम जारी किया जाना और उसके द्वारा वह बिल स्वीकार किया जाना चाहिए और जहाँ खरीदार का बैंक लाइसेंसीकृत अनुसूचित बैंक न हो वहाँ उस बैंक के अतिरिक्त उक्त बिल पर किसी लाइसेंसीकृत अनुसूचित बैंक के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, बिल खरीदार तथा खरीदार के बैंक के नाम संयुक्त रूप

से भी जारी किया जा सकता है और उनके द्वारा संयुक्त बिल स्वीकार भी किया जा सकता है ;

- (4) सामान्यतः बिल की मीमांसा अधिक से अधिक 90 दिनों की होनी चाहिए और अपवादात्मक मामलों में उसकी मीमांसा 120 दिनों तक की जा सकती है , किन्तु शर्त यह है कि जब उक्त बिल को पुनर्भाजन के लिए रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत किया जाए उसके समाप्त होने की अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए ;
- (5) बिल पर कम से कम दो खरे हस्ताक्षर होने चाहिए ;
- (6) इस योजना में वे विनियम बिल शामिल नहीं किये जाएंगे जो रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर सूचित किये जानेवाले पण्यों की शर्तियों से संबंधित हों ;
- (7) फिलहाल उक्त पुनर्भाजन सुविधाएँ बंबई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में स्थित रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही उपलब्ध होंगी, और
- (8) अनेक छोटे छोटे बिलों के पुनर्भाजन से बचने के लिए ऐसे बिलों को एकत्रित कर एक साथ दिया जाना चाहिए। पुनर्भाजन के लिए प्रस्तुत किये जानेवाले किसी भी एक बिल की राशि 5,000 रूपयों से कम नहीं होनी चाहिए और एक समय पर प्रस्तुत किये गये बिलों का कुल मूल्य 50,000 रूपयों से कम नहीं होना चाहिए।

128. रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए ऐसे बिलों का पुनर्भाजन कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। इस योजना के अधीन बैंकों को पुनर्भाजन सुविधाएँ पूरे वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी जाती हैं और 30 जून, 1971 के बाद बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक में पुनर्भाजन किये गये बिलों के कारण बैंक दर पर पुनर्भाजन प्राप्त करने की बैंकों की पात्रता पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी, भले ही उनकी चलमुद्रा संबंधी स्थिति कुछ भी हो। रिजर्व बैंक के पास रखे गये ऐसे विनियम बिलों की बकाया राशि 28 मई, 1971 को 16.73 करोड़ रूपयों के सर्वाच्चस्तर पर पहुँच गयी थी और 25 जून, 1971 को वह 10.39 करोड़ रूपयों थी।

सहभागिता प्रमाणपत्र

129. इस अवधि में वाणिज्य बैंक व्यवसाय की एक उल्लेखनीय गतिविधि यह भी कि कतिपय बैंकों ने सहभागिता प्रमाणपत्रों की एक योजना प्रारंभ की। सहभागिता प्रमाणपत्र एक ऐसा प्रपत्र है जिसके द्वारा कोई बैंक अपने द्वारा किसी ग्राहक (ऋणकर्ता) को दिये गये पूरे ऋण को या उसके किसी अंश को किसी तीसरी पार्टी (अंतरी) को बंध सकता है। सहभागिता प्रमाणपत्रों को अमल में लाने के पीछे यह उद्देश्य है कि निधिधियों के उपयोग को अधिक व्यापक बनाया जा सके, रिजर्व बैंक से ली जानेवाली वित्तीय सहायता कम की जा सके और उपलब्ध वित्तीय प्रपत्रों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सके। इस योजना के द्वारा वित्तीय संस्थाओं को ध्याज की आकर्षक दर पर अल्पावधि निवेश की आसक्ति प्राप्त होती है और उक्त योजना नई हुंडी बाजार योजना (जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है) के लिए उपयोगी सहायक योजना है। चूंकि सहभागिता प्रमाणपत्र केवल वित्तीय संस्थाओं को जारी किये जाते हैं, अतः ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने से बैंकों को उपलब्ध होनेवाली निधियाँ अन्तर सांस्थानिक लेनदेनों की दायक हैं। सहभागिता प्रमाणपत्रों के द्वारा बैंकों के लिए यह संभव होता है कि वे अन्य वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय अधिशेषों को 6 महीनों तक की अवधि के लिए माफ कर सकें।

सारणी 24—भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों, जमाराशियों और ऋणों में वृद्धि

(करोड़ रुपये में)

कार्यालय (संख्या)	जमाराशियों (अंतर बैंक जमाराशियों को छोड़कर)					ऋण (अंतर बैंक ऋण को छोड़कर)				
वर्ष	वार्षिक वृद्धि	मांग जमा राशियाँ	मीयादी जमा राशियाँ	कुल जमा राशियाँ	वार्षिक वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	बैंक ऋण	वार्षिक वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	
जून 1965 के अंत में	5727	+ 498	1275.1	1433.0	2708.1	+ 323.4	+ 13.6	2068.4	+ 294.6	+ 16.6
जून 1966 के अंत में	6139	+ 412	1477.3	1645.9	3123.2	+ 415.1	+ 15.3	2271.4	+ 203.0	+ 9.8
जून 1967 के अंत में	6620	+ 481	1664.6	1852.4	3517.0	+ 393.8	+ 12.6	2631.1	+ 359.7	+ 15.8
जून 1968 के अंत में	7044	+ 424	1874.8	2094.2	3969.0	+ 452.0	+ 12.9	3102.9	+ 471.8	+ 17.9
जून 1969 के अंत में	8045	+ 1001	2103.5	2542.3	4645.8	+ 676.8	+ 17.0	3598.8	+ 495.9	+ 16.0
जून 1970 के अंत में	9938	+ 1893	2328.8	2945.7	5274.5	+ 628.7	+ 13.5	4212.7	+ 613.9	+ 17.1
जून 1971 के अंत में*	11892	+ 1954	2725.1	3464.8	6189.9	+ 915.4	+ 17.4	4775.8	+ 563.1	+ 13.4

*अनन्तिम (25 जून, 1971 को)

नोट : कार्यालयों की संख्या को छोड़कर, उपर्युक्त आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) के अधीन बैंकों द्वारा भेजी गयी साप्ताहिक विवरणियों पर आधारित हैं।

सहस्रभागिता प्रमाणपत्र जारी करने वाला बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, एक ऐसी प्रमुख एजेंसी की भूमिका अदा कर सकता है जो अकेले ही ग्राहक के साथ लेन-देन करती है और इस प्रकार उसे एक ही समय पर कई ऋणदाता एजेंसियों के साथ लेन-देन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत में कारोबार करनेवाले कीसपय भारतीय और विदेशी बैंकों ने वित्तीय संस्थाओं अर्थात् बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, बीमा कंपनियों और भारत में निर्गमित इसी प्रकार की अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे संस्थाओं को सहभागिता प्रमाणपत्र जारी किये हैं। फिलहाल अब तक अनुमोदित की गयी यांजनाएँ केवल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। सहभागिता प्रमाणपत्रों के संदर्भ में 30 जून, 1971 को 15.43 करोड़ रुपये बकाया थे।

130. मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों से संबंधित ऋण प्रपत्रों के संदर्भ में एक बाजार का निर्माण करने की संभावना और ऐसे बाजार के निर्माण से उत्पन्न होनेवाली परिस्थितियों का परीक्षण करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 1970 में मीयादी ऋणों की सहभागिता व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1971 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि मीयादी ऋणों के प्रपत्रों के संदर्भ में एक सक्रिय बाजार का निर्माण हो जाने से अनेक प्रकार के लाभ होंगे, परन्तु साथ ही, वर्तमान वित्तीय बाजार की व्यवस्थाओं की अपनी कीसपय परिसीमाएँ भी हैं। यद्यपि प्रस्तावित प्रपत्रों के लिए एक बाजार का निर्माण करना हो तो उन परिसीमाओं को दूर करना होगा। उक्त दल के निष्कर्ष और सिफारिशें विचाराधीन हैं।

भुगतान शेष

1970-71 के दौरान प्रारक्षित निधियों की प्रवृत्तियाँ

131. आलोच्य वर्ष में विदेशी भुगतानों की स्थिति पिछले दो वर्षों के बिल्कुल विपरीत रही। विदेशी मद्रा की प्रारक्षित निधियों में जहाँ 1968-69 (जुलाई-जून) में 1180 लाख डालरों तथा 1969-70 (जुलाई-जून) में 2780 लाख डालरों की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी, वहाँ 1970-71 (जुलाई-जून) में 660 लाख डालरों की कमी हुई। यदि अंतर्राष्ट्रीय मद्रा कोष के साथ किये गये लेन-देनों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की विशेष जमाराशियों

की, वापसी अदायगी और अक्टूबर 1969 में हुए ड्यूस मार्क के पुन-मूल्यन के परिणामस्वरूप वेश की प्रारक्षित आस्तियों के ड्यूस मार्क अंश में हुई मूल्य वृद्धि तथा 10 मई, 1971 से किये गये उमके सम-मूल्य के निर्लंबन जैसे विशेष तत्वों के प्रभाव पर विचार न किया जाए तो प्रारक्षित निधियों में दस लाख डालरों से कम राशि की मामूली वृद्धि दिखाई पड़ेगी जब कि इसकी तुलना में 1969-70 में 3600 लाख डालरों तथा 1968-69 में 2610 लाख डालरों की वृद्धि हुई थी।

132. इस वर्ष मद्रा कोष से पुनः खरीदे गये आहरणों की कुल राशि 1350 लाख डालर थी; पिछले वर्ष यह राशि 1870 लाख डालर थी। इन पुनः क्रयों के परिणामस्वरूप मद्राकोष से किये गये आहरणों की कुल बकाया राशि का निपटान कर दिया गया। पाँचवें पंचवर्षीय सामान्य पुनरीक्षण के अधीन मद्राकोष में भारत का कांटा दिसंबर 1970 में 7500 लाख डालरों से बढ़ाकर 9400 लाख डालर कर दिया गया और इस वृद्धि के सोने के अंश (एक चौथाई) के संदर्भ में सोने की खरीद के लिए 300 लाख डालरों का व्यय किया गया। जनवरी 1957 के बाद पहली बार भारत ने दिसंबर 1970 में मद्रा कोष में रखी जानेवाली अपनी प्रारक्षित निधियों की स्थिति को पुनर्व्यवस्थित किया। जून 1971 के अंत में उसकी प्रारक्षित निधियों की राशि 761 लाख डालर थी। 1 जनवरी, 1971 को भारत को 1010 लाख डालरों के विशेष आहरण अधिकारों का दूसरा विनिधान प्राप्त हुआ जो एक साल पहले प्राप्त 1260 लाख डालरों के विनिधान से कम था। मद्राकोष को दिये गये सेवा-प्रभार की राशि भी इस वर्ष कम थी। पिछले वर्ष यह राशि 130 लाख डालर थी जबकि इस वर्ष यह राशि 60 लाख डालर है। इस प्रकार यद्यपि 1970-71 में मद्राकोष के साथ किये गये लेन-देनों के फलस्वरूप 700 लाख डालरों की राशि बाहर गयी तथापि, मद्राकोष में भारत के आहरण अधिकारों के रूप में प्रारक्षित निधियों का एक दूसरा वर्ग मजबूत हुआ।

133. मद्राकोष ने भारत को विशेष आहरण अधिकार प्राप्त दूसरे देशों से परिवर्तनीय मद्राओं के बदले जुलाई-सितंबर 1970 तथा अक्टूबर-दिसम्बर 1970 में अलग-अलग 140 लाख डालरों तथा जनवरी-मार्च 1971 में 480 लाख डालरों तक के विशेष आहरण अधिकार स्वीकार करने के लिए निर्रिक्त किया। इन निर्देशनों के अंतर्गत, भारत ने जुलाई 1970 और जून 1971 के बीच 410 लाख डालरों के विशेष आहरण अधिकार स्वीकार किये।

1970 में भुगतान स्थिति

134. जून 1971 में समाप्त हुए वर्ष के लिए भुगतान शेष संबंधी लेन-देन के विवरण अभी उपलब्ध नहीं हैं। भुगतान शेष से संबंधित प्राप्त पिछले आंकड़ों के संकलन केवल कैलेंडर वर्ष 1970 से संबंध रखते हैं और उन से यह पता चलता है कि 1969 की तुलना में इस वर्ष के दौरान भारत की विदेशी भुगतान स्थिति बिगड़ गयी है। इस गिरावट के महत्वपूर्ण कारणों में आयात संबंधी भारी व्यय तथा विदेशी सहायता का पहले से कम उपयोग शामिल हैं। दूसरी ओर, निर्यातों में 1969 की तुलना में केवल नाममात्र की वृद्धि हुई।

समग्र प्रवृत्तियाँ

135. इस वर्ष जहाँ कुल आयात व्यय में 115.1 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई वहाँ निर्यातों में 11.5 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि ही हो पाई और परिणामस्वरूप व्यापार-घाटे में भी वृद्धि हुई और वह 165.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 268.8 करोड़ रुपये हो गया (सारणी 25)। अग्रव्यय लेखों में, जिसमें सरकारी अंतरण

अव्यायगियों के लेन-देन भी शामिल हैं, 25.0 करोड़ रुपये का घाटा रहा जो 1969 के घाटे के तिगुने से भी अधिक था। किन्तु इस कमी की आंशिक पूर्ति मुद्रांतर सोने की घट-बढ़ के संदर्भ में प्राप्त 13.1 करोड़ रुपये की राशि से की गयी; उक्त राशि मुद्रा क्षेत्र में भारत के लिए निर्धारित अतिरिक्त क्रेटों में सोने के क्रेट के अंश की पूर्ति के निमित्त मुद्रांतर स्टॉक में से अंतरित किये गये सोने की उभयपक्षी प्रविष्टि की श्रांतक है। व्यापारिक पण्यों तथा अग्रव्यय लेन-देनों, दोनों में ही कमी हो जाने के कारण इस वर्ष के दौरान चालू लेखों के घाटे में 108 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और इससे उक्त घाटा बढ़कर 280.7 करोड़ रुपये हो गया। 'भूल-चूक' के अंतर्गत दिखायी गई अनिर्दिष्ट निकासी के हिसाब में लेने पर, जो इस वर्ष के दौरान हुए घाटे के लगभग आधे अंश का कारण थी, 1970 में कुल घाटा 287.9 करोड़ रुपये था जो 1969 की अपेक्षा लगभग 47 प्रतिशत अधिक है। चुकी पूंजीगत लेन-देनों से हुई वास्तविक प्राप्तियाँ भी पहले से कम थीं, इसलिए वर्ष के दौरान प्रारक्षित निधियों में हुई 44.4 करोड़ रुपये की वृद्धि पहले से 132.0 करोड़ रुपये कम थी।

सारणी 25-भारत का भुगतान शेष (प्रारंभिक)

(करोड़ रुपये)

	जनवरी- मार्च 1970	अप्रैल- जून 1970	जुलाई- सितंबर 1970	अक्तूबर- दिसंबर 1970	जनवरी- दिसंबर 1970	जनवरी दिसंबर 1969
प्र. चालू लेखा						
आयात लागत बीमा प्राइम सहित						
(क) गैर-सरकारी	168.3	166.0	166.4	154.5	655.2	608.2
(ख) सरकारी	244.6	239.9	276.6	262.0	1023.1	955.0
कुल आयात (क+ख)	412.9	405.9	443.0	416.5	1678.3	1563.2
निर्यात जहाज तक निःशुल्क	349.6	331.8	339.8	388.3	1409.5	1398.0
व्यापार शेष	-63.3	-74.1	-103.2	-28.2	-268.8	-165.2
मद्रास सोने में घट-बढ़ (वास्तविक)	—	—	—	+13.1	+13.1	—
सरकारी अंतरण अदायगियाँ (वास्तविक)	-0.3	+5.2	+27.3	+20.3	+52.5	+43.4
अन्य अग्रव्यय लेन-देन (वास्तविक)	-26.5	-5.2	-16.8	-29.0	-77.5	-50.9
चालू लेखा (वास्तविक)	-90.1	-74.1	-92.7	-23.8	-280.7	-172.7
प्रा. भूय-वक (वास्तविक)	+22.2	+16.9	-15.3	-41.0	-17.2	-30.4
इ. पूंजी लेखा						
गैर-सरकारी पूंजी (वास्तविक)	-5.5	-2.2	-6.2	-3.9	-17.8	-27.1
(क) वीपीवधि	-5.5	-2.3	-6.2	-3.8	-17.8	-29.4
(ख) अस्वावधि	—	+0.1	—	-0.1	—	+2.3
संक्रिया पूंजी (वास्तविक)	+1.4	+17.1	-10.6	-14.7	-6.8	-3.7
सरकारी पूंजी (वास्तविक)	+198.7	+58.0	+98.6	+11.6	+366.9	+410.3
(क) ऋण	+226.2	+139.6	+115.6	+162.5	+643.9	+777.9
(ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र	-42.8	-52.6	—	-52.6	-148.0	-111.1
(ग) ऋण परिशोधन	-28.8	-38.0	-43.5	-70.1	-180.4	-185.9
(घ) विविध	+44.1	+9.0	+26.5	-28.2	+51.4	-70.6
पूँजी लेखा (वास्तविक)	+194.6	+7.29	+81.8	-7.0	+342.3	+379.5
ई. प्रारक्षित निधियों में घट-बढ़ (अ+प्रा+ई) वृद्धि (+)/कमी (—)	+126.7	+15.7	-26.2	-71.8	+44.4	+176.4*

*इसमें अक्टूबर 1969 में हुए इयून मार्क के पुनर्मूल्यन के परिणाम स्वरूप प्रारक्षित निधियों के इयून मार्क अंश में हुई मूल्य वृद्धि शामिल नहीं है।

आयात

136. जून 1966 में हुए रुपये के अवमूल्यन के बाद से कुल वार्षिक आयात व्यय में निरंतर कमी की जो प्रवृत्ति विद्यमान थी वह आलोच्य वर्ष में विपरीत दिशा में चलने लगी और कुल आयात व्यय में 115.1 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात् वह 1078.3 करोड़ रुपये हो गया। यह सारी वृद्धि निजी साधनों से वित्तपोषित आयातों के कारण हुई है। दूसरी ओर विदेशी सहायता से वित्तपोषित आयातों में हुई कमी प्रमुख रूप से पण्यगत सहायता में, विशेष रूप से अमेरिकी पी. एल. 480 शीर्षक 1 कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जानेवाले अनाजों के आयात में हुए क्रमिक ह्रास के कारण हुई। यस्तुतः देश में विद्यमान अनाजों की पूर्ति की सुधरी हुई स्थिति के कारण अनाजों के आयात में लगभग 18 प्रतिशत की कमी की जा सकी। किन्तु देश में कच्ची रूई और धातुओं जैसी अन्य मर्चों की कमी के कारण पहले से अधिक मात्रा में आयात करने की आवश्यकता हो गयी। इसके अतिरिक्त मशीनरी और पूँजी उपकरणों के आयातों में भी तेजी आई। इन मर्चों के आयात पर किया गया अतिरिक्त व्यय अनाजों के आयात में हुई कमी से उत्पन्न बचत से बहुत अधिक था और उसी के कारण कुल वार्षिक आयात व्यय में पहले पाये गये ह्रास की प्रवृत्ति के विपरीत वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी।

137. यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो इस वर्ष गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों ही लेखों पर किये गये आयातों में क्रमशः 47.0 करोड़ रुपये और 68.1 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और उनकी राशि बढ़कर क्रमशः 655.2 करोड़ रुपये और 1023.1 करोड़ रुपये हो गयी। गैर-सरकारी लेखों में दो प्रमुख मर्चों अर्थात् कच्ची रूई और मशीनों के आयातों में वृद्धि दिखायी पड़ी। खनिज तेलों, वनस्पति तेलों और पटसन के आयातों में हुई कमी से दूसरी मर्चों के आयातों में हुई वृद्धि पर केवल आंशिक प्रभाव ही पड़ा है। सरकारी लेखों में अनाजों के आयातों में हुई कमी की पूर्ति अनाजों से इतर मर्चों, विशेषकर अलौह धातुओं, पूँजी उपकरणों और संधार सामग्री के आयातों में हुई वृद्धि से की गयी।

निर्यात

138. इस वर्ष निर्यातों की वृद्धि की गति पर्याप्त रूप से धीमी पड़ गई। निर्यातों में 11.5 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि हुई और उनकी राशि 1409.5 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के अधिकतर भाग में बहुत सी बातों ने मिलकर निर्यातों को बुरी तरह से प्रभूयति किया। जूट के सामान, काजू की गिरी आदि हमारी कुछ परंपरागत निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में विश्व की मांग कमजोर पड़ गयी थी, देश में कृषि संबंधी और औद्योगिक कच्ची सामग्री, विशेषकर कच्ची रूई, इस्पात और अलौह धातुओं के अभाव के कारण निर्यात के लिए उपलब्ध सामानों में कमी हो गयी थी तथा जून 1970 में कलकत्ता बंदरगाह में हुई हड़ताल के कारण निर्यात बंद हो गए थे। वर्ष के अंत में यह स्थिति कुछ सुधरने लगी और निर्यातों में सुधार परिलक्षित होने लगा। 1969 की भाँति पूरे वर्ष में हुआ मामूली सुधार भी परंपरेतर वस्तुओं, विशेषकर, इंजीनियरी सामान, खनिज लोह, कच्ची मैंगनीज और चीनी के कारण ही हो पाया। इसके विपरीत परंपरागत वस्तुओं के समग्र निर्यात भी प्रमुख रूप से जूट से बनी वस्तुओं, खालों और घमड़ों, तथा काजू की गिरी के निर्यातों में कमी हो जाने के कारण निरंतर कम होते गये।

अग्रस्थ लेनवहन

139. सरकारी अंतरण अदायगीयों के फलस्वरूप 52.5 करोड़ रुपये का अधिशेष हो गया जो 1969 की तुलना में 9.1 करोड़

रुपये अधिक था (सारणी 25)। यद्यपि इस वर्ष कुल प्राप्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी यह सारी की सारी वृद्धि कुल निकासी में हुई उस बचत का परिणाम है जो सिन्धु घाटी विकास निधि के विये जानेवाले वार्षिक अंशदानों के समाप्त कर देने से हुई, इस अंशदान की अंतिम किस्त 1969 में अदा की गयी थी। अन्य अग्रस्थ लेन वनें पर घाटे की राशि 50.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 77.5 करोड़ रुपये हो गयी। यहाँ भी बाहर जानेवाली कुल राशि में हुई वृद्धि के कारण ही स्थिति विगड़ी है क्योंकि इस वृद्धि का समायोजन कुल प्राप्तियों में हुई वृद्धि से केवल आंशिक रूप से हो पाया। इस वर्ष कुल अदायगीयों में 41.5 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात् उनकी राशि 496.2 करोड़ रुपये हो गयी। इस वृद्धि का आधे से कुछ अधिक भाग निवेश आय लेखों पर बाहर जानेवाली अतिरिक्त राशि के वृद्धि से तथा शेषांश यात्रा परिवहन और विविध सेवा संबंधी लेन-वनें पर की गई अदायगीयों में हुई वृद्धि का परिचायक है। अभी कुछ समय से निवेश आयलेखों पर बाहर जानेवाली कुल राशि, जो बाहर जानेवाली सारी राशि के आधे से अधिक रहती है निरंतर बढ़ती रही है और इस वर्ष उसमें 23.2 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात् उसकी राशि 271.5 करोड़ रुपये हो गयी। 1970 में जो अतिरिक्त राशि बाहर गयी उसका आधे से अधिक भाग ऋणों और साख पर व्याज की अदायगी से संबंधित है जिसकी राशि 1969 के 186.8 करोड़ रुपये की तुलना में 203.5 करोड़ रुपये थी। कुल प्राप्तियों में 14.9 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात् उनकी राशि 418.7 करोड़ रुपये हो गयी। 1970 में कुल प्राप्तियों में हुई वृद्धि के संदर्भ में निवेश आय प्राप्तियों का प्रमुख योगदान रहा, क्योंकि विदेशों में व्याज की ऊँची दरें विद्यमान थीं। विविध तथा परिवहन सेवाओं से प्राप्त आय में भी कुछ सुधार ब्रिष्टगावर हुआ। इन वृद्धियों में विदेशों से किये गये एकपक्षीय निजी अंतरणों में हुई कमी के कारण काफी कमी हो गयी।

पूँजीगत लेनवहन

140. पूँजीगत लेनवनें की वास्तविक प्राप्तियों में जो 1969 में घटकर लगभग आधी रह गई थी, 37.2 करोड़ रुपये की और कमी हुई और वे 342.3 करोड़ रुपये रह गयी। यद्यपि गैर-सरकारी पूँजीगत आवाजाही के संदर्भ में सुधार हुआ, तथापि बैंक-व्यवसाय और सरकारी क्षेत्रों से संबंधित आवाजाही पहले की अपेक्षा कम संतोषजनक थी। ऋणों में से अधिक आहरण किये जाने तथा तेल कंपनियों की निधियों के विपरीत दिशा में जाने के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र की प्राप्तियों में तेजी से वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप बाहर जानेवाली गैर-सरकारी पूँजी की वास्तविक राशि 27.1 करोड़ रुपये से घटकर 17.8 करोड़ रुपये रह गयी। दूसरी ओर बैंक-व्यवसाय क्षेत्र से बाहर जानेवाली वास्तविक राशि जो 6.8 करोड़ रुपये थी, इस वर्ष लगभग दोगुनी हो गया। 1969 की भाँति ही बाहर जानेवाली लगभग समूची वास्तविक राशि प्राधिकृत व्यापारियों की विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई वृद्धि का परिणाम थी।

141. सरकारी क्षेत्र में वास्तविक प्राप्तियों में और अधिक कमी हुई अर्थात् उनमें 43.4 करोड़ रुपये की कमी हुई इससे वह राशि 368.9 करोड़ रुपये रह गयी। विदेशी सहायता ऋणों के उपयोग में कमी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये पुनः क्रयों के रूप में अपेक्षाकृत अधिक निकासी, ये दोनों इसके दो प्रमुख कारण थे। विदेशी सहायता ऋणों के उपयोग में प्रमुखतः पी. एल. 480 प्रीतिरूप निधियों के ऋण वितरणों में हुई अत्यधिक संकुचन के कारण कमी हुई अर्थात् उपयोग किये गये ऋणों की राशि 780.6 करोड़ से घटकर 647.0 करोड़ रुपये रह गयी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये पुनः क्रयों की राशि 1969 के 111.1 करोड़ रुपये की तुलना में 148.0 करोड़ रुपये थी। किन्तु ऋण परिशोधन संबंधी अदायगीयों की राशि 182.6 करोड़ रुपये भी जो

पिछले वर्ष की तुलना में जरा सी कम थी। स्थिति का एक संतोष-प्रद पहलू यह था कि विविध पूँजीगत लेन-देनों में अनुकूल मोड़ आया जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष 51.4 करोड़ रुपयों की वास्तविक प्राप्ति हुई जब कि 1969 में 70.6 करोड़ रुपयों की राशि ग्राह्य गयी थी और इससे दूसरे सरकारी पूँजीगत लेन-देनों की प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत कुछ सुधार हुआ। इस अनुकूल परिणाम के कारण अंशतः विशेष आहरण अधिकारों के संदर्भ में किये गये विनिधान (94.5 करोड़ रुपयों) की उभयपक्षी प्रविष्टि तथा अंशतः पी. एल. 480 शीर्षक 1 कार्यक्रम के अंतर्गत किये गये लेन-देनों से अमेरिकी सरकार के प्रति उत्पन्न रूपया देयताओं में हुए परिवर्तन थे।

क्षेत्रीय प्रवृत्तियाँ

142. चालू लेखों की स्थिति में समग्र रूप से जो गिरावट आई है वह प्रमुखतः डालर क्षेत्र तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों के पास रहने वाले चालू लेखों में हुए घाटे की वृद्धि का परिणाम है (सारणी 26)। इस वर्ष केवल इन दो क्षेत्रों के पास रहनेवाले लेखों में हुए घाटे की राशियाँ में ही क्रमशः 150.7 करोड़ रुपयों और 63.0 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और वे राशियाँ बढ़कर क्रमशः 302.2 करोड़ रुपयों और 149 करोड़ रुपयों हो गईं। स्टर्लिंग क्षेत्र के संदर्भ में विद्यमान स्थिति भी कुछ कमजोर पड़ गयी, क्योंकि अधिशेष की मात्रा में 8.4 करोड़ रुपयों की कमी हुई और अधिवेश की राशि घट कर 105.7 करोड़ रुपयों रह गयी। दूसरी ओर 'शेष गैर-स्टर्लिंग क्षेत्र' के संदर्भ में स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ और अधिशेष की राशि में 4.5 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् वह राशि 102.2 करोड़ रुपयों हो गई।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संदर्भ में घाटे की राशि भी, जो 37.0 करोड़ रुपयों थी, 1969 की तुलना में कम ही थी और पूर्वांशित संधि, घाटी विकास निधि में किये जाने वाले वार्षिक अंशदानों के समाप्त कर देने के परिणामस्वरूप प्रमुख रूप से सरकारी अंतरण अदायगी से संबंधित लेन-देनों के संदर्भ में कम राशि के बाहर जाने के कारण घाटे में उक्त कमी हुई।

143. जहाँ स्टर्लिंग क्षेत्र के पास विद्यमान व्यापार अधिशेष प्रायः पूर्ववत् ही बना रहा और 'शेष गैर-स्टर्लिंग क्षेत्र' के पास विद्यमान अधिशेष में उल्लेखनीय सुधार पाया गया वहाँ डालर क्षेत्र और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों के पास विद्यमान व्यापार घाटे में पर्याप्त वृद्धि हुई (सारणी 26)। 'शेष गैर-स्टर्लिंग क्षेत्र' से किये गये आयातों को छोड़कर जिनमें कमी हुई है, शेष तीन क्षेत्रों से किये गये आयातों में वृद्धि दिखाई दी। वास्तव में समग्र आयात व्यय में हुई भारी वृद्धि का प्रमुख कारण डालर क्षेत्र तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों से किये गये आयातों में हुई वृद्धि है। स्टर्लिंग क्षेत्र और 'शेष गैर-स्टर्लिंग क्षेत्र' को किये गये निर्यातों में भी वृद्धि हुई और 'शेष गैर-स्टर्लिंग क्षेत्र' के मामले में यह वृद्धि काफी महत्वपूर्ण रही है। परंतु डालर क्षेत्र और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों से किये गये निर्यातों में हुई कमी के कारण उक्त वृद्धि काफी महत्वहीन हो गयी।

144. सभी क्षेत्रों के संदर्भ में अग्रव्य लेन-देनों और सरकारी अंतरण अदायगी से संबंधित लेन-देनों में ह्रास की स्थिति पायी गयी। जहाँ स्टर्लिंग और डालर क्षेत्रों के अधिशेष में कमी हुई वहाँ आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों तथा 'शेष

सारणी 26-चालू लेखों में भारत का क्षेत्रीय भुगतान शेष (प्रारंभिक)

(करोड़ रुपये)

	जनवरी- मार्च 1970	अप्रैल-जून 1970	जुलाई- सितंबर 1970	अक्तूबर- दिसंबर 1970	जनवरी- दिसंबर 1970	जनवरी- दिसंबर 1969
स्टर्लिंग क्षेत्र						
आयात लागत बीमा भाड़ा सहित	65.1	69.9	62.2	70.6	267.8	255.4
निर्यात जहाज तक निःशुल्क	87.8	80.2	90.0	106.5	364.5	351.4
व्यापार शेष	+ 22.7	+ 10.3	+ 27.8	+ 35.9	+ 96.7	+ 96.0
मुद्रांतर सोने में घट-बढ़ (वास्तविक)	—	—	—	—	—	—
सरकारी अंतरण अदायगियाँ (वास्तविक)	0.5	-0.8	-0.3	+ 0.4	- 1.2	+ 7.3
दूसरे अग्रव्य लेन-देन (वास्तविक)	+ 6.0	+ 2.5	+ 3.3	- 1.6	+ 10.2	+ 10.8
चालू लेखा (वास्तविक)	+ 28.2	+ 12.0	+ 30.8	+ 34.7	+ 105.7	+ 114.1
डालर क्षेत्र						
आयात लागत बीमा भाड़ा सहित	133.9	155.1	164.0	134.9	587.9	494.3
निर्यात जहाज तक निःशुल्क	57.8	50.8	54.5	69.8	232.9	290.6
व्यापार शेष	-76.1	-104.3	-109.5	-65.1	-355.0	-203.7
मुद्रांतर सोने में घट-बढ़ (वास्तविक)	—	—	—	+ 13.1	+ 13.1	—
सरकारी अंतरण अदायगियाँ (वास्तविक)	+ 1.8	+ 5.0	+ 28.1	+ 18.8	+ 53.7	+ 41.9
दूसरे अग्रव्य लेन-देन (वास्तविक)	-6.0	+ 1.6	+ 0.4	-10.0	-14.0	+ 10.3
चालू लेखा (वास्तविक)	-80.3	-97.7	-81.0	-43.2	-302.2	-151.5
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देश						
आयात लागत बीमा भाड़ा सहित	58.6	54.5	61.8	70.5	245.4	194.4
निर्यात जहाज तक निःशुल्क	32.3	30.4	27.7	31.6	122.0	132.3
व्यापार शेष	-26.3	-24.1	-34.1	-38.9	-123.4	-62.1
मुद्रांतर सोने में घट-बढ़ (वास्तविक)	—	—	—	—	—	—
सरकारी अंतरण अदायगियाँ (वास्तविक)	+ 1.7	1.3	+ 0.3	+ 1.3	+ 4.6	+ 9.9
दूसरे अग्रव्य लेन-देन (वास्तविक)	-3.4	-8.3	-6.4	-12.6	-30.7	-34.3
चालू लेखा (वास्तविक)	-28.0	-31.1	-40.2	-50.2	-149.5	-86.5

सारणी 26—बालू लेखे में भारत का क्षेत्रीय भुगतान शेष (प्रारंभिक)—(जारी)

(करोड़ रुपये)

	जनवरी- मार्च 1970	अप्रैल-जून 1970	जुलाई- सितंबर 1970	अक्तूबर- दिसंबर 1970	जनवरी- मार्च 1970	जनवरी- मार्च 1969
शेष गर-स्टीलिंग क्षेत्र						
आयात लागत बीमा भाड़ा सहित	155.3	126.4	155.0	140.5	577.2	619.1
निर्यात जहाज तक निःशुल्क	171.7	170.4	167.7	180.4	690.2	623.7
व्यापार शेष	+16.4	+44.0	+12.7	+39.9	113.0	4.6
मुद्रांतर सोने में घट-बढ़ (वास्तविक)	—	—	—	—	—	—
सरकारी भ्रंतरण भ्रदायगियां (वास्तविक)	-0.1	-0.1	—	—	-0.2	—
बूतरे भ्रवृष्य लेन-देन (वास्तविक)	-12.8	+7.0	-5.1	0.3	-10.6	-0.1
बालू लेखा (वास्तविक)	+3.5	+50.9	+7.6	+40.2	+102.2	+4.5
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं						
आयात लागत बीमा भाड़ा सहित	—	—	—	—	—	—
निर्यात जहाज तक निःशुल्क	—	—	—	—	—	—
व्यापार शेष	—	—	—	—	—	—
मुद्रांतर सोने में घट-बढ़ (वास्तविक)	—	—	—	—	—	—
सरकारी भ्रंतरण भ्रदायगियां (वास्तविक)	-3.2	-0.2	-0.8	-0.2	-4.4	-15.7
बूतरे भ्रवृष्य लेन-देन (वास्तविक)	-10.3	-8.1	-9.1	-5.1	-32.6	-37.7
बालू लेखा (वास्तविक)	-13.5	-8.3	-9.9	-5.3	-37.0	-53.4

गैर-स्टीलिंग क्षेत्र' के घाटे में वृद्धि हुई। स्टीलिंग क्षेत्र, डालर क्षेत्र तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों के संदर्भ में इन लेन-देनों के कारण बालू लेखे की स्थिति और बिगड़ गयी। इसके विपरीत 'शेष गैर-स्टीलिंग क्षेत्र' के संदर्भ में घाटे में जो वृद्धि हुई उसके कारण व्यापार शेष से प्राप्त लाभ अंशतः संतुलित हो गया।

विदेशी व्यापार :**संकलन की क्रियाविधि में परिवर्तन**

145. भुगतान शेष संबंधी पूर्वोक्त विश्लेषण केवल कैलेंडर वर्ष 1970 तक सीमित है। क्यों कि परवर्ती महीनों के लिए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। किन्तु व्यापारिक पण्य संबंधी लेन-देनों से संबंधित 1970-71 के वित्तीय वर्ष के आंकड़े वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा संकलित सांख्यिकीय विवरण में उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1970-71 (अप्रैल-मार्च) में निर्यातों की कुल राशि पिछले वर्ष के 18840 लाख डालरों की तुलना में 20410 लाख डालर थी जो इस

बात का द्योतक है कि इस वर्ष वृद्धि की दर 8 प्रतिशत थी जबकि 1969-70 में यह दर 4 प्रतिशत थी। 1970-71 में हुई वृद्धि के एक भाग का सांख्यिकीय महत्व है, क्योंकि यह वृद्धि वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा निर्यातों के आंकड़े तैयार करने के लिए अपनायी जानेवाली क्रियाविधि में किये गये परिवर्तन का परिणाम भी उक्त परिवर्तन नवम्बर 1970 से अमल में आया। जहाँ पहले निर्यातों के आंकड़े वास्तव में किये गये लदानों (अर्थात् अंतिम रूप से पारित पोत-परिवहन बिलों) के आधार पर संकलित किये जाते थे, वहाँ अब उन्हें उसी समय संकलित कर लिया जाता है जब परेषण पोत लदान के लिए स्वीकार कर लिये जाते हैं (अर्थात् अब उनका आधार पोत परिवहन बिलों की मूल प्रति होती है) यद्यपि उनमें अल्प लदानों और प्रतिरूद्ध लदानों के लिए समायोजन कर दिया जाता है जिनके ध्यारे सूचना किये जाने के महीने में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अब निर्यातों के आंकड़ों में स्वयमेव वृद्धि परिलक्षित होती है।* इसीलिए 1970-71 में किये गये निर्यातों का मूल्यांकन करते समय सूचना की क्रियाविधि में हुए परिवर्तन के लिए यथोचित गुंजाइश रखनी होगी। इसके परिणामस्वरूप विस्तृत वर्ष के उत्तरार्ध से संबंधित आंकड़े अंशतः पुराने आधार पर और अंशतः नये आधार पर तैयार किये गये हैं।

*यहाँ यह याद दिला दिया जाए कि 1965-66 में निर्यातों के तैयार करने का आधार किसी एक महीने में स्वीकार किये गए पोत-लदानों के स्थान पर उस महीने में किये गये वास्तविक पोतलदान कर दिया गया था ताकि आंकड़ों का संकलन अधिक यथार्थ हो सके। उस वर्ष में इस क्रियाविधि में हुए परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप निर्यातों के सांख्यिकीय आंकड़े कम रहे। 1970-71 में सूचना की प्रणाली को बदल देने से निर्यातों के आंकड़े बड़े बड़े दिखाई देंगे।

सारणी 27-भारत के मुख्य निर्यात

(दस लाख अमेरिकी डालरों में)

	1965-66	1968-69	1969-70	1969-70	1970-71	(4) की अपेक्षा (5) में वृद्धि (+) कमी (-)	(6)	(7)
				(अप्रैल-सितंबर)			वास्तविक	प्रतिशत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
प्र. किन मर्चों में वृद्धि हुई								
खनिज लोहा	89	118	126	52	63	+ 11	+ 21	
इंजीनियरी माल	37	92	120	56	79	+ 23	+ 41	
लोहा और इस्पात	26	105	116	52	58	+ 6	+ 12	
काजू की गिरी	58	81	77	41	43	+ 2	+ 5	
तेल की खली	73	66	55	25	34	+ 9	+ 36	
रसायन	23	32	40	20	21	+ 1	+ 5	
गरम मसाले	49	34	46	13	18	+ 5	+ 38	
चीनी	23	14	10	8	11	+ 3	+ 38	
कच्ची मैंगनीज	23	18	15	7	8	+ 1	+ 14	
आ. किन मर्चों में कमी हुई								
जूट का तागा और उससे बनी वस्तुएं	384	291	276	145	99	-46	-32	
सूत का तागा और उससे बनी वस्तुएं	148	134	134	74	72	-2	-3	
चाय	241	209	166	83	65	-18	-22	
खाल, छाल, चमड़ा और कपड़े की चीजें, जूतों को मिलाकर	90	116	132	68	53	-15	-22	
मोती, बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थर, न तराशे गए/तराशे गए	31	60	56	30	28	-2	-7	
काफी	27	24	26	22	19	-3	-14	
मछली और मछली से बनी वस्तुएं	14	30	42	21	20	-1	-5	
इ. जोड़	1693	1811	1884	934	928	- 6	-1	

स्त्रोत : वाणिज्यिक सूचना और प्रंक संकलन महानिदेशालय

146. अप्रैल-सितम्बर 1970 के दौरान निर्यातों की कुल राशि 9280 लाख डालर थी जो 1969 की तुल्यरूपी अवधि की राशि से 60 लाख डालर कम थी। निर्यातों में हुई यह कमी प्रमुखतः जूट से बनी चीजों के निर्यातों में हुई कमी का परिणाम थी। जूट से बनी चीजों के निर्यातों में इस अवधि में तेजी से 460 लाख डालरों की भारी कमी हुई। जिन अन्य प्रमुख वस्तुओं के निर्यातों में कमी हुई वे हैं : चाय (180 लाख डालर), खाल छाल, और चमड़ा (150 लाख डालर) काफी (30 लाख डालर) और सूती वस्त्र (20 लाख डालर)। इन वस्तुओं के निर्यात में हुई कमी कुछ सीमा तक निम्नलिखित वस्तुओं के निर्यातों से हुई अतिरिक्त प्राप्तियों से पूरी कर ली गई : इंजीनियरी सामान (230 लाख डालर), खनिज लोहा (110 लाख डालर), तेल की खली (90 लाख डालर), लोहा और इस्पात (60 लाख डालर), गर्म मसाले (50 लाख डालर) और चीनी (30 लाख डालर) (सारणी 27)।

147. 1970-71 के पूर्वार्ध में निर्यातों में जो शिथिलता आई उसे बहुत से आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के कारणों का परिणाम माना जा सकता है। मई-जुलाई 1970 के दौरान कलकत्ता बंदरगाह में हुई नाविकों की 10 सप्ताहों की हड़ताल के अलावा जिस का उन महीनों में निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, विशेष श्रेणियों के इस्पात एल्यूमिनियम और दूसरी अलाह धातुओं तथा कच्ची रूई जैसी मूलभूत उपयोगी वस्तुओं की पूर्ति में रुका-

वट होने के कारण भी निर्यातों में शिथिलता आई। दूसरा कारण यह था कि विदेशों में हमारी कतिपय निर्यात वस्तुओं विशेषकर जूट के कालीनों की पट्टियों, समुद्री उत्पादों, खाल, छाल और चमड़े तथा सूत की माँग में कमी हो गयी थी।

148. निर्यातों में गिरावट की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने विशेषकर अत्यावश्यक कच्चे माल की पूर्ति की स्थिति को सुधारने तथा निर्यात प्रयत्नों को अधिक गतिशील बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए। सितंबर 1970 में सरकार ने इस्पात की आयात नीति को उदार बनाया ताकि इंजीनियरी उत्पादों की निर्यात इकाइयों को उनकी अपनी आवश्यकता के अनुसार विशेष प्रकार का इस्पात पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता रहे। इस नीति के अधीन अलग-अलग इकाइयों के लिए नियत किये गये सामान्य कोटे के अतिरिक्त 1969-70 की वास्तविक खपत के 50 प्रतिशत अथवा पक्के निर्यात आर्डरों पर उत्पादन के लिए आवश्यक वास्तविक मात्रा तक इस्पात की कतिपय दुर्लभ श्रेणियों के आयात के लिए अनुमति प्रदान की गयी।

149. अंशतः सरकार द्वारा किये गये विभिन्न विकास पूरक प्रयत्नों के प्रभावस्वरूप तथा अंशतः देश में कच्चे मालों की उपलब्धता और निर्यात अधिशेषों में हुए सुधार के कारण अक्टूबर 1970 से निर्यातों की स्थिति में सुधार दृष्टिगोचर होना लगा। यद्यपि पूर्वोक्त लिखित सांख्यिकीय परीतीमात्रों के कारण 1970-71 और 1969-70

के उत्तरार्धों में निर्यातों में हुई वृद्धि का सही तुलनात्मक मूल्यांकन करना संभव नहीं है फिर भी जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे यह पता चलता है कि अक्टूबर-दिसम्बर 1970 में मूल्य की दृष्टि से निर्यातों में अत्यधिक वृद्धि हुई। अक्टूबर-दिसम्बर 1970 की तिमाही में किये गये निर्यातों का मूल्य 6050 लाख डालर था जो 1969 की तदनुसूची तिमाही के मूल्य से 32 प्रतिशत अधिक था और यह वास्तविक वृद्धि के केवल एक अंश का सातक था। उक्त वृद्धि पर-परागत और परंपरेतर दोनों प्रकार की प्रायः सभी मर्चों में समान रूप से हुई। जनवरी-मार्च 1971 में निर्यातों में हुई अत्यधिक वृद्धि के क्रमशः कम होते जाने का आभास मिलता है क्योंकि निर्यातों का मूल्य घटकर 5080 लाख डालर रह गया जो 1970 की तदनुसूची तिमाही से केवल 3 प्रतिशत अधिक था। 1971-72 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 1971) में निर्यातों में सामान्य वृद्धि हुई अर्थात् उनकी राशि बढ़कर 5120 लाख डालर हो गई। यदि इस की तुलना 1970 की तदनुसूची तिमाही से की जाए तो पता चलता है कि इनमें 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार अक्टूबर 1970 से निर्यातों में आम तौर पर सतत वृद्धि होने की प्रवृत्ति परिलक्षित है।

निर्यात : पण्यवार

150. अप्रैल-दिसम्बर 1970 के लिए उपलब्ध पण्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि यद्यपि बढ़ती हुई वंशी मांग के कारण लोहे और इस्पात के निर्यातों में सामान्य वृद्धि हुई है तथापि इंजीनयरी सामानों, खनिज लोहे और रसायनों के निर्यातों में वृद्धि बराबर होती रही। परंपरागत पण्यों में से, चाय के निर्यात में सुधार पाया गया जो कुछ सीमा तक 1970 के आरंभ में किये गये मारिशस करार का परिणाम है। जूट के माल के निर्यातों के संबंध में कमी की जो प्रवृत्ति पिछले वर्षों में देखी गई थी वह अमरीका की विशेषकर कालीनों की पीट्टियों की मांग में कमी होने तथा पाकिस्तान और कृत्रिम प्रतिकूलों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण बनी रही किन्तु पूर्वी बंगाल में हुई दुखद घटनाओं के कारण चालू वर्ष में अस्थायी तौर पर ही सही, इस प्रवृत्ति का अवरोध होने की संभावना है। सूती कपड़ों के थानों के संबंध में मुख्य समस्या कीमतों के कम रखने तथा अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की है इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन द्वारा 1 जनवरी 1972 से लगाये जाने वाले प्रस्तावित आयात शुल्क से भी उस देश के किये जानेवाले हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लोहे और इस्पात के संदर्भ में वंशी मांग के जोर पकड़ने के कारण हमारे लिए निर्यातों की वृद्धि की ऊंची दर बनाये रखना कठिन हो जाएगा। जहाँ तक इंजीनयरी माल के निर्यात का संबंध है, कीत-पय विशेष श्रेणियों के इस्पात की कमी और देश में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली बढ़ती हुई उसकी कीमतों उसके मार्ग में सब से बड़ी बाधाएँ हैं।

प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली का अपनाया जाना

151. निर्यात की संभावनाओं के संदर्भ में एक संतोषप्रद प्रगति यह हुई है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली को अपना लिया है जिस से हमारी उत्पादित और अर्ध उत्पादित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने का अवसर प्राप्त होगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों तथा जापान ने इस प्रणाली को क्रमशः 1 जुलाई और 1 अगस्त 1971 से लागू किया है। आशा की जाती है कि अमरीका और ब्रिटेन भी 1972 में किसी समय इस प्रणाली को अपना लेंगे। निर्यात के क्षेत्रों में संचयन बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, किन्तु विकसित देशों के इस नये दृष्टिकोण के साथ-साथ सरकार के निर्यात विकास अभियान के प्रभावस्वरूप तथा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग प्राप्त होने पर निर्यातों की वृद्धि में तीव्रता लाना संभव होना चाहिए।

निर्यात नीति संकल्प

152. निर्यात विकास के संबंध में इस वर्ष एक सहस्रपूर्ण प्रगति यह हुई कि 30 जुलाई 1970 के संसद में निर्यात नीति संकल्प प्रस्तुत किया गया जिसमें वंश को आत्मनिर्भर बनाने और विदेशी सहायता पर उसकी निर्भरता को कम करने के लिए इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया कि निर्यात से होनेवाली भारत की आमदनीयों को बहुत अधिक बढ़ाया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उक्त संकल्प में बहुत से उपाय दिये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नीलिखित शामिल हैं : (1) अर्थ-व्यवस्था के उदीयमान क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने के निमित्त बनायी गई उपयुक्त नीतियाँ और उपायों का अपनाया जाना, (2) अर्थ-व्यवस्था के उन सभी व्यापक क्षेत्रों के उत्पादों का और अधिक सही रूप से पता लगाया जाना जिनके निर्यात की संभावनाएँ वीर्णाधिक हैं, (3) निर्यात-अभिमुख इकाइयों के विस्तार के लिए सुविधाएँ प्रदान करना, (4) दूसरे विकासशील देशों की नयी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उद्योगों के लिए आवश्यक मूलभूत वस्तुओं, औद्योगिक मशीनरी, मशीनी औजारों और टिकाऊ उपभोक्ता माल के विकास के लिए उपकरणों के उत्पादकों और निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन देना और (5) निर्यातकों को प्रदान की जानेवाली ऋण सुविधाओं को सुदृढ़ और विस्तृत करना।

व्यापार विकास प्राधिकरण

153. निर्यात नीति संकल्प के अनुसरण में सरकार ने व्यापार सूचना, अनुसंधान और विश्लेषण, पण्यों के व्यापार तथा निर्यात उत्पादन और विकास के क्षेत्र में अनेक प्रकार की व्यक्तिगत सेवाओं के जीर्ये उद्यमकर्ताओं को उनके अपने निर्यातों की वृद्धि करने में सहायता दिलाने के उद्देश्य से जुलाई 1970 में व्यापार विकास प्राधिकरण के नाम से एक नये संगठन की स्थापना की। फरवरी 1971 में इस प्राधिकरण ने अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिमी यूरोप और जापान का घुनी हुई वस्तुओं (मुख्य रूप से इंजीनयरी माल) का निर्यात करने के इच्छुक अपनी सक्षम-इकाइयों को अनेक प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने की घोषणा की।

अन्य उपाय

154. इस वर्ष उठाये गये अन्य उपायों में निम्नीलिखित उपायों का उल्लेख किया जा सकता है : नारियल के रेशों के निर्यात पर से 25 प्रतिशत के यथा मूल्य निर्यात शुल्क को 30 जुलाई 1970 से हटा लिया गया तथा विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में निर्यात संबंधी प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए संस्थागत ढाँचे का विस्तार किया गया। इस वर्ष जो नई संस्थाएँ स्थापित की गईं उनमें काजू निगम, रूई निगम, जूट निगम, तथा प्रयोजना और उपस्क निगम शामिल हैं।

आयातों की प्रवृत्तियाँ

155. वार्षिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों के आधार पर 1970-71 में आयातों की कुल राशि 21710 लाख डालर थी जो 1969-70 के स्तर से 610 लाख डालर (3 प्रतिशत) अधिक थी। स्वयं के अवमूल्यन के बाद आयातों में पहली बार वृद्धि हुई है और यह समूची वृद्धि खाद्योत्पन्न वस्तुओं के संदर्भ में हुई और इससे निरंतर बढ़ते हुए औद्योगिक उत्पादन के परिणामस्वरूप आयातित कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती वस्तुओं, अतिरिक्त घटकों और पुर्जों के लिए उद्योगों की बढ़ती हुई आवश्यकताएँ परिलक्षित होती हैं।

आयात : पण्यवार

156. आयातों के पण्यवार ब्यारे दिसम्बर 1970 तक उपलब्ध हैं। उन से पता चलता है कि अप्रैल-दिसम्बर 1970 के दौरान अनाजों के

सारणी 28—भारत के मुख्य आयात

(बस लाख अमेरिकी डॉलरों में)

पण्य	वार्षिक			अप्रैल-दिसम्बर		(3) से	(2) से	(5) से
	1965-	1968-	1969-	1969-	1970-	(4) का	(4) का	(6) का
	66	69	70	70	71	प्रतिशत परिवर्तन		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1) अनाज (काजू को छोड़कर) वालों से	712	495	391	299	250	-21	-45	-16
अनाज और उनसे बनी वस्तुएं	676	449	348	269	226	-23	-49	-16
(2) कच्ची रुई	97	120	110	82	98	-8	+13	+20
(3) पटसन और मेस्ता	53	22	7	7	नगण्य	-68	-87	-
(4) काज	32	42	37	25	29	-12	+16	+16
(5) खनिज तेल	143	177	183	135	127	+3	+28	-6
उनमें से								
(क) कच्चा और अशोधित								
पेट्रोलियम	73	128	128	95	102	-	+75	+7
(ख) अन्य	70	49	55	40	25	+12	-21	-38
(6) रासायनिक पदार्थ	221	378	246	192	181	-35	+11	-6
उनमें से								
(क) उर्वरक	82	186	90	76	50	-52	+10	-34
(ख) अन्य	139	192	156	116	131	-19	+12	+13
(7) लोहा और इस्पात	206	115	108	75	136	-6	-48	+81
(8) अलौह धातुएं	145	119	99	65	114	-17	-32	+75
(9) कच्चा रबड़ (कृत्रिम और सुधारे								
गये रबड़ को मिलाकर)	10	7	13	11	4	+86	+30	-64
(10) ऊन और दूसरे पशुओं के रोम	11	15	23	17	18	+53	+109	+6
(11) पशुओं तथा वनस्पति के तेल और								
बर्फी	32	26	39	36	43	+50	+22	+19
(12) कागज, गत्ते और उनसे बनी								
चीन्ने]	28	24	32	24	23	+33	+14	-4
(13) मोती, बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य								
पत्थर, न तराफे गये/तराफे गये	3	37	38	27	23	+3	+1167	-15
(14) मशीनें और परिवहन उपकरण	1034	685	524	399	365	-24	-49	-9
(क) बिजली से हतर मशीनें	701	488	372	286	253	-24	-47	-12
(ख) बिजली की मशीनें	184	109	85	61	65	-22	-54	+7
(ग) परिवहन उपकरण	149	88	67	52	47	-24	-55	-10
(15) अन्य	232	283	240	169	167	-15	+3	-1
जोड़	2959	2445	2090*	1563	1578	-18	-29	+1

स्रोत : वाणिज्यिक सूचना और प्रक संकलन महानिदेशालय

* इसे बदल कर 21100 लाख डॉलर कर दिया गया है; किन्तु पण्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

खाद्योत्पाद वस्तुओं के आयातों के अधीन लोहे और इस्पात (610 लाख डालर (16 प्रतिशत) कम था। इस अवधि में खाद्योत्पाद वस्तुओं के आयातों में 580 लाख डालरों (4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। खाद्योत्पाद वस्तुओं के आयातों के अधीन लोहे और इस्पात (610 लाख डालर अथवा 81 प्रतिशत), अलौह धातुओं (490 लाख डालर अथवा 75 प्रतिशत), उर्वरकों से इतर रासायनिक पदार्थों (150 लाख डालर अथवा 13 प्रतिशत), कच्ची रूई, (160 लाख डालर अथवा 20 प्रतिशत) और काजू (40 लाख डालर अथवा 16 प्रतिशत) में भारी वृद्धि हुई। मशीनों और परिवहन उपकरणों तथा उर्वरकों के आयातों में क्रमशः 9 प्रतिशत और 34 प्रतिशत की कमी हुई। मशीनों के वर्ग में बिजली की मशीनों के आयातों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु यह वृद्धि बिजली से इतर मशीनों और परिवहन उपकरणों के आयातों में हुई क्रमशः 12 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कमी से काफी संतुलित हो गयी (सारणी 28)। लोहे और इस्पात तथा अलौह धातुओं के आयातों में हुई वृद्धि निर्यात उद्योगों की मांग की पूर्ति के लिए इन पण्यों का आपात कालीन आधार पर आयात करने के लिए किये गये विशेष प्रयत्नों का परिणाम थी। निवेश गतिविधियों के सुधार होने के बावजूद बिजली से इतर मशीनों के आयातों में जो कमी हुई है वह मशीन निर्माण उद्योग में आयात प्रसिद्धावन की दिशा में हुई प्रगति की परिचायक है।

आयात-नीति

157. आयात नीति विशेष रूप से निर्यात उद्योगों के लिए तथा सामान्य रूप से प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए उदार रही है। 1969-70 और 1970-71 में आयात लाइसेंसों के मूल्य में क्रमशः 27 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो आयातित कच्ची सामग्री के संदर्भ में उद्योगों की मांग को दर्शाती है। इसके परिणामस्वरूप 1971-72 के दौरान खाद्योत्पाद वस्तुओं के आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि होनी चाहिये। वास्तव में 1971-72 की पहली तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून 1971 में आयातों की समग्र राशि 6500 लाख डालर थी जो पिछले वर्ष की तदनुकूली अवधि के स्तर से 25 प्रतिशत अधिक थी।

विदेशी सहायता

प्राधिकार

158. राजकोषीय वर्ष 1970-71 में प्राधिकारों की कुल राशि 9810 लाख डालर थी जो पिछले वर्ष की राशि से 18 प्रतिशत अधिक थी, इसके विपरीत पिछले वर्ष उसमें 25 प्रतिशत की कमी हुई थी। प्राधिकृत ऋणों और अनुदानों में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् उनकी राशि 7370 लाख डालरों से बढ़कर 9810 लाख डालर हो गई और इस प्रकार कुल सहायता प्राधिकारों

सारणी 29—विदेशी सहायता*

(सं. लाख अमेरिकी डालरों में)†

	ऋण**	अनुदान	पी० एल० 480	जोड़
			सहायता②	(1+2+3)
	1	2	3	4
1. मार्च 1966 के प्राप्त तक वितरित की गयी रकम	2,194	115	226†	2,535
2. प्राधिकृत				
(क) 1966-67 में	1,425	106	524	2,055
(ख) 1967-68 में	595	22	324	941
(ग) 1968-69 में	1,052	93	96	1,241
(घ) 1969-70 में	697	40	98	835
(ङ) 1970-71 में	906	75	---	981
जोड़	4,675	336	1,042	6,053
3. प्रयुक्त				
(क) 1966-67 में	903	126	480	1,509
(ख) 1967-68 में	1,074	81	415	1,570
(ग) 1968-69 में	1,008	97	113	1,218
(घ) 1969-70 में	900	39	143	1,082
(ङ) 1970-71 में	892	58	50	1,000
जोड़	4,777	401	1,201	6,379
4. मार्च 1971 के प्राप्त तक वितरित की गयी रकम	2,078††	52††	---	2,130

*इसमें (क) अमेरिकी पी० एल० 480 शीर्षक II और III के अधीन दिये गये अनुदान और (ख) 1967-68 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखी गयी विशेष जमा राशियां शामिल नहीं हैं।

**इसमें पी० एल० 480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋणों की प्राधिकृत और प्रयुक्त राशियां शामिल हैं।

②इससे अमेरिकी पी० एल० 480 शीर्षक I कार्यक्रम के अधीन साल के आयात के लिए रखी गयी रुक्या जमा राशियों का पता लगता है, अतः इन निधियों से ऋणों और अनुदानों के रूप में वितरित की गयी राशि स्वम्भ 1 और 2 में शामिल नहीं की गयी है।

† गतावधिक करारों के लिए 1,840 लाख डालरों का समायोजन किया गया।

†† नवम्बर 1967 में पॉड स्टेलिंग और डेनिश क्रोनर और अगस्त 1969 में फ्रेंच फ्रैंक का जो अवमूल्यन हुआ तथा अक्टूबर, 1969 में ज्यूस मार्क का जो पुनर्मूल्यन हुआ उसके लिए समायोजन किया गया, किन्तु यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से दिये गये ऋणों पर लागू नहीं होता क्योंकि अलग अलग किस्तों के प्राधिकार तथा ग्राहकों के समक्ष पर विद्यमान सममूल्यों के आधार पर उनका हिस्सा लगाया जाना है।

गतावधिक करारों के लिए 670 लाख डालरों का समायोजन किया गया।

में वृद्धि हुई, इस वर्ष पी. एल. 480 सहायता* के संदर्भ में कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु इस संदर्भ में पिछले वर्ष 980 लाख डालर प्राधिकृत किये गये थे (सारणी 29)।

प्रायोजनागत और प्रायोजनंतर सहायता

159. 1970-71 में प्राधिकृत नयी सहायता में पिछले दो वर्षों की तरह ऋणों का स्थान प्रमुख था। उनका अंश प्राधिकृत कुल सहायता का 92 प्रतिशत था और शेष 8 प्रतिशत अनुदानों का अंश था। 1970-71 के कुल ऋण प्राधिकारों में से 3170 लाख डालरों के ऋण (35 प्रतिशत) विशिष्ट प्रायोजनाओं से संबंधित थे जब कि 5580 लाख डालरों के ऋण (लगभग 61 प्रतिशत) विशिष्ट प्रायोजनाओं से संबंधित नहीं थे। प्राधिकारों की 330 लाख डालरों की शेष राशि (4 प्रतिशत) ऋण शोधन सहायता के लिए दी गयी थी। ऋण प्राधिकारों में प्रायोजनंतर सहायता का अंश जहाँ 1969-70 में 45 प्रतिशत था वहाँ 1970-71 में बढ़कर 61 प्रतिशत

हो गया, क्योंकि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने प्रायोजनंतर ऋणों के रूप में बहुत अधिक राशि उपलब्ध करायी थी।

ऋण शोधन सहायता

160. 1970-71 के दौरान प्राधिकृत कुल ऋण शोधन सहायता (नये पुनर्वित्त ऋण प्रदान कर, वैसे ऋणों की अदायगियों के स्थगित कर, ऋणों के कार्यक्रम में परिवर्तन कर या ब्याज को रद्द/कम करके) की राशि 880 लाख डालर थी जो पिछले वर्ष की राशि से 230 लाख डालर कम थी (सारणी 30)। इस कमी के अधिकांश भाग का कारण यह था कि ब्रिटेन ने 1970-71 के लिए पिछले वर्ष में ही 180 लाख डालर की ऋणशोधन सहायता उपलब्ध करा दी थी। जापान और पश्चिम जर्मनी ने अपनी ऋण शोधन सहायता में क्रमशः 60 लाख डालर और 50 लाख डालर की वृद्धि की। 1970-71 में प्राप्त ऋण शोधन सहायता कुल ऋण शोधन प्रभारों का केवल 15 प्रतिशत थी।

सारणी 30- ऋण शोधन सहायता

(दस लाख अमेरिकी डालरों में)

	प्राधिकृत				
	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
(क) पुनर्वित्त ऋणों के रूप में					
1. आस्ट्रिया	0.9	0.5	0.9	1.1	1.5
2. बेल्जियम	---	---	1.1	1.1	1.1
3. फ्रांस	---	---	5.0	---	10.0
4. जर्मनी (पश्चिम)	---	7.2	14.6	15.5	20.8
5. इटली	---	---	5.5	7.4	---
6. ब्रिटेन	23.5	32.5	18.0	36.0	---
जोड़--क	24.4	40.2	45.1	61.1	33.4
(ख) अदायगियों के स्थगन के रूप में					
1. प्रॉपुलैटिव	---	15.0	15.0	15.0	15.0
3. अमेरिका	---	---	8.7	8.7	8.7
3. कनाडा	---	10.7	0.8	0.9	---
जोड़--ख	---	15.7	24.5	24.6	23.7
(ग) अदायगी के कार्यक्रम में परिवर्तन के रूप में					
1. जापान	2.5	6.2	16.8	19.6	25.4
जोड़--ग	2.5	6.2	16.8	19.6	25.4
(घ) अनुदानों के रूप में					
1. आस्ट्रिया	---	---	0.5	0.5	0.5
2. कनाडा	---	9.3	1.1	---	---
3. जर्मनी (पश्चिमी)	---	---	4.8	4.8	4.7
4. नीदरलैंड	---	---	0.6	0.6	0.7
जोड़--घ	---	9.3	7.0	5.9	5.9
कुल जोड़	26.9	71.4	93.4	111.2	98.4

* किन्तु, 1 अप्रैल 1971 को 1500 लाख डालरों के लिए एक नए पी. एल. 480 करार पर हस्ताक्षर किये गये, इस राशि में मई 1971 में 75 लाख डालरों की वृद्धि की गई ताकि सोयाबीन के तेल की अतिरिक्त पूर्तियों के लिए व्यवस्था की जा सके।

सारणी 30—ऋण शोधन सहायता (जारी)

(वस लाख अमेरिकी डालरों में)

	प्रयुक्त				
	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
(क) पुनर्निर्माण ऋणों के रूप में					
1. आस्ट्रिया	0.4	0.9	0.9	1.1	1.5
2. बेलजियम	—	—	1.1	1.1	1.1
3. फ्रांस	—	—	3.7	1.3	10.0
4. जर्मनी (पश्चिम)	—	7.2	14.6	16.3	20.8
5. इटली	—	—	—	—	5.5
6. ब्रिटेन	23.0	32.5	18.0	36.0	—
जोड़-क	23.4	40.6	38.3	55.8	38.9
(ख) अदायगी के स्थगन के रूप में					
1. प्र. पु. वि. बंक	—	15.0	15.0	15.0	15.0
2. अमेरिका	—	—	8.7	8.7	8.7
3. कनाडा	—	0.7	0.8	0.9	—
जोड़-ख	—	15.7	24.5	24.6	23.7
(ग) अदायगी के कार्यक्रम में परिवर्तन के रूप में					
1. जापान	2.5	6.2	16.8	19.6	25.4
जोड़-ग	2.5	6.2	16.8	19.6	25.4
(घ) अनुदानों के रूप में					
1. आस्ट्रिया	—	—	0.5	0.5	0.5
2. कनाडा	—	9.3	1.1	—	—
3. जर्मनी (पश्चिम)	—	—	4.8	5.0	4.7
4. नीदरलैंड	—	—	0.6	0.6	0.7
जोड़-घ	—	9.3	7.0	6.1	5.9
कुल जोड़	25.9	71.8	86.6	106.1	93.9

सारणी 31—विदेशी सहायता की उपलब्धि : कुल और वास्तविक

(वस लाख अमेरिकी डालरों में)

वर्ष	प्रयुक्त कुल सहायता	ऋण शोधन के लिए अदायगियां	व्याज की अदायगियां	कुल व्याज अदायगी (2+3)	उपलब्ध सहायता की वास्तविक रकम (1-4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1961-62	711	121	70	191	520
1962-63	933	101	81	182	751
1963-64	1,239	113	96	209	1,030
1964-65	1,520	145	110	255	1,265
1965-66	1,622	162	141	303	1,319
1966-67	1,509	210*	153	363	1,146
1967-68	1,570	275*	163	438	1,132
1968-69	1,218	276*	182@	458	760
1969-70	1,082	317*	189@	506	576
1970-71	1,000	339*	211@	550	450

*इसमें नीचे दिये गये पुनर्व्यवस्थित/स्थगित सहायता राशि के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
जापान	3	6	17	19	25
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	—	15	15	15	15
अमेरिका	—	—	6	6	6
कनाडा	—	1	1	1	—
जोड़	3	22	39	41	46

@ अमेरिका द्वारा 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में प्रति वर्ष 30 लाख डालरों का जो व्याज स्थगित किया गया वह इसमें शामिल नहीं है।

सहायता राशि के उपयोग की प्रवृत्तियाँ

161. किसी निर्धारित अवधि में वास्तव में प्रयुक्त की गयी सहायता राशि वर्तमान प्राधिकृत राशि के किसी विशिष्ट प्रायोजन से पूर्ण रूप से संबंध न किये गये अंश को छोड़कर अधिकांशतः पिछली अवधियों के प्राधिकरणों की श्राव्यक है। 1970-71 में प्रयुक्त की गयी उक्त राशि 10,000 लाख डालर थी जो पिछले वर्ष से 8 प्रतिशत कम थी। इस कमी का प्रमुख कारण यह था कि पी. एल. 480 पण्य संबंधी सहायता में कमी कर दी गयी थी। पी. एल. 480 शीर्षक 1 की सहायता के उपयोग में तेजी से कमी हुई अर्थात् उसकी राशि 1430 लाख डालरों से कम होकर 500 लाख डालर रह गयी। उपयोग किये गये ऋणों की राशि 8920 लाख डालर थी जो 1969-70 की तुलना में केवल 80 लाख डालर कम थी जब कि उपयोग की गयी अनुदान राशि 390 लाख डालरों से बढ़कर 580 लाख डालर हो गयी।

ऋणों की ब्याज अदायगी

162. यद्यपि ऋण सहायता का उपयोग कम हुआ फिर भी अधिकारिक विदेशी ऋणों की ब्याज-अदायगी बढ़ी रही। 1969-70 में 410 लाख डालरों और 1970-71 में 460 लाख डालरों के ब्याज की अदायगी के कार्यक्रम में परिवर्तन करने और उसका स्थगन करने के पश्चात् ब्याज की वास्तविक अदायगी की राशि में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् उक्त राशि 5060 लाख डालरों से बढ़कर 5500 लाख डालर हो गयी (सारणी 31)। इस प्रकार वास्तव में उपयोग की गयी विदेशी सहायता की राशि 5760 लाख डालरों से कम होकर 4500 लाख डालर हो गयी अर्थात् उक्त राशि तीन वर्ष पहले के स्तर की एक-तीहाई रह गयी। उपयोग की गयी सहायता राशि के संवर्धन में ब्याज-अदायगी का अनुपात इस वर्ष के दौरान 47 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया जब कि निर्यातों की श्रृष्टि से उसका अनुपात 27 प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया।

संचयी सहायता

163. 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1971 तक प्राधिकृत की गयी विदेशी सहायता की कुल राशि 1,82,250 लाख डालर थी। इसमें से 1,26,660 लाख डालर अथवा लगभग 70 प्रतिशत की राशि ऋणों के रूप में, 44,000 लाख डालर अथवा 24 प्रतिशत की राशि पी. एल. 480/665 और अन्य देशों की मद्राओं में अमेरिका से प्राप्त सहायता के रूप में और शेष 11,590 लाख डालर या 6 प्रतिशत की राशि अनुदानों के रूप में प्राप्त हुई। मार्च 1971 के अंत तक उपयोग में लायी गयी सहायता की राशि 1,58,320 लाख डालर थी जिसमें से 1,05,740 लाख डालर अथवा 67 प्रतिशत की राशि ऋणों के रूप में, 41,490 लाख डालर अथवा 26 प्रतिशत की राशि पी. एल. 480/665 और अन्य देशों की मद्रा संबंधी सहायता के रूप में, 11,090 लाख डालर अथवा 7 प्रतिशत की राशि अनुदानों के रूप में प्राप्त हुई थी (सारणी 32)।

164. कुल प्राधिकृत राशि का 50 प्रतिशत और उपयोग की गयी राशि का 53 प्रतिशत अमेरिका से प्राप्त हुआ था। कुल प्राधिकृत और उपयोग की गयी राशि का 13 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अन्तराष्ट्रीय विकास संघ से और 7 प्रतिशत ब्रिटेन तथा पश्चिम जर्मनी से प्राप्त हुआ था। सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से कुल प्राधिकृत राशि का 8 प्रतिशत और उपयोग की गयी राशि का 6 प्रतिशत प्राप्त हुआ था (सारणी 32)।

सहायता संबंधी शर्तों का उद्गारिकरण

165. पिछले तीन वर्षों में भारत को विकास संबंधी सहायता प्रदान करनेवाले कई देशों ने सहायता संबंधी शर्तों को विभिन्न

प्रकार से उद्गार बनाया है। आलोच्य वर्ष में स्वीडन और फ्रान्स ने अपनी सहायता शर्तों को उद्गार बनाया। 1970-71 में स्वीडन ने जो ऋण प्राधिकृत किये उनकी अवधि 50 वर्षों के बाद समाप्त होगी जब कि इसके पहले प्राधिकृत किये गये ऋणों की अवधि 25 वर्षों के बाद समाप्त होगी और उक्त ऋण ब्याज मुक्त ऋण थे जबकि इसके पहले के ऋणों पर 2 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। फ्रान्सीसी राजकोष द्वारा दिये गये ऋणों की ब्याज दर में वार्षिक 1/2 प्रतिशत की कमी की गयी अर्थात् उसे वार्षिक 3 प्रतिशत बना दिया गया। जैसे कि इस रिपोर्ट में और इसके पहले की रिपोर्टों में दी गयी जानकारी से स्पष्ट होता है, सहायता को प्रियर्सन आयोग द्वारा स्फारिश किये गये मानकों के अनुरूप बनाने के पहले अभी बहुत कुछ करना शेष है। 'विकास के भागीदार' के अधीन आयोग ने अपील की है कि आगे से विकास ऋण 2 प्रतिशत से अनधिक ब्याज दर पर दिये जाएँ, उनकी समाप्ति अवधि 25 और 40 वर्षों के बीच हो तथा उनके लिए 7 से 10 वर्षों तक को अनुग्रह अवधि प्रदान की जाए।

1971-72 के लिए स्वीकृत सहायता

166. भारत सहायता संघ ने जून 1971 में पेरिस में हुई अपनी बैठक में 1971-72 के लिए 12,500 लाख डालरों की कुल सहायता देने की सूचना दी। उक्त सहायता में पूर्व बंगाल से आनेवाले शरणार्थियों के लिए दी जानेवाली सहायता सम्मिलित नहीं है। उपर्युक्त कुल सहायता राशि में 56,00 लाख डालर की प्रायोजनतर सहायता, 900 लाख डालर की ऋण-शोधन सहायता, 5000 लाख डालर की प्रायोजना सहायता और 1000 लाख डालर की खाद्य सहायता सम्मिलित है। यह आशा की जा सकती है कि संघ द्वारा सूचित की गई सहायता पिछले वर्षों के विपरीत इस वर्ष पूर्ण रूप से वास्तविक प्राधिकारों का रूप प्राप्त करेगी। यहां इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के वित्तीय साधनों की तीसरी बार सम्पूर्ति करने का कार्य जहां जून 1971 तक समाप्त हो जाना चाहिए था वहां यह प्रमुख विकसित देशों द्वारा समय पर उचित कार्रवाई न किये जाने के कारण विलम्बित हो गया।

विदेशी निवेश नीति

167. इस वर्ष के दौरान सरकारी नीति के अनुसार चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन मिलता रहा फरवरी 1970 में घोषित की गयी नई औद्योगिक लाइसेंसिकरण नीति के संबंध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में विचार किया गया था। नीति के अनुसार 'बड़े औद्योगिक संस्थानों' और विदेशी उद्यमों को 'केन्द्रभूत' और 'भारी निवेश' क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना करने की अनुमति दी गयी है। इनमें वे उद्योग शामिल नहीं हैं जो औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किये गये हैं। इसके अलावा, 25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना के अधीन 'बड़े औद्योगिक संस्थान' और विदेशी संस्थाएँ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना कर सकेंगी अथवा औद्योगिक उत्पादन को विस्तारित कर सकेंगी परंतु शर्त यह है कि वे कुछ विशिष्ट निर्यात करने के वायदे करें। यह कार्रवाई सरकार की इस नीति के अंश के रूप में की गयी कि औद्योगिक क्षमता विकल्पपूर्ण और विशिष्ट रूप से स्थापित की जानी चाहिए जिससे निर्यातों के लिए विशेषकर ऐसी वस्तुओं जिनके संदर्भ में भारत की स्थिति संतोषजनक है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनुकूल प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, के निर्यातों के लिये उत्पादन को बढ़ाने में सुविधा हो सके। न्यूनतम निर्यात करने का जो वायदा किया जाना चाहिये उसका लक्ष्य यह है कि लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन किये जाने के लिए आरक्षित वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के मामले में नये अथवा अतिरिक्त उत्पादन के क्रमशः 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के बराबर के स्तर तक तीन वर्षों की अवधि के भीतर निर्यात किये जाएँ।

सारणी 32—कुल विदेशी सहायता (संबंधी)

(दस लाख अमेरिकी डालरों में)

					पी. एल. 480/ 665 सहायता और अन्य देशों की मुद्रा के रूप में सहायता				
					ऋण	अनुदान	जोड़		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्राधिकृत									
1.	तीसरी योजना तक	7,991	823	3,358	12,172
2.	1966-67 में	1,425	106	524	2,055
3.	1967-68 में	595	22	324	941
4.	1968-69 में	1,052	93	96	1,241
5.	1969-70 में	697	40	98	835
6.	1970-71 में	906	75	—	981
	जोड़	12,666	1,159	4,400	18,225
प्रयुक्त									
1.	तीसरी योजना तक	5,797	708	2,948	9,453
2.	1966-67 में	903	126	480	1,509
3.	1967-68 में	1,074	81	415	1,570
4.	1968-69 में	1,008	97	113	1,218
5.	1969-70 में	900	39	143	1,082
6.	1970-71 में	892	58	50	1,000
	जोड़	10,574	1,109	4,149	15,832

नोट : कृपया सारणी 29 की पाठ टिप्पणियाँ देखें।

सारणी 33—कुल विदेशी सहायता : स्रोत के अनुसार

(दस लाख अमेरिकी डालरों में)

मार्च 1971 तक प्राधिकृत					मार्च 1971 तक प्रयुक्त				
पी० एल० 480/665 सहायता और अन्य देशों की मुद्रा के रूप में सहायता					पी. एल. 480/665 सहायता और अन्य देशों की मुद्रा के रूप में सहायता				
ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़	जोड़
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/									
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	2,371	—	—	2,371	2,047	—	—	2,047	(13.0)
अमेरिकी	4,367	382	4,400	9,149	3,955	353	4,149	8,457	(50.2)
सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	1,362	16	—	1,378	893	14	—	907	(7.6)
पश्चिम जर्मनी	1,260	28	—	1,288	1,110	27	—	1,137	(7.1)
ब्रिटेन	1,276	16	—	1,292	1,124	15	—	1,139	(7.1)
जापान	478	1	—	479	451	1	—	452	(2.6)
अन्य	1,552	716	—	2,268	994	699	—	1,693	(12.4)
जोड़	12,666	1,159	4,400	18,225	10,574	1,109	4,149	15,832	(100.0)

नोट :—कृपया सारणी 29 की पाठ टिप्पणियाँ देखें। कोष्ठकों में दिये हुए आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं।

168. 20 जुलाई, 1970 को सरकार ने औद्योगिक मशीनों, बिजली इंजीनियरी और धातु विज्ञान से संबंधित उद्योगों जैसे इंजीनियरी उद्योगों तथा स्थायीनक उद्योगों के ऐसे 121 उद्योगों की एक विवरणात्मक सूची प्रकाशित की जहां टेक्नोलॉजी के और अधिक उपयोग किया जा सकता है और जहां विदेशी सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। विदेशी सहयोग की वास्तविक शक्तों का निर्धारण सरकारी नीति की रूपरेखा के अधीन प्रत्येक मामले के गुण अवगुण के आधार पर किया जाना चाहिये। इसके साथ ही सरकार ने यह भी संकेत किया कि तकनीकी सहयोग के संबंध में वर्तमान नीति के अधीन जिन शक्तों का पालन किया जाना चाहिये उनमें निर्यात प्रधान योजनाओं और लघु उद्योग यूनियनों के संबंध में जहां स्पष्टतः उचित हो, कुछ हद तक रियायत की जा सकती है।

169. शेयर पूंजी में गैर रिहायशी सहभागिता के लिए और ऋणों के रूप में विदेशों से लिए जाने वाले उधारों के लिए पूंजी शेयर नियंत्रक ने मिश्रित पूंजी कंपनियों को जो सहमतिपत्र प्रदान कीं, उनका कुल मूल्य 1970-71 में 12 करोड़ रुपये था जब कि वह 1969-70 में 20.1 करोड़ रुपये था। इस प्रकार इस वर्ष जो कमी हुई उसमें नई शेयर पूंजीगत सहभागिता, वॉनस शेयरों और विदेशों से प्राप्त ऋणों के मामले में क्रमशः हुई 5.4 करोड़ रुपया, 0.1 करोड़ रुपये और 2.6 करोड़ रुपया की कमी शामिल है। इस वर्ष विदेशों से ऋणों की कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई। 1970 में अनुमीक्षित किये गए सहभागिता करारों की संख्या 183 थी जब कि उक्त संख्या 1969 में 134 थी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति

170. इस वर्ष के अधिकांश भाग में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक शांत रहा किन्तु जब अमेरिका सहज मुद्रा नीति अपनाने लगा और इस कारण अमेरिका से बड़ी भारी मात्रा में अल्पावधि निधियां बाहर जाने लगीं तब, प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय भुगतान स्थिति के बावजूद मई 1971 के आरम्भ में मुद्रा संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। अमेरिकी भुगतान शेष में 1970 में 107 खरब डालरों का भारी घाटा विद्यमान था, 1971 की पहली तिमाही में घाटे की राशि 55 खरब डालर थी। इस प्रकार घाटे की वार्षिक वृद्धि वर 1970 की तुलना में जुगुनी से अधिक थी। जहां 1969 में सरकारी समझौते के आधार पर अमेरिकी भुगतान शेष में 27 खरब डालरों का अधिशेष विद्यमान था वहां अल्पावधि पूंजी की गतिविधियों के कारण 1970 में भारी घाटा पाया गया। अमेरिका के चालू लेखों की स्थिति में 1970 में 1969 की अपेक्षा थोड़ा सुधार हुआ। व्यापार अधिशेष की राशि जहां 1969 में 8 खरब अमेरिकी डालर थी वहां 1970 में बढ़कर 22 खरब अमेरिकी डालर हो गई, फिर भी जहां 1969 में 80 खरब डालरों से अधिक गैर-सरकारी चलमुद्रा निधियां प्राप्त हुईं वहां 1970 में उसका विपरीत स्थिति विद्यमान रही और 60 खरब डालरों की निधियां बाहर गईं।

171. अमेरिका के आर्थिक क्षेत्र में बराबर जो मंदी पाई जाती रही उससे अमेरिका को अपनी नियंत्रित मुद्रा नीति को इस प्रकार बदलना पड़ा कि सहज रूप से निधियां उपलब्ध हो सकें। इसके फलस्वरूप विभिन्न यूरोपीय क्षेत्रों में विभेदक ब्याज दर की व्यवस्था की गई। इन विभेदक ब्याज दरों के कारण अल्पावधि पूंजी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने लगी और इससे 1971 की पहली तिमाही में भुगतान शेष में घाटे की मात्रा बढ़ गयी। अप्रैल 1971 तक न्यूयार्क खजाना बिल दरों में हुई वृद्धि और पश्चिम यूरोप की आधिकारिक भांजन दरों में बराबर हुई कमियों के कारण विभेदक ब्याज दर में आनुपातिक कमी हुई किन्तु विभेदक ब्याज दर के कारण यूरोप के भीतर भारी मात्रा में जो निधियां आ

चुकी थीं उनसे यूरोपीय देशों की अर्थ व्यवस्था में एक ऐसी चलनशीलता आ गई थी जो पश्चिम जर्मनी सहित कुछ देशों के लिए स्वीकार्य नहीं थी और उक्त देशों के विचार से इस परीस्थिति में सुधार लाना कठिन था।

172. इस प्रसंग में विनिमय दरों में किये जाने वाले परिवर्तनों की भूमिका, अपने विदेशी लेखों को शीघ्रतापूर्वक समायोजित करने के अमेरिका के दायित्व, नियंत्रण मुक्त यूरोपीय डालर बाजार के स्वरूप, तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के समायोजन के वर्तमान तंत्र की कार्यप्रणाली पर सामान्यतः खुले तौर पर उच्चस्तरीय विचार विमर्श और घोषणाएं होनी लगीं और इसके फलस्वरूप मुद्रागत, विशेषकर ड्यूश मार्क के सममूल्यों में परिवर्तन होने की प्रत्याशा के कारण अमेरिका से भारी मात्रा में सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए निधियां बाहर जाने लगीं।

173. इस परीस्थिति में जर्मन और डच प्राधिकारियों ने यह निश्चय किया कि अपनी मुद्राओं को बाजारों में आने दिया जाए। स्विट्जरलैंड और आस्ट्रिया ने अपनी मुद्राओं के मूल्य में क्रमशः 7.07 प्रतिशत और 6.05 प्रतिशत की वृद्धि की और बेल्जियम ने सभी पूंजीगत अदायगियों को आधिकारिक बाजार से, जहां डालर को नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम का समर्थन प्राप्त है, विदेशी मुद्रा के निर्बाध बाजार में अंतरित किया, किन्तु सभी चालू अदायगियों को आधिकारिक बाजार तक सीमित किया गया।

174. अल्पावधि पूंजी की गतिविधि के विस्तार तथा अस्थिरता के कारण भुगतान संबंधी असंतुलनों से उत्पन्न तनाव की स्थिति तीव्र हो गयी और उससे राष्ट्रीय प्राधिकारियों की मुद्रागत स्वायत्तता में बाधा पड़ी। यूरोपीय डालर बाजार इन गतिविधियों के लिए न केवल बहुत अधिक सक्षम माध्यम, अपितु ऐसी निधियों का उल्लेखनीय स्रोत भी सिद्ध हुआ। अतः आलोच्य वर्ष के अंत के आसपास दस राष्ट्रों के वर्ग के केंद्रीय बैंकों ने इस बात का फार किया कि बाजार में और राशियां जमा न की जाएं। इसके साथ ही उक्त केंद्रीय बैंक यूरोपीय डालर बाजार को विनियमित करने के उपायों पर विचार कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय चल-मुद्रा और कम विकसित देश

175. यूरोपीय डालर बाजार को विनियमित करने के द्वारा मुद्रा विनिमय तंत्र को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय चलमुद्रा की अतिशयता की समस्या पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में इस बात पर ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय चलमुद्रा में 1970 में जो कुल वृद्धि हुई उसका अधिकांश भाग विकसित देशों का था। विश्व की कुल प्रारक्षित निधियों में, जिनमें निधि में विद्यमान सोने, विदेशी मुद्रा, विशेष आहरण अधिकार और प्रारक्षित राशि की स्थिति सम्मिलित है, 142 खरब डालरों की वृद्धि हुई, जब कि 1969 में केवल 7.4 खरब डालरों की वृद्धि हुई थी। कम विकसित देशों की प्रारक्षित निधियों में जहां 1969 में 15 खरब डालरों की वृद्धि हुई वहां 1970 में 26 खरब डालरों की वृद्धि हुई किन्तु विकसित देशों की प्रारक्षित निधियों में इस वर्ष 117 खरब डालरों की वृद्धि हुई जब कि उनमें पिछले वर्ष 7 खरब डालरों की कमी हुई थी। 1970 में अंतर्राष्ट्रीय चलमुद्रा में जो कुल वृद्धि हुई उसमें 121 खरब डालरों की वृद्धि केवल विदेशी मुद्राओं में हुई। कम विकसित देशों की विदेशी मुद्राओं में जहां केवल 19 खरब डालरों की वृद्धि हुई वहां विकसित देशों की विदेशी मुद्राओं में 102 खरब डालरों की वृद्धि हुई। इससे इस बात का पता चलता है कि प्रमुख रूप से औद्योगिक यूरोप और जापान को अत्यधिक मात्रा में डालर प्राप्त हुए। 1970 के आरम्भ में 8530 लाख डालर तक के विशेष आहरण अधिकारों का जो वितरण किया गया वह इस

वर्ष के दौरान कम विकसित देशों की प्रारक्षित निधियों में हुई सामान्य वृद्धि के लगभग एक तिहाई अंश का परिचायक है। किन्तु, विकसित देशों के मामले में 26 खरब डालरों के विशेष आहरण अधिकारों का जो नियतन हुआ वह उन देशों की प्रारक्षित निधियों में हुई वृद्धि की एक चौथाई से कम अंश का कारण था।

176. आलोच्य वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय चलमुद्रा में जो भारी वृद्धि हुई उससे विकासशील देशों को बहुत कम लाभ हुआ। वस्तुतः अगर विशेष आहरण अधिकारों के नियतन नहीं किये गये होते तो उन देशों की स्थिति 1969 की तुलना में कम स्वस्थ रही होती। स्वस्थ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध स्थापित करने के लिए अतिरिक्त चलमुद्रा का सुव्यवस्थित निर्माण आवश्यक है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए चलमुद्रा के नये साधन के रूप में रहनेवाले विशेष आहरण अधिकारों को संरक्षित करने और सशक्त रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। 1970 में चलमुद्रा की अत्यधिक माया की जो स्थिति उत्पन्न हुई (वह 1971 में भी जारी है) उसके रोकने के लिए कतिपय समायोजन आवश्यक हैं, किन्तु, उनके कारण सामाजिक रूप से धीरे धीरे विकास करने वाले विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन का प्रवेश

177. यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन का प्रवेश होने की संभावना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र की एक दूसरी महत्वपूर्ण गतिविधि है। इससे स्टर्लिंग की भूमिका में काफी तेजी से परिवर्तन होने का पूर्वानुमान है। ब्रिटेन ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय को यह स्पष्ट कर दिया है कि वह समुदाय में अपने प्रवेश के बाद आधिकारिक बकाया स्टर्लिंग राशिचों में व्यवस्थित रूप से और क्रमशः कमी करने के लिए प्रस्तुत है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के ब्रिटेन द्वारा दिये गये इस वचन के अलावा स्टर्लिंग की आरक्षित राशि की भूमिका को भी हटा देने के संबंध में व्यापक रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है। फिलहाल भारत सहित स्टर्लिंग के आधिकारिक धारकों के संदर्भ में स्टर्लिंग के कुर्ज में परिवर्तन करना पर्याप्त महत्व की बात होगी। अतः वैकल्पिक आरक्षित आस्तियों और वैकल्पिक मध्यस्थ मुद्रा/मुद्राओं का पता लगाना होगा किन्तु, इन व्यवस्थाओं से चलमुद्रा, अर्जन क्षमता या विनियमन मूल्य में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के एक सहायोगी देश द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव से भारी खतरा पैदा हो सकता है। वह प्रस्ताव इस प्रकार है: बकाया स्टर्लिंग की राशिचों के वर्तमान धारकों को जहाँ फिलहाल उनके पास रहने वाली बकाया राशिचों के एक निर्धारित प्रतिशत के संदर्भ में गारंटी प्रदान की जाती है उससे कम प्रतिशत की राशिचों के लिए गारंटी प्रदान की जानी चाहिए और साथ ही गारंटी की अवधि को भी बढ़ा देना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार

178. मई 1971 में यूरोप में जो चलमुद्रागत संकट उत्पन्न हुआ उसके कारण प्रत्याशित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र के सुधार के प्रयत्नों में और तीव्रता लायी गयी है। तदनुसार, इस वर्ष विनिमय की दैनिक बाजार दरों को अधिक लचीला बनाए जाने की प्रक्रिया के सुधार के एक आधार के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त होती सी प्रतीत होती है। इसके साथ ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की चलमुद्रा दरों की घट-बढ़ के मार्जिन को कम करने की विश्वास में उक्त देश स्वयं प्रयत्न कर रहे हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के वित्त मंत्रियों ने 15 जून, 1971 को अपनी चलमुद्राओं में एक-दूसरे देश की चलमुद्रा के संदर्भ में होनेवाली अधिकतम

संभाव्य घट-बढ़ों के स्वरूप में कमी लाने की विश्वास में प्रारंभिक कदम उठाने का निश्चय किया था। किन्तु, 10 मई 1971 से इंग्लिश मार्क और नीदरलैंड गिल्डर के भारी मात्रा में जारी हो जाने से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह कदम उठाया नहीं जा सका यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की चलमुद्राओं के बीच विनिमय संबंधी स्थायी बाजार-दरों के कारण उन देशों की अर्थव्यवस्था को समान्य लाभ प्राप्त होगा। किन्तु, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र की विधियों के अधीन बाजारों में कोष के सदस्य देशों की चलमुद्राओं में जिन मार्जिनों के भीतर घट-बढ़ हो सकती है उन मार्जिनों की वृद्धि होने के साथ साथ यदि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की चलमुद्राओं की उपयुक्त गतिविधि जारी रही तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय से बाहर के देशों की चलमुद्राओं के उक्त समुदाय की चलमुद्राओं की तुलना में हानि होगी। कम विकसित अर्थव्यवस्थावाले देशों की चलमुद्राओं की उन देशों की अपेक्षाकृत कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक हानि होगी।

विश्व व्यापार और सहायता

179. 1970 में मूल्य की दृष्टि से विश्व व्यापार में 1969 की तरह 14½ प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु, परिणाम की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में विश्व व्यापार में 2½ प्रतिशत कम अर्थात् 8½ प्रतिशत की वृद्धि हुई। विकासशील देशों के व्यापार पर उनके आयात-निर्यात के संतुलन में बाधा पड़ने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कम विकसित देशों के निर्यातों के परिमाण में 1869 की 7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु, उनके मूल्यों में जहाँ पिछले वर्ष 11½ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ इस वर्ष 11 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। परन्तु, विकसित देशों के निर्यातों के मूल्य की वृद्धि-दर इस वर्ष जहाँ 15 प्रतिशत से बढ़कर 16½ प्रतिशत हो गई वहाँ उनके परिणाम की वृद्धि दर 11 प्रतिशत से कम होकर 9 प्रतिशत हो गयी।

180. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कम विकसित देशों की विकास सहायता दिये जाने के संदर्भ में पियर्सन रिपोर्ट में सिफारिश किये गये मानकों का उल्लेख किया गया था और उसमें यह भी बताया गया था कि 1969 में वास्तविक सहायता की राशि उन मानकों से कम थी। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि पर्याप्त मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय चलमुद्रा के रहने से विकास सहायता प्रदान करने की क्षमता रखनेवाले देशों के भुगतानशेष संबंधी तनाव दूर हो जाते हैं और सहायता की राशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जाती है। फिर भी अधिकतर विकसित राष्ट्रों की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में काफी वृद्धि होने के बावजूद 1970 में सहायता की मात्रा में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्यों से विकासशील देशों को मिलनेवाली वास्तविक सहायता की मात्रा निर्यात ऋणों तथा निजी निवेशों की वृद्धि के कारण बढ़ गयी थी, किन्तु, आधिकारिक विकास सहायता 1969 के स्तर पर ही थी। किन्तु, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों से मिलने वाली आधिकारिक विकास सहायता में सहायता देने वाले देशों के कुल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत की दृष्टि से इस वर्ष कमी ही हुई जब कि कुल वास्तविक वित्तीय सहायता की मात्रा पिछले वर्ष के स्तर पर ही रही।

मूल्यांकन और संभावनाएँ

181. पिछले पंद्रहवाँ वर्ष में बैंक के लेखा वर्ष 1970-71 के दौरान भारतीय अर्थ व्यवस्था में पायी गयी गतिविधियों का जो विश्लेषण

*प्रारक्षित निधि में हुई यह वृद्धि कम विकसित देशों के बीच भी असमान थी। जो देश प्रमुख रूप से पेट्रोलियम, खनिज पदार्थों अथवा निर्मित वस्तुओं का निर्यात करते हैं, उक्त वृद्धि का आधा भाग उन से संबंधित था।

किया गया है उससे यह संकेत मिलता है कि एक ओर तो अर्थ व्यवस्था लगातार दूसरे वर्ष भी चौथी योजना के लिए निर्धारित दर पर विकास कर सकी किन्तु दूसरी ओर वह फिलहाल कीठन परिस्थितियों से भी गुजर रही है। अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में सर्वाधिक शांन्तीय पहलू मूल्य-स्थिति है। इस वर्ष के प्रारम्भ में मूल्यों पर वृद्धि का भारी दबाव दिखायी पड़ा। किन्तु बाद में विभिन्न प्रकार के प्रयासों के कारण मूल्यों में कमी आयी। फिर भी हाल ही के महीनों में मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति पुनः पायी जाने लगी। औद्योगिक कच्ची सामग्री के छोड़कर शेष सभी वर्गों की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की यह प्रवृत्ति पायी गयी, औद्योगिक कच्ची सामग्री में से रुई के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। कई निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इन वस्तुओं में रासायनिक पदार्थ, मशीनों और परिवहन के उपकरण तथा निर्मित सामग्री शामिल हैं जो उद्योगों और निर्यातों के भावी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

182. पूर्ति के संदर्भ में जहाँ लगातार चार वर्षों से अच्छे मानसून के कारण अनाजों की स्थिति में सुधार हुआ है और सरकार के पास विद्यमान उनके स्टाक की स्थिति संतोषजनक रही है वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मानसून के कारण यह स्थिति जारी नहीं रह पाएगी। काफी क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, कुछ क्षेत्रों पर भयंकर बाढ़ों और कुछ पर भारी सूखे का प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक खाद्य फसलों का संबंध है उनमें जितनी वृद्धि होगी उतनी की कमी भी होगी। नकदी फसलों के संदर्भ में उत्पादन प्रायः असमान और सामान्यतः निराशजनक था और निकट भविष्य में उनकी स्थिति संभवतः शांन्तीय ही रहेगी।

183. औद्योगिक उत्पादन में होनवाली वृद्धि की दर चौथी योजना के लिए निर्धारित दर से काफी कम हो गयी है। अभी कुछ समय से प्रतीत होता है कि उसकी वृद्धि दर में कुछ हद तक मंदी आ गयी है। लोहा, इस्पात और कोयले जैसे महत्वपूर्ण मूल उद्योगों और औद्योगिक मशीनों तथा परिवहन उपकरण जैसे पूंजीगत माल से संबंधित उद्योगों में उत्पादन के संदर्भ में समग्रतः कमी पायी गयी है। उपभोक्ता सामग्री में से सूती वस्त्र के उत्पादन में गतिहीनता बनी रही। कच्ची सामग्री की कमी, सरकारी क्षेत्र के निवेश में जारी रहनेवाली मंदी, पावर और परिवहन संबंधी बाधाएँ और तनावपूर्ण औद्योगिक संबंध उक्त मंदी की स्थिति के कारण थे।

184. मांग के संदर्भ में मुद्रा-पूर्ति की स्थिति में बराबर वृद्धि होती रही है। इस मुद्रा-विस्तार का प्रमुख कारण बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाला वास्तविक ऋण रहा है जिसमें असाधारण वृद्धि हुई है। इसके विपरीत बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में समग्र रूप से और वृद्धि दर की दृष्टि से भी थोड़ी सी वृद्धि हुई है। इस वर्ष के दौरान बैंकों ने रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ऋण में बकाया स्तर के लगभग एक-तिहाई तक कम कर दिया है। बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले ऋण में जो वृद्धि हुई उसका कारण बजट संबंधी कार्यकलापों में बढ़ता हुआ असंतुलन है। इस असंतुलन का प्रमुख कारण यह है कि कुल व्ययों में कम वृद्धि होने के बावजूद कुल प्राप्तियों में हुई वृद्धि की दर काफी कम थी। यह असंतुलन विशेष रूप से उन राज्य सरकारों में पाया गया जिन्होंने केंद्रीय सरकार की तुलना में रिजर्व बैंक से प्राप्त होनेवाली ऋण की दृष्टि से राशि का उपयोग कर लिया था। यद्यपि केंद्रीय सरकार ने विकास की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने और पूर्व बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को अस्थायी शरण प्रदान करने के लिए 1971-72 के बजट में कर राजस्व को बढ़ाने के कई कदम उठाये हैं फिर भी शरणार्थी समस्या इतनी व्यापक हो चुकी है कि वित्तीय साधनों पर

असहनीय बोझ-सा आ पड़ा है। राज्य सरकारों की समग्र बजट स्थिति भी काफी हद तक मुद्रा विस्तार का कारण बनी रहती है।

185. अर्थव्यवस्था में निवेश का जो कार्य होता है उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में सामान्य सुधार पाया जाता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लघु उद्योग और कृषि जैसे अग्रसार क्षेत्रों को प्राप्त होनवाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए किये गये विभिन्न प्रयत्नों के कारण उन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में निवेश हो सका है। साथ ही, यदि चौथी योजना की प्रत्याशाओं की पूर्ति करनी है तो यह आवश्यक है कि निवेश की कुल मात्रा को बढ़ाया जाए।

186. अर्थव्यवस्था के विदेशी क्षेत्र में बरबर दबाव पड़ते रहने के संकेत उपलब्ध हो रहे हैं। 1970 के कैलेंडर वर्ष में व्यापार और चालू खाते में 1969 के कैलेंडर वर्ष की अपेक्षा अधिक घाटे पाये गये। इसका प्रमुख कारण यह है कि महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री और रुई तथा इस्पात जैसी मूल निर्मित वस्तुओं के देशी उत्पादन में कमी हो जाने के कारण आयातों के लिए मांग बढ़ती जा रही है। निर्यातों में काफी लंबे अरसे तक कम वृद्धि होती रही है और अभी हाल ही में उनकी वृद्धि-दर में सुधार के संकेत दिखाई पड़े रहे हैं। किन्तु अब भी दीर्घाधिकार रूप से देश के निर्यातों में अधिक वृद्धि होने का कोई स्पष्ट संकेत उपलब्ध नहीं है। देश में कच्ची सामग्री की कमी के कारण मूल्यस्वरूप में वृद्धि हुई और निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन में विलंब हुआ, इस कारण निर्यात के विकास में बाधा पड़ी।

187. यह सक्ष्य है कि अस्थायी कारणों से इनमें अनेक कीठनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं और शीघ्र ही ये कीठनाइयाँ दूर हो जानी चाहिए। यह बात विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादन के उन क्षेत्रों के लिए लागू होती है जहाँ कच्ची सामग्री की कमी विकास के मार्ग में बाधा का प्रमुख कारण रही है। आयात-नीति को हाल ही में उदार बनाया गया, इस से उद्योगों और निर्यातों के क्षेत्रों को इस दिशा में पर्याप्त सहायता प्राप्त होगी। दीर्घकालीन दृष्टि से यह अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्ष प्रारंभ की गयी आयात प्रक्रिया के अनुरूप विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले अल्पाधिकार और दीर्घाधिकार ऋणों के विन्यास को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अर्थ व्यवस्था ने पर्याप्त प्रगति की है और इसे आगे भी जारी रखा गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 1900 नई शाखाएँ खोलकर अपनी क्षेत्रीय व्यापकता को काफी बढ़ाया है। उक्त शाखाओं में से अधिकांश शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोली गयीं और इस प्रकार पहले के अनेक बैंक रहित केंद्रों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की गयीं। तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षणों की समाप्ति के बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पिछले क्षेत्रों की सक्षम औद्योगिक प्रयाोजनाओं को बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित कदम उठाये हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ है कि पूर्वी क्षेत्र में बंद किये गये औद्योगिक यूनिटों को पुनर्व्यवस्थित करने या बंद किये जाने की स्थिति में रहनेवाले यूनिटों को पुनर्निर्मित करने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना की गयी। राष्ट्रीय बैंकों ने राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में अपनी ऋण-नीतियों को पुनर्व्यवस्थित किया है और विशेष रूप से कम साधनवाले ऋणकर्ताओं की सुविधा के लिए बनायी गयी योजनाओं को कार्यान्वित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। ऋण गारंटी निगम लघु उद्योगों से भिन्न छोटे ऋणकर्ताओं को इन बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करेगा। लघु उद्योगों के लिए ऐसी सुविधाएँ पहले से ही उपलब्ध थीं। उक्त निगम की स्थापना से बैंकों को महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। अग्रणी बैंक योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 165 जिलों में जिंसा सर्वेक्षण कार्य समाप्त कर दिया

हैं और नये सिरों से पत्ता लगाये गये केंद्रों को बैंकों के बीच वितरित करने के लिए आवश्यक समन्वयन कार्य प्रारम्भ किया गया है। इससे जिला ऋण योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में समन्वित रूप से कार्य करने का मार्ग खुलेगा। छोटे कृषक विकास एजेंसियां तथा सामान्य कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियां कई चुने हुए जिलों में स्थापित की गयी हैं। औद्योगिक क्षेत्र में कच्ची सामग्री के वितरण की वर्तमान प्रणाली को सुधारने के उद्देश्य से खनिज और धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम के कार्यक्षेत्र का व्यापक बनाने के साथ साथ रूई निगम, जूट निगम और काजू निगम नामक तीन संस्थाओं की स्थापना की गयी है और वे कार्य करने लग गयी हैं। औद्योगिक नीति के संबंध में, पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों और लघु उद्योगों के हित की दृष्टि से स्पष्ट रूप से नीति का पुनर्निर्धारण किया गया। 'संयुक्त क्षेत्र' के विकास के लिए वृत्त समिती की रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कदम उठाये गये।

188. कृषि क्षेत्र में नयी टेक्नालोजी के प्रयोग को व्यापक बनाने की दिशा में भी प्रगति जारी है। सिंचाई की क्षमता का अधिक उपयोग, व्यापक क्षेत्र में विकसित बीजों और उर्वरकों का उपयोग तथा कृषि की अच्छी प्रणालियों का प्रयोग किये जाने से यह स्पष्ट है कि जन्ता की अनाजों से संबंधित मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति उचित मात्रा में हो सकती है। किन्तु अब भी कुछ ऐसे व्यापक क्षेत्र हैं जो मानसून की विफलताओं के शिकार हो गये हैं। अनाजों के संवर्धन में भी गेहूँ में अधिकांश प्रगति हुई है। मूखी खेती की प्रणालियों को तैयार करने और गहरी भूमि से जल निकाले जाने के लिए किये जानेवाले प्रयत्नों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा इस देश में जहाँ चावल प्रमुख खाद्य पदार्थ है, अन्न समस्या का दीर्घकालीन समाधान करने के लिए चावल संबंधी टेक्नालोजी में विकास करने की आवश्यकता है। इसका यह तात्पर्य निकलता है कि इस दिशा में किये जाने वाले अनुसंधानों को और सशक्त करने की आवश्यकता है। नकदी फसलों के लिए उपयुक्त टेक्नालोजी का विकास करने की दिशा में हुई प्रगति अपर्याप्त ही है। इन अपर्याप्ताओं को दूर करने के लिए अनुसंधान के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

189. इन गतिविधियों से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था पहले से कहीं अधिक अच्छी है और इस कारण बराबर विकास होता रहेगा। कृषि में जो प्रगति हो रही है उससे औद्योगिक उत्पादों के लिए एक व्यापक बाजार खुलने आ रहा है। इस स्थिति का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए इसके लिए इस बात की अपेक्षा है कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा किये जाने वाले निवेशों में वृद्धि की जाए। इसके लिए इस बात की भी आवश्यकता होगी कि सरकारी और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्रों में संगठन संबंधी जो विभिन्न प्रकार की कमियाँ हाल ही के वर्षों में प्रकाश में आयी हैं उन्हें दूर किया जाए और औद्योगिक संबंधों में सुधार लाया जाए।

190. किन्तु फिलहाल सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि अर्थव्यवस्था में उचित मात्रा की मूल्य-स्थायिता बनाये रखी जाए। सरकारी क्षेत्र के बजट संबंधी कार्यकलापों के फलस्वरूप अधिकांशतः मुद्रा उपलब्ध के संदर्भ में जो भारी वृद्धि होती आ रही है उससे इस संबंध में कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यदि मुद्रा उपलब्ध में होनेवाली इन वृद्धियों और वास्तविक आय में होनेवाली वृद्धियों के बीच उचित संतुलन नहीं लाया जाए तो संभव है कि मूल्य स्थिति पुनः एक बार नियंत्रण से बाहर चली जाए। सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र के बीच बैंक ऋण के उपयोग के संबंध में भी संतुलन आवश्यक है। इसके लिए यह अनिवार्य होगा कि दोनों क्षेत्रों द्वारा बैंक ऋण का जो उपयोग किया जाता है उस पर भी अत्यंत सावधानी से नियंत्रण लगाया जाए।

इसके अलावा कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए उचित मामलों में प्रत्यक्ष नियंत्रण जैसे प्रयत्न भी करने होंगे।

2. औद्योगिक विस्तार की गतिविधियाँ

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्याकलाप और नीतियाँ

191. आलोच्य वर्ष में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भा. औ. वि. बैंक) अपने कार्यकलापों के क्षेत्र को विस्तारित करने और उनके स्वरूप को व्यापक बनाने के लिए किये जाने वाले अपने प्रयत्नों में तीव्रता लाया। अपने संगठन-स्वरूप को सरल और कारगर बनाने तथा वित्तीय सहायता से सम्बन्धित अपनी वर्तमान योजनाओं को कार्यान्वित करने के संदर्भ में अपनी प्रणालियों और मानदंडों को सुधारने के अलावा, उसने सक्षम औद्योगिक प्रयोजनाओं को प्रवर्धित करने, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ऐसी प्रयोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए विशेष प्रयत्न किये। भा. औ. वि. बैंक विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर निर्णय लेने के लिए एक अंतर सांस्थानिक वृत्त का गठन करने के उद्देश्य से विभिन्न अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं, जिन में अग्रणी बैंक और राज्य सरकारों के उद्योग विभाग शामिल हैं, को प्रोत्साहित करने और अपने नेतृत्व के अधीन उन्हें एक मंच पर लाने की दिशा में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है। इन समस्याओं में प्रयोजनाओं का पता लगाने से लेकर विस्तृत प्रयोजना रिपोर्टों को तैयार करने और संभवतः सहायता संघ के रूप में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने तक की बातें शामिल हैं। मीयादी ऋण देनेवाली अन्य संस्थाओं के सहयोग के साथ 1969-70 में छेस प्रयोजनाओं का पता लगाने के लिए प्रारम्भ किये गये सर्वेक्षण कार्य इस वर्ष के दौरान आठ राज्यों और तीन संघ-शासित क्षेत्रों में समाप्त किये गये। तीन राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र की सर्वेक्षण रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ की गयी। इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप जिन प्रयोजनाओं की परिकल्पना की गयी है उनकी स्थापना की संभावनाओं के संबंध में सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किये जा रहे हैं। कतिपय मामलों में ऐसे विचार-विमर्शों के पहले से ही कुछ गैर सरकारी तकनीकी परामर्श सेवाओं के सहयोग के साथ कुछ परिकल्पित प्रयोजनाओं की संभाव्यता के संबंध में अध्ययन कार्य किया जा रहा है।

192. पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम परिवर्तनीय ब्याज दरों की प्रणाली का प्रवर्तन किया जाना है, जिसके संबंध में 1969-70 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। भा. औ. वि. बैंक द्वारा किये जानेवाले ऋणों की ब्याज-दरों में आलोच्य वर्ष में जो परिवर्तन किये गये, उनके कारण परिवर्तनीय ब्याज दरों का स्वरूप और विभेदपूर्ण हो गया। इस प्रकार अक्टूबर 1970 में जब उसने औद्योगिक संस्थाओं को दिये जानेवाले प्रत्यक्ष ऋणों (निर्वातों के लिए दिये जानेवाले ऋणों को छोड़कर) की सामान्य ब्याज दर में वृद्धि की और पुनः जनवरी 1971 में जब उसने रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की ब्याज दर में की गई वृद्धि को परिणामस्वरूप पुनर्वित्त/पुनर्भाजन की ब्याज दरों में वृद्धि की तब पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक यूनिटों को दिये जानेवाले प्रत्यक्ष ऋणों और पुनर्वित्त की रियायती ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

193. इस वर्ष भा. औ. वि. बैंक ने कुछ ऐसे और कदम उठाये जिनसे लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में संस्थाओं को प्रोत्साहन मिल सके। इनमें राज्य वित्तीय निगम (रा. वि. निगम) के लिए 2.00 लाख रुपये तक के मीयादी ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त की मंजूरी और उसके वितरण की क्रिया-विधियों को सरल बनाना शामिल है, इस प्रकार पुनर्वित्त योजना को लगभग सहज बना दिया गया।

194. निर्यात वित्त के क्षेत्र में अपनी वर्तमान सहायता-योजनाओं के संदर्भ में भा. ऑ. वि. बैंक वाणिज्य बैंकों के साथ प्रमुख सह-भागी के रूप में उभर आया है। उसने दो दलों अर्थात् औपचारिक परामर्श दल और तदर्थ कार्यकारी दल का गठन किया है, दोनों दलों में भा. ऑ. वि. बैंक, वाणिज्य बैंकों, रिजर्व बैंक और निर्यात ऋण गारंटी निगम के सदस्य हैं। परामर्श दल का उद्देश्य निर्यात वित्त के क्षेत्र की स्थूल समस्याओं और नीतियों पर विचार-विमर्श करना, माल और सेवाओं के निर्यातों के क्षेत्रों तथा समग्रतापूर्वक प्रायोजनाओं के क्रियान्वयन और विदेशों में संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं का पता लगाना है। निर्यात-पूर्व स्थिति में निर्यातकों को मार्गदर्शन प्रदान करना तथा संबंधित मामलों में तुरंत अनुवर्ती कार्रवाई करना तदर्थ कार्यकारी दल का उद्देश्य है। भा. ऑ. वि. बैंक ने अपने द्वारा प्रकीर्तित निर्यात योजनाओं का व्यापक प्रचार किया और बंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली तथा मद्रास में आस्थायित अदायगी के आधार पर किये जानेवाले निर्यातों का वित्तपोषण करने की क्रियाविधियों के संबंध में विचार-गोष्ठियां भी आयोजित कीं ताकि उक्त क्षेत्र के विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान हो सके।

195. 1970-71 में भा. ऑ. वि. बैंक ने कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में क्षेत्रीय समितियों का गठन किया ताकि पिछले वर्ष इन क्षेत्रों में खोले गए क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता की जाए और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया जाए और निर्दिष्ट सीमाओं तक सहायता मंजूर करने के लिए निर्णय किये जाएं। अन्य 9 क्षेत्रों में अब तक खोले गये क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों के कारण भा. ऑ. वि. बैंक क्षेत्रीय समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकेगा और वह राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा सक्षम उद्यमियों के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित कर सकेगा।

196. भा. ऑ. वि. बैंक की पहल पर 12 अप्रैल 1971 को मिश्रित पूंजी कम्पनी के रूप में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की जां स्थापना की गयी वह आलाप्य वर्ष की एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी; उक्त निगम का मुख्यालय कलकत्ता में है। निगम की प्राधिकृत और अभिदत्त पूंजी क्रमशः 25 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये है। भा. ऑ. वि. बैंक ने शंकर पूंजी में से 50 प्रतिशत राशि का अभिदान किया है, और शेष राशि का अभिदान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और संघीयकृत बैंकों ने किया है। उक्त निगम बंध किये गये या बंध किये जाने की स्थिति में रहनेवाले औद्योगिक यूनिटों को शंकर पूंजी का पुनर्गठन करने, प्रबंध व्यवस्था को सशक्त बनाने, उत्पादों का विज्ञान-प्रगति करने, टेक्नोलॉजी और श्रमिक संबंधों में सुधार करने और सरल शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था कर पुनर्गठित करने का प्रयत्न करेगा।

197. आलाप्य वर्ष में भा. ऑ. वि. बैंक के कार्य कलपों अर्थात् वित्तपोषण की सभी योजनाओं के अंतर्गत की जानेवाली मंजूरीयों और वितरणों की मात्रा 1969-1970 की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। वित्तीय सहायता (गारंटीयों को छोड़कर) की कुल मंजूरी की राशि 1970-71 में 131.1 करोड़ रुपये थी जो 1969-70 के स्तर (65.2 करोड़ रुपये) से दुगुनी थी। वितरणों की राशि में भी लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् वह राशि 1969-70 के 52.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 1970-71 में 78.4 करोड़ रुपये हो गयी। भा. ऑ. वि. बैंक की स्थापना से लेकर जून 1971 के अंत तक उसके द्वारा मंजूर की गयी सहायता (गारंटीयों को छोड़कर) की कुल राशि 466.2 करोड़ रुपये थी और वितरणों की कुल राशि 358.4 करोड़ रुपये थी। 30 जून 1971 को बकाया रहनेवाली सहायता की राशि 265.3 करोड़ रुपये थी। इनके

अलावा जून 1971 के अंत तक मंजूर की गयी गारंटीयों की राशि 31.0 करोड़ रुपये थी।

198. औद्योगिक संस्थाओं के लिए भा. ऑ. वि. बैंक द्वारा ऋणों, हमीदारी और गारंटीयों के रूप में मंजूर की जानेवाली प्रत्यक्ष सहायता (निर्यातों के लिए दी जानेवाली सहायता से भिन्न) की राशि जहाँ 1969-70 में 22 प्रायोजनाओं के संबंध में 16.3 करोड़ रुपये थी वहाँ 1970-71 में बढ़कर 33 प्रायोजनाओं के संबंध में 51.4 करोड़ रुपये हो गयी। तकनीशन-उद्यमियों द्वारा नयी टेक्नोलॉजी का काम में लाते हुए गठित की गयी अपेक्षाकृत छोटी प्रायोजनाओं पर बराबर विशेष ध्यान दिया जाता रहा और आलाप्य वर्ष में भा. ऑ. वि. बैंक ने ऐसी दो प्रायोजनाओं के लिए सहायता मंजूर की। ऐसी अन्य 16 प्रायोजनाओं (तीन सार्वजनिक क्षेत्र की प्रायोजनाओं को मिलाकर) को जिनमें नयी क्षमता का निर्माण करने या विभिन्न वर्गों के उद्योगों की वर्तमान क्षमता का विस्तार/विज्ञान-प्रगति करने की परिकल्पना की गयी थी, सहायता प्रदान करने के अलावा 15 प्रायोजनाओं को उनके प्रायोजनागत व्यय में अपेक्षा से अधिक हुई वृद्धि की पूर्ति करने और/या औद्योगिक संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में विद्यमान सनाव को दूर करने के लिए पूरक सहायता भी प्रदान की गयी। भा. ऑ. वि. बैंक की यह नीति रही है कि सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की ऐसी प्रायोजनाओं को सहायता प्रदान की जाए जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम हों और जिनका प्रबंध उनकी प्रारंभिक अवधि में तथा उसके पश्चात् कुशलतापूर्वक किया जा सकता हो।

199. औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त के क्षेत्र में इस वर्ष मंजूर की गयी राशि 25.6 करोड़ रुपये थी जो 1969-70 में मंजूर किये गये 14.3 करोड़ रुपये की तुलना में 79 प्रतिशत अधिक थी। लघु उद्योगों तथा छोटे सड़क परिवहन चालकों को दिये जानेवाले ऋणों के संबंध में जो पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाती है उसमें इस वर्ष समग्रता की दृष्टि से और साथ ही कुल पुनर्वित्त सहायता में उसके अनुपात के संदर्भ में वृद्धि होती रही। 1970-71 में 1,483 आवेदन पत्रों के संदर्भ में मंजूर की गयी 25.6 करोड़ रुपये की कुल पुनर्वित्त सहायता में से लघु उद्योग यूनिटों तथा छोटे सड़क परिवहन चालकों को 1,388 आवेदनपत्रों के संदर्भ में प्रदान की गयी सहायता की राशि 14.8 करोड़ रुपये थी, इन क्षेत्रों के लिए मंजूर की गयी सहायता की राशि 1969-70 (6.1 करोड़ रुपये) की तुलना में दुगुनी से भी अधिक थी। कुल पुनर्वित्त में ऐसी सहायता का अनुपात जहाँ 1969-70 में 43 प्रतिशत था वहाँ 1970-71 में बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया।

200. मशीनों से सम्बन्धित विलों के पुनर्भाजन की योजना से अनेक मशीन-उत्पादक और मशीनों के उपयोगकर्ता लाभान्वित हुए हैं। पुनर्भाजित विलों का प्रत्यक्ष मूल्य 1969-70 के 24.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 1970-71 में 28.5 करोड़ रुपये हो गया। इस योजना के अधीन जून 1971 के अंत तक प्रदान की गयी कुल सहायता की राशि 89.9 करोड़ रुपये थी जिस से कुल मिलाकर 209 मशीन उत्पादक और मशीनों के 1,059 खरीदार उपयोगकर्ता लाभान्वित हुए। भांजनकर्ता बैंकों को इस योजना की क्रिया-विधि संबंधी बातों से परिचित कराने तथा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे लाभान्वित होने के उद्देश्य से भा. ऑ. वि. बैंक ने हाल ही में बंबई, नई दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में योजना से संबंधित वाणिज्य बैंकों के अधिकारियों की चार विचार गोष्ठियों का आयोजन किया।

201. निर्यात वित्त योजना के अंतर्गत भा. ऑ. वि. बैंक द्वारा दी जानेवाली सहायता में भी आलाप्य वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस शीर्ष के अधीन की गयी मंजूरीयों की राशि 1969-70 के 12.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 1970-71 में 26.1 करोड़ हो

गयी। इस राशि में निर्यातकों को दिये गये प्रत्यक्ष ऋण और गारंटीयां (12.4 करोड़ रुपये) तथा निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त (13.7 करोड़ रुपये) दोनों शामिल हैं। इस्पात की पट्टीयों, छद्म और रेलवे लाइन संबंधी उपकरण, डीजल इंजन, रेल बैंगन, सूती वस्त्र उद्योग की मशीनों, पारेषण लाइन टावर, मोटरगाड़ियाँ और फुर्जों जैसे विभिन्न प्रकार के इंजीनियरी सामानों के निर्यातों के लिए सहायता मंजूर की गयी।

202. इस वर्ष भा. ऑ. वि. बैंक ने भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के विशेष डिनेचरों में 1.8 करोड़ रुपये का अभिदान किया। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को उसकी स्थापना से लेकर जून 1971 के अंत तक प्रदान की गयी कुल राशि 15.7 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, भा. ऑ. वि. बैंक ने जून 1971 के अंत तक 16 राज्य विस्तीय निगमों के बांडों और शेयरों के निर्गमों में 6.9 करोड़ रुपये का अभिदान किया।

मीयादी ऋण देनेवाली अन्य अखिल भारतीय संस्थाएँ

203. मीयादी ऋण देनेवाली अन्य अखिल भारतीय संस्थाओं के कार्यकलापों की मात्रा में भी आलोच्य वर्ष में सराहनीय वृद्धि हुई। इस प्रकार भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के मंजूरी से सम्बन्धित कार्यकलापों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई अर्थात् मंजूरीयां (रुपया तथा विदेशी मुद्रा ऋण, हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान) 1969-70 (अप्रैल-मार्च) के 22.8 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1970-71 में 43.0 करोड़ रुपये हो गयीं। 1970-71 में उसके द्वारा वितरित 29.2 करोड़ रुपये की राशि भी 1969-70 (19.8 करोड़ रुपये) के मुकाबले में काफी अधिक थी। मंजूरीयां में हुई यह वृद्धि मुख्यतः विदेशी मुद्रा और रुपये ऋणों में हुई वृद्धि के कारण हुई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के मामले में कुल मंजूरीयां (रुपया और विदेशी मुद्रा-ऋण, हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई अर्थात् उनकी राशि 1969-70 के 18.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 1970-71 में 35.0 करोड़ रुपये हो गयी, किन्तु इस वर्ष किये गये वितरणों की 17.4 करोड़ रुपये की राशि लगभग पिछले वर्ष के स्तर के समान ही थी।

राज्य विस्तीय निगमों के कार्यकलाप

204. 18 राज्य विस्तीय निगमों (तमिलनाडु, औद्योगिक निवेश निगम को मिलाकर) द्वारा 1 अप्रैल 1970 से 31 मार्च 1971 तक की अवधि में मंजूर किये गये ऋणों की कुल राशि में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई अर्थात् उक्त राशि जहाँ 1969-70 में 32.2 करोड़ रुपये थी वहाँ इस वर्ष बढ़कर 49.0 करोड़ रुपये हो गयी। उक्त अवधि में किये गये वितरण भी काफी अधिक थे अर्थात् पिछले वर्ष जहाँ 21.4 करोड़ रुपये वितरित किये गये थे वहाँ इस वर्ष 32.9 करोड़ रुपये वितरित किये गये। 31 मार्च 1971 को 127.9 करोड़ रुपये के ऋण बकाया थे जो 31 मार्च 1970 को विद्यमान बकाया ऋणों की तुलना में 23.4 करोड़ रुपये अधिक थे। 1970-71 के दौरान की गयी कुल मंजूरीयां और वितरणों में से लघु उद्योगों का हिस्सा क्रमशः 35.8 करोड़ रुपये (73.1 प्रतिशत) और 22.7 करोड़ रुपये (69 प्रतिशत) था 11 जनवरी 1971 तक अर्थात् बैंक दर में वृद्धि करने के पूर्व राज्य विस्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों पर लिए जानेवाले ब्याज की दर 7 प्रतिशत और 8 प्रतिशत के बीच थी बशर्ते कि भा. ऑ. वि. बैंक से वार्षिक 4½ प्रतिशत की रियायती दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध हो। जब बैंक दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया तब उसके परिणामस्वरूप भा. ऑ. वि. बैंक ने पुनर्वित्त की अपनी रियायती ब्याज दर को 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया, किन्तु शर्त यह थी कि विस्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणकर्ताओं से ली

जानेवाली ब्याज-दर 8.5 प्रतिशत से अधिक न हो। तदनुसार नौ राज्य विस्तीय निगमों ने अपने द्वारा किये जानेवाले ऋणों की ब्याज दरों में सामान्यतः 0.5 प्रतिशत की वृद्धि की। अन्य यूनिटों को दिये गये ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत के बीच थी। चार राज्य विस्तीय निगमों ने पिछड़े क्षेत्रों के ऋणकर्ता यूनिटों से वार्षिक 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया।

205. राज्य विस्तीय निगमों के प्रतिनिधियों के 14 वें सम्मेलन में की गयी सिफारिशों के अनुसरण में राज्य विस्तीय निगमों द्वारा विस्तीय स्त्रोतों के जुटाये जाने, उनकी लाभदायकता तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अप्रैल 1970 में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। उक्त दल ने दिसंबर 1970 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उक्त रिपोर्ट संप्रति रिजर्व बैंक आफ इंडिया के विचाराधीन है।

लघु उद्योगों के लिये वित्त व्यवस्था

ऋण गारंटी योजना

206. 1 फरवरी 1970 से संशोधित ऋण गारंटी योजना ने (जिसके विवरण पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिये गये थे) आलोच्य वर्ष में पर्याप्त प्रगति की। जून 1971 के अंत तक 140 ऋण संस्थाओं, जिनमें सभी प्रमुख वाणिज्य बैंक शामिल हैं और 58 सहकारी बैंकों तथा राज्य विस्तीय निगमों ने संशोधित योजना में भाग लिया। जून 1971 के अंत में बकाया रहनेवाली गारंटीयों की राशि 790.97 करोड़ रुपये थी जब कि यह राशि जून 1970 के अंत में 661.77 करोड़ रुपये थी। जुलाई 1960 में गारंटी योजना का प्रारंभ किया गया; तब से लेकर जून 1971 के अंत तक 200 गारंटी दायताओं से सम्बन्धित दावों के संदर्भ में ऋण-संस्थाओं को 27.15 लाख रुपये की राशि अदा की गयी है। परन्तु जिन गारंटी दायताओं के संदर्भ में यह सूचना प्राप्त हुई है कि उनका भुगतान नहीं हुआ है और इसके परिणामस्वरूप अंततः दावों का निपटान करना पड़ सकता है और उनकी राशि मार्च 1971 के अंत में 1,799 मामलों के संबंध में 589.04 लाख रुपये थी जब कि यह राशि जून 1970 के अंत में 463 मामलों के संबंध में 141.97 लाख रुपये थी।

207. संशोधित योजना का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि ऋण संस्थाओं को उपलब्ध होनेवाली गारंटी रक्षा उन्हें अपने आप प्राप्त हो जाए। फिलहाल बैंकों/निगमों द्वारा लघु उद्योगों को जैसे ही ऋण स्वीधाएँ प्रदान की जाती हैं और उनके बारे में गारंटी संगठन (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) को नियत त्रैमासिक विवरणों में सूचित किया जाता है तत्काल वे गारंटीकृत मान ली जाती हैं। इस सीमा तक उक्त उद्देश्य की पूर्ति की गयी है। इसके अलावा, संशोधित योजना के अधीन गारंटी संगठन का दायित्व पहले ही योजना की अपेक्षा अधिक हो जाता है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि ऋण संस्थाएँ लघु उद्योग-यूनिटों को अग्रिम प्रदान करने और उनकी वसूली करने में उचित सावधानी बरतती हैं, गारंटी संगठन ने अपने अधिकारियों को बैंकों की शाखाओं में भेज कर उनके त्रैमासिक विवरणों का नमूना-परीक्षण करवाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। संशोधित योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के दौरान सूचना देनेवाली शाखाओं में से 5 प्रतिशत शाखाओं को नमूना-परीक्षण के लिए चुना गया।

208. विभिन्न संस्थाएँ लघु उद्योगों को जो ऋण प्रदान करती हैं उसकी मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से गारंटी योजना का प्रारंभ किया गया है। अतः गारंटी संगठन इस ढंग से योजना को कार्यान्वित कर रहा है कि लघु उद्योगों, विशेषकर कमजोर यूनिटों को सहायता प्राप्त हो। गारंटी संगठन के सूझाव पर 74 बैंकों (प्रमुख वाणिज्य बैंकों को मिलाकर) और 16 राज्य वित्तीय निगमों ने यह स्वीकार किया है कि वे गारंटी शुल्क के 1 प्रतिशत के दसवें हिस्से का भार स्वयं अपने ऊपर उठावेंगे और वे उसे अपने घटकों से वसूल नहीं करेंगे। योजना के अधीन प्रदान की जानेवाली गारंटी सुविधाओं के कारण ऋण संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जहाँ आवश्यक हो, लघु उद्योगों को दिये जानेवाले ऋणों से सम्बन्धित अपनी शर्तों विशेषकर मार्जिन-अपेक्षा संबंधी शर्तों का उदार बनायें। ऋण संस्थाएँ उपयुक्त योजनाओं, विशेषकर योग्यता प्राप्त तकनीशनों/उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के संदर्भ में सरल शर्तों पर ऋण या गैर जमानती ऋण प्रदान कर सकती हैं। ऐसे सरल या गैर जमानती ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत आते हैं। जहाँ कोई यूनिट किसी बैंक को अपने द्वारा वय राशि की अदायगी नहीं कर पाता हो वहाँ गारंटी संगठन अविलंब उसकी पुनर्व्यवस्था की संभावना की जाँच करता है और योग्य मामलों में ऋण संस्था से यह अनुरोध किया जाता है कि वह संस्था का परिपोषण करने का एक कार्यक्रम शुरू करे।

लघु उद्योगों के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की वित्तीय सहायता

209. जुलाई 1970 से मार्च 1971 तक के 9 महीनों की अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के लिए मंजूर की गयी कुल ऋण-सीमाओं में 1969-70 की तदनुसूची अवधि में मंजूर की गयी ऋण-सीमाओं में हुई 158.8 करोड़ रुपये की वृद्धि की अपेक्षा 83.8 करोड़ रुपये की और वृद्धि हुई अर्थात् उनकी राशि उक्त अवधि में 888.3 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या 89,307 से बढ़कर 1,03,550 हो गयी अर्थात् उनमें 15.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बकाया रहनेवाले अग्रिमों की कुल राशि मार्च 1971 के अंत में 493.1 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसमें जुलाई 1969—मार्च 1970 में जहाँ 108.3 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी वहाँ मार्च 1971 तक की अवधि में 79.1 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। आलांच्य अवधि में बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किये गये ऋणों में जो अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई उस पर जून 1968 से इस क्षेत्र के प्रदान किये गये अग्रिमों में हुई वृद्धि के संवर्ध में विचार करना है; जून 1968 और जून 1970 के बीच उक्त ऋणों में 224 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह भी ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है कि कुल बैंक ऋणों में से लघु उद्योगों को प्राप्त बैंक ऋण का अनुपात जहाँ जून 1970 में 9.8 प्रतिशत था वहाँ मार्च 1971 में बढ़कर 10.6 प्रतिशत हो गया; इससे यह संकेत मिलता है कि 1970-71 के अधिक कामकाज के समय के अंतिम भाग में ऋण की जो तंगी पायी गयी उसका प्रभाव लघु उद्योग क्षेत्र को प्रदान किये जानेवाले ऋण की मात्रा पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम ही पड़ा है। लघु उद्योगों को दिये जानेवाले अग्रिमों में से औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों को जो हिस्सा प्राप्त होता है उसमें जून 1968 से वृद्धि हुई है, यह वृद्धि आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दिसंबर 1970 के अन्त तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योग यूनिटों के लिए मंजूर किये गये मीयादी ऋणों (किश्ती ऋणों को मिलाकर) की राशि 112 करोड़ रुपये थी, और इसकी तुलना में बकाया राशि 76 करोड़ रुपये अर्थात् इस क्षेत्र को दिये गये कुल ऋणों का लगभग 16 प्रतिशत थी।

210. लघु उद्योगों को दिये गये कुल ऋणों के बकाया अंश का 89 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के बैंकों (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंक तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंक) के संदर्भ में था। उस बकाया अंश का 40 प्रतिशत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों के हिस्से में था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह द्वारा लघु उद्योगों के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की राशि मार्च 1971 के अंत में 320.4 करोड़ रुपये थी जो जून 1970 के स्तर से 28 करोड़ रुपये अधिक थी। यह वृद्धि 1970-71 की तदनुसूची अवधि में हुई वृद्धि के आधे से भी कम थी। इस समूह द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों में से मार्च 1971 के अंत में 197 करोड़ रुपये की जो राशि बकाया थी वह जून 1970 के स्तर से 33.7 करोड़ रुपये (या 21 प्रतिशत) अधिक थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह द्वारा कारीगरों और अन्य योग्यताप्राप्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपनी योजना के अधीन मंजूर की गयी ऋण-राशि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा दृग्गुनी से भी अधिक थी अर्थात् मार्च 1970 के अन्त में जहाँ उक्त राशि 297 यूनिटों के संदर्भ में 3.4 करोड़ रुपये थी वहाँ मार्च 1971 के अंत में 582 यूनिटों के संदर्भ में 7.1 करोड़ रुपये थी।

211. 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लघु उद्योग यूनिटों के लिए मार्च 1971 के अंत तक कुल 459 करोड़ रुपये की ऋण सीमाएँ मंजूर की थी जो जून 1970 और मार्च 1971 के बीच हुई 47 करोड़ रुपये (या 11 प्रतिशत) की वृद्धि की द्योतक हैं। इन बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या में आलांच्य अवधि में 5779 की वृद्धि हुई। मार्च 1971 के अंत में 244 करोड़ रुपये के जो बकाया ऋण थे वे इस संवर्ध में हुई 37.2 करोड़ रुपये की वृद्धि को दिखाते हैं हालाँकि यह वृद्धि 1969-70 की तदनुसूची अवधि में हुई वृद्धि (50.7 करोड़ रुपये) से कुछ कम ही थी।

212. तकनीकी रूप से योग्यताप्राप्त उद्यमियों को उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा बनायी गयी विशेष योजनाओं का उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था। सात राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में उपलब्ध आँकड़ों से यह पता चलता है कि उन बैंकों ने अपनी सम्बन्धित योजनाओं के अधीन दिसंबर 1970 के अंत तक 540 उद्यमियों के लिए 1.35 करोड़ रुपये मंजूर किये थे।

219. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा छोटे सड़क और जल परिवहन चालकों को दी जानेवाली सहायता की मात्रा में और वृद्धि हुई। मार्च 1971 के अंतिम शुक्रवार तक इस क्षेत्र के लिए 63.9 करोड़ रुपये की जो ऋण सीमाएँ मंजूर की गयी थी वे जून 1970 के अंत में विद्यमान स्तर से 23.2 करोड़ रुपये अधिक थीं जब कि 1969-70 की तदनुसूची अवधि में उक्त सीमाओं में 20.8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। मार्च 1971 के अंत में 47.5 करोड़ रुपये की जो ऋण राशि बकाया थी, वह जून 1970 के अंत में विद्यमान बकाया राशि (30.6 करोड़ रुपये) से लगभग 50 प्रतिशत अधिक थी। औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किये गये ऋण की राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी; मार्च 1971 के अंत में मंजूर की गयी ऋण सीमाओं और बकाया ऋणों की राशियाँ क्रमशः 3.74 करोड़ रुपये और 3.17 करोड़ रुपये थीं जब कि उक्त राशियाँ मार्च 1970 के अंत में क्रमशः 1.17 करोड़ रुपये और 36 लाख रुपये थीं।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

214. 1 जुलाई 1970 से 30 जून 1971 तक की अवधि में 18.00 करोड़ रुपये के यूनिट बंधे गये जब कि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 22.83 करोड़ रुपये के यूनिट बंधे गये थे; पुनः खरीदे गये यूनिटों की राशियाँ उक्त अवधियों में क्रमशः

3.19 करोड़ रुपये और 2.03 करोड़ रुपये थी। 1970-71 में हास की जो सामान्य स्थिति पायी गयी उसका मुख्य कारण यह था कि अर्थ व्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरों में वृद्धि लायी गयी थी। इससे अपेक्षाकृत छोटे और मझौले आय वर्गों के निवेशकों के लिए उपलब्ध अन्य निवेश-माध्यमों की लाभप्रवृत्ति में सुधार हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि वित्त अधिनियम, 1970 के अधीन लगभग सभी प्रकार की वित्तीय अस्तित्वों में किये जानेवाले निवेशों से प्राप्त आय (3,000 रूपयों तक) को आयकर से छूट दी गयी थी, इसके पूर्व ट्रस्ट के यूनिटों में किये गये निवेशों तथा भारतीय कंपनियों के शेयरों से प्राप्त लाभांशों से प्रत्येक के संदर्भ में मिलनेवाली 1,000 रूपयों तक की आय (विभिन्न अल्प बचत और हाक बचत योजनाओं से प्राप्त समूचे ब्याज के अलावा) तक ही यह छूट सीमित थी।

215. बेचे गये और ट्रस्ट के पास बकाया रहनेवाले यूनिटों के कुल मूल्य की राशि 30 जून 1971 को 92.25 करोड़ रूपयों से अधिक थी और ट्रस्ट के पास बकाया रहनेवाले यूनिटों के कुल मूल्य की राशि 30 जून 1971 को 92.25 करोड़ रूपयों से अधिक थी और ट्रस्ट में पंजीकृत यूनिटधारियों की कुल संख्या 3,80,000 से भी अधिक थी। ट्रस्ट के समग्र निवेशों की राशि 30 जून 1971 को 105.14 करोड़ रूपयें थी। इन में से सामान्य शेयरों की राशि 39.66 करोड़ रूपयें (37.7 प्रतिशत), अधिमान्य शेयरों की राशि 13.08 करोड़ रूपयें (12.4 प्रतिशत), डिबेंचरों की राशि 40.89 करोड़ रूपयें (38.9 प्रतिशत) और सरकारी प्रतिभूतियों और वित्तीय निगमों के बांडों की राशि 0.45 करोड़ रूपयें (0.4 प्रतिशत) थी। शेष 11.06 करोड़ रूपयें (10.6 प्रतिशत) की राशि ऐसे डिबेंचरों से संबंधित अग्रिम जमाराशियों, जिनके लिए हमीदारी/अभिदान की स्वीकृति ट्रस्ट ने दी थी, शेयर और डिबेंचर खरीदने के लिए दिये गये आवेदनशुल्क, अग्रिम बोली जमाराशि और बोली तथा अल्प सूचना पर प्रतिबंध जमाराशियों से सम्बन्धित थी।

216. निवेश करने वाली जनता के बीच यूनिटों की बिक्री का प्रचार करनेवाले एजेंटों और स्टॉक ब्रोकर्स का जो तंत्र बना था उसमें और वृद्धि हुई। अनुमोदित एजेंटों और ब्रोकर्स की संख्या 30 जून 1971 को क्रमशः 2,756 और 320 थी, यह संख्या पिछले वर्ष की उसी तारीख को क्रमशः 2,303 और 315 थी। ट्रस्ट के कार्यालयों के काउंटरों पर जो बिक्रियाएँ होती हैं उनके अलावा बड़े-बड़े बैंकों की सभी शाखाओं में तथा वेश भर के लगभग 18,000 हाकधरों में यूनिट बेचे जाते हैं।

217. पिछली रिपोर्ट में ट्रस्ट द्वारा 1 जुलाई 1970 से प्रारंभ की गई बालोपहार योजना, 1970 का उल्लेख किया गया था जिसके द्वारा किसी नाबालिग बच्चे के माता-पिता तथा निकट के रिश्तेदारों तथा अन्य व्यक्तियों को बच्चे के हित के लिए यूनिटों के रूप में पूंजी संचित करने की सुविधा प्रदान की गयी थी। उक्त योजना को अच्छी सफलता मिली है अर्थात् 30 जून 1971 तक उस योजना के अधीन बेचे गये यूनिटों की राशि 2,300 से अधिक आवेदनपत्रों के संदर्भ में 56 लाख रूपयों से अधिक थी। भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग के साथ एक "यूनिट से संबंधित बीमा योजना" बनायी जा रही है और यह योजना शीघ्र ही अमल में लायी जानेवाली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि निवेशकों, विशेषकर समुदाय के अपेक्षाकृत छोटे और मझौले आय वर्गों के निवेशकों के नियमित रूप से बचत करने तथा इन बचतों का ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश करने की सुविधा प्रदान की जाए और इसके साथ योजना की अवधि के दौरान जीवन-बीमा-रक्षा की सुविधा भी प्राप्त हो।

3. वारिण्य बैंक व्यवसाय की प्रगति

218. प्रमुख वारिण्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण अर्थव्यवस्था में उत्पन्न तीव्रता को नियंत्रण करने और राष्ट्रीय नीति तथा उद्देश्यों

के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं की अधिकाधिक तथा सुव्यवस्थित रूप से पूर्ति करने के उद्देश्य से किया गया। सरकारी आर्थिक नीति के संपूर्ण स्वरूप को हाल ही के वर्षों में इस उद्देश्य से पुनर्व्यवस्थित किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में पहले से कहीं अच्छा संतुलन तथा समान आर्थिक आधार लाया जा सके। अग्रणी बैंक योजना और शाखा विस्तार के कार्यक्रम निश्चित ही बैंकिंग सुविधाओं को क्षेत्रीय दृष्टि से अधिक व्यापक बनाएंगे। बैंकिंग संघटन के माध्यम से सुनिश्चित ढंग से सामाजिक प्राथमिकताओं की पूर्ति में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा उपयोग में लायी जानेवाली वर्तमान प्रणालियों और मानकों में सुधार लाने का प्रारम्भ किया जा चुका है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण संबंधी नीतियों को पर्याप्त मात्रा में दिशांतरित कर दिया है, इसके साथ ही रिजर्व बैंक इस संदर्भ में अपनी तरफ से सुनिश्चित उपाय और मार्गदर्शन प्रदान करने का प्रयत्न करता रहा है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो उद्योग और व्यापार के संगठित क्षेत्रों की ऋण संबंधी जिन आवश्यकताओं की पूर्ति बैंक अब तक प्रायः अपनी तरफ से ही करते आ रहे थे उनकी पूर्ति अब भी उसी प्रकार होती आ रही है, किन्तु अब छोटे किसानों, छोटे पैमाने के उत्पादकों, फुटकर व्यापारियों, सड़क परिवहन चालकों, छोटे व्यापारियों, व्यावसायिकों और स्थानीय वित्तीय व्यक्तियों जैसे कम वित्तीय साधनवाले अनेक ऋणकर्ताओं को भी ब्याज की उचित दरों पर ऋणदाता संस्थाओं द्वारा ऋण-सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। लघु उद्योगों के क्षेत्र के लिए पिछले दस वर्षों से अधिक अवधि से एक ऋण गारंटी योजना चलायी जा रही है। इस योजना में पिछले वर्ष सुव्यवस्थित ढंग से संशोधन किया गया और ऐसी व्यवस्था की गयी कि ऐसे उद्योगों को बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋणों के लिए प्रायः अपने आप ही गारंटी-रक्षा उपलब्ध हो जाए। परंतु लघु उद्योगों की अपेक्षा कुछ और भी ऐसे छोटे ऋणकर्ता हैं जिनकी बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रायः उपेक्षा ही की जाती थी। ऐसे ऋणकर्ताओं को जिनके कार्यकलापों में पर्याप्त नियोजन-क्षमता विद्यमान है, ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने उपयुक्त मार्गदर्शी सिध्दंत जारी किये हैं। कृषि को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में भी मार्गदर्शी सिध्दंत जारी किये गये हैं, यह एक ऐसा दूसरा क्षेत्र है, जो अभी कुछ समय पहले तक वारिण्य बैंकों की ऋणप्रणाली से लगभग बाहर ही रखा जाता था। परंतु ऐसे वर्गों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये जाने में जोखिम का तत्त्व रहता ही है और उस संदर्भ में थोड़ी सी गारंटी-रक्षा की अपेक्षा भी रहती है, अतः भारतीय ऋण गारंटी निगम, लिमिटेड नाम की एक नयी सार्वजनिक सीमित कंपनी गठित की गयी है और उक्त निगम ने गारंटी प्रदान करने के लिए निर्विकट योजनाएँ बनायी हैं।

219. आगे के पैराग्राफों में संगठन संबंधी परिवर्तनों तथा बैंक ऋणों की विभिन्न योजनाओं तथा उनके संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये मार्गदर्शी सिध्दंतों के विवरण दिये गये हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए व्यापक स्वरूप के बांडों की योजना

220. चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक के लिए 18 जुलाई 1970 से केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले निदेशक बांडों का जो गठन किया गया था उसके संबंध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। पहले निदेशक-बांडों का गठन किये जाने के पश्चात् रिजर्व बैंक का 16 फरवरी 1970 का वह निदेश, जिसके अनुसार कतिपय विशिष्ट वर्गों के लेनदारों के संदर्भ में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था, 14 अगस्त 1970 को वापिस ले लिया गया और बैंकों को यह सलाह दी गयी कि उक्त निदेश में उल्लिखित विषयों के संबंध में उस तारीख के पश्चात् उनके अपने-अपने निदेशक

बोर्डों द्वारा निर्णय किये जाने चाहिए। इसके बाद केंद्रीय सरकार ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिकरण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए व्यापक स्वरूप के निदेशक बोर्डों के गठन, अध्यक्ष की नियुक्ति, प्रबंध समिति तथा अन्य समितियों की स्थापना के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध व्यवस्थाएं) योजना, 1970 नामक एक योजना बनायी। इस योजना के अधीन प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड में अधिक से अधिक 15 निदेशक होंगे। उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3(क) के अधीन यह व्यवस्था की गयी है कि धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन बनायी गयी राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध व्यवस्थाएं) योजना के अंतर्गत गठित प्रत्येक निदेशक बोर्ड में ऐसे बैंकों के कर्मचारियों और जमाकर्तारों के प्रतिनिधि तथा किसानों, कामगारों तथा कारीगरों के वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के हित का प्रतिनिधित्व करनेवाले अन्य व्यक्ति सम्मिलित किये जाएंगे। इस योजना में बैंक के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधियों और एक जमाकर्ता के अलावा किसानों, कामगारों तथा कारीगरों के वर्गों में से प्रत्येक के एक-एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गयी है। सरकार को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे एक या अधिक विषयों जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के कारोबार के लिए उपयोगी हो सकते हैं, की विशेष जानकारी अथवा उनका व्यावहारिक अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों में से अधिक से अधिक पांच निदेशकों को नियुक्त करे। अधिक से अधिक दो पूर्णकालिक निदेशक भी होंगे जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा। इनके अलावा प्रत्येक बोर्ड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्रीय सरकार के एक-एक अधिकारी होंगे।

221. इस योजना में यह व्यवस्था भी की गयी है कि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक बोर्ड में दो कर्मचारियों की नियुक्ति हो। उनमें से एक बैंक के कामगारों में से और दूसरा कामगारों से भिन्न बैंक के कर्मचारियों में से होगा। कामगार कर्मचारियों में से निदेशक की नियुक्ति संबंधित बैंक के प्रतिनिधि संघ द्वारा दी गयी तीन नामों की सूची में से सरकार करेगी। कामगारों से भिन्न कर्मचारियों में से दूसरे निदेशक की नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परामर्श लेकर सरकार करेगी।

222. इस योजना में प्रतिनिधि संघ की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है : उक्त संघ मजदूर संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन पंजीकृत हो अथवा ऐसे संघों का महासंघ हो और परिस्थिति के अनुसार मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा उचित जांच पड़ताल के बाद उक्त संघ या महासंघ इस प्रकार प्रमाणित किया गया हो कि राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति अधिकतम कामगार उसके ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने संघ को अथवा महासंघ में सम्मिलित संघों में से किसी संघ को नियमित रूप से द्रव्य राशि अदा की हो। यह भी शर्त है कि संबंधित बैंक में नियुक्त कुल कामगारों के कम से कम 15 प्रतिशत कामगार जांच पड़ताल के बाद संघ या महासंघ के सदस्य सिद्ध हों। योजना की पहली अनुसूची में राष्ट्रीयकृत बैंकों के संघों की सक्षमता की जांच पड़ताल की क्रियाविधि निर्धारित की गयी है।

223. उपर्युक्त अधिनियम के अधीन उक्त योजना को अमल में लाने के कम से कम तीस दिन पहले संसद के दोनों सदन में प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। अतः योजना 17 नवंबर 1970 को संसद के दोनों सदन में प्रस्तुत की गयी और दिसम्बर 1970 में उसपर दो सदन में विचार विमर्श किया गया।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाएँ

224. राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी समुद्रपारीय शाखाओं के संबंध में प्रत्येक देश की स्थानीय विधियों के अनुसार उस समय विद्यमान

बैंकों के नाम रहनेवाली संपत्तियों तथा अन्य आस्तियों आदि को सम्बन्धित नये बैंकों के नाम अंतरित करने के लिए उचित कदम उठा रहे हैं। जैसे कि पहले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका है, उगांडा में संबंधित दो राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय कानूनी अपेक्षाओं का पालन करते हुए सहायक कंपनियों का गठन किया है, उगांडा सरकार ने पहले इन कंपनियों के 60 प्रतिशत शेयरों को अपने अधिकार में ले लिया था। किन्तु हाल ही में इस स्थिति में परिवर्तन हुआ है और कंपनी के जिन शेयरों पर सरकार का अधिकार रहेगा उनके प्रतिशत को कम कर 49 कर दिया गया है। सहायक बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सहायक बैंक ऑफ इंडिया को अपने अधिकार में लिए जाने के संबंध में अब बातचीत चल रही है। बैंकों की मलेशिया में स्थित शाखाओं के मामले में चूंकि उस देश में विदेशी सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित बैंकों को बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति नहीं है, एक नयी कंपनी गठित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है ताकि वह तीन भारतीय बैंकों अर्थात् इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और युनाइटेड कमर्शियल बैंक की ग्यारह शाखाओं के कारोबार को अपने अधिकार में ले सके। प्रस्तावित कंपनी की चुक्ता पूंजी का 33-1/3 प्रतिशत भारत स्थित उन तीन नये बैंकों के अधिकार में रहेगा, दूसरा 33-1/3 प्रतिशत भारतीय मूल के मलेशिया नागरिकों के अधिकार में रहेगा, 30 प्रतिशत मलेशिया स्थित अन्य मलेशिया नागरिकों, कंपनियों और निगमों में विभाजित किया जाएगा और शेष 3-1/3 प्रतिशत अनियंत्रित रहेगा। सिंगापुर स्थित शाखाओं के संदर्भ में उस देश की संसद ने बैंकिंग अधिनियम, 1970 को पारित कर दिया है जो जनवरी 1971 में अमल में आया। उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी भी ऐसे बैंक को, जिसका प्रधान कार्यालय सिंगापुर के बाहर स्थित हो तभी लाइसेंस प्रदान किया जाएगा जब (1) उसकी जारी की गयी और चुक्ता पूंजी 60 लाख सिंगापुर डालरों (लगभग 1.47 करोड़ रुपये) के बराबर की राशि से कम न हो और (2) उसके पास सिंगापुर में किये जानेवाले कारोबार के संदर्भ में अनुमोदित आस्तियों के रूप में स्वयं अपने प्रधान कार्यालय की 30 लाख सिंगापुर डालरों (लगभग 73.50 लाख रुपये) से अन्योन्य निधियाँ हों। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त अधिनियम के अमल में आने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर अर्थात् दिसम्बर 1972 के अंत तक इन उपबंधों का पालन करें। इसके अलावा सिंगापुर स्थित प्रत्येक ऐसे बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वहां की सरकार द्वारा निर्धारित किया जानेवाला वार्षिक लाइसेंस शुल्क अदा करे। 1971 के लिए सिंगापुर स्थित मुख्य शाखा के लिए 50,000 सिंगापुर डालर और प्रत्येक उप-शाखा के लिए 5,000 सिंगापुर डालर का लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है और चार बैंकों, अर्थात् युनाइटेड कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने इस वर्ष का आवश्यक शुल्क अदा कर दिया है।

225. यह बात विचाराधीन है कि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं का स्वरूप भविष्य में कैसा हो।

अग्रणी बैंक योजना

226. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिसम्बर 1969 में रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भ की गयी अग्रणी बैंक योजना के मूल स्वरूप, उद्देश्यों और मौलिक कार्यक्रमों के विवरण दिये जा चुके हैं। मूल उद्देश्यों में से एक यह है कि देश में बैंक व्यवसाय संबंधी जो विकासात्मक गतिविधियाँ हो रही हैं उन्हें "क्षेत्रीय दृष्टिकोण" प्रदान किया जाए और इस प्रकार यह सुनिश्चित कर लिया जाए

कि बैंकिंग संघटन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सभी क्षेत्रों और समुदाय के सभी वर्गों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। योजना के अधीन देश के सभी जिलों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा गैर सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों के बीच विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लिये नियत किये गये जिलों में बैंक व्यवसाय के विकास की संभावना के संबंध में सर्वेक्षण करे, संस्थाओं तथा ऋण के संबंध में विद्यमान खाइयों का पता लगाये तथा उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करने की दिशा में अग्रसर हो और इस प्रकार संबंधित जिलों की आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया में अपने आपको व्यापक रूप से सम्मिलित कर दे, संक्षेप में बैंकों के माध्यम से जिले के विकास में प्रगति लायी जा सके। अतः बैंकों के समक्ष तत्काल यह कार्य उपस्थित हुआ कि वे अपने लिए नियत किये गये जिलों के संबंध में मौलिक जानकारी प्राप्त कर लें ताकि वे कार्रवाइयाँ करने के लिए उपयुक्त योजनाएँ बना सकें। इस उद्देश्य के लिए बैंकों से यह कहा गया कि वे अपने लिए नियत किये गये जिलों के वित्तीय स्त्रोतों और उनकी क्षमताओं का शीघ्र और प्रभावकारी ढंग से प्रारंभिक सर्वेक्षण करें। प्रत्येक बैंक के लिए नियत किए गये जिलों में से कुछ जिलों का सर्वेक्षण-कार्य समाप्त होने पर बैंकों के बीच अधिक समन्वयन लाने और जिला स्तर पर विकास-त्मक कार्यक्रम बनाने तथा अनुवर्ती कार्रवाइयों के कार्यक्रम का आधार निर्धारित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तीन अधिकारियों के एक दल ने अभिरक्षकों/अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनके सर्वेक्षणों के संबंध में अलग-अलग रूप से गंभीर विचार-विमर्श किये ताकि सर्वेक्षण की संभावनाओं में सुधार लाया जा सके और योजना के महत्व और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के महत्वों पर प्रकाश डाला जा सके।

227. बैंकों ने अपने लिए नियत किये गये जिलों का सर्वेक्षण कार्य पूरा करने की दिशा में अच्छी प्रगति की है। 335 जिलों में से 163 जिलों के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्टें समाप्त हो चुकी हैं और अन्य जिलों में से अधिकांश जिलों के संबंध में रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

228. बैंकों के बीच पारस्परिक सहयोग का स्वरूप निर्धारित करने और पता लगाये गये केंद्रों के नियतन की प्रणाली को स्पष्ट करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने छः शहरों अर्थात् मद्रास, कलकत्ता, पटना, कानपुर, भोपाल और दिल्ली में बैंकों के प्रादेशिक सम्मेलनों का आयोजन किया जिनमें अग्रणी बैंकों द्वारा अपने सर्वेक्षणों के वॉरान पता लगाये गये 1,194 बैंक रहित केंद्रों में से 383 केंद्र अग्रणी बैंकों के लिए और 341 केंद्र अन्य बैंकों के लिए नियत कर दिये गये। बैंकों से यह कहा गया है कि प्रत्येक जिले में जिन केंद्रों का पता लगाया गया उनमें शाखा-विस्तार का कार्य, जहाँ तक हो सके, संबंधित "अग्रणी बैंक" के तत्वावधान में किया जाना चाहिये। इस प्रणाली के अनुसरण में बैंक अपने द्वारा पता लगाये गये केंद्रों के नियतन को अंतिम रूप देने के निमित्त बैठकों का आयोजन करते आ रहे हैं।

229. जिला-स्तर पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए आधार प्रस्तुत करने, जिसमें वाणिज्य बैंकों के कार्यक्रमों और जिला विकास कार्यक्रमों में समन्वयन लाना भी शामिल है, के उद्देश्य से कतिपय बैंक जिले में कार्य करनेवाली वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों और जिला-अधिकारियों की समन्वयन समीतियाँ स्थापित कर चुके हैं।

ऋण आयोजना

230. ऋण आयोजना अथवा बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय स्त्रोतों का विवेकपूर्ण वितरण आर्थिक योजना और नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसी आयोजना का महत्व तब और बढ़

जाता है जब बैंकों को मुख्यतः उन्हीं जमाराशियों के साथ अपना कारोबार चलाना पड़ता है, जिन्हें वे जुटा पाते हैं और जब केंद्रीय बैंकों से उनके द्वारा ऋण लिये जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है और उन्हें स्वयं ही योजना तथा मुद्रा संबंधी समग्र आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। समग्र बैंकिंग संघटन के लिए रिजर्व बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जमाराशि की वृद्धि की प्रत्याशित गति, विभिन्न क्षेत्रों की सामान्य आर्थिक स्थिति और संभाव्य गतिविधियों का ध्यान में रखते हुए एक व्यापक ऋण योजना बनाने का कार्य करता है। ऋण योजना बनाने के संदर्भ में पहला कदम यह है कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश और अनाजों की उगाही, समीकरण भंडार संबंधी कार्यकलाप आदि सरकार के कुछ अत्यावश्यक वाणिज्यिक कार्यकलापों आदि से सम्बंधित कतिपय पूर्वपक्षों के लिए राशि का वितरण करने की व्यवस्था की जाए। प्राथमिकतावाले क्षेत्रों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं का सामूहिक अनुमान तैयार करना दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। अधिक कामकाज तथा कम कामकाज के समय के लिए, विशेष कर मौसमी परिवर्तनों से प्रभावित होनेवाले क्षेत्रों के संदर्भ में अलग-अलग अनुमान तैयार किये जाते हैं।

231. समग्र बैंकिंग संघटन के लिए बनायी गयी इस व्यापक ऋण योजना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक बैंक की अलग-अलग ऋण योजना पर विचार किया जा रहा है। प्रत्येक बैंक के साथ इस उद्देश्य से अलग-अलग रूप से विचार-विमर्श किये जा रहे हैं कि निधियों का उपयोग करने के लिए उसे अपना कार्यक्रम बनाने में सहायता दी जाए। इस संदर्भ में उन विशेष परिस्थितियों पर जिनमें प्रत्येक बैंक कारोबार कर रहा हो, ध्यान दिया जाता है। यह उद्देश्य भी रहता है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का पालन हो और साथ ही पर्याप्त मात्रा में अच्छी लाभदायकता भी बनाये रखी जाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जहाँ ऋण जमा अनुपात कम हो वहाँ उसे बढ़ाने की सलाह दी जाती है। चूंकि वित्तीय स्त्रोतों के पूर्ण उपयोग की योजना के संबंध में यह पहली अपेक्षा रहती है कि पर्याप्त मात्रा में ऋण का निरंतर प्रवर्तन हो, अतः बैंकों से कहा जाता है कि वे वर्तमान ऋण का पुनः उपयोग करने और ऋण को वास्तविक उत्पादक उद्देश्यों के साथ जोड़ने की संभावनाओं का पता लगायें। इसके अलावा, नयी हुई बाजार योजना के अधीन विनिमय बिल का ऋण प्रपत्र के रूप में अधिक मात्रा में काम लाने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। इस दिशा में प्रारंभिक कदम के रूप में कंपनियों के बही ऋणों आदि पर ऋण देने की वर्तमान प्रणाली को बदलकर बैंक ऐसे लेन-देनों के संबंध में आहीरा बिलों का भाजन करने की प्रणाली को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस संदर्भ में इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया है कि विशेषकर ऐसे क्षेत्रों को जिनके संबंध में बैंक अभी अपेक्षाकृत अनुभवहीन हैं, दिये गये ऋणों की बसूली को सुनिश्चित कर लिया जाए। भावी कार्यों की जटिलता को देखते हुए बैंकों से यह कहा गया है कि वे भविष्य में व्यापक ऋण योजनाएँ प्रारम्भ करने के लिए एक मजबूत संगठन तंत्र बनाने की ओर तत्काल ध्यान दें।

ऋण प्राधिकरण योजना

232. रिजर्व बैंक द्वारा 1965 में प्रारम्भ की गया ऋण प्राधिकरण योजना बैंक ऋण को योजनागत प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने के लिए किये गये उपायों में से एक है। उसमें आलोच्य वर्ष में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इस संदर्भ में उद्देश्य प्रधान दृष्टिकोण को इस प्रकार व्यापक बनाया गया है कि अधिक मात्रा में ऋण लेनेवालों पर वित्तीय नियमन लगाने की दृष्टि से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किये जानेवाले ऋण संबंधी मूल्यांकन का भी उसके अधीन लाया जा सके। ऋणकर्ताओं के वित्तीय विवरणों से उनके पिछले कार्य का जो पता चला उसके

आधार पर और साथ ही अंततः ऋण का जो उपयोग होता है उसका आधार पर भी ऋण संबंधी आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 30 जून 1970 के परिपत्र के अनुसार ऋणों के मूल्यांकन के लिए फार्मों का एक व्यापक सेट बनाया है जिससे इस उद्देश्य के लिए गठित अध्ययन दल ने अंतिम रूप दिया है। तदनुसार बैंकों के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि वे ऋणकर्ताओं द्वारा निम्नीलिखित विषयों पर प्रस्तुत किये गये आंकड़ों का एकीकृत करें और उनका अध्ययन करें :

(क) वर्तमान ऋण सीमाओं का उपयोग, (ख) कुल कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकताएँ और उपलब्ध बैंक वित्त, इस संदर्भ में इन दोनों के बीच रहनेवाली खाइयों को दूर करने के संबंध में ऋणकर्ता कंपनी की क्षमता से संबंधित आंकड़ों का भी अध्ययन करें, (ग) पिछले तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय स्थिति ; (घ) नकदी निधि की उपलब्ध मात्रा और (ङ) मियादी ऋणों के संदर्भ में प्रायोजनागत लागत और उसका वित्तपोषण। इस समय विचारणीय अन्य पहले निम्न प्रकार हैं ; अंतर कंपनी ऋण और निवेश, बड़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं का संचयन, अचल/गैर-चालू आस्तियों के अधिग्रहण के लिए अल्पावीध निधियों को वित्तीयरित करना, ऋण सुविधाओं के सुरक्षित स्वरूप या गारंटी-कर्ताओं की कम हौसियत के बावजूद गारंटी-कमीशन की अदायगी, आदि। दूसरे शब्दों में अब बैंकों से यह अपेक्षा होगी कि वे ऋण मूल्यांकन और ऋणकर्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर ऋण दें। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पहले से अच्छे समन्वयन के साथ रिजर्व बैंक ने जो विनियामक प्रणाली बनायी है उससे उचित मूल्यांकन और वित्तीय मूल्य-निर्धारण किया जा सकेगा और यह आशा की जाती है कि यह प्रणाली बैंक-ऋण के उचित उपयोग और वितरण के संदर्भ में अधिक प्रभावकारी तंत्र सिद्ध होगी। बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि वे यह न समझें कि निर्धारित फार्मों में आंकड़ों को एकीकृत करने तक कार्य समाप्त हो जाता है ; बल्कि यह समझें कि वे आंकड़े ऋण सुविधाओं के लिए प्राप्त प्रार्थनाओं पर विवेकपूर्ण निर्णय करने के लिए साधन मात्र हैं। उन्हें यह भी सुझाव दिया गया है कि नियमित रूप से वित्तीय आंकड़ों को एकत्र कर उनका अध्ययन करने से ऋणकर्ताओं के पिछले अनुभवों के आधार पर उनकी ऋण संबंधी भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में सहायता हो सकती है। सूचीकृत कतिपय बैंकों ने इस संबंध में यह संकेत किया कि ऋण सुविधाओं के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों पर प्रणालीबद्ध ढंग से कार्रवाई करने के लिए उनके अधिकारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है अतः बैंक ने यह निश्चय किया है कि आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए बंबई के बैंक प्रशिक्षण कालेज में उपयुक्त पाठ्यक्रमों की एक माला का आयोजन किया जाए।

233. जो योजना मूलतः 1 करोड़ या उससे अधिक रुपये की ऋण सीमा के लिए लागू थी, उसे मई 1971 में 25 लाख रुपये से अधिक राशि की व्यक्तिगत मियादी ऋण सीमाओं के लिए भी लागू कर दिया गया। तदनुसार बैंकों से यह कहा गया कि चाहे किसी पार्टी को समग्र बैंकिंग संघटन से उपलब्ध कुल ऋण सीमाएँ कितनी भी क्यों न हों फिर भी वे किसी एक पार्टी के लिए 25 लाख रुपये से अधिक राशि के और तीन वर्षों से अधिक अवधि में प्रत्येक व्यक्तिगत मध्यावधि या दीर्घावधि ऋण मंजूर करते समय (स्वयं या अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर) योजना के अधीन रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त कर लें। इस उपाय को इसलिए भी आवश्यक माना गया कि अब अनुसूचित

वाणिज्य बैंकों द्वारा उल्लेखनीय मात्रा में मियादी ऋण प्रदान किये हैं और इस कारण बैंकों तथा मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के कार्यकलापों के बीच समन्वयन लाने की अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रकार का नियमन इस कारण और भी आवश्यक हो जाता है कि किसी भी हालत में वाणिज्य बैंकों को औद्योगिक संस्थाओं की कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। इसके अलावा, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे रिजर्व बैंक को एक तिमाही विवरण (24 सितंबर, 1971 का समाप्त हुई तिमाही से) पेश करें जिसमें प्रत्येक तिमाही में उनके द्वारा मंजूर किये गये और तीन वर्षों के बाद प्रत्येक 10 लाख रुपये से अधिक राशि के सभी मियादी ऋणों के कतिपय विवरण दिये जाएँ।

234. ऋण प्राधिकरण योजना की कार्यप्रणाली को लचीलेपन के साथ अमल में लाया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन औद्योगिक संस्थाओं को पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो जाए जिन्हें वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा हो और जिन्हें पर्याप्त मात्रा में और कभी-कभी तत्काल ऋण सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती हो। इस प्रकार चीनी उद्योग द्वारा अनुभव की गयी गंभीर वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1971 में 12 प्रमुख बैंकों को (जो प्रमुख रूप से चीनी मिलों की वित्तीय सहायता कर रहे थे) यह सलाह दी कि अलग-अलग चीनी कारखानों के लिए पिछले मौसम की अधिकतम बकाया राशि के 125 प्रतिशत तक की अभिवर्धित ऋणसीमा मंजूर करने के पहले उन्हें रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

235. इसी प्रकार अनेक राजनीतिक और श्रमिक समस्याओं से पीड़ित पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक यूनिटों की सहायता करने के निमित्त ऋण प्राधिकरण योजना को उदार बना दिया गया ताकि वाणिज्य बैंक उस क्षेत्र के अलग-अलग यूनिटों को (कांयला कंपनियों को मिलाकर) पूर्व प्राधिकरण के बिना ही अस्थायी अथवा अत्यावश्यक ऋण सुविधाएँ प्रदान कर सकें। वास्तव में अधिक मात्रा में ऋण सुविधाएँ प्राप्त कराने के लिए या सभी कमजोर यूनिटों की वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त सभी उपयुक्त प्रस्तावों के संदर्भ में बैंक स्तर पर तथा इस योजना के अधीन सामान्यतः अविलंब कार्रवाई की जा चुकी है। इसी प्रकार उड़ीसा और असम में जहाँ उद्योगों का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है, उद्योगों की जो समस्याएँ विद्यमान थीं उन पर भी अधिक संख्या के ऋणकर्ताओं को ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के संदर्भ में समुचित कार्रवाई की गयी है।

236. जुलाई, 1970-जून, 1971 के दौरान इस योजना के अधीन ऋण-सीमाओं के प्राधिकरण के लिए बैंकों से 338 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे। उन प्रस्तावों में से अधिकांश प्रस्ताव रक्षा/निर्यात के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन कार्य और अन्य प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों में लगी हुई संस्थाओं की कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति से और कुछ प्रस्ताव ऐसी संस्थाओं के विस्तार/आधुनिकीकरण, आदि की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित थे। कतिपय आवेदनपत्रों को अस्वीकार करने के प्रमुख कारण निम्न प्रकार थे : (1) वर्तमान सीमाओं का बहुत कम ही उपयोग किया गया, (2) कच्ची सामग्री को समेटने या उनका स्टॉक करने की प्रवृत्ति पायी गयी ; (3) किसी एक पार्टी के हाथ में बैंक अग्रिम कौन्त्र हो सकते थे , (4) कंपनियों अपने वित्तीय साधनों का विभिन्न कंपनियों में निवेश कर या उन्हें ऋण के रूप में दूसरों को प्रदान कर स्वयं बैंकों से मिलनेवाले ऋणों पर बहुत अधिक मात्रा में निर्भर रहती

*निम्नीलिखित मामलों में योजना के अधीन पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है (1) निर्यातों से सम्बन्धित पोतलदानांतर ऋण के रूप में किये जानेवाले मियादी ऋण; (2) बिजली बोर्डों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिए जाने वाले तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की गारंटी पर किये जानेवाले मियादी ऋण और (3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और कृषि पुनर्वित्त निगम के साथ समरूप आधार पर अथवा उनकी पुनर्वित्त योजनाओं के अधीन प्रदान किये जानेवाले मियादी ऋण।

धीं (5) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और मियादी ऋण देने वाली अन्य विस्तीय संस्थाओं द्वारा लागू किये गये विस्तीय नियंत्रण से बचने के लिए किसी वाणिज्य बैंक से ऐसे अधिमों की मांग की गयी जो अप्रत्यक्ष रूप से चयनात्मक ऋण नियंत्रण के उद्देश्य के विपरीत हों, इन अधिमों में निम्नीलिखित शामिल हैं ; निदेशों के अधीन आने वाले पण्यों के व्यापारियों के शेयरों, अवल आस्तियों आदि अन्य आस्तियों पर दिये जानेवाले गैर-जमानती ऋण या अधिम ।

शाखा विस्तार

237. वाणिज्य बैंकों के शाखा विस्तार कार्य में 1970 में जो वृद्धि हुई वह अभूतपूर्व थी । वाणिज्य बैंकों द्वारा समग्र रूप से 1968 और 1969 में जहाँ क्रमशः 677 और 1,369 शाखाएँ

खोली गयीं थीं वहाँ 1970 में कुल 2,137 नयी शाखाएँ खोली गयीं । इस संदर्भ में चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य विशेष रूप से सहायनीय था । इन बैंकों ने 1970 में 1,285 शाखाएँ खोली जबकि 1969 और 1968 में क्रमशः 913 और 405 शाखाएँ खोली थीं । स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों द्वारा इस विधा में किया गया कार्य भी समान रूप से सहायनीय था, क्योंकि उन्होंने 1970 में कुल मिलाकर 628 नयी शाखाएँ खोलीं जब कि 1969 और 1968 में क्रमशः 199 और 161 शाखाएँ खोली थीं ।

238. शाखा विस्तार की यह गति 1971 के पूर्वार्ध में भी बनी रही । इस प्रकार इस अवधि में वाणिज्य बैंकों ने 833 अतिरिक्त शाखाएँ खोलीं थीं, इनमें से 444 शाखाएँ 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा और 256 शाखाएँ स्टेट बैंक समूह द्वारा खोली गयीं (सारणी 34) ।

सारणी 34—वाणिज्य बैंकों द्वारा 1969-70 और 1970-71 में खोले गये नये कार्यालय

	वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय						बैंक कार्यालय	
	1969-70			1970-71			30 जून 1970	30 जून 1971
	जुलाई-दिसंबर 1969	जनवरी-जून 1970	जुलाई-जून 1969-70	जुलाई-दिसंबर 1970	जनवरी-जून 1971	जुलाई-जून 1970-71	को	को
1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	65 (36)	190 (149)	255 (185)	234 (164)	178 (123)	412 (287)	1875	2286
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंक	54 (29)	116 (96)	170 (125)	86 (64)	87 (55)	173 (119)	1060	1233
3. चौदह राष्ट्रीयकृत बैंक	508 (313)	677 (517)	1185 (830)	608 (413)	444 (245)	1052 (658)	5318	6368
4. अन्य अनुसूचित बैंक	144 (78)	85 (45)	229 (123)	124 (57)	115 (65)	239 (122)	1554	1875
5. विदेशी बैंक	1 (—)	— (—)	1 (—)	— (—)	— (—)	— (—)	131	130
6. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	772 (456)	1068 (807)	1840 (1263)	1052 (698)	824 (488)	1876 (1186)	9938	11892
7. गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक	21 (14)	12 (9)	33 (23)	5 (—)	9 (8)	14 (8)	193	121
सभी वाणिज्य बैंक	793 (470)	1080 (816)	1873 (1286)	1057 (698)	833 (496)	1890 (1194)	10131*	12013*

* इस वर्ष के दौरान बंद किये गये कार्यालयों को छोड़कर ।

नोट : कोष्ठकों में दिये हुए आंकड़े बैकरीय केन्द्रों में खोले गये कार्यालयों से संबंधित हैं ।

239. रिजर्व बैंक की 1969-70 की वार्षिक रिपोर्ट में उसके द्वारा दिसम्बर 1969 में बनाये गये शाखा विस्तार कार्यक्रम के विवरण दिये गये थे ; उक्त कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों तथा गैर सरकारी क्षेत्र के 8 बैंकों को 1970 के दौरान बैंक रीहत केंद्रों के लिए निधारित 1186 कार्यालयों सहित 1350 कार्यालय खोलने की आवश्यकता थी । इस लक्ष्य के संदर्भ में सम्बन्धित बैंकों ने 1,155 कार्यालय खोले जिन में बैंक रीहत केंद्रों में खोले गये 997 कार्यालय शामिल हैं ।

240. 1970-71 के समग्र लेखा वर्ष में सभी वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालयों की कुल संख्या 1,890 थी जब कि 1969-70 में उक्त संख्या 1,873 थी (सारणी 34) । 1970-71 के दौरान खोले गये कुल 1,890 कार्यालयों में से चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1052 कार्यालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों ने 585 कार्यालय खोले थे । कुल कार्यालयों में से 1,194 कार्यालय बैंक रीहत केंद्रों में खोले गये थे ।

241. बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के पश्चात् बैंकिंग संगठन के क्षेत्रीय विस्तार में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के बाद पहले दो वर्षों के दौरान (1 जुलाई 1969 से जून 1971 के अंत तक) खोली गयी 3,763 नयी शाखाओं में से, लगभग 2,480 शाखाएँ (66.0 प्रतिशत अब तक के बैंकरीहत केंद्रों में खोली गयी थीं (सारणी 35)। शेष तक के बैंकरीहत केंद्रों में खोले गये इन कार्यालयों में से भी लगभग 34 प्रतिशत कार्यालय उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सार्वभूमिक कम विकसित राज्यों में खोले गये थे। दादरा और नागर हवेली, मणिपुर और त्रिपुरा के संघशासित क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान खोले गये सभी नये कार्यालय अब तक के बैंकरीहत केंद्रों में खोले गये थे। 1969-70 और 1970-71 में खोले गये नये कार्यालयों की कुल संख्या में अब तक के बैंकरीहत केंद्रों में खोले गये नये कार्यालयों का अनुपात आठ राज्यों के संदर्भ में 67 प्रतिशत से भी अधिक था, अर्थात् मध्य प्रदेश (74 प्रतिशत), तमिलनाडु, (72 प्रतिशत),

असम (82 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (68 प्रतिशत), राजस्थान (69 प्रतिशत) मैसूर (69 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (73 प्रतिशत) और बिहार (70 प्रतिशत)।

242. शाखा विस्तार में हुई प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभावस्वरूप बैंक कार्यालयों की सेवा प्राप्त आबादी के राष्ट्रीय औसत में तेजी से कमी होगी अर्थात् जहाँ जून 1969 के अन्त में बैंक कार्यालयों की सेवा प्राप्त आबादी प्रति कार्यालय 65,000 थी वहाँ जून 1971 के अंत में प्रति कार्यालय 46,000 थी। इसी प्रकार प्रत्येक कार्यालय की सेवा प्राप्त आबादी के औसत का सभी राज्यों में कम कर दिया गया है और अधिकांश राज्यों में उसमें बड़ी मात्रा में कमी की गयी है (सारणी 35)। जिन जिलों में बैंक कार्यालय नहीं थे उनकी संख्या दिसंबर 1967 के अंत में 13 थी और उक्त संख्या जून 1971 के अंत में घटकर 3 हो गयी और इन तीन जिलों में भी शाखाएँ खोलने के लिए 6 लाइसेंस जारी किये गये हैं।

सारणी 35—जून 1969, जून 1970 और मई 1971 के अंत में विद्यमान बैंक कार्यालयों का राज्यवार वितरण

राज्य/संघशासित क्षेत्र	शाखाओं की संख्या			1969-70 के	1970-71 के		आबादी प्रति		
				दौरान खोली	दौरान खोली		बैंक कार्यालय		
				गयी शाखाएं	गयी शाखाएं		(हजारों में)		
	जून 1969 के अंत में	जून 1970 के अंत में	जून 1971 के अंत में	कुल	उत्तम से बैंकरहित केंद्रों में खोली गयी	कुल	उत्तम से बैंकरहित केंद्रों में खोली गयी	जून 1969 के अंत में	जून 1971 के अंत में
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
राज्य									
1. आंध्र प्रदेश . . .	567	722	869	155	101	147	95	75	50
2. असम . . .	81	107	137	26	19	30	27	188	108
3. बिहार . . .	273	361	453	89	65	92	62	207	124
4. गुजरात . . .	752	919	1105	167	104	187	106	34	24
5. हरियाणा . . .	172	219	258	47	32	39	19	57	39
6. हिमाचल प्रदेश . . .	42	62	87	21	20	25	23	80	39
7. जम्मू और काश्मीर . . .	35	74	101	39	29	27	13	114	46
8. केरल . . .	601	713	845	112	72	132	100	35	25
9. मध्य प्रदेश . . .	343	460	566	117	104	107	62	116	73
10. महाराष्ट्र . . .	1118	1304	1471	186	87	167	86	44	34
11. मैसूर . . .	756	954	1124	198	147	170	107	38	26
12. नागालैंड . . .	2	4	5	2	1	1	1	205	103
13. उड़ीसा . . .	100	133	173	33	23	40	30	212	126
14. पंजाब . . .	346	465	556	119	88	91	55	42	24
15. राजस्थान . . .	364	432	525	68	48	93	61	70	49
16. तमिलनाडु . . .	1060	1213	1371	155	122	164	107	37	30
17. उत्तर प्रदेश . . .	747	932	1147	185	138	215	132	119	77
18. पश्चिम बंगाल . . .	504	588	684	84	65	96	67	87	65
संघशासित क्षेत्र									
19. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह . . .	1	2	2	1	—	—	—	82	57
20. चंडीगढ़ . . .	20	26	28	6	—	2	—	7	9
21. दादरा और नागर हवेली . . .	—	1	3	1	1	2	2	—	25
22. दिल्ली . . .	274	318	350	44	9	32	2	10	12
23. गोवा, दमन और दीव . . .	85	101	111	16	10	10	9	8	8
24. लक्षद्वीप और मिनिक्काय द्वीप . . .	—	—	2	—	—	2	2	—	16
25. मणिपुर . . .	2	2	5	—	—	3	3	497	214
26. नेफा . . .	—	—	3	—	—	3	3	—	148
27. पांडिचेरी . . .	12	13	20	1	—	7	4	31	24
28. त्रिपुरा . . .	5	6	12	1	1	6	6	276	130
कुल . . .	8262	10131	12013	1873	1286	1890	1194	65	46

सारणी 36—वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का क्षेत्रवार वितरण

शाखाओं की संख्या

	जून 1969 के अन्त में		जून 1970 के अन्त में		दिसम्बर 1970 के अन्त में		जून 1971 के अन्त में	
	संख्या	कुल में %	संख्या	कुल में %	संख्या	कुल में %	संख्या	कुल में %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(I) ग्रामीण	1,832	22.4	3,062	30.2	3,766	33.6	4,279	35.6
(II) अर्ध शहरी	3,322	40.1	3,695	36.5	3,880	34.6	4,016	33.4
(III) शहरी	1,447	17.5	1,583	15.6	1,673	15.0	1,778	14.8
(IV) महानगर/पत्तन शहर	1,661	20.0	1,791	17.7	1,865	16.8	1,940	16.2
जोड़	8,262	100.0	10,131	100.0	11,184	100.0	12,013	100.0

243. सारणी 36 में देश में स्थित बैंक-शाखाओं का क्षेत्रवार वितरण प्रस्तुत किया गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वाणिज्य बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम में आलांच्य अर्वाध में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के खोलने की विधा में बैंकों का शुकाव स्पष्ट रूप से देखा गया। कुल बैंक शाखाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की बैंक शाखाओं का अनुपात जून 1969 के अन्त में जहाँ 22.4 प्रतिशत था वहाँ जून 1970 के अन्त में बढ़कर 30.2 प्रतिशत और जून 1971 के अन्त में 35.6 प्रतिशत हो गया।

244. अस्तित्वों और वृद्धताओं का अंतरण कर देने, कार्यालयों को बन्द करने, दूसरी अनुसूची में बैंकों का समावेश करने आदि के कारण कार्यालयों की संख्या में परिवर्तन होने के बावजूद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 1954 की वृद्धि हुई। परंतु गौर अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों की संख्या में आलांच्य अर्वाध में 72 की कमी हुई (सारणी 37)। जून 1971 के अन्त में अनुसूचित और गौर-अनुसूचित बैंकों की संख्या क्रमशः 11,892 और 121 थी जब कि उनकी संख्या जून 1970 के अन्त में क्रमशः 9,938 और 193 थी।

245. जमाग्रांथि जुटाने तथा छात्रों, कामगारों आदि में बचत की आवृत्त पैदा करने की अत्यधिक आवश्यकता के संदर्भ में यह निश्चय किया गया है कि वाणिज्य बैंकों को स्कूलों, फालोंजों, कारखानों आदि स्थानों में अतिरिक्त काउंटर खोलने तथा सीमित स्वरूप के कारोबार चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसे काउंटर सम्बन्धित बैंकों के निकटतम कार्यालयों से संबद्ध होंगे।

246. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि बैंकों से यह कहा गया है कि वे बैंक सुविधा युक्त केंद्रों और महानगरों और पत्तन शहरों में नयी शाखाएँ खोलने के संबंध में अपने प्रस्ताव को पेश करें। विभिन्न बैंकों से प्राप्त कार्यक्रमों के आधार पर बैंकों को शहरी केंद्रों में 309 कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी। इस संबंध में लाइसेंस जारी करते समय इस मानक को ध्यान में रखा गया कि जिन बैंकों के 60 प्रतिशत से अधिक कार्यालय ग्रामीण और अर्ध शहरी केंद्रों में हों उन्हें ग्रामीण और अर्धशहरी केंद्रों में उनके द्वारा वो कार्यालय खोलने पर शहरी केंद्र में एक कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाए। बैंकों से अलग-अलग रूप से प्राप्त आवृत्त पत्रों के आधार पर मानक से सम्बन्धित इन्ही अपेक्षाओं के अधीन ऐसे केंद्रों में कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। 1971 की जनगणना के आधार पर कलकत्ता महानगर की आबादी में पायी गयी पर्याप्त वृद्धि के कारण बैंक कार्यालयों की संख्या को बढ़ाने की संभावना को देखते हुए 1 जुलाई 1971 से यह निश्चय किया

गया है कि कलकत्ता में कार्यालय खोलने के संदर्भ में बैंकों की पात्रता का निर्धारण ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में उनके द्वारा किये गये शाखा-विस्तार कार्य के आधार पर करने की आवश्यकता नहीं है।

नियोजन क्षमतायुक्त योजनाओं के लिए विशेष भाग

247. केंद्रीय वित्त मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अभिरक्षकों के साथ जुलाई 1970 में जो विचार-विमर्श किये उनके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया ने बैंकों की विशेष ऋण योजनाओं का, विशेष रूप से उनकी नियोजन क्षमता के संदर्भ में पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से श्री बी. डी. ठक्कर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने दिसम्बर 1970 में अपनी रिपोर्ट पेश की। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्वनिर्वाहित सहित नियोजन क्षमता का पता लगाने के बावजूद समिति ने स्वनिर्वाहित व्यक्तियों की सहायता करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा शुरू की गयी विभिन्न ऋण योजनाओं का पुनरीक्षण किया। समिति ने यह पाया कि बैंकों द्वारा बनायी गयी विशेष योजनाओं में से किसी भी योजना द्वारा समाज के अपेक्षाकृत कमजोर क्षेत्रों को वास्तव में कोई विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। इस उद्देश्य से कि बैंक उद्यमियों की सहायता तथा नियोजन की व्यवस्था कर सकें, समिति ने उक्त कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाये हैं:—

(1) शाखा एजेंटों की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियाँ दी जानी चाहिए और उन्हें कार्यक्रमों की संभावनाओं, विवरणों तथा उन उद्देश्यों, जिनकी पूर्ति की जानी है, की पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए। समिति ने शाखा अधिकारियों के लिए अविलम्ब एक व्यापक और तीव्र प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

(2) छोटे उद्यमियों के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में प्रवर्तकों के तकनीकी तथा ऐसे अन्य अगाध और वित्तर योगदानों को जमानत के रूप में उचित महत्व दिया जाना चाहिए और कम मार्जिन पर तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ बिना मार्जिन के वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और

(3) किसी बैंक के लिए यह संभव होना चाहिए कि वह किसी भिन्नायी ऋण पर प्रारंभिक अवस्था में कम दर पर और बाद में उत्तमतर दर पर व्याज ले। वापसी अदायगी का कार्यक्रम बनाते समय यूनिट की प्रारंभिक अवधि और आय-निर्माण क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऋण देते समय बैंकों को साधारण रूप से अन्य पार्टियों की गारन्टी पर जोर नहीं देना चाहिए।

सारणी 37—अनुसूचित और गैर अनुसूचित बाणिज्य बैंकों द्वारा भारत में खोले गये और किये गये कार्यालयों की संख्या

अनुसूचित बाणिज्य बैंक	खोले गये नये कार्यालय				समामेलन, विलियन, प्राप्ति और वैयक्तियों के अंतरण तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में जोड़े या उसमें से हटाये जाने के कारण परिवर्तन	बंद किये गये वर्तमान कार्यालय	कार्यालयों की संख्या में समग्र घट-बढ़	प्रवधि के अंत में कार्यालयों की संख्या
	1	2	3	4	5			
अनुसूचित बाणिज्य बैंक								
1968								
जनवरी-जून	222 (37)	-10	-4	+ 228 7044
जुलाई-दिसंबर	443 (50)	+ 1	-6	+ 438 7482
1969								
जनवरी-जून	565 (24)	+ 1	-3	+ 563 8045
जुलाई-दिसंबर	772 (65)	+ 53	-3	+ 822 8867
1970								
जनवरी-जून	1068 (190)	+ 3	-	+ 1071 9938
जुलाई-दिसंबर	1052 (164)	+ 54	-4	+ 1102 11040
1971								
जनवरी-जून	824 (178)	+ 32	-4	+ 852 11892
गैर अनुसूचित बाणिज्य बैंक								
1968								
जनवरी-जून	7	-10	-3	-6 203
जुलाई-दिसंबर	3	.	.	.	5	-1	-	+ 4 207
1969								
जनवरी-जून	11	-1	-	+ 10 217
जुलाई-दिसंबर	21	-53	-1	-33 184
1970								
जनवरी-जून	12	-3	-	+ 9 193
जुलाई-दिसंबर	5	-54	-	-49 144
1971								
जनवरी-जून	9	-32	-	-23 121
सभी बाणिज्य बैंक								
1968								
जनवरी-जून	229	-	-7	+ 222 7247
जुलाई-दिसंबर	449	-	-6	+ 442 7689
1969								
जनवरी-जून	576	-	-3	573 8262
जुलाई-दिसंबर	793	-	-4	+ 789 9051
1970								
जनवरी-जून	1080	-	-	+ 1080 10131
जुलाई-दिसंबर	1057	-	-4	+ 1053 11184
1971								
जनवरी-जून	833	-	-4	+ 829 12013

नोट : (1) कोष्ठकों में दिये हुए आंकड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सम्बन्धित हैं।

(2) इन आंकड़ों में प्रशासनिक, मोरामी, अस्थायी और गैर बैंकिंग कार्यालय और भारत के बाहर स्थित कार्यालय शामिल नहीं हैं।

248. समिति ने व्यावसायिकों और फुटकर व्यापारियों के उपयोग के लिए सरलीकृत आदर्श फार्मों की सिफारिश की है और इस बात पर जोर दिया है कि आवेदन फार्म सभी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। बैंकों को चाहिए कि वे अनुवर्ती कार्यक्रमों और पर्यवेक्षण की पर्याप्त व्यवस्थाएं करें और कार्यक्रमों के अनुसार अग्रिमों की वसूली करने की भी व्यवस्था करें।

249. समिति द्वारा किये गये अन्य महत्वपूर्ण सुझाव संक्षेप में निम्न प्रकार हैं, यदि छोटे उद्यमियों को, विशेषकर शहरी और महानगरी क्षेत्रों के उद्यमियों को औद्योगिक आस्थानों के विनिर्माण के लिए जीवन बीमा निगम या अन्य एजेंसियों से पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं हो तो वाणिज्य बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे आस्थानों तथा घरेलू और कुटीर उद्योगों के विनिर्माण के लिए सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इसके अलावा पट्टे पर उपकरण देने की जो सुविधा कुछ प्रगतिशील देशों में बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, वह भारत में भी उद्योगों के लिए कुछ हद तक सहायक सिद्ध हो सकती है। छोटे उद्यमियों के ऋणों की राशि की अदायगी में बड़े और मझौले उद्योगों और सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के कारण होने वाले विलम्ब कम करने के लिए रिजर्व बैंक एक उपयुक्त कार्यक्रम बना सकता है। व्यावसायिकों और स्वनिर्वाहित व्यक्तियों की सहायता के लिए समन्वित व्यवस्था करने के उद्देश्य से समिति ने एक विविध सेवा एजेंसी की स्थापना करने की सिफारिश की है। यह एजेंसी संभाव्य ऋणकर्ता के संबंध में जानकारी एकत्र करने का प्रबन्ध करेगी। समिति का यह मत है कि महानगरों और बड़े-बड़े शहरों में तथा देश के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के कतिपय चुने हुए कार्यक्षेत्रों में ऐसी एजेंसी का तत्काल गठन किया जाना चाहिए। विविध सेवा एजेंसी वित्त संबंधी कोई कार्य नहीं करेगी परंतु वह केवल एक समन्वयकारी/आयोजक/सलाहकारी संस्था होगी।

250. समिति की सिफारिशों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वीकार कर लिया है। उनके अनुवर्ती उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों की विशेष ऋण योजनाओं के संबंध में सभी वाणिज्य बैंकों के लिए मार्च 1971 में निर्देश जारी किये हैं।

251. उन निर्देशों के संदर्भ में यह पाया गया है कि स्वनिर्वाहित व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों को बैंक हाल ही के महीनों में अधिकाधिक मात्रा में ऋण प्रदान करते आ रहे हैं और अब यह स्थिति आ पहुँची है कि इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने का कार्य लगातार और सुव्यवस्थित रूप से किया जाए जो सहायता दी जाती है वह अनिवार्यतः आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए और वह उस योजना की आर्थिक क्षमता के अनुकूल नहीं होनी चाहिए जिस के लिए वह दी जाती है। ऋण देने की योजनाओं को शाखा स्तर पर पर्याप्त लचीलेपन के साथ अमल में लाना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शाखाओं के एजेंटों को समुचित प्राधिकार दिया जाए। सूचीक शाखाओं के एजेंटों को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ती है, अतः तुरंत गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि शाखाओं के अधिकारियों को आवश्यक प्रणाली प्राप्त हो सके। ऋण सहायता को अधिक सार्थक बनाने के लिए बैंकों को उधारकर्ताओं की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करना होगा कि किस प्रकार उत्तम रूप से समीकृत वित्तीय तथा प्रबंध संबंधी सहायता की व्यवस्था की जा सकती है, या उसका आयोजन किया जा सकता है। विविध सेवा एजेंसी की स्थापना करना इस उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन हो सकता है। निर्धारित के अन्तिम-उपयोग पर निगरानी रखने और कार्यक्रम के अनुसार अग्रिमों की वसूली करने के लिए अनुवर्ती कारवाइयाँ और पर्यवेक्षण

व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए। समिति की सिफारिश के अनुसार बैंक ने बड़े उद्योगों से प्राप्य बकाया राशियों को वसूल कर उन्हें छोटे उद्यमियों को उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम बनाने के निमित्त एक कार्यकारी दल का गठन किया है।

अग्रतावाले और उर्ध्वक्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना

252. पिछले कुछ समय से, भारत सरकार गारंटीयों या उनके समान अन्य सुविधाओं की ऐसी एकमात्र किन्तु व्यापक प्रणाली की एक योजना बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही थी जिससे कि बैंक अब तक अपेक्षाकृत उर्ध्वक्षेत्रों में स्थित व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान कर सकें। इस विषय का अनुशीलन करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग के तत्कालीन अपर सीचव (संप्रति उप गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) श्री. एस्. एस्. शिरालकर की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया।

253. कार्यकारी दल ने यह अनुभव किया कि छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण दिये जाने में पर्याप्त मात्रा में जोखिम विद्यमान है और वे विभिन्न प्रकार के भी हैं। उनसे विशिष्ट बैंकों या विशिष्ट क्षेत्रों जिनमें अपेक्षाकृत बैंकरीहित राज्य और पिछड़े क्षेत्र शामिल हैं, पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः उक्त दल इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि बैंक संघटन के हित तथा व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इन जोखिमों को एकत्र किया जाय और उन्हें एक सामान्य और केंद्रीकृत गारंटी योजना के अंतर्गत लाया जाए।

ऋण गारंटी निगम

254. उक्त दल की सिफारिशों के आधार पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक या अधिक ऋण गारंटी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड नाम की एक नयी सार्वजनिक सीमित कम्पनी का प्रवर्तन किया। 14 जनवरी 1971 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन उक्त कम्पनी का पंजीयन किया गया। निगम की प्राधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये है। इस पूंजी में से 2 करोड़ रुपये के लिए प्रारम्भ में 20,000 ईक्विटी शेयर जारी किये गये जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1000 रुपये था और यह पूंजी पूर्णतः चुक्ता कर दी गयी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा उसके सहायक बैंकों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने उक्त शेयर ले लिए हैं। निगम के निर्देशक बोर्ड में 8 सदस्य हैं जिनमें दो सदस्य (अध्यक्ष सहित) रिजर्व बैंक और शेष सदस्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निगम ने भारतीय ऋण गारंटी निगम (छोटे ऋण) गारंटी योजना, 1971 बनायी और उसे 1 अप्रैल 1971 से लागू किया। इसके अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा छोटे ऋणकर्ताओं को कतिपय निर्विवाद सीमाओं के भीतर दी जानेवाली ऋण सुविधाएँ आती हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं के निम्नीलिखित वर्ग आते हैं : अलग अलग परिवहन चालक या अधिक से अधिक ऐसे छः चालकों का संघ, उर्वरकों और उनसे भिन्न इतर वस्तुओं का व्यापार करनेवाले व्यक्ति, फर्म और सहकारी समितियाँ व्यावसायिक और स्वनिर्वाहित व्यक्ति, स्थायिक कारावारी उद्यमों वाले व्यक्ति और फर्म तथा कारशक्कारी और कृषि संबंधी अन्य कार्यकलापों में लगे हुए कृषक। यह निगम अशांध्य या वसूल होने में संदिग्ध राशियों को पचहत्तर प्रतिशत की राशि की रक्षा करता है जब कि ऋणदाता संगठन शेष पच्चीस प्रतिशत की राशि का भार वहन करते हैं। योग्य ऋण सुविधाओं के संवर्धन में बकाया रहने वाली राशियों पर आधे प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क वसूल किया जाता है। उक्त योजना में उपयुक्त सुरक्षात्मक उपाय भी किये गये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन सुविधाओं का उपयोग वास्तविक तथा उत्पादक उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है। इस योजना में भाग लेनेवाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने यह वचन दत्ते हुए करार निष्पादित किये हैं या निष्पादित करने

की सहमति दी है कि वे अबाध गारंटी के अंतर्गत आनेवाले अभिग्रहों की सूचना देंगे, बैंकों द्वारा निर्धारित संबंधित नियमों के अनुसार गारंटीकृत अभिग्रहों पर कार्रवाई करेंगे, गारंटीकृत लेखों से संबंधित रीजिस्ट्रारों, प्रलेखों तथा अन्य अभिलेखों को पंथक करेंगे और निगम के प्रति कतिपय अन्य दायित्वों का बहन करना स्वीकार करेंगे। प्रत्येक तिताही के अंत में विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान की गयी गारंटीकृत ऋण सुविधाओं की कुल राशि दर्शानेवाले तिताही विवरण बैंकों से प्राप्त हो रहे हैं। निगम बैंकों के बाह्य लेखा-परीक्षकों और आंतरिक निरीक्षण तंत्र तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से गारंटीकृत अभिग्रहों का एक नमूना परीक्षण करने का विचार कर रहा है।

बाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए वित्तीय सहायता

255. बाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण के एक अंश के रूप में कृषि के लिए दी जानेवाली वित्तीय सहायता अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो गयी है और फलस्वरूप वह कुल बैंक ऋण का लगभग दसवाँ हिस्सा है। ऋण संबंधी मूल्यांकन की क्रियाविधियाँ, ऋणांतर पर्यवेक्षण और ऋण की वस्तु की संबंध में अपनायी जानेवाली प्रणालियाँ में व्यापक रूप से पायी गयी विद्यमानताओं के कारण रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1970 में कृषि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के विषय में सभी बाणिज्य बैंकों के नाम मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये। रिजर्व बैंक ने कृषि के वित्तीय सहायता देने के संबंध में बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली परिचालन संबंधी कार्यपद्धति, नीति और क्रियाविधियों का जो अध्ययन किया उसके आधार पर उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये गये। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस बात पर बल दिया गया है कि बाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को दिये जानेवाले ऋण का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषि कार्यकर्ताओं के अपने कार्यात्मकों को उच्चतर तकनीकी स्तर पर ले जाने में सहायता मिले। कृषि को दिये जानेवाले ऋण उद्देश्यपूर्ण हों और साथ ही वह केवल पहले ही से सक्षम रहनेवाले कृषि कार्यकर्ताओं के अपना अधिशेष और बढ़ाने के लिए नहीं दिये जाएं परन्तु वे उन कृषि कार्यकर्ताओं के भी दिए जाएं जो सीमान्त और संभाव्य रूप से सक्षम हों। शाखा एजेंट को दी गयी विवेकाधीन शक्तिचाही ऐसी होनी चाहिए कि वह बिना केन्द्रीय कार्यालय के परामर्श के स्वयं ऋण के लिए किये गये आवेदनों के कम से कम 80 प्रतिशत आवेदनों का निबटारा कर सके। शाखा एजेंट को चाहिए कि वह कृषि संबंधी मूल आंकड़े एकत्र करे और उन्हें तत्काल अवलोकन के लिए अपने पास रखे। वित्तीय सहायता की मात्राएँ कृषि के काम आनेवाली सभी मूल वस्तुओं तथा कृषि कार्यकर्ताओं की कुल आय या उन्हें उपलब्ध अन्य साधनों पर विचार करते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। अल्पावधि और मध्यावधि दोनों ऋणों के संदर्भ में उनकी धारणी अदायगी का कार्यक्रम उस समय से संबंध होना चाहिए जब कृषि कार्यकर्ता ने अपनी फसल बेच दी हो और उसके पास नकद राशि हो। शाखा एजेंट को चाहिए कि वह ऋण की वस्तु संबंधी क्रियाविधियों को निष्पक्ष-तापूर्ण किन्तु सुनिश्चित रखे। बैंकों की शाखाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अपने क्षेत्र में स्थित अन्य संस्थाओं से निकट संबंध स्थापित करें और अपने अपने क्षेत्रों के संदर्भ में कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यक्रम की जानकारी रखें।

विभेदात्मक ब्याज दरों के संबंध में सीमांत

256. वित्त मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों/अभि-
रक्षकों की 22 जुलाई 1970 की बैठक में यह सुझाव दिया था कि बैंकों से वित्तीय सहायता पाने योग्य और सावधानी से चुने गये कम आय-
वाले वर्गों के लिए ब्याज की कम दरें और अधिक संपन्न ऋण-
कर्ताओं के लिए ब्याज की उच्चतर दरें लागू की जाएं। इस सुझाव के अनुसरण में बैंक ऑफ इंडिया ने विभेदात्मक ब्याज दरों के प्रश्न का अनुशीलन करने के लिए सितंबर 1970 में बैंक के उप

गवर्नर डा. आर. के. हजारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उक्त समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित थे :
(1) प्रत्येक क्षेत्र के ऋणकर्ताओं से बैंकों द्वारा जो विभेदात्मक ब्याज दरें पहले से ही वसूल की जा रही हैं उनकी संभावनाओं और सीमाओं का पुनरीक्षण करना, (2) प्रत्येक क्षेत्र के भीतर से उन ऋण कर्ताओं का पता लगाने के लिए मानदंड निर्धारित करना जिनको ब्याज की कम दरों की सुविधा प्रदान की जा सकती है, (3) प्रत्येक क्षेत्र के लिए स्वीकार्य विभेदात्मक ब्याज दरों की परिसीमा का संकेत करना और (4) इस प्रश्न का परीक्षण करना कि ब्याज की कम दरों के स्थान पर या उनके अतिरिक्त क्या कोई अन्य रियायतें दी जा सकती हैं।

257. उक्त समिति ने मई 1971 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें यह बताया गया कि बैंकों द्वारा विभेदात्मक ब्याज दरें वसूल किये जाने के उद्देश्य के संदर्भ में ऋणकर्ताओं का पता लगाने का जो निष्पक्ष और व्यवहार्य मानदंड है वही ऋण के आकार का आधार हो सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह मानदंड सभी क्षेत्रों के लिए समान हो। इस उद्देश्य से कि छोटे ऋणकर्ताओं का चयन अपने आप हो सके यह सुझाव दिया गया है कि विभेदात्मक ब्याज दरों की योजना को नयी ऋण गारंटी योजना से जोड़ दिया जाए ताकि उसके अंतर्गत अग्रतावाले और उपेक्षित क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं के दिये जानेवाले छोटे ऋण भी आ सकें। समिति की राय में विभेदात्मक ब्याज दरों की बहुत अधिक व्यापकता अनु-
चित होगी। व्यापक रूप से विभेदात्मक ब्याज दरों को लागू करने में जो विविध व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं उनपर विचार करते हुए समिति ने ऋणकर्ताओं के प्राथमिकता-प्राप्त वर्गों के लिए 8-1/2 और 10 प्रतिशत के बीच की विभेदात्मक ब्याज-दरें सुझायीं। इसके अलावा, छोटे ऋणकर्ताओं को राहत प्रदान करने के संदर्भ में एक उपाय के रूप में समिति ने यह सिफारिश की है कि ऋण देनेवाला बैंक छोटे ऋणकर्ताओं के मामले में ऋण-गारंटी योजना के अधीन दृश्य-ऋण गारंटी शुल्क का भार अपने ऊपर ले ले। समिति ने इस और संकेत किया है कि जमानतों और मार्जिनों के मामले में जो रियायतें दी गयी हैं वे अधिक महत्व रखती हैं और उसने कुछ ऐसी रियायतें भी सुझायी हैं जिनके द्वारा बैंक इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। समिति ने यह भी सुझाया है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा उसकी सिफारिशों के अपनाये जाने के प्रश्न की भी जाँच की जाए। समिति द्वारा की गयी सिफारिशें रिजर्व बैंक और सरकार के विचाराधीन हैं।

258. एक सदस्य डा. अशोक मित्र ने ३ प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत के बीच की और अधिक व्यापक दरों का सुझाव देते हुए एक असहमति-नोटपत्र प्रस्तुत की।

जमाराशि जुटाने के उपाय

259. बाणिज्य बैंक अनेक अतिरिक्त उपायों और योजनाओं के जरिए जमाराशि जुटाने के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहे हैं। साथ ही, रिजर्व बैंक ने अगस्त 1970 में इस कार्य में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से जमाराशि पर दलाली की अदायगी के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों में छूट दी। इस प्रकार, बैंकों द्वारा प्रारंभ की गयी विशेष योजनाओं के अधीन घर घर जाकर जमाराशि जुटाने के लिए नियुक्त किये जानेवाले एजेंटों को दलाली की अदायगी करने की अनुमति दी गयी। रिजर्व बैंक ने 24 अक्टूबर 1970 को बाणिज्य बैंकों के नाम काफी अधिक मात्रा में जमाराशि जुटाने के महत्व और आवश्यकता के संबंध में उन्हें पुनः एक बार समझाते हुए एक परिपत्र जारी किया। यद्यपि रिजर्व बैंक का आशय कोई विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त या मानकीकृत सुझाव प्रस्तुत करना नहीं था फिर भी बैंकों को यह बताया गया कि उचित सामूहिक

पुरस्कारों, आदि द्वारा जमाराशि-संचयन के अभियानों में कर्मचारियों को सम्मिलित करने, प्रत्येक शाखा तथा समूहों बैंक के लिए उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करने जमाराशि-संचयन के अभियानों का आयोजन करने आदि से बैंकों के वित्तीय साधनों को काफी मात्रा में बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

260. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जमाराशियों के संचयन के विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 23 और 24 दिसम्बर 1970 को मुम्बई में 20 प्रमुख बैंकों के मुख्य अर्थशास्त्रियों और मुख्य विकास अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने शाखा तंत्र, शाखाओं के प्रकार, संस्थाओं के भीतर और विभिन्न संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा, कर्मचारियों और जमाकर्तारों को प्रोत्साहन, प्रचार के माध्यम, बचत के साधन, जमाराशियों की व्याज-दरों में लचीलापन और जमाराशियों की संभावना का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक विशेष अध्ययन और सर्वेक्षण जैसे जमाराशि-संचयन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

छोटे बैंकों की बैठक

261. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में स्थित गैर सरकारी क्षेत्र के छोटे बैंकों (अर्थात् 50 करोड़ रुपये से कम जमाराशियों वाले) की दो बैठकें क्रमशः 14 और 15 मई 1971 को मुद्रा में और 9 जून 1971 को दिल्ली में बुलाई। संबंधित क्षेत्रों में स्थित छोटे बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को उक्त बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया; उक्त दोनों बैठकों की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के बैंकिंग के कार्यकारी उप-गवर्नर ने की। बैंकों के परिचालन से संबंधित समस्याओं के विविध पहलुओं अर्थात् निधियों का व्यापक उपयोग करना, अग्रता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना, अग्रणी बैंक योजना, जमाराशियों का संचयन और प्रशिक्षण, संगठन और प्रबंध आदि पर उक्त बैठकों में मुख्य रूप से विचार-विमर्श किया गया। छोटे बैंकों के कर्मचारियों के प्रशिक्षणार्थ प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने की योजनाएँ तैयार करने के लिए विमर्श दोनों का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक के बैंक परिचालन और विकास विभाग के मुख्य अधिकारी और सदस्य कतिपय बैंकों के अध्यक्ष हैं।

शेयरों पर अभिग्रह

262. सट्टेबाजी के उद्देश्यों और/या दूसरे अस्वस्थ कार्यों के लिए बैंक वित्त उपयोग को हतोत्साहित करने और रोकने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया कि शेयरों पर दिये जाने वाले अभिग्रहों को विनियमित किया जाए और रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में 28 अगस्त 1970 को एक निर्देश जारी किया। इस निर्देश के अनुसार, किसी ऋणकर्ता को शेयरों की जमानत पर 50,000 रुपये से अधिक राशि की अभिग्रह-सीमा प्रदान करने वाले या ऐसी सीमा का नवीकरण करने वाले प्रत्येक वाणिज्य बैंक से इस आशय की शर्त लगाने की अपेक्षा की जाती है कि संबंधित शेयर बैंक के नाम अंतरित किये जाएंगे और उन शेयरों के संदर्भ में अनन्य मताधिकार बैंक के होंगे जिनका प्रयोग बैंक किसी भी प्रकार से कर सकेगा, बैंक को चाहिए कि वह शेयरों को अविलंब अपने नाम अंतरित कर ले।

263. उक्त निर्देश में यह भी व्यवस्था है कि कोई भी वाणिज्य बैंक अपने द्वारा बंधकग्राही के रूप में धारण किये गये शेयरों के संबंध में रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना मताधिकारों का प्रयोग नहीं करे और मताधिकारों का प्रयोग रिजर्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों के अनुसार ही किया जाए।

264. शेयर दलाल द्वारा अभिग्रहों की जमानत के रूप में रखे गये शेयरों के मामले में उक्त निर्देश के उपबन्ध केवल तभी लागू होंगे जब वे शेयर तीन महीनों से अधिक अवधि के लिए रखे जाते हों। इस उपबन्ध का आशय यह है कि शेयर दलाल अपने सामान्य कारोबार को बिना किसी कीटनाई के चला सकें।

265. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक निवेशकों को अपनी असली आवश्यकताओं के लिए निधियाँ उपलब्ध करने में कोई कीटनाई या असुविधा न हो, शेयरों पर दिये जाने वाले अभिग्रहों की 50,000 रुपये तक की सीमाओं को इस निर्देश के क्षेत्र से छूट दी गयी है।

निर्देशों, आदि की वैयक्तिक गारंटियों पर अभिग्रह

266. रिजर्व बैंक ने बैंकों और मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं की उन प्रथाओं का पुनरीक्षण किया जिनके अनुसार वे ऋण मंजूर करते समय ऋणकर्ता संस्थाओं के निर्देशकों और अन्य प्रबंध कर्मचारियों से वैयक्तिक गारंटियाँ लेते हैं। इस पुनरीक्षण से पता चला कि प्रबंध एजेंसी पद्धति के स्थान पर उद्यमियों का एक वर्ग धीरे-धीरे उभर रहा है और प्रबंधक वर्गों का व्यवसायीकरण हो रहा है और सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों के वित्तीय तथा तकनीकी मूल्यांकन की प्रणालियों में सुधार हो रहा है। इन निष्कर्षों के फलस्वरूप, यह अनुभव किया गया कि ऋण मंजूर करते समय ऋणकर्ता संस्थाओं के निर्देशकों और अन्य प्रबंध कर्मचारियों से साधारणतः वैयक्तिक गारंटियाँ लेने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अतः रिजर्व बैंक ने जुलाई 1970 में ऋणदाता संस्थाओं के लिए ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जिनकी सहायता से वे उन परिस्थितियों का पता लगा सकें जिनमें गारंटी आवश्यक होगी या आवश्यक नहीं होगी। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस बात पर बल दिया गया है कि इस बात का सुनिश्चय करने में सावधानी बरती जाए कि निर्देशक और अन्य प्रबंध कर्मचारी ऋणकर्ता संस्थाओं से पारिश्रमिक प्राप्त करने के श्रोत के रूप में गारंटी प्रथा का उपयोग न करें।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

267. आलांच्य वर्ष में सामान्य और चयनात्मक ऋण नियंत्रणों में समय समय पर संशोधन किये गये। सामान्य ऋण नियंत्रण में किये गये संशोधन भाग 1 के पैराग्राफों में दिये गये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित शामिल हैं; 9 जनवरी 1971 से बैंक दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया, वास्तविक चलभूदा अनुपात में वृद्धि की गयी और नयी हंडी बाजार योजना लागू की गयी। चयनात्मक ऋण नियंत्रण कच्ची रुई और कपास, अनाजों तिलहन और वनस्पति सहित वनस्पति तेलों पर दिये जाने वाले अभिग्रहों से संबंधित थे। इस संबंध में किये गये प्रमुख उपाय नीचे दिये गये हैं।

268. रिजर्व बैंक ने 23 अक्टूबर 1970 को नयी फसल के विपणन में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से रुई और कपास पर दिये जाने वाले अभिग्रहों का उद्धार बनाया, सूती मिलों को दिये जाने वाले अभिग्रहों पर से उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रण हटाया गया और मिलों तथा दूसरों के लिए मार्जिनों की एक क्रमिक प्रणाली निर्धारित की गयी। फिर भी, बाद में रुई के मूल्यों में जो तीव्र माँगोत्तार वृद्धि हुई उसको देखते हुए बैंक विस्तार की सहायता से रुई के स्टोको का संग्रह करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से 12 दिसम्बर 1970 को संबंधित नियंत्रण को कड़ा कर दिया गया। रुई पर दिये जाने वाले अभिग्रहों से संबंधित न्यूनतम मार्जिन को बढ़ाया गया और मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को दिये जाने वाले अभिग्रहों की उच्चतम सीमा में कमी की गयी। अन्य बातों के

साथ साथ, देशी रूई के कीतपय प्रकारों की कटाई में विलम्ब होने के कारण रूई के व्यापारियों द्वारा रूई के विपणन के संदर्भ में जो कठिनाई अनुभव की गयी उसी देखते हुए रिजर्व बैंक ने 30 जून 1971 को कीतपय विश्वायतों की घोषणा की। इस प्रकार चार महीनों की जिस अवधि (फरवरी-मई 1971) के दौरान सूती मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को अक्टूबर 1970—जनवरी 1971 की अवधि के दौरान विपणन की गई रूई और कपास पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में 60 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन लागू किया गया था, उसे और दो महीने के लिए अर्धतः अगस्त 1971 तक बढ़ा दिया गया। इसके पहले बैद्यता की इस अवधि को एक महीने के लिए अर्धतः मई से जून 1971 तक बढ़ाया गया था।

269. सूती बस्त्रों पर दिये जानेवाले अग्रिमों में वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुए 4 फरवरी 1971 को बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे सूती बस्त्रों पर दिये जानेवाले अग्रिमों में कमी करें और न्यूनतम मार्जिन को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दें। अप्रैल 1971 में प्रमुख बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे मरम्मत के अधीन मिलों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर यूनिटों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्चतम मार्जिन को अत्यन्तम रूप से लागू करें।

270. अनाजों पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में रिजर्व बैंक ने पूर्ति की वर्तमान और भावी स्थिति को देखते हुए 17 दिसम्बर 1970 को अपने नियंत्रण में संशोधन किया। इस प्रकार, अन्य बातों के साथ साथ, उक्त नियंत्रण में उपयुक्त परिवर्तन किये गये ताकि (1) वाणिज्य बैंक कृषकों को खड़ी फसलों पर प्रत्यक्ष ऋण प्रदान कर सकें और ऐसी फसलों के मुख्यस्थित विपणन में सहायता हो सके, (2) बैंकों को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपने कृषि संबंधी कारोबार को व्यापक बनाने की दिशा में सहायता हो जा सके और (3) 50,000 या उससे कम आवासी वाले केंद्रों में बैंक ढाल मिलों (परन्तु चावल मिलों से इतर) जैसे अनाजों का परिष्करण करनेवाले यूनिटों को अग्रिम प्रदान कर सकें।

271. तिलहन की अच्छी फसल होने की संभावना के बावजूद तिलहनों और वनस्पति तेलों के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने 25 जनवरी 1971 को तिलहनों, वनस्पति तेलों और वनस्पति पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर लागू न्यूनतम मार्जिन को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करते हुए उन पर लगाये गये अपने नियंत्रण को ढूँढ़ कर दिया। फिर भी, देश में सरसों के बीजों और तोरिया बीजों की पूर्ति और मूल्यों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बैंकों द्वारा इन तिलहनों तथा मोयाबीन पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर लागू न्यूनतम मार्जिन को 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया। इन अग्रिमों के उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रण से भी छूट दी गयी।

272. साथ ही, असम, नागालैंड, मेघालय और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों और मणिपुर, नेफा तथा त्रिपुरा के संघशासित क्षेत्रों में ऋणकर्मियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए, रिजर्व बैंक ने इन क्षेत्रों में अनाजों, तिलहनों वनस्पति तेलों और रूई तथा कपास पर दिये जानेवाले अग्रिमों को सभी नियंत्रणों से पूरी छूट दी।

273. अत्यन्तम रूप से नियंत्रण संबंधी स्थिति को दर्शानेवाला एक चार्ट आगे दिया गया है।

अत्यन्तम रूप से नियंत्रण: सहकारी बैंक

274. देशी रूई और कपास की पूर्ति की स्थिति और उनके मूल्यों में पायी गयी प्रवृत्तियों को देखते हुए, 1970-71 में एक निदेश

जारी किया गया जिसके अनुसार सरकारी बैंकों में यह अपेक्षा की गयी कि वे अपने द्वारा सहकारी सूती मिलों को दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में यदि संबंधित जमानत दृष्टिबंधक के रूप में दी जाए तो 30 प्रतिशत का मार्जिन बनाये रखें और यदि वह जमानत बंधक के रूप में दी जाए तो 20 प्रतिशत का मार्जिन बनाये रखें। यदि संबंधित राज्य सरकार द्वारा उक्त ऋण ग्रीमार्ग मूलधन की वापसी अदायगी और व्याज के भुगतान के संबंध में पूर्णतया गारंटीकृत हों तो बंधक और दृष्टिबंधक के रूप में जमानत के दिये जाने पर उक्त मार्जिनों को घटाकर 10 प्रतिशत किया जा सकता है। अन्यथा के संबंध में, बंधक और दृष्टिबंधक के रूप में जमानत के दिये जाने पर मार्जिन पहले की तरह क्रमशः 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत ही बने रहे। रूई और कपास की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों की उच्चतम सीमा के संबंध में जारी किये गये निर्देश में लगाये गये प्रतिबंधों को उसी स्तर पर बनाये रखा गया अर्थात् उच्चतम सीमा किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक (या किसी संघशासित क्षेत्र में कार्य करनेवाले किसी राज्य सहकारी बैंक) के मामले में कुल दंड्यताओं का 20 प्रतिशत और किसी राज्य सहकारी बैंक के मामले में कुल दंड्यताओं का 10 प्रतिशत रहेगी। इस निर्देश के उद्देश्य के लिए अग्रिमों के कुल स्तर में सहकारी सूती मिलों को दिये जानेवाले अग्रिम शामिल नहीं किये जाएंगे परन्तु ऐसी मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को दिये जानेवाले अग्रिम ही शामिल किये जाएंगे। आयातित रूई और देशी रूई के कीतपय प्रकारों पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में जो छूट दी गयी थीं उन्हें जारी रखा गया।

275. कीतपय केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर उनके द्वारा गृह की जमानत पर दिये जानेवाले ऋण के स्तर के संबंध में लगाये गये प्रतिबंध को सितंबर 1970 में वापस ले लिया गया। फिर भी, बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे गृह के बंधक रखने पर 25 प्रतिशत और दृष्टिबंधक रखने पर 40 प्रतिशत का सामान्य मार्जिन बनाये रखें।

संगठन से संबंधित अन्य विषय

गैर सरकारी बैंकों के बोर्डों का पुनर्गठन

276. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10-क, जो 1 फरवरी 1969 से अमल में आ गयी थी, की आवश्यकताओं के अनुसार गैर सरकारी क्षेत्र के 10 करोड़ रुपयों से कम जमाराशियाँ वाले तीन छोटे बैंकों को छोड़कर शेष सभी बैंकिंग कम्पनियों ने अपने अपने निदेशक बोर्डों के पुनर्गठन का कार्य पूरा कर दिया है। गैर सरकारी क्षेत्र के ऐसे 9 भारतीय बैंकों में से जिनकी जमाराशियाँ (1 फरवरी 1969 को) 10 करोड़ रुपये और उनसे अधिक थीं आठ बैंकों ने जून 1970 के पहले कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी थी और शेष 1 बैंक ने आलोच्य वर्ष में इस दिशा में कार्रवाई की। 10 करोड़ रुपयों से कम जमाराशियाँ वाले बैंकों में से 34 बैंक (जिनमें से 14 बैंक आलोच्य वर्ष में) अपने अपने निदेशक बोर्डों का पुनर्गठन कर चुके हैं जब कि उन 3 बैंकों के मामले में, जिन्होंने कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई अनुभव की, केन्द्रीय सरकार ने, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, 1 अगस्त, 1971 की अवधि तक छूट दी; इस मामले में उन बैंकों के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

277. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 ख के अनुसार, गैर सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक भारतीय बैंकिंग कंपनी के लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष का होना आवश्यक है जिससे संबंधित बैंक के प्रबंध का कार्य सौंपा जाएगा। संगति गैर सरकारी क्षेत्र

में स्थित 47 बैंकों में से 41 बैंकों ने इस आवश्यकता की पूर्ति पहले ही कर दी है। शेष बैंकों के मामले में केंद्रीय सरकार ने 1 अगस्त 1971 तक के लिए अर्वाध बड़ा दी है। परंतु, इन छः बैंकों के मामले में भी, रिजर्व बैंक ने दो बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिये हैं और शेष चार बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि वे निर्धारित अधिध के भीतर कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें।

278. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ख के अनुसार, गैर सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति तथा अपने निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति/पारिश्रमिक से संबंधित उपबन्धों में किये जानेवाले किसी संशोधन के संबंध में रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। गैर सरकारी बैंकिंग कंपनियों से उनके मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति या उनके पारिश्रमिक के संबंध में प्राप्त 213 आवेदनों में 1 जुलाई 1970 से 30 जून 1971 तक के वर्ष में निपटा दिया गया। इनमें से 191 आवेदनों का अनुमोदन किया गया और 22 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया।

बैंकों का निरीक्षण

279. बैंकों की वित्तीय स्थिति और उनके परिचालन की पद्धतियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से बैंकों का आवधिक निरीक्षण किये जाने के रिजर्व बैंक के कार्यक्रमों के अनुसार, जुलाई 1970 से जून 1971 तक के वर्ष में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अधीन 40 अनुसूचित बैंकों और 7 गैर अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण किया गया या निरीक्षण शुरू किया गया। साथ ही, भारतीय बैंकों की मलयेशिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और श्रीलंका में स्थित विदेशी शाखाओं का भी निरीक्षण किया गया/निरीक्षण शुरू किया गया। अधिनियम की धारा 45 थ के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन रहनेवाले दो बैंकों का भी निरीक्षण किया गया तथा एक और बैंक का निरीक्षण शुरू किया गया ताकि यह मालूम किया जाए कि उनके परिसमापन से संबंधित क्रियाविधियों में कोई भारी अनियमितताएँ तो नहीं हैं।

280. आलोच्य वर्ष में, वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का केंद्रीय निरीक्षण इस उद्देश्य से शुरू किया

गया कि अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय उद्देश्यों के संदर्भ में उन शाखाओं की कार्य-पद्धतियों, विशेषकर जमा-गणियों के जुटाने और समाज के अधिक कमजोर और उपेक्षित वर्गों के वित्तीय सहायता देने के संबंध में, का पता लगाया जा सके और उनकी कार्य-पद्धतियों में सुधार लाने के उपाय सुझाये जा सकें। 58 केंद्रों में वाणिज्य बैंकों के 565 कार्यालयों में ऐसे निरीक्षण किये गये।

बैंकों का विलयन

281. रिजर्व बैंक ने गैर सरकारी तौर पर प्रबंधित वाणिज्य बैंक संघटन को सौविधिक उपबन्धों के अनुसार स्वीच्छक समा-मेलन और दृयताओं तथा आस्तियों के अंतरण की प्रक्रियाओं के जरिए मजबूत बनाने की अपनी चयनात्मक नीति को जारी रखा। आलोच्य वर्ष में दिल्ली क्षेत्र में स्थित साहूकार बैंक लिमिटेड नामक एक बैंक ने, जो व्यवस्था-योजना के अधीन कार्य कर रहा था, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) के अधीन उसी क्षेत्र में स्थित एक अन्य बैंक (न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड) में अपनी आस्तियों और दृयताओं को नयी निर्धि में अंतरित कर दिया। रिजर्व बैंक ने कानपुर क्षेत्र में स्थित बरैली कारपोरेशन (बैंक) लिमिटेड नामक एक अनुसूचित बैंक को उसी क्षेत्र में स्थित बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड नामक एक अनुसूचित बैंक के साथ स्वीच्छक आधार पर समामेलित करने के प्रस्ताव का सिद्धान्ततः अनुमोदन किया और संबंधित बैंकों को इस मामले में आगे के कार्रवाई करने की सलाह दी।

282. इस वर्ष बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किसी बैंक का अधिस्थगन नहीं किया गया। सितंबर 1960 से अधिस्थगन किये गये बैंकों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात् उक्त संख्या 60 ही रही : इन बैंकों की कुल जमागण 49.95 करोड़ रुपये हैं। इसके फलस्वरूप अन्य बैंकों के साथ समामेलन, (स्वीच्छक या अन्यथा) परिसमापन आदि और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के संबंध में की गयी व्यवस्थाओं के विस्तृत विवरण पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिये गये हैं।

30 जून 1971 को चयनारमक ऋण नियंत्रण की स्थिति

न्यूनतम माजिन	व्याज की न्यूनतम दर	ऋण का स्तर	छूटें	प्रतिबंध
1	2	3	4	5
ग्रनाज				
1. (i) भारतीय खाद्य निगम सभी पार्टियों द्वारा वैध रूप से नियुक्त एजेंटों को उनके द्वारा एजेंट की हैसियत से रखे गये स्टॉकों पर दिये जानेवाले,	के लिए वार्षिक 10 प्रतिशत।	जनवरी-फरवरी 1971 से शुरू होनेवाली प्रत्येक द्वैमासिक अवधि के लिए उच्चतम सीमा:	महाराष्ट्र में धान छूट दी गयी है:	और चावल, ज्वार और नागली (रागी) के वितरण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंसित ग्रनाज व्यापारियों को छोड़ कर अन्य पार्टियों को ऋण
(ii) भारतीय खाद्य निगम से खरीदे गये गेहूँ के स्टॉकों पर घाटे की बेलन मिलों को दिये जानेवाले ऋणियों के लिए 25 प्रतिशत		1970 की तदनुषी द्वैमासिक अवधि में बनाये रखे गये (धान और चावल गेहूँ और अन्य ग्रनाजों पर दिये जानेवाले ऋणियों के कुल संबंध में भ्रमण	(i) राज्य सरकार और किसी राज्य सरकार द्वारा उगाही करने वाले एजेंटों के रूप में नियुक्त किये गये भिन्नवालों और थोक व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋण, बशर्ते कि उगाही करने वाले ऐसे एजेंटों केवल संबंधित राज्य सरकार के एजेंटों के रूप में ही कार्य करते हों और उन पर अपनी या अन्य पार्टियों की ओर से धान को चावल में परिवर्तित करने या धान या चावल खरीदने /वितरित	

न्यूनतम साजिन	न्याज की न्यूनतम दर	ऋण का स्तर	छूटें	प्रतिबंध
1	2	3	4	5
2. स्टार्च का उत्पादन करने वाले यूनितों को छोड़कर अन्य पाटियों को सब्जियों पर दिये जानेवाले अग्रिमों के लिए 30 प्रतिशत।		अलग) ऋण के शीतल स्तर का 100 प्रतिशत। अतिरिक्त सीमा : 50,000 या उससे कम आबादी वाले क्षेत्र में 1-1-1970 को या उसके बाद खोली गयी प्रत्येक नयी शाखा के लिए अनाजों के तीनों वर्गों (अर्थात् धान और चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों) या उनमें से किसी एक वर्ग पर दिये जानेवाले अग्रिम के लिए 25,000 रुपये की संयुक्त सीमा।	करने से रोक लगा दी गयी हो। (ii) भारतीय खाद्य निगम को दिये जानेवाले अग्रिम (निगम के विधिवत् नियुक्त एजेंटों को दिये जानेवाले अग्रिमों को छोड़कर)। (iii) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, दिल्ली या किसी राज्य सरकार के माध्यम से दिये जानेवाले अग्रिम, या यथास्थिति, संबंधित राज्य सरकार या बीज अधिनियम 1966 के अधीन प्राधिकृत किसी प्रमाणित एजेंसी द्वारा प्रमाणीकृत अधिक उपजवाले/संकर बीजों पर और उक्त अधिनियम, की धारा 5 के अधीन अधिसूचित बीजों पर दिये जानेवाले अग्रिम। (iv) थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों और उपभोक्ता सहकारी समितियों के राज्य और राष्ट्रीय महासंघों को दिये जानेवाले अग्रिम। (v) महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के अधीन विधिवत् रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गयी और महाराष्ट्र राज्य के जिला कलक्टरों द्वारा धान और ज्वार, ज्वार और नागली (रागी) का व्यापार करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत सहकारी समितियों को दिये जाने वाले अग्रिम। (vi) पश्चिम बंगाल के सांविधिक रूप से राजनीकृत क्षेत्रों में राजनीकृत अनाजों के वितरण के लिए पश्चिम-बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त किये गये थोक और फुटकर व्यापारियों को राजनीकृत अनाजों पर दिये जाने वाले अग्रिम। (vii) असम, मेघालय, नागालैण्ड, जम्मू व काश्मीर के राज्यों और मणिपुर, नेफा और त्रिपुरा के संघशासित क्षेत्रों में दिये जाने वाले अग्रिम। (viii) अनाजों की भावाजाही के संबंध में आहूत मांग प्रलेखी बिलों की जमानत पर या उनकी खरीद या भोजन के रूप में दिये जाने वाले अग्रिम।	सीमाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
3 (i) स्टार्च का उत्पादन करने वाले यूनितों को सब्जियों पर दिये जानेवाले, (ii) चावल मिलों को धान दिये जानेवाले,				
(iii) 50,000 या उससे कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित अनाजों का परिष्करण करने वाले (चावल मिलों से हटकर), यूनितों की चार सप्ताहों की खपत के बराबर के स्टार्चों के लिए ऐसे यूनितों को धान और चावल को छोड़कर अन्य अनाजों के स्टार्चों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए 35 प्रतिशत।				
4. अनाज के स्टार्चों के संबंध में जारी की गयी सरकारी गोदाम रसीदों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए 40 प्रतिशत।				
5. अन्य सभी अग्रिमों के लिए 50 प्रतिशत।				
			2. अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को साजिन और उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रणों से छूट दी गई है :	
			(i) जो की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिम और	
			(ii) अनाजों पर सीधे कृषकों को और अपने कारखाने-सब्सिडियों को ऋण प्रदान करने के लिये प्राथमिक सहकारी समितियों को दिये जाने वाले अग्रिम ; ये अग्रिम खरीद फसल पर उसकी कटाई की तारीख से दो महीनों	

न्यूनतम माजिन	ब्याज की न्यूनतम दर	ऋण का स्तर	छूटें	प्रतिबंध
1	2	3	4	5
			की अवधि के लिए पहले दिये गये अग्रिमों के विस्तार के रूप में हैं; परन्तु शर्त यह है कि ऐसी प्रत्येक ऋण सीमा की राशि 2,500 रुपये प्रति कुषक या फसल ऋण की बकाया राशि, इसमें से जो भी कम हो, से अधिक न हो।	
			3. अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रण से छूट दी गयी है :	
			(i) भारतीय खाद्य निगम के खरीदे गये गेहूं की जमानत पर घाटे की बेलन मिलों को दिये जाने वाले अग्रिम,	
			(ii) सभी पार्टियों को मक्के पर दिये जाने वाले अग्रिम, और	
			(iii) 50,000 या उससे कम भावादी वाले केन्द्रों में स्थित बाल मिलों (परन्तु चावल मिलों से इतर) जैसे अनाजों का परिष्करण करने-वाले यूनिटों को धान और चावल को छोड़कर अन्य अनाजों पर दिये जानेवाले अग्रिम।	

मूंगफली और 'अन्य तिलहन'

1. (अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को छोड़कर)
 - (i) मूंगफली और
 - (ii) 'अन्य तिलहन' पर दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में अलग अलग रूप से 75 प्रतिशत।
 2. (क) उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्य में स्थित प्रत्येक मिल की दो महीनों की खपत के बराबर के खाद्य तिलहनों के स्टॉकों पर दिये जाने वाले।

(ख) तेल मिलों को बिनालों पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर 25 प्रतिशत।
 3. (क) तोरिया बीजों/सरसों के बीजों पर दिये जाने वाले, और

(ख) सोयाबीन पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर 60 प्रतिशत।
- वार्षिक 12 प्रतिशत। जनवरी-फरवरी, 1971 से शुरू होने वाली प्रत्येक द्वैमासिक अवधि के लिए (i) मूंगफली और (ii) 'अन्य तिलहन' में से प्रत्येक के लिए नीचे लिखे अनुसार अलग अलग उच्चतम सीमाएं : 1967 की तबनुकूपी द्वैमासिक अवधि में मूंगफली और 'अन्य तिलहन' के संबंध में बनाये रखे गये ऋण के कुल औसत स्तर का 70 प्रतिशत।
- I. (i) बिनालों, (ii) तोरिया बीजों/सरसों के बीजों और (iii) सोयाबीन पर दिये जाने वाले अग्रिमों की उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रण से छूट दी गयी है।
 - II. (i) (अलसी और एरंड के बीजों को छोड़कर) अखाद्य तिलहनों और (ii) केरल और मैसूर में खाद्य वर्ग के खोपरे पर दिये जाने वाले अग्रिमों को माजिन और उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रणों से छूट दी गयी है।
 - III. अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को नियंत्रण से पूरी छूट दी गयी है :
 - (क) भारतीय खाद्य निगम और राज्य व्यापार निगम को दिये जाने वाले अग्रिम।
 - (ख) तिलहनों, तिलहनों से संबंधित तैयारहित और/या चरबीरहित खलियों और/या तिलहनों के निस्सारणों के निर्यातकों को विशिष्ट पक्के निर्यात टिकों के संबंध में और/या निर्यात बिलों पर दी जानेवाली ऋण सीमाएं।
 - (ग) थोक उपभोक्ता, सहकारी भंडारों और उप-भोक्ता सहकारी समितियों के राज्य तथा राष्ट्रीय महासंघों को दिये जाने वाले अग्रिम।
 - (घ) साल बीजों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिम।
 - (ङ) असम, मेघालय, नागालैण्ड और जम्मू व काश्मीर के राज्यों और मणिपुर, नेफा, और त्रिपुरा के संघशासित क्षेत्रों में स्थित सभी पार्टियों को दिये जाने वाले अग्रिम।

न्यूनतम मार्जिन	आय की न्यूनतम दर	कृषि का स्तर	छूटें	प्रतिबंध
1	2	3	4	5

(ग) तिलहनों की आवाजाही के संबंध में प्राह-
रित मांग प्रलेखी बिलों की जमानत पर
या उन की खरीद या भाजन के रूप में विये
जाने वाले अधिम ।

वनस्पति तेल और वनस्पति

1. (अधिमों के निम्नलिखित वर्गों को छोड़कर) वनस्पति तेलों और वनस्पति पर दिये जाने वाले अधिमों के लिए 75 प्रतिशत ।
 2. (i) बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित फ़ैक्टरियों द्वारा औद्योगिक कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किये जाने के लिए अलसी और एरंड के तेलों से परिष्कृत किये गये तेलों के स्टॉकों पर दिये जाने वाले और
(ii) वनस्पति निर्माताओं को बिनोले के तेल पर दिये जानेवाले अधिमों के लिए 25 प्रतिशत ।
 3. वनस्पति निर्माताओं को पूर्वी क्षेत्र में स्थित प्रत्येक फ़ैक्टरी की 6 सप्ताहों की खपत के बराबर के और उसके द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किये जाने वाले वनस्पति तेलों के स्टॉक पर दिये जाने वाले अधिमों के लिए 40 प्रतिशत; उक्त खपत का निर्धारण अक्तूबर, 1969 से मार्च 1970 तक की अवधि के दौरान हुई साप्ताहिक खपत के औसत के आधार पर किया जायगा ।
 4. वनस्पति निर्माताओं को उत्तरी क्षेत्र में स्थित प्रत्येक फ़ैक्टरी की 6 सप्ताहों की खपत और दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक फ़ैक्टरी की 4 सप्ताहों की खपत के बराबर के और उसके द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किये जाने वाले वनस्पति तेलों के स्टॉकों पर दिये जाने वाले अधिमों के लिए 50 प्रतिशत; उक्त खपत का निर्धारण अक्तूबर, 1969 से मार्च 1970 तक की अवधि के दौरान हुई साप्ताहिक खपत के औसत के आधार पर किया जायगा ।
12. जनवरी-फरवरी, 1971 से शुरू होने वाली प्रत्येक द्मासिक अवधि के लिए नीचे लिखे अनुसार उच्चतम सीमा :
1967 की तदनुकूली द्वै-मासिक अवधि में वास्तविक रूप से बनाये रखे गये ऋण के कुल औसत स्तर का 70 प्रतिशत ।
- I. (i) वनस्पति निर्माताओं और रजिस्ट्रीकृत तेल मिलों को वनस्पति तेलों और वनस्पति पर दिये जाने वाले अधिमों और
(ii) बिनोले के तेल पर दिये जाने वाले अधिमों को उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रण से छूट दी गयी है ।
 - II. अखाद्य वनस्पति तेलों और अलसी के तेल और एरंड के तेल से इतर अन्य अखाद्य वनस्पति तेलों से परिष्कृत किये गये तेलों या उनके निस्सारणों पर दिये जाने वाले अधिमों को मार्जिन और उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रण से छूट दी गयी है ।
 - III. अधिमों के निम्नलिखित वर्गों को नियंत्रण से पूरी छूट दी गयी है
(क) भारतीय खाद्य निगम और राज्य व्यापार निगम को वनस्पति तेलों और वनस्पति के स्टॉकों पर दिये जाने वाले अधिम ।
(ख) वनस्पति निर्माताओं को पी० एल० 480 करार के अधीन आयात किये गये सोयाबीन तेल के स्टॉकों पर और इसी सरकार से उपहार के रूप में या वाणिज्यिक आधार पर प्राप्त स्टॉकों पर, जो राज्य व्यापार निगम और/या राज्य सरकारों द्वारा वनस्पति निर्माताओं को वितरित किये जाए, दिये जाने वाले अधिम ।
(ग) वनस्पति निर्माताओं द्वारा भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय के सैनिक खरीद संगठन के साथ किये गये या किये जाने वाले ठेकों के अनुसार उक्त निर्माताओं द्वारा उक्त संगठन को देने के लिए अपने पास रखे गये वनस्पति के स्टॉकों पर दिये जाने वाले अधिम ।
(घ) तेलरहित और/या चरबीरहित खलियों के निर्यातकों को विशिष्ट पक्के निर्यात ठेकों के संबंध में और/या निर्यात बिलों पर वनस्पति तेलों और वनस्पति के स्टॉकों पर दिये जाने वाले अधिम ।
(ङ) तेलरहित और/या चरबीरहित खलियों के निर्यातकों को पक्के निर्यात आर्डरों/साख-पत्रों के आधार पर तिलहनों और/या अन्य कच्ची सामग्री की जमानत पर संबंधित निर्यात आर्डर में निर्दिष्ट खलियों के उत्पादन

न्यूनतम मार्जिन	व्याज की न्यूनतम दर	ऋण का स्तर	छूटें	प्रतिबंध
1	2	3	4	5

के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री के मूल्य की सीमा तक दिये जाने वाले पैकिंग साख अग्रिम, भले ही कच्ची सामग्री का मूल्य संबंधित निर्यात आर्डर के मूल्य से अधिक हो; परन्तु (i) ऐसे अग्रिमों का समायोजन गोण उत्पादन के रूप में प्राप्त तेल के मूल्य की सीमा तक उक्त तेल की बिक्री की आगम राशि से या तेल का निस्सारण होते ही तकदी में किया जाए और पैकिंग ऋण से संबंधित शेष राशि का समायोजन संबंधित निर्यात बिल की आगम राशि से किया जाए और (ii) गोण उत्पादन के रूप में प्राप्त तेल पर अलग लेखे में दिये जानेवाले अग्रिमों को उनमें दिये जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि के लिए छूट दी जाती है।

- (च) थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों और उपभोक्ता सहकारी समितियों के राज्य तथा राष्ट्रीय महासंघों को दिये जाने वाले अग्रिम।
- (छ) असम, मेघालय, नागालैण्ड और जम्मू व काश्मीर के राज्यों और मणिपुर, नेफा और त्रिपुरा के संघशासित क्षेत्रों में दिये जाने वाले अग्रिम।
- (ज) वनस्पति लेखों और वनस्पति की आवाजाही के संबंध में आहरित मांग प्रलेखी बिलों की जमानत पर या उनकी खरीद या भोजन के रूप में दिये जाने वाले अग्रिम।

नयी वनस्पति फैंक्टरियों के लिए :

मार्जिन फैंक्टरी के स्थान के आधार पर 6/4 सप्ताहों की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए; उक्त आवश्यकता का निर्धारण फैंक्टरी की स्थापना की तारीख से जो वास्तविक साप्ताहिक खपत हुई उसके औसत के आधार पर किया जायगा।

भविष्य में संभवतः उत्पादन शुरू करने वाले वनस्पति यूनिटों के लिए :

मार्जिन फैंक्टरी के स्थान के आधार पर 6/4 सप्ताहों की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए; उक्त आवश्यकता का निर्धारण पहले छः महीनों के लिए संबंधित यूनिट की साप्ताहिक उत्पादन क्षमता के औसत की एक-तिहाई के आधार पर और उसके बाद पिछले छः महीनों के दौरान हुई वास्तविक साप्ताहिक खपत के औसत के आधार पर किया जायेगा।

न्यूनतम माजिन	व्याज की न्यूनतम दर	ऋण का स्तर	छूटें	प्रतिबंध
1	2	3	4	5
रुई और कपास				
मिलों को :	सभी पार्टियों के लिए	1. मिलों को दिये जानेवाले अग्रिमों के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं है। 2. अन्यो के लिए : अक्टूबर 1970-जनवरी 1971 से शुरू होने वाली प्रत्येक चार महीनों की अवधि के लिए नीचे लिखे अनुसार उच्चतम सीमा : पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1969, 1968 और 1967 में से किसी भी वर्ष की तदनुसूची चार महीनों की अवधि में विद्यमान सर्वोच्च स्तर का 75 प्रतिशत। जून-सितम्बर 1971 की अवधि के लिए : वही उच्चतम सीमा जो पिछले चार महीनों की अवधि अर्थात् फरवरी-मई 1971 में रही हो (अर्थात् पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1969, 1968 और 1967 में से किसी भी वर्ष की फरवरी-मई की चार महीनों की अवधि में विद्यमान सर्वोच्च स्तर के 75 प्रतिशत के बराबर की उच्चतम सीमा)।	I. अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को नियंत्रण से पूरी छूट दी गयी है : 1. आयातित रुई और कपास के स्टॉकों पर दिये जानेवाले अग्रिम। 2. रुई के निर्यातों के लिए पोतलदानपूर्व ऋण के संबंध में दिये जानेवाले अग्रिम, बशर्ते कि पक्के निर्यात आर्डर के संबंध में अग्रिम दिया जाए और पोतलदान किये जाने पर संबंधित निर्यात बिल के बेचान द्वारा उसकी वापसी अवश्यगी की जाए। 3. भारत से निर्यात की जानेवाली रुई से संबंधित निर्यात बिलों की जमानत पर या उनकी खरीद या भांजन के रूप में दिये जानेवाले अग्रिम। 4. रुई और कपास की आवाजाही के संबंध में आहूत मांग प्रलेखी बिलों की जमानत पर या उनकी खरीद या भांजन के रूप में दिये जाने वाले अग्रिम। 5. रुई के निर्यात योग्य प्रकारों अर्थात् बंगाल देशी चुनी हुई पीली रुई (यलो पिकिम्स) जोडास, झाड़न रुई (स्वीपिम्स), आदि के स्टॉकों को जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिम, बशर्ते कि ऐसे स्टॉकों के संबंध में संबंधित पार्टियों को पक्के निर्यात आर्डर प्राप्त हो गये हों और वे बैंकों के पास रखे गये हों। 6. असम, मेघालय, नागालैंड, जम्मू तथा काश्मीर के राज्यों और मणिपुर, नेफा और त्रिपुरा के संघशासित क्षेत्रों में दिये जानेवाले अग्रिम।	
अ. कमजोर मिलों के लिए :	वार्षिक 12 प्रतिशत।			
I. प्राधिकृत नियंत्रक के अधीन मिलें : मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी के अधीन मिलें : सरकार के परिचालन/स्वामित्व/प्रबंध के अधीन रहने वाली मिलें/प्राधिकृत एजेंसियाँ (राज्य वस्त्र निगम सहित) और उड़ीसा में स्थित मिलें। (i) 6 सप्ताहों की खपत की मात्रा के स्टॉकों के लिए 20 प्रतिशत। (ii) 6 सप्ताहों की खपत की मात्रा से अधिक रहने वाले स्टॉकों के लिए 35 प्रतिशत।				
II. सूती वस्त्र उद्योग के लिए बैंक ऋण से संबंधित अध्ययन दल द्वारा विचार की गयी आर्थिक दृष्टि से कमजोर मिलें : (i) 6 सप्ताहों की खपत की मात्रा के स्टॉकों के लिए वही माजिन जो 21 जनवरी 1970 के निर्देश के पहले था। (ii) 6 सप्ताहों की खपत की मात्रा से अधिक रहने वाले स्टॉकों के लिये 35 प्रतिशत।				
आ. अन्य मिलें :				
I. पश्चिम बंगाल से इतर राज्यों में स्थित मिलें : (i) 6 सप्ताहों की खपत की मात्रा के स्टॉकों के लिए 25 प्रतिशत। (ii) 6 और 8 के बीच के सप्ताहों की खपत की मात्रा के स्टॉकों के लिए 40 प्रतिशत। (iii) 8 सप्ताहों की खपत की मात्रा से अधिक रहने वाले स्टॉकों के लिए 60 प्रतिशत।				
II. पश्चिम बंगाल में स्थित मिलें : (i) 10 सप्ताहों की खपत की मात्रा के स्टॉकों के लिए 20 प्रतिशत। (ii) 10 सप्ताहों की खपत की मात्रा से अधिक रहने वाले स्टॉकों के लिए 35 प्रतिशत।				
अग्रिमों को :				
अ. रुई और कपास के पुराने स्टॉकों (अर्थात् अक्टूबर 1970 से पहले विपणन किये गये) के लिए 75 प्रतिशत।				
				II. शाल्य चिकित्सा संबंधी रुई (अग्रशोषक रुई) के निर्माताओं को रुई और कपास पर दिये जानेवाले अग्रिमों, को माजिन और उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रणों से छूट दी गयी है, बशर्ते कि ऋणकर्ता शाल्य चिकित्सा संबंधी रुई तैयार करने के लिए ऐसे स्टॉक अपने पास रखे, न कि पुनः बेचने के लिए।
				III. अग्रिमों के निम्नलिखित वर्गों को माजिन संबंधी नियंत्रण से छूट दी गयी है। (i) सूती मिलों को ऐसे सूती वस्त्र (सूत सहित) तैयार करने के लिए आवश्यक देशी रुई और कपास के स्टॉकों पर पोतलदानपूर्व ऋण के संबंध में दिये जानेवाले अग्रिम जिनके संबंध में पक्के निर्यात आर्डर सीधे मिलों द्वारा या ऐसे व्यापारी-निर्यातकों द्वारा, जिनके जरिए मिलें निर्यात किया करती हैं, प्राप्त किये गये हों; बशर्ते कि व्यापारी-निर्यातकों द्वारा प्राप्त ठेकों को सूती वस्त्र निर्यात विकास परिषद में रजिस्ट्रीकृत किया गया हो। यदि मिलों द्वारा पक्के निर्यात

न्यूनतम माजिन	व्याज की न्यूनतम दर	श्रृंखला का स्तर	छूटें	प्रतिबंध
1	2	3	4	5
आ. नये स्टाकों के लिए				
(i) अक्टूबर 1970—जनवरी 1971 में विपणन किये गये				ग्राहक सीधे प्राप्त किये गये हों तो पोतल-दान किये जाने पर संबंधित नियति बिलों के बेचान द्वारा अधिमों की वापसी सहायगी की जानी चाहिए।
(क) 60 प्रतिशत—अक्टूबर 1970—जनवरी 1971				(ii) पश्चिम बंगाल में स्थित मरम्मत के अधीन मिलों और पश्चिम बंगाल सरकार या उसकी प्राधिकृत एजेंसियों के स्वामित्व/प्रबंध/परिचालन के अधीन रहनेवाली मिलों को प्रत्येक मिल की 10 सप्ताहों की छपत की मात्रा के बराबर के स्टाकों पर दिये जानेवाले अधिम।
(ख) 60 प्रतिशत—फरवरी 1971—अगस्त 1971				
(ग) 75 प्रतिशत—उसके बाद				
(ii) फरवरी 1971—मई 1971 में विपणन किये गये				
(क) 60 प्रतिशत—फरवरी 1971—मई 1971				
(ख) 60 प्रतिशत—जून 1971—सितंबर 1971				
(ग) 75 प्रतिशत—उसके बाद				
(iii) जून 1971—सितंबर 1971 में विपणन किये गये				
(क) 60 प्रतिशत—जून 1971—सितंबर 1971				
(ख) 60 प्रतिशत—अक्टूबर 1971—जनवरी 1972				
(ग) 75 प्रतिशत—उसके बाद				

283. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अधीन की जानेवाली समामेलन-योजनाओं के अनुसार यह आवश्यक है कि जमाकर्ताओं को पूरी रकम अदा करने के बाद अंतर्गती बैंकों के पास शेष रहनेवाली अतिरिक्त रकम को अन्य बैंकों के साथ समामेलित किये गये बैंकों के शेयरधारियों को अदा कर दिया जाए। 12 अंतरक बैंकों के शेयरधारियों को पूरी रकम की अदायगी कर दी गयी है जब कि अन्य 14 अंतरक बैंकों के शेयरधारियों को आनुपातिक अदायगीयों की जा रही है।

बैंकों का लाइसेंसिकरण

284. आलोच्य वर्ष में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन लॉर्ड कृष्ण बैंक लिमिटेड और जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक लिमिटेड नामक दो बैंकों को भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किये गये। इसी अवधि में, 14 प्रमुख भारतीय वाणिज्य बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिये

गये; क्योंकि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 4 के अनुसार उन बैंकिंग कंपनियों को तत्पन्नरूपी नये बैंकों में अंतरित कर उनके अधिकार में लाया गया। इसके फलस्वरूप उनके द्वारा भारत में बैंकिंग कारोबार करना बंद किया गया। इस प्रकार, उन बैंकों की संख्या बढ़कर 50 हो गयी जिनके मामलों में लाइसेंस रद्द किये गये हैं और जून 1971 के अंत में लाइसेंसीकृत बैंकों की कुल संख्या घटकर 46 हो गयी। साथ ही, सरकारी क्षेत्र में 22 बैंक थे जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंक और उपयुक्त राष्ट्रीयकृत उपक्रमों का कारोबार करने के लिए गठित 14 तत्पन्नरूपी नये बैंक शामिल हैं; इनके लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

285. आलोच्य वर्ष में, उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन पंजाब एण्ड काश्मीर बैंक लिमिटेड नामक एक वर्तमान बैंक को भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस देने से इनकार

कर दिया गया जब कि उक्त धारा के अधीन भारत में बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस मांगते हुए एक कंपनी से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। जून 1971 के अंत में उन बैंकों की कुल संख्या 282 थी जिनके लाइसेंस देने से इनकार कर दिया गया था। चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक बैंक के वर्तमान उपक्रम के संदर्भ में भारत में बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए उसने एक नये लाइसेंस की मांग करते हुए आवेदन किया है जो अभी विचाराधीन है।

परिसमापन की कार्यवाहियाँ

286. आलोच्य वर्ष में, उच्च न्यायालय द्वारा 10 गैर अनुसूचित बैंकों का विघटन किया गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 (1) के अधीन रिजर्व बैंक से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद एक बैंक का स्वीच्छक परिसमापन हो गया जब कि 2 बैंकों का न्यायालय द्वारा परिसमापन किया गया।

287. रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 द के अधीन संबंधित बैंकों के परिसमापकों द्वारा प्रस्तुत की गयी 215 विवरणियों की जाँच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति की गयी है और परिसमापन संबंधी कार्यवाहियों में अनुचित विलंब नहीं किया गया है।

288. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 थ के अधीन 3 बैंकों के निरीक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार से निदेश प्राप्त हुए।

ऋण सूचना

289. रिजर्व बैंक के ऋण सूचना प्रभाग ने मार्च 1971 में बैंकों के ऋणकर्ताओं के संबंध में ऋण संबंधी सूचनाओं को एकत्र करने और उनपर कार्यवाही करने की पद्धति को व्यवस्थित रूप से परिशीलित किया ताकि ऐसी सूचनाओं के क्षेत्र को व्यापक बनाया जा सके और अधिक अद्यतन आंकड़े रखे जा सकें और वे आंकड़े बैंकों के लिए अधिक उपयोगी हो सकें। बैंक व्यवसाय के विकास के सामाजिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में किये गये प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में, ऋणकर्ताओं के संबंध में अब प्राप्त की जानेवाली ऋण संबंधी सूचनाओं के अंतर्गत ऋण का उद्देश्य, ऋणकर्ता का व्यवसाय आदि कीतपय व्यापक पहलू भी शामिल हैं। उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, विवरणी के फार्म और विषय को उपयुक्त रूप से परिशीलित किया गया है और उक्त विवरणी का संकलन करने के लिए बैंकों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रदान किये गये हैं। इसके अलावा, इस उद्देश्य से कि बैंक सरलता से विवरणी का संकलन कर सकें, रिजर्व बैंक ने (उपयुक्त संशोधनों के साथ) "एक-सी बकाया बीहियाँ—बैंक ऋण के सांख्यिकीय आंकड़े" के लिए निर्धारित पद्धति के आधार पर एक संकेत-पद्धति अपनायी है जो बैंकों को पहले ही सूचित की जा चुकी है। चूंकि यह पाया गया कि पहले विद्यमान स्तरों (अर्थात् 5 लाख रुपये और उनसे अधिक राशि की जमानती ऋण सीमाओं और 1 लाख रुपये और उससे अधिक राशि की गैर जमानती ऋण सीमाओं) के अनुसार तिमाही आधार पर ऋण सूचना का जो संकलन किया जाता था उसमें बैंकों को तथा उन आंकड़ों पर कार्यवाही करने में रिजर्व बैंक को काफी समय और शक्ति लगानी पड़ती थी; अतः यह निश्चय किया गया कि बड़े ऋणकर्ताओं (जिनकी जमानती ऋण सीमाओं की राशि 10 लाख रुपये और उनसे अधिक हो और गैर जमानती ऋण सीमाओं की राशि 2 लाख रुपये और उनसे अधिक हो) के संबंध में ये आंकड़े त्रैमासिक रूप से प्राप्त किये जाएँ और जिन ऋणकर्ताओं की जमानती ऋण सीमाओं की राशि 5 लाख रुपये और उनसे

अधिक हो और गैर जमानती ऋण सीमाओं की राशि 1 लाख रुपये और उससे अधिक हो उन ऋणकर्ताओं के संबंध में ये आंकड़े केवल अर्धवार्षिक रूप से अर्थात् जून और दिसंबर के अंत में प्राप्त किये जाएँ। बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि वे बड़ी ऋण सीमाओं के लिए प्राप्त सभी आवेदनों पर कार्यवाही करते समय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध ऋण संबंधी सूचनाओं का उपयोग अधिक मात्रा में करें। परिशीलित विवरणी को लागू किये जाने के फलस्वरूप अब यह संभव होगा कि बैंकों के ऋण संबंधी अधिक अद्यतन सूचनाएं दी जा सकें। 1 जुलाई 1970 से 30 जून 1971 तक के वर्ष के दौरान इस प्रभाग ने 34 आवेदक बैंकों/संस्थाओं का 1,458 आवेदनों के संबंध में सूचनाएं प्रदान कीं।

समाशोधन गृह सुविधाएँ

290. देश में बैंकिंग सुविधाओं को व्यापक बनाने की रिजर्व बैंक की नीति के एक अंश के रूप में आलोच्य वर्ष में समाशोधन गृह सुविधाओं को और अधिक व्यापक बनाया गया। इस प्रकार, इस वर्ष (जुलाई 1970 से जून 1971 तक) के दौरान 28 और समाशोधन गृह स्थापित किये गये; इससे देश में कार्यशील समाशोधन गृहों की कुल संख्या बढ़कर 135 हो गयी। इन में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा क्रमशः 9,102 और 24 समाशोधन गृहों का प्रबंध किया जाता है।

जूट उद्योग संबंधी कार्यकारी दल

291. जूट उद्योग की ऋण समस्याओं से संबंधित कार्यकारी दल का उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था। रिजर्व बैंक ने उक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट का अनुशीलन किया। कार्यकारी दल ने, अन्य बातों के साथ साथ, यह सिफारिश की थी कि जूट मिलों के उत्पादन के जिस अंश का निर्यात किया जाता है उसके संबंध में दिये जानेवाले ऋणों के लिए ब्याज की रियायती दर लागू कर इस उद्योग को कुछ राहत देने के लिए एक अलग योजना बनायी जाए। कार्यकारी दल ने इस योजना के व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त भी सुझाये थे। अनुशीलन करने के बाद, बैंक का उक्त सुझाव स्वीकार्य प्रतीत हुआ, अतः उसे इस विषय में सरकार की सहमति प्राप्त होने पर सभी बैंकों को भेजा जाएगा। कार्यकारी दल की अन्य सिफारिशें भी सामान्यतः स्वीकार्य प्रतीत हुई और भारतीय बैंक संघ को यह सूचित किया गया है कि वह अपने सदस्य-बैंकों से उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की प्रार्थना करे।

वाणिज्य बैंकों के कारोबार के परिणाम

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

292. राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित 69 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 1970 के वर्ष के लिए अपने लाभ और हानि लेखों का प्रकाशन किया है। उन बैंकों के कारोबार के परिणामों का विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि 1969 की तुलना में इस वर्ष उनके लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनके लाभों की राशि 21.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 26.3 करोड़ रुपये हो गयी है। जहाँ उन बैंकों की कुल आय में 1969 में 42.8 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी वहाँ उसमें 1970 में 87.9 करोड़ रुपये (22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 'ब्याज और भांजन' से प्राप्त आमदनी में आक्रामक वृद्धि हो जाने के कारण आय में यह वृद्धि हुई, 'ब्याज और भांजन' में 1969 में 36.3 करोड़ रुपये या 12 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई थी उसकी तुलना में 1970 में 82.7 करोड़ रुपये या 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 'कमीशन, विनिमय शुल्क और दलाली' से मिलनेवाली

*13 विदेशी बैंकों सहित सभी प्रमुख बैंक सम्मिलित हैं।

आमदनी में 1969 में जो वृद्धि हुई थी उसकी तुलना में 1970 में हुई वृद्धि कम थी। 1970 में 69 बैंकों के कुल व्यय में 83.2 करोड़ रुपये (22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जब कि 1969 में उसमें 41.4 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 'वैतन, भत्ते और भविष्य निधि में अंशदान' संबंधी व्यय में जहां 1969 में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां 1970 में 1969 की व्यय-राशि से अधिक 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 'जमाराशियाँ और ऋणों पर' अक्षा किये गये ब्याज' में भी वृद्धि हुई; जहां 1969 में हुई वृद्धि की यह दर 11 प्रतिशत थी वहां 1970 में 19 प्रतिशत थी।

स्टेट बैंक समुदाय

293. स्टेट बैंक आफ इंडिया की कुल आय जहां 1969 में 91.4 करोड़ रुपये थी वहां यह बढ़कर 1970 में 112.7 करोड़ रुपये हो गयी और कुल व्यय 85.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 107.3 करोड़ रुपये हो गया। आय की तुलना में व्यय में जो अधिक वृद्धि हुई उसका कारण इस वर्ष स्थापना व्यय (10.9 करोड़ रुपये) और जमाराशियाँ तथा ऋणों पर अदा किये गये ब्याज (8.6 करोड़ रुपये) में हुई अधिक वृद्धि है। इसके फलस्वरूप, लाभ-शेष में थोड़ी सी कमी हुई अर्थात् जहां यह 1969 में 5.50 करोड़ रुपये था वहां 1970 में घटकर 5.40 करोड़ रुपये हो गया। लाभ की इस राशि में से, स्टेट बैंक ने 1.09 करोड़ रुपये प्रतिरक्षित निधियों में अंतरित किये और 2.70 करोड़ रुपये कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने और 1.29 करोड़ रुपये शेयरधारियों को लाभांश वितरित करने के निमित्त अलग रखे; इन सभी मामलों में किये गये वितरण 1969 में किये गये वितरणों के बराबर ही थे। सहायक बैंकों की आमदनी जहां 1969 में 26.7 करोड़ रुपये थी वहां यह बढ़कर 1970 में 32.5 करोड़ रुपये हो गयी जब कि उनके खर्च में अपेक्षाकृत बहुत कम वृद्धि हुई अर्थात् वह 25.8 करोड़ रुपये से बढ़कर केवल 31.2 करोड़ रुपये हुआ। इसके फलस्वरूप, उनकी लाभ-राशि 1969 के 95 लाख रुपये से बढ़कर 1970 में 1.33 करोड़ रुपये हो गयी। इन बैंकों ने 13 लाख रुपये प्रारक्षित निधियों में अंतरित किये, 35 लाख रुपये स्टेट बैंक के लाभांश के रूप में अदा किये और 77 लाख रुपये कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने के निमित्त अलग रखे। यद्यपि प्रारक्षित निधियों में अंतरित की गयी राशि 1969 की तुलना में कम थी फिर भी स्टेट बैंक को लाभांश के रूप में अदा की गयी राशि तथा कर्मचारियों को अदा की जानेवाली बोनस राशि 1969 की तुलना में अधिक थी।

राष्ट्रीयकृत बैंक

294. राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 31 दिसम्बर 1969 तक के अपने पहले तुलन पत्र और लाभ हानि लेखें दिसम्बर 1970 में प्रकाशित किये। इन चौदह बैंकों ने, अपने सभी व्ययों की पूर्ति करने के बाद और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए राशि सुरक्षित रखने के बाद, 1969 के लाभों में से कुल 3.69 करोड़ रुपये की राशि प्रारक्षित निधि में अंतरित की (जब कि राष्ट्रीयकरण के पहले इनके पूर्ववर्ती बैंकों ने 1968 के लाभों में से 1.80 करोड़ रुपये की राशि प्रारक्षित निधि में अंतरित की थी)। राष्ट्रीयकरण की तारीख के बाद की अवधि में अर्जित किये गये शुद्ध लाभों में से कुल 2.33 करोड़ रुपये का लाभ-अधिशेष की राशि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10(7) के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर दी गयी।

295. 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हाल ही में प्रकाशित किये गये 1970 के उनके कारोबार के परिणामों में यह पता चलता है कि (कर्मचारियों को बोनस की अदायगी करने के पहले किन्तु करों की अदायगी करने के बाद) उनके अर्जित लाभों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, इन लाभों की राशि जहां 1969 में 10.9 करोड़ रुपये थी वहां 1970 में वह 13.8 करोड़ रुपये हो गयी। अधिकतम शाखाओं खोलने और

बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में परिशोधन किये जाने के कारण दायताओं के बढ़ जाने के फलस्वरूप बैंकों के स्थापना व्यय में तेजी से वृद्धि हो जाने के बावजूद उनके लाभों में इतनी वृद्धि हुई।

296. इन बैंकों की कुल आय जहां 1969 में 217.6 करोड़ रुपये थी वहां यह 1970 में बढ़कर 266.7 रुपये हो गयी और उनका कुल व्यय 206.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 252.9 करोड़ रुपये हो गया। बैंकों द्वारा ऋणों पर लिये जानेवाले ब्याज की दरों पर लगायी गयी 9.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा को रिजर्व बैंक ने फरवरी 1970 में हटा दिया था, इस कारण उनकी ब्याज दरों में वृद्धि की गयी और साथ ही इस वर्ष के दौरान ऋण-जमा अनुपात भी अपेक्षाकृत ऊंचा था, इन प्रमुख कारणों से इन बैंकों की आय में वृद्धि हुई।

297. राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने लाभों में से 2.8 करोड़ रुपये प्रारक्षित निधि के निमित्त अलग रखे, 6.9 करोड़ रुपये कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने के लिये नियत किये और सीधीधक आवश्यकताओं के अनुसार शेष 4.2 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर दी।

गैर बैंकिंग कंपनियों पर नियंत्रण

298. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि वृक्षिण भारत में, विशेषकर मैसूर राज्य में, ऐसे 'वित्त निगमों' की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है जो ब्याज की अपेक्षाकृत उच्चतर दरों पर जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करते आ रहे हैं। चूंकि ये निगम साझेदारी फर्म हैं, अतः जमाराशियाँ स्वीकार करने के संबंध में गैर बैंकिंग कंपनियों को जारी किये जानेवाले निवृत्तों के उपबंध उनपर फिलहाल लागू नहीं होते। इन निगमों पर स्थानीय साहूकार अधिनियमों के उपबंधों को लागू करने और कीतपय अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इन अधिनियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर मैसूर और तमिलनाडु सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

299. आंध्र प्रदेश की विधान सभा ने चिट फंड कंपनियों के कारोबार को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। केरल में चिट कंपनियों से संबंधित वर्तमान विधि में संशोधन करने का प्रश्न वहां की राज्य सरकार के विचाराधीन है। मैसूर सरकार इस उद्देश्य के लिए स्थानीय अधिनियम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

300. 31 मार्च, 1968 तक की विवरणियों के आधार पर गैर बैंकिंग कंपनियों के पास रहनेवाली जमाराशियाँ का जो सर्वेक्षण किया गया उसके अनुसार कुल 27,338 कार्यरत मिश्रित पूंजी कंपनियों (वित्तीय तथा वित्तेतर) में से 2,398 कंपनियों ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया को विवरणियाँ प्रस्तुत कीं और उन्होंने 5.30 लाख लेखों की सूचना दी। जहां मार्च 1967 के अंत में इन कंपनियों के पास (186.60 करोड़ रुपये के छूट-प्राप्त ऋण सहित) कुल जमाराशियाँ 430.51 करोड़ रुपये थी वहां मार्च 1968 के अंत में उनके पास (जमा राशियों के रूप में न माने जानेवाले 209.59 करोड़ रुपये के छूट-प्राप्त ऋण सहित) कुल जमाराशियाँ 477.89 करोड़ रुपये थी। जमाराशियों की इस रकम में इन कंपनियों द्वारा विश्व बैंक, अमेरिकी अंतराष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतराष्ट्रीय विकास संघ, राष्ट्रमंडल विकास वित्त निगम और आयात-निर्यात बैंक जैसे विदेशी स्रोतों से लिये गये 79.60 करोड़ रुपये तक के गैर जमानती ऋण शामिल हैं (क्योंकि ये ऋण छूट प्राप्त ऋणों के वर्ग में नहीं आते), मार्च 1967 के अंत में ऐसे ऋणों की अनुमानित राशि 92 करोड़ रुपये थी।

जमा बीमा निगम

301. जहां जून 1970 के अंत में बीमाकृत बैंकों की संख्या 83 थी वहां वह घटकर जून 1971 के अंत में 82 हो गयी, क्योंकि एक बैंक की अस्तित्वों और दायताएं दूसरे बीमाकृत बैंक में अंतरित कर दी गयी

थी। आलोच्य वर्ष में किसी नये बैंक को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया। इस अवधि में बीमाकृत जमाराशियों के संदर्भ में निगम की कोई नयी दृष्टता उत्पन्न नहीं हुई। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अधीन समामिलित एक बैंक के संबंध में, जिसका उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था, जमाकर्ताओं की सूची की जांच करने के बाद निगम का वाचित्व निर्धारित किया गया और उसकी अदायगी कर दी गयी। निगम की स्थापना से लेकर 30 जून 1971 तक की अवधि में निगम द्वारा 14 बैंकों के जिन दावों के संबंध में अदायगी की गयी या व्यवस्था की गयी उनकी कुल राशि 113.04 लाख रुपये थी। इस वर्ष निगम ने जिन प्रतिस्थापित दावों के संबंध में अदायगी की या व्यवस्था की उनके संदर्भ में उसे प्रतिपूर्ति के रूप में 1.43 लाख रुपयों की राशि प्राप्त हुई, इससे 30 जून 1971 तक प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कुल राशि बढ़कर 37.54 लाख रुपये हो गयी।

302. बीमा रक्षा के लिए निर्धारित सीमा को अप्रैल 1970 में प्रति जमाकर्ता 5,000 रुपयों से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया था, उसमें इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बीमाकृत बैंकों द्वारा अपनी जमाराशियों के संबंध में वैय प्रीमियम की दर में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात् उक्त दर प्रति 100 रुपये वार्षिक 5 पैसे ही थी। उपलब्ध पिछले सांख्यिकीय आँकड़ों के अनुसार सितम्बर 1970 के अंत में बीमाकृत बैंकों के जमा लेखों का 98.4 प्रतिशत और उनकी जमाराशियों का 61.9 प्रतिशत बीमा योजना द्वारा प्रतिरक्षित किया गया था।

सहकारी क्षेत्र में जमा बीमा योजना

303. कतिपय राज्यों ने अपने राज्य सहकारी समिति अधिनियमों को पहले ही संशोधित कर दिया है ताकि संबंधित राज्यों के सहकारी बैंकों के लिए जमा बीमा योजना को लागू करने में सुविधा हो। 1 जुलाई 1971 से जमा बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के उपबन्धों को आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों और गोवा, दमन और दीव के संघशासित क्षेत्रों के सहकारी बैंकों के लिए लागू करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जमा बीमा निगम ने 1 जुलाई 1971 तक उपयुक्त राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के 385 योग्य सहकारी बैंकों को रजिस्ट्रीकृत किया है। यह सुनिश्चित करने के विचार से कि अन्य राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा किए जाने वाले संशोधनों में एकरूपता हो, कृषि ऋण विभाग ने संबंधित सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में स्थित सहकारी बैंकों के लिए जमा बीमा योजना को लागू करने के उद्देश्य से उनके संबंधित सहकारी समिति अधिनियमों को संशोधित करने के लिए उपयुक्त सरकारों के पास नमूना संशोधन भेज दिए थे।

बैंकिंग आयोग

304. बैंक व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं का अनुशीलन करने और उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग द्वारा गठित किए गए 5 अध्ययन दलों के संबंध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था।

305. देशी बैंकों और बैंक प्रणालियों से संबंधित अध्ययन दलों ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है और अन्य अध्ययन दल भी अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। बैंक संघटन को प्रभावित करने वाले विधान से संबंधित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट के प्रथम भाग को अंतिम रूप दे दिया है और द्वितीय भाग तैयार किया जा रहा है। आयोग की ओर से विश्वविद्यालयों और दूसरी संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों और छोटे दस्तकारों से संबंधित जो सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किए गए वे समाप्त हो गये हैं और उनकी रिपोर्टों का अधिकांश भाग आयोग को प्राप्त हो चुका है। जमाकर्ताओं को बैंकों से प्राप्त होने वाली सेवाओं का सर्वेक्षण कार्य

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को सौंपा गया था। उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया है और अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है।

306. आयोग ने इस अवधि में राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा किया। उसने विवेचन में केंद्र सरकार के अधिकारियों से भी भेंट की। विभिन्न राज्यों का दौरा करने का आयोग का कार्यक्रम जून 1971 में समाप्त हो गया। आयोग ने नई दिल्ली जाकर वित्त मंत्री से विचार विमर्श किए। आयोग ने बंबई में बैंकों, विशेषज्ञों और अन्यो के साथ भी विचार विमर्श किए। आशा की जाती है कि आयोग 1971 के अंत तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगा।

4. सहकारी बैंक व्यवसाय की गतिविधियाँ

307. सहकारी बैंकों द्वारा प्रगतिशील ऋण नीतियों के लागू किए जाने और जमाराशियों के जुटाए जाने और छोटें तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों और कृषि तथा संबंधित व्यवसायों में लगे हुए जन जाति वर्गों के लिए एक उपयुक्त ऋण तंत्र प्रारंभ किए जाने की दिशा में पिछले वर्षों में जो उपलब्धियाँ हुई थी उन्हें समीकृत करने का महत्वपूर्ण कार्य आलोच्य वर्ष में किया गया। फसली ऋण प्रणाली सहकारी बैंकों की ऋण व्यवस्था का एक सामान्य रूप बन चुकी है; उसमें क्षेत्रों द्वारा कृषि में काम आने वाली मूल वस्तुओं का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग किए जाने के परिप्रेक्ष्य में और अधिक सुधार हुआ है। इन गतिविधियों के फलस्वरूप सहकारी बैंकों को जो ऋण सहायता दी गई उसके साथ साथ इस बात का इतमीनान कर लेने के भी प्रयत्न किए गए कि सहकारी बैंक ऋण प्रदान करने एवं उनकी वसूली के कार्य में माँसमी आधार को बनाये रखें। इस उद्देश्य से कि रिजर्व बैंक पर बैंकों की निर्भरता को क्रमशः कम किया जाए, रिजर्व बैंक ने देश के बड़े केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए जमाराशियों के लक्ष्य निर्धारित किए। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज-दरों को उनके द्वारा जुटाई जाने वाली जमाराशियों के समानरूप कर देने की जो सिफारिश की थी उसके संदर्भ में यह एक प्रारंभिक कदम था। इसी प्रकार भूमि विकास बैंकों के संदर्भ में ग्रामीण बचतों को जुटाने के लिए प्रारंभ किये गये उनके ग्रामीण डिबेंचर कार्यक्रम को सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम से संबंधित कर दिया गया। वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक समितियों का वित्त-पोषण करायें जाने की योजना को बराबर कार्यान्वित करते हुए, ऋण-स्थिरीकरण की व्यवस्थाओं का उपयोग कर व्यापक रूप से प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित क्षेत्रों को निरन्तर ऋण प्राप्त कराते हुए और कमजोर केंद्रीय सहकारी बैंकों के पुनः स्थापन के लिए ठंडे योजनाएँ सुझाकर सहकारी ऋण विन्यास को सशक्त बनाते हुए रिजर्व बैंक कमजोर केंद्रीय सहकारी बैंकों के क्षेत्र में ऋण के संदर्भ में विद्यमान खाइयों को तुर करने के लिए बराबर प्रयास करता रहा।

कृषि ऋण मंडल

308. अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति की सिफारिश पर, ग्रामीण और सहकारी ऋण संबंधी पहले की स्थायी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर जो कृषि ऋण मंडल स्थापित किया गया उसकी पहली बैठक 3 अगस्त, 1970 को हुई। उसमें इस बात का सुनिश्चित कर लेने के लिए कि कृषि क्षेत्र को समय पर पर्याप्त ऋण प्राप्त हो, रिजर्व बैंक तथा अन्य विकास एजेंसियों द्वारा जो कदम उठाये जाने चाहिए उनके संबंध में पुनरीक्षण समिति द्वारा दी गयी विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया गया। इस मंडल के निर्णयों के अनुसार राज्य सरकारों और सहकारी बैंकों को यह सलाह दी गई कि वे सिफारिशों को अमल में लाने के संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करें। जहाँ तक रिजर्व बैंक के अपने कार्यों और नीतियों से संबंधित सिफारिशों का प्रश्न है, बैंक उनके क्रियान्वयन के लिए कदम उठा चुका है।

सारणी 38—वाणिज्य बैंक व्यवसाय की प्रवृत्तियों का विहंगावलोकन
(जून के अंतिम शुक्रवार को)

	1966	1967	1968	1969	1970	1971
1	2	3	4	5	6	7
I. बैंकों की संख्या						
(i) अनुसूचित बैंक	76	74	73	73	72	74
(ii) गैर-अनुसूचित बैंक	31	24	19	16	13	12
II. कार्यालयों की संख्या						
(i) अनुसूचित बैंक	6139	6620	7044	8045	9938	11892
(ii) गैर-अनुसूचित बैंक	240	216	203	217	193	149
III. कुल जमाराशियां (करोड़ रुपये में)						
(i) अनुसूचित बैंक	3123.2	3517.0	3969.0	4645.8	5274.5	6189.9
(ii) गैर-अनुसूचित बैंक	25.0	24.5	26.2	28.0	13.8	14.7
IV. मांग जमाराशियां (करोड़ रुपये में)						
(i) अनुसूचित बैंक	1477.3	1664.6	1874.8	2103.5	2328.8	2725.1
(ii) गैर-अनुसूचित बैंक	9.1	9.1	10.2	11.7	8.4	9.3
V. सीमादी जमाराशियां (करोड़ रुपये में)						
(i) अनुसूचित बैंक	1645.9	1852.4	2094.2	2542.3	2945.7	3464.8
(ii) गैर-अनुसूचित बैंक	15.9	15.4	16.0	16.3	5.4	5.4
VI. जमाराशियां, राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में (%)	15.3	14.8	14.1	16.3	17.0	18.0*
VII. कुल बैंक ऋण (करोड़ रुपये में)						
(i) अनुसूचित बैंक	2271.4	2631.1	3102.9	3598.8	4212.7	4775.8
(ii) गैर-अनुसूचित बैंक	15.0	15.1	12.8	16.4	3.5	3.1
VIII. ऋण-जमा अनुपात (%)						
(i) अनुसूचित बैंक	72.7	74.8	78.2	77.5	79.9	77.2
(ii) गैर-अनुसूचित बैंक	60.0	61.6	48.9	58.6	25.4	21.1
IX. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (करोड़ रुपये में)						
(i) अनुसूचित बैंक	918.8	922.6	975.6	1126.3	1186.1	1369.4
(ii) गैर-अनुसूचित बैंक	5.6	5.4	6.6	6.7	3.4	4.0
X. निवेश-जमा अनुपात (%)						
(i) अनुसूचित बैंक	29.4	26.2	24.6	24.2	22.5	22.1
(ii) गैर-अनुसूचित बैंक	22.4	22.0	25.2	23.9	24.6	27.2
XI. नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया राशियां (करोड़ रुपये में)						
(i) अनुसूचित बैंक	195.3	258.8	269.5	380.3	357.6	393.5
(ii) गैर-अनुसूचित बैंक	1.7	1.9	2.1	2.5	0.9	1.1
XII. नकदी-जमा अनुपात (%)						
(i) अनुसूचित बैंक	6.3	7.4	6.8	8.2	6.8	6.4
(ii) गैर-अनुसूचित बैंक	6.8	7.8	8.0	8.9	6.5	7.5

नोट: (1) गैर अनुसूचित बैंकों के संबंध में अंतिम स्तंभ में दिये गये आंकड़े अगस्त 1970 से संबंधित हैं।

(2) जून 1971 के आंकड़े अंतिम हैं।

(3) गैर अनुसूचित बैंकों के 1970 और 1971 के आंकड़े अंतिम हैं।

*वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के आधार पर (अनुमानित)।

309. लघु और कुटीर उद्योग, कृषि में दीर्घावधि निवेश, विपणन इत्यादि कीतपय विशेष सहकारी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित समस्याओं पर परामर्श देने के लिए, कृषि ऋण मंडल ने दो स्थायी समितियों का भी गठन किया है। आलाओच्य वर्ष में इन दोनों स्थायी समितियों की पहली बैठक हुई। पहली स्थायी समिति ने जहाँ अन्य बातों के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, कृषि क्षेत्र के विस्तार तथा विपणन के कार्य आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार किया, वहाँ दूसरी स्थायी समिति ने कृषि उत्पादन और निवेश के लिए बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधाओं के क्षेत्र में हुई प्रगति का पुनरीक्षण किया। इन स्थायी समितियों के द्वारा किये गये महत्वपूर्ण निर्णयों में से कुछ इस प्रकार हैं: बैंक फसलों के विपणन और परिष्करण के लिए आवश्यक ऋण की अलग व्यवस्था करें और वह सामान्य वन उत्पादों के विपणन के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करें। इनके अलावा इस बात पर भी निर्णय किया गया कि किन उद्देश्यों के लिए सहकारी बैंक मध्यावधि ऋण प्रदान कर सकते हैं। कृषि ऋण मंडल ने केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जमा राशियों के जुटाये जाने के प्रयासों के साथ बैंक द्वारा ऋणों पर लिये जानेवाले ब्याज की दर का सापेक्ष संबंध स्थापित करने के बारे में पुनरीक्षण समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का विस्तृत परीक्षण करने के लिए एक अध्ययन दल की भी नियुक्ति की। इस वर्ष के दौरान उक्त अध्ययन दल की एक बैठक हुई। उसमें दल ने अपने आलाओच्य विषयों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

छाट, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर अन्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

310. ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने चुने हुए जिलों में 46 छाट क्षेत्र विकास एजेंसियों और 37 सामान्य क्षेत्र तथा कृषि श्रम प्रायोजनाओं की संस्थापना का अनुमोदन किया है। छाट क्षेत्र विकास एजेंसियों/सामान्य क्षेत्र तथा कृषि श्रम प्रायोजनाओं के क्षेत्रों में सहकारी बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं के रिजर्व बैंक सक्रिय रूप से सहायता देता रहा है जिससे कि उनकी नीतियों और क्रियाविधियों छाट और सामान्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकें और उनके अपने वित्तीय साधनों की वृद्धि हो ताकि उनकी ऋण-आवश्यकताओं की पूर्णतः सम्पूर्ति हो सके। इसके साथ ही, रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चय करने के लिए भी कदम उठाया कि इन प्रायोजनाओं से बाहर के क्षेत्रों में भी, छाट और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों की ऋण-आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

311. योजना आयोग के परामर्श के अनुसार, रिजर्व बैंक ने कुछ छाट क्षेत्र विकास एजेंसियों की प्रायोजनाओं का विशेष अध्ययन किया। इन अध्ययन रिपोर्टों में छाट क्षेत्रों का पता लगाने तथा फसल के स्वरूप, सिंचाई-सुविधा की उपलब्धता, सहायक व्यवसायों की संभावना आदि के ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों की ऋण संबंधी तथा अन्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्य पद्धति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्देश किया गया था। वर्तमान ऋण एजेंसियों को सशक्त बनाने और उद्योग के लिए अपेक्षित मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी उपाय सुझाए गए। इस भूमिका का निरूपण करने और छाट क्षेत्रों को लाभ के लिए बनाए गये कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहकारी बैंकों के सामने आनेवाली समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए, रिजर्व बैंक ने अहमदाबाद, बंगलूर, चंडीगढ़ और कलकत्ता में केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। केंद्रीय सहकारी

बैंकों से भी कहा गया कि वे छाट क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सहकारी बैंक से प्राप्त उधारों में से पहले ही से निर्धारित प्रतिशत की मात्रा का उपयोग करें।

वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण समितियों का वित्तपोषण

312. कमजोर केंद्रीय सहकारी बैंकों के क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्तपोषण किये जाने के संदर्भ में जो संक्रमणकालीन योजना पिछले वर्ष खरीफ 1970 के कार्यक्रमों के वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए प्रारम्भ की गई थी, वह आलाओच्य वर्ष में जारी रही। इस योजना के अंतर्गत, स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह को मिलाकर 20 वाणिज्य बैंकों की 300 शाखाओं के लिए आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश के 49 जिलों में स्थित 1,974 समितियों को नियत किया गया। जून 1971 के अंत तक वाणिज्य बैंकों ने 1,546 समितियों को कुल 8.93 करोड़ रुपये की राशि के ऋण दिये थे। इसके अलावा, 589 समितियों के संदर्भ में 2.13 करोड़ रुपये की दायताओं को भी वाणिज्य बैंकों ने अपने उपर ले लिया था; इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत उनकी कुल दायताओं की राशि 9.06 करोड़ रुपये हो गयी। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और मैसूर में इस योजना के अंतर्गत हुई प्रगति उत्साहप्रद रही। योजना के कार्यान्वयन में प्रारंभ में क्रियाविधियों और संगठन से संबंधित जो कठिनाइयां हुईं उनके बावजूद यह कहा जा सकता है कि इस दिशा में काफी सफलता प्राप्त की गयी है, किन्तु संबंधित सभी एजेंसियों के सम्मिलित प्रयासों के द्वारा और अधिक तेजी से प्रगति लायी जा सकती है। इस योजना के अधीन, कृषि ऋण समितियों का वित्तपोषण करने वाले वाणिज्य बैंक, 4.1/2 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर पर रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। कृषि उत्पादों के द्विष्टिकबंधक रखने पर (ऋण नियंत्रण संबंधी शर्तों के अधीन), सदस्यों को ऋण दिये जाने के लिए समितियों को वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जानेवाले अभिमानों को, संबंधित फसल की कटाई की तारीख से दो महीनों की अवधि के लिए उच्चतम सीमा संबंधी नियंत्रण और मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं से भी छूट दी जाती है, बशर्ते कि प्रत्येक सदस्य को दिये जाने वाले ऋण की राशि को 2,500 रुपये की अधिकतम राशि या फसल ऋण की बकाया राशि में से जो भी कम हो, उस राशि तक सीमित कर दिया जाए। समितियों को पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने के संदर्भ में ये रियायतें वाणिज्य बैंकों के लिए प्रोत्साहनप्रद हैं।

सहकारी गरीबीहारी

313. संबंधित क्षेत्रों में सहकारी ऋण-नियन्त्रास को मजबूत बनाने के पहले रिजर्व बैंक के प्रयत्न से वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्त पोषण कराये जाने की उक्त योजना प्रारंभ की गई। इस दिशा में प्रयत्न जारी रखे गये और रिजर्व बैंक ने उन क्षेत्रों में जहां उपर्युक्त योजना अमल में थी तथा अन्य स्थानों में स्थित कमजोर केंद्रीय सहकारी बैंकों के पुनः स्थापन के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाए और राज्य सरकारों और संबंधित सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, उन कार्यक्रमों को अमल में लाने की सिफारिश की गई। महत्वपूर्ण सुझाव निम्नीलिखित बातों से संबंधित थे—(1) केंद्रीय सहकारी बैंकों के पुंजी-नियन्त्रास को सशक्त बनाना, (2) ऋण नीतियों और क्रिया-विधियों को उपयुक्त बनाना, (3) कालातीत ऋणों तथा भविष्य में दिए जानेवाले ऋणों की बसूली से संबंधित प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना, (4) अशोध्य ऋण संबंधी प्रारक्षित निधियों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता, और (5) जमा-राशियां जुटाना। आलाओच्य वर्ष में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों के

प्रतिनिधियों के साथ पुनःस्थापन योजनाओं से संबंधित विभिन्न विषयों एवं समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैंक इन प्रयत्नों की प्रगति पर बराबर ध्यान दे रहा है।

314. जनवरी और मई 1971 के बीच, ग्रामीण ऋण के कार्यभारी उप गवर्नर ने 12 राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ सहकारी ऋणों तथा तत्संबंधी गतिविधियों के अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं तथा समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। इन विचार-विमर्शों के दौरान, निरन्तर जारी रहनेवाली कमजोरियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और सहकारी बैंकों द्वारा जमा राशियों के जुटाये जाने, बढ़ती हुई कालातीत राशि, स्वीकृत पद्धति पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्गठन, कमजोर केंद्रीय सहकारी बैंकों के पुनःस्थापन और भूमि विकास बैंकों की समस्याओं के संबंध में उपचारमूलक प्रयत्न सुझाये गये।

सहकारी ऋण : नीति, क्रियाविधियाँ और कार्यकलाप छोट/कमजोर कृषकों के लिए विशेष प्रयत्न

315. कृषि संबंधी माँसमी कार्यकलापों तथा फसलों के विपणन के लिए राज्य सहकारी बैंकों के वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के संदर्भ में इस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण शर्त यह लगायी कि प्रत्येक केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गई ऋण सीमा का एक भाग आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों के वित्तीय सहायता देने के लिए अलग से रख दिया जाए। प्रारंभ में केंद्रीय सहकारी बैंकों को यह सलाह दी गई कि वे संबंधित राज्य सहकारी बैंकों से लिये गये उधारों की जो राशि 30 जून, 1971 को बकाया रहती है उसमें कम से कम 10 प्रतिशत को छोट/सामान्य या आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों को दिये जाने के लिए समितियों के नाम बकाया के रूप में दिखायें। जून, 1972 के अंत तक यह प्रतिशत 20 तक बढ़ा दिया जाएगा।

316. आन्ध्र प्रदेश के जन-जाति वर्गों के कृषि कार्यकलापों के सहायता देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा गिरिजन सहकारी निगम को मान्यता प्रदान की गई ताकि उसके माध्यम से उन तीन जिलों में जहाँ सामान्य सहकारी ऋण विन्यास जन-जाति वर्गों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के संदर्भ में या तो कमजोर या या अनिच्छुक था, जन-जाति वर्गों के कृषकों को कृषि ऋण प्रदान कराया जा सके। रिजर्व बैंक ने यह भी निश्चय किया कि जन-जाति वर्गों के सामान्य वन उत्पादों के विपणन के लिए वन विपणन सहकारी संस्थाओं को दिए गए अप्रमों के लिए राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की जाएं।

फसलों के विपणन के लिए पृथक् ऋण सीमाएं

317. ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने यह सिफारिश की, कि "कृषि संबंधी माँसमी कार्यकलापों" और "फसलों के विपणन" के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया पृथक् ऋण सीमाएं मंजूर कर सकता है। 1968-69 में रिजर्व बैंक रूई और कपास के विपणन के लिए पृथक् ऋण सीमाएं मंजूर करने की प्रणाली को प्रारंभ कर चुका था, अब यह निश्चय किया गया है कि 1971-72 से अन्य सभी फसलों के विपणन के लिए भी पृथक् ऋण सीमाएं मंजूर की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि कृषि संबंधी माँसमी कार्यकलापों के लिए निर्धारित ऋण सीमा का उपयोग फसलों के विपणन के वित्तपोषण के लिए न किया जाए।

रिजर्व बैंक द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता में प्रगति

318. कृषि ऋण की बढ़ती हुई मांग के साथ साथ कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता में

प्रति वर्ष कमशः वृद्धि होती आ रही है। कृषि संबंधी माँसमी कार्यकलापों तथा फसलों के विपणन के लिए बैंक दर से 2 प्रतिशत कम रियायती दर पर रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों के लिए मंजूर की गयी ऋण-सीमाओं की राशि जहाँ 1969-70 में 370.16 करोड़ रुपये थी वहाँ 1970-71 में बढ़कर 390.11 करोड़ रुपये हो गई। इस वर्ष आहीरित की गई कुल राशि 1969-70 के 425.09 करोड़ रुपयों के मुकाबले में 424.49 करोड़ रुपये थी। वापसी अदायगी की राशि 1969-70 के 394.06 करोड़ रुपयों के मुकाबले में इस वर्ष 449.76 करोड़ रुपये थी। इस संवर्ध में 30 जून, 1971 को 188.84 करोड़ रुपये बकाया थे जब कि 30 जून 1970 को 214.11 करोड़ रुपये बकाया थे (सारणी 39)। रूई और कपास के विपणन की वित्तीय सहायता के निमित्त राज्य सहकारी बैंकों के लिए मंजूर की गयी विशेष अल्पवाधि ऋण-सीमाएं 1970-71 के दौरान 10.65 करोड़ रुपये थी जब कि 1969-70 के दौरान 7.75 करोड़ रुपये थीं। इस संवर्ध में कुल आहीरित राशि 8.56 करोड़ रुपये, वापसी अदायगी की राशि 9.52 करोड़ रुपये तथा बकाया राशि 1.03 करोड़ रुपये थी, जब कि उक्त राशियाँ 1969-70 में क्रमशः 9.33 करोड़ रुपये, 8.24 करोड़ रुपये और 1.99 करोड़ रुपये थीं।

सारणी 39—कृषि संबंधी माँसमी कार्यकलापों तथा फसलों के विपणन के लिए रियायती ब्याज दर पर राज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए अल्पवाधि ऋण (1960-61 से 1970-71 तक)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मंजूर की गई ऋण सीमाएं	आहीरित राशि	बकाया राशि
1960-61	111.79	142.91	100.88
1961-62	138.18	154.22	115.20
1962-63	163.94	199.72	124.28
1963-64	186.21	298.18	146.54
1964-65	199.86	253.33	150.51
1965-66	212.06	260.36	143.67
1966-67	257.50	292.20	135.38
1967-68	314.15	364.89	137.17
1968-69	337.52	411.15	183.09
1969-70	370.16	425.09	214.11
1970-71	390.11	424.49	188.84

ऋणों के विषय जाने तथा उनकी वसूली का माँसमी आधार

319. ऋणों के दिए जाने तथा उनकी वसूली के माँसमी आधार के संबंध में वित्तीय नियमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने उन अवधिओं की सिफारिश की जब रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गयी अल्पवाधि ऋण सीमाओं से आहरण नहीं किए जा सकते। कृषि ऋण मंडल ने यह अनुभव किया कि केंद्रीय बैंकों को शिखर बैंक से जो ऋण प्राप्त होते हैं उनके बकाया स्तर को यदि वर्ष के किसी भाग के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर तक केंद्रीय बैंक कम कर दें तो ऋण के माँसमी आधार के सिद्धांत की पूर्ति हो सकती है; इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि केंद्रीय बैंकों के पास किसी भी समय अनुरोधित रूप से भारी अधिशेष विद्यमान नहीं रहते। केंद्रीय सहकारी बैंकों को जिन न्यूनतम सीमाओं तक अल्पवाधि ऋणों को कम करना होगा उन्हें रिजर्व बैंक तथा कुछ चुने हुए राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों के बीच हुए पारस्परिक विचार-विमर्शों के द्वारा निर्धारित किया गया। राज्यों के सहकारी विभागों के परामर्श के साथ राज्य सहकारी बैंकों से ऋण

गया है कि वे जिले की फसल प्रणाली आदि को स्थूल रूप से ध्यान में रखते हुए, अन्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए भी पारस्परिक सहमति के आधार पर इस प्रकार की ऋण सीमाओं का निर्धारण करें।

उर्वरकों के लिए वित्तीय सहायता

320. विश्वर विपणन समितियों का रासायनिक उर्वरक खरीदने, उनका स्टॉक करने और वितरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के निमित्त रिजर्व बैंक सरकारी गारंटी पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन बैंक दर पर सहकारी बैंकों का वित्त पोषण करता रहा। दिसम्बर, 1969 से उपयुक्त उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता देने के संबंध में केवल उन्हीं मामलों में विचार किया गया जहां राज्य सहकारी विपणन समितियाँ वाणिज्य बैंकों से आवश्यक निधि प्राप्त करने में असमर्थ रहें। 1970 के कैलेंडर वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों के लिए मंजूर की गई कुल ऋण सीमाओं में हुई कमी इसका कारण थी। 1970 के कैलेंडर वर्ष के दौरान मंजूर की गई ऋण सीमाएँ, आहरित ऋण-राशि तथा वर्ष के अंत में विद्यमान बकाया राशि क्रमशः 16.80 करोड़ रुपये, 11.27 करोड़ रुपये तथा 4.22 करोड़ रुपये थी। 1971 (जून के अंत तक) के तदनुसूची आंकड़े क्रमशः 19.25 करोड़ रुपये, 17.43 करोड़ रुपये तथा 3.43 करोड़ रुपये थे। इस संबंध में स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता रहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रिजर्व बैंक के यथाचित सहयोग के साथ वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा उर्वरकों के विपणन की ऋण संबंधी न्यायोचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है।

सहकारी चीनी कारखाने

321. चीनी के स्टॉकों के द्विष्टिबंधक रखने पर सहकारी चीनी के कारखानों की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज-दर पर एक राज्य सहकारी बैंक को दस सहकारी चीनी कारखानों के निमित्त 7.50 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण-सीमा प्रदान की गयी। कुल आहरित राशि 5.32 करोड़ रुपये थी और 30 जून, 1971 को बकाया राशि 4.32 करोड़ रुपये थी।

कृषि पुनर्वित्त निगम का ऋण

322. कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा खरीदे गए विशेष विकास डिर्बचरों की गारंटी पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ड) के अधीन, कृषि पुनर्वित्त निगम के लिए 1970-71 के लिए बैंक दर पर 8.00 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमा मंजूर की गई। ऋण सीमा पर कुल आहरित राशि 11.80 करोड़ रुपये तथा 30 जून, 1971 को विद्यमान बकाया राशि 7.52 करोड़ रुपये थी।

मध्यावधि वित्त

323. कृषि उद्देश्यों के लिए दिये जानेवाले मध्यावधि ऋणों के क्षेत्र में रिजर्व बैंक की नीति का उद्देश्य यह रहा कि कुओं का निर्माण, पम्पसेटों तथा कृषि साधनों का क्रय आदि सुस्पष्ट उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में किये गये कतिपय अध्ययनों से यह विदित हुआ कि अनेक केन्द्रीय बैंकों के द्वारा दिये गये मध्यावधि ऋणों का पर्याप्त अंश ऐसे उद्देश्यों के लिए दिया गया था जो सुस्पष्ट नहीं थे; अतः यह निश्चय किया गया कि 1970-71 में दी जानेवाली मध्यावधि ऋण-सीमाओं को इस प्रकार विनियमित कर दिया जाए कि ऋण निश्चित रूप से सुस्पष्ट उत्पादक उद्देश्यों के लिए ही प्राप्त हों। तदनुसार, रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त

करने के लिए एक केन्द्रीय बैंक को चाहिए कि वह अपने मध्यावधि ऋणों के कम से कम 40 प्रतिशत को निम्नीलिखित चार उद्देश्यों में से किसी एक अथवा अधिक के लिए प्रदान करे—(1) कुओं का निर्माण तथा अन्य सामान्य सिंचाई योजनाएँ, (2) कुओं तथा सिंचाई के अन्य स्त्रोतों की मरम्मतें, (3) पंपसेटों जैसी मशीनों की खरीद और (4) कृषि साधनों की खरीद। इस बात पर ध्यान देने के संबंध में सतर्कता बरती गई कि उन क्षेत्रों के लिए जहाँ भूमि विकास बैंकों ने कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता से योजनाएँ बनायी हैं, केन्द्रीय सहकारी बैंक लंबे-चौड़े कार्यक्रम न बनायें और मियादी ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में केन्द्रीय बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों के बीच उचित समन्वय हो।

दुग्ध पशुओं की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

324. रिजर्व बैंक ने 1966 में, ऐसे क्षेत्र में जहाँ सहकारी रूप में संगठित डेरी विकास प्रायोजना प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही हो, दुग्ध पशुओं की खरीद के लिए दी जानेवाली अपनी वित्तीय सहायता को दुग्ध पूर्ति समितियों के माध्यम से प्रदान कराने की योजना का अनुमोदन किया। ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार, दिसम्बर, 1970 में रिजर्व बैंक ने यह स्वीकार किया कि उक्त ऋण दुग्ध पूर्ति समितियों के द्वारा उनके अपने सदस्यों को दिये जाएँ, भले ही दुग्ध के निजीकरण, परिष्करण एवं विपणन तथा दूध के उत्पादों से संबंधित कार्य किसी निजी या सरकारी डेरी द्वारा किया जा रहा हो। इस उद्देश्य से कि छोटे कृषक कृषि के साथ-साथ डेरी उद्योग तथा मृगीपालन से सम्बन्धित कार्य भी कर सकें, जून 1971 में यह निश्चय किया गया कि अचल संपत्ति को गिरवी रखने या भूमि को बंधक रखने की शर्त लगायी बिना ही उन्हें 2,000 रुपये की सीमा तक मध्यावधि ऋण दिये जा सकते हैं।

मध्यावधि ऋण सीमाएँ

325. इस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 48क(2) (ख) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 17(4क) के अधीन बैंक दर से 1-1/2 प्रतिशत कम दर पर मंजूर की गई मध्यावधि ऋण सीमाओं की कुल राशि 17.55 करोड़ रुपये थी, जब कि पिछले वर्ष उक्त राशि 18.30 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, बैंक दर पर सहकारी चीनी कारखानों के शंयर खरीदने के निमित्त एक राज्य सहकारी बैंक के लिए कुल 1.21 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया। 1970-71 के दौरान उसमें से आहरित राशि (बैंक दर पर मंजूर की गई ऋण सीमाओं को मिलाकर) 14.20 करोड़ रुपये थी जबकि 1969-70 में यह राशि 11.48 करोड़ रुपये थी और 30 जून 1971 को बकाया राशि 24.31 करोड़ रुपये थी जब कि पिछले वर्ष के अंत में यह राशि 20.45 करोड़ रुपये थी। (सारणी 40)

सारणी 40—कृषि उद्देश्यों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को रियायती दर पर प्रदान किये गये मध्यावधि ऋण (1960-61 से 1970-71 तक)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मंजूर की गई ऋण सीमाएँ	आहरित राशि	बकाया राशि
1960-61	4.68	5.69	8.81
1961-62	9.56	7.39	11.67
1962-63	9.31	4.18	10.56
1963-64	14.01	7.45	13.00
1964-65	14.39	7.91	14.32
1965-66	14.11	7.45	14.96
1966-67	15.49	8.37	15.41
1967-68	16.57	9.12	16.47
1968-69	19.00	8.98	17.60
1969-70	18.30	11.48	20.45
1970-71	18.76	14.20	24.31

326. पहले की तरह 1970-71 के दौरान चार राज्य सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से बैंक दर से 1-1/2 प्रतिशत कम दर पर मंजूर की गयी मध्यावधि ऋण सीमाओं की कुल राशि 21.80 करोड़ रुपये थी, जिससे की वह प्राकृतिक विपत्तियों से उत्पन्न कीटनाशकों को पार करने के लिए अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदल सकें। इस वर्ष के दौरान निधि से आहीस्त कुल राशि 13.64 करोड़ रुपये थी और 30 जून 1971 को राज्य सहकारी बैंकों के पास विद्यमान बकाया राशि 13.86 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, दो राज्य सहकारी बैंकों के लिए उनके द्वारा अपनी स्थिरीकरण निधि में से जिन सरकारी/न्यासी प्रतिभूतियों में निवेश किये गये थे उन्हें बन्धक रखने पर बैंक-दर पर 7.00 करोड़ रुपयों की अल्पावधि ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं ताकि वे अपने क्षेत्रों के केंद्रीय सहकारी बैंकों को परिचर्तन सुविधाएँ प्रदान कर सकें। जून 1971 तक इन ऋण सीमाओं से आहीस्त राशि 4.18 करोड़ रुपये थी तथा 30 जून 1971 को विद्यमान बकाया राशि 2.50 करोड़ रुपये थी।

327. बुनकर समितियों के उत्पादन तथा विपणन संबंधी कार्य-कलापों का वित्त पोषण करने के लिए बैंक दर से 1-1/2 प्रतिशत कम ब्याज की रियायती दर पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(2) (खख) के अधीन रिजर्व बैंक ने सामान्य रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की। पिछले वर्ष निर्धारित नियमों तथा शर्तों के अनुसार, 22 'अनुमोचित' समूहों के अधीन आनेवाले अन्य कूटीर तथा लघु, उद्योग यूनिटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी राज्य सहकारी बैंकों को उसी धारा के अधीन पहली बार वित्तीय सहायता दी गयी। बुनकर समितियों के उत्पादन तथा विपणन संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण करने के लिए बैंक दर से 1-1/2 प्रतिशत कम दर पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 17(2) (खख) के अधीन, 11 राज्य सहकारी बैंकों के लिए 1970-71 के वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 10.12 करोड़ रुपयों की ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं जबकि 1969-70 में 8.18 करोड़ रुपयों की ऋण सीमाएँ मंजूर की गयी थीं। इस वर्ष उनमें से आहीस्त की गई राशि 12.36 करोड़ रुपये थी जब कि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि 9.49 करोड़ रुपये थी तथा 31 मार्च 1971 को 7.83 करोड़ रुपये बकाया थे जब कि पिछले वर्ष के अंत में 6.42 करोड़ रुपये बकाया थे। शिखर हथकरभा बुनकर समितियों के सूत व्यवसाय के वित्त पोषण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 17(2) (क) के अधीन, तीन राज्य सहकारी बैंकों के लिए 80.00 लाख रुपयों की ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं जब कि पिछले वर्ष मंजूर की गई ऋण सीमाओं की राशि 69.00 लाख रुपये थी। इस वर्ष उनमें से आहीस्त की गयी कुल राशि 4.00 लाख रुपये थी और 31 मार्च 1971 के अंत में बकाया राशि 2.93 लाख रुपये थी। अनुमोक्त कूटीर तथा लघु उद्योग यूनिटों को वित्तीय सहायता देने के लिए 4 केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा 8 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की और से पहली बार बैंक दर पर चार राज्य सहकारी बैंकों के लिए कुल 46.59 लाख रुपयों की ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं। इन ऋण सीमाओं से आहीस्त 1.95 लाख रुपयों की पूरी राशि 31 मार्च 1971 को बकाया थी।

शहरी सहकारी बैंक

328. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने शहरी ग्राहकों की बैंक व्यवसाय और ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उक्त ग्राहकों में सामान्यतः शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारी छोटे कारोबार करनेवाले, कारीगर, कारखानों के कामगार, वृत्तभागी व्यक्ति आदि आते हैं। उन बैंकों की ऋण नीतियों को पुन-

र्व्यवस्थित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को यह सलाह देते आ रहा था कि शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिपूर्ति आधार पर पुनर्वित्त दिया जाना चाहिए। उक्त पुनर्वित्त की मात्रा को उपभोग-स्थाय, वाणिज्य और व्यापार तथा लघु उद्योगों के लिए शहरी बैंकों द्वारा किये जानेवाले ऋणों और अप्रमों के क्रमशः 50 प्रतिशत, 66-2/3 प्रतिशत और 75 प्रतिशत तक सीमित करना था। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को मोटे तौर पर कूटीर उद्योगों और लघु उद्योगों के यूनिटों के 22 वर्गों के उत्पादन और विपणन संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण करने के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(2) (खख) या (4) (ग) के अधीन पुनर्वित्त-सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं। पहली बार 1970-71 के वित्तीय वर्ष में रिजर्व बैंक ने गुजरात और मणिपुर राज्य सहकारी बैंकों के लिए 8 प्राथमिक (शहरी) बैंकों की तरफ से कुल 42.45 लाख रुपयों की ऋण सीमाएँ मंजूर की थी। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से ऋण प्रदान करता रहा ताकि वे चयनात्मक आधार पर प्राथमिक (शहरी) बैंकों की शंकर पूंजी में अंशदान कर सकें। 1970-71 के वित्तीय वर्ष के दौरान 19 प्राथमिक (शहरी) बैंकों की शंकर पूंजी में अंशदान करने के लिए 10.30 लाख रुपयों की राशि मंजूर की गयी।

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से विशेष सहायता

329. सहकारी ऋण संस्थाओं की शंकर पूंजी में अंशदान करने के लिए राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से प्राप्त होनेवाली वित्तीय सहायता से संबंधित नियमों तथा शर्तों को आलोच्य वर्ष में उद्धार बना दिया गया। तदनुसार, पुनःस्थापन की योजना के अधीन रहनेवाले आर्थिक रूप से कमजोर केंद्रीय सहकारी बैंक अब अपनी चुकता पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक अंशदान प्राप्त करने के अधिकारी हैं भले ही प्राप्य कालातीत राशि का प्रतिशत 30 से अधिक किन्तु 50 से कम हो। कमजोर केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा छोटे कृषक विकास एसोसिएशंस/सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजनार्थ के क्षेत्रों में कार्य करनेवाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ 10,000 रुपयों के अंशदान के पात्र हैं चाहे कालातीत राशि का स्तर कूट भी क्यों न हो। 10,000 रुपयों से अधिक अंशदानों पर कालातीत राशि, उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण जारी किये जाने आदि से संबंधित शर्तें लागू होंगी। राज्य सरकारों के अंशदान के उद्देश्य के लिए यह भी पर्याप्त माना जाता है कि राज्य सरकारें सहकारी ऋण समितियों द्वारा लिये गये ऋणों के 10 प्रतिशत से अन्यून शंकरों के लिए प्रारंभिक स्तर पर अंशदान करें जब कि अब तक निर्धारित उपर्युक्त प्रतिशत 20 था।

दीर्घावधि वित्त

330. 1970-71 के वित्तीय वर्ष के दौरान, 6 राज्य सहकारी बैंकों, 105 केंद्रीय सहकारी बैंकों, 4,076 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, 8 केंद्रीय भूमि विकास बैंकों, 146 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों तथा 19 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की शंकर पूंजी में अंशदान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 46(क) (2) (क) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 17(4) (कक) के अधीन राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में से 14 राज्य सरकारों के लिए कुल 11.85 करोड़ रुपयों के ऋण (0.03 करोड़ रुपये की मात्रा तक पिछले वर्ष नवीकृत किये गये ऋणों को छोड़कर) मंजूर किये गये। इसके अलावा, 1969-70 के दौरान मंजूर की गयी 75.96 लाख रुपयों की राशि के आह्वन की अवधि को 1970-71 तक बढ़ा दिया गया। 1970-71 के वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा आहीस्त की गयी कुल राशि 12.49 करोड़ रुपये थी जबकि 1969-70 के दौरान उक्त राशि 6.80 करोड़ रुपये थी (सारणी 41)। इस संदर्भ

में 31 मार्च 1971 को राज्य सरकारों के नाम कुल 41.93 करोड़ रुपये बकाया थे जब कि 31 मार्च 1970 को 33.83 करोड़ रुपये बकाया थे।

दीर्घावधि ऋण देनेवाली सहाकारी संस्थाओं में सुधार लाने के लिए विशेष उपाय

331. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 1970-71 के लिए भूमि विकास बैंकों के 141.20 करोड़ रुपयों के सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम का उल्लेख किया गया था। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा की जानेवाली सहायता में कमी हो जाने के कारण उक्त डिबेंचर कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि को कम कर 139.20 करोड़ रुपये कर दिया गया। उपर्युक्त अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर 31 मार्च 1971 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान भूमि विकास बैंकों ने कुल 123.56 करोड़ रुपयों के डिबेंचर जारी किए। बैंकों द्वारा वास्तव में एकत्रित की गयी कुल अभिदान राशि 127 करोड़ रुपये थी। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने 36.62 करोड़ रुपयों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय जीवन बीमा निगम ने (रिजर्व बैंक की अभिदान राशि 4.16 करोड़ रुपये) 22.15 करोड़ रुपयों तथा वाणिज्य बैंकों ने 29.91 करोड़ रुपयों का अभिदान किया। अनुमोदित कार्यक्रम में जो कमी हुई वह अंशतः भूमि विकास बैंकों की संगठनात्मक त्रिफलताओं के कारण हुई और साथ ही, अंशतः ऋणों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल की प्रणाली में क्रमशः सुधार होने के कारण भी हुई, उक्त सुधार के कारण अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए अपेक्षित ऋणों की मात्रा को कम कर दिया गया था।

सारणी 41—सहाकारी ऋण संस्थाओं की शेषर पूंजी में अंशदान करने के लिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण—1960-61 से 1970-71 तक

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष*	नवीनकृत ऋणों को मिलकर मंजूर की गई ऋण सीमाएं	आवृत्त राशि
1960-61	3.23	2.75
1961-62	5.60	5.43
1962-63	4.94	4.91
1963-64	3.35	3.30
1964-65	4.38	4.18
1965-66	2.68	2.88
1966-67	2.47	2.27
1967-68	7.37	7.36
1968-69	4.13	3.78
1969-70	7.49	6.80
1970-71	11.88	12.49 @

* वित्तीय वर्ष

@ 1969-70 के दौरान मंजूर किये गये 75.96 लाख रुपयों के ऋणों को मिलकर जिनके आहरण की अवधि को बढ़ा दिया गया था।

332. 1971-72 के वित्तीय वर्ष के डिबेंचर कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए मार्च, 1971 में रिजर्व बैंक ने प्रमुख निवेशकों तथा केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक का

आयोजन किया। इस वर्ष के लिए 140 करोड़ रुपयों का डिबेंचर कार्यक्रम अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया। केन्द्रीय और राज्य सरकारों से इस डिबेंचर कार्यक्रम के लिए उपलब्ध होनेवाली सहायता की राशि 34 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी। यह आशा की गयी कि सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं से 27 करोड़ रुपये तथा वाणिज्य बैंकों से 30 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस बात का सुनिश्चय कर लेने के लिए कि विभिन्न सरकारी तथा संस्थागत स्रोतों से भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर कार्यक्रम को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हो, की गई व्यवस्थाओं को दृष्टि में रखते हुए, रिजर्व बैंक पिछले वर्षों की भांति उन उद्देश्यों पर बल देता रहा जिनके लिए भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने चाहिए। इसीलिए 1971-72 के लिए यह शर्त जारी रही कि प्रदान की जानेवाली ऋण राशि का कम से कम 90 प्रतिशत उत्पादक उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए और उस निर्धारित राशि का 70 प्रतिशत सुस्पष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित होना चाहिए।

333. 1969-70 से, केवल ऐसे भूमि विकास बैंक, जिनकी प्रारंभिक स्तर पर पिछले सहाकारी वर्ष के अंत में विकसित कालातीत राशि इस वर्ष की मांग राशि के 15 प्रतिशत से कम रही, डिबेंचर कार्यक्रम के अधीन प्रदान की जानेवाली वित्तीय सहायता के 100 प्रतिशत के पात्र थे। जिन बैंकों के मामले में ऋणों की वसूली उपर्युक्त स्तर तक नहीं पहुँची हो वे केवल कम वित्तीय सहायता पाने के ही योग्य हैं। उक्त सहायता में क्रमिक रूप से कमी की जाएगी। उक्त शर्त को लागू करने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि जिन भूमि विकास बैंकों के संदर्भ में प्राप्य कालातीत राशि की मात्रा अधिक हो उनके डिबेंचर कार्यक्रम के लिए पूरी सहायता प्रदान करने से यदि अस्वीकार कर दिया जाए तो उक्त बैंकों को कालातीत ऋणों की वसूली करने की उपर्युक्त कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

334. पिछले दो वर्षों के दौरान रिजर्व बैंक भूमि विकास बैंकों को इस बात की आवश्यकता के बारे में समझाने का प्रयत्न करता रहा है कि वे कृषि विकास के उद्देश्य के अनुरूप बनायी गयी परिचालनगत क्रियाविधियों और नीतियों को अपनाएँ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के द्वारा मंजूर की गयी कृषि ऋण प्रायोजनाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ कृषि पुनर्वित्त निगम तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा किये गये कारारों की शर्तों के कारण, अभी कुछ समय से इस बात की आवश्यकता आ पड़ी है कि ऋण देने के संबंध में भूमि विकास बैंक कुछ नियमों का तत्काल अनुपालन करें। तदनुसार, भूमि विकास बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऋण प्रदान करने के अपने सामान्य कार्य के संदर्भ में भी, प्रायोजना ऋणों के संबंध में प्रायोजना कारारों में निर्धारित शर्तों तथा क्रियाविधियों के समान या उनके अनुरूप शर्तों तथा क्रियाविधियों को ही अपनाएँ। भूमि विकास बैंकों के कार्य के दूसरे पहलुओं, विशेषकर साधन स्रोतों की व्यवस्था के संबंध में भी गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास जारी रखे गये।

335. ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने भूमि विकास बैंकों के द्वारा ग्रामीण डिबेंचरों के जारी किये जाने की नीति का पुनरीक्षण करते हुए यह सिफारिश की कि ग्रामीण डिबेंचर कार्यक्रम को सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम के 5 प्रतिशत से कम नहीं होना यह परामर्श दिया कि किसी भी राज्य में ग्रामीण डिबेंचर कार्यक्रम, सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम के 5 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त सिफारिश को कृषि ऋण मंडल ने सामान्य

रूप से स्वीकार किया और यह सुझाव दिया कि 1970-71 से इस सिफारिश को कार्यान्वित करने की दशा में प्रारंभिक कदम उठाया जा सकता है। इस सिफारिश के अनुसार विस्मर 1970 में भूमि विकास बैंकों को सलाह दी गई कि 1970-71 के दौरान व वर्ष के लिए अनुमोदित सामान्य ढिबेंचर कार्यक्रम के कम से कम 2½ प्रतिशत की कुल राशि के लिए ग्रामीण ढिबेंचरों की एक या अधिक श्रेणियों को जारी करें। 31 मार्च 1971 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, भूमि विकास बैंकों ने कुल 4.39 करोड़ रुपये की राशि के लिए ग्रामीण ढिबेंचर जारी किये, इन ढिबेंचरों में रिजर्व बैंक के अंशदान की राशि 0.18 करोड़ रुपये थी। ग्रामीण ढिबेंचरों में रिजर्व बैंक द्वारा किये गये नियंत्रणों की कुल राशि 31 मार्च 1971 को 8.59 करोड़ रुपये थी।

सहकारी बैंकों की संख्या

336. 30 जून 1971 को बैंक विनियम अधिनियम, 1949 के अधीन आनेवाले 1,315 सहकारी बैंक—29 राज्य, 366 केन्द्रीय तथा 920 प्राथमिक बैंक—ये जब कि वर्ष के प्रारंभ में 1317 सहकारी बैंक (28 राज्य, 366 केन्द्रीय और 923 प्राथमिक) थे। वर्ष के दौरान बैंकों की संख्या में जो कमी हुई उसका प्रधान कारण यह था कि प्राथमिक सहकारी बैंकों की सूचि से कतिपय कृष्यंतर ऋण समितियों को हटा दिया गया था।

337. रुई और कपास की जमानत पर, राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिये जानेवाले अग्रिमों पर नियंत्रण को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से, आलोच्य वर्ष में चयनात्मक नियंत्रण उपायों को लागू किया गया, जिनकी चर्चा पृष्ठ 94 पर की गई है।

कृषि पुनर्वित्त निगम

मंजूरीयां और वितरण

338. 1970-71 के दौरान, सिंचाई और भूमि विकास के व्यापक क्षेत्र से संबंधित 100 कृषि विकास योजनाओं @ के संदर्भ में निगम ने पुनर्वित्त की मंजूरी दी। इन योजनाओं की वित्तीय सहायता की कुल राशि 62.15 करोड़ रुपये थी। इन योजनाओं के अधीन निगम के वायदे की राशि 53.92 करोड़ रुपये थी।

339. आलोच्य वर्ष के दौरान मंजूर की गई 100 योजनाओं में से 67 योजनाएं केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के द्वारा कार्यान्वित की जानी चाहिए, उनके मामले में संबंधित बैंकों के द्वारा जारी किये जानेवाले विशेष विकास ढिबेंचरों में अंशदान के रूप में पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा। छः योजनाएं राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा तथा शेष 27 योजनाएं अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के द्वारा कार्यान्वित की जानी चाहिए, जिनके मामलों में पुनर्वित्त ऋण के रूप में दिया जाएगा।

340. आलोच्य वर्ष में, 100 योजनाएं मंजूर की गईं, जिनमें लघु सिंचाई कार्यों के विकास की योजनाएं, भूमि विकास की 9 योजनाएं, बागान और बागवानी की 26 योजनाएं और कृषि यंत्रिकरण की 1 योजना सम्मिलित थीं। शेष योजनाओं में से 2 योजनाएं मुर्गी पालन के विकास के लिए, 2 योजनाएं मछली पालन के उद्योग के विकास तथा के लिए, 3 योजनाएं डेरी

विकास के लिए तथा 2 योजनाएं गोदामों के निर्माण के लिए थीं।

341. इस वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय गतिविधि यह पायी गयी कि डेरी विकास की योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संदर्भ में काफी प्रगति हुई। इस वर्ष तीन डेरी योजनाएं मंजूर की गईं जिनमें डेरी उद्योग और कृषि को समन्वित कर कृषि संबंधी मिश्रित कार्य करने में लगे हुए कृषकों तथा सहकारी दुग्ध समितियों के व्यवसायिक कृष्यंतर दूध विक्रेताओं को दूधारू पशु खरीदने के लिए 142.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता सम्मिलित है। साथ ही, एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि यह भी थी कि पहली बार एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के द्वारा एक राज्य कृषि उद्योग निगम को निगम ने पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की थीं। अनुसूचित वाणिज्य बैंक से निधि प्राप्त कर भूमि को समतल बनाने के लिए कृषि उद्योग निगम कृषकों को सेवाएं प्रदान करेगा। बैंक द्वारा दी जाने वाली उक्त निधि के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम पुनर्वित्त प्रदान करेगा। इसी प्रकार, कृषि पुनर्वित्त निगम ने पहली बार छोटे कृषकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लघु सिंचाई योजनाओं का अनुमोदन किया—एक हरियाणा में अम्बाला जिले की नारायणगढ़ तहसील में हरियाणा लघु सिंचाई नलकूप निगम के द्वारा 170 गहरे नलकूपों के लिए 161.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की योजना थी और दूसरी योजना पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 300 कम गहरे नलकूपों को खोदने के लिए 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने से संबंधित थी। उक्त दोनों योजनाओं के क्षेत्र छोटे कृषकों की विकास एजेंसियों के अंतर्गत आते हैं जिनके लिए कृषि पुनर्वित्त निगम ने 100 प्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान किया है। ऐसी ही और अनेक योजनाओं पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। दो और राज्यों — मैसूर तथा हरियाणा में निगम कृषकों की गोदाम समस्या को भी हल करने में सफल हुआ; इस संदर्भ में निगम ने मैसूर और हरियाणा के लिए एक एक योजना मंजूर की जिसके अंतर्गत क्रमशः 71.10 लाख रुपये और 19.42 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजनाएं निगम के द्वारा पहले ही तीन राज्यों अर्थात् गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मंजूर की गई गोदाम योजनाओं के अतिरिक्त थीं। जो क्षेत्र और राज्य पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं उनमें अधिक से अधिक योजनाओं को लागू करने की दिशा में निगम ने विशेष प्रयत्न किये और इस संबंध में ऐसी योजनाएं तैयार करने के लिए निगम ने अपने अधिकारियों को भेजा है जो संबंधित वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकारों के द्वारा प्रवर्तित की जा सकती हैं। इस संबंध में निगम के अध्यक्ष ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किये जिनके संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई निगम के प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारियों द्वारा की गई। इन राज्यों में और अधिक योजनाओं का प्रवर्तन करने की दृष्टि से भारत सरकार के अधिकारियों और राज्य सरकारों तथा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष बैठकें हुईं।

@ मंजूर की गयी परंतु बाद में रद्द की गयी इन योजनाओं को छोड़कर।

342. इस वर्ष के दौरान, निगम ने पहले मंजूर की गई कुछ योजनाओं के संदर्भ में दी गयी वित्तीय सहायता में कटौती करने का अनुमोदन किया, साथ ही निगम ने कुछ योजनाओं को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए भी अपना अनुमोदन प्रदान किया ताकि विशेष विकास डिब्बों को जारी करने की अवधि बढ़ायी जा सके। यदि पिछले वर्षों के दौरान मंजूर की गई योजनाओं को पुनर्व्यवस्थित करने और रद्द कर देने आदि के परिणाम-स्वरूप पहले ही मंजूर की गई कुछ योजनाओं के परिव्यय में हुए परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाए तो आठ वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान निगम के द्वारा मंजूर की गई योजनाओं की कुल संख्या 30 जून 1971 को 458 रह जाती है। उन योजनाओं के अधीन प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता तथा निगम के वायव्य की राशि क्रमशः 293.00 करोड़ रुपये और 248.66 करोड़ रुपये होती है।

343. इस वर्ष के दौरान निगम के द्वारा वितरित की गयी राशि 30.62 करोड़ रुपये थी, इससे जून 1971 के अंत तक वितरित की गयी कुल राशि बढ़कर 89.71 करोड़ रुपये हो गई। इस वर्ष के दौरान वितरित की गई 30.62 करोड़ रुपयों की राशि में से, केंद्रीय भूमि विकास बैंकों को 26.65 करोड़ रुपये, राज्य सहकारी बैंकों को 1.19 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 2.78 करोड़ रुपये वितरित किये गये। इस वर्ष 8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और 5 राज्य सहकारी बैंकों ने क्रमशः 31.12 लाख रुपयों और 26.57 लाख रुपयों की मूल देय राशि लौटायी।

वित्तीय स्रोतों का बढ़ाना

344. इस वर्ष के दौरान, निगम ने निम्नलिखित प्रकार से वित्तीय स्रोतों को बढ़ाया—(1) कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम की धारा 20(1)(ग) के अधीन भारत सरकार से उधारों के रूप में 22 करोड़ रुपये, (2) 5ई प्रतिशत कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1982 (2 श्रेणियां) जारी कर खुले बाजार से लगभग 8.53 करोड़ रुपये। इसके अतिरिक्त, कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 20(1)(ख) के अधीन, इस अवधि के दौरान रिजर्व बैंक से निगम द्वारा लिये गये अल्पावधिक उधारों की कुल राशि 11.80 करोड़ रुपये थी जिसमें से 4.28 करोड़ रुपये अप्रैल 1971 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लौटा दिये गये।

नीतिगत और क्रियाविधियां

345. आलोच्य वर्ष में नीतियों तथा क्रियाविधियों से संबंधित निम्नलिखित परिवर्तन अमल में लाए गए : (क) 23 नवम्बर 1970 को या उसके बाद मंजूर की जानेवाली योजनाओं के संदर्भ में निगम ने अपने पुनर्वित्त पर लिये जानेवाले ब्याज की दर को बढ़ाकर वार्षिक 6ई प्रतिशत कर दिया है।

(ख) निगम के द्वारा मंजूर की गई लघु सिंचाई योजनाओं के संदर्भ में, केंद्रीय भूमि विकास बैंकों के द्वारा जारी किये जानेवाली विशेष विकास डिब्बों में राज्य सरकारों से प्रदान से किये जानेवाले 10 प्रतिशत अंशदान की विशेष रियायत को 30 जून 1972 तक बढ़ा दिया गया।

(ग) निगम ने विशेष रूप से यह निश्चय किया कि वह योग्य संस्थाओं के माध्यम से लघु कृषक विकास एजेंसियों के द्वारा प्रवर्तित और अपने द्वारा मंजूर की गयी सक्षम योजनाओं के संदर्भ में 30 जून 1971 तक प्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करेगा। प्रारंभ में यह रियायत केवल एक वर्ष के लिए प्रदान की गयी थी और अब उसे 30 जून 1972 तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) 14 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ये बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा उसके सहायक बैंक कृषि विकास कार्यों के लिए काफी अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करते आ रहे हैं। वाणिज्य बैंकों को वित्त जानेवाली पुनर्वित्त की मात्रा के संबंध में निगम एक लचीली नीति का पालन कर रहा है। ऐसे बैंकों के खल मुद्रा स्रोतों की स्थिति का ध्यान में रखते हुए निगम उन्हें पुनर्वित्त प्रदान करता है। इस वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान किये जाने की क्रियाविधि के सरलीकरण के लिए निगम ने अनेक कदम उठाये।

346. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा उससे संबंध संस्था अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने कृषि का आधुनिकीकरण तथा उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए किये जानेवाले पूंजीगत निवेशों के संदर्भ में वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से तीन प्रयोजनाओं को मंजूर किया था। आलोच्य वर्ष में, चार और प्रयोजनाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, भारत सरकार तथा निगम के बीच किये गये करारों पर हस्ताक्षर हुए जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 67.80 करोड़ रुपयों (904.00 लाख डालर) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा; इसमें से 61.67 करोड़ रुपये निगम के द्वारा निम्न प्रकार उपलब्ध कराये जाएंगे :

कृषि पुनर्वित्त निगम के द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि (करोड़ रुपयों में)	
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण	
हरियाणा कृषि ऋण प्रायोजना . 250 लाख डालर	18.75
	18.75 करोड़ रुपये
तमिलनाडु कृषि ऋण प्रायोजना . 350 लाख डालर	22.35
	26.25 करोड़ रुपये
आंध्र प्रदेश कृषि ऋण प्रायोजना . 244.00 लाख डालर	18.09
	18.30 करोड़ रुपये
कृषि संबंधी हवाई प्रायोजना . 60.00 लाख डालर	2.48
	4.50 करोड़ रुपये

इन प्रयोजनाओं के कार्यान्वयन में पुनर्वित्त प्रदान करने वाली एकमात्र एजेंसी के रूप में और साथ ही एक ऐसी एजेंसी के रूप में जिसने तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं की दृष्टि से आंतरिक रूप से योजनाओं में निहित क्षमता के संबंध में अपने को स्वयं संतुष्ट कर लेना चाहिए, निगम सक्रिय रूप से संबंधित है। इस वर्ष के दौरान निगम का कानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को स्थानान्तरित कर दिया गया।

5. विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी गतिविधियां

मारिशस यात्रा योजना, 1970

347. विदेशी मुद्रा नियंत्रण के अंतर्गत पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यात्रा संबंधी नियमों के उद्गारीकरण की जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था उसे आलोच्य वर्ष में भी जारी रखा गया। 7 अगस्त 1970 से अमल में लायी गयी मारिशस यात्रा योजना 1970 के अधीन, तीन वर्षों में एक बार मारिशस की यात्रा करने के लिए भारत में निवास करनेवाले किसी भी व्यक्ति के लिए हवाई/जहाज रानी कंपनियों और यात्रा एजेंटों के द्वारा यात्रा टिकट बुक किये जा सकते हैं। एयर इंडिया द्वारा मारिशस की यात्रा करनेवाले ऐसे व्यक्ति 100 अमीरिकी डालरों की विदेशी मुद्रा

प्राप्त करने के पात्र होंगे। कारोबार या अन्य किसी उद्देश्य से या रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त 'पी' फार्म अनुमोदन के अधीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गयी विदेशी मुद्रा के साथ की गयी किसी भी मारिशस यात्रा पर इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा और विदेशी यात्रा योजना, 1970 के अधीन की गयी मारिशस से हटकर देशों की यात्रा के कारण कोई भी व्यक्ति मारिशस यात्रा योजना का लाभ उठाने से वंचित नहीं होगा। इसी प्रकार यदि अन्यथा अनुमत हो तो मारिशस यात्रा योजना, 1970 के अधीन की गयी मारिशस यात्रा के कारण भी कोई व्यक्ति विदेशी यात्रा योजना, 1970 से लाभान्वित होने से वंचित नहीं होगा।

100 अमेरिकी डालरों की विदेशी मुद्रा की हकदारी

348. एयर इंडिया/भारतीय जहाजरानी निगम के वायुयानों/जहाजों से यात्रा करनेवाले यात्रियों को प्राप्य 100 अमेरिकी डालरों की विदेशी मुद्रा की सुविधा को निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए भी लागू कर दिया है :—

(क) विदेश यात्रा योजना, 1970 के अधीन अन्य देशों की यात्रा के लिए किसी दूसरे टिकट की आवश्यकता के बिना ही परिभ्रमण टिकटों पर इंडियन एयर लाइन्स के वायुयान के द्वारा यात्रा करनेवाले ऐसे व्यक्ति जो अफगानिस्तान या बर्मा की यात्रा करने के लिए उक्त योजना की सुविधा से लाभान्वित होने के पात्र हैं, और

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनके पास वि सिंविथा स्टीम नेवीगेशन कंपनी लिमिटेड के जहाजों से यात्रा करने के लिए विदेशी यात्रा योजना, 1970 के अधीन जारी किये गये अप्रुपंकनीय परिभ्रमण टिकट हों।

विदेशी मुद्रा नोटों और सिक्कों की बिक्री

349. मार्च, 1971 तक हवाई अड्डों और गोदी में कारोबार करनेवाले प्राधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापारियों और लाइसेंसीकृत मुद्रा परिवर्तकों के मुद्रा विनिमय कार्यालयों को यह अनुमति दी गई थी कि वे निर्धारित सीमाओं और क्रियाविधिक औपचारिकताओं की शर्त पर निम्नलिखित यात्रियों को छोड़कर भारत से बाहर जानेवाले अन्य यात्रियों को विदेशी मुद्रा नोट और सिक्के बेंचें।

(क) पारगमन यात्री, और

(ख) ऐसे यात्री जिनके पास भारत के बाहर अनिश्चित अवधि के लिए जारी किये गये टिकट (वापसी टिकटों के मिलाकर) हों।

उपयुक्त (क) और (ख) की वर्जित श्रेणियों के अधीन आनेवाले यात्रियों को मिलाकर भारतीय नागरिकतायुक्त सभी यात्रियों के लिए इस सुविधा को 23 मार्च 1971 से बढ़ा दिया गया है। दूसरे शब्दों में, एक ऐसे यात्री को जो भारत का नागरिक हो (अर्थात्, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारतीय पारपत्र हो चाहे वह भारत में या विदेशों में जारी किया गया हो), इस बात पर विचार किये बिना कि किस मुद्रा में उसके टिकट का किराया अदा किया गया और किस स्थान पर टिकट जारी किया गया, विदेशी मुद्रा नोटों और सिक्कों की बिक्री की जा सकती है।

पूर्व बंगाल के शरणार्थियों की वित्तीय सहायता

350. पूर्व बंगाल से आनेवाले शरणार्थियों को सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से, विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों को यह अनुमति दी गई है कि वे सामान्य रूप से गैर रिहायशियों पर लागू होनेवाली विदेशी मुद्रा-निबंधन संबंधी औपचारिकताओं के बिना मुक्त रूप से उन व्यक्तियों के नाम जो पूर्व बंगाल से आए हैं और अस्थायी रूप से भारत के निवासी हैं, चालू/बचत/सावधि जमा लेखे खोलें।

इन लेखों को रिहायशी लेखों के रूप में माना जाएगा और इन लेखों का परिचालन अबाध रूप से किया जा सकता है।

प्राधिकृत व्यापारी लाइसेंस जारी करना

351. वंश के विदेशी मुद्रा कारोबार में भाग लेने के लिए छोटे बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, हाल ही में विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए निम्न बैंकों को लाइसेंस दिये गये हैं :— बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड, वाराणसी, विन्ध्य बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, और विजया बैंक लिमिटेड, बंगलूर।

352. जून 1971 के समाप्त हुए वर्ष के दौरान दी गयी विदेशी मुद्रा से संबंधित ओकड़ तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशों में यात्रा करने के निमित्त अनुमोदित किये गये 'पी' फार्म संबंधी आवेदन पत्रों की संख्या के विवरण आगे की सारणी में दिये गये हैं।

विदेशी मुद्रा परमिट और 'पी' फार्म अनुमोदन

1. विदेशी मुद्रा परमिट

यात्रा का उद्देश्य	परमितों की संख्या	विदेशी मुद्रा की मंजूर की गई राशि (हजार रुपये में)
अध्ययन/प्रशिक्षण		
(क) ब्रिटेन और यूरोप		
(i) तकनीकी	501	35,18
(ii) गैर-तकनीकी	625	28,45
(ख) अमेरिका और कनाडा		
(i) तकनीकी	2,366	5,78,38
(ii) गैर-तकनीकी	1,182	2,58,44
(ग) अन्य देश		
(i) तकनीकी	194	17,99
(ii) गैर-तकनीकी	120	6,63
कारोबार	10,892	6,58,72
डाक्टरी चिकित्सा	499	52,03
अध्ययन यात्रा	850	33,43
सम्मेलनों में भाग लेना	1,129	20,37
विविध	8,360	2,14,65
जोड़	26,718	19,04,27

2. 'पी' फार्म

यात्रा का उद्देश्य	मंजूर किये गये 'पी' फार्मों की संख्या
परिवार के प्रमुख से मिलना	11,838
रिश्तेदारों से मिलना	8,797
निर्यात वृद्धि	196
विदेशों में नौकरी	4,352
स्थायी निवास के लिए उपरवास	7,916
विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी	3,256
विविध	19,741
जोड़	56,096

6 रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित सर्वेक्षण और विशार ग्रीष्म

353. भारत सरकार के प्रयत्न से, शहरी क्षेत्रों में श्रमंतर कर्मचारियों के परिवारों की कर्जदारी की मात्रा, स्वरूप तथा विन्यास संबंधी विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण का प्रवर्तन किया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने 1970-71 के दौरान अपनी 25वीं पारी में लगभग 9,000 शहरी खंडों में उपयुक्त कार्यक्रम का प्रचार करने का क्षेत्रीय कार्य किया।

354. भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा राज्य सरकारों के सहयोग के साथ रिजर्व बैंक वार्षिक 'अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण, 1971-72' का आयोजन करने की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है।

355. 1501 गैर-सरकारी, वित्तर मन्त्राली और बड़ी सार्वजनिक सीमित कंपनियों के 1967-68 के लेखों के विश्लेषण के आधार पर सांख्यिकी विभाग ने आर्थिक विभाग के सहयोग से एक अध्ययन किया और उसे रिजर्व बैंक बुलेटिन के अक्टूबर 1970 के अंक में प्रकाशित किया। जनवरी-जून 1970 की अवधि से संबंधित औद्योगिक स्थिति का सर्वेक्षण रिजर्व बैंक बुलेटिन के जनवरी 1971 के अंक में प्रकाशित किया गया।

356. रिजर्व बैंक के ऋण आयोजना कक्ष में जुलाई 1969 सितम्बर 1970 तक की अवधि में वाणिज्य बैंकों द्वारा किये गये शाखा विस्तार कार्यों और नयी शाखाओं द्वारा किये गये कार्य के स्वरूप के संबंध में विशेष अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से पता चला कि वाणिज्य बैंक व्यवसाय के विशेष और कार्य संबंधी विस्तार की दिशा में जुलाई, 1969 में 14 बड़े वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद उल्लेखनीय प्रगति हुई है। रिजर्व बैंक बुलेटिन के नवंबर 1970 के अंक में इस अध्ययन के निष्कर्ष परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किये गये। रिजर्व बैंक द्वारा एक विशेष पुस्तिका प्रकाशित की गई जिसमें निम्नलिखित बातों का विवरण दिया गया— (1) बैंकों की विशेष ऋण योजनाएं : मार्गदर्शी सिद्धान्त, (2) संभाव्य नियोजन-क्षमता के संदर्भ में बैंकों की ऋण योजनाओं पर समीति की रिपोर्ट, (3) अप्रत्याशित और उपेक्षित क्षेत्रों को दिये जानेवाले छोटे ऋणों के लिए गारंटी योजनाएं, (4) लघु उद्योगों को दिये जानेवाले ऋणों के लिए गारंटी योजनाएं, (5) वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि का वित्त पोषण : मार्गदर्शी सिद्धान्त। रिजर्व बैंक बुलेटिन के फरवरी 1971 के अंक में यह पुस्तिका भी एक परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित की गयी। विभेदक व्याज दरों से संबंधित समीति की रिपोर्ट भी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गयी है।

357. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि आर्थिक विभाग के अंतराष्ट्रीय वित्त प्रभाग द्वारा प्रारंभ किये गये अवगीकृत प्राप्ति (अर्थात्, वे प्राप्ति) जिनकी राशि 10,000 रुपये से कम या उनके बराबर हैं और जिनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग को उद्देश्यवार विवरण भेजें) से संबंधित कार्य को बराबर आगे भी जारी रखने का निश्चय किया गया है। अक्टूबर-नवंबर 1969 की तिमाही के दौरान प्राप्त हुई अवगीकृत राशियों के संबंध में किये गये सर्वेक्षण के परिणाम रिजर्व बैंक बुलेटिन के मार्च, 1971 के अंक में प्रकाशित किये गये। 1970 के लिए किये गये सर्वेक्षण में जुलाई-सितंबर की तिमाही की अवधि ली गयी और इससे परिणामों का अब अध्ययन किया जा रहा है। 1971 के सर्वेक्षण में अप्रैल-जून की तिमाही अवधि आती है और उक्त सर्वेक्षण प्रगति कर रहा है। अन्तरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग भारतीय और विदेशी जहाजरानी तथा हवाई कंपनियों से संबंधित माल-भाड़े

और यात्रा किराये के भुगतान और प्राप्ति का सर्वेक्षण वार्षिक आधार पर बराबर करता रहा। यह प्रभाग विदेशी निवेश का सर्वेक्षण करने के लिए विदेशी कंपनियों और भारतीय मिश्रित पूंजी कंपनियों की शाखाओं से तिमाही रिपोर्टें भी मांगता रहा। मूलतः इन रिपोर्टों पर आधारित "1967-68 में भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति" शीर्षक एक लेख, रिजर्व बैंक बुलेटिन के मार्च 1971 के अंक में प्रकाशित किया गया। 1967-68 के अंत में भारत के अन्तराष्ट्रीय निवेश की जो स्थिति रही उसे प्रस्तुत करने के अलावा, उक्त लेख में आंशिक आंकड़ों के आधार पर 1968-69 के अंत में विद्यमान स्थिति पर स्थूल रूप से अनुमान प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, विदेशी निवेश सर्वेक्षण रिपोर्टों से प्राप्त अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, इस अध्ययन के द्वारा देश के समग्र भुगतान शेष के समायोजित आंकड़े प्रस्तुत किये गये।

358. कृषि ऋण विभाग के प्रयत्न से, आर्थिक विभाग के ग्रामीण सर्वेक्षण प्रभाग ने पांच राज्यों के पांच चुने हुए जिलों में कृषकों की बचत क्षमता का क्षेत्रीय अध्ययन कार्य प्रारंभ किया। उक्त अध्ययन का उद्देश्य यह था कि चुने हुए जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले कृषकों की बचत क्षमता का अनुमान लगाने का प्रयास किया जाए और यह पता लगाया जाए कि कैसे और किस मात्रा तक सांस्थानिक एजेंसियां जमा करने की ऐसी क्षमता का उपयोग कर रही हैं। इस प्रभाग ने कृषि ऋण विभाग के साथ मिल कर पांच राज्यों के पांच जिलों में "भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋणों को वापस अदा करने की क्षमता का निर्धारण करने और उन ऋणों से संबंधित बंधकों का मूल्यांकन करने" के लिए भी एक दूसरा अध्ययन कार्य किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह था कि एक ऐसी उपयुक्त कार्यपद्धति बनायी जाए जिससे कि भूमि विकास बैंक इस उद्देश्य से क्षेत्रीय अध्ययन कर सकें कि वे जमानत पर आधारित अपनी ऋण-नीतियों में परिवर्तन कर उन्हें उत्पादन पर आधारित बना सकें। साथ ही, भूमि विकास बैंकों द्वारा बंधकों के मूल्यांकन के संदर्भ में अपनाई जानेवाली प्रणालियों का भी अध्ययन करने की आवश्यकता थी, क्योंकि मूल्यांकन की वर्तमान प्रणालियां न तो संतोषप्रद थीं और न वैज्ञानिक ही और अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समीति के सुझाव के अनुसार उक्त प्रणालियों के स्थान पर आय की पूंजीकरण प्रणाली को अमल में लाने की भी आवश्यकता थी। इसके अलावा इस प्रभाग ने छंदे कृषकों के लिए सहकारी ऋणों की उपलब्धता से संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन की रिपोर्ट को भी अंतिम रूप दिया। यह अध्ययन आठ राज्यों में से आठ चुने हुए जिलों में किया गया। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे : (क) छंदे कृषकों को उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए सहकारी समीतियों से उपलब्ध ऋण का मूल्यांकन करना, (ख) ऐसे ऋणों की उपलब्धता को प्रभावित करनेवाले प्रमुख तत्वों का मूल्यांकन करना और (ग) इस बात का परीक्षण करना कि क्या सहकारी समीतियों में कोई निहित स्वार्थ विद्यमान है, यदि ऐसा है तो क्या उससे छंदे कृषकों को ऋण मिलने में कोई बाधा पड़ती है।

359. इन तत्त्व सर्वेक्षणों के अलावा, प्रभाग अपेक्षाकृत वीर्य-कालीन दो सर्वेक्षणों में लगा रहा। उनमें से एक सर्वेक्षण का उद्देश्य इस बात का अध्ययन करना था कि किस सीमा तक सहकारी ऋण कृषि उत्पादन में अपना योग दे रहा है, और उधारकर्ताओं को उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायता दे रहा है तथा दूसरे सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के विभिन्न कृषिगत आर्थिक परिवेशों के संदर्भ में छंदे कृषकों की ऋण समस्याओं तथा तत्संबंधी अन्य समस्याओं का अध्ययन करना था। सहकारी बैंकों द्वारा दिये जानेवाले अभिमत तथा जमा राशियों के संबंध में नियमित रूप से प्रश्नावली भेजकर जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे जारी रखा गया।

प्रभाग ने "कृषि ऋण का अध्ययन" शीर्षक का एक प्रकाशन भी प्रस्तुत किया।

360. आर्थिक विभाग के राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग के द्वारा 1965-66 और 1966-67 के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के वित्त संबंधी जो सर्वेक्षण किये गये उनके निष्कर्ष रिजर्व बैंक बुलेटिन के सितंबर 1970 के अंक में प्रकाशित किये गये, 1967-68 और 1968-69 के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के वित्त संबंधी सर्वेक्षण के लिए प्राप्त ऑकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है। 31 मार्च 1969 तक की केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्रतीभूतियों के स्वामित्व का वार्षिक सर्वेक्षण रिजर्व बैंक बुलेटिन के मई 1971 के अंक में प्रकाशित किया गया, 31 मार्च 1970 तक के सर्वेक्षण के लिए प्राप्त ऑकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है।

7. शिक्षा और प्रशिक्षण

361. इस वर्ष के दौरान अलग अलग बैंकों को उनकी अपनी परिचालन क्षमता तथा कार्य को सुधारने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान द्वारा प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श-संवाओं के संदर्भ में किये गये प्रमुख कार्यक्रमों के विवरण नीचे दिये जाते हैं।

पाठ्यक्रम

362. 1970 के दौरान, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाये : (1) बैंकों के लगभग 1500 बैंक अधिकारियों के लिए कृषि वित्त पर एक-समान साप्ताहिक क्षेत्रीय कार्यशिविर तथा प्रशिक्षण के पाँच कार्यक्रम, (2) लघु उद्योग के वित्त पोषण के संबंध में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए लघु उद्योग वित्त संबंधी पाठ्यक्रम, (3) एक समय में मूलतः एक बैंक के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, 1970 में बैंक आफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, (4) कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों के निमित्त शाखा प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, (5) कार्यपालक विकास कार्यक्रम जिसमें निम्नलिखित शामिल थे : (क) क्षेत्रीय प्रबंधक के स्तर के व्यक्तियों के लिए वरिष्ठ कार्यपालक पाठ्यक्रम और (ख) उप महा प्रबंधक/सहायक महा प्रबंधक के स्तर के व्यक्तियों के लिए उत्तमतर प्रबंध संबंधी विचार गोष्ठी, (6) परिचालन प्रबंध कार्यक्रम—प्रत्येक बैंक में से दो दो व्यक्तियों के हिसाब से 28 व्यक्तियों के लिए दो सप्ताह का एक श्रमशक्ति विकास कार्यक्रम, (7) वाणिज्य बैंकों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, निर्यात ऋण और गारंटी निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम तथा विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए निर्यात वित्त पर क्षेत्रगत प्रबंध कार्यक्रम, (8) पूर्वी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में चलाए गये प्रशिक्षण प्रबंध कार्यक्रम जिनमें यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड कर्माश्रित बैंक तथा इलाहाबाद बैंक के शिक्षकों ने भाग लिया था, (9) मलेशिया में राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान के संकाय के सदस्यों में से एक सदस्य के द्वारा बैंक ऑफ भूमि-पुत्रा, मलयेशिया की प्रार्थना पर चलाया गया कृषि वित्त संबंधी समुद्रपारीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

अनुसंधान

363. इस उद्देश्य से कि समस्याओं की अच्छी जानकारी हो और व्यावहारिक कठिनाइयों को सुलझाया जाए, संस्थान ने बैंक व्यवसाय के निम्नलिखित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान प्रार्थना-जनाओं का प्रारम्भ किया : परिवेशगत और प्रबंध संबंधी अध्ययन, ऋण तथा ऋण क्षेत्र का प्रबंध, जमाराशियाँ जुटाना, ऋण अनुसंधान विश्लेषण, निर्यात क्षमता का विकास, समेकित सूचना तथा नियंत्रण प्रणाली, प्रबंध नियंत्रण प्रणाली, श्रमशक्ति का पूर्वी-मुमान, औद्योगिक संबंध और सूचना, भर्ती आदि।

कार्यशिविर

364. दिसंबर 1970 के अंत में वाणिज्य बैंकों के कर्मचारी विभाग के कार्यपालकों के लिए 'भर्ती तथा चयन' पर एक कार्य-शिविर का आयोजन किया गया। 1971 के बीच में 'कारोबार-आयोजना' पर चलाये जाने-वाले एक उत्तम स्तरीय कार्यशिविर के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया है।

शिक्षण सामग्री

365. अधिक उपयुक्त प्रशिक्षण प्रणाली तैयार करने की दृष्टि से बैंकों के कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों के कुछ शिक्षकों की सहायता से राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान निम्नलिखित विषयों पर नियमित अध्ययन सामग्री तैयार कर रहा है—(1) प्रेषण, (2) सुरक्षा तिजोरी कक्ष, और संस्थान निम्नलिखित विषयों पर भी कार्य कर रहा है—(3) चेकों की जांच पड़ताल (4) जमा लेखे और (5) वसूली। संस्थान ने यह योजना बनाई है कि बैंक संघटन में बार बार किये जाने-वाले कार्यकलापों के लिए अनेक प्रकार के उपयोगी स्वयं शिक्षक पाठ तैयार करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया जाए। साथ ही इस वर्ष के दौरान आयोजित किये गये वरिष्ठ प्रबंध पाठ्यक्रमों के उपयोग के लिए, अहमदाबाद के भारतीय प्रबंध संस्थान ने शिक्षण संबंधी बहुत से वृत्त विवरण तैयार किये। राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने भी स्वयं अनेक वृत्त-विवरण एकत्रित किये। इनके अतिरिक्त, कारोबार संबंधी बहुत से मनोविनोदपूर्ण कार्यक्रम तथा अनुकरणात्मक अभ्यास भी तैयार किये गये हैं।

प्रकाशन और सूचना का प्रचारण

366. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने निम्नलिखित विषयों पर अपने द्वारा आयोजित 'कार्य शिविरों' से संबंधित रिपोर्टें प्रकाशित कीं : (1) लघु उद्योगों का वित्तपोषण, (2) कृषि का वित्तपोषण, (3) जमाराशि जुटाना, (4) ग्राहक सेवा, (5) बैंक व्यवसाय में प्रबंध विकास और (6) निर्यातों का वित्तपोषण। राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान के दो और प्रकाशन भी निकले : (1) वाणिज्य बैंकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा समिति और (2) पाठ्यक्रमों की निर्देशिका, 1970-71, जिसमें विभिन्न वाणिज्य बैंकों के कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों तथा अन्य अनुसंधान और प्रबंध संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के व्यौरे दिये गये हैं।

परामर्श

367. संस्थान ने बैंक आफ इंडिया, इंडियन बैंक, आन्ध्र बैंक और इंडियन ओवर्सीज बैंक को नये प्रकार की परीक्षा प्रक्रियाओं का प्रयोग कर नियुक्ति के लिए सीधे कर्मचारियों का चयन करने के संदर्भ में परामर्श संवाएँ प्रदान कीं। साथ ही यह संस्थान व्यापार विकास परामर्श सेवा के संदर्भ में आंध्र बैंक और इंडियन बैंक के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इस परामर्श सेवा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं : (1) तीन से पाँच वर्षों की अवधि के लिए व्यापार विकास योजना, (2) बैंक के बदलते हुए स्वरूप के अनुरूप उसके संगठनात्मक तंत्र का निर्माण और (3) भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रमशक्ति आयोजन और प्रबंध विकास जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है। संस्थान ने यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उनके अपने प्रबंध विकास कार्यक्रमों के निरूपण और कार्यान्वयन में सहायता देने की भी सहमति दी है। निम्नलिखित कार्यों में पर्याप्त प्रगति हुई है : (1) कर्मचारी-वर्ग सूची का निर्माण, (2) मूल्यांकन प्रणाली की दिशा में कार्य निरूपण और (3) श्रमशक्ति आयोजन। ये दोनों बैंक अन्य बैंकों को यह सूचना उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गये हैं।

सामान्य

368. 1969 तथा 1970 में किये गये कार्य के आधार पर, 1971 के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने निम्नीलिखित विषयों पर एक व्यापक कार्यक्रम करने का विचार किया है—(1) बैंक व्यवसाय के उत्तम कर्मचारी-वर्ग का प्रशिक्षण, (2) प्रशिक्षण तथा शिक्षण की नयी सामग्री, विशेष रूप से स्वयं शिक्षक पाठ तैयार करना, (3) बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण अनुसंधान प्रयोजनाएँ, और (4) विस्तृत परामर्श सेवाएँ, विशेष रूप से भूतर्फी, और चयन-परीक्षा, ऋण संबंधी जोखिम के विश्लेषण और कारोबार के विकास के क्षेत्रों में परामर्श सेवाएँ।

बैंक प्रशिक्षण कालेज

369. रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रवर्तन और आयोजन करता रहा। आलोच्य वर्ष में, कालेज ने 4 प्रवर पाठ्यक्रमों, 3 मध्यवर्ती पाठ्यक्रमों और औद्योगिक वित्त व्यवस्था तथा संगठन एवं प्रणाली से संबंधित दो दो पाठ्यक्रम तथा विदेशी मुद्रा, कर्मचारी वर्ग और संगठन से संबंधित एक एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया। वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षी निरीक्षण कर्मचारी वर्ग के लिए भी एक पाठ्यक्रम चलाया गया। आलोच्य वर्ष में कालेज में निम्नीलिखित दो नये पाठ्यक्रम शुरू किये गये : मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं और मीयादी ऋण संबंधी प्रस्तावों पर कार्य करनेवाले बैंकों के विधि अधिकारियों के लिए एक पाठ्यक्रम और अपेक्षाकृत बड़ी राशियों के ऋण संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन करनेवाले वाणिज्य बैंकों के मध्यम प्रबंध स्तर के अधिकारियों के लिए एक ऋण मूल्यांकन पाठ्यक्रम। इस अवधि में इस कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों की कुल संख्या 477 थी (इनमें विदेशों के तीन अधिकारी भी शामिल हैं)। 1954 में जब इस कालेज की स्थापना की गयी तब से लेकर अब तक कुल 4,447 अधिकारियों ने कालेज द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं के अधिकारियों और वाणिज्य बैंकों के ऐसे अधिकारियों के लिए जो मीयादी ऋण प्रदान करने संबंधित कार्य करते हैं, कालेज शीघ्र ही एक प्रयोजना मूल्यांकन (वित्तीय) पाठ्यक्रम तथा बाजार-विश्लेषण तथा मांग निरूपण से संबंधित एक पाठ्यक्रम आयोजित करने का विचार कर रहा है। हाल ही में, रिजर्व बैंक के अपने अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन करने का कार्य भी कालेज का सौंपा गया है। आलोच्य वर्ष में, बैंक परिचालन तथा विकास विभाग के अधिकारियों के लिए एक निरीक्षण प्रथम केन्द्रीय बैंक संघटन पाठ्यक्रम 1 चलाये गये। इस समय प्रथम केन्द्रीय बैंक संघटन पाठ्यक्रम 1 चलाये गये। इस समय कालेज में, द्वितीय केन्द्रीय बैंक संघटन पाठ्यक्रम 1 चल रहा है।

सहकारी बैंक प्रशिक्षण कालेज, पूना

370. राज्य, केन्द्रीय और शहरी सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों के कर्मचारियों के लिए रिजर्व बैंक सहकारी बैंक व्यवसाय के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता रहा। आलोच्य वर्ष में राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों के प्रबंधक वर्ग के लिए और राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखा प्रबंधकों/एजेंटों के लिए उक्त कालेज में दो दो पाठ्यक्रम चलाये गये। इस अवधि में, वाणिज्य बैंकों के वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग तथा मध्यम स्तरीय कर्मचारी वर्ग के लिए कृषि वित्त पर एक एक पाठ्यक्रम

आयोजित किया गया। रिजर्व बैंक के बैंक परिचालन तथा विकास विभाग के अधिकारियों को कृषि ऋण के क्षेत्र में, विशेष रूप से वाणिज्य बैंकों के ऋण क्षेत्र के संदर्भ में पायी जानेवाली नवीनतम गतिविधियों से परिचित कराने के उद्देश्य से कृषि वित्त पर एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

371. आलोच्य वर्ष में इस कालेज में निम्नीलिखित नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए : (क) राज्य/प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के प्रबंध कर्मचारी वर्ग के लिए एक पाठ्यक्रम, (ख) औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करनेवाले केन्द्रीय बैंकों के प्रबंधकों/उप प्रबंधकों के लिए एक पाठ्यक्रम, (ग) राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध कर्मचारी वर्ग के लिए एक पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम और (घ) शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंध कर्मचारी वर्ग के लिए एक पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम। आलोच्य वर्ष में राज्य/प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के प्रबंध कर्मचारी वर्ग के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम चार बार आयोजित किया गया और अन्य पाठ्यक्रम एक एक बार आयोजित किये गये।

372. इस अवधि में कालेज में सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों के जिन अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उनकी कुल संख्या 509 थी (इनमें विदेशों के 2 अधिकारी भी शामिल हैं)। 1969 में जब इस कालेज की स्थापना की गयी, तब से लेकर अब तक कुल 720 अधिकारियों ने कालेज द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कालेज ने वाणिज्य बैंकों द्वारा चलाये जानेवाले कालेजों में कृषि वित्त का अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए एक विचार-गोष्ठी का भी आयोजन किया। हाल ही में, कालेज के प्रिंसिपल ने बैंक/उप-महत्वा राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान का अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण किया है जिसके साथ रिजर्व बैंक ने पिछले वर्ष एक सहयोग करार कर लिया था।

कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज, मद्रास

373. कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज, मद्रास स्टाफ आफिसर ग्रेड 2 और सहायक कर्मचारी वर्ग के लिए केन्द्रीय बैंक संघटन पर सामान्य पाठ्यक्रम तथा बैंक परिचालन तथा विकास विभाग और कृषि ऋण विभाग के अधिकारियों के लिए निरीक्षण प्रधान पाठ्यक्रम का आयोजन नियमित रूप से करता रहा। इस कालेज में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या 2,947 है।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

374. रिजर्व बैंक के अवर तथा प्रवर क्लर्कों के लिए बम्बई, मद्रास और नई दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पाठ्यक्रमों का आयोजन करते रहे। कीतपय अनिवार्य प्रशासनिक कारणों से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता प्रत्याशा के अनुसार पुनः नहीं खोला जा सका। विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त क्लर्क कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या 6,210 है।

कर्मचारी वर्ग की प्रतिनिधित्व

375. भारतीय प्रशासी कर्मचारी कालेज, हैदराबाद के साथ की गयी स्थायी व्यवस्थाओं के अधीन, रिजर्व बैंक के अधिकारी उस कालेज के द्वारा आयोजित प्रबंध विकास पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिनिधित्व किये गये। वाणिज्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के लिए बैंक प्रशिक्षण कालेज द्वारा चलाए जानेवाले कुछ पाठ्यक्रमों में और साथ ही अखिल भारतीय प्रबंध संस्था तथा राज्य स्तरीय प्रबंध संस्थाओं, उत्पादित परिषदों, प्रबंध संस्थाओं तथा कुछ इसी प्रकार के अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित प्रबंध विकास संबंधी अल्पकालीन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी रिजर्व बैंक के अधिकारियों को भेजा गया। रिजर्व बैंक ने आलोच्य अवधि

में, मनीला में आयोजित 8 वें दक्षिण पूर्व एशिया, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया केन्द्रीय बैंक व्यवस्था पाठ्यक्रम, बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा आयोजित केन्द्रीय बैंक व्यवस्था पाठ्यक्रम तथा कुछ विदेशी संस्थानों द्वारा आयोजित रिजर्व बैंक के कृति के अन्य पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। ब्रिटेन, जापान, पश्चिम जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आदि देशों की बैंक व्यवसाय संबंधी संस्थाओं तथा वित्तीय संस्थाओं में अध्ययन दौरे/प्रशिक्षण के लिए भी अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हिन्दी की प्रगति

376. आलोच्य वर्ष में रिजर्व बैंक ने 30 जून 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कामकाज एवं भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट का हिन्दी संस्करण प्रकाशित किया। उसमें मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट, 1969-70 से चुने गये विवरणों के हिन्दी रूपांतर तथा रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नाम जारी किये गये महत्वपूर्ण परिपत्रों के हिन्दी रूपांतर परीक्षाओं के रूप में दिये गये। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कृषि पुनर्विस्तार निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा जमा बीमा निगम को उनकी वार्षिक रिपोर्टों के हिन्दी अनुवाद एवं प्रकाशन के लिए रिजर्व बैंक बराबर सहायता प्रदान करता रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य और कार्य पद्धति के संशोधित संस्करण तथा संशोधित विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियम पुस्तक (छठा संस्करण) के असांख्यिक अंश का हिन्दी में अनुवाद किया गया और उपयुक्त नियम पुस्तक के असांख्यिक अंश का उक्त अनुवाद भारत सरकार के पास भेजा गया। भारत में सहकारी गतिविधि से संबंधित आंकड़े जुटाने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों की सहकारी समितियों के पंजीकों के पास भेजने के लिए रिजर्व बैंक ने फार्मों का हिन्दी रूपांतर भी प्रस्तुत किया।

377. 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का पालन करते हुए रिजर्व बैंक प्रेस विज्ञप्तियों/नोटों/प्रकाशनियों/सांश्रों, नोटिसों, विज्ञापनों और अधिसूचनाओं को अंग्रेजी और हिन्दी में एक साथ जारी करता रहा। जनता, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त पत्र स्वीकार किये गये और जहाँ जहाँ आवश्यक था, उनका हिन्दी में उत्तर दिया गया।

378. रिजर्व बैंक विभिन्न केन्द्रों में अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए स्वीच्छक आधार पर अपनी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी कक्षाएँ चलाता रहा। हिन्दी में वृद्धता प्राप्त करने के लिए जो प्रोत्साहन दिये जाते थे वे आलोच्य वर्ष में जारी रहे। रिजर्व बैंक के टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपराइटिंग (टंकण कला) सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिन्दी टाइपराइटिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहन के रूप में मानदंड प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

8. लेखा और अन्य विषय

379. 30, जून 1971 को समाप्त हुए लेखा वर्ष में सांख्यिक और अन्य व्यवस्थाएँ करने के बाद बैंक की आय पिछले वर्ष के 105.43 करोड़ रुपये की तुलना में करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के कुल व्यय की राशि पिछले वर्ष के 30.45 करोड़ रुपये की तुलना में 36.46 करोड़ रुपये थी। केन्द्रीय सरकार को अदा करने के लिए अलग से रखी गयी वास्तविक लाभ-राशि 100 करोड़ रुपये थी जब कि पिछले वर्ष यह राशि 73 करोड़ रुपये थी।

380. राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि, राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरकरण) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में जो अंशदान किये गये उनकी राशि क्रमशः 18 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये थी जब कि 1969-70

में यह राशि क्रमशः 17 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये थी।

381. 1970-71 में आय में 31.01 करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई वह प्रमुख रूप से प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों, राज्य सरकारों, बैंकों आदि को दिये गये ऋणों और अधिमों पर अधिक मात्रा में ब्याज प्राप्त होने तथा रुपये खजाना बिलों पर अधिक मात्रा में बट्टा प्राप्त होने के कारण हुई। व्यय में 0.01 करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई वह मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से स्थापना व्यय में हुई वृद्धि के कारण हुई : (1) श्रेणी 2, 3, और 4 के कर्मचारियों के वेतनमानों के परिशोधन के कारण उन्हें वेतन की बढ़ावा राशि दी गयी, और (2) अधिकारी वर्ग को अंतरिम राहत दी गयी तथा उक्त वर्ग के वेतन का तदर्थ पुनर्नियतन किया गया।

लेखा परीक्षक

382. रिजर्व बैंक के लेखों की परीक्षा मेसर्स ए. एफ. फर्गुसन एंड कंपनी, बम्बई, मेसर्स राय एंड राय, कलकत्ता, मेसर्स सूरी एंड कंपनी, मद्रास और मेसर्स ठाकुर बंछनाथ अय्यर एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा की गयी जिन्हें भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी तारोख 28 अप्रैल 1971 की अधिसूचना सं. एफ. 3(50)-बीसी/69 द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था। इस बात का इतमीनान कर लेने के उद्देश्य से कि बैंक के सांख्यिक लेखा परीक्षकों द्वारा बैंक के अधिकतर कार्यालयों के लेखों की परीक्षा हो, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के परम्परात्मक कार्यालयों के अलावा कानपुर, नागपुर और नई दिल्ली के कार्यालयों की भी बहियों की लेखा परीक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है। लेखा परीक्षकों के लिए प्रतीत कार्यालय 15,000 रुपये का पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है।

केन्द्रीय बोर्ड

383. सर्वश्री वी. वी. चारी और एस. एस. शिरालकर ने क्रमशः 17 नवंबर 1970 और 18 दिसंबर 1970 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए उप-गवर्नर का पदभार ग्रहण किया। श्री. सी. पी. एन. सिंह और प्रो. एम. मुजीब 14 जनवरी 1971 को अपनी पदावधि समाप्त होने पर केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक पद से निवृत्त हुए। संनित्व निदेशकों की सेवाओं के प्रति बोर्ड अपना आभार प्रदर्शित करता है।

384. इस वर्ष केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठकें हुईं जिनमें से चार बैठकें बम्बई में हुईं और मद्रास, कलकत्ता तथा नई दिल्ली में एक-एक बैठक हुई। केन्द्रीय बोर्ड की समिति की वाचन बैठकें हुईं जिनमें से दस बैठकें नई दिल्ली में, दो बैठकें मद्रास में और शेष बैठकें बम्बई में हुईं।

385. श्री. के. एन. मेहता 21 जनवरी 1971 को कारोबार बंद होने के समय से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये।

स्थानीय बोर्ड

386. आलोच्य वर्ष में स्थानीय बोर्डों के स्वरूप या सदस्यता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

कार्यालय खोलना और बंद करना तथा संगठन और प्रबन्ध में परिवर्तन

387. विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग का एक कार्यालय 2 नवंबर 1970 से कोचिन में खोला गया। अपने आप में पूर्ण एक सरकारी ऋण कार्यालय 1 मई 1971 से अहमदाबाद में खोला गया। बैंकिंग परिवर्तन और विकास विभाग के चार कार्यालय गोंहाटी, पटना, जम्शु और जयपुर में क्रमशः 15 फरवरी, 1 मार्च, 15 मई और 15 जून 1971 को खोले गये। कृषि ऋण विभाग का कानपुर स्थित क्षेत्रीय

कार्यालय मई 1971 में लखनऊ को स्थानान्तरित कर दिया गया। कृषि ऋण विभाग चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का दर्जा बढ़ाया गया और उक्त कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व काश्मीर को लाया गया।

बैंक के भवन कार्यालय भवन

388. नागपुर कार्यालय के उपभवन का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है और बंगलूर में प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है। हैदराबाद में और बंबई के मिंट के अहाते में बनाये जानेवाले कार्यालय भवन और भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के प्रस्तावित कार्यालय भवन और उप-भवन योजना की स्थिति में है। जयपुर में नगर विकास मंडल द्वारा बैंक को बंची गयी भूमि के स्वामित्व के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण योजना की प्रगति में बाधा पड़ गयी है। अहमदाबाद और गौहाटी के कार्यालय भवनों के लिए वास्तुकों की नियुक्ति करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

389. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस विभाग के उप कार्यालय और बैंकिंग विभाग के अनुभाग खोलने के लिए अहमदाबाद और भुवनेश्वर में पट्टे पर भवन लेने के प्रस्तावों का उल्लेख किया गया था। अहमदाबाद में भवन ले लिया गया है और भुवनेश्वर के भवन के संबंध में यह आशा की जाती है कि वह निकट भविष्य में प्राप्त हो जाएगा। इनके अलावा गौहाटी, जयपुर और जम्मू में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए भी पट्टे पर भवन ले लिया गया है।

आवास भवन

390. बैंक सभी प्रमुख केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के आवास भवनों की व्यवस्था करने की बराबर कोशिश कर रहा है। इन आवास भवनों के लिए बैंक भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आलोच्य वर्ष में मद्रास में ग्रेड 1 के स्टाफ ऑफिसरों के लिए 11 फ्लैटों और बंबई में क्लर्कों तथा अधीन कर्मचारियों के लिए क्रमशः 240 और 192 फ्लैटों की कालोनी का निर्माण कार्य समाप्त किया गया। बंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, नागपुर, पटना और कानपुर में बैंक ने अब तक कर्मचारियों के लिए जितने फ्लैटों की व्यवस्था की है उनकी कुल संख्या ग्रेड 1 के स्टाफ ऑफिसरों के लिए 160, ग्रेड 2 के स्टाफ ऑफिसरों के लिए 366 तथा क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों के लिए क्रमशः 1,616 और 744 है। इससे इन केंद्रों के कुल कर्मचारियों के लगभग 15 प्रतिशत कर्मचारियों को आवास प्राप्त हुआ है। क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली और कलकत्ता में क्रमशः 272 और 456 फ्लैटों का निर्माण-कार्य प्रगति कर रहा है तथा बंगलूर में ग्रेड 1 और 2 के स्टाफ ऑफिसरों के लिए 56 फ्लैटों तथा क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों के लिए कानपुर में 224 फ्लैटों, नागपुर में 104 फ्लैटों और मद्रास में 16 फ्लैटों का निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है। बंबई में ग्रेड 1 और 2 के स्टाफ ऑफिसरों के लिए 152 फ्लैटों और नई दिल्ली में क्लर्कों के लिए 48 अतिरिक्त फ्लैटों का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। नई दिल्ली में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के स्टाफ ऑफिसरों के लिए और भुवनेश्वर, मद्रास, बंगलूर तथा हैदराबाद में श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए और कालोनीयों का निर्माण करने का कार्य योजना की स्थिति में है। कानपुर में ग्रेड 1 और 2 के स्टाफ ऑफिसरों के प्रस्तावित आवासों के लिए वास्तुकों की नियुक्ति करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

391. ऐसे केंद्रों में जहां कोई भूमि प्राप्त नहीं की गयी है या जहां आवासों की संख्या अपर्याप्त है, आवास भवनों का निर्माण करने के निमित्त उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

392. स्टाफ ऑफिसरों के लिए कंपनी पट्टे पर फ्लैट लेने की योजना जारी है, क्योंकि जिन शहरों में बैंक के कार्यालय स्थित हैं वहां की आवास स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आलोच्य वर्ष में 227 फ्लैट पट्टे पर लिये गये। पट्टे पर फ्लैट लेने की योजना 1967 में शुरू की गयी। इस योजना के अधीन अब तक पट्टे पर लिये गये फ्लैटों की कुल संख्या 716 हो गयी है।

विविध

393. कलकत्ता के पुराने कार्यालय भवन का नवीकरण कार्य समाप्त होनेवाला है और कानपुर के पुराने कार्यालय भवन का नवीकरण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। नई दिल्ली में सरंजनी नगर तथा कस्तूरबा नगर में स्थित कालोनीयों में सामुदायिक केंद्रों का निर्माण करने का कार्य योजना की स्थिति में है।

मालिक-कर्मचारी संबंध

394. रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रबंधकों और श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के कामगार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के बीच वतन मानों तथा भत्तों आदि के परिशोधन के संबंध में 1 जून 1970 से जो बातचीत शुरू हुई उसका उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था। अब तक एक तरफ बैंक के प्रबंधकों और दूसरी तरफ अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ तथा अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कामगार महासंघ के बीच श्रेणी 2, 3, और 4 के कामगार कर्मचारियों के वतन, भत्तों तथा कुछ दूसरी सेवा शर्तों के परिशोधन के संबंध में समझौते हुए हैं। संघ और महासंघ के साथ जो करार किया गये हैं वे दोनों पार्टियों पर 31 दिसम्बर 1973 तक बाध्यकारी हैं। उक्त दोनों संगठनों की मांगों के प्रपत्र में सम्मिलित सभी बातों का निबटारा उन करारों में नहीं हुआ है, अतः शेष बातों का भी निबटारा करने के लिए उन के साथ बातचीत चल रही है। वाणिज्य बैंकों के कामगार कर्मचारियों के यूनियनों और भारतीय बैंक संगठन के बीच बैंकों के कर्मचारियों के वतन-स्वरूप के परिशोधन के संबंध में बातचीत हुई और 12 अक्टूबर 1970 को उन के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौता 1 जनवरी 1970 से चार वर्षों के लिए अमल में रहेगा।

कर्मचारियों के लिए आवास ऋण योजना

395. आलोच्य वर्ष में जो आवास ऋण मंजूर किये गये उनका विवरण नीचे दिया जाता है।

	समितियों की संख्या	राशि रु०
(क) नयी सहकारी गृह निर्माण समितियाँ	16	72,84,220
पहले ही गठित सहकारी गृह निर्माण समितियों को दिये गये प्रतिरिक्त ऋण	7	3,29,585
जोड़		76,13,805
	कर्मचारियों की संख्या	राशि रु०
(ख) घलन घलन कर्मचारी नये ऋण	145	27,44,798
जिन कर्मचारियों ने पहले ही ऋण लिये थे उतको दिये गये प्रतिरिक्त ऋण	2	2,850
जोड़		27,47,648

1981 में योजना के अमल में आने से लेकर अब तक मंजूर किये गये 'समिति' ऋणों और 'व्यक्तिगत' ऋणों की कुल राशि क्रमशः रु. 2,83,94,160 और रु. 78,45,103 है। कुल मिलाकर 1,710 कर्मचारियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
30 जून 1971 का तालन-पत्र
इस विभाग

देयताएं				प्राप्तियां			
रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट 18,00,36,776.00				सोने का सिक्का और बुलियन :			
संचलन में नोट 4435,03,88,195.50				(क) भारत में रखा हुआ 182,53,10,862.72			
जारी किये गये कुल नोट 4453,04,24,971.50				(ख) भारत के बाहर रखा हुआ			
				विदेशी प्रतिभूतियां 278,41,99,950.06			
				जोड़ 460,95,10,812.78			
				रुपये का सिक्का 39,15,33,741.55			
				भारत सरकार की रुपये प्रतिभूतियां 3952,93,80,417.17			
				वैशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र			
कुल देयताएं 4453,04,24,971.50				कुल प्राप्तियां 4453,04,24,971.50			
बैंकिंग विभाग							
देयताएं				प्राप्तियां			
रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.
चुक्ता पूंजी 5,00,00,000.00				नोट 18,00,36,776.00			
प्रारक्षित निधि 150,00,00,000.00				रुपये का सिक्का 92,062.00			
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि 190,00,00,000.00				छोटा सिक्का 3,14,775.60			
राष्ट्रीय कृषि-ऋण (स्थिरीकरण) निधि 39,00,00,000.00				खरीदे और भुनाय गए बिल			
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि 135,00,00,000.00				(क) देशी 10,02,29,513.79			
				(ख) विदेशी —			
				(ग) सरकारी खजाना बिल 15,79,86,288.22			
				विदेशों में रखा हुआ बकाया* 94,12,01,406.55			
				निवेश** 423,54,81,728.38			
जमा राशियां :—				ऋण और अधिम :—			
(क) सरकारी				(i) केंद्रीय सरकार को —			
(i) केंद्रीय सनकार 54,98,95,012.38				(ii) राज्य सरकारों को 55,77,00,000.00			
(ii) राज्य सरकारें 86,63,13,936.17				ऋण और अधिम :—			
				(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 265,84,70,000.00			
				(ii) राज्य सहकारी बैंकों को 206,83,71,602.00			
				(iii) दूसरों को 13,78,60,000.00			
(ख) बैंक				राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अधिम और निवेश			
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 248,69,06,124.78				(क) ऋण और अधिम			
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 18,83,72,356.57				(i) राज्य सरकारों को 42,03,55,639.52			
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 83,62,402.90				(ii) राज्य सहकारी बैंकों को 24,31,43,271.66			
(iv) अन्य बैंक 1,02,07,228.20				(iii) केंद्रीय भूमिबंधक बैंकों को —			
(ग) अन्य 162,56,14,761.21				(ख) केंद्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबचरों में निवेश 10,14,98,135.00			
देय बिल 37,24,27,949.41				राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अधिम			
अन्य देयताएं 194,31,73,420.38				(क) राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अधिम 13,66,14,587.00			
				राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अधिम और निवेश			
				(क) विकास बैंक को ऋण और अधिम 55,04,21,044.00			
				(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश —			
				अन्य प्राप्तियां 75,14,96,362.28			
कुल देयताएं 1324,12,73,192.00				कुल प्राप्तियां 1324,12,73,192.00			

प्रगत: चुक्ता शेयरों पर फुटकर देयता रु. 8,99,992.80 (पौण्ड 50,000 के स्टलिंग निवेशों को रु. 100=5.5556 पौण्ड की दर पर बदला गया)।

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

** (i) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

(ii) इसमें विदेशों में रखे गये रु. 5,31,09,367.80 (50,000 पौण्ड और 6,961,250 अमेरिकी डालर के समान राशि) शामिल हैं।

† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रवत ऋण और अधिम शामिल नहीं हैं।

‡ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सीमायी बिलों पर अधिम दिए गये 171,91,00,000 रुपये शामिल हैं।

†† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रवत ऋण और अधिम शामिल नहीं हैं।

जे. एस. नकला,

मुख्य लेखापाल

तारीख 28 जुलाई 1971

एस. जगन्नाथन, गवर्नर

पी. एन. डमरो, उप गवर्नर

आर. के. हजारी, उप गवर्नर

बी. बी. चारी, उप गवर्नर

एस. एस. शिरालकर, उप गवर्नर

30 जून 1971 का समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

आय	र.	पै.
व्याज, भाजन, विनियम, कमीशन आदि	136,46,38,146.95	
व्यय		
स्थापना	20,58,91,346.23	
निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फीस और व्यय	57,802.80	
लेखा परीक्षकों की फीस	90,000.00	
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	93,93,714.68	
विधि प्रभार	39,151.82	
डाक और तार खर्च	11,32,016.41	
कोष-प्रेषण	60,14,579.19	
लेखन सामग्री, आदि	30,40,811.73	
प्रतिभूति-छपाई (चेक, नोट फार्म आदि)	4,90,81,764.01	
बक संपत्ति का मूल्यह्रास और मरम्मतें	95,05,283.57	
एजेंसी प्रभार	7,21,10,258.74	
कर्मचारी निधि और अधिवार्षिकी निधि में अंशदान	7,32,000.00	
विविध व्यय	75,48,975.46	
उपलब्ध वास्तविक शेष राशि	100,00,00,442.31	
जोड़	136,46,38,146.95	
केंद्रीय सरकार को देय अधिमेय	100,00,00,442.31	
प्रारक्षित निधि लेखा		
30 जून 1971 को शेष	150,00,00,000.00	
लाभ-हानि लेखों से अंतरित किया गया	कुछ नहीं	
जोड़	150,00,00,000.00	

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद।

जे. एस. मरुला
मुख्य लेखापाल

एस. जगन्नाथन, गवर्नर
पी. एन. डायरी, उप गवर्नर
आर. के. हजारी, उप गवर्नर
बी. बी. चारी, उप गवर्नर
एस. एस. शिरालकर, उप गवर्नर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति को सेवा में,

हम रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून 1971 तक के रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र तथा लेखों पर केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने केंद्रीय कार्यालय और कलकत्ता, बंबई, मद्रास, नई दिल्ली, कानपुर और नागपुर के कार्यालयों के लेखों और उनसे सम्बन्धित प्रमाणपत्रों और वाउचरों से और साथ ही, दूसरे कार्यालयों और शाखाओं के मैनेजरों द्वारा पेश की गई प्रमाणित उन विवरणियों से जिन्हें उक्त तुलन-पत्र में समाविष्ट किया गया है, उपर्युक्त तुलन-पत्र की जांच कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि हमने केंद्रीय बोर्ड से जो-जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, वह सारा स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गई है और यह संतोषजनक है। हमारी राय में यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है; इसमें रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया नियम अधिनियम 1934 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण दिए गए हैं और इसमें उक्त अधिनियम और विनियमों के अनुसार आस्तियों का मूल्य निर्धारण किया गया है। जहां तक हमारी जानकारी है यह तुलन-पत्र हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

तारीख 28 जुलाई 1971

राय एण्ड राय,
ए. एफ. फसगुन एण्ड कंपनी
ठाकर बंधनाथ अम्बर एण्ड कंपनी
सूरि एण्ड कंपनी } लेखा परीक्षक

[सं 3 (9) बी. प्रो. III]

आर. राजामणी, उप सचिव,

वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग, नई दिल्ली।

New Delhi, the 25th October, 1972

SUBJECT: *Annual Report of the working of the Reserve Bank of India and trend and progress of banking in India for the year July, 1, 1970 to June 30, 1971.*

S.O. 508.—In accordance with Section 53(2) of The Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following Report on the working of the Reserve Bank of India and Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1971.

I. Over all Trends in the Economy

The performance of the Indian economy during the Bank's accounting year July 1970 to June 1971 was rather uneven, though in terms of overall growth rate it appeared fairly satisfactory. In particular, as the year progressed, adverse trends emerged in some of the important sectors. National income at constant prices is estimated to have expanded by 5 to 5.5 per cent over 1969-70, attaining for the second year in succession the overall target of growth postulated in the Fourth Plan. To a large extent, this rise was due to a growth rate of over 6 per cent in the agricultural sector. The dominant group in this sector, viz., foodgrains production, continued its upward movement for the second year in succession, recording a rise of over 8.0 per cent. In contrast, the rate of growth in industrial production showed deceleration. The prices continued to be under pressure throughout the year. On the external side, while India strengthened her second line of reserves by completing the programme of repurchases from the I.M.F., the deficit in the balance of payments on current account widened. Over the year, exports registered a rise but in respect of imports, there was a reversal of the declining trend noticed since devaluation. The tragic developments in East Bengal, following the military crackdown in March 1971, have led to a serious problem of millions of evacuees seeking refuge in our country. Provision of food and shelter to these unfortunate people has put a heavy strain on the country's resources and their continued inflow is bound to act as a serious constraint on the tempo of economic development.

2. Investment in the economy does not yet seem to have picked up to an adequate level. Public sector investment though larger than in the preceding year was much lower than last year. Investment activity in the small-scale sector public response to new issues was encouraging. Financial assistance sanctioned as well as disbursements made against earlier sanctions by the term-lending institutions were appreciably larger than last year. The stock market after a recovery in the earlier months, however, showed a bearish trend. On the whole, the organised sector of industry remained subdued with capital consents and capital issues lower than last year. Investment activity in the small-scale sector appears to have improved. Institutional finance for investment in agriculture showed a further increase over the previous year's level.

3. Budgetary operations in 1970-71 have shown a much wider gap between receipts and disbursements than expected, particularly in the case of State Governments, leading to a considerable increase in bank financing of the deficit. The budgetary policy of the Central Government for 1971-72 has been framed against the background of generally improved prospects in the economic situation and the need to accelerate the tempo of development. The budget provides for a substantial step-up in Plan outlays in order to impart the necessary thrust to developmental activities. It also provides further measures for moving nearer to the social objectives of reducing regional disparities and bringing about an egalitarian society. A special provision of Rs. 75 crores has been made for employment-oriented works in rural areas and for creating employment opportunities for the educated unemployed. The budget has also provided for Rs. 60 crores for expenditure in connection with the evacuees. However, the inflow of evacuees has been much larger than anticipated earlier and the strain on budgetary resources would be correspondingly increased.*

*An additional provision of Rs. 200 crores has been made for expenditure to be incurred by end-December 1971 on evacuees from East Bengal.

4. In view of the continuous pressure on prices and the much larger credit expansion by the banking system in the first half of the year, monetary policy was constantly directed towards curbing the inflationary trends in the economy. Important measures taken were the stepping up of the Bank rate by one percentage point to 6 per cent, the raising of the Bank's statutory and net liquidity ratios, substantial alterations in the basis of eligibility for refinancing in respect of advances to priority sectors and for food procurement, advice to banks to exercise the utmost restraint, and the tightening of selective credit controls on specified commodities. At the same time, banks were advised to step-up the pace of deposit mobilisation; with a view to helping the banks to augment their resource-base, upward revision of various deposit rates was permitted. The rate of credit expansion slowed down considerably thereafter and the pressure on prices eased.

5. The public sector banks vigorously continued their branch expansion programme and oriented their lending policies in favour of the priority sectors, and prepared special schemes for assisting the backward areas and the weaker sections of the community. At the same time, it has been impressed upon the banks that in lending to priority sectors, a minimum standard of quality should be maintained and proper utilisation and return flow of funds should be ensured.

Output, Prices and Policy Measures

Farm Output

6. For the second year in succession during 1970-71, agricultural production showed a fairly high rate of expansion. While favourable weather conditions, particularly during the kharif season, have no doubt played a part in this, the extension of irrigation facilities and use of better water management techniques, the expansion of area under the High Yielding Varieties Programme and adoption of modern technology on a wider scale, have all contributed to this progress. A large part of this progress was due to the output of food, grains which at 107.8 million tonnes showed an increase of 8.3 million tonnes over the previous year. All major cereals except jowar shared the increase. Production of pulses, however, showed a marginal decline. The performance of major cash crops, however, was uneven. Output of both cotton and raw jute during 1970-71 is expected to be lower than in 1969-70. While cotton output was adversely affected by heavy unseasonable rains and attacks by pests in certain cotton producing tracts, decline in raw jute was due partly to adverse weather conditions during the sowing period and partly to reduction in acreage. Among major oilseeds, groundnuts production registered a significant improvement from 5.1 million tonnes to 6.1 million tonnes. Sugarcane (in terms of gur) is likely to remain around the previous year's level of output of 13.4 million tonnes.

Table 1—Trends in Agricultural Production

	Unit	1969-70 (Final Esti- mates)	1970-71 (Esti- mates)
1. Foodgrains	Million tonnes	99.5	107.8£
(i) Rice	-do-	40.4	42.5£
(ii) Wheat	-do-	20.1	23.3£
2. Raw Cotton*	Million bales†	6.1	5.4
3. Raw Jute and Mesta‡	-do-	6.8	6.1
4. Groundnuts‡	Million tonnes	5.1	6.1
5. Sugarcane (in terms of gur)	-do-	13.4	13.4

£ Final estimates.

*Trade estimates.

†Bales of 180 kgs.

‡Final estimates for 1970-71 and partially revised estimates for 1969-70.

Industrial Output

7. The period under review witnessed a noticeable slackening in the tempo of industrial growth. After registering annual increases of 6.4 per cent and 7.1 per cent during 1968 and 1969, the C.S.O's Index of Industrial Production (Base: 1960=100) recorded a growth rate of only 4.5 per cent* for 1970. The set-back became more pronounced during the latter half of the year which showed a growth rate of only 3.0 per cent over the corresponding period of 1969. Latest available data show that during January—March 1971 the increase in the index over the corresponding months of 1970 works out to only 1.5 per cent. The slackness in the tempo of industrial growth was due to a variety of adverse factors: shortages of key raw materials such as cotton, oilseeds and basic metals; power and transport bottlenecks; strained industrial relations; and a short-

*The slow-down in the growth rate is in part due to statistical reasons. There has been some transfer of units out of the books of D.G.T.D. to the small-scale sector without corresponding adjustments for the past years.

fall in the targeted rate of increase in the public sector investment.

8. Almost all major industrial groups whether classified according to *uses* or *inputs* have shared in the deceleration in varying degrees. Thus *basic* industries showed an increase of only 4.2 per cent during 1970 as against 8.9 per cent in 1969. Growth rate in *intermediate goods* industries, which was 4.2 per cent in 1969 declined to 2.7 per cent. *Consumer goods* industries witnessed a growth rate of 6.3 per cent as against one of 10.2 per cent in 1969, the fall being particularly sharp in the sub-group 'consumer durable goods industries.' The group *capital goods* industries alone showed an improvement in the rate of increase from 1.8 per cent in 1969 to 4.7 per cent in 1970.

9. Input-wise, while growth rates in *agro-based* industries and *metal-based* industries registered marginal declines from 5.5 per cent and 5.8 per cent during 1969 to 4.5 per cent and 5.2 per cent, respectively, during 1970, the fall in *chemical-based* industries was steeper from 10.3 per cent to 7.5 per cent.

Table 2—Trends in Industrial Production
(Variations (%) over corresponding period of previous year)

	Weights	1969	1970	January—June		July—December	
				1969	1970	1969	1970
General Index (Crude)	100.00	+7.1	+4.5	+8.0	+6.2	+6.1	+3.0
<i>Use-Based Classification:</i>							
Basic industries	25.11	+8.9	+4.2	+9.6	+5.9	+8.3	+2.6
Capital goods industries ..	11.76	+1.8	+4.7	+4.1	+7.4	—0.8	+2.5
Intermediate goods industries ..	25.88	+4.2	+2.7	+3.0	+5.1	+5.1	+0.6
Consumer goods industries ..	37.25	+10.2	+6.3	+12.6	+6.8	+7.9	+5.5
(a) Consumer durable goods industries	5.68	+12.9	+3.2	+17.0	+2.7	+9.7	+3.1
(b) Consumer non-durable goods industries	31.57	+9.3	+7.3	+11.2	+8.2	+7.3	+6.3
<i>Input-Based Classification:</i>							
Agro-based industries	44.08	+5.5	+4.5	+5.8	+6.0	+5.5	+2.9
Metal-based industries	16.55	+5.8	+5.2	+8.5	+6.9	+3.1	+3.7
Chemical-based industries ..	8.94	+10.3	+7.5	+13.2	+10.7	+7.7	+4.6
<i>Sectoral Indicators:</i>							
(1) Transport equipment and allied industries	10.90	+0.4	+0.1	+5.4	+1.8	—4.6	—1.4
(2) Electricity and allied industries	8.42	+14.2	+11.1	+15.4	+12.1	+12.8	+10.4

Note :—This table is based on C.S.O's Index Number of Industrial Production (Base : 1960=100). Group indices are derived.

10. The *sectoral indicators* show that the output of 'transport equipment and allied industries' was virtually stagnant during 1970 as in 1969. The 'electricity and allied industries' group maintained a high level of growth rate (about 11 per cent) though it was lower than that in the preceding year (14.2 per cent). Figures relating to some of the important industries showing absolute declines in output are given in Table 3 and figures for industries showing high growth rates in Table 4.

Capacity Utilisation

11. With this slackening in the industrial growth rate, the problem of under-utilisation of capacity was accentuated particularly in such industries as iron and steel, heavy mechanical engineering and industrial machinery and rail-road equipment. For finished steel, the utilisation ratio worked out to 68 per cent during the second half of 1970 as compared with 70 per cent during the corresponding period of 1969. Those industries manufacturing machinery for cement mills, tea, printing, leather and rubber products, experienced a reduction in capacity utilisation during 1970 as compared with 1969. In respect of railway wagons, hardly

39 per cent of the installed capacity was utilised due to a steady decline in orders from the railways. Other important industries which showed a reduction in capacity utilisation ratio during 1970 included, among others, cement, steel castings, steel pipes and tubes, storage batteries and dry cells. The utilisation ratio in almost all of these industries was not only lower during the second half of 1970 than during the first half but was also lower during the calendar year 1970 as compared with 1969.

12. However, some industries did register some improvement in the utilisation of their rated capacity. Important amongst these were power transformers, electrical motors, electrical cables and wires, because of larger outlays on rural electrification programmes. In motor vehicles, machine tools and some basic chemicals such as caustic soda, the capacity utilisation improved because of maintenance of high demand.

Casual Factors

13. The casual factors for the slowdown in industrial growth are many and they differ from industry to industry.

Table 3—Industries showing Absolute Declines in Output during 1970

Industry	(In percentage)	
	Growth rates during	
	1969	1970
Iron and steel (basic industries) ..	+8.5	—6.9
Brass manufacturing	+28.5	—4.6
Prime movers, boilers and stream generating plants	+0.5	—2.7
Rail-road equipment	—10.6	—19.8
Dyestuff and dyes	+9.6	—1.4

Table 4—Industries Showing High Growth Rates During 1970

Industry	(In percentage)	
	Growth rates during	
	1969	1970
<i>Basic Industries:</i>		
Heavy inorganic chemicals ..	+14.0	+6.5
Fertilisers	+22.1	+21.3
Aluminium	+5.9	+19.6
Electricity	+12.9	+10.3
<i>Capital Goods Industries:</i>		
Machinery apparatus and supplies for generation, etc. (Power transformers)	+4.6	+40.6
Electrical motors and furnaces ..	+8.7	+34.5
Electrical cables and insulated wires	+5.4	+9.0
<i>Intermediate Goods Industries:</i>		
Jute manufactures	—19.3	+9.4
<i>Consumer Goods Industries:</i>		
Sugar (refined)	+76.4	+10.9
Tea	+3.1	+18.8
Vanaspati	+1.6	+8.2
Commercial office and household machines	—14.1	+14.3
Motor cycles and bicycles	+10.4	+9.8

Output of iron and steel was adversely affected by strained industrial relations and other organisational problems, shortages of raw materials such as refractories and lime and shutdown of some plants due to mechanical failures and for capital repairs. The absolute decline in the output of iron and steel had, in turn, an adverse impact on the output of a number of steel-based engineering industries. Output of coal was adversely affected by reduced demand, particularly from the railways, and also by transport bottlenecks. Reduction in wagon loadings during the year, following general slackness in overall industrial activity and also immobilisation of wagons as a result of an unsatisfactory law and order situation in the Eastern region, adversely affected railway finances resulting in a cut in their investment programmes. This, in turn, severely affected the demand for a wide range of engineering products, particularly the rail-road equipment. Besides the railways, many other major industrial projects in the public sector such as Bokaro Steel, petrochemicals and fertiliser plants could not achieve the targeted rate of increase in investment outlays; this affected output in the engineering sector except in industries belonging to heavy electrical group which has registered substantial increases in the output of generators, power transformers and other equipment to cater to the growing demand for electricity. The recent rural electrification programme is an additional factor.

14. With the improvement in power supply in rural areas, demand for diesel engines has levelled off in recent months. Among consumer goods industries, the cotton textile industry has been passing through a difficult phase due to shortage of raw cotton.

15. As stated already, slackness in industrial growth in general was partly due to shortages of key raw materials like cotton, oilseeds and steel, in addition to power and transport bottlenecks. Shortfall in public sector investment had its impact on a number of mechanical engineering industries in which additional capacity was built up earlier in anticipation of a steady expansion of public sector investment. Further, there has recently been a shift in investment programme in favour of agricultural and employment-oriented schemes; these schemes have, in the initial stages at least, a limited potential for generating additional demand for the products of the heavy mechanical engineering industry. Labour relations continued to remain disturbed. Total man-days lost in 1970 on account of strikes and lock-outs add up to 19 million about the same as in 1969.

16. In contrast to a decline in the rate of growth of output of organised industries, the performance of small-scale and decentralised sectors in recent years has shown improvement. The cloth output in the decentralised sector, for instance, recorded an improvement of about 4.4 per cent during 1970.

Employment Situation

17. In the absence of adequate data, it is difficult to assess the employment situation during 1970-71. Overall employment in the 'organised sector', which was virtually stagnant during the years 1966-67 and 1967-68, registered an improvement of 1.9 per cent in 1968-69 and 2.5 per cent in 1969-70. In both these years, the growth rate was higher in public sector than in private sector. Data regarding employment in 1970-71, available for the period April—September 1970 show that total employment in 'organised sector' increased by about 2.7 per cent over the corresponding period of the previous year. Employment in public sector rose by 2.9 per cent during this period and that in private sector by 2.3 per cent. Further, data from the Live Registers of the Employment Exchanges available for 1970-71 (April—March) also show a rising trend in employment in the 'organised sector.' Rate of growth in 'placements' has shown a sharp increase from 0.9 per cent in 1969-70 to 5.1 per cent in 1970-71 and that in 'vacancies notified' from an absolute decline of 0.6 per cent to a rise of 4.8 per cent.

18. With the recent emphasis on employment-oriented schemes, both in rural and urban areas, and with the increase in agricultural production, employment situation in the unorganised sector also may be expected to improve. The Central Budget has made provision of Rs. 50 crores for employment-oriented works in rural areas and Rs. 25 crores for creation of employment opportunities for the educated unemployed. Besides, some of the special programme formulated for the benefit of marginal farmers, farmers in dry-farming areas and agricultural labour may also be helpful. The Marginal Farmers and Agricultural Labour (MFAL) projects to be taken up in 41 selected districts (of which 30 have already been approved and financial allocation in respect of 22 projects have been made upto March 1971) with a project outlay of Rs. 1 crore each are particularly oriented towards development of subsidiary occupations such as poultry and dairy farming. The rural works programme proposed to be undertaken in 54 chronically drought-prone districts in different States, for which an outlay of Rs. 100 crores is envisaged during the Fourth Plan, is expected to provide significant employment opportunities for farmers in these areas.

19. The commercial banks also have expanded credit facilities at reasonable rates of interest for purposes with a considerable employment potential to a large number of borrowers of small means, such as, small farmers, small-scale manufacturers, retail traders, road transport operators, small businessmen professionals and self-employed persons.

Price Situation

20. The general price level over the year under review showed a rise of 3.1 per cent, compared with an increase of 4.0 per cent recorded in the preceding year. The undertone was one of continued pressure although between September 1970 and May 1971, prices fluctuated with a narrow range.

21. The Economic Adviser's Index Number of Wholesale Prices (Base: 1961-62 = 100), which stood at 180.5 by end-June 1970 moved up further to reach the peak at 183.8 on

September 12, 1970. This was followed by a period of narrow fluctuations with the onset of the harvesting season; as the under-lying trend was one of continued pressure, the index again touched its earlier peak of 183.8 on January 9, 1971 and hovered around this level till the end of the month. The main factor responsible for pressure on prices during this period was the supply shortages, in relation to rising demand, in respect of key industrial raw materials such as cotton and oilseeds in the earlier part of the year. With

the adoption of corrective measures, such as larger imports, equitable distribution, general and selective credit controls, the pressure on prices eased and the price index declined to 180.6 on February 27, 1971. Thereafter, it fluctuated narrowly between 180—183 till the third week of May 1971. Following the onset of lean season for agricultural commodities, the pressure on prices reasserted itself. Variations in index on wholesale prices during the last two accounting years are brought out in Table 5.

Table 5.—Trends in Index Numbers of Wholesale Prices

(Base : 1961-62 = 100)

								Percentage Variations					
								End-June 1969	End-June 1970	End-June 1971	End-June 1970 over End-June 1969	End-June 1971 over End-June 1970	
Weights*													
<i>All Commodities</i>								1000	173.5	180.5	186.1	+4.0	+3.1
<i>Food Articles</i>								413	201.9	204.3	206.8	+1.2	+1.2
Foodgrains								(35.8)	210.8	212.1	207.0	+0.6	-2.4
(i) Rice								(16.2)	202.4	209.2	204.8	+3.4	-2.1
(ii) Wheat								(7.8)	207.8	205.9	199.9	-0.9	-2.9
(iii) Jowar								(2.2)	198.3	188.8	191.9	-4.8	+1.6
(iv) Bajra								(1.1)	207.2	187.6	139.5	-9.5	-25.6
Pulses								(6.5)	241.6	240.0	247.8	-0.7	+3.3
Edible Oils								(13.0)	211.1	239.5	198.1	+13.5	-17.3
<i>Liquor and Tobacco</i>								25	202.2	184.5	194.4	-8.8	+5.4
Tobacco Manufactures								(47.5)	199.5	212.1	245.6	+6.3	+15.8
<i>Fuel, Power, Light and Lubricants</i>								61	153.4	160.3	170.5	+4.5	+6.4
<i>Industrial Raw Materials</i>								121	185.7	201.3	191.0	+8.4	-5.1
Cotton Raw								(18.5)	169.7	191.0	229.8	+12.6	+20.3
Jute Raw								(9.6)	189.3	159.6	152.0	-15.7	-4.8
Oilseeds								(43.3)	215.1	244.3	204.0	+13.6	-16.5
Groundnuts								(20.8)	216.9	240.1	192.9	+10.7	-19.7
<i>Chemicals</i>								7	179.1	185.1	195.0	+3.4	+5.3
<i>Machinery and Transport Equipment</i>								79	133.7	145.7	156.1	+9.0	+7.1
<i>Manufactures</i>								294	140.9	151.7	165.4	+7.7	+9.0
(i) Intermediate Products								(19.5)	155.3	174.9	193.0	+12.6	+10.3
(ii) Finished Products								(80.5)	137.4	146.0	158.7	+6.3	+8.7
Cotton Manufactures								(26.8)	131.1	140.0	159.4	+6.8	+13.9
Jute Manufactures								(8.1)	148.1	166.5	191.2	+12.4	+14.8
Chemical Products								(9.2)	135.6	143.9	149.5	+6.1	+3.9
Iron and Steel Manufactures								(12.2)	149.7	160.8	177.6	+7.4	+10.4
Paper Products								(3.3)	120.4	121.3	124.7	+0.7	+2.8

*Figures in brackets refer to the percentage distribution of the weightage assigned to respective main groups.

22. Groupwise, the prices of Food Articles experienced relative stability, while those of Industrial Raw Materials registered a decline mainly because of perceptible fall in groundnuts and other edible oil prices from the high levels reached in the previous year. Almost all other groups showed larger increases than in the preceding year.

23. The relative stability in the price index for Food Articles reflected their relatively easier supply position. Following good harvest for the fourth year in succession, prices of 'foodgrains' recorded a significant fall of 2.4 per cent as against an increase, though fractional (0.6 per cent), noticed during the previous year. Prices of major cereals such as rice and wheat recorded declines of 2.1 per cent and 2.9 per cent, respectively. Prices of bajra moved down by as much as 25.6 per cent. As against these declines, prices of 'pulses' witnessed a rise of 3.3 per cent and jowar prices, an increase of 1.6 per cent. 'Edible oils' prices, which were ex-

periencing severe pressure till the beginning of October 1970, eased thereafter on better crop prospects during the 1970-71 season, particularly in respect of groundnuts. On balance, 'edible oils' prices recorded a substantial fall of 17.3 per cent during the year under review as compared with the rise of 13.5 per cent during 1969-70.

24. The marked fall of 5.1 per cent (as against a rise of 8.4 per cent during 1969-70) in the Industrial Raw Materials group was brought about by the declines in prices of 'oilseeds' (16.5 per cent) and raw jute (4.8 per cent). During 1969-70, while prices of raw jute had witnessed a substantial fall of 15.7 per cent, those of 'oilseeds' had risen by 13.6 per cent. In contrast, raw cotton prices experienced renewed pressure during the year under review and there was a rise of 20.3 per cent on top of an increase of 12.6 per cent recorded during 1969-70. Except for a temporary respite noticed during the months of September-October 1970 when trade estimates had placed the cotton crop for 1970-71 at a high level of 62 lakh bales (which was subsequently revised

downward to only 54 lakh bales), raw cotton prices had shown a marked upward trend almost continuously from the beginning of 1970 due to acute scarcity of domestic cotton and delayed imports. By February 6, 1971, the wholesale price index for raw cotton had reached the peak level of 257.0, recording a rise of 53 per cent over the level at the beginning of 1970. Subsequently, however, with the stepping up of Government's import programme and tightening of credit control measures, cotton prices tended to fall and by May 15, 1971, their index had reached 218.1 showing a fall of 15.1 per cent over the above peak level. Thereafter, cotton prices again edged upwards due to inadequate pick-up in import arrivals, and the index stood at 229.8 at the end of the year.

25. Though estimated output of raw jute in 1970-71 was lower than that in the previous year, its prices showed a gradually declining trend upto the beginning of March 1971 due to sluggish manufacturing activity, following labour unrest in the jute mill industry, as also in Calcutta port which affected jute exports. With subsequent improvement in mills' demand for raw jute, the prices tended to rise. This was aided by developments in East Bengal. As a result though over the year the raw jute index recorded a substantial fall, during the last quarter (April-June), it showed a rise of 6.6 per cent.

26. The decline in prices of 'oilseeds' to the extent of 16.5 per cent, in contrast to a steep increase of 13.6 per cent in 1969-70, was mainly brought about by a substantial fall of 19.7 per cent in groundnuts prices. These have been steadily declining throughout the year under review owing to promising crop prospects; the down-trend was accentuated by heavy market arrivals of new groundnut crop during September-October 1970 and later due to reports of the signing of a new P.L. 480 agreement for import of 75,000 tonnes of soyabean oil from the U.S.A.

27. Associated with supply shortages noticed in respect of certain key industrial raw materials is the rise of 90 per cent during 1970-71 in the prices of Manufactures, on top of a rise of 7.7 per cent during 1969-70. The increase has been all-round. Among 'finished products', industries to record large increases are cotton and jute manufactures. Increases in their prices were of the order of 13.9 per cent and 14.8 per cent over and above the increases of 6.8 per cent and 12.4 per cent, respectively, recorded in the preceding year. The prices of 'iron and steel manufactures' rose by 7.4 per cent during 1969-70 and by 10.4 per cent during 1970-71. Besides, items like paper products and chemical products have shown continuous increases in prices.

28. Within the group Liquor and Tobacco, prices of 'tobacco manufactures', which rose by 3.2 per cent during the first eleven months of the accounting year (July 1970—May 1971), experienced a sharp increase of 12.2 per cent during the month of June 1971; as a result, over the year, these prices showed a rise of 15.8 per cent as compared with a rise of 6.3 per cent during the previous year. Similarly,

within the group 'Fuel, Power, Light and Lubricants', prices of mineral oils, kerosene oil and petrol, which had almost remained stable during the first eleven months, registered sharp increases during the month of June 1971, ranging from 6.0 to 19.0 per cent.

29. The relative stability noticed in respect of 'foodgrains' prices during the year under review is also reflected in the movement in the All-India Consumer Price Index for Working Class (Base: 1960=100), which recorded a smaller rise of 1.1 per cent during July 1970—June 1971 as compared with the rise of 3.9 per cent recorded during 1969-70.

Policy Measures—Agricultural Commodities

30. Following increase in foodgrains output for the second year in succession, procurement of foodgrains was sizeably stepped up, controls on movements of all foodgrains except rice were generally removed, and size of foodgrains stocks with Governments showed a further increase of nearly three million tonnes by the end of the year, despite a lower leave of imports.

31. With the steady improvement in domestic output, imports of foodgrains have been reduced to 3.6 million tonnes in 1970 from 5.7 million tonnes in 1968 and 3.9 million tonnes in 1969. During 1971, imports are likely to be lower than 3 million tonnes. In fact, during the first six months of 1971, only 0.7 million tonnes of foodgrains were imported as against 1.8 million tonnes during the corresponding period of 1970. Government have also proposed to stop all concessional imports of foodgrains by 1972.

32. Notwithstanding lower imports, stocks of foodgrains with the Central and State Governments stood at 8.5 million tonnes at the end of June 1971, registering an increase of 2.7 million tonnes over the level a year ago. Allowing for an operational stock of 2 million tonnes, buffer stock of foodgrains may be reckoned at 6.5 million tonnes. Such a high level of stock build-up was made possible by intensified procurement operations and lower off-take of foodgrains through the public distribution system.

33. Procurement of foodgrains from the 1969-70 crop totalled 6.6 million tonnes. Total procurement from the 1970-71 crop till end-June 1971 aggregated 8.1 million tonnes as against the target of 9.5 million tonnes set for the entire crop year. The Food Corporation of India is gradually acquiring a commanding position in the foodgrains trade; it procured 7.4 million tonnes of foodgrains from the 1970-71 crop till end-June 1971 as compared with 5.4 million tonnes from the entire 1969-70 crop.

34. Due to improved open market availability, volume of foodgrains distributed through fair price/ration shops has been declining for the past two years. During 1970, total quantity distributed was 8.9 million tonnes as compared with 9.5 million tonnes in 1969. The number of fair price/ration shops also declined from 1.39 lakhs as at the end of 1969 to 1.22 lakhs as at the end of 1970.

Table 6—Basic Data Relating to Food Management

Table 6. Basic Data Relating to Food Management										(Million tonnes)	
						1968-69 Crop		1969-70 Crop		1970-71 Crop	
						Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement
Procurement											
Total Foodgrains						7.9	6.1	9.2	6.6	9.5	8.1*
Of which :											
Rice (November-October)						3.5	3.3	4.5	3.0	4.7	3.1*
Wheat (April—March)						3.6	2.3	3.7	3.2	4.0	4.5*
Imports†						5.7		3.9		3.6	
Public Distribution of Foodgrains						10.4		9.5		8.9	
Year-end Stocks of Foodgrains						5.5		5.8		8.5	

35. As for movement restrictions, the movement of wheat and wheat products was made free throughout the country except in the statutorily rationed areas of Bombay, Calcutta, and the Asansol-Durgapur complex, with effect from April 1970. Subsequently, in May 1971, the ban on movement of wheat in the statutorily rationed area of Bombay was lifted.

36. In respect to key agricultural raw materials, prices of which caused anxiety during the year, Government stepped up its import programme. In the case of raw cotton, Government decided to import about 13.3 lakh bales during the 1970-71 season as against 9.1 lakh bales imported during 1969-70 (Table 7). However, there was considerable delay in actual import arrivals, and prices of cotton experienced a sharp upward rise, which necessitated tightening of control on bank advances against cotton in mid-December 1970. The Textile Commissioner imposed on December 9, 1970 a further reduction in cotton stocks to be held by the Mills. Also the Forward Markets Commission suspended futures trading in Kapas and reduced the period for non-transferable specific delivery contracts in cotton from six months to three months in December 1970 and further to one month in February 1971. In respect of oilseeds, Government permitted large imports of soyabean oil under P.L. 480 and made arrangements for the import of rapeseed. As prices of oilseeds and oils ruled at levels much higher than the preceding year due to speculative stock-holding despite reported rise in groundnut output, the Reserve Bank had to tighten its credit control measures regarding bank advances against oilseeds, vegetable oils and vanaspati towards end-January 1971.

37. The programmes under the New Agricultural strategy designed to strengthen the productive base of agriculture were further expanded and also intensified during the year under review. New dimensions were added to the programme of agricultural development so as to extend the coverage to dry farming areas as also to provide infra-structural facilities for the weaker sections of the rural community to share the benefits of development. Initially, food production policy was directed at exploiting, through concentrated application of new techniques, the existing production potential of areas with assured water supply and other favourable conditions. Though the strategy has yielded promising results, it has so far not benefited the farmers in dry areas, as also the weaker sections of the farm community. Therefore, additional programmes were undertaken to benefit the dry farming regions and to improve the lot of small but potentially viable farmers, marginal farmers and agricultural labour.

Table 7—Availability¹ of Raw Materials for Industries

	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71 (Estimates)
Raw Cotton (Lakh bales of 180 kgs. each) (September-August)				
Production	65.4†	59.2	60.7	54.0
Imports	7.8	4.3	9.1	13.3
Availability	92.4	84.7	86.9	83.8
Mill consumption ..	61.7	62.0	63.7	59.3
Raw Jute and Mesta (Lakh bales of 180 kgs. each) (July-June)				
Production	75.9	38.4	67.9	61.4*
Imports	—	6.1	—	—
Availability	94.6	64.5	75.9	75.4
Mill consumption ..	71.3	58.5	62.0	60.0
Major Oilseeds³ (Million tonnes) (July-June)				
Production	8.3	6.8	7.6	8.4

1. Availability is defined as production, imports and opening stocks.

2. Trade estimate, including non-commercial production.

3. Groundnut, rapeseed and mustard, linseed, sesamum and castorseed.

†Actual bales.

*Final estimate.

38. Among the existing programmes, coverage under high-yielding varieties is expected to be 14.0 million hectares in 1970-71 as against the actual achievement of 11.4 million hectares in the previous year. Besides further progress has been made in evolving new improved varieties for both rice and wheat, and areas under them have increased considerably during the year under review. Coverage under high-yielding varieties of rice has shown a significant increase at 5.50 million hectares during 1970-71 against the target of 4.45 million hectares. Among coarse grains, hybrid varieties of bajra have given encouraging results. Substantial achievements, in quantitative terms, were recorded in other programmes like multiple cropping, plant protection and minor and medium irrigation. Efforts at evolving new techniques for raising yield rates of important commercial crops were also vigorously pursued during the year under review.

39. Though the quantity of fertilisers consumed has increased, rate of growth has slowed down during both 1969-70 and 1970-71, partly due to larger stock accumulation earlier with dealers and farmers. The consumption of fertilisers has shown a notable rise in areas with adequate water supply and in areas where coverage of high-yielding varieties has been increasing; the other areas remain yet to be adequately covered. With rural electrification programme gaining momentum, the number of villages electrified has increased as also the number of agricultural pumpsets energised. There has been further progress in installation of private tubewells and induction of tractors (Table 8). Following the adoption of "multi-agency approach", quantum of institutional credit extended to agriculture has made rapid strides. Total credit extended by co-operatives during 1969-70 amounted to Rs. 682 crores as against the year's target of Rs. 640 crores and the actual credit of Rs. 616 crores supplied in the previous year. Short and medium-term credit during 1970-71 amounted to about Rs. 615 crores; long-term credit extended by land development banks is also expected to increase further during the year. Farm credit by commercial banks registered a phenomenal increase during 1970-71; as against the outstandings of Rs. 183 crores, on the eve of nationalisation of the major commercial banks, in June 1969, outstandings as at the end of March 1971 increased to Rs. 379 crores.

40. The Small Farmers Development Agencies have been approved for 45 selected districts as against the target of 46 districts to be covered during the remaining years of the Fourth Plan and financial allocations were made in respect of 43 agencies upto March 1971. These agencies would locate the small but potentially viable farmers, identify their problems and help in the provision of institutional credit, inputs, etc. Agencies for developing special programmes for providing supplementary occupation and employment-oriented activities in respect of marginal farmers and agricultural labour have been set up. The Agro-Industries Corporations already established in all the States except in Nagaland and Meghalaya, have shown further progress in making available essential farm inputs and agricultural machinery. The Central budget for 1971-72 has provided Rs. 50 crores to be spent on a countrywide crash programme of employment-oriented schemes in rural areas. A sum of Rs. 18.5 crores for grants has also been provided in the budget for 1971-72 for rural works in chronically drought affected areas.

41. In regard to raw cotton and raw jute, Government also took steps to canalise their imports/supplies through public sector agencies for which special corporations were established. The Cotton Corporation of India started functioning from September 15, 1970 which, besides canalising cotton imports, is also entrusted with the task of price support operations, purchase of extra long-staple cotton and supply of cotton to mills working under Government management. The Corporation has already started purchasing domestic cotton to meet the requirements of mills mainly in the public sector. In the case of jute, the Jute Corporation of India was established on April 2, 1971 for purchasing raw jute so as to ensure minimum support price to the growers and to build up buffer stocks through internal purchases and imports, if necessary.

Industrial Commodities

42. In the industrial sector, the tempo of growth was partly affected by shortfalls in public sector investment during the first two years of the Fourth Plan. This has been sought to be corrected by raising the public sector Plan outlay for 1971-72 to Rs. 3024 crores, i.e., by about Rs. 600

Table 8 - Progress of New Agricultural Strategy

Programme	Units	1968-69	1969-70	1970-71 (Target)
<i>Gross Area Covered</i>				
High-yielding varieties	Million hectares	9.3	11.4	15.1 (14.0)
Multiple cropping	"	6.1	8.0	10.2 (9.5)
Plant protection	"	40.0	48.0	52.0* (52.0)
<i>Consumption of Fertilisers</i>				
Nitrogenous (N)	'000 tonnes (nutrients)	1760	2009	2540 (2113)
Phosphatic (P ₂ O ₅)	"	1208	1398	1730 (1426)
Potassic (K ₂ O)	"	382	435	560 (461)
.. .. .	"	170	176	250 (226)
<i>Gross Area Irrigated</i>				
Major and medium**	Million hectares	18.6	19.4	20.0 (20.7)
Minor	"	19.0	20.4	21.9 (21.9)
<i>Institutional Investment on Minor Irrigation</i>				
.. .. .	(Rs. Crores)	106	120	— (30)
Agricultural pumpsets energised	'000 Nos.	1069	1329	1609 (1594)
Private tube wells installed	"	67	90	— (100)
Indigenous production of tractors	"	15.5†	17.1‡	25.0 (20.1)

Note : Figures in brackets are likely achievements.

*The original target was 42.3 million hectares.

**Potential.

†In addition, 15,500 tractors were imported.

‡In addition, 14,888 tractors have already been shipped up to March 31, 1971 against contracts concluded for import of 33,500 tractors against 1969-70 requirements.

crores above the likely Plan expenditure in 1970-71. Import policy for 1971-72 was considerably liberalised in regard to the requirements of priority sectors. Besides, import policy has provided special facilities for the import of raw materials to facilitate the revival of closed engineering units, particularly in West Bengal. A new corporation, namely, the Industrial Reconstruction Corporation of India, was established in April 1971, with headquarters at Calcutta, with a view to helping rehabilitation of closed units or units facing the risk of closure, particularly in West Bengal.

43. In regard to industrial development policy, while the new licensing policy as enunciated by Government in February 1970 continued to provide the basis for industrial advancement, the year under review saw a distinct policy re-orientation in favour of industries established in backward regions and those in the small-scale sector including the ones initiated by the young technicians, engineers and other self-employed persons, with a view to promoting wider dispersal and decentralisation of industries. A series of incentives have been devised for the promotion of these industries. The Central budget for 1971-72 has provided for a reduction in import duty in respect of machinery imported by small units and also differential excise duties, particularly on producer goods. The term-lending institutions like IDBI and IFCI have evolved new policies for encouraging industries set up in backward regions. Import policy for 1971-72 also makes special provision for the raw material requirements of small-scale units, young technicians, engineers, and other self-employed persons and also in respect of industries established in backward regions.

44. Government took certain concrete steps to foster the development of 'joint sector' in Indian industry on the lines of the recommendations of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee's (Dutt Committee) Report to which a reference is made later in this Report.

45. In the field of licensing policy, the number of items reserved for the small-scale sector has been increased, bringing the total of reserved items to 128. The 'banned' list for the purpose of industrial licensing, which had been under suspension since March 1970 on an experimental basis, has been dispensed with.

46. Besides, specific policy measures were adopted depending upon the exigencies of individual industries. In respect of some, as in electrical cables and wires and aluminium and its products, the market conditions attracted statutory price controls by Government. Besides, the use of copper in the manufacture of electrical cables and wires was prohibited except where they are intended for exports. Where the cost structure of industries entailed a reduction in prices, such a reduction was effected, either through statutory reduction as in rayon tyre yarn, cord and fabric (done on the advice of the Tariff Commission) or through informal arrangements with the industries concerned as in respect of the retail prices of automotive tyres and tubes. The prices of drugs and medicines were brought under a comprehensive system of control. Price increases were permitted where wage, raw material or other costs have escalated in recent years. Cycle prices were allowed to be raised due to increases in the prices of steel. In cement, price increases were permitted with a view to replenishing the balance in the freight equalisation account.

47. In steel, to mitigate the severe shortages, imports were considerably liberalised. As a result the import licences for steel issued during the financial year 1970-71 were more than twice the value of licences issued during 1969-70. Government also adopted a series of other measures, such as regulation of steel exports and introduction of the requisite changes in the product-mix by the main producers. The system of distribution was streamlined and distribution control was extended to practically all iron and steel products, without any distinction between scarce and non-scarce categories. Billets being supplied to re-rollers at controlled prices, the informal price control was also extended to the steel re-rolled products so as to prohibit them from appropriating a high margin.

48. Among agricultural commodities and agro-based industries under price controls, the prices of natural rubber were permitted to be raised with a view to protecting the interests of small growers. In view of the comfortable supply of sugar, controls on its price, distribution and movement were removed, but the mechanism of monthly release was continued.

Budgetary Operation@

49. Budgetary operations of the Central and State Governments in 1970-71 indicate a considerable worsening of the overall position. As against a modest overall deficit^a of Rs. 37 crores in 1969-70 (actuals) the revised estimates for 1970-71 show a deficit of Rs. 455 crores. This worsening has taken place despite a slow-down in the rate of growth in total disbursements because of the considerably smaller growth rate of total receipts. For 1971-72 the deficit is estimated at Rs. 387** crores.

Trends in Outlays

50. The growth rate in total disbursements (revenue and capital) of the Central and State Governments together declined to 40 per cent in 1970-71@@ from 11.4 per cent in 1969-70 for the year 1971-72, such disbursements are estimated to show a rise of over 8 per cent (Table 9). The com-

@The amounts mentioned in this Section relate to the fiscal year (April-March) unless stated otherwise.

* The net increase in outstanding Treasury Bills and withdrawal from cash balances in respect of the Centre and withdrawal from cash balances, net sales of securities held by States in their cash balance investment account and net transfer from Revenue Reserve Funds of States in respect of State Governments.

** This does not take into account the effects of supplementary demands for grants presented to the Lok Sabha, on August 5, 1971, which provide for an additional expenditure of Rs. 200 crores in connection with relief to refugees from East Bengal for the period upto end-December 1971. Since credit is also taken for an amount of Rs. 50 crores in the form of foreign assistance, the net impact on the budgetary position of the Centre is Rs. 150 crores.

@@ All references to figures relating to 1970-71 represent revised estimates for the year unless stated otherwise.

bined revenue expenditure of the Centre and States which had increased by 11 per cent and 12 per cent, respectively, in 1968-69 and 1969-70 increased by 10 per cent in 1970-71; budget estimates for 1971-72 provide for an increase of nearly 10 per cent in revenue expenditure. Capital disbursements of the Centre and States together increased by a little less than 10 per cent in 1970-71, as against a rise of a little over 10 per cent in 1969-70; the increase in such disbursements anticipated for 1971-72 at about 7 per cent is lower than in the preceding two years.

51. During 1970-71, non-developmental outlay of the Centre and States together (excluding special items of expenditure of non-recurring type like subscriptions to the international financial institutions, etc., for which provision was made in 1970-71 revised) rose by 7 per cent as against 18 per cent in 1969-70. For 1971-72 the combined non-developmental outlay would show a rise of about 6 per cent over such expenditure (excluding special items) in 1970-71. The developmental outlay of the Centre and States together which had increased by 8 per cent in 1969-70 (as against 14 per cent in 1968-69) increased by almost 14 per cent in 1970-71 (excluding a special item of expenditure of non-recurring nature, viz., provision for compensation to nationalised banks included in 1970-71 revised). For 1971-72, budgeted developmental outlay shows an increase of about 16 per cent over 1970-71 (excluding provisions for compensation to nationalised banks). The Plan outlay of Centre and States is estimated at Rs 3024 crores in 1971-72—nearly Rs. 400 crores more than that provided for in 1970-71 (budget).

Trends in Receipts

52. The rate of growth in total receipts of the Central and State Governments during 1970-71 (excluding notional receipts on account of compensation bonds in respect of nationalised banks and special securities issued to international financial institutions, etc.) was 3 per cent as against 15 per cent in 1969-70. Total receipts budgeted for 1971-72 would show a rise of about 12 per cent over 1970-71 (excluding notional receipts). Revenue receipts of the Centre and States together, which had increased by over 11 per cent in 1969-70 rose by almost the same rate in 1970-71;

Table 9—Combined Receipts and Disbursements of Central and State Governments

	(Amounts in Rupees Crores)							
	1969-70 (Accounts)		1970-71 (Budget Estimates) (a)		1970-71 (Revised Estimates)		1971-72 (Budget Estimates) (a)	
	Amount	Per cent increase(+)/decrease(—) over the previous year	Amount	Per cent increase(+)/decrease(—) over the previous year	Amount	Per cent increase(+)/decrease(—) over the previous year	Amount	Per cent increase(+)/decrease(—) over the previous year
I. Total Receipts (A+B)	8179	+15.2	8229	+0.6	8579	+4.9	9436	+10.0
A. Revenue Receipts	5392	+11.3	5813	+7.8	6004	+11.4	6666	+11.0
of which :								
Tax Receipts	4182	+12.2	4564	+9.1	4700	+12.4	5259	+11.9
B. Capital Receipts	2787	+23.7	2416	—13.3	2575	—7.6	2770	+7.6
II. Total Disbursements	8216	+11.4	8590	+4.6	9034	+10.0	9823	+8.7
of which :								
Developmental Outlay (a+b)	3140	+8.4	3620	+15.3	3647	+16.1	4128	+13.2
(a) Revenue	2105	+11.9	2323	+10.4	2417	+14.8	2741	+13.4
(b) Capital	1035	+2.0	1297	+25.3	1230	+18.8	1387	+12.8
Non-Developmental Outlay (a+b)	3279	+17.5	3328	+1.5	3697	+12.7	3723	+0.7
(a) Revenue	3157	+12.0	3210	+1.7	3377	+7.0	3574	+5.8
(b) Capital	122		118	—3.3	320	+162.3	149	—53.4
III. Overall Surplus (+) or Deficit (—) (I—II)	—37(b)		—361(b)		—455(b)		—387(b)(c)	

Note : Figures are adjusted for inter-Governmental transfers and hence differ from those given in Tables 12 and 13.

The combined overall position, however, remains unchanged.

(a) Includes effects of budget proposals.

(b) As measured by increase in outstanding Treasury Bills of Centre, withdrawal of cash balances of Centre and States, net sale of securities held by States in their cash balance investment account and net transfers from revenue reserve funds of States.

(c) This does not take into account the impact on Budgetary Position of net expenditure of Rs. 150 crores for relief to refugees from East Bengal provided for in the Supplementary Demands for Grants.

in 1971-72, however, the rate of growth in revenue receipts is placed at 11 per cent—slightly lower than that in the preceding two years. The rate of growth in tax revenue, which had accelerated from about 9 per cent in 1968-69 to about 12 per cent in 1969-70, was maintained at the same level in 1970-71; in 1971-72 the growth rate in tax revenue will be fractionally lower than in the preceding year. The revenue from taxes on commodities and services increased by 15 per cent in 1970-71 as against 12 per cent in 1969-70 thus raising its share in total tax revenue to 76.3 per cent in 1970-71 from 74.4 per cent in 1969-70. In 1971-72 the increase in tax revenue from this source is expected to be about 13 per cent; revenue from such taxes will constitute 77 per cent of the total tax revenue.

Budgetary Deficit for 1970-71

53. The overall deficit of the Central Government turned out to Rs. 230 crores in 1970-71—nominally higher than originally envisaged (Rs. 227 crores)*. In the case of State Governments, revised estimates of overall deficit in 1970-71 at Rs. 225 crores showed an increase of Rs. 91 crores over the budget anticipation. The quantum of actual overall deficit of Central & State Governments for 1970-71 is not yet known. However, the likely deficit can be gauged from the magnitude of net Reserve Bank credit to the Government sector which during the fiscal year 1970-71, increased by Rs. 332 crores as against an increase of Rs. 13 crores in the fiscal year 1969-70. Net Reserve Bank credit to the Central Government increased by Rs. 107 crores in 1970-71 as against an increase of Rs. 81 crores in 1969-70. In regard to States, the increase in net Reserve Bank credit was of the order of Rs. 225 crores as against a decline of Rs. 68 crores in 1969-70.

54. During the current fiscal year so far (April 1 to June 25, 1971), net Reserve Bank credit to Government sector increased by Rs. 468.0 crores as against an increase

*It is indicated by the Union Finance Minister that overall deficit of the Centre for 1970-71 may be of the order of Rs. 270 crores.

of Rs. 65.5 crores in the corresponding period of the preceding year. Net Reserve Bank credit to Central Government increased by Rs. 375.2 crores (as against an increase of Rs. 56.1 crores during the same period in 1970) and to State Governments by Rs. 92.8 crores as compared with an increase of Rs. 9.4 crores in the corresponding period of last year).

Overdrafts by States

55. For the past few years there have emerged persistent overdrafts of certain State Governments with the Reserve Bank of India. Total outstanding overdrafts of 11 States (as on 28th June 1971) were Rs. 371.29 crores as against Rs. 82.74 crores (6 States) as on June 27, 1970. Table 10 presents the overall budgetary position of all the States together for 1965-66 to 1970-71. It also shows the overdraft position of the State Governments with the Reserve Bank of India as at the end of each financial year and total disbursements on Revenue and Capital accounts combined. The table shows that the overall deficits of State Governments during the past five or six years have widened between the budget forecast and the revised estimates, and so have their disbursements. The precise reasons for the overdrafts of some of the State Governments are not clear. It would be useful, however, to see the trends in disbursements and variations in them between budget forecast and revised estimates.

56. For 1970-71 where the break-down of total disbursements into Plan and non-Plan is available, the data show that total disbursements increased in revised estimates over budget forecast; this has occurred both in respect of Plan and non-Plan expenditure, the increase in non-Plan expenditure being much larger. In 1970-71 while the overall deficit in the revised estimates has shown a deterioration of Rs. 320.4 crores over budget estimates, Plan expenditure has gone up by Rs. 104.6 crores, and non-Plan expenditure by Rs. 295.0 crores (Table 11). The overdrafts (10 States) as at the end of March 1971 amounted to Rs. 268.2 crores.

Table 10—State Governments' Overall Budgetary Position, Aggregate Disbursements and Overdrafts from Reserve Bank of India during 1965-66 to 1970-71

		(Rupees Crores)				
		Overall Deficit(—)/ Surplus (+)	Aggregate Disbursements on Revenue and Capital Accounts Combined**	Variation of Overall Deficit in R.E. over B.E. Increase (+) Decrease(—)	Variation of Aggregate Disbursements in R.E. over B.E. Increase(+) Decrease(—)	Overdrafts from Reserve Bank of India as on March 31
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1965-66	(B.E.)*	— 45.6	2965.3			
	(R.E.)	—188.9	3269.7	+143.3	+304.4	120.2
	(Accts.)	— 66.8	3216.5			
1966-67	(B.E.)*	+170.6	3204.1			
	(R.E.)	— 76.2	3431.0	+246.8	+226.9	15.8
	(Accts.)	— 6.5	3339.7			
1967-68	(B.E.)*	— 49.7	3784.5			
	(R.E.)	—102.6	3882.1	+ 52.9	+ 97.6	31.5
	(Accts.)	— 38.2	3835.6			
1968-69	(B.E.)*	+138.0	3847.9			
	(R.E.)	—152.7	4314.2	+290.7	+466.3	144.7
	(Accts.)	— 11.8	4461.5			
1969-70	(B.E.)*	— 88.9	4797.3			
	(R.E.)	—145.8	4935.1	+ 56.9	+137.8	91.7
	(Accts.)	+ 8.9	4907.6			
1970-71	(B.E.)*	+ 95.7@	5033.3@			
	(R.E.)	—224.7@	5432.9@	+320.4	+399.6	268.2

** Excluding remittances (net).

* Include yield from additional measures proposed by States and increase in transfer of resources from the Centre, viz, share in Central taxes, grants-in-aid and net loans as reflected in the revised estimates over the budget estimates of States.

@Excluding Himachal Pradesh as revised estimates for the State are not available.

B.E.—Budget Estimates.

R.E.—Revised Estimates.

Table 11 — State Government's Overall Budgetary Position and Aggregate Disbursements during 1970-71 and 1971-72

(Rupees Crores)

	1970-71			
	Budget Estimates	Revised Estimates	Variation in Revised Estimates over Budget Estimates column (2) over column (1) [Increase(+)/Decrease(—)]	1971-72 Budget Estimates
	(1)	(2)	(3)	(4)
Overall Surplus (+) or Deficit (—) of all States	+95.7@†	—224.7†	+320.4	—153.8E
Overall Surplus (+) or Deficit (—) of States having overdrafts as on March 31, 1971	+66.7@	—169.6	+236.3	
Aggregate Disbursements* of all States (a+b)	5033.3†	5432.9†	+399.6	5700.1
(a) Plan	(100.0)	(100.0)		(100.0)
(b) Non-Plan	1142.2 (22.7)	1246.8 (22.9)	+104.6	1489.3 (26.1)
Aggregate Disbursements* of States having overdrafts as on March 31, 1971 (a+b)	3095.5 (100.0)	3371.2 (100.0)	+275.7	
(a) Plan	655.3 (21.2)	748.1 (22.2)	+92.8	
(b) Non-Plan	2440.2 (78.8)	2623.1 (77.8)	+182.9	

Notes : (1) Figures in brackets are percentages to aggregate disbursements.

(2) Plan expenditure comprises expenditure on State Plans and Centrally Sponsored Schemes.

(3) The Gujarat State has treated the expenditure on Centrally-sponsored schemes as non-Plan expenditure. To ensure uniformity in presentation this has been treated as Plan expenditure.

@Include yield from additional measures proposed by States and increase in transfer of resources from the Centre, viz., share in Central taxes, grants-in-aid and net loans as reflected in the revised estimates over budget estimates of States.

EInclude yield from additional measures proposed by States (Rs. 45.3 crores) and States' share (approximately Rs. 41 crores) in Centre's additional taxation.

†Excluding Himachal Pradesh as the revised estimates for the State are not available.

*Relate to aggregate disbursements on revenue and capital accounts combines excluding remittances (net).

57. The States have been obtaining short-term ad hoc loans from the Central Government to enable them to clear their overdrafts with the Reserve Bank of India. Such ad hoc loans amounted to Rs. 378 crores during 1965-66 to 1968-69. Since 1969-70, the Central Government has initiated a scheme of special accommodation to meet the overall non-Plan gaps of some States. For this purpose Rs. 279 crores were provided in 1969-70, Rs. 195 crores in 1970-71 (revised estimates) and Rs. 120 crores in 1971-72 (budget estimates).

58. The problem of these overdrafts has been engaging the attention of the Bank. The Fifth Finance Commission (1968) which examined the problem of unauthorised overdrafts of certain States with the Reserve Bank of India has made recommendations regarding the avoidance of unauthorised overdrafts and the procedure for dealing with such overdrafts; the Centre brought the recommendations to the notice of the State Governments.

Overall Position for 1971-72

59. For 1971-72, the overall deficits of Centre and States at the existing rates of taxation are estimated at Rs. 397 crores and Rs. 240 crores respectively. After taking into account the additional tax proposals, the deficit for the Centre for 1971-72 would be reduced to Rs. 233 crores* as compared with Rs. 230 crores for 1970-71. The State Governments are expected to end with a surplus of Rs. 39

crores as against a deficit of Rs. 225 crores in 1970-71, after taking into account the impact of additional resource mobilisation of States, shares of States in Centre's additional taxation and the net additional amount of transfers to be received by the States from the Centre. †Some State Governments have already begun taking recourse to overdrafts from the Reserve Bank of India. As on August 13, 1971 outstanding overdrafts (8 States) stood at Rs. 108.0 crores as against Rs. 52.5 crores (6 States) on August 14, 1970:

Centre's Budget for 1971-72

60. The Union Budget for 1971-72 was framed against the background of generally improved prospects in the economic situation, and also against the shortfalls in Centre's Plan outlay for second year in succession. The Finance Minister emphasised the need for timely implementation of Plan projects so as to increase the tempo of economic activity and to provide a stimulus thereby to employment. Besides stepping up the Central Sector Plan outlay by 13 per cent over 1970-71 budget, the Central Budget makes a provision of Rs. 75 crores for employment-oriented works in rural areas (Rs. 50 crores) and for creation of employment opportunities for the educated unemployed (Rs. 25 crores).

61. (For the Central Government, the aggregate receipts on revenue and capital accounts for 1971-72 (including yield

*This does not take into account impact on budgetary position of net expenditure of Rs. 150 crores for relief to refugees from East Bengal provided for in the Supplementary Demands for Grants.

†Including Rs. 100 crores of grants-in-aid to State Governments provided under the Supplementary Demand for Grants for 1971-72 to meet the additional expenditure on account of refugees from East Bengal.

from additional tax measures) are estimated at Rs. 6,244 crores, showing a rise of 5.4 per cent over 1970-71 Table 12). Tax revenues, inclusive of the yield from fresh tax measures, show an increase of 11.3 per cent over 1970-71. Net domestic market borrowing and small savings are placed higher in the budget than in 1970-71, whereas the budgeted amount of net external borrowings will be the lowest for any year since 1964-65. Aggregate disbursements at Rs. 6,477 crores show an increase of 5.3 per cent (Rs. 324 crores) over 1970-71. The increase is entirely under revenue expenditure which at Rs. 3,527 crores is placed Rs. 385 crores higher than in 1970-71; an increase of Rs. 60 crores is on account of 'tentative' provision for relief to evacuees from East Bengal*. A part of the increase in revenue expenditure will be offset by reduction of Rs. 61 crores in capital disbursements. Since aggregate receipts and dis-

bursments are expected to rise almost by the same magnitude, the overall deficit at Rs. 233 crores is only nominally higher than the overall deficit in 1970-71 (Rs. 230 crores). The overall deficit will constitute 3.6 per cent of aggregate disbursements as against 3.7 per cent in 1970-71.

*Since credit is taken 'for the present', for external assistance of Rs. 20 crores on revenue account, net budgetary impact on account of relief to evacuees will be Rs. 40 crores. In addition, the Supplementary Demands for Grants provide for an expenditure of Rs. 200 crores for relief to refugees from East Bengal for the period upto end-December 1971; it also takes credit for Rs. 50 crores by way of external assistance. Thus the net budgetary outgo on this account would be Rs. 150 crores.

Table 12—Overall Budgetary Position of Centre

								(Rupees Crores)			
								1969-70	1970-71	1970-71	1971-72
								(Accounts)	(Budget Estimates)	(Revised Estimates)	(Budget Estimates)
								(1)	(2)	(3)	(4)
I. Aggregate Receipts (A+B)								5667	5573	5923	6080
A. Revenue Receipts								3027	3241	3340	3503
of which :											(6244)
Tax Revenue								2201	2390	2442	2553
											(2717)
B. Capital Receipts								2640	2332	2583	2577
of which :											
Internal Market Borrowings (Gross)								536	455	427	500
External Borrowings* (Gross)								633	719	681	666
II. Aggregate Disbursements								5713	5800	6153	6477
of which :											
(a) Development outlay								889	1152	1047	1178
(b) Non-Development outlay								2073	2158	2435	2409
(c) Discharge of internal loans								393	293	291	332
(d) Discharge of external loans								179	200	196	216
III. Overall Deficit (I—II)								(—46)	(—)227	(—)230	(—)397
											[(—)233**]

Note : (i) Figures in brackets are after taking into account the estimated yield from additional tax measures.

(ii) Figures given here do not tally with those in the budget papers as certain adjustments have been made.

* Including P.L. 480 Loans.

** This excludes the net impact of Supplementary Demands for Grants (Rs. 150 crores) for relief to refugees from East Bengal.

Plan Outlay

62. The Plan outlay of the Centre and States is estimated at Rs. 3024 crores for 1971-72; this amount is nearly Rs. 400 crores higher than the corresponding provision for 1970-71 and about Rs. 600 crores higher than the likely Plan expenditure in 1970-71. The Central budget makes provision for Rs. 2135 crores for Plan outlay showing an increase of Rs. 229 crores (12 per cent) over 1970-71 (budget estimates). This is mainly accounted for by a step-up in the provision for the Central sector Plan in the budget by Rs. 155 crores (to Rs. 1350 crores) and an increase of Rs. 67 crores in Central assistance for State Plan schemes. Sectorwise, Central sector Plan provision in respect of 'agriculture and allied programmes' shows a rise of 60 per cent over the corresponding provision in the 1970-71 budget. The budget provision under 'transport and communications' shows a step-up of about 10 per cent. In regard to industry, there is a nominal increase; while provision for coal and petrochemicals is stepped up, lower provision is made for fertilisers.

Centre's Tax Measures

63. Tax proposals were framed in the budget for 1971-72, with a view, among other things, to minimising opportunities for evasion and reducing inequalities of income and

wealth. The proposals of additional taxation are estimated to yield Rs. 205 crores (including States' share of Rs. 41 crores) in 1971-72. Besides, additional revenue on account of changes in postal tariffs is estimated to be Rs. 10.8 crores in a full year and upward revision in freight rates and passenger fares by Railways are expected to yield Rs. 26 crores in 1971-72 (Rs. 35 crores in a full year); these, however, do not accrue to the Centre.

64. Of the total estimated additional revenue in 1971-72, taxes on commodities and services (including tax on foreign travel) account for 86.8 per cent. There are 24 new items, including consumer goods as well as producer goods, on which excise duty at ad valorem rates is levied for the first time. The rate structure in respect of import duty is simplified by prescribing four ad valorem rates of import duty in place of seven. The rate of surcharge on personal income-tax is raised from 10 to 15 per cent on incomes exceeding Rs. 15,000. The rate of tax on net wealth above Rs. 15 lakhs is raised to 8 per cent from the existing rates of 4 and 5 per cent on slabs of net wealth between Rs. 15 lakhs and Rs. 20 lakhs and above Rs. 20 lakhs, respectively. The rate of surtax leviable on company profits remains unchanged at 25 per cent for profits upto 15 per cent of capital; in respect of profits exceeding this limit, the rate of tax is raised to 30 per cent. The incidence of tax on long-term capital gains is also raised.

65. The development rebate was introduced in 1955-56 in respect of new investment in plant or machinery installed and new ships acquired after March 31, 1954. No development rebate would be allowed on ships acquired or machinery or plant installed after May 31, 1974. The list of priority industries is curtailed by deleting certain industries from the list and the special tax exemption in respect of profits of priority industries is reduced. For computing tax-exempt profits under the "Tax Holiday" provisions, debentures and long-term borrowings will be excluded from the term "capital employed". These measures are estimated to yield Rs. 22 crores in a full year. As regards concessions to personal savings, the monetary ceiling in respect of savings through life insurance premia, provident fund contributions, etc., qualifying for deduction from taxable income, is raised from Rs. 1,5000 to Rs. 20,000 in the case of individuals and some modifications are made in the computation of tax relief in this behalf. The exemption of income upto Rs. 3,000 derived from specified financial assets will now include interest on members' deposits with co-operative societies; the relief will now be confined to individuals and Hindu Undivided Families. Standard deductions in respect of assessee other than those who own motor cars is raised.

State Budgets for 1971-72

66. The aggregate receipts on revenue (at 1970-71 rates taxation and capital accounts budgeted by the State Gov-

ernments at Rs. 5,464 crores for 1971-72 represent 4.9 per cent (Rs. 256 crores) rise over 1970-71 (Table 13). States' own tax revenues are estimated to rise by 6.6 per cent to Rs. 1607 crores in 1971-72. Aggregate disbursements are placed at Rs. 5704 crores in 1971-72 showing 5.0 per cent (Rs. 271 crores) increase over 1970-71. The increase in the projected level of disbursements is mainly due to stepped-up provision for development expenditure which at Rs. 2,950 crores is 13.5 per cent higher than in 1970-71 and will constitute a little over one-half of aggregate disbursements in 1971-72 (as against 47.9 per cent in 1970-71). The budgeted amount of non-development expenditure (Rs. 1632 crores) shows an increase of Rs. 67 crores over 1970-71, and other disbursements, comprising mainly loans and advances by States, repayment of loans to Centre and market loans are expected to decline by over 11 per cent from 1970-71.

67. For 1971-72, budgetary transactions of the State Governments (without taking into account the yield from proposals for fresh resources) are expected to end up with an overall deficit of Rs. 240 crores; this is the net result of a deficit of Rs. 267 crores on capital account and a surplus of Rs. 27 crores on revenue account. Taking into account the expected yield of Rs. 45 crores from the proposed additional resource mobilisation of some of the States and their share of Rs. 41 crores in Centre's fresh tax effort, the overall deficit gets reduced to Rs. 154 crores. Further, if adjustment is made for net additional amount to be received by them from

Table 13—Overall Budgetary Position of States

								(Rupees Crores)	
								1969-70 (Accounts)	1970-71 (Budget Estimates)+
								1970-71 (Revised Estimates)	1971-72 Budget Estimates)*
								(1)	(2)
								(3)	(4)
I. Aggregate Receipts (A + B)								4957	4918
A. Revenue Receipts (i + ii)								3172	3430
(i) States' own Revenue Receipts								2015	2144
of which :									
Tax Receipts								1356	1446
(ii) Resources transferred from the Centre (a + b)								1157	1286
(a) Shared Taxes								625	728
(b) Grants from Centre								532	558
B. Capital Receipts (i + ii)								1785	1488
(i) States' own Capital Receipts								755	694
of which :									
Market Borrowings (Gross)								173	152@
(ii) Loans from Centre (Gross)								1030	794
II. Aggregate Disbursements								4948	5052
of which :									
(a) Developmental Outlay								2251	2468
(b) Non-Developmental Outlay								1481	1470
(c) Repayment of Loans to Centre								608	610
(d) Loans and Advances to Third Parties								432	394
(e) Repayment of Market Loans								85	62
III. Overall Surplus (+) or Deficit (—) (I—II)								+9	—134
									—225
									—240
									(—154)

Note : Figures given here do not tally with those given in the budget papers as certain adjustments have been made here.

+ Include the effect of budget proposals.

* Figures in brackets are after taking into account estimated yield from budget proposals.

@ Exclude receipts from market loans floated by Bihar and Maharashtra (Rs. 27 crores).

the Centre (Rs. 193 crores*) the State Governments will have a Surplus of Rs. 19 crores† as against the overall deficit of Rs. 225 crores in 1970-71.

68. Seven State Governments namely, Andhra Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Mysore, Nagaland and Orissa, have proposed measures to raise additional resources; Kerala, Rajasthan and Tamil Nadu have proposed measures as also granted fiscal concessions. In the net, additional measures are expected to yield in 1971-72 Rs. 45.3 crores (inclusive of measures to streamline administration and recovery of arrears); Haryana has, however announced only a minor tax concession but the loss in tax revenue is negligible.

Market Borrowings

69. The combined net receipt from market borrowings by Centre and State Governments in 1970-71 amounted to Rs. 235 crores—Rs. 11 crores more than those in 1969-70. Net borrowings by the States in 1970-71 were Rs. 17 crores more than in 1969-70 whereas those of the Centre were Rs. 6 crores lower than in 1969-70.

70. As in the past, the Centre's borrowing programme for 1970-71 was completed in two phases. Total subscriptions in regard to the 5½ per cent 2000 Loan floated on April 11, 1970 for an aggregate amount of Rs. 275 crores amounted to Rs. 290 crores comprising Rs. 150 crores in cash and Rs. 140 crores by way of conversion. The 4-1/2 per cent Loan 1977 and the 5-1/2 per cent 2000 Loan (re-issue) issued on October 15, 1970 for a total sum of Rs. 125 crores brought in together Rs. 138 crores (Rs. 76 crores in cash and Rs. 62 crores by way of conversion). Of the total amount of Rs. 293 crores of maturing loans, the amount offered for conversion was Rs. 202 crores. After providing for cash repayments of the unconverted portion of maturing loans (Rs. 91 crores), net market borrowings of the Centre during 1970-71 aggregated Rs. 135 crores—Rs. 27 crores less than the amount (Rs. 162 crores) originally budgeted for.

71. For 1971-72, the Centre Budget has taken credit for Rs. 500 crores (gross) as receipt from market borrowings. The first phase of the Central Government's market borrowing programme was completed on July 1, 1971, when three loans were floated for a total amount of Rs. 375 crores; total subscriptions amounted to Rs. 405 crores (Rs. 298 crores in conversion and Rs. 107 crores in cash).

72. On July 15, 1970 fifteen State Governments issued 5-3/4 per cent Development Loans maturing after 12 years for an aggregate amount of Rs. 142.50 crores. All the loans were issued at par. Maturing loans of 12 States for a total amount of Rs. 57 crores were offered for conversion into their respective loans. All the loans were over-subscribed as in the last year; the over-subscription exceeded 10 per cent of the notified amount. After making partial allotment, subscriptions amounting to Rs. 157 crores were accepted; of this, cash subscription amounted to Rs. 125 crores and conversion, Rs. 32 crores. After providing for cash repayments (Rs. 25 crores) on account of maturing loans not tendered for conversion, net borrowing amounted to Rs. 100 crores in 1970-71 as against Rs. 83 crores in 1969-70.

Collection from Small Savings

73. Net collections from small saving during 1970-71 are placed at Rs. 188½ crores compared with Rs. 129 crores

*The State Governments have taken credit for smaller amounts of grants and net loans and slightly larger amount of shares in taxes in their budgets than the respective amounts shown in the Central Government Budget. The net additional amount to be received from the Centre includes Rs. 100 crores of grants-in-aid to State Governments provided under the Supplementary Demand for Grants for 1971-72 to meet the additional expenditure on account of refugees from East Bengal.

†The position in 1971-72 may further improve if receipts from market loans (Rs. 27 crores) floated by Bihar and Maharashtra, for which credit is not taken in their budgets, are taken into account.

‡Net collections from small savings are now estimated at Rs. 197 crores for 1970-71 for which break-up is not yet available.

realised during the year 1969-70; the provisional figures of total (net) collections exceeded the revised estimates for 1970-71 by Rs. 43 crores. Out of total net collection of Rs. 188 crores, a little less than two thirds (about 65 per cent) was accounted for by the two new saving media, viz., Post Office Time Deposit Scheme Rs. 73 crores) and National Savings Certificates—II issue Rs. 50 crores). For 1971-72, the Union Budget has taken credit for Rs. 180 crores from this source. There were no additions to the existing media of small savings during this year. But consequent upon the change in the Bank rate, the interest rates on all the existing media were enhanced with effect from January 15, 1971. The changes in the interest rates thus effected range from ½ per cent to ¾ per cent on the different small savings scrips. Moreover the limits of deposits in the 7-year National Saving Certificates (II and III issues taken together) have been increased from Rs. 25,000 to Rs. 50,000 for individual holding and from Rs. 50,000 to Rs. 1,00,000 for joint holding with effect from August 1, 1971.

74. Net receipt from Public Provident Fund Scheme estimated at Rs. 5 crores in the 1970-71 budget are placed at Rs. 2.5 crores in the Revised Estimates. However, actual collection amounted to Rs. 4.6 crores as compared with Rs. 2.5 crores in 1969-70. The collection under this item are placed at Rs. 4 crores for 1971-72.

Gilt-edged Market

75. The gilt-edged market remained generally steady during the first half of the year under review while in the second half, following the Bank rate rise an easy trend set in. The R. B. I.'s All India Index for Government and Semi-Government securities (Base: 1961-62-100) remained unchanged at the end-June 1970 level of 99.3 till the first week of November 1970 and slid down to 98.9 by end-December 1970. With the stepping up of the Bank rate by a full percentage point with effect from January 9, 1971, prices in the gilt-edged market eased further, the Index declining to 98.2 by end-January and 97.6 by end-June 1971. While the Index for Central Government Securities slipped down by 2.1 points to 96.9 over the year, those for State Government and semi-Government Securities declined by 0.2 point and 0.1 point to 100.3 and 101.2, respectively. The Bank's open market operations continued to be directed towards maintaining orderly conditions in the market and alignment of the yield pattern to the prevailing structure of interest rates through adjustments in its buying and selling rates. Purchases and sale of securities by the Bank during the accounting year aggregated Rs. 275.7 crores and Rs. 359.8 crores respectively, resulting in net sales of Rs. 84.1 crores, as compared with the net sales of Rs. 30.0 crores in the preceding year.

Private Corporate Sector

76. New investment activity in the private corporate sector did not indicate any clear upturn during the year under review. The slower pick-up in public sector investment expenditure appeared to have caused a slackening to some extent in new investment activity in the private corporate sector. In regard to financing of investment, as compared with 1969-70, there was greater dependence on loan finance, resulting in larger financial assistance sanctioned and disbursed by the term-lending institutions, while new capital issues were substantially lower. As regards the actual capital raised, there was a rise in respect of equity and preference shares while capital raised through debentures showed a sharp decline. Public response to new issues was encouraging. Corporate performance, as indicated by a preliminary study of dividend announcements, showed some improvement. The equity prices scaled new heights in October 1970 but reacted thereafter and remained subdued during the greater part of the year.

Capital Consents

77. There was a decline in consents/acknowledgements of proposals accorded to non-Government public limited companies for new capital issues in the form of shares (excluding bonus) and debentures. The amount consented at Rs. 52.58 crores in 1970-71 (July-June) was considerably lower than Rs. 89.0 crores in 1969-70. A substantial part of the decline was in respect of consent for 'further'

§Provisional.

issues, which were lower at Rs. 31.9 crores as against Rs. 69.6 crores in 1969-70. Contents for 'initial' issue were slightly higher at Rs. 20.5 crores than Rs. 19.5 crores in the previous year. Security-wise, consents were granted for equity issues of Rs. 32.5 crores and debentures of Rs. 11.6 crores in 1970-71 as against Rs. 43.4 crores and Rs. 37.8 crores, respectively, in 1969-70. Consents for the issue of preference shares at Rs. 8.3 crores were marginally higher than Rs. 7.8 crores in the previous year.

78. As regards bonus issues, it may be recalled that Government had issued new guidelines for finalising proposals made since April 1970. During 1970-71 (July-June) consents accorded to non-Government public limited companies for bonus issues declined to Rs. 34.1* crores from Rs. 45.4 crores in the previous year. The guidelines for issue of bonus shares were further amended in May 1971 with a view to protecting the interests of general investors. According to the latest amendments, the proportion of residual reserves required to be retained after the proposed capitalisation has been raised from 20 per cent to 33-1/3 per cent of the increased paidup capital of the company. It is also stipulated that along with the proposal for issue of bonus shares, the management should give clear indication of their intention regarding the first annual dividend payable on the expanded capital of the company and obtain the shareholders' approval for it.

New Issue Activity

79. The new capital issues activity slackened during July 1970-June 1971. The amount of capital issued through prospectuses and rights was lower at Rs. 50.7 crores* than

Rs. 81.5 crores in 1969-70 (July-June). Security-wise, the decline was mainly in debentures, though equity and preference issues were also lower to some extent. Besides, the decline was exclusively under 'further' issues which fell sharply to Rs. 17.0 crores from Rs. 54.2 crores in 1969-70. 'Initial' issues, on the other hand, continued to show a rising trend and were higher at Rs. 33.7 crores than Rs. 27.3 crores in 1969-70. Consequently, 'initial' issues constituted a major proportion of the total new issues made during 1970-71. Public response to capital issues indicated further improvement and a number of issues were oversubscribed. Institutional underwriters provided the bulk of underwriting support, but available data indicate that with improvement in public response, the proportion of the amount devolving on underwriters declined to 23.4 per cent of the total amount underwritten in 1970 from 27.6 per cent 1969.

Assistance by Term-lending Institutions

80. Term-lending institutions sanctioned substantially higher financial assistance during 1970-71 (April-March) than in 1969-70. Aggregate financial assistance sanctioned by these institutions** in the form of loans, underwriting of and direct subscriptions to shares and debentures increased to Rs. 231.7* crores from Rs. 153.6 crores in 1969-70 (April-March). Disbursements† amounted to Rs. 147.5* crores as against Rs. 115.5 crores in 1969-70. The Industrial Development Bank of India (IDBI) sanctioned a substantially higher amount or loans*** amounting to Rs. 80.3* crores during April 1970-March 1971 as against Rs. 46.9 crores in April 1969-March 1970 and its disbursements were also higher at Rs. 51.1* crores as compared with Rs. 43.3 crores.

@Including disbursements on account of guarantees.

***Including refinance to banks and rediscounts.

Table 14—Financial Assistance Sanctioned and Disbursed by Term-Lending Institutions during 1969-70 and 1970-71

Name of the Institution	(Rupees Crores)											
	Loans				Underwriting of and Direct Subscription to Shares and Debentures				Total			
	1970-71		1969-70		1970-71		1969-70		1970-71		1969-70	
	Sanc-	Dis-	Sanc-	Dis-	Sanc-	Dis-	Sanc-	Dis-	Sanc-	Dis-	Sanc-	Dis-
	tioned	bursed	tioned	bursed	tioned	bursed	tioned	bursed	tioned	bursed	tioned	bursed
Industrial Development Bank of India	80.3*	51.1*	46.9*	43.3*	4.3	4.7	6.2	1.8	84.6	55.8	53.1	45.1
	[17.0]	[13.7]	[7.8]	[5.7]					[17.0]	[13.7]	[7.8]	[5.7]
Industrial Finance Corporation of India	31.1	16.5†	17.2	16.4†	3.8	0.9	1.4	1.1	35.0	17.4	18.6	17.5
	(5.8)	(2.6)	(1.8)	(1.9)					(5.8)	(2.6)	(1.8)	(1.9)
Industrial Credit and Investment Corporation of India	37.6	26.1	17.9	16.1	5.4	3.1	4.9	3.7	43.0	29.2	22.8	19.8
	(28.0)	(21.5)	(13.7)	(11.8)					(28.0)	(21.5)	(13.7)	(11.8)
State Financial Corporations	48.8	32.7†	32.9	21.4†	0.5	0.3	0.5	0.3	49.3	33.0	33.4	21.7
State Industrial Development Corporations **	16.3	9.2	20.3	7.5	3.5	2.9	5.4	3.9	19.8	12.1	25.7	11.4
Total	214.1	135.6	135.2	104.7	17.5	11.9	18.4	10.8	231.7	147.5	153.6	115.5
Unit Trust of India	—	—	—	—	15.2	8.4	9.9	8.1	15.2	8.4	9.9	8.1
Life Insurance Corporation of India‡	—	—	2.6	1.7	—	—	10.8	10.1	—	—	13.3	11.8

Note : (i) Figures in brackets relate to foreign currency loans. (ii) Data for 1970-71 are provisional.

*Comprising direct loans; refinance to banks and rediscounts; refinance to SFCs indicated separately within square brackets is excluded to avoid double counting since this is covered under loans of SFCs.

†Including disbursements on account of guarantees.

**Data relate to 10 SIDCS, the GIIC and the SICOM.

‡Figures for 1970-71 are not available.

81. The Life Insurance Corporation and the Unit Trust of India continued to lend support to the private corporate sector by their underwriting and investment operations. The Unit Trust of India provided during 1970-71 (April-March) a larger assistance of Rs. 15.2^{*} crores by way of underwriting of, and direct subscriptions to shares and debentures as compared with Rs. 9.9 crores in the previous year. The Life Insurance Corporation had sanctioned Rs. 10.8 crores during 1969-70 (April-March) for the underwriting of, and direct subscription to shares and debentures as against Rs. 14.4 crores in 1968-69 (April-March).

82. A reference was made earlier to the Dutt Committee's Report regarding the development of "joint sector" in Indian industry. In pursuance of the Committee's recommendations, Government announced on May 1, 1971 certain guidelines for conversion of loans into equity in respect of such industrial units which receive large financial assistance from the all-India long-term financial institutions. According to these guidelines, the financial institutions while sanctioning rupee loans of Rs. 50 lakhs and more to one company would normally provide, in the loan covenant, for the option of converting loan into equity consistent with the maintenance of a reasonable debt-equity ratio. In respect of loans ranging between Rs. 25 lakhs and Rs. 50 lakhs, the financial institutions may use their discretion and in cases of loans not exceeding Rs. 25 lakhs, the institutions may not stipulate for the conversion of loans into equity.

83. Thus, an increasingly active role is envisaged for public sector in the field of industrial development, and in this connection, mention may be made of the Reserve Bank's directive to commercial banks stipulating that in the event of their granting or renewing a credit limit of over Rs. 50,000 against the security of shares to a borrower, the shares so pledged should be transferred to their names and that they should have exclusive voting rights in respect thereof. Towards the end of the year under review, the management of all general insurance companies was also taken over by Government.

Equity Prices

84. On the major stock exchanges, the rising trend in equity prices noticed since mid-February 1970 was accelerated in the following months, culminating in a new peak level in the first week of October, 1970. The market sentiment was favourably influenced by the investment incentives provided in the Union Budget for 1970-71, scarcity of good floating scrips, favourable monsoon and prospects of improved crop output and sustained flow of encouraging corporate news. The Reserve Bank's All-India Index of Prices of Variable Dividend Industrial Securities (Base: 1961-62-100) spurted up from 100.0 during the week ended June 27, 1970 to a new peak of 110.1 by October 3, 1970. Prices, however, tended to drift lower thereafter upto the first week of January 1971 when the equity Index reached the level of 101.4. Though the Bank rate was raised, effective from January 9, 1971, the flow of encouraging corporate news imparted some steadiness to equity prices in the remaining weeks of January 1971. Thereafter, prices again turned easy and by June 26, 1971, the equity price Index moved down to 97.5, recording a fall of 11.4 per cent from the peak level reached on October 3, 1970. Over the accounting year also, the Index showed a fall of 2.5 per cent as compared with the rise of 0.7 per cent during 1969-70 (July-June). The bearish factors which affected the market sentiment were: the reported difficulties experienced by cotton textile mills on account of sharp rise in raw cotton prices; apprehensions regarding conversion of loans provided by public financial institution to companies into equities; the Government instructions to the stock exchanges to square-up all outstanding forward business; and the Union Budget proposals for 1971-72, which were considered by the market as not very encouraging to the private corporate sector.

Corporate Dividends

85. A preliminary study of dividend announcements by public limited companies indicates that corporate performance during 1970-71 was somewhat better than in 1969-70. Of the 630 public limited companies which closed their accounts between April 1970 and March 1971, 200 or 32 per cent of

the companies raised their dividend rates in 1970-71 as against 195 or 31 per cent in 1969-70; the number of Companies which maintained dividends at the same rates as in the previous year was 198 or 31 per cent as against an equal number in 1969-70. Of the remaining 232 companies, 100 companies or 16 per cent reduced their dividends, the corresponding figures for the preceding year being 79 companies or 13 per cent. On the other hand, the number of companies paying 'nil' dividends was lower at 132 or 21 per cent in 1970-71 as against 158 or 25 per cent last year. In regard to actual rates of dividends, there was a market increase in the number of companies paying dividends between 11 and 20 per cent from 186 (30 per cent) in 1969-70 to 216 (34 per cent) in 1970-71. The number of companies paying dividends between 6 and 10 per cent was lower at 188 (30 per cent) as against 202 (32 per cent) last year, while those paying dividends above 20 per cent constituted 3 per cent of the total number of companies in both the years.

Investment Finance for Agriculture

86. The tempo of investment in agriculture financed by various institutional agencies gained further momentum during the year under review. Finance provided in the form of disbursements for agricultural schemes by ARC, AFC and REC and draws from the Reserve Bank's medium-term loans and debentures floated by Central Co-operative Land Development Banks together showed a substantial increase during 1970-71 over the level in 1969-70. Disbursements made by AFC showed some fall while those by ARC registered an increase. Draws from Reserve Bank's medium-term loans maintained the previous year's level. The Rural Electrification Corporation made during the year a maiden disbursement of as much as Rs. 26.04 crores. The year under review experienced a fewer number of schemes sanctioned and lower levels of commitments made by ARC and AFC, while the REC's sanctions and commitments showed a sharp increase (Table 15). Commercial banks' lendings to agriculture for medium-term purposes also made a considerable headway; so also the medium-term loans disbursed by the Central and State Co-operative banks.

Trends in Money Supply

87. The year 1970-71 (July-June) was characterised by a markedly higher increase in money supply with the public (Rs. 814 crores) than in the preceding year (Rs. 592 crores). The growth rate during the year worked out to 12.3 per cent as compared with 9.8 per cent in 1969-70. Total monetary resources which comprise money supply and time deposits with the banks, also registered a larger increase of Rs. 1363 crores or 14.0 per cent as against Rs. 1011 crores or 11.6 per cent (Table 16). There was thus a considerable step-up in aggregate demand in the economy. Component-wise, absolute increase in currency continued to be larger than that in demand deposits, but in terms of growth rates, deposit money showed a considerably higher rate than currency. Time deposits increased even faster, both in terms of absolute figures and rate of growth, than either currency or demand deposits. Of the total increase in aggregate monetary resources, time deposits accounted for 40.3 per cent while currency with the public and deposit money accounted for 31.3 per cent and 28.4 per cent, respectively.

88. Among the factors accounting for monetary expansion during 1970-71, net bank credit to Government, with the phenomenal increase of Rs. 924 crores, was a predominant factor reflecting generally the growing imbalance in the budgetary operations and particularly the problem of overdrafts by the State Governments. Bank credit to the commercial sector showed a smaller expansion both in absolute terms as well as in terms of the growth rate. The rate of expansion was not uniform throughout the year; the expansion was of a considerably higher order during the first half of the accounting year July-December 1970 (Rs. 330 crores) than during the corresponding half of 1969 (Rs. 153 crores), while during the second half the trend was reversed with an expansion of only Rs. 299 crores during January-June 1971 as against Rs. 602 crores during January-June 1970. The expansionary impact of these factors was offset, to some extent, by (i) a decline of Rs. 97 crores in net foreign exchange assets of the banking sector, which in 1969-70 had recorded an increase of Rs. 264 crores, and (ii) a rise of Rs. 110 crores in net non-monetary liabilities of the banking system. The reduction in net foreign assets reflects partly a pick-up in

*Provisional

Table 15—Investment Finance for Agriculture
(July—June)

(Rupees Crores)

	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
1. Debentures floated by Central Co-operative Land Mortgage/Development Banks ¹											
(a) Ordinary debentures ..	9.97	10.50	19.25	23.34	34.81	43.10	52.05	64.51	103.82	114.82*	119.49
(b) Rural debentures ..	1.55	2.24*	1.57	1.84	3.23	4.33	2.93	1.57	5.00	1.10	4.78
2. Agriculture Refinance Corporation (ARC) ²											
(a) No. of schemes sanctioned				3	10	24	15	89	108	142	100
(b) Total outlay ..				2.72	20.60	17.96	10.53	68.16	79.21	92.78	62.15
(c) ARC's commitments ..				2.45	16.88	14.18	8.53	58.64	69.32	70.92	53.92
(d) Disbursements during the year				—	0.45	4.45	2.08	5.67	17.84	28.60	30.62
3. Agricultural Finance Corporation (AFC) ³											
(a) No. of schemes sanctioned									6	21*	10
(b) Total outlay ..									61.50	45.70*	23.33
(c) Disbursements during the year									0.96*	15.77*	13.24
4. Rural Electrification Corporation (REC) ⁴											
(a) No. of schemes sanctioned										49*	74
(b) Total outlay ..										32.01*	49.71
(c) REC's commitments										29.79*	49.38
(d) Disbursements during the year										—	26.04
5. Reserve Bank of India Medium-term loans											
(a) Amount sanctioned ..	4.68	9.56	9.31	14.01	14.39	14.11	15.49	16.57	19.00	18.30	18.76
(b) Drawals during the year	5.69	7.39	4.18	7.45	7.91	7.45	8.37*	9.12	8.98*	11.48	11.38

Note : Figures of investment finance made available by commercial banks other than by way of contribution to the debentures floated by central co-operative land mortgage / development banks and participation with the Agricultural Finance Corporation, are not available. Similarly, figures of investment finance provided by co-operative credit agencies out of their owned funds are also not available.

1. Co-operative land mortgage/development banks also floated special development debentures to the extent of Rs. 18.00 lakhs in 1961-62, Rs. 5.41 lakhs in 1963-64, Rs. 1.45 lakhs in 1965-66, Rs. 1.23 lakhs in 1966-67, Rs. 0.32 lakh in 1967-68 and Rs. 0.18 lakhs in 1968-69. While the first series of special development debentures were floated prior to the inception of A.R.C., the remaining series were those not falling under A.R.C. schemes.

2. The operations reflect schemes sanctioned during the year after excluding schemes within drawn during the same year. In earlier Reports operations of each year were presented after taking into account : (i) withdrawals made during the same year and also withdrawals made in subsequent years, (ii) reductions in the financial outlays made in subsequent years and (iii) rephasing of schemes, if any. As on June 30, 1971 after accounting for withdrawals and rephasing of schemes, the cumulative number of schemes sanctioned as 458 involving financial assistance of Rs. 293.00 crores, the Corporation's commitments being Rs. 248.66 crores.

3. The data presented relate to schemes sanctioned during the year after taking into account cancellations of schemes and changes in outlays, if any, during the same year but without taking into account cancellation of schemes and changes in outlays, if any, subsequently. After taking into account these factors, since its inception, i.e., from April 1, 1968 to June 30, 1971, the Corporation sanctioned 33 scheme involving a total outlay of Rs. 128.08 crores and disbursed an amount of Rs. 29.97 crores.

4. Of this, three schemes in 1969-70 and two in 1970-71 related to Rural Electric Co-operatives.

*Revised.

Table 16—Trends in Money Supply and Monetary Resources (Annual)

(Rupees crores)

	Variations during July-June		
	1968-69	1969-70	1970-71
1. Currency with the Public	+341 (+9.9)	+381 (+10.1)	+427 (+10.2)
2. Demand Deposits	+225 (+11.1)	+211 (+9.4)	+387 (+15.7)
3. Money Supply (1+2)	+566 (+10.3)	+592 (+9.8)	+814 (+12.3)
4. Time Deposits	+473 (+21.5)	+419 (+15.6)	+549 (+17.7)
5. Total Monetary Resources (3+4)	+1039 (+13.5)	+1011 (+11.6)	+1363 (+14.0)
6. Net Bank Credit to Government	+433 (+9.9)	+2 (—)	+924 (+19.2)
7. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector	+153@ (+84.6)	+264 (+66.0)	—97 (—14.6)
8. Government's Net Currency Liabilities to the Public	+33 (+10.4)	+20 (+5.6)	+18 (+4.8)
9. Total (6+7+8)	+619@ (+12.7)	+286 (+5.1)	+845 (+14.4)
10. Bank Credit to Commercial Sector*	+641 (+17.6)	+755 (+17.7)	+629 (+12.5)
(a) Net Bank Credit to Commercial Sector*	+167 (+11.7)	+336 (+21.1)	+80 (+4.1)
11. Net Non-Monetary liabilities of R.B.I. (Increase—)	—95@	—60	—177
12. Net Non-Monetary Liabilities of other banks (Increase—)	—125	+29	+67
13. Total (9+10)	+1260@ (+14.8)	+1041 (+10.6)	+1474 (+13.5)

Note : Figures in brackets represent percentage variations.

@ Excluding changes due to revaluation of gold held in the Issue Department of the Reserve Bank with effect from February 1, 1969.

* Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for commercial purposes.

imports following import liberalisation and partly a larger decline in aid utilisation following shrinkages in both aid-financed food imports and non-project aid, discussed in subsequent paragraphs.

Seasonal Trends

89. During the slack season of 1970 (May-October), money supply with the public registered a contra-seasonal expansion of Rs. 143 crores as against a contraction of Rs. 58 crores in the 1969 slack season (Table 17). The expansion in money supply stemmed mainly from an increase of Rs. 111 crores in net bank credit to Government and an accrual of Rs. 36 crores to net foreign exchange assets of the banking system. Bank credit to the commercial sector also contributed significantly to the monetary expansion.

90. Seasonal expansion in money supply during the busy season of 1970-71 (November 1970—April 1971) was, however, smaller at Rs. 572 crores (8.5 per cent) as compared with the increase of Rs. 703 crores (12 per cent) during the 1969-70 busy season. Rise in currency component at Rs. 400 crores was Rs. 117 crores smaller than that in the last busy season. Increase in demand deposits was also smaller by Rs. 14 crores. Increase in time deposits was, however, Rs. 81 crores larger than in the 1969-70 busy season.

91. Increase in net bank credit to Government during the 1970-71 busy season was markedly larger at Rs. 620 crores as against the rise of Rs. 130 crores in

Rs. 130 crores in the last busy season. However, foreign exchange assets declined by Rs. 85 crores, whereas in the previous busy season there was a rise of Rs. 168 crores. Adjusting for the increase in time deposits, expansion in net bank credit to the commercial sector at Rs. 204 crores in the 1970-71 busy season was smaller than that at Rs. 438 crores in the preceding busy season. Bank credit for procurement of food-grains increased by Rs. 70.3 crores during the period. Expansion of bank credit to the commercial sector during the first two months of the busy season. (November-December 1970) was relatively of a higher order (Rs. 199 crores) than during the subsequent four months (Rs. 249 crores). There was also a rise of Rs. 182 crores in net non-monetary liabilities of the banking system which had a contractionary impact on money supply. This together with the decline in net foreign exchange assets and a smaller increase in net bank credit to the commercial sector were responsible for the smaller increase in money supply during the 1970-71 busy season.

92. During the first two months of the current slack season (May-June 1971) there was a contra-seasonal expansion in money supply, as in the corresponding months of 1970 slack season. While net bank credit to Government registered a substantial rise as against a small decline in the comparable period of the previous slack season, net bank credit to the commercial sector recorded a decline as against an increase in the 1970 season.

Table 17—Trends in Money Supply and Monetary Resources (Seasonal)

	Variations during the			
	Slack Season		Busy Season	
	1969	1970	1969-70	1970-71
1. Currency with the Public	-149 (-4.0)	-34 (-0.8)	+517 (+14.3)	+400 (+9.7)
2. Demand Deposits of Banks	+91 (+4.2)	+1.77 (+7.3)	+186 (+8.3)	+172 (+6.6)
3. Money Supply (1+2)	-58 (-1.0)	+143 (+2.2)	+703 (+12.0)	+572 (+8.5)
4. Time Deposits	+248 (+9.6)	+277 (+9.2)	+163 (+5.7)	+244 (+7.4)
5. Monetary Resources (3+4)	+190 (+2.2)	+420 (+4.4)	+866 (+10.0)	+816 (+8.2)
6. Net Bank Credit to Government	-14 (-0.3)	+111 (+2.3)	+130 (+2.8)	+620 (+12.5)
7. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector	+59 (+15.4)	+36 (+5.9)	+168 (+38.0)	-85 (-13.2)
8. Government's Net Currency Liabilities to the Public	— (—)	+6 (+1.6)	+19 (+5.5)	+15 (+4.1)
9. Total (6+7+8)	+45	+153	+317	+550
10. Bank Credit to Commercial Sector*	+136 (+3.3)	+311 (+6.4)	+602 (+14.2)	+448 (+8.7)
(a) Net Bank Credit to Commercial Sector*	-111 (-7.3)	+34 (+1.8)	+438 (+31.1)	+204 (+10.9)
11. Net Non-Monetary Liabilities of R.B.I., (Increase—)	+15	+27	-77	-113
12. Net Non-Monetary Liabilities of other banks (Increase—)	-6	-71	+25	-69
13. Total (9+10)	+181 (+1.9)	+464 (+4.4)	+919 (+9.4)	+998 (+9.0)

Note : Figures in brackets represent percentage variations.

* Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for commercial purposes.

Banking Trends and Credit Policy

93. In the first half of the year under review, bank credit was expanding at a pace faster than bank deposits and, therefore, commercial banks had turned increasingly to the Reserve Bank for accommodation. Such accommodation had touched as on January 1, 1971, a record level of Rs. 351 crores, a steep increase from Rs. 150 crores as at the end of October, 1970 when the traditional slack season was to have ended and when, therefore, banks' borrowings should have been nominal. This high level of borrowings, which had been in addition to Govt's borrowings from the banking system accentuated the pressure on the general price level which had emanated from physical shortages. During this period, the general price level was about 5 to 6 per cent above the level a year ago. The Bank, therefore, tightened general credit control by raising the Bank rate from 5 to 6 per cent effective from January 9, 1971 and by stepping up the 'net liquidity ratio' from 33 per cent to 34 per cent with effect from January 29, 1971. At the same time, to assist them in deposit mobilisation, the banks were asked to raise rates of deposits by 1/4 to 1/2 percentage point. In regard to lending rates consequent upon changes in the Bank rate and the net liquidity ratio, the banks were asked to ensure that, on an average, increase in the rate charged by them on advances was only about 1 per cent. In view of the rising pressure on prices of cotton, oil-seeds and vegetable oils, selective controls on advances against these were tightened further. While all these measures had their immediate impact as reflected in a considerably reduced rate of expansion in bank credit thereafter, quantum of increase in commercial bank credit was still relatively high and, therefore, the situation was not one which could have been viewed with complacency. Therefore, in a mid-season review of the credit situation on February 4, 1971, the Governor stressed the need for continued restraint in bank credit and for greater efforts towards deposit mobilisation. Besides, with the objective of rendering the bank lending system more purpose-oriented, the Governor impressed upon banks that they have a promotional role in bringing about a more wide-spread use of bill of exchange as an instrument of credit and that the refinance facilities under the newly introduced Bill Rediscounting Scheme would be available at the Bank rate round the year. As a further concession, bills rediscounted under the Scheme after June 30, 1971 would not impair the banks' entitlement to refinance at the Bank rate irrespective of their net liquidity ratio position. Steps were also taken to expand the scope of this Scheme by including other categories of bills.

94. In furtherance of the objective of nationalisation, the flow of credit to priority and hitherto neglected sectors was accelerated. Since the nationalisation upon June 1971, roughly three fourths of deposit growth net of statutory investment has been absorbed in credit to agriculture, small industry, road transport operators, retail trade and small business, professional and self-employed persons and education. In incremental bank credit during this period, the share of advances to these sectors worked out to 68 per cent. The share of credit to these sectors rose from 14.5 per cent of total advances at the end of June 1969 to 23.8 per cent at the end of March 1971.

95. There was also a substantial rise in advances for food procurement operations which increased from Rs. 207 crores on June 26, 1970 to Rs. 379 crores on June 25, 1971. These advances increased further to Rs. 431 crores on July 30, 1971 (last Friday).

Annual Variations (July 1970—June 1971)

96. For the year as a whole, scheduled commercial banks' credit recorded a smaller expansion while deposit growth was considerably larger than in 1969-70. Banks were, therefore, in a position to increase their investment and cash balances and also repay a part of their borrowings from the Reserve Bank.

97. Total scheduled commercial banks' credit recorded during 1970-71, an increase of Rs. 563.1 crores or 13 per cent as compared with Rs. 613.9 crores or 17 per cent in 1969-70 (July-June). On the other hand, accretion to deposits amounted to Rs. 915.4 crores or 17 per cent in 1970-71 as compared with Rs. 628.7 crores or 13 per cent in 1969-70. The rate of expansion in bank credit was not uniform during the year, the increase in the earlier half of the year

at Rs. 239.8 crores being considerably higher than that in the corresponding half of the previous year at Rs. 17.1 crores, while in the latter half, the expansion was Rs. 323.3 crores as against Rs. 596.8 crores in the corresponding half of the previous year. Credit-deposit ratio at 77.2 per cent as at the end of June 1971 was 2.7 percentage points lower than the ratio a year ago (79.9 per cent). Of the total increase of Rs. 915.4 crores in deposits in 1970-71, time deposits accounted for 56.7 per cent as against 64.1 per cent of the increase in 1969-70. Increase in 1970-71 in the investments of scheduled commercial banks in Government and other approved securities by Rs. 294.7 crores was more than double that in 1969-70 (Rs. 145.3 crores). The investment-deposit ratio reached 29.0 per cent on June 25, 1971 as against 28.5 per cent on June 26, 1970. Cash and balances with the Reserve Bank of India showed, during the year, an increase of Rs. 35.9 crores as against a decline of Rs. 22.7 crores in the previous year, but on account of the steep increase in deposits, the cash ratio at 6.4 per cent actually fell by 0.4 percentage point. The outstanding level of borrowings from the Reserve Bank at Rs. 207.2 crores as on June 25, 1971 showed a fall of Rs. 84.3 crores over the level (Rs. 291.5 crores) a year ago. During the year as a whole, however, despite rise in deposits, borrowings of the commercial banks from the Reserve Bank were consistently higher than in the corresponding weeks of the previous year upto April 1971, touching a peak of Rs. 443 crores on March 19, 1971 before declining in the following weeks to Rs. 190.7 crores at the end of the 1970-71 busy season. On June 25, 1971 they were Rs. 207.2 crores as against Rs. 291.5 crores on June 26, 1970 (Table 18).

98. With strained liquidity position of banks, the call money rate in Bombay which ruled between 4 and 6 per cent during July to December 1970 started moving up in early 1971 reaching a peak of 13 per cent in the first week of February 1971, after which it came down steadily to 6 per cent on April 30, 1971. The rate at the end of June 1971 was 4-1/2 per cent as against 6-1/2 per cent at the end of June 1970. In the previous year, however, the rate ruled between 3-1/2 and 4-1/2 per cent during July 1969 to January 1970 after which it showed a continuous rise and reached 9 per cent on March 31, 1970; thereafter, it came down to 6-1/2 per cent on April 30, 1970. In Calcutta, the rate ranged between 4-1/2 to 5-1/2 per cent upto November 1970; from July 1970, it rose steadily reaching the peak of 12 per cent in February 1971 and declined thereafter to 5-1/2 per cent on April 30, 1971. In the previous year, the rate moved between 3 and 5 1/2 per cent from July 1969 upto end-February 1970, rising up later to 9-3/4 per cent on March 31; it closed at 7 per cent on April 30, 1970. The rate at the end of June 1971 was 4-3/4 per cent as against 5-1/2 per cent last year.

Seasonal Trends

99. The slack season of 1970 was marked by a virtual absence of any slackness in credit; bank credit recorded a sharp contra-seasonal expansion, and though deposits also rose substantially, strain on liquidity of the banking system was felt almost throughout the season. In the 1969 slack season also there was a contra-seasonal expansion of Rs. 31.3 crores in bank credit but in the slack season of 1970 it was much more pronounced, amounting to Rs. 225.6 crores. This increase was due both to a smaller contraction of advances against seasonal commodities as well as a larger expansion in advances against non-seasonal items. Though deposit accretion was higher, both in absolute as well as relative terms, at Rs. 448.6 crores (8.8 per cent) as against Rs. 348.1 crores (7.8 per cent) in the 1969 slack season, the credit-deposit ratio at the end of 1970 slack season at 77.0 per cent was about 4 percentage points higher than the ratio a year ago (72.9 per cent). The continued pressure on banks' resources resulted in a smaller quantum being put in investments, viz., Rs. 188 crores as against Rs. 240 crores in the previous slack season, and a smaller proportion of the borrowings from the Reserve Bank being repaid (36 per cent) than in the 1969 slack season (68 per cent).

100. In the light of the credit and price situation and in the context of the need envisaged in the Fourth Plan for reaching a certain proportion of additional deposits to be invested by banks in Government and other approved securities, Governor asked banks, in August 1970, to step up their holdings of assets that go to make the statutory liquidity ratio from 27 per cent to 28 per cent from the last Friday

Table 18—Annual Variations in Important Banking Data

(Rupees Crores)									
	End-June 1968	Variation during the year ended June 1968	End-June 1969	Variation during the year ended June 1969	End-June 1970	Variation during the year ended June 1970	End-June 1971*	Variation during the year ended June 1971	
1. Total Bank Credit	3102.9	+471.8	3598.8	+495.9	4212.7	+613.9	4775.8	+563.1	
2. Total Investments	1160.7	+90.8	1358.9	+198.2	1504.2	+145.3	1798.9	+294.7	
(a) in Government securities	975.6	+53.0	1126.3	+150.7	1186.1	+59.8	1369.4	+183.3	
(b) in other approved securities	185.1	+37.8	232.6	+47.5	318.1	+85.5	429.5	+111.4	
3. Cash and Balances with the Reserve Bank of India	269.5	+10.7	380.3	+110.8	357.6	—22.7	393.5	+35.9	
4. Money at call	50.6	—7.1	88.1	+37.5	47.9	—40.2	74.8	+26.9	
5. Aggregate Deposits	3969.0	+452.0	4645.8	+676.8	5274.5	+628.7	6189.9	+915.4	
(a) Demand	1874.8	+210.2	2103.5	+228.7	2328.8	+225.3	2725.1	+396.3	
(b) Time	2094.2	+241.8	2542.3	+448.1	2945.7	+403.4	3464.8	+519.1	
6. Borrowings from the Reserve Bank of India	103.5	+92.0	172.2	+68.7	291.5	+119.3	207.2	—84.3	

*Provisional (as on June 25, 1971).

Source: Returns submitted under Section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, except in respect of borrowings from the Reserve Bank of India which are based on borrowing advices from regional offices of the Reserve Bank of India.

Table 19—Seasonal Variations in Scheduled Commercial Banks Data

(Rupees Crores)						
	Slack Season 1969	Busy Season 1969-70	Slack Season 1970	Busy Season 1970-71	Slack Season upto June 25, 1971*	Busy Season upto June 26, 1970
1. Bank Credit	+31.3	+562.9	+225.6	+409.2	+85.5	+157.2
2. Investments in Government securities and other approved securities	+239.5	—53.8	+187.6	+128.5	+11.5	+32.9
(a) in Government securities	+208.3	—100.9	+155.3	+53.7	—4.8	+20.9
(b) in other approved securities	+31.2	+47.1	+32.3	+74.8	+16.3	+12.0
3. Cash and Balances with the Reserve Bank of India	+26.7	+7.7	+31.2	+7.9	+39.1	+42.3
4. Money at call	—25.8	—14.8	—5.6	—5.8	+41.9	+3.6
5. Aggregate Deposits	+348.1	+320.9	+448.6	+421.2	+211.2	+165.5
(a) Demand	+115.0	+171.9	+174.3	+186.3	+98.2	+62.5
(b) Time	+233.1	+149.0	+274.3	+234.8	+113.0	+103.0
6. Borrowings from the Reserve Bank of India	+67.5	+203.0	—86.0	—40.2	+16.5	+55.0

*Provisional.

Notes: (1) Data are based on weekly returns submitted by banks under Section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, except in respect of borrowings from the Reserve Bank of India which are based on weekly borrowing advices from regional offices of the Reserve Bank of India.

(2) The variations are based on the last Friday figures of April and October.

of August 1970. Simultaneously, the minimum net liquidity ratio for purposes of determining the penal rate of interest chargeable on the excess borrowings of a bank from the Reserve Bank was also raised by one percentage point to 33 per cent effective from the last Friday of August 1970. (Earlier, these ratios had been raised by one percentage point each to 27 per cent and 32 per cent, respectively from the last Friday of April 1970). Measures were also announced to regulate advances against shares with a view to preventing the use of bank finance for speculative purposes. Refinance facilities under the existing Bill Market Scheme for the 1969-70 season which were to lapse by the close of June 1970 were, however, continued beyond June 30, 1970 in respect of bank advances to priority sectors as well as for purposes of food procurement and distribution.

Credit Policy for 1970-71 Busy Season

101. The new busy season had started with an unprecedently high level of banks' borrowings from the Reserve Bank at Rs. 150 crores. Announcing the credit policy for

the busy season of 1970-71 on November 10, 1970, Governor prevailed upon the banks to step up mobilisation of deposits to meet the increasing demand for credit, particularly for the priority sectors, and assured continued availability of refinance from the Reserve Bank at Bank rate/concessional rate for all legitimate productive activities. While fully appreciating the need for credit restraint, a higher level of credit expansion in the busy season of 1970-71, as compared with the earlier years, was considered unavoidable on account of the need to maintain the tempo of economic expansion and the need to continue the provision of credit for priority sectors and backward areas. It was pointed out to the banks that their aim should be to absorb expansion of credit even in respect of priority sectors within their own deposit resources over a period of time and recourse to the Reserve Bank should be had only in the ultimate resort and as far as possible for short periods. The Reserve Bank would, however, continue to make available, discretionary accommodation in deserving cases at the Bank rate to ease liquidity pressure on banks arising from sudden or specially heavy demands of credit.

102. With a view to providing additional finance to the banking system in the busy season for normal seasonal operations, the Reserve Bank effected some changes in its system of refinance. Thus, while refinance at Bank rate/concessional rate would continue to be made available in respect of increases over a prescribed base period to the priority sectors, the base period itself, was however, moved forward and in calculating the increase in 1970-71, the base period was changed to the average level of such credit in the corresponding quarter of the previous year (1969-70 instead of 1968-69).

103. The Reserve Bank had already announced in August 1970 the introduction of the new Bills Rediscounting Scheme with effect from November 1, 1970. The scheme is expected to even out liquidity within the banking system and minimise bank's recourse to the Reserve Bank as such recourse will normally be only when the banking system as a whole is short of funds rather than when only a few banks are in need of funds. The salient features of the scheme and also the subsequent modifications are discussed in later paragraphs.

104. In regard to advances of banks for food procurement/storage/distribution purposes to the Food Corporation of India, State Governments and/or their authorised agencies, the Bank announced that refinance would be made available at the Bank rate upto 50 per cent of the increase in such advances over the actual level of such advances as on October 30, 1970. In April 1971, this refinance facility was increased to 75 per cent for the period April 9, 1971 to June 30, 1971, and was later extended till end July 1971. This facility is to be reduced to 60 per cent for August 1971 and thereafter to 50 per cent of the increase in such advances over the specified base date (October 30, 1970). The Bank also indicated that it would consider the provision of discretionary accommodation to banks at the Bank rate in deserving cases in order to ease pressure on liquidity of individual banks arising out of sudden or specially heavy demand for credit.

105. By the end of 1970, there were indications of developing pressures of credit and monetary expansion on the price situation. Thus, in the first two months of the busy season of 1970-71, credit expanded by Rs. 147.3 crores as compared with a rise of Rs. 123.3 crores in the corresponding two months of the preceding busy season. Increase in money supply over the year ended December 25, 1970 too was considerably larger at Rs. 755 crores (12 per cent) as against an increase of Rs. 647 crores in the preceding year. In December 1970, the general price level was higher by 6.5 per cent than in the corresponding month of 1969.

106. There was also an increase recourse by banks to borrowings from the Reserve Bank which recorded an increase of Rs. 152.2 crores at the end of December 1970 over the outstanding level of Rs. 150 crores at the beginning of the busy season. It was felt that with the progress of the busy season, the pressure would intensify further. It was, therefore, considered necessary to restrain the rate of credit expansion along with the provision of incentive for stimulating savings and assisting deposit mobilisation. With this end in view, the Bank rate was raised from 5 per cent to 6 per cent with effect from January 9, 1971. Following this, the minimum 'net liquidity ratio' was also raised by one percentage point from 33 per cent to 34 per cent effective from January 29, 1971. The liquidity ratio for the purpose of Section 24 of the Banking Regulation Act, together with the cash reserve requirements under Section 42 of the Reserve Bank of India Act, however, continued to remain unchanged at 31 per cent. Banks were advised that while adjusting rates of interest on their advances consequent upon these changes, they should ensure that, on an average, increase in their lending rates was only about one percentage point. As for the priority sectors, however, the Reserve Bank continued to provide refinance on the existing basis, viz., (i) at 4-1/2 per cent, irrespective of the net liquidity ratio, against the increase in credit over the specified base period in respect of export credit and credit to primary agricultural co-operative credit societies in the selected districts in terms of the scheme instituted for this purpose; (ii) at the Bank rate, irrespective of the net liquidity ratio, in regard to the increase in short-term lending to small-scale industries and

agriculturists over the specified base period and rediscounting of bills under the new Bills Rediscounting Scheme, and (iii) at the Bank rate in respect of bank advances for food procurement operations upto 50 per cent of such advances as on October 30, 1970.

107. With a view to encouraging savings and further assisting deposit mobilisation, the ceiling rates on various categories of deposits were increased. The rate on savings accounts was increased from 3-1/2 to 4 per cent. The rate on deposits for 15 days to 45 days was stepped up from 1.25 to 2.00 per cent and that on 46 days to 90 days from 2.50 per cent to 3.00 per cent. An increase of one quarter of one per cent was announced in respect of various other maturity categories of deposits upto one year and an increase of 1/2 per cent in the maturity categories of deposits for one year and over upto 5 years. The maximum rate payable was fixed at 7-1/4 per cent in respect of deposits for periods above 5 years. Smaller banks were to be allowed, as before, to quote rates slightly higher than those offered by larger banks.

108. Selective credit controls were also modified on specified commodities, wherever necessary, in the context of changed supply and price situation. Details of these measures are given in Part III of this Report.

109. At the time of the mid-term review of monetary and credit situation on February 4, 1971, the Governor while expressing satisfaction at the slowing down of the rate of expansion in bank credit and reduction in borrowings from the Reserve Bank consequent upon tightening of the credit control measures, stressed the need for continued restraint in credit and for greater efforts towards deposit mobilisation. The Governor assured the banks of availability of refinance facilities on the existing basis but made it clear that discretionary accommodation would be available at the Bank rate only in exceptional cases. While granting such accommodation, account would be taken, among other things, of efforts made by a bank towards deposit mobilisation, purposeful credit planning, its commitments towards financing of food procurement operations and the problems faced by the bank in regard to its operations in backward areas. The Governor also advised banks to exercise strict scrutiny of the purpose as well as terms and conditions of credit extended by shroffs while discounting *multani* hundis, since banks were directly lending to small borrowers on an increasing scale. With the objective of rendering the lending system of banks more purpose-oriented and related to actual needs of borrowers for a specified period of time, the Governor also advised banks, at the meeting on February 4, 1971, to initiate measures for a gradual replacement of the existing cash credit system with bills and loans. The scope of the new rediscounting scheme for bills has been expanded to include other categories of bills. The rediscounting facilities under the scheme would be available throughout the year and rediscounting of bills by banks after June 30, 1971 would not impair their net liquidity ratio. It was also decided to close, as of June 30, 1971, the existing Bill Market Scheme under which refinance was made available to banks against the security of bills, though, as mentioned earlier, the Scheme was continued in respect of bank advances for food procurement and distribution.

110. The Reserve Bank also fixed in February 1971, a maximum penal rate of 15 per cent for excess borrowing by banks. Hitherto, the rate of interest charged by the Reserve Bank increased by one percentage point above the Bank rate for a shortfall of every one percentage point or a fraction thereof in the bank's net liquidity ratio below 34 per cent. The ceiling of 15 per cent would afford relief to the banks when their borrowings from the Reserve Bank increased to such a level as to reduce their net liquidity ratio below 26 per cent. At the same time, certain safeguards were provided for giving discretionary accommodation in exceptional cases.

111. In February 1971, the basis of refinance facilities against export credit was reviewed in the context of the ceiling of 6 per cent on interest rate on export credits sanctioned by banks and with a view to reducing an element of uncertainty about the quantum of refinance available at 4-1/2 per cent and at Bank rate over the year as a whole. According to the revised arrangement, refinance was to be available irrespective of the net liquidity ratio

Table 20—Seasonal Pattern of Principal Ratios of Scheduled Commercial Banks

(Rupees Crores)

	October 1969		April 1970		October 1970		April 1971		June 1971*		June 1970	
	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage
1. Bank Credit	3492.6	72.9	4055.5	69.4	4281.1	77.0	4690.3	78.5	4775.8	77.2	4212.7	79.9
2. Investments in Government and other approved securities	1525.1	31.8	1471.3	28.8	1658.9	29.8	1787.4	29.9	1798.9	29.0	1504.2	28.5
(a) in Government securities	1266.1	26.4	1165.2	22.8	1320.5	23.7	1374.2	23.0	1369.4	22.1	1186.1	22.5
(b) in other approved securities	259.0	5.4	306.1	6.0	338.4	6.1	413.2	6.9	429.5	6.9	318.1	6.0
3. Cash and Balances with Reserve Bank	307.6	6.4	315.3	6.2	346.3	6.2	354.4	5.9	393.5	6.4	357.6	6.8
4. Money at Call and Short Notice	59.1	..	44.3	—	38.7	—	32.9	—	74.8	—	47.9	—
5. Aggregate Deposits	4788.1	100.0	5109.0	100.0	5557.6	100.0	5978.7	100.0	6189.9	100.0	5274.5	100.0
(a) Demand	2094.4	43.7	2266.3	44.4	2440.6	43.9	2626.9	43.9	2725.1	44.0	2328.8	44.2
(b) Time	2693.7	56.3	2842.7	55.6	3117.0	56.1	3351.8	56.1	3464.8	56.0	2945.7	55.8
6. Borrowings from Reserve Bank	33.5	—	236.5	—	150.5	—	190.7	—	207.2	—	291.5	—

Notes: (1) The percentages are ratios to aggregate deposits:

(2) Data are based on weekly returns submitted by banks under Section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, except in respect of borrowings from Reserve Bank of India which are based on weekly borrowing advices received from regional offices of the Reserve Bank of India. All figures relate to the last Friday of the month.

*Provisional (Refers to June 25th).

Table 21—Seasonal Trends in Bank Credit : Security-wise Classification

(Rupees Crores)

								Busy Season	Slack Season		Busy Season upto mid-April	
								1968-69	1969	1970	1969-70	1970-71†
Seasonal Advances§								+ 206.8	—192.0	—172.9	+ 116.3	+ 199.1
Paddy and Rice								+ 41.1	— 29.0	— 31.1	— 6.8	+ 20.7
Wheat								— 33.7	+ 14.4	+ 14.5	— 59.5	— 6.6
Other foodgrains								+ 9.0	— 3.1	— 30.9	+ 2.1	+ 14.1
Sugar								+ 98.9	— 44.6	— 49.9	+ 85.7	+ 73.6
Gur								+ 3.7	— 3.6	— 3.8	+ 3.6	+ 6.4
Groundnuts								+ 11.8	— 13.7	— 10.2	+ 12.2	+ 8.3
Other oilseeds								+ 13.9	—170.0	— 11.3	+ 9.0	+ 7.3
Vegetable oils								+ 1.6	— 10.2	— 8.9	+ 12.4	+ 15.3
Cotton and kapas								+ 68.1	— 86.9	— 53.7	+ 54.9	+ 63.9
Raw jute								+ 1.0	— 6.1	— 9.8	+ 14.4	+ 8.2
Tea								— 8.6	+ 7.8	+ 22.2	— 11.7	— 12.1
Non Seasonal Advances								+131.4	+185.0	+382.4	—318.8	+105.2
Cotton textiles								+ 0.5	+ 1.0	— 4.3	+ 39.2	+ 36.5
Jute textiles								+ 6.1	— 0.8	+ 11.0	+ 9.9	— 6.0
Iron, steel and engineering goods*								— 12.7	+ 44.9	+ 49.6	+ 83.8	+ 43.1
Chemicals, dyes, paints, drugs and pharmaceuticals¶								+ 48.2	+ 7.4	— 3.5	— 14.6	+ 40.4
Electrical goods								— 6.7	+ 18.4	n.a.	n.a.	n.a.
Assets of Industrial concerns—												
Fixed or floating								+ 4.7	+ 10.3	+ 8.0	+ 19.0	+ 11.9
Shares of joint stock Companies								+ 3.0	— 1.5	— 3.0	+ 2.3	— 4.1
Government and other trustee securities								— 1.7	+ 0.6	n.a.	n.a.	n.a.
Gold and silver bullion and ornaments								+ 1.5	+ 8.4	n.a.	n.a.	n.a.
Total Secured Advances								+338.2	— 7.0	+209.5	+435.1	+304.3
Unsecured Advances								+ 55.8	+ 25.2	+ 19.0	+ 73.7	+120.5
Total Advances								+394.0	+ 18.2	+228.5	+508.8	+424.8

† Estimates based on mid-April 1971 returns received from selected branches of banks.

‡ Excluding plantations other than tea.

§ Including plantations other than tea.

* Includes advances against vehicles.

‡ Includes advances against fertilisers.

n.a.—not available.

Source: Fortnightly/Monthly Survey of Bank's Advances classified according to security. These figures may not tally with those given in Table 19 as these relate to reporting branches only.

upto an amount equal to 10 per cent of the annual average of export credit in 1970 at the concessional rate of 4 1/2 per cent, and an additional amount upto 10 per cent of the annual average of export credit at the *Bank rate*. However, with a view to bringing about a proper alignment of the structure of interest rates charged by scheduled commercial banks on export credit, the Reserve Bank increased, with effect from April 17, 1971, the ceiling rate on export credit from 6 per cent to 7 per cent per annum for pre-shipment (packing credit) and post-shipment credits other than credit provided for exporters on deferred payment terms. The maximum rate of interest on deferred payment terms was continued at 6 per cent and the subsidy of 1.5 per cent under the Export Credit (Interest Subsidy) Scheme continued as before on all export credit provided.

112. On April 17, it was decided to reduce the minimum amount of a single bill offered for rediscounting under the Bills Rediscounting Scheme from Rs. 10,000 to Rs. 5,000; the value of bills offered at any time for rediscounting by a bank would, however, continue to be not less than Rs. 50,000.

Banking Trends During 1970-71 Busy Season

113. During the busy season of 1970-71, bank credit expanded by Rs. 409.2 crores as against an expansion of Rs. 562.9 crores in the previous busy season, the declaration in the growth of bank credit being attributable to the credit control measures taken by the Reserve Bank in early 1971. While between October 30, 1970 and the first week of January 1971 (just prior to raising the Bank rate), bank credit had expanded by Rs. 265 crores as against Rs. 241 crores during the corresponding period of the previous year, expansion in the subsequent period amounted to Rs. 144 crores as against Rs. 322 crores recorded, in the corresponding period of the previous busy season.

114. Advances for food procurement operations recorded an increase of Rs. 77 crores or about a fifth of the total bank credit expansion of Rs. 380 crores during the busy season as against a contraction of the order of Rs. 27.3 crores in such advances during the previous busy season. On the other hand, credit for other purposes recorded a smaller expansion at Rs. 302.9 crores as against Rs. 590.2 crores during the previous busy season.

115. Security-wise analysis of bank credit (based on estimates) in the 1970-71 busy season (upto April 16, 1971) shows that there was an increase in advances against food-grains (Rs. 28 crores) as against a contraction (Rs. 64 crores) during the corresponding period of the previous busy season. Expansion in respect of other seasonal advances like sugar, oilseeds and raw jute was smaller than in the previous busy season. In respect of gur and vegetable oils, there were larger increases, and contraction in regard to tea advances was about the same as in the previous busy season. Among non-seasonal advances, there was a sharp increase in advances against chemicals, dyes, etc., as against a contraction in the corresponding period of the previous busy season, while cotton textiles and iron and steel products and assets of industrial concerns recorded smaller increases as compared with the increases in the previous busy season; jute textiles showed a contraction as against an expansion in the previous busy season. Advances against shares of industrial concerns declined as compared with a moderate increase during the previous busy season. In contrast to the trend in secured advances, expansion in regard to unsecured advances was substantial. The major part of rise in unsecured advances arose out of the accounting procedure followed after July 1970 in respect of the participation of the nationalised banks with the State Bank of India in financing food procurement operations. Advances given by the nationalised banks were in lieu of usance promissory notes lodged by the Food Corporation of India with the State Bank of India and as such were shown under unsecured advances. In the earlier years, on the other hand, these were shown as advances secured against hypothecation of stocks.

116. Increase in aggregate deposits of scheduled commercial banks during the 1970-71 busy season amounted to Rs. 421.1 crores which was higher by Rs. 100.2 crores as compared with the increase in the previous busy season.

Consequently, the credit-deposit ratio at the end of April 1971 was lower at 78.5 per cent by 0.9 percentage point as compared with the ratio a year ago. Increase in time deposits (Rs. 235 crores) during the 1970-71 busy season was substantially higher (Rs. 86 crores) than the increase in the previous busy season, attributable perhaps to the upward revision of deposit rates by 1/4 to 1/2 per cent. In respect of demand deposits also, the increase (Rs. 186 crores) was larger by Rs. 14 crores as compared with the increase in the previous busy season. The relative shares of the two components in the total deposits remained the same at the end of April 1971 as in April 1970 at 44 and 56 per cent for demand and time deposits, respectively.

117. Despite this increase in deposits, the order of recourse of commercial banks to the Reserve Bank of India during the busy season of 1970-71 was higher than in the previous busy season, though the level at the end of the busy season (Rs. 190.7 crores) was very much lower as compared with the level a year ago (Rs. 236.5 crores). The busy season having commenced at a very high level of Rs. 150.5 crores, the borrowings increased steadily touching the peak of Rs. 443 crores on March 19, 1971 before declining in the subsequent weeks to Rs. 191 crores on April 30, 1971. The level at the end of the busy season of 1970-71 was Rs. 40 crores above the level at the end of October 1970 which, however, compared favourably with the increase of Rs. 203 crores during the previous busy season. Investments in Government and other approved securities recorded an increase of Rs. 114.2 crores during the busy season of 1970-71 as against a disinvestment of Rs. 53.8 crores during the 1969-70 busy season raising the ratio of investments in Government and other approved securities to deposits from 28.8 per cent at the end of April 1970 to 29.9 per cent at the end of April 1971. Perhaps, the stepped-up liquidity requirements acted as a constraint on the ability of commercial banks to shift resources from investments in Government securities to bank credit. The cash and balances with the Reserve Bank recorded a marginally larger increase (Rs. 7.9 crores) than that in the previous period (Rs. 7.7 crores).

118. The curtailment of refinance facilities by the Reserve Bank in the face of unabated demand for credit was naturally reflected in the trend of call money rates as discussed earlier. To enlarge the call money market, the Reserve Bank allowed in November 1970 the Life Insurance Corporation and the Unit Trust of India to place their surplus funds with banks as money at call and short notice. Earlier, in September 1970, the State Bank of India was permitted by the Reserve Bank to enter the call money market. The subsidiaries of the State Bank which were hitherto operating only as borrowers were also permitted to operate as lenders enabling them to place their surplus funds in the inter-bank call money market.

Export Finance

119. The preferential treatment accorded to exports in the form of refinance facilities given to banks at the concessional rate/Bank rate, irrespective of net liquidity ratio, for financing export credit was continued by the Reserve Bank during the year. As on the last Friday of June 1971, outstanding amount of refinance stood at Rs. 35.5 crores in regard to packing credit for exports and Rs. 36.6 crores in respect of post-shipment credit. Though the level was much lower than that a year ago, the share of export refinance in the total refinance remained around 35 per cent. During the busy season, however, the outstandings were throughout much higher than in the previous year, refinance against export credit reaching a peak of Rs. 134 crores on April 2, 1971 out of the total borrowings of Rs. 356 crores.

120. The banks also continued to avail themselves of the interest subsidy in regard to export credit provided by them. During the period under review, claims from 45 eligible commercial banks were received and an aggregate amount of Rs. 4.09 crores was paid to them. Out of this amount, Rs. 2.19 crores represented the subsidy in respect of pre-shipment credit and Rs. 1.90 crores for post-shipment credit.

121. Available figures in regard to scheduled commercial banks' advances to exporters indicate a steady increase in export credit from Rs. 321.93 crores as at the end of

Table 22—Scheduled Commercial Banks' Advances to Agriculture, Small Scale Sector and Exports.

(Amounts in Rupees Crores)
(Number of Accounts in thousands)

	State Bank of India and Subsidiaries		14 Nationalised Banks		Total Public Sector Banks		Other Scheduled Commercial Banks		Total	
	No. of Accounts*	Amount	No. of Accounts*	Amount	No. of Accounts*	Amount	No. of Accounts*	Amount	No. of Accounts*	Amount
1. Total for Agricultural Purposes :										
June 1970.	240	141.91	392	159.73	632	301.64	210	40.13	842	341.77
March 1971.	280	142.97	521	194.57	801	337.54	255	40.98	1056	378.52
of which :										
Direct Finance to Farmers :										
June 1970	239	55.51	374	104.87	613	160.38	205	23.60	818	183.98
March 1971	279	72.01	505	134.72	784	206.73	247	28.35	1031	235.08
2. Total Small Scale Sector (a + b + c):										
June 1970	42	167.79	45	226.96	87	394.74	9	50.83	96	445.57
March 1971	52	204.83	60	278.13	112	482.96	11	60.81	123	543.77
(a) Road and Water transport Operators:										
June 1970	2	4.55	9	19.86	11	24.41	2	6.22	13	30.63
March 1971	4	7.86	16	31.48	20	39.34	3	8.12	23	47.46
(b) Small-Scale Industries :										
June 1970	40	163.24	36	206.32	76	369.56	8	44.49	84	414.05
March 1971	48	196.97	44	243.55	92	440.52	8	52.62	100	493.14
(c) Setting up Industrial Estates :										
June 1970	—	—	—	0.77	—	0.77	—	0.12	—	0.89
March 1971	—	—	—	3.10	—	3.10	—	0.07	—	3.17
3. Exports :										
June 1970	—	92.02	—	158.04	—	250.06	—	70.44	—	320.49
March 1971**	—	103.37@	—	173.58+	—	276.95	—	86.46	—	363.41+

Note: The figures are as on the last Friday of the month.

* Figures relate to number of units in respect of item No. 2 (Small Scale Sector).

** Provisional.

@ Includes provisional figures of State Bank of India.

+ Excludes the figures of Punjab National Bank.

Source : Special returns received from banks.

March 1970 to Rs. 363.41 crores as at the end of March 1971, the 14 nationalised banks and the State Bank group accounting for about three fourth of the total.

122. Major credit policy measures taken in respect of export credit have already been outlined earlier. Among procedural relaxations effected, the important one was the advice given by the Reserve Bank, in November 1970, to scheduled commercial banks that the norm relating to the debt-equity ratio in respect of exporter-borrowers may be relaxed on merits insofar as export credits were concerned and the amount due under the term-debt availed of against exports on deferred payment basis may be excluded while calculating this ratio.

Advances to Agriculture, Small-scale Industries

123. One of the major objectives of nationalisation of the 14 major scheduled commercial banks was to channelise the flow of credit to the hitherto neglected sectors. Accordingly, the question of helping the small borrowers was given the highest priority in the formulation of policies of the commercial banks. Progress of scheduled commercial banks in this regard is presented in Table 23 on the basis of available data. Between June 1970 and March 1971, the number of borrowal accounts increased in respect of agriculture from 8.4 lakhs to 10.6 lakhs and the number of borrowing units in respect of small-scale industries increased from 0.8 to 1.0 lakh, road and water transport operators from 13,000 to 23,000. Over the same period, outstanding advances rose, in the case of agriculture from Rs. 342 crores to Rs. 379 crores, small-scale industries from Rs. 414 crores to Rs. 493 crores and road transport operators from Rs. 31 crores to Rs. 47 crores. As a proportion of aggregate advances of all scheduled commercial banks, advances to agri-

culture increased from 8.1 to 8.2 per cent, in respect of small-scale industries from 9.8 to 10.6 per cent and in the case of exports from 7.6 to 7.8 per cent between end-June 1970 and end-March 1971.

Table 23—Advances to 'Other Sectors' by 14 Nationalised Banks

	June 1970		March 1971	
	No. of Accounts (Rs. '000s)	Amount (lakhs)	No. of Accounts (Rs. '000s)	Amount (lakhs)
Retail trade and Small business	88	42.82	107	5279
Professional and self employed persons..	28	617	38	818
Education	5	205	7	372

124. The progress made by the 14 nationalised banks in the field of extending credit to the weaker sections of society is evident from the fact that there was a notable rise in the number of borrowal accounts as well as bank advances to retail trade and small business, self-employed and professional persons and for education. Between June 1970 and March 1971, the borrowal accounts in respect of retail traders and small business increased from 0.9 lakh to 1.1 lakhs, professionals and self-employed persons from 28,000 to 38,000 and borrowal accounts for education purposes from 5,000 to 7,000. Over the same period, outstanding advances to retail trade and small business rose

from Rs. 43 crores to Rs. 53 crores. Professional and self-employed persons were given advances totalling Rs. 8 crores, compared with only Rs. 6 crores in June 1970. Advances for education were as much as Rs. 3.7 crores in March 1971 as against Rs. 2.1 crores in June 1970. (Table 23)

125. In July 1970, a Committee under the Chairmanship of Shri V. D. Thakkar was constituted to review the special credit schemes of banks with particular reference to their employment potential. On the basis of the Committee's recommendations, the Reserve Bank issued guidelines to all commercial banks in March 1971 (details are referred to in Part III of this Report). Also, the Bank through a circular letter issued in December 1970, provided guidelines to all commercial banks for financing of agricultural development, with a view to improving the quality of lendings and helping small and potentially viable farmers to move to a higher technological plane. The Committee set up in September 1970 for examining the question of differential interest rates had submitted its report in June 1971 (for details see Part III). The Credit Guarantee Corporation was set up to administer a comprehensive credit guarantee scheme for loans to small borrowers in the priority and hitherto neglected sectors. The Scheme came into force in April 1971 covering credit facilities (upto certain limits) extended to transport operators, traders, self-employed persons, owners of business enterprises and farmers engaged in cultivation, etc.

Bills Rediscounting Scheme

126. In the previous year's Report mention was made of the constitution of a Study Group by the Reserve Bank of India, in February 1970, to go into the question of enlarging the use of bill of exchange as an instrument of credit and the creation of a bill market in India. The Group submitted its Report in June 1970. It recommended that the Reserve Bank should take steps towards the creation of a bill market in India by encouraging the use of bill of exchange as an instrument of credit. According to the Study Group, the creation of genuine bill market would impart flexibility to the money market, even out liquidity within the banking system and enable the Reserve Bank to exercise more effective control over the money market.

127. The Reserve Bank accepted the main recommendations of the Study Group and in November 1970, introduced a new bills rediscounting scheme in terms of Section 17(2)(a) of the Reserve Bank of India Act. The main features of the Scheme including the modifications introduced therein are given below :

- (i) all licensed scheduled commercial banks including the public sector banks will be eligible to offer bills of exchange to the Reserve Bank for rediscount;
- (ii) the scheme covers only genuine trade bills which evidence sale of goods;
- (iii) the bill should be drawn on and accepted by the purchaser's bank and where the latter is not a licensed scheduled bank the bills should in addition

bear the signature of a licensed scheduled bank; the bill may also be drawn on the buyer and the buyer's bank jointly and accepted by them jointly;

- (iv) the bill should normally be of a usance not exceeding 90 days and in exceptional cases it may have usance upto 120 days provided at the time of offering to the Reserve Bank for rediscount, the bill should have maturity not exceeding 90 days;
- (v) the bill should bear at least two good signatures;
- (vi) the scheme would exclude bills of exchange arising out of sales of such commodities as Reserve Bank may indicate from time to time;
- (vii) the rediscounting facilities for the present would be made available at the Reserve Bank's offices at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi; and
- (viii) to avoid rediscounting of a number of small bills, such bills should be given in bunches. The amount of a single bill offered for rediscount should not be less than Rs. 5,000 and the total value of bills offered at a time should not be less than Rs. 50,000.

128. The Bank has already commenced rediscounting such bills for the scheduled commercial banks. The refinance facilities under the scheme are made available to banks throughout the year and bills rediscounted by banks with the Reserve Bank after June 30, 1971 will not impair the banks' entitlement to refinance at the Bank rate, irrespective of their net liquidity position. The outstanding amount of bills of exchange held by the Reserve Bank reached a peak level of Rs. 16.73 crores on May 28, 1971; it stood at Rs. 10.39 crores on June 25, 1971.

Participation Certificates

129. An interesting development in commercial banking during the period was the introduction of a Scheme of Participation Certificates by some banks. A participation certificate is an instrument whereby a bank can sell to a third party (the transferee) a part or all of a loan made by the bank to a client (the borrower). The objective behind the introduction of participation certificates is to provide for greater mobilisation of funds, reduce recourse to the Reserve Bank and diversify the availability of financial instruments. It offers a shortterm investment asset at an attractive rate of interest to the financial institutions and is a useful adjunct to the new Bill Market Scheme (referred to earlier). Since the Participation Certificates are issued only to the financial institutions, the funds that become available to the banks through the issuance of such certificates represent inter-institutional transactions. The Participation Certificates make it possible for the banks to acquire surplus resources of other financial institutions, ranging upto 6 months. The bank issuing the Participation Certificates can, among other things, assume the role of a prime agency which alone deals with the customer, obviating the need

Table 24—Growth in Scheduled Commercial Banks' Offices, Deposits and Credit in India

(Amounts in Rupees Crores)										
Offices (Nos.)				Deposits (excluding inter-bank deposits)				Credit (excluding inter-bank credit)		
	Total	Annual Increase	Demand Deposits	Time Deposits	Aggregate Deposits.	Annual Increase	Percentage-Rise	Bank Credit	Annual Increase	Percentage-Rise
End-June 1965	5727	+498	1275.1	1433.0	2708.1	+323.4	+13.6	2068.4	+294.6	+16.6
End-June 1966	6139	+412	1477.3	1645.9	3123.2	+415.1	+15.3	2271.4	+203.0	+9.8
End-June 1967	6620	+481	1664.6	1852.4	3517.0	+393.8	+12.6	2631.1	+359.7	+15.8
End-June 1968	7044	+424	1874.8	2094.2	3969.0	+452.0	+12.9	3102.9	+471.8	+17.9
End-June 1969	8045	+1001	2103.5	2542.3	4645.8	+676.8	+17.0	3598.8	+495.9	+16.0
End-June 1970	9938	+1893	2328.8	2945.7	5274.5	+628.7	+13.5	4212.7	+613.9	+17.1
End-June 1971*	11892	+1954	2725.1	3464.8	6189.9	+915.4	+17.4	4775.8	+563.1	+13.4

*Provisional (as on June 25, 1971).

Note : Data are based on weekly returns submitted by banks, under Section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934 except number of offices.

on his part to deal with several lending agencies simultaneously. Some Indian and foreign banks functioning in India have issued Participation Certificates to financial institutions such as banks, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, insurance companies and similar other financial institutions incorporated in India. For the present, the scheme approved so far pertains to only working capital requirements. The amount of Participation Certificates outstanding as on June 30, 1971 was Rs. 15.43 crores.

130. With a view to examining the scope for, and implications of the creation of a market for instruments of debt covering medium and long-term loans, the Reserve Bank constituted in October 1970 a Study Group on Term Loan Participation Arrangements. The Study Group submitted its report in March 1971. The report noted that the creation of an active market in the instruments of term loans will have a number of advantages, but there are also certain limitations in the existing financial market arrangements which have to be overcome for the emergence of a market for the proposed instruments. The findings and recommendations are under consideration.

Balance of Payments

Trends in Reserves During 1970-71

131. The external payments position during the year under review was in sharp contrast with that in the previous two years. Foreign exchange reserves which had shown substantial increases of \$ 118 million in 1968-69 (July-June) and \$ 278 million in 1969-70 (July-June) registered a decline of \$ 66 million during 1970-71 (July-June). Excluding the effect of special factors such as transactions with the International Monetary Fund, the refund of IBRD special deposits and the appreciation of the Deutsche Mark component of the country's reserve assets following the revaluation of Deutsche Mark in October 1969 as also the suspension of its par value since May 10, 1971, the reserves would show a nominal rise of less than a million dollars as compared with \$ 360 million in 1969-70 and \$ 261 million in 1968-69.

132. Repurchases of drawings from the Fund amounted during the year to \$135 million, as against \$ 187 million in the preceding year. With these repurchases the entire outstanding drawings from the Fund were settled. Under the fifth quinquennial general review India's quota in the Fund was increased in December 1970 from \$ 750 million to \$ 940 million and in connection with the gold component (one-fourth) of this increase an outlay of \$ 30 million was made for the purchase of gold. For the first time since January 1957 India re-established a reserve position with the Fund in December 1970; at end-June 1971 the reserve position amounted to \$ 76.1 million. On January 1, 1971, India received the second allocation of Special Drawing Rights of \$ 101 million which was lower than the \$ 126 million allocated a year earlier. Service charges paid to the Fund were also lower: \$ 6 million as against \$ 13 million in the preceding year. Thus, although transactions with the Fund accounted for an outgo of \$ 70 million in 1970-71, there was a strengthening of the second line of reserves in the form of India's drawing power on the Fund.

133. India was designated by the Fund for acceptance of SDRs from other SDR participants in exchange for convertible currencies to the extent of \$ 14 million each during July-September 1970 and October-December 1970 and \$ 48 million during January-March 1971. Under these designations, India accepted SDRs worth \$ 41 million between July 1970 and June 1971.

Payments position in 1970

134. Details of balance of payments transactions for the year ended June 1971 are not yet available. The latest balance of payments compilations relate only to the calendar year 1970 and show that India's external payments position worsened during this year as compared with 1969. Amongst the factors responsible for this deterioration were the large import bill and lower utilisation of external assistance. On the other hand, exports were only nominally higher than in 1969.

Overall Trends

135. Over the year while the aggregate import bill increased by Rs. 115.1 crores, exports moved up nominally by Rs. 11.5 crores and the trade deficit widened in consequence from Rs. 165.2 crores to Rs. 268.8 crores (Table 25). On the invisibles account, including official transfer payment transactions, there was a deficit of Rs. 25.0 crores, which was more than thrice the deficit in 1969. A part of this deterioration was, however, made good by the net receipt of Rs. 13.1 crores by way of non-monetary gold movement, representing the contra entry for gold transferred from the non-monetary stock for meeting a part of the gold tranche of India's additional quota in the Fund. Following the deterioration under merchandise as well as invisibles, the deficit on current account widened over the year by Rs. 108.0 crores to Rs. 280.7 crores. Taking into account the unidentified outflow shown under "errors and omissions," which nearly halved over the year, the total deficit amounted to Rs. 297.9 crores in 1970, nearly 47 per cent higher than in 1969. As the net inflow from capital transactions was also lower, the accretion to the reserves at Rs. 44.4 crores was lower over the year by Rs. 132.0 crores.

Imports

136. The continuous decline in the annual aggregate import bill since the devaluation of the rupee in June 1966 was reversed during the year under review when it moved up by Rs. 115.1 crores to Rs. 1,678.3 crores. Imports financed out of own resources accounted for the entire rise. Aid financed imports, on the other hand, declined mainly because of the tapering off of commodity assistance, particularly foodgrain imports, under the U.S. P.L. 480 Title I programme. In fact, the improved domestic supply position made it possible to reduce foodgrain imports by about 18 per cent. But domestic shortages of other items such as raw cotton and metals made larger imports necessary. Further, imports of machinery and capital equipment also picked up. The additional outlay on the import of these items far exceeded the saving resulting from the fall in foodgrain imports and led to the reversal of the earlier declining trend in the annual aggregate import bill.

137. Sector-wise, imports on both private and Government accounts increased over the year by Rs. 47.0 crores and Rs. 68.1 crores to Rs. 655.2 crores and Rs. 1,023.1 crores, respectively. On private account, the two major items showing a rise were imports of raw cotton and machinery. The fall in imports of mineral oils, vegetable oils and raw jute only partly offset the rise under other items. On Government account, the decline in foodgrain imports was more than made up by the increase in imports of non-food items, notably non-ferrous metals, capital equipment and communication stores.

Exports

138. The growth in exports slowed down considerably over the year. Exports increased marginally by Rs. 11.5 crores to Rs. 1,409.5 crores. For the major part of the year, a combination of several factors adversely affected exports. World demand for some of our traditional export items such as jute goods, cashew kernels, etc., weakened; domestic shortages of agricultural and industrial raw materials, notably raw cotton, steel and non-ferrous metals reduced export availabilities and the strike at Calcutta port immobilised exports in June 1970. It was only towards the end of the year that the situation tended to ease and exports began to recover. As in 1969 even the nominal improvement noticed for the year as a whole was entirely brought about by non-traditional items, notably engineering goods, iron ore, manganese ore and sugar. The combined exports of the traditional items, on the other hand, continued to decline largely because of the fall under jute manufactures, hides and skins, and cashew kernels.

Invisibles

139. Official transfer payment transactions resulted in a surplus of Rs. 52.5 crores, which was larger by Rs. 9.1 crores than in 1969 (Table 25). With gross receipts remaining unchanged over the year, the entire improvement

Table 25—India's Balance of Payments (Preliminary)

	(Rupees Crores)					
	January-March 1970	April-June 1970	July-September 1970	October-December 1970	January-December 1970	January-December 1969
A. Current Account						
Imports c.i.f.						
(a) Private	168.3	166.0	166.4	154.5	655.2	608.2
(b) Government	244.6	239.9	276.6	262.0	1023.1	955.0
Total Imports (a+b)	412.9	405.9	443.0	416.5	1678.3	1563.2
Exports F.o.b.	349.6	331.8	339.8	388.3	1409.5	1398.0
Trade Balance	-63.3	-74.1	-103.2	-28.2	-268.8	-165.2
Non-Monetary Gold Movement (Net)	—	—	—	+13.1	+13.1	—
Official Transfer Payments (Net)	-0.3	+5.2	+27.3	+20.3	+52.5	+43.4
Other Invisibles (Net)	-26.5	-5.2	-16.8	-29.0	-77.5	-50.9
Current Account (Net)	-90.1	-74.1	-92.7	-23.8	-280.7	-172.7
B. Errors and omissions (Net)	+22.2	+16.9	-15.3	-41.0	-17.2	-30.4
C. Capital Account						
Private Capital (Net)	-5.5	-2.2	-6.2	-3.9	-17.8	-27.1
(a) Long-term	-5.5	-2.3	-6.2	-3.8	-17.8	-29.4
(b) Short-term	—	+0.1	—	-0.1	—	+2.3
Banking Capital (Net)	+1.4	+17.1	10.6	+14.7	+6.8	-3.7
Official Capital (Net)	+198.7	+58.0	+98.6	+11.6	+366.9	+410.3
(a) Loans	+226.2	+139.6	+115.6	+162.5	+643.9	+777.9
(b) I.M.F.	-42.8	-52.6	—	-52.6	-148.0	-111.1
(c) Amortisation	-28.8	-38.0	-43.5	-70.1	-180.4	-185.9
(d) Miscellaneous	+44.1	+9.0	+26.5	-28.2	+51.4	-70.6
Capital Account (Net)	+194.6	+72.9	+81.8	-7.0	+342.3	+379.5
D. Movement in reserves (A+B+C)	+126.7	+15.7	-26.2	-71.8	+44.4	+176.4*
Increase (+) / Decrease (-)						

*Excludes the appreciation in the Deutsche Mark component of the reserves following the revaluation of the D-mark in October 1969.

reflected the saving in the gross outgo due to the termination of the annual contributions to the Indus Basin Development Fund, the last instalment of which was paid in 1969. The deficit on account of the other invisible transactions widened from Rs. 50.9 crores to Rs. 77.5 crores. Here again, the situation worsened because of the increase in the gross outgo which was offset only in part by the increase in gross receipts. Over the year, gross payments moved up by Rs. 41.5 crores to Rs. 496.2 crores. A little more than half of this increase represented the additional outgo on investment income account and the balance reflected the step-up in the payments on account of travel, transportation and miscellaneous service transactions. For sometime now the gross outgo on investment income account, which amounts to more than half of the total gross outgo, has been growing steadily and over the year it went up by Rs. 23.2 crores to Rs. 271.5 crores. More than half of the additional outgo in 1970 was accounted for by interest payments on loans and credits, which amounted to Rs. 203.5 crores as against Rs. 186.8 crores in 1969. Gross receipts went up by Rs. 14.9 crores to Rs. 418.7 crores. The main contribution to the increase in gross receipts in 1970 was made by investment income receipts following the higher interest rates prevailing abroad. Earnings from miscellaneous and transportation services also showed some improvement. The increases were moderated, to a large extent, by the fall in private unilateral transfers from abroad.

Capital Transactions

140. The net inflow from capital transactions, which was nearly halved in 1969, declined further by Rs. 37.2 crores to Rs. 342.3 crores. While there was an improvement in regard to private capital movements, those relating to banking and official sectors turned less favourable than before. Larger drawings on loans and the reverse movement

of oil companies' funds stepped up the gross inflow to the private sector with the result that the net private capital outflow declined from Rs. 27.1 crores to Rs. 17.8 crores. In the banking sector, on the other hand, the net outflow, which amounted to Rs. 6.8 crores, nearly doubled over the year; as in 1969 almost the entire net outflow was brought about by an increase in authorised dealers' foreign currency assets.

141. In the official sector there was a further setback in the net inflow, which declined by Rs. 43.4 crores to Rs. 366.9 crores. The two major factors here were the fall in the utilisation of external assistance loans and the relatively large outgo by way of repurchases from the I.M.F. The utilisation of external assistance loans declined from Rs. 780.6 crores to Rs. 647.0 crores mainly because of the sizeable contraction in loan disbursements from P.L. 480 counterpart funds. Repurchases from the I.M.F. amounted to Rs. 148.0 crores as against Rs. 111.1 crores in 1969. Amortisation payments, which amounted to Rs. 182.6 crores, however, were marginally lower than last year. A redeeming feature of the situation was the favourable turn under miscellaneous capital transactions, which brought about a net inflow of Rs. 51.4 crores as compared to a net outflow of Rs. 70.6 crores in 1969, offsetting to a sizeable extent the adverse movements under other official capital transactions. This favourable outturn reflected partly the contra entry for the allocation of SDRs (Rs. 94.5 crores) and partly the changes in rupee liabilities to the U.S. Government arising out of transactions under the P.L. 480 Title I programme.

Regional Trends

142. The worsening of the overall current account position was largely a reflection of the widening of the deficit on current account with the dollar area and O.E.C.D.

countries (Table 26). The deficit with these two areas alone increased over the year by Rs. 150.7 crores and Rs. 63.0 crores to Rs. 302.2 crores and Rs. 149.5 crores, respectively. There was also some weakening of the position with the sterling area in that the surplus declined by Rs. 8.4 crores to Rs. 105.7 crores. With the 'rest of non-sterling area,' on the other hand, the position improved considerably, the surplus moving up from Rs. 4.5 crores to Rs. 102.2 crores. The deficit with international institutions, which amounted to Rs. 37.0 crores, was also lower than in 1969 due mainly to the reduced outgo on account of official transfer payment transactions, following the termination of the annual contributions to the Indus Basin Development Fund referred to earlier.

143. While the trade surplus with the sterling area remained more or less the same as before and that with the 'rest of non-sterling area' registered a marked improvement, the trade deficits with the dollar area and the O.E.C.D. countries widened sizeably (Table 26). Barring imports from the 'rest of non-sterling area,' which were marked down, those from the remaining three areas registered a rise. In fact, the spurt in the overall import bill was more than accounted for by the rise in imports from the dollar area and the O.E.C.D. countries. Exports to sterling area and the 'rest of non-sterling area' increased, the improvement in the case of latter being sizeable. But the gain was wiped out to a large extent by the decline in exports to the dollar area and the O.E.C.D. countries.

144. With all the regions there was a deterioration in the position on invisibles account, including official transfer payment transactions. While the surplus with the sterling and dollar areas dwindled, the deficits with the O.E.C.D. countries and the 'rest of non-sterling area' widened. In the case of the sterling area, dollar area and the O.E.C.D. countries, these transactions tended to aggravate the position on current account. With the 'rest of non-sterling area,' on the other hand, the widening of the deficit offset in part the gain in the trade balance.

Foreign Trade

Change in Compliation Procedure

145. While the foregoing discussion on the balance of payments is confined to the calendar year 1970, as data for later months are not yet available, on merchandise transactions, data are available for the financial year 1970-71 in the statistics compiled by the DGCIS. According to these statistics, exports during the financial year 1970-71 (April-March) amounted to \$2,041 million as compared with \$1,884 million in the previous year showing a growth rate of 8 per cent as against 4 per cent in 1969-70. A part of the increase registered in 1970-71 is statistical, resulting from the change in procedure, for recording exports, adopted by the DGCIS which became effective from November 1970. Exports, which were previously recorded on the basis of actual shipments made (*i.e.*, finally passed shipping

Table 26—India's Regional Balance of Payments on Current Account (Preliminary)

(Rupees crores)

	January-March 1970	April-June 1970	July-September 1970	October-December 1970	January-December 1970	January-December 1969
Sterling Area						
Imports c.i.f.	65.1	69.9	62.2	70.6	267.8	255.4
Exports f.o.b.	87.8	80.2	90.0	106.5	364.5	+351.4
Trade Balance	+22.7	+10.3	+27.8	+35.9	+96.7	+96.0
Non-Monetary Gold Movement (Net)	—	—	—	—	—	—
Official Transfer Payments (Net)	—0.5	—0.8	—0.3	+0.4	—1.2	+7.3
Other Invisibles (Net)	+6.0	+2.5	+3.3	—1.6	+10.2	+10.8
Current Account (Net)	+28.2	+12.0	+30.8	+34.7	+105.7	+114.1
Dollar Area						
Imports c.i.f.	133.9	155.1	164.0	134.9	587.9	494.3
Exports f.o.b.	57.8	50.8	54.5	69.8	232.9	290.6
Trade Balance	—76.1	—104.3	—109.5	—65.1	—355.0	—203.7
Non-Monetary Gold Movement (Net)	—	—	—	+13.1	+13.1	—
Official Transfer Payments (Net)	+1.8	+5.0	+28.1	+18.8	+53.7	+41.9
Other Invisibles (Net)	—6.0	+1.6	+0.4	—10.0	—14.0	+10.3
Current Account (Net)	—80.3	—97.7	—81.0	—43.2	—302.2	—151.5
O.E.C.D. Countries :						
Imports c.i.f.	58.6	54.5	61.8	70.5	245.4	194.4
Exports f.o.b.	32.3	30.4	27.7	31.6	122.0	132.3
Trade Balance	—26.3	—24.1	—34.1	—38.9	—123.4	—62.1
Non-Monetary Gold Movement (Net)	—	—	—	—	—	—
Official Transfer Payments (Net)	+1.7	+1.3	+0.3	+1.3	+4.6	+9.9
Other Invisibles (Net)	—3.4	—8.3	—6.4	+12.6	—30.7	—34.3
Current Account (Net)	—28.0	—31.1	—40.2	—50.2	—149.5	—86.5
Rest of Non-Sterling Area :						
Imports c.i.f.	155.3	126.4	155.0	140.5	577.2	619.1
Exports f.o.b.	171.7	170.4	167.7	180.4	690.2	623.7
Trade Balance	+16.4	+44.0	+12.7	+39.9	+113.0	+4.6
Non-Monetary Gold Movement (Net)	—	—	—	—	—	—
Official Transfer Payments (Net)	—0.1	+0.1	—	—	—0.2	—
Other Invisibles (Net)	—12.8	+7.0	—5.1	+0.3	—10.6	—0.1
Current Account (Net)	+3.5	—50.9	+7.6	+40.2	+102.2	+4.5
International Institutions :						
Imports c.i.f.	—	—	—	—	—	—
Exports f.o.b.	—	—	—	—	—	—
Trade Balance	—	—	—	—	—	—
Non-Monetary Gold Movement (Net)	—	—	—	—	—	—
Official Transfer Payments (Net)	—3.2	—0.2	—0.8	—0.2	—4.4	—15.7
Other Invisibles (Net)	—10.3	—8.1	—9.1	—5.1	—32.6	—37.7
Current Account (Net)	—13.5	—8.3	—9.9	—5.3	—37.0	—53.4

bills), are now being compiled as and when the consignments are approved for shipment (i.e., on the basis of original copy of the shipping bills, adjusting, however, for short and shutout shipments details of which are received during the month of reporting). There is thus a built-in lead now in the recording of exports.* Hence an assessment of the export performance in 1970-71 has to make due allowance for the change in the procedure for reporting, which has resulted in the data for the second half of the financial year being partly assembled on the old basis and partly on the new basis.

146. During April-September 1970, exports amounted to \$ 928 million. \$ 6 million lower than in the corresponding period of 1969. The dip in exports was primarily due to lower exports of jute manufactures which declined sharply during the period by as much as \$ 46 million. The other major items that registered declines were tea (\$ 18 million), hides and skins and leather (\$ 15 million), coffee (\$ 3 million) and cotton textiles (\$ 2 million). The shortfalls in these items were, to some extent, made good by larger earnings from engineering goods (\$ 23 million), iron ore (\$ 11 million) oil cakes (\$ 9 million), iron and steel (\$ 6 million), spices (\$ 5 million) and sugar (\$ 3 million) (Table 27).

147. The slowing down of exports during the first half of 1970-71 may be attributed to several factors, both domestic and international. Apart from the ten weeks' strike of the bargemen in the port of Calcutta during May-July 1970, which adversely affected exports in these months, exports slowed down also because of a constraint on the supply of basic inputs such as special categories of steel, aluminium and other non-ferrous metals and raw cotton. Externally, there was a slackness in the demand for some of our export items, especially for jute carpet backing, marine products, hides, skins and leather and cotton yarn.

148. In order to arrest the declining trend in exports, Government took several measures, particularly to improve the supply position of essential raw materials and also to gear up the export efforts. In September 1970, the Government liberalised the import policy for steel so as to make available an adequate quantity of special types of steel required by the export units of engineering products. Under this policy, imports of certain scarce categories of

steel were allowed to the extent of either 50 per cent of actual consumption in 1969-70 or the actual requirement for production against firm export orders in addition to the regular quota allotted to the individual units.

149. Reflecting partly the impact of the various promotional measures undertaken by the Government and partly the improved domestic availabilities of both raw materials and export surpluses, exports began to look up from October 1970. Although a precise appraisal of the expansion in exports during the second half of 1970-71 *vis-a-vis* 1969-70 is not possible owing to the statistical limitations referred to earlier, nevertheless the recorded data point to a spurt in exports in terms of value during October-December 1970. The recorded value of exports during the quarter October-December at \$ 605 million was 32 per cent higher than in the corresponding quarter of 1969, only a part of which represents the true increase. The increase was shared by almost all the items, both traditional and non-traditional. In January-March 1971, the spurt in exports seems to have tapered off, with exports declining to \$ 508 million at which level they show an increase of just 3 per cent over the corresponding quarter of 1970. In the first quarter of 1971-72 (April-June 1971), exports moved up marginally to \$ 512 million and when compared with the corresponding period of 1970 they were higher by 13 per cent. Exports have thus generally maintained an upward trend since October 1970 as compared with the previous year.

Exports : Commodity-wise

150. The commodity-wise details available for April-December 1970 show that exports of engineering goods, iron ore and chemicals continued to increase, although the growth in exports of iron and steel has been modest due to increasing domestic demand. Among traditional commodities, tea recorded an improvement, benefiting to some extent from the Mauritius Agreement concluded in early 1970. In regard to jute goods, the downtrend in exports noticed in the past few years has continued, with the slackening of the U.S. demand particularly for carpet backing and with increasing competition from Pakistan and synthetic substitutes, although this trend is likely to be arrested during the current year, *albeit* temporarily, owing to tragic developments in East Bengal. As for cotton piece-goods, the problem is one of keeping down costs and improving our competitiveness; further, with the proposed imposition of an import duty by the U.K. from January 1,

Table 27—India's Principal Exports

	1965-66	1968-69	1969-70	1969-70 (April-September)	1970-71	(U.S.\$ Million)	
						Increase(+) / Decrease(—) of (5) over (4)	
							Actual Percentage
	1	2	3	4	5	6	7
A. Items showing a rise							
Iron Ore	89	118	126	52	63	+11	+21
Engineering goods	37	92	120	56	79	+23	+41
Iron and steel	26	105	116	52	58	+6	+12
Cashew kernels	58	81	77	41	43	+2	+5
Oil cakes	73	66	55	25	34	+9	+36
Chemicals	23	32	40	20	21	+1	+5
Spices	49	34	46	13	18	+5	+38
Sugar	23	14	10	8	11	+3	+38
Manganese ore	23	18	15	7	8	+1	+14
B. Items showing a fall							
Jute yarn and manufactures	384	291	276	145	99	—46	—32
Cotton yarn and manufactures	148	134	154	74	72	—2	—3
Tea	241	209	166	83	65	—18	—22
Hides, skins, leather and leather goods including footwear	90	116	132	68	53	—15	—22
Pearls, precious and semi-precious stones, unworked/ worked	31	60	56	30	28	—2	—7
Coffee	27	24	26	22	19	—3	—14
Fish and fish preparations	14	30	42	21	20	—1	—5
C. Total	1693	1811	1884	934	928	—6	—1

Source : DGCIS.

* It may be recalled that in 1965-66, the basis for recording the exports data was changed from shipments approved during a month to actual shipments made during that month, so as to compile statistics on a more realistic basis. In that year, exports were statistically understated as a direct consequence of the change in recording. In 1970-71 with a reversal in the method of reporting, exports will be overstated.

1972, our exports to that country would be adversely affected. In regard to iron and steel, the pull of domestic demand would render it difficult for us to maintain a high rate of growth. As for engineering goods, the main constraint is the shortage of certain special categories of steel and the rising domestic costs which affect production.

Adoption of G.S.P.

151. In regard to export prospects, a favourable development is the adoption of the Generalised System of Preferences (GSP) by the developed countries for the developing countries which would provide opportunities to increase our exports of manufactured and semi-manufactured items. The E.E.C. countries and Japan have implemented the GSP with effect from July 1, and August 1, 1971, respectively. The U.S.A. and U.K. are expected to follow suit sometime in 1972. The export front is indeed beset with many difficulties, but with the new mood of the advanced countries, it should be possible to accelerate the growth in exports, given the active co-operation of the industry and trade and under the stimulus of the export promotion drive of the Government.

Export Policy Resolution

152. In regard to export promotion, an important development during the year was the presentation of the Export Policy Resolution to the Parliament on July 30, 1970, which emphasised the need for expanding India's export earnings at a high rate so that the country may be self-reliant and reduce its dependence on external assistance. To achieve this objective, the Resolution outlined a number of measures, which included, *inter alia*, (i) the adoption of appropriate policies and measures designed to promote investment in the development of the promising sectors of the economy, (ii) more precise identification of products in each of the broad sectors of the economy which have long-term export potential, (iii) facilitating expansion of export-oriented units, (iv) special encouragement to producers and exporters of equipment for development of the infra-structure, industrial machinery, machine tools and consumer durables to meet the emerging requirements of other developing countries, and (v) strengthening and expansion of credit facilities for exporters.

Trade Development Authority

153. In pursuance of the Export Policy Resolution, the Government set up a new organisation, namely, the Trade Development Authority (TDA) in July 1970 to assist enterprises to build up their exports through a package of personalised services in the field of trade information, research and analysis, merchandising and export production and promotion. In February 1971, the TDA announced a package of services for its member units interested in exporting selected products (mainly engineering goods) to the U.S.A., the U.K., Canada, Western Europe and Japan.

Other Measures

154. Among other measures taken during the year, mention may also be made of the abolition of the 25 per cent *ad valorem* export duty on the export of coir fibre effective from July 30, 1970, and the enlargement of the institutional framework to promote export efforts in respect of specified items. The new institutions set up during the year included the Cashew Corporation, the Cotton Corporation, the Jute Corporation and the Projects and Equipment Corporation.

Trends in Imports

155. Imports, on the basis of the DGCIS data, amounted to \$2171 million during 1970-71 showing a rise of \$61 million (3 per cent) over the level in 1969-70. The rise in imports, which has taken place for the first time after the devaluation of the rupee, was wholly accounted for by non-food items and reflects the growing needs of industry for imported raw materials, intermediates, components and spares emanating from the continued increase in industrial production.

Imports : Commodity-wise

156. Commodity-wise details of imports are available upto December 1970. They show that foodgrain imports during April-December 1970 were \$43 million (16 per cent) lower than in April-December 1969. Non-food imports recorded a rise of \$58 million (4 per cent) during this period. Under non-food imports, sharp increases have taken place under iron and steel (\$61 million or 81 per cent), non-

ferrous metals (\$49 million or 75 per cent), chemicals other than fertilisers (\$15 million or 13 per cent), raw cotton (\$16 million or 20 per cent) and cashewnuts (\$4 million or 16 per cent). Imports of machinery and transport equipment and fertilisers declined by 9 per cent and 34 per cent, respectively. Among the machinery group, imports of electrical machinery increased by 7 per cent which was, however, more than offset by the declines of 12 per cent and 10 per cent in the imports of non-electrical machinery and transport equipment (Table 28). The rise in the imports of iron and steel and non-ferrous metals was the result of special efforts made to import these commodities on an emergency basis to meet the demand from export industries. The reduction in non-electrical machinery imports, which has taken place despite an improvement in investment activity, reflects the progress made in the field of import substitution in the machine building industry.

Import policy

157. The import policy has been liberal for the export industries in particular and for priority industries in general. In 1969-70 and 1970-71, the value of import licences increased by 27 per cent and 36 per cent, respectively, reflecting the increase in the demand for imported raw materials by the industry. This should result in a significant increase in non-food imports during 1971-72. In fact, in the first quarter of 1971-72, i.e., April-June 1971, imports aggregated \$650 million recording an increase of 25 per cent over the level during the corresponding period of the previous year.

External Assistance

Authorisations

158. In the fiscal year 1970-71, authorisations totalled \$981 million, recording a rise of 18 per cent over the year, in contrast with the fall of 25 per cent in the preceding year. Loans and grants authorised went up by 33 per cent from \$737 million to \$981 million to bring about the rise in the total assistance authorisations; there were no authorisations of P.L. 480 aid* which amounted to \$98 million in the preceding year (Table 29).

Project and Non-project Aid

159. As in the last two years, loans predominated in the fresh aid authorised during 1970-71. They accounted for 92 per cent of the total aid authorised, grants making up the balance of 8 per cent. Of the total loan authorisations in 1970-71, loans for \$317 million (35 per cent) were tied to specific projects while loans for \$556 million (about 61 per cent) were not tied to any projects; the balance of \$33 million (4 per cent) of the authorisation was provided as debt relief. The share of non-project aid in the loan authorisations increased from 45 per cent in 1969-70 to 61 per cent in 1970-71 as the U.S.A. and the I.D.A. made available substantial amounts in non-project loans.

Debt Relief

160. Total debt relief assistance (either in the form of fresh refinancing credits, postponements of payments due, rescheduling of debt or cancellation/reduction of interest) authorised during 1970-71 amounted to \$88 million, \$23 million lower than in the previous year (Table 30). The bulk of this decline was due to the fact that the U.K. made available its debt relief assistance for 1970-71 amounting to \$18 million in the preceding year itself. Japan and West Germany increased their debt relief assistance by \$6 million and \$5 million, respectively. Debt relief assistance amounted to only 15 per cent of the total debt service charges during 1970-71.

Trends in Utilisation

161. The amount of assistance actually utilised in any given period largely reflects authorisations in the preceding periods, but for the completely untied part of the current authorisations.

* On April, 1971, however, a fresh P.L. 480 agreement was signed for \$150 million, the amount being increased by \$7.5 million in May, 1971 to accommodate additional supplies of soyabean oil.

Table 28—India's Principal Imports

Commodities	(U.S. \$ Million)							
	Annual		April-December		Percentage Change of			
	1965-66	1968-69	1969-70	1969-70	1970-71	(4) over (3)	(4) over (2)	(6) over (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Food: (excluding cashewnuts)	712	495	391	299	250	—21	—45	—16
Cereals and cereal preparations	676	449	348	269	226	—23	—49	—16
2. Raw cotton	97	120	110	82	98	—8	+13	+20
3. Raw jute and mesta	53	22	7	7	Negl.	—68	—87	—
4. Cashewnuts	32	42	37	25	29	—12	+16	+16
5. Minerals oils :	143	177	183	135	127	+3	+28	—6
Of which:								
(a) Petroleum crude and partly refined	73	128	128	95	102	—	+75	+7
(b) Others	70	49	55	40	25	+12	—21	—38
6. Chemicals :	221	378	246	192	181	—35	+11	—6
Of which:								
(a) Fertilizers	82	186	90	76	50	—52	+10	—34
(b) Others	139	192	156	116	131	—19	+12	+13
7. Iron and steel	206	115	108	75	136	—6	—48	+81
8. Non-ferrous metals	145	119	99	65	114	—17	—32	+75
9. Crude rubber (including synthetic and reclaimed)	10	7	13	11	4	+86	+30	—64
10. Wool and other animal hair	11	15	23	17	18	+53	+109	+6
11. Animal and vegetable oils and fats	32	26	39	36	43	+50	+22	+19
12. Paper, paper board and manufactures thereof	28	24	32	24	23	+33	+14	—4
13. Pearls, precious and semi-precious stones unworked/worked	3	37	38	27	23	+3	+1167	—15
14. Machinery and transport equipment:	1034	685	524	399	365	—24	—49	—9
(a) Machinery other than electric	701	488	372	286	253	—24	—47	—12
(b) Electrical machinery	184	109	85	61	65	—22	—54	+7
(c) Transport equipment	149	88	67	52	47	—24	—55	+10
15. Others	232	283	240	169	167	—15	+3	—1
Total	2959	2545	2090*	1563	1578	—18	—29	+1

Source: DGCIS.

* The figure has been revised to \$2110 million but commodity-wise details are not available.

Table 29—External Assistance*

	(U.S. \$ Million)			
	Loans**	Grants	P.L. 480 Aid@	Total (1+2+3)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Amount undisbursed as at the end of March 1966	2,194	115	226†	2,535
2. Authorisations during				
(a) 1966-67	1,425	106	524	2,055
(b) 1967-68	595	22	324	941
(c) 1968-69	1,052	93	96	1,241
(d) 1969-70	697	40	98	835
(e) 1970-71	906	75	—	981
Total	4,675	336	1,042	6,053
3. Utilisation during				
(a) 1966-67	903	126	480	1,509
(b) 1967-68	1,074	81	415	1,570
(c) 1968-69	1,008	97	113	1,218
(d) 1969-70	900	39	143	1,082
(e) 1970-71	892	58	50	1,000
Total	4,777	401	1,201	6,379
4. Amount undisbursed as at the end of March 1971	2,078†	52†	—£	2,130

* Excludes (a) grants under U.S. P.L. 480 Title II and III and (b) special deposits placed by the I.B.R.D. with the Reserve Bank of India during 1967-68.

** Includes authorisations and utilisation of P.L. 480 Convertible Local Currency Credits.

@ Represents rupee deposits against import of goods under U.S. P.L. 480 Title I programme; disbursements out of these funds by way of loans and grants are, therefore, excluded from columns 1 and 2.

† Adjusted for the lapsed agreements by \$184 million.

‡ Adjusted for the devaluation of Pound Sterling and Danish Kroner in November 1967, of French Franc in August 1969 and for the revaluation of Deutsche Mark in October 1969, except in case of loans from the IBRD and the IDA which are reckoned at the parties prevailing at the time of authorisation and drawals of individual instalments.

£ Adjusted for the lapsed agreements by \$67 million.

In 1970-71, however, the fall of 8 per cent over the year, to \$1,000 million arose mainly from the tapering off of the P.L. 480 Commodity assistance. Utilisation of P.L. 480 Title I aid declined sharply from \$143 million to \$50 million. At \$892 million, utilisation of loans was only \$8 million lower than in 1969-70, while the grants utilised went up from \$39 million to \$58 million.

Debt Servicing

162. Although the utilisation declined, the cost of servicing of official external debt continued to grow. After rescheduling and postponement of debt service charges of \$41 million in 1969-70 and \$46 million in 1970-71, the actual servicing payment rose by 9 per cent from \$506 million to \$550 million (Table 31). The net utilisation of external assistance thus declined from \$576 million to \$450 million or to one-third of the level three years ago. As a proportion of the aid utilised, the servicing payments went up over the year from 47 per cent to 55 per cent, while as a proportion of the exports they increased from 27 per cent to 29 per cent.

Cumulative Assistance

163. Cumulatively, external assistance authorised from August 15, 1947, to March 31, 1971 amounted to \$18,225 million, of which \$12,666 million or nearly 70 per cent was in the form of loans, \$4,400 million or 24 per cent was in the form of P.L. 480/665 and Third Country Currency assistance from the U.S.A. and the balance of \$1,159 million or 6 per cent was in the form of grants. The assistance utilised upto the end of March 1971 is placed at \$15,832 million, loans accounting for \$10,574 million or 67 per cent, P.L. 480/665 and Third Country Currency assistance for \$4,149 million or 26 per cent and grants for \$1,109 million or 7 per cent (Table 32).

164. The U.S.A. accounted for 50 per cent of the total authorisations and 53 per cent of the total utilisation. The I.B.R.D. and I.D.A. together accounted for 13 per cent and the U.K. and West Germany for 7 per cent each of the total authorisations as well as the total utilisation, and the U.S.S.R. accounted for 8 per cent of the total authorisations and 6 per cent of the total utilisation (Table 32).

Liberalisation of Aid Terms

165. In the last three years, a number of countries providing development assistance to India have liberalised in varying degrees the terms on which it is made available. During the year under review, Sweden and France liberalised the terms of their assistance. The loan authorised by Sweden in 1970-71 has a maturity of 50 years as compared with that of 25 years in the case of loans authorised earlier and carries no interest while the interest is charged at 2 per cent per annum on the previous loans. The interest rate on the loans provided by the French Treasury was reduced by 1/2 per cent per annum to 3 per cent per annum. Much, however, remains to be done in this respect, as would be clear from the relevant information given in this and earlier Reports, before the assistance received is placed on the norms recommended by the Pearson Commission. The Commission advocated in 'Partners in Development' that development loans "henceforth be provided at interest of no more than 2 per cent, a maturity of between 25 and 40 years and a grace period from 7 to 10 years."

Aid Pledged for 1971-72

166. The Aid India Consortium at its meeting held in Paris in June 1971 gave indications of a total assistance of \$1,250 million for 1971-72, excluding the assistance to be given for evacuees from the East Bengal. The indicated amount comprises non-project assistance of \$560 million, debt relief assistance of \$90 million, project assistance of \$500 million and food aid of \$100 million. It is to be hoped that unlike in recent years the Consortium indications would be fully translated into actual authorisations. It may be noted that the third replenishment of the resources of the I.D.A. which should have been completed by June, 1971 has been delayed for want of suitable action by the major developed countries.

Foreign Investment Policy

167. During the year, the official policy continued to encourage the flow of foreign investments into selected indus-

trial fields. Under the new industrial licensing policy announced in February 1970, the details of which were discussed in the previous year's Report, the 'Larger Industrial Houses' and foreign enterprises are permitted to set up industries in the 'core' and the 'heavy investments' sectors, except industries reserved for the public sector under the Industrial Policy Resolution, 1956. Further, under the notification dated July 25, 1970 'Larger Industrial Houses' and foreign concerns would be able to establish undertakings or expand production in industries in other sectors provided they undertook specific export commitments. This was done "as part of Government's policy that industrial capacity would have to be consciously and specifically built up in order to facilitate production for exports, particularly in respect of those items where India has a comparative advantage and where favourable trends are emerging in the international markets." The minimum export commitment to be so undertaken is to achieve within a period of three years a level of exports equal to 75 per cent of the new or additional production in case of products which are reserved for production in the small-scale sector and 60 per cent or more in case of other products.

168. On July 20, 1970, the Government published an illustrative list of 121 items from engineering industries—such as industrial machinery, electrical engineering and metallurgical and chemical industries, where a significant technological gap exists and where there is scope for foreign collaboration. The actual terms and conditions for collaboration are to be decided on the merits of each case within the broad framework of Government's policy on these matters. At the same time the Government indicated that requirements under the current policy regarding technical collaboration could be relaxed in some measure, wherever clearly justified, for export-oriented schemes and to small-scale units.

169. The total value of consents granted by the Controller of Capital Issues to joint stock companies for non-resident participation in share capital and for borrowings from abroad by way of loans amounted to Rs. 12 crores during 1970-71 as against Rs. 20.1 crores during 1969-70. The fall consisted of Rs. 5.4 crores in respect of fresh share capital participation, Rs. 0.1 crore in case of bonus shares and Rs. 2.6 crores in case of loans from abroad. During the year there were no consents for loans from abroad. The collaboration agreements approved during 1970 numbered 183 as compared with 134 during 1969.

International Monetary Situation

170. The international monetary scene was relatively calm during the major part of the year under review. However, massive outflows of short-term funds from the U.S. following the adoption of an easy monetary policy by the U.S.A., despite an adverse international payments position, led, early in May 1971, to a currency crisis. The U.S. balance of payments recorded a substantial deficit of \$10.7 billion in 1970. In the first quarter of 1971, the deficit amounted to \$5.5 billion, thus showing an annual rate which was more than double that in 1970. Movements of short-term capital funds were largely responsible for turning the surplus of \$2.7 billion in 1969 on the U.S. balance of payments on official settlements basis into a massive deficit in 1970; on current account the position had in fact shown some improvement in 1970 over the position in 1969. The trade surplus increased from U.S. \$0.6 billion in 1969 to U.S. \$2.2 billion in 1970. However, the inflow of private liquid funds of over \$8 billion in 1969 was reversed and there was an outflow of similar funds of \$6 billion in 1970.

171. The continuing recession in economic activity in the U.S. necessitated a shift in its monetary policy from restriction to ease. In the result, a considerable interest rate differential emerged in favour of the European centres. Sizeable short-term capital movements induced by this differential were mainly responsible for the widening of the balance of payments deficit in the first quarter of 1971. By April 1971, a rise in the New York Treasury Bill rates and a round of reductions in the official discount rates in Western Europe narrowed down the interest differential. But the massive flows that had already come into Europe in response to the interest differential had imparted a measure of liquidity to the continental economies which some countries, including West Germany, considered unacceptable and difficult to neutralise.

Table 30—Debt Relief Assistance

(U.S. \$ Million)

	Authorisation					Utilisation				
	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
A. By way of refinancing credits										
1. Austria	0.9	0.5	0.9	1.1	1.5	0.4	0.9	0.9	1.1	1.5
2. Belgium	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
3. France	5.0	..	10.0	3.7	1.3	10.0
4. Germany (West)	7.2	14.6	15.5	20.8	..	7.2	14.6	16.3	20.8
5. Italy	5.5	7.4	5.5
6. United Kingdom	23.5	32.5	18.0	36.0	..	23.0	32.5	18.0	36.0	..
Total—A.	24.4	40.2	45.1	61.1	33.4	23.4	40.6	38.3	55.8	38.9
B— By way of postponement of payments										
1. I.B.R.D.	15.0	15.0	15.0	15.0	..	15.0	15.0	15.0	15.0
2. U.S.A.	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
3. Canada	10.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	..
Total—B	15.7	24.5	24.6	23.7	—	15.7	24.5	24.6	23.7
C. By way of rescheduling of payments										
1. Japan	2.5	6.2	16.8	19.6	25.4	2.5	6.2	16.8	19.6	25.4
Total—C.	2.5	6.2	16.8	19.6	25.4	2.5	6.2	16.8	19.6	25.4
D. By way of Grants										
1. Austria	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2. Canada	9.3	1.1	9.3	1.1
3. Germany (West)	4.8	4.8	4.7	4.8	5.0	4.7
4. Netherlands	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7
Total—D	—	9.3	7.0	5.9	5.9	—	9.3	7.0	6.1	5.9
Grand Total	26.9	71.4	93.4	111.2	88.4	25.9	71.8	86.6	106.1	93.9

Table 31—Inflow of Foreign Assistance : Gross and Net

(U.S. \$ Million)

Year	Gross aid utilisation	Amortisation payments	Interest payments	Total debt service (2+3)	Net inflow of aid (1—4)
1961-62	711	121	70	191	520
1962-63	933	101	81	182	751
1963-64	1,239	113	96	209	1,030
1964-65	1,520	145	110	255	1,265
1965-66	1,622	162	141	303	1,319
1966-67	1,509	210*	153	363	1,146
1967-68	1,570	275*	163	438	1,132
1968-69	1,218	276*	182@	458	760
1969-70	1,082	317*	189@	506	576
1970-71	1,000	339*	211@	550	450

*Excludes amounts rescheduled/postponed as under:

	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
Japan	3	6	17	19	25
I.B.R.D.	15	15	15	15
U.S.A.	6	6	6
Canada	1	1	1	..
Total	3	22	39	41	46

@Excludes interest payments postponed by the U.S.A. amounting to \$83 million each in 1968-69, 1969-70 and 1970-71

Table 32—Aggregate External Assistance (Cumulative)

(U.S. \$ Million)

	Loans	Grants	P.L. 480/665 Aid and Third Country-cur- rency Assistance	Total
Authorisations				
1. Upto Third Plan	7,991	823	3,358	12,172
2. During 1966-67	1,425	106	524	2,055
3. During 1967-68	595	22	324	941
4. During 1968-69	1,052	93	96	1,241
5. During 1969-70	697	40	98	835
6. During 1970-71	906	75	..	981
Total	12,666	1,159	4,400	81,225
Utilisation				
1. Upto Third Plan	5,797	708	2,948	9,453
2. During 1966-67	903	126	480	1,509
3. During 1967-68	1,074	81	415	1,570
4. During 1968-69	1,008	97	113	1,218
5. During 1969-70	900	39	143	1,082
6. During 1970-71	892	58	50	1,000
Total	10,574	1,109	4,149	15,832

NOTE : Please refer to footnotes to Table 29.

Table 33—Aggregate External Assistance : Source-wise

(U.S. \$ Million)

	Authorised upto March 1971				Utilised upto March 1971			
	Loans	Grants	P.L. 480/ 665 Aid and Third Country Currency Assistance	Total	Loans	Grants	P.L. 480/ 665 Aid and Third Country Currency Assistance	Total
I.B.R.D./I.D.A.	2,371	2,371 (13.0)	2,047	2,047 (12.9)
U.S.A.	4,367	382	4,400	9,149 (50.2)	3,955	353	4,149	8,457 (53.4)
U.S.S.R.	1,362	16	..	1,378 (7.6)	893	14	..	907 (5.7)
West Germany	1,260	28	..	1,288 (7.1)	1,110	27	..	1,137 (7.2)
United Kingdom	1,276	16	..	1,292 (7.1)	1,124	15	..	1,139 (7.2)
Japan	478	1	..	479 (2.6)	451	1	..	452 (2.9)
Others	1,552	716	..	2,268 (12.4)	994	699	..	1,693 (10.7)
Total	12,666	1,159	4,400	18,225 (100.0)	10,574	1,109	4,149	15,832 (100.0)

NOTE : Please refer to footnotes to Table 29.

Figures in brackets represent percentages to total.

172. In this context, the role of exchange rate changes, the responsibility of the U.S. to adjust its external accounts rapidly, the nature of the regulation-free Euro-dollar market, and the working of the existing international payments adjustment mechanism generally became matters of more open high level discussions and pronouncements, and led in turn to a massive speculative outflow from the U.S. in anticipation of a change in currency parities, particularly of the Deutsche mark.

173. In this situation, the German and Dutch authorities decided to allow their currencies to float on the markets. Switzerland and Austria upvalued their currencies by 7.07 per cent and 5.05 per cent, respectively, and Belgium transferred all capital payments from the official market in which the dollar is supported by the National Bank of Belgium to the free market in foreign exchange, all current payments being simultaneously restricted to the official market.

174. The magnitude and volatility of short-term capital movements accentuate the strains caused by payments imbalances and inhibit the monetary autonomy of national authorities. As the Euro-dollar market not only provided a highly efficient channel for these movements but was also a significant source of such funds, the central banks of the Group of Ten reached around the end of the year under report, an agreement to abstain from making further deposits in the market and are considering methods to regulate the market.

International Liquidity and LDCs

175. Simultaneously with the consideration of measures to control the transmission mechanism by regulating the Euro-dollar market, attention is being given to the problem of excessive international liquidity. In this connection, it has to be noted that by far the larger share of the total addition to international liquidity in 1970 accrued to the developed nations. Aggregate world reserves consisting of gold, foreign exchange, SDRs and reserve positions in the Fund rose by \$14.2 billion as against only \$0.74 billion in 1969. The reserves of less developed countries increased by \$2.6 billion as against \$1.5 billion in 1969, but those of developed nations swelled by \$11.7 billion whereas they had fallen by \$0.7 billion in the previous year. Increases in total foreign exchange holdings alone accounted for \$12.1 billion of the total addition to international liquidity in 1970. Foreign exchange holdings of less developed countries rose by only \$1.9 billion while those of the developed nations went up by as much as \$10.2 billion, reflecting the huge dollar outflows principally to industrial Europe and Japan. The allocation of SDRs to the tune of \$853 million at the beginning of 1970 accounted for about one-third of the modest increase in the reserves of the less developed countries during the year.* In the case of developed countries, however, the allocation of \$2.6 billion of SDRs accounted for less than one-fourth of the rise in their reserves.

176. The developing countries did not materially benefit from the huge additions to international liquidity during the year under review. Indeed, but for the SDR allocations, their position would have been less healthy than in 1969. Healthy international economic relationships demand orderly creation of additional liquidity. To this end, SDRs, the new instrument of liquidity, need to be protected and vigorously developed; and adjustments needed to prevent the kind of excessive liquidity creation that took place in 1970—and has continued in 1971 also—should not impose any sacrifices on the economies of developing countries seeking to develop at a socially tolerable pace.

U. K.'s Entry into E. E. C.

177. Another development of major international monetary significance is the likely entry of the U.K. into the European Economic Community, which foreshadows a fairly rapid change in the role of sterling. The U.K. has made clear to the EEC her "readiness to envisage an orderly and gradual reduction of official sterling balances" after her accession.

*This reserve gain itself was unevenly distributed among the less developed countries: countries whose exports consist chiefly of petroleum, minerals or manufactures accounted for half of the gain of the group.

Apart from the understanding given by the U.K. to the EEC, the shedding of the reserve role of sterling is also widely being discussed. For the present official holders of sterling, including India, changes in the status of sterling would be a matter of considerable importance. Alternative reserve assets as well as alternative intervention currency/currencies would have to be found. The arrangements moreover should not entail any losses, either in terms of liquidity, earning power or exchange value. From this point of view the proposal reported to be made by one of the EEC partners is fraught with considerable danger. The proposal is that the existing holders of sterling balances should be guaranteed a lower percentage than at present of their holdings while extending the period of guarantee.

International Monetary Reform

178. The May 1971 currency crisis in Europe has expectedly given a further impetus to the efforts to reform the international monetary mechanism. Accordingly, increased flexibility for day to day market rates of exchange appears to have gained wider approval during the year as one instrument of reform. Simultaneously, however there has been a move towards a lowering of the margin for fluctuations in the rates of the EEC currencies among themselves. The EEC Finance Ministers had decided to make a beginning on June 15, 1971 towards a reduction in the maximum possible swings among their currencies in terms of one another. But the floating of the D-mark and the Netherlands guilder from May 10, 1971 has prevented this step being taken as scheduled. Fixed market exchange rates among the EEC currencies may confer material benefits on the EEC economies. But if this development takes place simultaneously with a widening, under the IMF statutes, of the margins within which the members' currencies may fluctuate on the markets, the non-EEC currencies would be at a disadvantage vis-a-vis the EEC currencies. The currencies of less developed economies would be at a significantly greater disadvantage in view of their relatively weaker economic position.

World Trade and Aid Flows

179. World trade in 1970 recorded in terms of value the same rate of growth — 14-1/2 per cent — as in 1969, while the growth in volume was 8-1/2 percent or 2-1/2 percentage points lower than in the preceding year. The performance of the developing countries was impaired by the adverse movement in their terms of trade. Exports of the less developed countries increased in volume by 8 per cent as against 7 per cent in 1969, but in value they rose by 11 per cent as against 11-1/2 per cent in the preceding year. The growth in the value of developed countries' exports from 15 per cent to 15-1/2 per cent over the year, however, was accompanied by a fall in the growth of volume from 11 per cent to 9 per cent.

180. Reference was made in the last year's Report to the norms recommended in the Pearson Report in regard to the development assistance to less developed countries, and it was also pointed out that the actual assistance flows in 1969 fell short of those norms. It is widely held that adequate international liquidity encourages the flow of assistance by removing balance of payments constraints on potential providers of developmental assistance. Despite substantial accretions to the exchange reserves of most developed nations, however, the assistance flows did not materially improve in 1970. The net financial flows from members of the O.E.C.D. to developing countries showed some increase over the year owing to the growth of export credits and private investments, while official development assistance remained at about the same level as in 1969. But, as a percentage of the GNP of the donor countries, official developmental flows from the O.E.C.D. member countries declined over the year, while the total net financial flows remained at about the same level.

Assessment and Prospects

181. The review of the developments in the Indian economy during the Bank's accounting year 1970-71 in the foregoing paragraphs indicates that although the economy was able to attain for the second year in succession the targeted rate of growth in the Fourth Plan, it is currently passing through quite a difficult period. Foremost among the aspects of the economy which is causing concern is the price situation. The

year began with a strong upward pressure on prices. Subsequently, as a result of the various measures taken, prices eased off. However, in the recent months the rising trend has asserted itself once again. All the commodity groups except 'industrial raw materials' have been on the uptrend. Amongst industrial raw materials, raw cotton prices have shown a phenomenal increase. A number of 'manufacturers' have registered large increases. These include items like chemicals, machinery and transport equipment and manufactures, which are important from the point of view of future growth of the industry and exports.

182. On the supply side, while four successive years of good monsoons have eased the food situation and a comfortable stock position has been built up with the Government, there are indications that the current monsoon may not maintain this record. Sizeable areas have been affected, some by severe floods and others by severe drought. As far as food crops are concerned, this may cause perhaps no more than a small set-back to the growth rate. As regards cash crops, the performance of which is rather uneven and generally disappointing, the situation in the immediate future is likely to remain difficult.

183. The rate of growth of industrial production has fallen considerably short of the targeted rate for the Fourth Plan; and, of late, a certain amount of deceleration seems to have developed in the growth rate. Important basic industries like iron and steel and coal and capital goods industries like industrial machinery and transport equipment have all recorded absolute declines. Among consumer goods, cotton textile output continued to stagnate. Shortages of raw materials, continued slackness in public sector investment, power and transport bottlenecks and strained industrial relations have all contributed to the deceleration.

184. As regards the demand side, money supply continues to expand at a high rate. The main expansionary factor has been net bank credit to Government which has showed phenomenal increase. Bank credit to the commercial sector by contrast showed a smaller expansion both in absolute terms as well as in terms of the growth rate. Over the year, banks reduced their borrowing from the Reserve Bank by nearly one-third of the outstanding level. The larger bank credit to Government reflects generally the growing imbalance in the budgetary operations, arising mainly on account of the considerably smaller growth rate of total receipts despite a slow-down in the rate of growth in total disbursements. The imbalance is particularly marked in the case of the State Governments, which used up more than twice the amount of Reserve Bank credit as compared to the Central Government. Though the Central Government has taken a number of measures in the budget for 1971-72 to raise tax revenues to meet the growing needs of development and to provide temporary shelter to the evacuees from East Bengal, the dimensions of the evacuee problem have grown so vastly as to place an intolerable burden on the resources. The overall budgetary position of the State Governments continues to add to the monetary expansions at a substantial rate.

185. Investment in the economy has shown a moderate degree of improvement both in the public and the private sectors. More important, investment in priority sectors such as small-scale industries and agriculture has been facilitated considerably as a result of the various measures taken to increase the flow of finance to these sectors. All the same, the total volume of investment needs to be stepped up significantly if the Fourth Plan expectations are to be fulfilled.

186. In the external sector of the economy there are signs of increasing pressure. The trade as well as the current account deficits for the calendar year 1970 were somewhat larger than those for the calendar year 1969. The main cause for this is the increasing demand for imports arising out of shortages in domestic production of important raw materials and basic manufactures like raw cotton and steel. Exports have shown some signs of an improvement in the growth rate recently after a long period of low growth. However, there are as yet no clear indications that the country have achieved a high rate of growth in exports on a long-term basis. Domestic shortages of raw materials have hampered progress by raising the cost structure and causing delays in export production.

187. Many of these difficulties, it is true, have been the result of the operation of temporary factors and should soon disappear. This applies particularly to those sectors of industrial production where shortages of raw materials have been the main bottleneck. The recent liberalisation in import policy would assist industry and exports considerably in this respect. More important, in the longer perspective, the economy has made considerable progress in gearing up the institutional structure for short and long-term credit closely with the planning process initiated last year, and this was carried further. The public sector banks have enlarged their territorial coverage sizeable by opening nearly 1900 new branches mostly in the rural and semi-urban areas, providing banking facilities to a large number of previously unbanked centres. Following completion of techno-economic surveys, systematic measures have been adopted by IDBI to promote viable industrial projects in the backward areas. Another important development in this direction is the setting up of the Industrial Reconstruction Corporation of India for rehabilitation of closed industrial units or those facing the risk of closure by way of reconstruction in eastern India. The nationalised banks have oriented their lending policies in the light of national policies and priorities and have shown notable progress in implementation of schemes designed specifically for the benefit of borrowers of small means. The establishment of the Credit Guarantee Corporation which would provide guarantee for lendings by these banks to small borrowers other than small-scale industries for which these facilities already existed, would provide the banks valuable support. Under the Lead Bank Scheme district surveys have been completed in about 165 districts by the public sector banks and the process of co-ordination for allocation of newly identified centres between the banks has been initiated; this should pave the way for co-ordinated action in implementation of district credit plan. The Small Farmers Development Agencies and the Marginal Farmers and Agricultural Labour Agencies have been set up in a large number of selected districts. In the industrial sector, with a view to improving the existing system of distribution of raw materials, besides widening the scope of the MMTC and STC, three institutions, viz., the Cotton Corporation, the Jute Corporation and the Cashew Corporation have been newly constituted and have already started functioning. In respect of the Industrial Policy there was a distinct policy reorientation in favour of industries established in backward regions and those in the small-scale sector. Positive steps were also taken to foster the development of 'joint sector' on the lines of the Dutt Committee Report.

188. Progress also continues to be made in the spread of the new technology in agriculture. Larger utilisation of the irrigation potential, wider spread of improved seeds and fertilisers, and better farming practices mean that the basic need of the public for foodgrains can be satisfied reasonably. However, there are still large areas subject to the vagaries of the monsoon. Also, even in foodgrains most of the breakthrough is in respect of wheat. Efforts at evolving dry farming techniques and further exploitation of deeper acquiferous of ground water call for the highest priority. Again, in a predominantly rice eating country the long-term solution of the food problem requires a breakthrough in rice technology. This in turn means that research efforts in this regard need to be further strengthened. Progress in developing an appropriate technology for the cash crops continues to remain inadequate. Research efforts are being pursued to overcome these inadequacies.

189. These developments suggest that the economy is in a better position than ever before to attain a high sustained rate of growth. With the progress that is being made in agriculture a vast market for industrial products is beginning to wake up. To tap it fully would require a strong and sustained upsurge in industrial production requiring in turn a step-up in investment by both the public and the private sectors. It will also require overcoming the various organisational deficiencies that have come to light in recent years in both the public and the private sectors of industry and an improvement in the industrial relations.

190. The most important need of the moment, however, is the maintenance of a reasonable degree of price stability in the economy. The massive increases in money supply that are taking place largely as a result of the budgetary

operations of the governmental sector pose a difficult problem in this regard. Unless a reasonable degree of balance is achieved between these increases in money supply and the increases in real income, there is a likelihood of the price situation getting out of hand once again. Balance is also necessary between the governmental sector and the private sector as to the use of bank credit. This would call for the most careful control on the use of bank credit by both the sectors, in addition to such measures as direct controls in suitable cases for protection of the weaker sections.

II. DEVELOPMENTS IN INDUSTRIAL FINANCE

IDBI's Operations and Policies

191. During the year under review, the Industrial Development Bank of India (IDBI) intensified its efforts to widen the scope and enlarge the size of its operations. Apart from streamlining its set-up and refining its methods and criteria regarding the operations of its existing schemes of finance, it adopted special measures to promote viable industrial projects, particularly in the backward areas. The IDBI is playing a role of a catalytic agent in inducing and bringing together, under its leadership, various all-India and State level institutions, including the lead banks and the Industries Departments of State Governments to form an inter-institutional group to take decisions on a wide range of problems. These range from identification of a project to preparation of detailed project reports and provision of technical and financial assistance possibly on a consortium basis. Surveys to identify concrete projects, initiated during 1969-70 in collaboration with other term-lending institutions, were completed during the year in eight States and four Union Territories. The survey reports relating to four States and one Union Territory were finalised and follow-up action initiated. The possibilities of setting up projects that have emerged from these surveys are being discussed with the concerned State Governments. In some cases, even before such discussions, the feasibility studies of some identified project ideas are being made in association with some private technical consultancy services.

192. An important measure for stimulating the setting up of industrial projects in backward areas is the system of differential interest rates, to which a reference was made in the Annual Report for the year 1969-70. The changes effected in IDBI's lending rates during the year under review further widened the interest rates differentials. Thus, in October, 1970, when it raised the normal rate of interest on direct loans to industrial concerns (other than for exports) and again, in January 1971, when it raised the refinance/rediscout rates following the raising of the Bank rate by the Reserve Bank, the concessional rates for direct loans and refinance in respect of industrial units in backward areas were kept unchanged.

193. During the year, IDBI took further steps to encourage the flow of institutional finance to the small-scale sector. These include simplification of procedures for sanction and disbursement of refinance to State Financial Corporations (SFCs) in respect of term loans up to Rs. 2.00 lakhs, thus making the refinance scheme near-automatic.

194. Among its existing schemes of assistance in the field of export finance, IDBI has emerged as a major partner along with commercial banks. It has set up two groups, viz., the Informal Consultative Group and the ad-hoc Working Group, comprising members, in both the groups, from IDBI, commercial banks, the Reserve Bank and Export Credit Guarantee Corporation (ECGC). The objective of the Consultative Group is to discuss broad problems and policies in the field of export finance and identification of possibilities in the fields of exports of goods and services, and turn-key jobs and joint ventures abroad. The Ad-hoc Working Group is to provide guidance to exporters at the pre-bid stage and to expedite the processing of cases. IDBI also gave wide publicity to the export schemes operated by it and conducted seminars of bankers in Bombay, Calcutta, New Delhi and Madras on the techniques of financing exports on deferred payment basis so as to share ideas and experience in the field.

195. During 1970-71, IDBI constituted Regional Committees at Calcutta, Madras and New Delhi to help and guide the regional offices opened at these centres during the previous year and to take decisions for sanction of assistance upto specified limits. The regional offices together with the branch offices opened so far in 9 other centres would enable IDBI to have a first hand knowledge of the regional problems and to establish live contacts with State level institutions as well as with potential entrepreneurs.

196. Another important development during the year was the setting up of the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd., at the initiative of IDBI, on April 12, 1971, as a joint stock company with its headquarters at Calcutta. It has authorised and subscribed capital of Rs. 25 crores and Rs. 10 crores, respectively. The IDBI has subscribed 50 per cent of the share capital, and the balance was shared by the Industrial Finance Corporation of India (IFCI), the Life Insurance Corporation of India (LIC), the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd., (ICICI), the State Bank of India and the nationalised banks. The Corporation will endeavour to rehabilitate closed industrial units or those facing the risk of closure, by way of reconstruction of share capital, strengthening of management, diversification of products, improvement in technology and labour relations and rendering financial assistance on soft terms.

197. During the year under review, IDBI's size of operations, both sanctions and disbursements under all the schemes of finance, was markedly larger than during 1969-70. Total sanctions of assistance (excluding guarantees) at Rs. 131.1 crores during 1970-71 were double the level in 1969-70 (Rs. 65.2 crores). Disbursements were also higher by about 50 per cent, having risen from Rs. 52.3 crores in 1969-70 to Rs. 78.4 crores in 1970-71. Since its inception till the end of June 1971, IDBI's assistance sanctioned (excluding guarantees) totalled Rs. 466.2 crores and disbursements Rs. 358.4 crores. Assistance outstanding as on June 30, 1971 amounted to Rs. 265.3 crores. Besides, guarantees sanctioned up to the end of June 1971 amounted to Rs. 31.0 crores.

198. IDBI's direct assistance (other than for exports) in the form of loans, underwriting and guarantees sanctioned to industrial concerns increased from Rs. 16.3 crores in 1969-70 in respect of 22 projects to Rs. 51.4 crores in 1970-71 covering 33 projects. Special attention continued to be paid to comparatively small projects introducing new technology set up by technician-entrepreneurs, and during the year, it sanctioned assistance to two such projects. Besides assisting 16 other projects (including three public sector projects), which envisaged the setting up of new capacity or expansion/diversification of existing capacity in various types of industries, supplementary assistance was granted to 15 projects for meeting the over-run in project cost and/or relieving the strain on the financial position of industrial concerns. It has been the policy of IDBI to assist public as well as private sector projects which are economically viable and which could be managed efficiently during their gestation period as well as later.

199. In the sphere of refinance of industrial loans, sanctions during the year at Rs. 25.6 crores were higher by 79 per cent as compared with Rs. 14.3 crores in 1969-70. Refinance assistance in respect of loans to small-scale industries and small road transport operators continued to increase both in absolute terms and as a proportion to total refinance. Of the total refinance assistance sanctioned for Rs. 25.6 crores in respect of 1,483 applications during 1970-71, those granted to small-scale industrial units and small road transport operators amounted to Rs. 14.8 crores in respect of 1,388 applications; assistance sanctioned to these sectors more than doubled as compared with that in 1969-70 (Rs. 6.1 crores). As a proportion of total refinance, such assistance increased from 43 per cent in 1969-70 to 58 per cent in 1970-71.

200. The scheme for rediscounting of machinery bills has benefited several machinery manufacturers and users of machinery. The face value of bills rediscounted rose from Rs. 24.1 crores in 1969-70 to Rs. 28.5 crores in 1970-71. Total assistance under the scheme up to the end of June

1971 amounted to Rs. 89.9 crores, benefiting in all 209 machinery manufacturers and 1,059 purchaser-users of machinery. In order to acquaint the discounting banks with the procedural matters relating to the scheme and also to benefit from their experience in operating it, IDBI conducted recently four seminars of commercial bank officers associated with the scheme at Bombay, New Delhi, Calcutta and Madras.

201. The IDBI's assistance under the export finance scheme also registered a notable increase during the year under review. Sanctions under this head rose from Rs. 12.5 crores in 1969-70 to Rs. 26.1 crores in 1970-71. This covers both direct loans and guarantees to exporters (Rs. 12.4 crores) and refinance of export credits (Rs. 13.7 crores). The assistance sanctioned covered exports of a wide range of engineering products such as steel rails, bars and railway track equipment, diesel engines, railway wagons, textile machinery, transmission line towers, automobiles and spares, etc.

202. During the year, IDBI contributed Rs. 1.8 crores to the special debentures of ICICI. The amount disbursed to ICICI since inception up to the end of June 1971 totalled Rs. 15.7 crores. Besides, IDBI subscribed, up to the end of June 1971, Rs. 6.9 crores to the bonds and shares issues of 16 SFCs.

Other All-India Term-Lending Institutions

203. The size of operations of the other all-India term-lending institutions also showed an appreciable rise during the year under review. Thus, the operations of the ICICI showed a marked increase in sanctions (rupee and foreign currency loans, underwriting and direct subscriptions) from Rs. 22.8 crores in 1969-70 (April-March) to Rs. 43.0 crores in 1970-71. Its disbursements at Rs. 29.2 crores in 1970-71 were also considerably higher than in 1969-70 (Rs. 19.8 crores). The increase in sanctions was mainly brought about by increases in foreign currency and rupee loans. In the case of the IFCI, while total sanctions (rupee and foreign currency loans, underwriting and direct subscriptions) registered a notable increase from Rs. 18.6 crores in 1969-70 to Rs. 35.0 crores in 1970-71, disbursements during the year at Rs. 17.4 crores were more or less at the same level as in the previous year.

Operations of State Financial Corporations

204. Total loans sanctioned by 18 SFCs (including the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation) during the period April 1, 1970 to March 31, 1971 increased by over 50 per cent to Rs. 49.0 crores from Rs. 32.2 crores in 1969-70. Disbursement during the period were also noticeably higher at Rs. 32.9 crores as compared with Rs. 21.4 crores during the previous year. Loans outstanding as on March 31, 1971 stood at Rs. 127.9 crores, registering a net increase of Rs. 23.4 crores over the outstanding as on March 31, 1970. Of the total sanctions and disbursements during 1970-71, the share of small-scale industries was Rs. 35.8 crores (73.1 per cent) and Rs. 22.7 crores (69 per cent), respectively. Till January 1971, i.e., before the Bank rate was raised, the effective lending rate of SFCs to small-scale industries ranged between 7 per cent and 8 per cent subject to availability of refinance from IDBI at a concessional rate of 4-1/2 per cent per annum. Consequent upon the increase in the Bank rate from 5 per cent to 6 per cent, IDBI raised its concessional rate of refinance from 4.5 per cent to 5 per cent subject to the rate charged to borrowers by the financial institutions not exceeding 8.5 per cent. Correspondingly, nine SFCs raised their lending rates generally by 0.5 per cent. On loans to other units, the effective lending rate was between 7.5 per cent and 10.5 per cent. Four SFCs charged interest at 6 per cent per annum to borrowing units in backward areas.

205. In pursuance of the recommendations of the 14th Conference of representatives of SFCs, a Working Group on Resource Mobilisation, Profitability and Allied Problems of SFCs was set up in April 1970. The Group's Report submitted in December 1970 is at present under consideration of the Reserve Bank of India.

Financing of Small-Scale Industries

Credit Guarantee Scheme

206. The Credit Guarantee Scheme as modified with effect from February 1, 1970 (details of which were given in the previous year's Report) made considerable progress during the year under review. By the end of June 1971, 149 credit institutions including all the major commercial banks, and 56 co-operative banks and State Financial Corporations had joined the modified Scheme. The amount of guarantees outstanding as at the end of June 1971 stood at Rs. 790.97 crores as against Rs. 661.77 crores at the end of June 1970. Since the inception of the Guarantee Scheme in July 1970. Since the inception of 1971, claims of guarantee obligations numbering 200 for an aggregate sum of Rs. 27.15 lakhs were paid to the credit institutions. However, as at the end of March 1971, amounts reported in default, which might eventually lead to settlement of claims, covered 1,799 cases for Rs. 589.04 lakhs, as against 463 cases for Rs. 141.97 lakhs as at the end of June 1970.

207. One of the important objectives of the modified Scheme is to introduce an element of automaticity in the guarantee cover available to credit institutions. This has been achieved inasmuch as the credit facilities granted to small-scale industries by banks/Corporations are deemed to be guaranteed as soon as they are granted and reported to the Guarantee Organisation (RBI) in the prescribed quarterly statements. Further, under the modified Scheme, the Guarantee Organisation bears a larger risk than under the earlier Scheme. To ensure that credit institutions exercise due vigilance and care in sanctioning and recovering advances to small-scale industrial units, the Guarantee Organisation has introduced a programme of test checks of quarterly statements by deputing its officers to the branches of banks. During the first year of the operation of the modified Scheme, 5 per cent of the reporting branches were selected for test checks.

208. As the Guarantee Scheme has been introduced with a view to enlarging the flow of institutional credit to small-scale industries, the Guarantee Organisation operates the Scheme in a manner helpful to the small industries, particularly the weaker units. On a suggestion made by the Guarantee Organisation, 74 banks (including major commercial banks) and 16 State Financial Corporations have agreed to bear themselves the guarantee fee at 1/10 of 1 per cent instead of recovering it from their constituents. With the guarantee facilities afforded under the Scheme, credit institutions are expected to liberalise, where necessary, their terms of lending to small-scale industries, particularly in regard to margin requirements. Soft loans or loans on a clean basis, wherever deserving, might be extended by credit institutions, especially in respect of schemes promoted by qualified technicians/entrepreneurs. The Guarantee Scheme covers such soft or clean advances. Where a unit defaults in the payment of its dues to a bank, the Guarantee Organisation examines expeditiously the possibility of rehabilitating it and in deserving cases, the credit institution is urged to undertake a programme of nursing.

Scheduled Commercial Bank's Finance to Small-scale Industries

209. During the 9 month period July 1970 to March 1971, total credit limits sanctioned by scheduled commercial banks to small-scale industries recorded a rise of Rs. 83.8 crores to Rs. 868.3 crores over and above the increase of Rs. 156.8 crores in limits sanctioned in the corresponding period of 1969-70. The number of units financed increased from 89,307 to 1,03,550 or by 15.9 per cent. The amount of outstanding advances totalled Rs. 493.1 crores as at the end of March 1971, showing a rise of Rs. 79.1 crores as against an increase of Rs. 108.3 crores during July 1969—March 1970. The relatively smaller rise in credit extended by banks to small-scale industries during the period under review has to be viewed in the context of spurt

in advances to this sector since June 1968, the rise in credit between June 1968 and June 1970 being Rs. 224 crores. It is also significant to note that the proportion of bank credit to small-scale industries in total bank credit has gone up during the latter part of 1970-71 busy season was felt less from 9.8 per cent in June 1970 to 10.6 per cent in March 1971, indicating that the impact of credit stringency witnessed on the flow of credit to small-scale industry sector than on other sectors. The share of industrially backward States in advances to small-scale industries has gone up since June 1968, the increase being particularly marked in respect of Andhra Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. The amount of term loans (including instalment credit) sanctioned by scheduled commercial banks to small-scale industrial units as at the end of December 1970 was of the order of Rs. 112 crores, the outstanding against which amounted to Rs. 76 crores, i.e. about 16 per cent of the total credit to this sector.

210. The banks in the public sector (the State Bank of India and its subsidiaries and 14 nationalised banks) accounted for 89 per cent of the total outstanding credit to small-scale industries, the share of the State Bank of India and its subsidiaries being 40 per cent. The credit limits sanctioned by the State Bank of India Group to small-scale industries as at the end of March 1971 amounted to Rs. 320.4 crores recording a rise of Rs. 28 crores over the June 1970 level. This increase was less than half the rise in the corresponding period of 1969-70. The outstanding credit by this Group to small-scale industries at Rs. 197 crores as at the end of March 1971 showed a rise of Rs. 33.7 crores (or 21 per cent) over the level at the end of June 1970. The amount of loans sanctioned by the State Bank of India Group, under their Scheme for financing craftsmen and other qualified entrepreneurs, more than doubled from Rs. 3.4 crores covering 297 units as at the end of March 1970 to Rs. 7.1 crores covering 562 units as at the end of March 1971.

211. The 14 nationalised banks sanctioned to small-scale industrial units credit limits for an aggregate amount of Rs. 459 crores as at the end of March 1971, showing a rise of Rs. 47 crores (or 11 per cent) between June 1970 and March 1971. The number of units financed by these banks increased by 5779 during the period. Outstanding credit at Rs. 244 crores at end-March 1971 showed an increase of Rs. 37.2 crores which was somewhat lower than the increase in the corresponding period of 1969-70 (Rs. 50.7 crores).

212. A reference was made in the last year's Report to the special schemes formulated by banks to finance technically qualified entrepreneurs on liberal terms. Data available for seven nationalised banks show that these banks had, under their respective schemes, sanctioned Rs. 1.35 crores covering 540 entrepreneurs as at the end of December 1970.

213. There was a further step-up in the scale of assistance by scheduled commercial banks to small road and water transport operators. Credit limits sanctioned to this sector as on the last Friday of March 1971 amounted to Rs. 63.9 crores, showing a rise of Rs. 23.2 crores over end-June 1970 level as compared with the rise of Rs. 20.8 crores in the corresponding period of 1969-70. The amount of outstanding credit at Rs. 47.5 crores as at the end of March 1971 was about 50 per cent higher than that as at the end of June 1970 (Rs. 30.6 crores). There was also a marked increase in the credit extended by scheduled commercial banks for setting up industrial estates, the amount of limits sanctioned being Rs. 3.74 crores as at the end of March 1971 as against Rs. 1.17 crores as at the end of March 1970, and the amount outstanding being Rs. 3.17 crores as compared with Rs. 36 lakhs.

Unit Trust of India

214. Sale of units during the period July 1, 1970 to June 30, 1971, amounted to Rs. 18.00 crores as against Rs. 22.83 crores in the corresponding period of the preceding year; the corresponding repurchases were Rs. 3.19 crores and Rs. 2.03 crores. A moderate set-back noticed in 1970-71 reflected mainly the hardening of the interest rates in the economy, which improved the competitive position of other investment media available to investors in the relatively small and medium income groups. Another important factor was

the extension, under the Finance Act, 1970, of exemption from income-tax to income (up to Rs. 3,000) earned from investments in practically all types of financial assets; till then this exemption was restricted to income up to Rs. 1,000 each from investment in the Trust units and dividends on shares in Indian companies (apart from the whole of the interest earned on a number of small and postal saving schemes).

215. The aggregate value of units sold and outstanding with the Trust as of June 30, 1971 amounted to over Rs. 92.25 crores, the total number of unit-holders registered with the Trust being over 3,80,000. As of June 30, 1971, overall investments of the Trust aggregated Rs. 105.14 crores. Of these, ordinary shares accounted for Rs. 39.66 crores (37.7 per cent), preference shares for Rs. 13.08 crores (12.4 per cent), debentures for Rs. 40.89 crores (38.9 per cent) and Government securities and bonds of financial corporations for Rs. 0.45 crores (0.4 per cent). The balance of Rs. 11.06 crores (10.6 per cent) represented advance deposits for debentures which the Trust had agreed to underwrite/subscribe, application money for purchase of shares and debentures, advance call deposit and call and short notice deposits.

216. There was a further expansion in the network of agents and stock brokers who canvass sale of units among the investing public. The number of approved agents and brokers as on June 30, 1971 stood at 2,756 and 320, respectively, as against 2,303 and 315 as on the corresponding date last year. Besides sales over the counter at the Trust's Offices, units continued to be on sale at all the branches of leading banks and at about 18,000 post offices throughout the country.

217. Reference was made in the last Report to the Children's Gift Plan, 1970, launched by the Trust from July 1, 1970, which provides a facility to parents, close relatives of a minor child and others to accumulate capital in the form of units for the benefit of the child. The Plan has made a good start, sale of units under it till June 30, 1971 amounting to over Rs. 56 lakhs under more than 2,300 applications. A 'Unit-Linked-Insurance Plan' is being formulated in co-operation with the Life Insurance Corporation of India and this is proposed to be introduced shortly. The main objective of this Plan is to provide investors, especially from the relatively small and middle-income groups of the community, a facility for regular savings and investment of these savings in units of the Trust combined with the advantage of life insurance cover during the period of the Plan.

III. PROGRESS IN COMMERCIAL BANKING

218. The nationalisation of major commercial banks was done 'to control the heights of the economy and to meet progressively and serve better the needs of development of the economy in conformity with national policy and objectives.' The entire gamut of Government's economic policy has been re-oriented in recent years with a view to bringing about a better regional balance and also a more egalitarian economic base. The Lead Bank Scheme and programmes for branch expansion would no doubt bring about a wider territorial spread of banking facilities. With a view to subserving in a positive way, the social priorities through the banking system, a beginning has already been made in refining the existing methods and criteria used by the banks. The nationalised banks have considerably diversified their lending policies; simultaneously, the Reserve Bank on its part has been endeavouring to provide precise measures and guide-lines in this regard. In concrete terms, while the credit needs of organised sectors of industry and trade, which the banks hitherto almost solely met, continue to be provided for, institutional credit facilities at reasonable rates of interest are extended to a large number of borrowers of small means, such as small farmers small-scale manufacturers, retail traders, road-transport operators, small businessmen, professionals and self-employed persons. For the small-scale industries sector, a Credit Guarantee Scheme has been in operation now for more than a decade. This Scheme was systematically revised last year and the guarantee cover for the banks' lending to such industries was made almost automatic. But, there are still smaller borrowers than the small-scale industries who had been almost neglected by the banking system. With a view to facilitating the extension of credit to such borrowers whose

activities possess considerable employment potential, appropriate guidelines have been issued by the Bank. Guidelines have also been issued in respect of banks' lendings to agriculture, another field which was till recently practically outside the commercial banking lending system. Bank lending for such categories does, however, involve an element of risk and needs some cover of guarantees and therefore, a new public limited company known as the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., has been set up and the Corporation has formulated definite schemes of giving guarantee.

219. The following paragraphs bring out details of organisational changes and various schemes for bank lendings and the Reserve Bank guidelines thereon.

Scheme for Broad-based Board for Nationalised Banks

220. A reference was made in the previous year's Report to the constitution, by the Central Government, of the first Boards of Directors for each of the fourteen nationalised banks with effect from July 18, 1970. With the constitution of the first Boards of Directors, the Reserve Bank's directive of February 16, 1970, requiring the nationalised banks to obtain its prior approval for certain specified types of transactions, was withdrawn on August 14, 1970 and the banks were advised that the matters referred to therein should thenceforward be decided by their respective Boards of Directors. Subsequently, a scheme called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 was framed by the Central Government under Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Under the Scheme, each nationalised bank will have on its Boards directors not exceeding 15. Sub-section 3(a) of Section 9 of the Act lays down that every Board of Directors constituted under the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme framed under sub-section 1 of Section 9 shall include representatives of the employees and depositors of such banks and such other persons as may represent the interests of each of the following categories, viz., farmers, workers and artisans. The Scheme provides for two representatives of the employees of the bank and one of the depositors, besides providing one representative each of the interests of farmers, workers and artisans. Government are also empowered to appoint not more than five directors from amongst persons having special knowledge or practical experience in respect of one or more matters which are likely to be useful for the working of the nationalised banks. There will also be not more than two wholetime Directors, of whom, one shall be the Managing Director. Besides, there will be one official of the Reserve Bank of India and one official of the Central Government on each of the Boards.

221. The Scheme also makes provisions for the appointment in each nationalised bank of two employees on the Board of Directors—one from among those who are workmen in the bank and the other from the employees in the bank other than workmen. The director from the employees who are workmen is to be appointed by the Government out of a panel of three names furnished by the Representative Union in the concerned bank. The other director from amongst employees who are not workmen would be appointed by the Government in consultation with the Reserve Bank of India.

222. A Representative Union has been defined in the Scheme as a Union registered under the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926) or a federation of such Unions, where such Union or federation, as the case may be, is certified, after due verification by the Chief Labour Commissioner (Central), as having the largest number of workmen employed in the nationalised bank as members who have regularly paid their dues to the Union or to any of the Unions constituting the federation. This is subject to a minimum of 15 per cent of the total number of workmen employed in the concerned nationalised bank being verified members of the Union or federation. The First Schedule to the Scheme prescribes the procedures to be followed for verification of membership of Unions operating in nationalised banks.

223. Under the Act, referred to above, the Scheme is required to be placed before both the Houses of Parliament for a minimum period of thirty days before it could be brought into force. The Scheme was accordingly placed before

both the Houses of Parliament on November 17, 1970 and was discussed by the two Houses in December, 1970.

Foreign Branches of Nationalised Banks

224. With regard to their overseas branches, the nationalised banks are taking suitable steps according to local laws in each country for effecting the transfer of the properties and other assets, etc., standing in the names of the then existing banks to the corresponding new banks. As mentioned in the previous year's Report, in Uganda, the two nationalised banks concerned, viz., Bank of Baroda and Bank of India, have formed subsidiary companies to comply with the local legal requirements. The Government of Uganda had earlier acquired 60 per cent of shares in these companies. This position has recently undergone a change and the Government share-holding in the company has been reduced to 49 per cent. Negotiations are now in progress for taking over the subsidiary Bank of India by the subsidiary Bank of Baroda. In the case of the branches in Malaysia, as foreign State-owned or State-controlled banks are not permitted to carry on banking business in that country, it is proposed to form a new company to take over the business of the eleven branches of the three Indian banks, viz., Indian Bank, Indian Overseas Bank and United Commercial Bank. The three corresponding new banks in India and Malaysian citizens of Indian origin would each hold 33 1/3 per cent of the paid-up capital of the proposed company. 30 per cent of the paid-up capital would be allotted to other Malaysian citizens, companies and corporations resident in Malaysia and the remaining 3 1/3 per cent would be unrestricted. As for branches in Singapore, the Parliament of that country has passed the Banking Act, 1970 which came into force in January, 1971. Under Section 9 of the Act, no bank whose Head Office is situated outside Singapore shall be granted licence unless (i) its issued and paid-up capital is not less than the equivalent of 6 million Singapore dollars (about Rs. 1.47 crores), and (ii) it holds net Head Office funds not less than 3 million Singapore dollars (about Rs. 73.50 lakhs), in respect of its business in Singapore at all times in the form of approved assets. The banks are required to comply with these provisions within a period of two years from the date of coming into operation of the said Act, i.e., by the end of December, 1972. Further, every bank in Singapore is required to pay such annual licence fee as may be prescribed by their Government. For the year 1971, licence fee of S. \$50,000 for the main branch and S. \$5,000 for each of the sub-branches in Singapore has been prescribed and the four banks, viz., United Commercial Bank, Bank of India, Indian Bank and Indian Overseas Bank, have paid the requisite fees for the year.

225. The future set-up of the foreign branches of the Indian banks is under consideration.

Lead Bank Scheme

226. The previous year's Report contained genesis, objectives and basic programmes of the Lead Bank Scheme introduced by the Bank in December 1969. The basic objective was one of orienting banking development in the country towards an "area approach" and thus ensuring that the developmental needs of all regions and all sections of the community are served by the banking system in conformity with national priorities. Under the Scheme, all the districts in the country were allotted among public sector banks and a few of the private sector banks. Each bank is expected to survey the potential for banking development in the allotted districts, to identify institutional and credit gaps and to take the initiative in endeavouring to fill them and thus intensively involved itself in the process of economic advancement of the districts concerned: in sum, the promotion of the development of the district through the medium of banks. The immediate task before the banks, therefore, was to acquire a basic knowledge of the districts allotted to them so as to enable them to formulate suitable schemes of action. For this purpose, banks were asked to carry out quick and impressionistic initial surveys of resources and potentials of the districts allotted to them. On completion of surveys for some of the districts allotted to each bank, with a view to bringing about greater co-ordination amongst themselves and the district developmental programmes and laying down the basis of follow-up programme of action, a team of three officers from the Reserve Bank and the Union Finance Ministry held intensive, individual discussions regarding the surveys with the Custodians/Chairmen and Senior Officials so as to improve the

scope of the survey and highlight the significance of the scheme and the follow-up action needed.

227. Good progress has been made by the banks in completion of surveys of the districts allotted to them. The Survey reports in respect of 165 districts out of 335 have been completed and the reports in respect of most of the other districts are in the process of preparation.

228. To set the pattern of mutual cooperation among banks and illustrate the manner of allocation of identified centres, the Bank convened regional conferences of bankers at six cities, viz., Madras, Calcutta, Patna, Kanpur, Bhopal and Delhi in which, of the 1,194 unbanked centres identified by the lead banks in the course of their surveys, 383 centres were allotted to lead banks and 341 centres to other banks. Banks have been told that, as far as possible, the process of branch expansion in identified centres in each district should be done under the auspices of the concerned 'lead bank'. Following this pattern, banks have been convening meetings to finalise allotment of centres identified by them.

229. To provide a basis for appropriate follow-up action at the district level including co-ordination of commercial banks' programmes with the district development programmes, some banks have already set up Co-ordination Committees comprising representatives of financial institutions operating in the district and district officials.

Credit Planning

230. Credit planning or a rational allocation of the resources available with banks, is an important aspect of economic planning and policy. The significance of such planning is enhanced when banks have to operate principally with the deposits they are able to mobilize and when recourse to borrowings from the central banks is restricted and is itself tuned to overall plan and monetary requirements. For the system as a whole, the Reserve Bank undertakes formulation of a broad credit plan, taking account of the national priorities, the anticipated pace of deposit accretion, general economic situation and likely developments in different sectors. The first step in the formulation of a credit plan is to provide allocation for certain pre-emptions such as investments in Government securities and the requirements of certain essential governmental commercial operations like food procurement, buffer stock operations, etc. Another important step is that of arriving at aggregative estimates for key sectors including the priority sectors. Separate estimates are made for the busy and slack seasons, particularly in respect of sectors susceptible to seasonal changes.

231. Against the background of this broad credit plan for the system as a whole, the individual credit plan of each bank is viewed. Discussions are held periodically with each individual bank to assist it in working out its programme for deployment of funds, taking account of the special circumstances in which each bank operates and with the objective of serving national priorities while maintaining reasonably good profitability. To this end advice is given to raise the credit-deposit ratio in cases where it is low. Since any scheme for fuller utilisation of resources presupposes a substantial 'roll over' of credit, banks are asked to explore the scope for redeployment of existing credit and linking it to genuine productive purposes. There is, besides, the effort to enlarge the use of the bill of exchange as an instrument of credit under the new Bill Market Scheme. As an initial step in this direction, banks are endeavouring to change over from the existing practice of lending against book debts of companies, etc., to that of discounting bills drawn in respect of such transactions. Also in this context, the need to ensure the recovery of loans, extended particularly to sectors in which the banks are yet relatively inexperienced, is stressed. Considering the complexity of the tasks ahead, banks are asked to devote urgent attention to the building up of a strong organisational set-up to undertake comprehensive credit plans for the future.

Credit Authorisation Scheme

232. The Credit Authorisation Scheme, which was introduced by the Reserve Bank in 1965 as one of the measures to align bank credit in accordance with Plan priorities, has undergone a major transformation during the year under review. The focus, which was purpose-oriented, has been widened to cover credit appraisal on the part of the sche-

duled commercial banks with a view to imposing financial discipline on the larger borrowers. For the purpose of proper assessment of the credit requirements in the light of the past performance as revealed by the financial statements of borrowers and the end-use of the credit, the Bank had, in terms of the circular letter of June 30, 1970, introduced a comprehensive set of forms for credit appraisal, as finalised by the Study Group set up for the purpose. Accordingly, banks are now required to collect and study data furnished by borrowers on (a) utilisation of the existing credit limits, (b) total working capital requirements and bank finance permissible together with the data relating to the borrowing company's ability to meet the gap between the two, (c) comparative financial position for the previous 3 years, (d) cash flow and (e) in respect of term loans, project cost and financing thereof. The other aspects now required to be looked into are inter-corporate lending and investments, excessive inventory build-up, diversion of short-term funds for acquisition of fixed/non-current assets, payment of guarantee commission in spite of the secured nature of facilities or the low worth of the guarantors, etc. In other words, banks would now be required to lend on the basis of credit appraisal and actual needs of the borrowers. The regulatory system now evolved by the Bank, with a better co-ordination with the scheduled commercial banks, will permit a proper evaluation and financial appraisal and is expected to be a more effective mechanism for appropriate use and dispersal of bank credit. Banks have been advised that the collection of data in the prescribed forms should not be considered as an end in itself, but as a tool for taking judicious decisions on the proposals for credit facilities. It has also been suggested to them that systematic collection and processing of financial data should serve as guide for forecasting the credit requirements of the borrowers in the light of their past performance. As some of the banks indicated in this connection that their officers may require training in the matter of processing the applications for credit facilities in a systematic manner, the Bank has decided to have series of courses at the Bankers Training College, Bombay for imparting the necessary training.

233. In May 1971, the Scheme which was originally applicable to credit limit of Rs. 1 crore or more was further extended to cover individual term credit limits exceeding Rs. 25 lakhs as well. Accordingly, the banks were asked to seek prior authorisation* under the Scheme for sanctioning (singly or jointly with other institutions) individual medium or long-term loans exceeding Rs. 25 lakhs repayable over a period of more than three years to any single party, irrespective of the totality of the credit limits available to it from the banking system as a whole. This measure was also considered necessary as term loans are now granted by scheduled commercial banks on a significant scale, and there is, therefore, an imperative need for co-ordination in the activities of the banks and term-lending institutions. This type of discipline is all the more necessary as the working capital requirements of the industrial concerns would, in any case, have to be met by the commercial banks. Further, the scheduled commercial banks have been asked to furnish to the Bank a quarterly statement (commencing from the quarter ending September 24, 1971) showing certain particulars of all term loans exceeding Rs. 10 lakhs and repayable after three years, sanctioned by them during each quarter.

234. The working of the Credit Authorisation Scheme has, however, been operated with flexibility in order to ensure adequate availability of credit to industrial concerns which developed financial strains and needed sizeable and, sometimes, immediate credit facilities. Thus, in order to relieve the sugar industry from acute financial difficulty which it was facing, the Bank, in April 1971, advised 12 major banks (which were mainly financing sugar mills) that they need not seek the Bank's prior approval for sanctioning increased credit limits to the individual sugar units to the extent of 125 per cent of the previous season's maximum outstandings.

*Prior authorisation under the Scheme is not necessary in respect of (i) term-loans by way of post-shipment credit relating to exports (ii) term-loans granted to Electricity Boards and Public Sector Undertakings and those granted against guarantee of Central and State Governments and (iii) term-loans granted on the *pari passu* basis with the Industrial Development Bank of India and Agricultural Refinance Corporation or under their refinancing schemes.

235. Also, in order to assist industrial units in the Eastern Region which is beset with many political and labour problems, the Credit Authorisation Scheme has been liberalised so that the commercial banks can grant temporary or urgent credit facilities to the individual units (including coal companies) in the region, without prior authorisation. In fact, all feasible proposals for larger credit facilities or for financing all sick units have generally been expeditiously cleared both at the bank level as also under the Scheme. Similarly, the problems of the industries in Orissa and Assam, where their growth has been comparatively slow, have also been properly looked into as far as the credit facilities to larger borrowers are concerned.

236. During the year July 1970—June 1971, 338 applications were received from banks for authorisation of credit limits under the Scheme. The proposals were mostly for the purpose of meeting the working capital requirements and a few were for financing expansion/modernisation, etc., of the concerns engaged in defence/export-oriented and other priority industries. As for the rejection of certain applications, the main reason were: (i) Gross under-utilisation of the existing limits; (ii) Cornering or stock-piling of raw materials; (iii) Concentration of bank advances in the hands of a single party; (iv) Excessive reliance on bank borrowings, the company's own resources having been diverted for inter-corporate investments/lending; (v) Advances sought from a commercial bank to avoid the financial discipline

imposed by the Industrial Development Bank of India and other term financial institutions; and (vi) Advances which would indirectly defeat the purpose of selective credit control, i.e., clean loans or advances against other assets, e.g., shares, block assets, etc., to dealers in commodities covered by the directives.

Branch Expansion

237. The progress recorded in the expansion of branch net-work of the commercial banks during 1970 was unprecedented. Taking the commercial banks as a whole, as against 677 and 1,369 branches opened during the years 1968 and 1969, respectively, the new branches opened during 1970 totalled 2,137. The performance of fourteen nationalised banks in this regard was particularly impressive. These banks opened as many as 1,285 bank branches during 1970 as against 913 in 1969 and 405 in 1968. Equally impressive was the progress made by the State Bank and its subsidiaries, which together opened 626 new branches during 1970 as compared with 199 in 1969 and 161 in 1968.

238. The tempo of branch expansion continued during the first half of 1971. Thus, there was a further addition of 833 bank branches opened by commercial banks together during this period; of these, 444 were opened by the 14 nationalised banks and 265 by the State Bank group (Table 34).

Table 34—New Offices Opened by Commercial Banks during 1969-70 and 1970-71

	New Offices opened by commercial banks						Bank Offices	
	1969-70			1970-71			As on	As on
	July-Dec. 1969	Jan.-June 1970	July-June 1969-70	July-Dec. 1970	Jan.-June 1971	July-June 1970-71	June 30, 1970	June 30, 1971
1. State Bank of India	65 (36)	190 (149)	255 (185)	234 (164)	178 (123)	412 (287)	1875	2286
2. Subsidiaries of State Bank of India ..	54 (29)	116 (96)	170 (125)	86 (64)	87 (55)	173 (119)	1060	1233
3. Fourteen nationalised banks	508 (313)	677 (517)	1185 (830)	608 (413)	444 (245)	1052 (658)	5318	6368
4. Other scheduled banks	144 (78)	85 (45)	229 (123)	124 (57)	115 (65)	239 (122)	1554	1875
5. Foreign banks	1 (—)	— (—)	1 (—)	— (—)	— (—)	— (—)	131	130
6. All scheduled commercial banks ..	772 (456)	1068 (807)	1840 (1263)	1052 (698)	824 (488)	1876 (1186)	9938	11892
7. Non-scheduled commercial banks ..	21 (14)	12 (9)	33 (23)	5 (—)	9 (8)	14 (8)	193	121
All commercial banks	793 (470)	1080 (816)	1873 (1286)	1057 (698)	833 (496)	1890 (1194)	10131*	12013*

Note: Figures within brackets relate to offices opened at unbanked centres.

*Excluding offices closed during the year.

239. The Bank's Annual Report for 1969-70 had contained the details of a programme of branch expansion drawn up by the Reserve Bank in December 1969, under which 22 public sector banks and 8 private sector banks were required to open, during the year 1970, 1,350 offices, including 1,186 at unbanked centres. As against this target, the concerned banks opened 1,155 offices including 997 at unbanked centres.

240. For the accounting year 1970-71 as a whole, the opening of new offices by all commercial banks totalled 1,890 as against 1,873 in 1969-70 (Table 34). Of the 1,890 offices opened during 1970-71, fourteen nationalised banks accounted for 1,052 offices and State Bank of India and its subsidiaries for 585 offices. Of the total, 1,194 offices were opened at unbanked centres.

241. The territorial spread of banking has also gained considerable momentum since bank nationalisation. Thus, out of 3,763 new branches opened during the first two years of nationalisation (from July 1, 1969 upto end-June 1971),

as many as 2,480 branches (66.0 per cent) were opened in the hitherto unbanked centres (Table 35). Even out of these offices opened in the hitherto un-banked centres, as much as 34 per cent were opened in the relatively under-developed States of Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, West Bengal, Assam, Madhya Pradesh and Jammu and Kashmir. In the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli, Manipur and Tripura, all the new offices opened during the period were in the hitherto un-banked centres. The proportion of new offices opened in the hitherto unbanked centres to the total number of new offices opened during 1969-70 and 1970-71 was more than 67 per cent in eight States, viz., Madhya Pradesh (74 per cent), Tamil Nadu (72 per cent), Assam (82 per cent), Uttar Pradesh (68 per cent), Rajasthan (68 per cent), Mysore (69 per cent), West Bengal (73 per cent) and Bihar (70 per cent).

242. The phenomenal increase in branch expansion is also reflected in a sharp decline in the national average of population covered by bank offices from 65,000 per office as at the end of June 1969 to 46,000 per office at the end of

June 1971. Similarly, the average population per bank office has been brought down in all the States and substantially in most of the States (Table 35). The number of districts without bank offices which stood at 13 at the end of December 1967 came down to 3 at the end of June 1971 and even in these 3 districts 6 licences have been issued for the opening of branches.

243. Table 36 brings out the centre-wise distribution of bank branches in the country. It may be noticed that in the programme of branch expansion by commercial banks, there

was a distinct shift in favour of rural areas during the period under review. The proportion of bank branches in rural areas increased from 22.4 per cent of the total as at end of June 1969 to 30.2 per cent at the end of June 1970 and to 35.6 per cent as at the end of June 1971.

244. Allowing for the change in number of offices due to transfer of assets and liabilities, closure of offices, inclusion of banks in the Second Schedule, etc., the number of offices of scheduled commercial banks increased by 1,954. Offices of non-scheduled banks, however, declined by 72 during the

Table 35—State-wise Distribution of Bank Offices as at end-June 1969, end-June 1970 and end-June 1971.

States/Union Territories	No. of offices as at the end of			Opened during 1969-70		Opened during 1970-71		Population per bank office (in thousands) as at the end of	
	June 1969	June 1970	June 1971	Total	Of which at unbanked centres	Total	Of which at unbanked centres	June 1969	June 1971
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>States :</i>									
1. Andhra Pradesh	567	722	869	155	101	147	95	75	50
2. Assam	81	107	137	26	19	30	27	188	108
3. Bihar	273	361	453	89	65	92	62	207	124
4. Gujarat	752	919	1105	167	104	187	106	34	24
5. Haryana	172	219	258	47	32	39	19	57	39
6. Himachal Pradesh	42	62	87	21	20	25	23	80	39
7. Jammu and Kashmir	35	74	101	39	29	27	13	114	46
8. Kerala	601	713	845	112	72	132	100	35	25
9. Madhya Pradesh	343	460	566	117	104	107	62	116	73
10. Maharashtra	1118	1304	1471	186	87	167	86	44	34
11. Mysore	756	954	1124	198	147	170	107	38	26
12. Nagaland	2	4	5	2	1	1	1	205	103
13. Orissa	100	133	173	33	23	40	30	212	126
14. Punjab	346	465	556	119	88	91	55	42	24
15. Rajasthan	364	432	525	68	48	93	61	70	49
16. Tamil Nadu	1060	1213	1371	155	122	164	107	37	30
17. Uttar Pradesh	747	932	1147	185	138	215	132	119	77
18. West Bengal	504	588	684	84	65	96	67	87	65
<i>Union Territories :</i>									
19. Andaman, Nicobar Islands	1	2	2	1	—	—	—	82	57
20. Chandigarh	20	26	28	6	—	2	—	7	9
21. Dadra and Nagar Haveli	—	1	3	1	1	2	2	—	25
22. Delhi	274	318	350	44	9	32	2	10	12
23. Goa, Daman and Diu	85	101	111	16	10	10	9	8	8
24. Laccadiv and Minicoy Islands.	—	—	2	—	—	2	2	—	16
25. Manipur	2	2	5	—	—	3	3	497	214
26. NEFA	—	—	3	—	—	3	3	—	148
27. Pondicherry	12	13	20	1	—	7	4	31	24
28. Tripura	5	6	12	1	1	6	6	276	130
Total	8262	10131	12013	1873	1286	1890	1194	65	46

Table 36—Centre-wise Distribution of Commercial Bank Branches

	No. of branches as at the end of							
	June 1969		June 1970		Dec. 1970		June 1971	
	No.	% to total	No.	% to total	No.	% to total	No.	% to total
(i) Rural	1,832	22.4	3,062	30.2	3,766	33.6	4,279	35.6
(ii) Semi-urban	3,322	40.1	3,695	36.5	3,880	34.6	4,016	33.4
(iii) Urban	1,447	17.5	1,583	15.6	1,673	15.0	1,778	14.8
(iv) Metropolitan/Port-towns	1,661	20.0	1,791	17.7	1,865	16.8	1,940	16.2
Total	8,262	100.0	10,131	100.0	11,184	100.0	12,013	100.0

period (Table 37). As at the end of June 1971, the number of offices of scheduled and non-scheduled banks stood at 11,892 and 121, respectively. At the end of June 1970, the corresponding figures were 9,938 and 193, respectively.

245. In the context of the urgent need for mobilising deposits and inculcating the habit of thrift amongst students, workmen, etc., it has been decided to encourage commercial banks to open extension counters at places like schools, colleges, factories, etc., and conduct restricted types of business. Such counters will be attached to the nearest offices of the concerned banks.

246. It was also mentioned in the previous year's Report that banks were asked to submit proposals for their branch

expansion in banked centres, including metropolitan cities and Port towns. On the basis of the programmes received from various banks, permission was granted to banks for opening 309 offices in urban centres. While issuing licences in this regard, the norm that was kept in view was that in the case of banks which have more than 60 per cent of their offices in rural and semi-urban centres, one office in an urban centre was allowed for every two offices opened in rural and semi-urban centres; in the case of other banks one office in an urban centre was allowed for every three offices in semi-urban and rural centres. Licences for such centres on the basis of individual applications received from banks are being continued to be issued under same norm requirements. In view of the scope for increasing the number of bank offices in the metropolitan centre of Calcutta, following considerable

Table 37—Number of Offices Opened and Closed by Scheduled and Non-Scheduled Commercial Banks in India

								New Offices opened	Changes due to amalga- mation, mergers, transfers of assets and liabi- lities and inclusion in and exclu- sion from the second sched- ule to the R.B.I. Act, 1934	Existing offices closed	Overall variation in the number of offices	Number of offices at the end of the period
								1	2	3	4	5
Scheduled Commercial Banks :												
1968												
	January-June	222 (37)	-10	-4	+228	7044
	July-December	443 (50)	+1	-6	+438	7482
1969												
	January-June	565 (24)	+1	-3	+563	8045
	July-December	772 (65)	+53	-3	+822	8867
1970												
	January-June	1068 (190)	+3	—	+1071	9938
	July-December	1052 (164)	+54	-4	+1102	11040
1971												
	January-June	824 (178)	+32	-4	+852	11892
Non-Scheduled Commercial Banks :												
1968												
	January-June	7	-10	-3	-6	203
	July-December	5	-1	—	+4	207
1969												
	January-June	11	-1	—	+10	217
	July-December	21	-53	-1	-33	184
1970												
	January-June	12	-3	—	+9	193
	July-December	5	-54	—	-49	144
1971												
	January-June	9	-32	—	-23	121
All Commercial Banks												
1968												
	January-June	229	—	-7	+222	7247
	July-December	448	—	-6	+442	7689
1969												
	January-June	576	—	-3	+573	8262
	July-December	793	—	-4	+789	9051
1970												
	January-June	1080	—	—	+1080	10131
	July-December	1057	—	-4	+1053	11184
1971												
	January-June	833	—	-4	+829	12013

Notes : (1) Figures within brackets relate to the State Bank of India.

(2) Data exclude administrative, seasonal, temporary, non-banking offices and offices outside India.

rise in population as revealed by the 1971 Census, it has been decided, effective July 1, 1971, that the eligibility of banks to open offices at Calcutta need not be linked to performance in branch expansion in rural and semi-urban areas.

Special Credit for Schemes with Employment Potential

247. As a sequel to the discussions which the Union Finance Minister had with the Custodians of public sector banks in July 1970, the Reserve Bank of India set up a Committee under the Chairmanship of Shri V. D. Thakkar to review the special credit schemes of banks with particular reference to their employment potential. The Committee submitted its report in December 1970. After identifying the employment potential including self-employment, in various sectors of the economy, the Committee reviewed the various credit schemes introduced by the banks to help the self-employed. The Committee noted that none of the special schemes formulated by banks really offered any special facilities for the relatively weaker sections of the society. With a view to enabling banks to assist entrepreneurship and provide employment, the Committee evolved the following guidelines for action.

(i) Sufficient discretionary powers to administer the schemes should be given to the branch agents who should be given sufficient orientation about the scope and content of the programmes and the objectives that are sought to be achieved. The Committee emphasised the urgent need for a massive and rapid training programme for the branch officials;

(ii) In several categories of small entrepreneurs, the promoters technical and such other intangible and non-financial contributions will have to be given due weightage as security, and assistance should be provided at lower margins or even without margins where warranted; and

(iii) It should be possible for a bank to charge, on a term loan, a lower rate of interest in the initial stage, and a higher rate of interest subsequently. The schedule of repayment should take into account the gestation period and the income-generating capacity of the unit. Bank should not insist on the guarantee of third parties for the grant of loans as a matter of course.

248. The Committee has suggested Model Simplified Forms for use by Professionals and by Retailers, etc., and has stressed that application forms should be made available in all local languages. Banks should organise adequate follow-up and supervision arrangements and also arrangements for effecting recovery of advances according to schedule.

249. Other important suggestions made by the Committee are briefly as follows. If adequate assistance is not available from the Life Insurance Corporation or other agencies for the construction of Industrial Estates for small entrepreneurs, particularly in the urban and metropolitan areas, commercial banks will have to take an effective part in helping construction of such estates as also household and cottage industries. Further, equipment leasing, a facility made available by banks in some of the advanced countries, might be of some assistance in India. The Reserve Bank may work out a suitable programme for reducing delay in payment of bills to small entrepreneurs by large and medium industries and Government Departments and public sector concerns. In order to evolve a coordinated arrangement for helping the professional and self-employed categories, the Committee has recommended the setting up of a Multi-Services Agency. This Agency will make arrangements for collection of information on the prospective borrower. The Committee is of the opinion that such Agency should be immediately set up in metropolitan cities and larger towns, as well as in certain chosen operational bases in the relatively backward areas in the country. The Multi-Services Agency will have no financing function but will only be a co-ordinating/planning/advisory body.

250. The recommendations of the Committee were accepted by the Reserve Bank of India. As a follow-up measure, the Reserve Bank of India has issued guidelines to all commercial banks on the special credit schemes of banks, in March 1971.

251. It has been noted in the guidelines that banks have been dispensing credit to different categories of self-employed persons on an increasing scale in recent months and a stage has been reached when the portfolio of financial assistance to

this sector requires to be handled on a continuing and organised basis. The assistance that is provided should be essentially need-based, consistent with economic viability of the proposition being financed. Credit schemes should be implemented at the branch level with adequate degree of flexibility which calls for appropriate delegation of authority to branch agents. Since the branch agents have a key role to play, a rapid training programme will have to be organised urgently to provide the necessary orientation to the branch officials. In order to make the credit assistance more meaningful, banks will have to consider as to how best integrated financial and management assistance could be arranged or organised, taking into account the totality of the requirements of the borrowers; the setting up of Multi-Service Agency may be one way of achieving this purpose. Adequate follow-up and supervisory arrangements should be organised to keep track of the end-use of funds and for effecting recovery of the advances according to schedule. As recommended by the Committee, the Bank has also constituted a Working Group for evolving a programme of liquidation of the outstanding dues of large industries to small entrepreneurs.

Credit Guarantee Scheme for Priority and Neglected Sectors

252. For some time past, the Government of India was considering the question of formulating a scheme for a simple but wide-ranging system of guarantees or other comparable facilities for lending by banks to individual borrowers in sectors which had remained relatively neglected so far. A Working Group under the Chairmanship of Shri S. S. Shiralkar, then Additional Secretary, Department of Banking, of the Union Finance Ministry (now Deputy Governor, Reserve Bank of India) was constituted to examine this matter.

253. The Working Group felt that the risks of lending to small borrowers, as affecting particular banks or in particular areas including the relatively unbanked States and backward regions, might be appreciable and also uneven and came to the conclusion that in the interest of the banking system as also in the wider public interest, these risks should be pooled and covered under a common and centralised guarantee scheme.

Credit Guarantee Corporation

254. Based on the Group's recommendation a new Public limited company known as the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was promoted by the Reserve Bank of India to administer one or more credit guarantee schemes. This company was registered under the Companies Act, 1956 on the 14th January 1971. The authorised capital of the Corporation is Rs. 10 crores, of which Rs. 2 crores divided into 20,000 equity shares of Rs. 1,000 each, has been initially issued and is fully paid-up. The shares have been taken up by the Reserve Bank of India, the State Bank of India and its subsidiaries and the scheduled commercial banks. The Board of Directors of the Corporation consists of six members, of whom two (including the Chairman) represent the Reserve Bank and the remaining four represent the scheduled commercial banks. The Corporation formulated the Credit Guarantee Corporation of India (Small Loans) Guarantee Scheme, 1971 and brought it into force from April 1, 1971. It covers credit facilities, within certain specified limits, granted by scheduled commercial banks to the small borrowers. The categories of borrowers covered by the scheme are individual transport operators or an association of not more than six such operators, individuals, firms and co-operative societies trading in fertilisers and goods other than fertilisers, professional and self-employed persons, individuals and firms owning business enterprises and farmers engaged in cultivation and allied agricultural operations. The Corporation covers seventy-five per cent of the amounts which are bad or doubtful of recovery, the other twenty-five per cent being borne by the lending organisations. A guarantee fee of one half of one per cent per annum is charged on the amounts outstanding on account of the eligible credit facilities. Suitable safeguards for ensuring that the facilities are used for bona fide and productive purposes are provided in the scheme. The scheduled commercial banks participating in the scheme have executed or agreed to execute agreements undertaking to report the advances covered by the blanket guarantee, to conduct the guaranteed advances according to the relevant rules prescribed by the banks, to segregate the registers, documents and other records pertaining to the guaranteed accounts

and to undertake certain other obligations in relation to the Corporation. Quarterly statements showing the aggregate amount of guaranteed credit facilities granted to various sectors at the end of each quarter are being obtained from the banks. A test check of the guaranteed advances is proposed to be undertaken by the Corporation with the assistance of the external auditors and internal inspection machinery of the banks and the Reserve Bank of India.

Financing of Agriculture by Commercial Banks

255. Agricultural finance as a part of total commercial bank lending has become increasingly important and presently accounts for about one-tenth of the total bank credit. In view of the wide divergence in the practices followed in regard to the procedures of appraisal, post-credit supervision and recovery, the Reserve Bank issued in December 1970, guidelines to all commercial banks for financing of agriculture. The guidelines were prepared on the basis of a study carried out by the Bank into the methodology of operations, policy and procedures adopted by the banks for financing agriculture. The guidelines emphasise that the main objective of commercial banks' lending to agriculture is to assist cultivators to move to a higher technological plane of activity. Credit for agriculture would have to be purposive and should be provided not only to already viable cultivators for further increasing their surpluses but, more importantly, to marginal and potentially viable cultivators. The discretionary powers allowed to the branch agent should be such that at least 80 per cent of the proposals can be cleared by him, without reference to the Central Office. The branch agent should collect and have for ready reference, the basic agricultural data, and the scales of finance should be worked out considering all the inputs required as well as the off-farm income or resources available to cultivators. For both short and medium-term loans, the repayment schedule of loans should coincide with the time when the cultivator has sold his produce and is fluid. The branch agent should keep the recovery procedures fair but firm. It is necessary for the bank branches to establish close relationship with other institutions in the area and to be informed about the programme of the Agricultural Refinance Corporation in their areas.

Committee on Differential Interest Rates

256. The Finance Minister had suggested at his meeting with the Chairman/Custodians of the public sector banks on July 22, 1970 that lower interest rates could be charged to carefully selected low income groups deserving financial assistance from banks, and higher rates might be charged to the more affluent borrowers. In pursuance of this suggestion, the Reserve Bank of India constituted, in September 1970, a Committee under the Chairmanship of Dr. R. K. Hazari, Deputy Governor of the Bank, to examine the question of differential interest rates. The terms of reference of the Committee were (i) to review the scope and the extent to which differential interest rates are already being charged by banks to borrowers in each sector, (ii) to determine the criteria for identifying the borrowers who could be granted the benefit of a lower interest rate within each sector, (iii) to indicate the range of the differential that could be allowed in each sector and (iv) to examine if any other concession could be granted either in lieu of or in addition to lower interest rates.

257. The Committee which submitted its report in May 1971 has observed that an objective and practicable, criterion for identification of the borrowers for the purpose of charging differential interest rates by banks can only be the size of the loan which need not be uniform for all sectors. As a measure of automaticity for the selection of small borrowers, linking of the scheme of differential interest rates with the new Credit Guarantee Scheme for covering small loans to borrowers in the priority and neglected sectors has been suggested. In the opinion of the Committee, too wide a range of differential would be inadvisable. Taking into consideration the various practical problems involved in introducing a wide differential range, the Committee suggested interest rates varying between 8-1/2—10 per cent to the preferred classes of borrowers. In addition, as a measure of relief of small borrowers, the Committee has recommended that the Guarantee fees under Credit Guarantee Scheme in the case of small borrowers should be borne by the lending bank. The Committee has also pointed out that concessions by way of relaxations on securities and margins

are of major significance and has suggested some concessions as an indication of the lines along which banks could proceed. The Committee has suggested that the question of co-operative institutions adopting its recommendations should be examined. The recommendations made by the Committee are under the consideration of the Reserve Bank and the Government.

258. Dr. Ashok Mitra, a member, submitted a note of dissent suggesting a range of interest rates varying from 1/2 per cent to 20 per cent.

Measures for Deposit Mobilisation

259. While, commercial banks are making concerted efforts at deposit mobilisation through a series of additional measures and schemes, the Reserve Bank, with a view to assisting them in this task, relaxed in August, 1970, the restrictions on the payment of brokerage on deposits, thus allowing such payments to agents employed for the door-to-door collection of deposits under special schemes introduced by the banks. On October 24, 1970, the Bank issued a circular to the commercial banks, once again impressing upon them the need for and the importance of substantial step-up in deposit mobilisation. Although it was not the Reserve Bank's intention to offer any specific guidelines or standardised suggestions, it was pointed out that staff involvement in the campaigns for deposit mobilisation through proper group awards, etc., fixing up appropriate targets for each branch and a bank as a whole, organisation of deposit mobilisation campaigns, etc., might help augmenting banks' resources on a substantial scale.

260. A meeting of the Chief Economists and Chief Development Officers of 20 major banks to discuss the various aspect of deposit mobilisation was convened by the Reserve Bank of India on December 23 and 24, 1970 at Bohmay. The participants discussed the different facets of deposit mobilisation, such as branch net-work, types of branches, intra-institutional and inter-institutional competition, incentives to staff and depositors, publicity media, instruments of saving, interest elasticity of deposits and special studies and surveys needed for estimating deposit potential.

Meetings of Small Bankers

261. Two meetings of small private sector bankers (i.e., those with deposits of less than Rs. 50 crores) in the Southern and Northern Regions were convened by the Reserve Bank of India at Madurai on May, 11 and 15, 1971 and at Delhi on June 9, 1971. The Chief Executive Officers of the small banks in the respective regions were invited to participate in the meetings which were presided over by the Deputy Governor of the Reserve Bank in charge of Banking. Discussions at the meeting centred on various aspects of the operational problems of the banks such as development of funds, lending to priority sectors, the lead bank scheme, deposit mobilisation and training, organisation and management. Steering Groups, headed by the Chief Officer, Department of Banking Operations and Development, Reserve Bank of India and consisting of Chairmen of some of the banks as members were set up to formulate proposals for the establishment of training centres for training the personnel of small banks.

Advances against Shares

262. With a view to discouraging and preventing bank finance from being utilised for speculative purposes and/or other unhealthy practices, it was decided to regulate advances against shares and a directive in this regard was issued by the Reserve Bank on August 28, 1970. In terms of this directive, every commercial bank, which grants or renews an advance limit of over Rs. 50,000 against the security of shares to a borrower, is required to stipulate that the shares shall be transferred to its name and that it should have exclusive voting rights in respect thereof which it may exercise in any manner whatsoever, and that it should get the shares transferred to its name expeditiously.

263. The directive provides that no commercial bank shall exercise voting rights in respect of the shares held by it as pledged except with the prior approval of the Reserve Bank and in accordance with such directions as may be given by the Reserve Bank.

264. In the case of shares lodged by a share-broker as security against advances, the provisions of the directive will apply only if the shares are held for a period longer than three months. This provision is intended to enable the sharebrokers to carry on their normal business operations without any difficulty.

265. With a view to ensuring that no hardship or inconvenience is caused to genuine investors in raising funds for their bonafide needs, limits of advances against shares upto Rs. 50,000 have been exempted from the purview of the directive.

Advances on Personal Guarantees of Directors, etc.

266. The Bank made a review of the practices of banks and term-lending institutions taking personal guarantees from directors and other managerial personnel of borrowing concerns while sanctioning loans. The review revealed a gradual rise of entrepreneurial class in the place of managing agency system and the professionalisation of managerial cadres and the improvements in the techniques of financial and technical appraisal of proposals for assistance. In view of these findings, it was felt that there is no longer need for taking personal guarantees as a matter of course from directors and other managerial personnel of borrowing concerns while sanctioning loans. The Reserve Bank, therefore, provided in July 1970, guidelines to lending institutions to help them identify the circumstances under which a guarantee may or may not be necessary. It has been stressed in the guidelines that care should be taken to ensure that the system of guarantees is not used by the directors and other managerial personnel as a source of remuneration from the borrowing concerns.

Selective Credit Controls

267. During the year under review modification were made from time to time in both the general as well as selective credit controls. The former are given in paragraphs of Part I. These included, among others, the change in the Bank rate from 5 per cent to 6 per cent with effect from January 9, 1971, the raising of the net liquidity ratio and the introduction of the new Bill Market Scheme. The selective credit controls related to advances against raw cotton and kapas, foodgrains, oilseeds and vegetable oils including vanaspati. The main measures taken in this regard are indicated below:

268. On October 23, 1970, the Reserve Bank effected a moderate liberalisation regarding advances against *raw cotton and kapas* with a view to aiding the marketing of the new crop; the ceiling limit on advances to cotton mills was removed and a graded system of margins was prescribed for mills as well as for others. However, in view of the subsequent sharp contra-seasonal rise in the prices of cotton, the control in this regard was tightened on December 12, 1970 in order to discourage hoarding of raw cotton stocks with the help of bank finance. The minimum margin on advances against raw cotton was raised and the ceiling limit on advances to parties other than mills was reduced. In view of the difficulty experienced by the cotton trade in marketing of cotton, owing to, *inter alia*, delayed harvesting of certain varieties of indigenous cotton certain relaxations were announced by the Reserve Bank on June 30, 1971. Thus, the four-month period (February-May 1971) during which the minimum margin of 60 per cent was applicable in respect of advances against cotton and kapas marketed during the period October 1970-January 1971 to parties other than cotton mills was extended by the month upto August 1971; earlier, the validity period had been extended by one month from May to June 1971.

269. In view of the rising trend of advances against cotton textiles, banks were advised on February 4, 1971 to reduce their advances against cotton textiles and raise the minimum margin from 25 per cent to 40 per cent. In April 1971, the major banks were advised to apply the higher margin selectively, keeping in view the position of sick mills and financially weak units.

270. In respect of advances against *foodgrains*, the Bank modified its control on December 17, 1970 in view of the prevailing and prospective supply position. Thus, *inter alia*,

suitable changes were made with a view (i) to enable commercial banks in extending direct credit to farmers against standing crops and to help in orderly marketing of such crops, (ii) to assist the banks in expanding their agricultural business in rural and semi-urban areas and (iii) to enable banks to grant advances to foodgrains processing units such as *dal* mills (but other than rice mills), at centres with a population of 50,000 or below.

271. In view of the sharp rise in prices of oil seeds and vegetable oils, despite prospects of a good oilseeds crop, the Bank tightened its control on January 25, 1971 by raising the minimum margin from 60 per cent to 75 per cent on advances against oilseeds, vegetable oils and vanaspati. However, in view of the current supply and prices position in regard to mustardseed and rapeseed in the country, the minimum margin was lowered on advances against these oilseeds from 75 per cent to 60 per cent, as well as on bank advances against soyabeans. These advances were also exempted from ceiling control.

272. Further, in order to mitigate the difficulties of borrowers in the States of Assam, Nagaland, Meghalaya and Jammu and Kashmir and in the Union Territories of Manipur, NEFA and Tripura, the Bank granted complete exemption from the controls on advances against foodgrains, oilseeds and vegetable oils as well as cotton and kapas in these areas.

273. A chart showing the position in regard to selective credit controls is appended.

Selective Credit Controls: Co-operative Banks

274. Having regard to the supply position of indigenous cotton and kapas and the trends in prices, a directive was issued during the year 1970-71 stipulating the co-operative banks to maintain a margin of 30 per cent in respect of advances to co-operative cotton mills if the relative security offered was by way of hypothecation, and 20 per cent if it was by way of pledge. These margins could be reduced to 10 per cent against pledge and hypothecation if the credit limits were fully guaranteed by the State Government in regard to repayment of principal and payment of interest. In regard to others, the margins, as in the past, continued to be 25 and 40 per cent against pledge and hypothecation, respectively. The restriction imposed in the directive issued in regard to the ceiling on advances against the security of cotton and kapas were continued at the same level, *viz.*, 20 per cent of the total liabilities in the case of a central co-operative bank (or a State co-operative bank operating in a Union Territory) and 10 per cent in the case of a State co-operative bank. The aggregate level of advances for the purposes of directive would not include advances to co-operative cotton mills but only advances to parties other than such mills. The exemptions accorded in respect of advances against imported cotton as well as certain types of indigenous cotton were continued.

275. The restriction imposed on certain central co-operative banks in regard to the level of their credit against the security of *gur* was rescinded in September 1970. The banks were, however, required to maintain the normal margin of 25 per cent against pledge and 40 per cent against hypothecation in respect of this commodity.

SELECTIVE CREDIT CONTROLS : POSITION AS ON JUNE 30, 1971

Minimum Margin	Minimum Rate of Interest	Level of credit	Exemptions	Prohibition
1	2	3	4	5
Foodgrains				
1. 25% for advances : (i) to the duly appointed agents of the Food Corporation of India against stocks held as agents, (ii) to roller flour mills against stocks of <i>wheat</i> purchased from F.C.I. 2. 30% for advances against <i>maize</i> to parties other than starch manufacturing units. 3. 35% for advances : (i) against <i>maize</i> to starch manufacturing units ; (ii) against <i>paddy</i> to rice mills ; (iii) against stocks of food-grains other than paddy and rice to foodgrain processing units (other than rice mills) located at centres with a population of 50,000 or below for stocks equivalent to four weeks' consumption of such units. 4. 40% for advances against official warehouse receipts covering stocks of food-grains. 5. 50% for all other advances.	10% per annum for all parties.	Ceiling for each two-months period commencing from January-February 1971 : 100% of the average aggregate level of credit maintained in the corresponding two-month period in 1970 (separately in respect of advances against paddy and rice, wheat and 'other food-grains'). Additional limit : Combined limit of Rs. 25,000 for advances against any one or all of the three groups of food-grains (<i>viz.</i> , paddy and rice, wheat and other foodgrains) for each new branch opened on or after 1-1-1970 at a centre with a population of 50,000 or below.	1. The following types of advances are <i>completely</i> exempted from the control : (i) Advances to State Government and millers and wholesale dealers who are appointed as procuring agents by a State Government subject to the condition that such procuring agents are acting exclusively as agents of the concerned State Government and are precluded from purchasing/distributing paddy or rice or converting paddy into rice on behalf of themselves or other parties. (ii) Advances to the Food Corporation of India (excluding advances granted to its duly appointed agents). (iii) Advances against high yielding/hybrid seeds produced under contract with the National Seeds Corporation Ltd., Delhi, or a State Government or which bear the certification of the said Corporation or as the case may be, the concerned State Government or of any certification agencies authorised under the Seeds Act, 1966 and seeds notified under Section 5 of the said Act. (iv) Advances granted to Wholesale Consumers' Co-operative Stores and State and National Federations of Consumers' Co-operatives. (v) Advances granted to co-operative societies duly registered or deemed to be registered under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 and duly authorised by the District Collectors in the State of Maharashtra to deal in paddy and rice, jowar and nagli (ragi). (vi) Advances against rational food-grains to wholesalers and retailers appointed by the West Bengal Government for distribution of rationed articles in the statutorily rationed areas of West Bengal. (vii) Advances in the States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Jammu and Kashmir and in the Union Territories of Manipur, NEFA and Tripura. (viii) Advances against the security of or by way of purchase or discount of demand documentary bills drawn in connection with the movement of foodgrains. 2. The following types of advances are exempted from <i>margin and ceiling</i> controls : (i) Advances against the security of barley and	Granting of credit limit to parties other than traders dealing in food-grain licensed by the Government of Maharashtra for distribution of paddy and rice, jowar and nagli (ragi) in Maharashtra is prohibited.

Minimum Margin	Minimum Rate of Interest	Level of credit	Exemptions	Prohibition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(ii) Advances directly granted to farmers and primary co-operative societies for extending credit to their cultivator-members against foodgrains which represent an extension of advances granted earlier against the standing crop for a period of two months from the date of harvesting the said crop provided that the amount of each of such credit limits does not exceed Rs. 2,500 per farmer or the amount of the crop loan outstanding, whichever is lower.	
			3. The following types of advances are exempted from ceiling control :	
			(i) Advances to roller flour mills against the security of wheat purchased from the F.C.I.	
			(ii) Advances against maize to all parties, and	
			(iii) Advances against foodgrains other than paddy and rice to foodgrains processing units such as dal mills (but other than rice mills) at centres with a population of 50,000 or below.	

Minimum Margin	Minimum Rate of Interest	Level of credit	Exemptions	Prohibition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Vegetable Oils and Vanaspati				
1. 75% for advances against Vegetable Oils and Vanaspati (except for the following types of advances).	12% per annum	Ceiling for each two-month period commencing from January-February 1971, as follow :	I. Advances against (i) Vegetable oils and Vanaspati to Vanaspati Manufacturers and registered oil mills and (ii) cottonseed oil are exempted from <i>ceiling</i> control.	
2. 25% for advances against : (i) stocks of oils processed from linseed oil and castorseed oil for use as industrial raw material by factories in Bihar, Orissa and West Bengal; (ii) cottonseed oil to vanaspati manufacturers.		70% of the average aggregate level of credit actually maintained during the corresponding two month period in 1967.	II. Advances against non-edible vegetable oils and oils or extractions thereof processed from non-edible vegetable oils other than linseed oil and castorseed oil are exempted from <i>margin</i> and <i>ceiling</i> control. III. Following types of advances are <i>completely</i> exempted from control : (a) Advances to the Food Corporation of India and the State Trading Corporation against stocks of vegetable oils and vanaspati. (b) Advances to vanaspati manufacturers against the stocks of soyabean oil imported under the P.L.-480 Agreement and of sunflower oil imported as a gift or on commercial basis from the Government of U.S.S.R. and distributed by the S.T.C. and/or State Governments to vanaspati manufacturers. (c) Advances against stocks of vanaspati held by vanaspati manufacturers for being delivered to the Army Purchase Organisation in the Ministry of Food and Agriculture, Government of India, in pursuance of contracts entered into or to be entered into with the said Organisation by the said manufacturers. (d) Advances against stocks of vegetable oils and vanaspati in favour of exporters of de-oiled and/or de-fatted cakes in respect of specific firm export contracts and/or against export bills. (e) Packing credit advances to the exporters of de-oiled and/or de-fatted cakes on the basis of firm export orders/letter of credit against the security of oilseeds and/or other raw material to the extent of the value of raw material required for producing cakes covered by the export order, even though the value of the raw material exceeds the value of the relative export order; provided (i) such advances to the extent of the value of by-product oil shall be adjusted by the sale proceeds of the by-product oil or in cash as soon as the oil is extracted and the balance in the packing credit account shall be adjusted by the proceeds of the relative export bill, and (ii) advances against the by-product oil granted in a separate account are exempted for a period of 30 days from the date of advance.	
3. 40 % for advances to vanaspati manufacturers against vegetable oils to the extent of stocks of such oils used as raw material equivalent to 6 weeks' consumption of each factory located in Eastern Zone worked out on the basis of average of weekly consumption during October 1969 to March 1970.				
4. 50% for advances to vanaspati manufactures against vegetable oils to the extent of stocks of oils used as raw material equivalent to 6 weeks' consumption of each factory located in Northern Zone and 4 weeks' consumption of each factory located in Southern and Western Zones, worked out on the basis of average of weekly consumption during October 1969 to March 1970.				
For New Vanaspati Factories:				
The margin is to be related to 6/4 weeks' requirement depending on the location of the factory, based on the average actual weekly consumption from the date of its establishment, and				

Minimum Margin	Minimum Rate of Interest	Level of credit	Exemptions	Prohibition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p><i>For Vanaspati Units likely to start production in future:</i> The margin is to be related to 6/4 weeks' requirement depending on the location of the factory, based on the one-third of the average weekly productive capacity of the unit for the first six months and thereafter based on the average actual weekly consumption during the preceding six months.</p>			<p>(f) Advances to Wholesale Consumers' Co-operative Stores and the State and National Federations of Consumers' Co-operatives.</p> <p>(g) Advances in the States of Assam, Meghalaya, Nagaland, and Jammu and Kashmir and Union Territories of Manipur, NEFA and Tripura.</p> <p>(h) Advances against the security of or by way of purchase or discount of demand documentary bills drawn in connection with the movement of vegetable oils and vanaspati.</p>	

Cotton and Kapas

To Mills:

- A. *For weak mills:*
- 12% per annum for all parties.
- I. *Mills under Authorised Controller:*
Mills under Chief Executive Authority:
Government run/owned/managed mills/authorised agencies (including State Textile Corporation) and Mills in Orissa.
- 20% for stocks of 6 weeks' consumption.
 - 35% for stocks in excess of 6 weeks' consumption.
- Provided for the period June-September 1971:*
Ceiling same as in the preceding four-month period viz., February-May 1971 i.e., equivalent to 75% of the peak level in the four-month period of February-May in any of the preceding three years, viz., 1969, 1968 and 1967.
- I. *Financially weak mills covered by Working Group on Bank Credit for Cotton Textile Industry:*
- Same as maintained prior to January 21, 1970 directive for stocks of 6 weeks' consumption.
 - 35% for stocks in excess of 6 weeks' consumption.
- B. *Other Mills:*
- I. *Mills in States other than in West Bengal:*
- 25% for stocks of 6 weeks' consumption.
1. No ceiling for advances to mills.
2. For others: Ceiling for each four-month period commencing from October 1970-January 1971 as follows: 75% of the peak level in the corresponding four-month period in any of the preceding 3 years, viz., 1969, 1968 and 1967, whichever is highest.
1. *The following types of advances are completely exempted from control:*
- Advances against stocks of imported cotton and kapas.
 - Advances in respect of pre-shipment credit for cotton exports, provided the advance is made in respect of a firm export order and is repaid on negotiation of the relevant export bill on shipment.
 - Advances against the security of or by way of purchase or discount of export bills relating to export of cotton from India.
 - Advances against the security of or by way of purchase or discount of demand documentary bills drawn in connection with the movement of cotton and kapas.
 - Advances against the security of stocks of exportable varieties of cotton, viz., Bengal Deshi, Yellow Pickings, Zodas, Sweepings, etc., provided that firm export orders in respect of the stocks have been received by the parties and lodged with the banks.
 - Advances in the States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Jammu & Kashmir and in the Union Territories of Manipur, NEFA and Tripura.
- II. Advances against cotton and kapas to manufacturer of surgical cotton (absorbent cotton wool), provided that such stock is held by the borrower for manufacture of surgical cotton and not for resale are exempted from *margin* and *ceiling* controls.
- III. The following types of advances are exempted from *margin* control:
- Advances to cotton mills in respect of pre-shipment credit against such stocks of indigenous cotton and kapas as are required for the manu-

Minimum Margin	Minimum Rate of Interest	Level of credit	Exemptions	Prohibition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ii) 40% for stocks between 6-8 weeks' consumption.			facture of cotton textiles (including yarn) in respect of which firm export orders have been received either directly by the mills or by the merchant-exporters through whom the mills are exporting provided the contracts with merchant-exporters are registered with Cotton Textiles Export Promotion Council. If firm export orders are received by the mills directly, the advances should be repaid on negotiation of the relevant export bill on shipment.	
(iii) 60% for stocks in excess of 8 weeks' consumption.				
II. Mills in West Bengal:				
(i) 20% for stocks of 10 weeks' consumption.				
(ii) 35% for stock in excess of 10 week's consumption.				
<i>To others :</i>				
A. For Old Stocks (i.e., marketed prior to October 1970) of cotton and kapas : 75%			(ii) Advances to sick mills in West Bengal and mills owned/managed/run by the Government of West Bengal or by its authorised agencies against the stocks equivalent to 10 weeks' consumption of each mill.	
B. For New Stocks :				
(i) Marketed in October 1970-January 1971 :				
(a) 60%—October 1970—January 1971				
(b) 60%—February 1971—August 1971				
(c) 75%—Thereafter.				
(ii) Marketed in February 1971—May 1971 :				
(a) 60%—February 1971—May 1971				
(b) 60%—June 1971—September 1971				
(c) 75%—Thereafter.				
(iii) Marketed in June 1971—September 1971 :				
(a) 60%—June 1971—September 1971				
(b) 60%—October 1971—January 1972				
(c) 75%—Thereafter.				

Other Organisational Matters

Reconstruction of Boards of Private Banks

276. In accordance with the requirements of Section 10A of the Banking Regulation Act 1949, which had come into force on February 1, 1969, the process of reconstitution of the Boards of Directors has been completed by all the banking companies in the private sector except three small banks with deposits of less than Rs. 10 crores. Of the 9 Indian banks in the private sector with deposits of Rs. 10 crores and above (as on February 1, 1969), eight banks had complied with the legal provisions before June 1970 and the remaining one took steps in this direction during the year under review. Among the banks having deposits of less than Rs. 10 crores, 34 banks have already reconstituted their Boards of Directors (of which 14 during the year under review), while in the case of 3 banks which have found difficulty in complying with the provisions of law, the Central Government has, on the recommendation of the Reserve Bank, granted exemption upto August 1, 1971, and the matter is being pursued with them.

277. In terms of Section 10B of the Banking Regulation Act, 1949, every Indian banking company in the private sector is required to have a whole-time Chairman who shall be entrusted with the management of its affairs. Out of 47 banks in the private sector at present, 41 banks have already complied with this requirement. In the case of the remaining

banks, the Central Government has granted extension of time limit upto August 1, 1971. However, even in respect of these six banks, proposals submitted by two banks have been agreed to by the Reserve Bank in principle and the remaining four banks have been advised to take early steps to comply with the requirements of law within the time allowed.

278. In terms of Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949, banking companies in the private sector are required to obtain the prior approval of the Reserve Bank regarding appointment/re-appointment of their Chief Executive Officers as also for any amendment in respect of the provisions relating to appointment/remuneration of their directors/Chief Executive Officers. Applications from private banking companies numbering 213 for the appointment/re-appointment or remuneration of their Chief Executive Officers were disposed of during the year July 1, 1970 to June 30, 1971. Of these, 191 applications were approved and 22 rejected.

Inspection of Banks

279. In pursuance of the Reserve Bank's programme of periodical inspections of banks with a view to assessing their financial position as well as methods of operation, 40 scheduled banks and 7 non-scheduled banks were either inspected or taken up for inspection under Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949 during the year July 1970 to June 1971. Besides, the inspection of foreign branches of Indian

banks in Malaysia, U.K., Singapore and Ceylon was carried out/taken up. Inspection of two banks in liquidation was also carried out and of one more bank taken up under Section 45Q of the Act for ascertaining whether there were any substantial irregularities in their winding up proceedings.

280. During the year under review, centrewise inspection of Branches commercial banks was introduced with the object of finding out *inter alia* the functioning of these branches *vis-a-vis* national objectives, specially in the field of mobilisation of deposits and financing of the weaker and neglected section of the community and suggesting ways and means of bringing about improvement in their functioning. Such inspections were conducted at 58 centres served by 565 offices of commercial banks.

Bank Mergers

281. The Bank continued its selective policy of strengthening the privately managed commercial banking system through processes of voluntary amalgamation and the transfer of liabilities and assets as per statutory provisions. One bank in the Delhi area, namely, Sahukara Bank Ltd., which was working under a scheme of arrangement, transferred its assets and liabilities in the new Fund to another bank (New Bank of India Ltd.) in the same area under Section 293(1) of the Companies Act, 1956 during the year under review. A proposal to amalgamate a scheduled bank, *viz.*, Bareilly Corporation (Bank) Ltd. in the Kanpur area with another scheduled bank, *viz.*, Banares State Bank Ltd., in the same area on a voluntary basis was approved by the Bank in principle and the banks were advised to proceed further in the matter.

282. No bank was granted moratorium by the Central Government under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 during the year. The total number of banks granted moratoria since September 1960 remained unchanged at 60 with deposits amounting to Rs. 49.95 crores. The details regarding the consequential arrangements such as amalgamation with other banks, liquidation (voluntary or otherwise), etc., and protection of depositors' interest were detailed in the last year's Report.

283. In terms of the schemes of amalgamation under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, the shareholders of the banks which have been amalgamated with other banks are required to be paid the surplus amount left with the transferee banks after paying the depositors in full. The shareholders of 12 transferor banks have been paid in full while *pro rata* payments are being made to the shareholders of 14 other transferor banks.

Licensing of Banks

284. During the year under review, licences under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 to carry on banking business in India were granted to two banks, *viz.*, Lord Krishna Bank Ltd., and Jammu and Kashmir Bank Ltd. During the period, the licences held by 14 major Indian commercial banks were cancelled, since they had ceased to carry on banking business in India. Consequent on their undertakings having been transferred to and vested in the corresponding new banks in terms of Section 4 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Thus, the number of banks in whose cases licences have been cancelled increased to 50, while the total number of licenced banks stood reduced to 46 as at the end of June 1971. Besides, there were 22 banks in the public sector comprising the State Bank of India, its seven subsidiaries and the 14 corresponding new banks set up to carry on the business of above mentioned nationalised undertakings, which are not required to obtain a licence.

285. During the year under review, a licence under Section 22 of the Act carry on banking business in India was refused to one existing bank, *viz.*, Punjab and Kashmir Bank Ltd., while an application of a company for grant of a licence under the Section to commence banking business in India was rejected. The total number of banks to which licences were refused stood at 282 as at the end of June 1971. The existing undertaking of one of the fourteen nationalised banks has also applied for grant of a fresh licence to commence banking business in India and its application is pending.

Liquidation Proceedings

286. During the year under review, 10 non-scheduled banks were dissolved by the High Court. One bank went into voluntary liquidation after obtaining from the Reserve Bank a certificate under Section 44(1) of the Banking Regulation Act, 1949 while 2 banks went into Court liquidation.

287. The Bank scrutinised 215 returns submitted by the liquidators of the banks under Section 45R of the Banking Regulation Act, 1949, with a view to ensuring that legal requirements were complied with and that the liquidation proceedings were not unduly delayed.

288. Directives were received from the Central Government for the inspection of 3 banks under Section 45Q of the Banking Regulation Act, 1949.

Credit Information

289. The Reserve Bank's Credit Information Division made a systematic revision in March 1971 of the system of collecting and processing credit information on the borrowers of the banks in order to widen the scope of such information and maintain more up-to-date data and thus enhance its utility to the banks. In the context of the nationalisation of major banks that underscores the social objectives of the banking development, the credit information now obtained on the borrowers covers certain wider aspects such as purpose of credit, occupation of borrower, etc. Keeping the above considerations in view, the form and content of the return have been appropriately revised and the banks have been provided with comprehensive guidelines for compiling the return. Further, with a view to facilitating easy compilation of the return by banks, the Reserve Bank has adopted (with suitable modifications) a code system on the lines prescribed for "Uniform Balance Books—Statistics relating to bank credit", which was already advised to the banks earlier. As it was observed that the compilation of credit information on a quarterly basis at the previously existing levels (*viz.*, secured limits of Rs. 5 lakhs and over and unsecured limits of Rs. 1 lakh and over) involved considerable time and effort on the part of banks as well as in processing the data in the Reserve Bank, it was decided to obtain data on the larger borrowers (covering all secured limits of Rs. 10 lakhs and over and unsecured limits of Rs. 2 lakhs and over) quarterly, whereas data on the borrowers having secured limits of Rs. 5 lakhs and over and unsecured limits of Rs. 1 lakh and over would be obtained only half-yearly, *i.e.*, at the end of June and December. Banks have also been advised to make increasing use of the credit information available with the Reserve Bank while processing all applications for larger limits. With the introduction of the revised return, it would be possible to furnish more up-to-date credit information to banks. During the year July 1, 1970 to June 30, 1971, the Division furnished information in respect of 1,458 applications to 34 applicant banks/institutions.

Clearing House Facilities

290. During the year under review, the clearing house facilities were further expanded as part of the Bank's policy of extension of banking facilities in the country. Thus, during the year (July 1970 to June 1971) 28 more clearing houses were established, bringing the total number of clearing houses functioning in the country to 135. Of these, 9 are managed by the Reserve Bank of India, 102 by the State Bank of India and 24 by the Subsidiaries of the State Bank of India.

Working Group on Jute Industry

291. The Report of the Working Group on credit problems of the jute industry, a mention of which was made in the last year's Report, was examined by the Bank. The Group had recommended, *inter alia*, that a separate scheme be formulated for providing some relief to the industry by way of charging a concessional rate of interest on the borrowings in respect of that portion of the mills' production which is exported. The Group had also indicated the broad guidelines of the scheme. After examination, the suggestion was found acceptable to the Bank and hence, it would be circulated to the banks on obtaining Government's concurrence.

in the matter. The other recommendations of the Group were also found generally acceptable and the Indian Banks' Association had been advised to request the member banks to implement them.

Working Results of Commercial Banks

All Scheduled Commercial Banks

292. An analysis of the working results of 69* scheduled commercial banks including those of nationalised banks, which have published their profit and loss accounts for the year 1970 reveals that there was a noticeable improvement in their profits during the year as compared with 1969; thus, their profits rose from Rs. 21.6 crores to Rs. 26.3 crores. The total income of these banks increased by Rs. 87.9 crores (22 per cent) during 1970 as against an increase of Rs. 42.8 crores (12 per cent) in 1969. The increase has been due to the spurt in earnings from 'interest and discount' which rose by Rs. 82.7 crores or by 25 per cent during 1970 as compared with the rise of Rs. 36.3 crores or by 12 per cent in 1969. The rise in earnings from 'commission, exchange and brokerage' was smaller in 1970 when compared with the rise in 1969. The total expenses of the 69 banks increased by Rs. 83.2 crores (22 per cent) in 1970 as compared with Rs. 41.4 crores (12 per cent) in 1969. Expenditure on 'salaries, allowances and Provident Fund contributions' showed an increase of 27 per cent in 1970 over 1969 as against an increase of 11 per cent in 1969. 'Interest paid on deposits and borrowings' also showed an increase, the rate of increase being 19 per cent in 1970 as compared with 11 per cent in 1969.

State Bank Group

239. Total income of the State Bank of India improved from Rs. 91.4 crores in 1969 to Rs. 112.7 crores in 1970, and total expenditure rose from Rs. 85.9 crores to Rs. 107.3 crores. The larger rise in expenditure than in income was due to the sizeable increase in establishment expenses (Rs. 10.9 crores) and in interest paid on deposits and borrowings (Rs. 8.6 crores) during the year. Consequently the balance of profit recorded a marginal fall from Rs. 5.50 crores in 1969 to Rs. 5.40 crores in 1970. Out of the profits, the State Bank transferred Rs. 1.09 crores to reserves, earmarked Rs. 2.70 crores for payment of bonus to staff and Rs. 1.29 crores as dividend to shareholders, the allocations in all these cases being the same as in 1969. The Subsidiary banks increased their earnings from Rs. 26.7 crores in 1969 to Rs. 32.5 crores in 1970, while their expenditure rose somewhat less from Rs. 25.8 crores to Rs. 31.2 crores. As a result, their profits improved from Rs. 95 lakhs in 1969 to Rs. 1.33 crores in 1970. These banks transferred Rs. 13 lakhs to reserves, paid Rs. 35 lakhs as dividend to the State bank and earmarked as bonus to staff a sum of Rs. 77 lakhs. While the transfer to reserves was less than in 1969, payment of dividend to the State Bank and of bonus to staff was higher than in 1969.

Nationalised Banks

294. The nationalised banks published in December 1970 their first balance sheets and profit and loss accounts as on December 31, 1969. These fourteen banks have, after meeting all their expenses and after providing for the usual and necessary provisions, transferred out of profits for 1969 a total amount of Rs. 3.69 crores to the Reserve Fund (as against Rs. 1.80 crores transferred by the predecessor banks before nationalisation out of profits for 1968). Out of their net profits earned during the period since the date of nationalisation, surplus profits transferred by them to the Central Government in terms of Section 10(7) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 aggregated Rs. 2.33 crores.

295. The working results of the 14 nationalised banks for the year 1970, published by them recently, reveal a marked improvement in the profits (before payment of bonus to staff, but after tax) earned by them, which amounted to Rs. 13.8 crores in 1970 as against Rs. 10.9 crores in 1969. This has occurred despite a sharp rise in their establishment expenses following the opening of a record number of branches and increased commitments due to the revision of wages and salaries of bank staff.

296. The total income of these banks increased from Rs. 217.6 crores in 1969 to Rs. 266.7 crores in 1970 and their total expenses from Rs. 206.7 crores to Rs. 252.9 crores. The increase in their earnings was largely due to the upward revision of banks' lending rates following the removal by the Reserve Bank of the ceiling of 9.5 per cent on lending rates in February 1970 and the prevalence of a relatively high credit-deposit ratio during the year.

297. Out of their profits, the nationalised banks earmarked Rs. 2.8 crores for the Reserve Fund, allocated Rs. 6.9 crores as bonus to staff and transferred the balance of Rs. 4.2 crores to Central Government as per statutory requirements.

Control over Non-Banking Companies

298. A reference was made in the last year's Report regarding the large increase in the number of 'Finance Corporations' in South India, particularly in Mysore State, which have been accepting deposits from the public at relatively higher rates of interest. Since these corporations are partnership firms, the provisions of the directions issued to non-banking companies in regard to acceptance of deposits are not applicable to them at present. The question of enforcing the provisions of the local Money-Lenders Acts in relation to these corporations and of amending these enactments so as to provide for certain additional safeguards has been taken up with the Governments of Mysore and Tamil Nadu.

299. The Legislative Assembly of Andhra Pradesh has passed a Bill to regulate the business of chit fund companies. The question of amending the existing law relating to 'chitties' in Kerala is still under consideration of the State Government. The Government of Mysore has been considering the question of enacting local legislation for this purpose.

300. According to the survey of deposits with non-banking companies, based on the returns as on March 31, 1968, 2,398 companies out of a total number of 27,338 joint stock companies (financial and non-financial) at work submitted returns to the Reserve Bank of India and they reported 5.30 lakhs of accounts. The total amount of deposits (including exempted loans not counting as deposits at Rs. 209.59 crores) held by them as at the end of March 1968 was Rs. 477.89 crores as against Rs. 430.51 crores as at the end of March 1967 (including exempted loans amounting to Rs. 186.60 crores). The amount of deposits includes unsecured borrowings to the extent of Rs. 79.60 crores by companies from foreign sources such as World Bank, U.S.A.I.D., I.D.A., C.D.F.C. and the Ex-im Bank (as these do not fall in the category of exempted loans) as against the estimated amount of Rs. 92 crores at the end of March 1967.

Deposit Insurance Corporation

301. The number of insured banks declined to 82 at the end of June 1971 from 83 as at the end of June 1970, due to transfer of assets and liabilities of one bank to another insured bank. No new bank was registered during the year under review. During the period no fresh liability of the Corporation arose in respect of insured deposits. The liability of the Corporation in respect of one bank amalgamated under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 referred to in the last year's Report, was determined after scrutiny of the list of depositors and was paid. The total claims paid or provided for by the Corporation since its inception upto June 30, 1971 amounted to Rs. 113.04 lakhs in respect of 14 banks. During the year, the Corporation received reimbursement of Rs. 1.43 lakhs in respect of subrogated claims paid or provided for by it, raising the total amount of reimbursements received upto June 30, 1971 to Rs. 37.54 lakhs.

302. There was no change in the limit of insurance cover which was raised from Rs. 5,000 to Rs. 10,000 per depositor in April 1970. The rate of premium payable by insured banks on their deposits also remained unchanged at 5 paise per Rs. 100 per annum. According to the latest available statistics, 96.4 per cent of the deposit accounts and 61.9 per cent of the amount of deposits in insured banks were protected by the insurance scheme as at the end of September 1970.

*Covers all major Banks including thirteen foreign banks.

Deposit Insurance Scheme in the Co-operative Field

303. Some of the States have already amended the State Co-operative Societies' Acts to facilitate extension of Deposit Insurance Scheme to co-operative banks in their respective States. A notification extending the provision of Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968 with effect from July 1, 1971 to the co-operative banks in the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and the Union Territory of Goa, Daman and Diu has also been issued by the Government of India. The Deposit Insurance Corporation has registered, as on July 1, 1971, 385 eligible co-operative banks in the States and Union Territory mentioned above. With a view to ensuring uniformity in the amendments to be carried out by the Governments of other States/Union Territories, model amendments were circulated to them by the Agricultural Credit Department for amending their respective co-operative societies' Acts for the purpose of extending the Deposit Insurance Scheme to co-operative banks in their jurisdiction.

Banking Commission

304. In the last year's Report, mention was made about the constitution of five Study Groups by the Commission to examine and report on different aspects of banking.

305. The Study Groups on Indigenous Bankers and Bank Procedures have completed their work and the other Study Groups are about to finalise their reports. As regards the Study Group on Legislation Affecting Banking, the first part of the report has been finalised and the second part is under preparation. The surveys of Small-Scale Industries and Small Artisans undertaken by Universities and other bodies on behalf of the Commission have been completed and the major part of the report has been received by the Commission. The National Council of Applied Economic Research which was entrusted with a survey of bank services to depositors has completed it and submitted its report to the Commission.

306. During this period, the Commission visited the States of Rajasthan, Jammu and Kashmir, West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh. It also met the officials of the Government of Kerala at Trivandrum. The Commission's programme of visiting the various States came to an end in June 1971. The Commission visited New Delhi and held discussions with the Finance Minister. The Commission has also held meetings in Bombay with bankers, experts and others. The Commission is expected to finalise its report by the end of 1971.

Table 39—Commercial Banking Trends at a Glance
(As on the last Friday of June)

	1966	1967	1968	1969	1970	1971
I. Number of Banks						
(i) Scheduled Banks	76	74	73	73	72	74
(ii) Non-Scheduled Banks	31	24	19	16	13	12
II. Number of Offices						
(i) Scheduled Banks	6139	6,620	7,044	8,045	9,938	11,892
(ii) Non-Scheduled Banks	240	216	203	217	193	149
III. Aggregate Deposits (Rs. Crores)						
(i) Scheduled Banks	3123.2	3,517.0	3969.0	4645.8	5274.5	6189.9
(ii) Non-Scheduled Banks	25.0	24.5	26.2	28.0	13.8	14.7
IV. Demand Deposits (Rs. Crores)						
(i) Scheduled Banks	1477.3	1664.6	1874.8	2103.5	2328.8	2725.1
(ii) Non-Scheduled Banks	9.1	9.1	10.2	11.7	8.4	9.3
V. Time Deposits (Rs. Crores)						
(i) Scheduled Banks	1645.9	1852.4	2094.2	2542.3	2945.7	3464.8
(ii) Non-Scheduled Banks	15.9	15.4	16.0	16.3	5.4	5.4
VI. Deposits as percentage of National Income (%)	15.3	14.8	14.1	16.3	17.0	18.0*
VII. Total Bank Credit (Rs. Crores)						
(i) Scheduled Banks	2271.4	2631.1	3102.9	3598.8	4212.7	4775.8
(ii) Non-Scheduled Banks	15.0	15.1	12.8	16.4	3.5	3.1
VIII. Credit-Deposit Ratio (%)						
(i) Scheduled Banks	72.7	74.8	78.2	77.5	79.9	77.2
(ii) Non-Scheduled Banks	60.0	61.6	48.9	58.6	25.4	21.1
IX. Investments in Government Securities (Rs. Crores)						
(i) Scheduled Banks	918.8	922.6	975.6	1126.3	1186.1	1369.4
(ii) Non-Scheduled Banks	5.6	5.4	6.6	6.7	3.4	4.0
X. Investment Deposit Ratio (%)						
(i) Scheduled Banks	29.4	26.2	24.6	24.2	22.5	22.1
(ii) Non-Scheduled Banks	22.4	22.0	25.2	23.9	24.6	27.2
XI. Cash and Balances with R.B.I. (Rs. Crores)						
(i) Scheduled Banks	195.3	258.8	269.5	380.3	357.6	393.5
(ii) Non-Scheduled Banks	1.7	1.9	2.1	2.5	0.9	1.1
XII. Cash-Deposit Ratio (%)						
(i) Scheduled Banks	6.3	7.4	6.8	8.2	6.8	6.4
(ii) Non-Scheduled Banks	6.8	7.8	8.0	8.9	6.5	7.5

Notes : (1) The figures for non-scheduled banks in the last column relate to August 1970.

(2) The figures for June 1971 are provisional.

(3) The figures for non-scheduled banks for 1970 and 1971 are provisional.

* Based on National Income at current prices (estimated).

IV. DEVELOPMENTS IN CO-OPERATIVE BANKING

307. The year under review was characterised by consolidation of gains made in previous years in the direction of adoption of progressive loaning policies and mobilisation of deposits by co-operative banks and in opening a line of credit to the small and economically weak farmers as well as to tribals engaged in agriculture and allied occupations. The crop loan system which has come to be adopted as a normal feature of lending by the co-operative banks, by and large, had undergone further refinements in the context of larger use of inputs by the agriculturists. The credit support that was extended to the co-operative banks consequent on these developments was also accompanied by efforts to ensure that the co-operative banks observed seasonality in their lending and recoveries. With a view to progressively decreasing the reliance of the banks on the Reserve Bank, the Bank fixed targets for deposits for the bigger of the central co-operative banks in the country. This was also a preparatory measure for the eventual linking of the Bank's lending rates to deposit mobilisation, as recommended by the All-India Rural Credit Review Committee. Similarly, in the case of land development banks, their rural debenture programme which was meant to mobilise rural savings, was linked to their ordinary debenture programme. The Bank continued its efforts in filling up the credit gaps in the areas of weak central Co-operative banks by continuing the implementation of the scheme of financing primary societies by commercial banks, in maintaining the credit flow in areas which were effected by widespread natural calamities by making use of credit stabilisation arrangements, and in strengthening the co-operative credit structure by suggesting concrete schemes for rehabilitation of weak central co-operative banks.

Agricultural Credit Board

308. The Agricultural Credit Board which was set up by reconstituting the erstwhile Standing Advisory Committee on Rural and Co-operative Credit on the recommendation of the All-India Rural Credit Review Committee, held its first meeting on August 3, 1970 and considered the Review Committee's various recommendations regarding the measures to be adopted by the Reserve Bank and other agencies of development for ensuring timely and adequate farm credit. In pursuance of the decisions of this Board, the State Governments and the co-operative banks were advised to take the action required of them in implementing the recommendations. As for the recommendations pertaining to its own functions and policies, the Bank has already initiated action for their implementation.

309. The Agricultural Credit Board also constituted two Standing Committees to advise it on problems of financing certain specialised fields of co-operative activity such as small-scale and cottage industries, long-term investment in agriculture, marketing, etc. The two Standing Committees had their first meetings during the year under review. While the Standing Committee I considered, among others, the problems relating to financing of small-scale and cottage industries, distribution and marketing in the agricultural sector, etc., the Standing Committee II reviewed the progress made in the sphere of credit facilities offered by the Bank for agricultural production and investment. Some of the important decisions arrived at by these Standing Committees related to the Bank providing separate line of credit for marketing of crops including processing, refinance for the marketing of minor forest produce and the purposes for which medium-term loans might be advanced by co-operative banks. The Agricultural Credit Board had also appointed a Study Group for a detailed examination of the recommendation of the Review Committee regarding the linking of the rate of interest on loans from the Bank to the efforts at deposit mobilisation by central co-operative banks. The Study Group, which met once during the year, considered various implications of the issues referred to it. The Group's report is awaited.

Financing of Small, Marginal and other Economically Weak Farmers

310. In pursuance of the recommendation of the Rural Credit Review Committee, the Government of India have approved the establishment of 46 Small Farmers Development Agencies (S.F.D.A.) and 37 Marginal Farmers and Agricultural Labour projects (M.F.A.L.) in selected districts.

The Bank has been actively assisting the co-operative banks and other credit institutions in the S.F.D.A./M.F.A.L. areas in attuning their policies and procedures to the needs of the small and marginal farmers and in augmenting their own resources so as to meet the credit needs fully. Simultaneously, the Bank took steps to ensure that credit needs of small and economically weak farmers are met even in areas outside these projects.

311. In pursuance of a suggestion from the Planning Commission, the Bank undertook special studies of some S.F.D.A. projects. These study reports indicated guidelines on the methodology to be adopted in identifying the small farmers and in ascertaining the credit and other needs of such farmers keeping in view the cropping pattern, availability of irrigation facility, scope for subsidiary occupations, etc. Measures were also suggested for strengthening the existing credit agencies and for building up the requisite infra-structure. In order to spell out the role and also to discuss the problems faced by co-operative banks in implementation of the programmes for the benefit of small farmers the bank convened regional conferences of representatives of central co-operative banks and State Governments at Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh and Calcutta. The central co-operative banks were also called upon to use a pre-determined percentage of their borrowings from the State co-operative bank for financing the small farmers.

Commercial Bank's Financing of Agricultural Credit Societies

312. The transitional scheme of financing of primary agricultural credit societies by commercial banks, in the areas of weak central co-operative banks, introduced last year with the financing of the Kharif 1970 operations, was continued during the year under review. Under the scheme, 1974 societies in 49 districts of Andhra Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Mysore and Uttar Pradesh were allotted to 300 branches of 20 commercial banks including the State Bank of India Group. As at the end of June 1971, the commercial banks advanced loans aggregating Rs. 6.93 crores to 1,546 societies. In addition, liabilities amounting to Rs. 2.13 crores in respect of 589 societies were also taken over by the commercial banks, thus bringing their total involvement, under the scheme, to Rs. 9.06 crores. The progress achieved under the scheme has been encouraging in Andhra Pradesh, Haryana and Mysore. Despite the procedural and organisational difficulties initially faced in implementing the scheme, a fair measure of success might be said to have been achieved, and the progress could further be accelerated subject to concerted efforts being made by all the agencies concerned. The commercial banks, financing agricultural credit societies under the scheme, are eligible for refinance facility from the Reserve Bank at a concessional rate of interest of 4-1/2 per cent. Their advances to the societies for issue of loans to members against pledge of agricultural produce (subject to credit control measures) are also exempted from ceiling as well as margin requirements for a period of two months from the date of harvest of the relevant crop, provided the amount of loan per member is restricted to a maximum amount of Rs. 2,500 or the crop loan outstanding whichever is lower. These concessions serve as incentives to the commercial banks in providing adequate credit support to the societies.

Co-operative Development

313. The above scheme of commercial banks' financing of primary agricultural credit societies was introduced at the instance of the Bank, pending the strengthening of the co-operative credit structure in the concerned areas. Efforts in this direction were continued and specific programmes of rehabilitation of weak central co-operative banks in areas where the above scheme was in operation and elsewhere were drawn up by the Bank and, after detailed discussions with the representatives of the State Governments and co-operative banks concerned, these programmes were recommended for implementation. The important suggestions related to : (i) strengthening of the capital structure of the central co-operative banks; (ii) rationalization of loaning policies and procedures; (iii) strengthening of the administrative and supervisory arrangements for recovery of overdues and future loans; (iv) financial assistance from the State Governments to augment the bad debt reserves; and (v) mobilization of deposits. During

the year under review, discussions were held with representatives of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Mysore States on various issues and problems connected with rehabilitation schemes. The Bank is closely following the progress of these measures.

314. Between January and May 1971, the Deputy Governor in-charge of rural credit held discussions on the more important aspects and problems of co-operative credit and development with the representatives of 12 States Governments. During these discussions, the persisting weaknesses were pointed out and the remedial measures suggested relating to mobilization of deposits by co-operative banks, mounting overdues, reorganization of the primary agricultural credit societies on the accepted pattern, rehabilitation of work central co-operative banks and problems of land development banks.

CO-OPERATIVE CREDIT: POLICY, PROCEDURES AND OPERATIONS

Special Measures for Small/Weak farmers

315. An important stipulation introduced by the Reserve Bank during the year in regard to the provision of financial accommodation to State co-operative banks for seasonal agricultural operations and marketing of crops was that a portion of the credit limit sanctioned by the Bank to each central co-operative bank should be earmarked for financing small and economically weak farmers. To start with, central co-operative banks were advised to show at least 10 per cent of outstandings of borrowings from the concerned State co-operative banks as on June 30, 1971 as covered by outstandings of loans to societies against small/marginal or economically weak farmers. This percentage would be increased to 20 by the end of June 1972.

316. With the object of helping agricultural operations of the tribals in Andhra Pradesh, the Girijan Co-operative Corporation was recognised by the Bank for the purpose of channelling agricultural credit to tribal cultivators in three districts, where the normal co-operative credit structure was either weak or unwilling to finance the tribals. The Bank also decided to provide refinance facilities to State co-operative banks for advances made to forest marketing co-operatives for the marketing of minor forest produce of tribals.

Separate Credit Limits for Marketing of Crops

317. The Rural Credit Review Committee recommended that the Reserve Bank might sanction separate credit limits for "seasonal agricultural operations" and "marketing of crops". While the Bank had already introduced the practice of sanctioning separate credit limits for the marketing of cotton and kapas in 1968-69, it has now been decided that from 1971-72 onwards separate limits should be sanctioned for marketing all other crops also. The objective is to see that the limit meant for seasonal agricultural operations is not diverted towards financing marketing of crops.

Progress of Bank's Financial Accommodation

318. The financial accommodation from the Bank for agricultural purposes has been progressively increasing year after year with the growing demand for agricultural credit. The credit limits sanctioned by the Bank to State co-operative banks for financing seasonal agricultural operations and marketing of crops at the concessional rate of 2 per cent below the Bank rate increased from Rs. 370.16 crores during 1969-70 to Rs. 390.11 crores during 1970-71. The drawings during the year aggregated Rs. 424.49 crores as against Rs. 425.09 crores in 1969-70. Repayments were of the order of Rs. 449.76 crores as against Rs. 394.06 crores in 1969-70. The outstandings as on June 30, 1971 stood at Rs. 188.84 crores as compared with Rs. 214.11 crores as on June 30, 1970 (Table 39). The special short-term credit limits sanctioned to State co-operative banks for financing marketing of cotton and kapas during the year 1970-71 were Rs. 10.65 crores as against Rs. 7.75 crores during 1969-70. The aggregate drawings were Rs. 8.56 crores, repayments Rs. 9.52 crores and outstandings Rs. 1.03 crores. The figures for 1969-70 were Rs. 9.33 crores, Rs. 8.24 crores and Rs. 1.99 crores, respectively.

49 G of I/72-21

Table 39—Short-term Loans Provided by the Reserve Bank of India to State Co-operative Banks at the Concessional Rate of Interest for Seasonal Agricultural Operations and Marketing of Crops (1960-61 to 1970-71)

(Rs. crores)

Year	Limits sanctioned	Drawals	Outstandings
1960-61	111.79	142.91	100.88
1961-62	138.18	154.22	115.20
1962-63	163.94	199.72	124.28
1963-64	186.21	298.18	146.54
1964-65	199.86	253.33	150.51
1965-66	212.66	260.36	143.67
1966-67	257.50	292.20	135.38
1967-68	314.15	364.89	137.17
1968-69	337.52	411.15	183.09
1969-70	370.16	425.09	214.11
1970-71	390.11	424.49	188.84

Seasonality in Lending and Recovery

319. In order to ensure the financial discipline of seasonality in lending and recovery of loans, the Rural Credit Review Committee recommended closed periods for drawings on the short-term credit limits sanctioned by the Bank. The Agricultural Credit Board felt that the principle of seasonality could as well be achieved by requiring the central banks to bring down the level of outstandings under borrowings from the apex bank to a given minimum level during any part of the year, which would also ensure that the banks were not left with unduly large surplus at any time. The minimum levels upto which the borrowings on the short-term loans by the central cooperative banks should be reduced have been arrived at by mutual discussions between the Bank and the representatives of some selected States/Central co-operative banks. The State co-operative banks in consultation with Cooperative Departments of their States have been asked to fix similar limits for other central co-operative banks on mutually agreed lines taking into account broadly the cropping pattern of the district, etc.

Finance for Fertilizers

320. The Bank continued to provide financial accommodation to the State co-operative banks at Bank rate under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act, against Government guarantee, for financing the apex marketing societies for purchase, stocking and distribution of chemical fertilizers. Since December 1969, accommodation for the purpose was considered only in cases where the State cooperative marketing societies were unable to obtain the necessary funds from commercial banks. This accounted for the decline in the aggregate limits sanctioned by the Bank to State co-operative banks for the purpose during the calendar year 1970. The limits sanctioned, drawings and outstandings at the end of the year were Rs. 16.80 crores, Rs. 11.27 crores and Rs. 4.22 crores, respectively. The corresponding figures for 1971 (upto the end of June) are Rs. 19.25 crores, Rs. 17.43 crores and Rs. 3.43 crores. The position in this regard is under constant review with a view to ensuring that the legitimate credit needs of fertilizer marketing are met by commercial and co-operative banks, appropriately supplemented by the Bank.

Co-operative Sugar Factories

321. A short-term credit limit of Rs. 7.50 crores was sanctioned to one State co-operative bank on behalf of ten co-operative sugar factories under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act at 2 per cent above the Bank rate for financing the working capital requirements of co-operative sugar factories against stocks of sugar by way of pledge. The total drawings aggregated Rs. 5.32 crores and the outstandings as on June 30, 1971 were Rs. 4.32 crores.

Loans to A R C

322. The Agricultural Refinance Corporation was sanctioned for the year 1970-71 a short-term credit limit of Rs. 8.00 crores at the Bank rate under Section 17(4)(E) of the Reserve Bank of India Act against the security of special development debentures purchased by it. The aggregate drawings on the limit amounted to Rs. 11.80 crores and the outstandings as on June 30, 1971 were Rs. 7.52 crores.

Medium-term Finance

323. In the sphere of medium-term loans for agricultural purposes, the Bank's policy was aimed at encouraging loans for identifiable purposes such as construction of wells, purchase of pumpsets and agricultural implements, etc. As certain studies made in this connection revealed that a good portion of the medium-term loans advanced by a number of central banks was meant for purposes which were not clearly identifiable, it was decided to regulate the grant of medium-term credit limits in 1970-71 in such a way as to bring about a definite shift towards loans for identifiable productive purposes. Accordingly, for availing of the accommodation from the Bank, a central bank was required to advance at least 40 per cent of its medium-term loans for any one or more of the four purposes, viz., (i) construction of wells and other minor irrigation schemes, (ii) repairs to wells and other irrigation sources, (iii) purchase of machinery such as, pumpsets, and (iv) purchase of agricultural implements. Precautions were also taken to see that the central co-operative banks did not come up with ambitious programmes in areas where land development banks had drawn up schemes with the assistance of the Agricultural Refinance Corporation and that there was proper co-ordination between the central banks and the land development banks in the sphere of term lending.

Finance for Milch Cattle Purchase

324. In 1966, the Bank had approved the channelling of its finance for purchase of milch cattle through milk supply societies in an area where a co-operatively organised dairy development project was in effective operation. Following the recommendation of the Rural Credit Review Committee, the Bank, in December 1970, agreed to these loans being granted by the milk supply societies to their members even if the pasteurisation, processing and marketing of milk and milk products were undertaken by a private or government dairy. With a view to enabling the small farmers to take up dairying or poultry activities alongside agriculture, it was decided in June 1971 that medium-term loans might be advanced upto a limit of Rs. 2,000 without insisting on the mortgage of immovable property or charge on land.

Medium-term Limits

325. During the year, the aggregate of medium-term credit limits sanctioned under Section 17(4AA) read with Section 46A (2) (b) of the Reserve Bank of India Act at 1-1/2 per cent below the Bank rate was Rs. 17.55 crores as against Rs. 18.30 crores sanctioned in the previous year. In addition, one State co-operative bank was sanctioned loans aggregating Rs. 1.21 crores for purchase of shares in co-operative sugar factories at the Bank rate. The drawals (including those limits sanctioned at the Bank rate) were Rs. 14.20 crores during 1970-71 as against Rs. 11.48 crores in 1969-70 and the outstandings as on June 30, 1971 were Rs. 24.31 crores as against Rs. 20.45 crores at the end of the previous year (Table 40).

Table 40—Medium-Term loans for agricultural purposes provided by the Reserve Bank of India to State Co-operative Banks at the concessional rate (1960-61 to 1970-71)

(Rs. crores)				
Year	Limits sanctioned	Drawals	Outstandings	
1960-61	4.68	5.69	8.81	..
1961-62	9.56	7.39	11.67	..
1962-63	9.31	4.18	10.56	..
1963-64	14.01	7.45	13.00	..
1964-65	14.39	7.91	14.32	..
1965-66	14.11	7.45	14.96	..
1966-67	15.49	8.37	15.41	..
1967-68	16.57	9.12	16.47	..
1968-69	19.00	8.98	17.60	..
1969-70	18.30	11.48	20.45	..
1970-71	18.76	14.20	24.31	..

326. As in the past, during 1970-71 medium-term credit limits aggregating Rs. 21.80 crores at 1-1/2 per cent below the Bank rate were sanctioned to four State co-opera-

tive banks from out of the National Agricultural Credit (Stabilization) Fund to enable them to convert the short-term loans into medium-term loans to tide over the difficulties arising out of natural calamities. The total draws from the Fund during the year were Rs. 13.64 crores and the outstandings with State co-operative banks were Rs. 13.66 crores as on June 30, 1971. Besides, two State co-operative banks were sanctioned short-term credit limits of Rs. 7.00 crores at the Bank rate against the pledges of Government/Trustee securities representing the investments out of their Stabilization Funds for granting conversion facilities to the Central co-operative banks in their areas. The draws against these limits till June 1971 amounted to Rs. 4.18 crores and the amount outstanding as on June 30, 1971 was Rs. 2.50 crores.

327. The Bank generally provided financial accommodation under Section 17(2)(bb) of the Reserve Bank of India Act for financing the production and marketing activities of weavers' societies at concessional rate of interests at 1-1/2 per cent below the Bank rate. Accommodation was also provided for the first time, as per terms and conditions finalised last year, under the same Section to State co-operative banks for financing the other cottage and small-scale industrial units coming under the 22 'approved' groups. During the financial year 1970-71, 11 State co-operative banks were sanctioned credit limits aggregating Rs. 10.12 crores as against Rs. 8.18 crores during 1969-70, under Section 17(2)(bb) read with Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act at 1-1/2 per cent below the Bank rate for financing the production and marketing activities of weavers' societies. The draws amounted to Rs. 12.36 crores as against Rs. 9.49 crores during the previous year and outstandings as on March 31, 1971 stood at Rs. 7.83 crores as against Rs. 6.42 crores at the end of the previous year. Three State co-operative banks were sanctioned credit limits of Rs. 80.00 lakhs under Section 17(2)(a) read with Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act for financing yarn business of apex handloom weavers' societies as against Rs. 69.00 lakhs sanctioned last year. Draws aggregated Rs. 4.00 lakhs and outstandings at the end of March 31, 1971 were Rs. 2.93 lakhs. Four State co-operative banks were for the first time sanctioned limits aggregating Rs. 46.59 lakhs at Bank rate on behalf of 4 central co-operative banks and 8 primary (urban) co-operative banks for financing approved cottage and small-scale industrial units. A sum of Rs. 1.95 lakhs drawn against these limits was fully outstandings as on March 31, 1971.

Urban Co-operative Banks

328. The primary (urban) co-operative banks are catering to the banking and credit needs of urban clientele constituting generally small traders, small businessmen, artisans, factory workers, salaried persons, etc., in urban and semi-urban areas. With a view to bringing about reorientation in their loaning policies, the Bank had been advising the State co-operative banks that refinance to urban co-operative banks should be on a reimbursement basis. Such refinance was to be limited to 50 per cent, 66-2/3 per cent and 75 per cent of the loans and advances provided by the urban banks, for consumption expenditure, commerce and trade and small-scale industries, respectively. As indicated earlier, the primary (urban) co-operative banks are eligible for refinance facilities under Section 17(2)(bb) or (4)(c) of the Reserve Bank of India Act for financing the production and marketing activities of 22 broad groups of cottage and small-scale industrial units at Bank rate. For the first time during the financial year 1970-71, the Bank had sanctioned credit limits aggregating Rs. 42.45 lakhs to the Gujarat and Manipur State Co-operative Banks on behalf of 8 primary (urban) banks. The Bank continued to provide loans to State Governments from the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund to enable them to contribute to the share capital of primary (urban) banks on a selective basis. During the financial year 1970-71, a sum of Rs. 10.30 lakhs was sanctioned for contribution to share capital of 19 primary (urban) banks.

Special Assistance from N.A.C. (L.T.O.) Fund

329. The terms and conditions governing financial accommodation from the Bank's National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund to the State Governments

for contributing to the share capital of co-operative credit institutions were liberalised during the year under review. Accordingly, the financially weak central co-operative banks, which are under a scheme of rehabilitation, are now eligible for contribution in excess of 50 per cent of their total paid-up capital, even if the percentage of overdues to demand exceeds 30 but not more than 50. Primary agricultural credit societies operating in the areas of weak central co-operative banks and of S.F.D.A./M.F.A.L. projects are eligible for contributions upto Rs. 10,000 irrespective of the level of over dues. Contributions above Rs. 10,000 are subjects to the conditions regarding overdues, issue of loans for productive purposes, etc. It is also considered adequate for the purpose of State contribution, to link shareholdings to borrowings at not less than 10 per cent instead of 20 per cent as hitherto at the primary level.

Long-term Finance

330. During the financial year 1970-71, loans aggregating Rs. 11.85 crores (excluding renewals of the previous year to the extent of Rs. 0.03 crore) were sanctioned to 14 State Governments out of the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund under Section 17(4)(AA) read with Section 46A(2)(a) of the Reserve Bank of India Act for contribution to the share capital of 6 State co-operative banks, 105 central co-operative banks, 4,076 primary agricultural credit societies, 8 central land development banks, 146 primary land development banks and 19 primary (urban) co-operative banks. Further, a sum of Rs. 75.96 lakhs sanctioned during 1969-70 was extended for draws during 1970-71. The aggregate draws of the State Governments during the financial year 1970-71 amounted to Rs. 12.49 crores as against Rs. 6.80 crores during 1969-70 (Table 41). The total amount outstanding against the State Governments on this account was Rs. 41.93 crores as on March 31, 1971 as against Rs. 33.83 crores as on March 31, 1970.

Table 41—Loans from the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund to State Governments for Contribution to the Share Capital of Co-operative Credit Institutions-1960-61 to 1970-71

(Rs. crores)

Year*	Limits sanctioned including renewals	Drawals
1960-61	3.23	2.75
1961-62	5.60	5.43
1962-63	4.94	4.91
1963-64	3.35	3.30
1964-65	4.38	4.18
1965-66	2.68	2.68
1966-67	2.47	2.27
1967-68	7.37	7.36
1968-69	4.13	3.78
1969-70	7.49	6.80
1970-71	11.88	12.49@

*Financial year.

@Including extended loans of the order of Rs. 75.96 lakhs sanctioned during 1969-70.

Special Measures to Improve the Co-operative Long-term Lending Institutions

331. A reference was made in the last year's Report to the ordinary debenture programme of the land development banks fixed at Rs. 141.20 crores for the year 1970-71. The programme was revised downward to Rs. 139.20 crores due to reduced support from the Central and State Governments. Against the above approved programme, the land development banks issued debentures for an aggregate amount of Rs. 123.56 crores during the financial year ended March 31, 1971. The subscriptions actually collected by the banks aggregated Rs. 127 crores. The Central and State Governments subscribed Rs. 36.62 crores, the Reserve Bank of India the State Bank of India and the Life Insurance Corporation of India together Rs. 22.15 crores (the Reserve Bank's contribution being Rs. 4.16 crores) and the commercial banks, Rs. 29.91 crores. The shortfall in the approved programme was partly due to organisational failures in the land development banks and partly to the progressive improvement in the quality of scrutiny of loan applications resulting in a reduction in the volume of loans for unproductive purposes.

322. The Bank convened a meeting of the representatives of the principal investors and the central land development banks in March 1971 to finalise the debenture programme for the financial year 1971-72. A programme of Rs. 140 crores was tentatively agreed upon for the year. The support available towards the programme from the Central and State Governments was placed at Rs. 34 crores. The public sector institutions were expected to provide Rs. 27 crores and the commercial banks, Rs. 30 crores. In view of the arrangements made for ensuring adequate support to the debenture programme of the land development banks from different governmental and institutional sources, the Bank continued to lay emphasis, as in previous years, on the purposes for which loans should be advanced by the land development banks. Thus, the condition that at least 90 per cent of the loans advanced should be for productive purposes, of which 70 per cent for easily identifiable purposes, was continued for the year 1971-72.

333. Since 1969-70, only such of the land development banks, overdues of which at the primary level were less than 15 per cent of the demand for the year as at the end of the previous co-operative year, were eligible for 100 per cent of the support provided for under the debenture programme. The banks in which the recovery of loans did not reach the above level were eligible only for a lower support on a tapering-off basis. An important consideration which prevailed in imposing the above condition was the expectation that the denial of full support to the debenture programme of the land development banks with higher levels of overdues would compel them to initiate appropriate action for the recovery of the overdue loans.

334. The Bank had also been endeavouring during the last two years to impress upon the land development banks the need to adopt operational procedures and policies oriented towards agricultural development. The need for the observance of some discipline in regard to loaning by the land development banks had lately assumed urgency because of the terms of the agreements entered into between the Agricultural Refinance Corporation and the land development banks with the International Development Association in respect of the agricultural credit projects sanctioned by the latter. The land development banks, accordingly, are required to adopt, even in regard to their normal lendings, the terms and procedures similar to, or consistent with, those stipulated in the project agreements in respect of the project lendings. Efforts were also continued to bring about qualitative improvements in regard to other aspects of working of land development banks, particularly resources management.

335. The Rural Credit Review Committee which reviewed the policy in regard to the floatation of rural debentures by land development banks recommended that the rural debenture programme should be linked to their ordinary debenture programme. The committee suggested that the rural debenture programme should not be less than 5 per cent of the ordinary debenture programme in any State. The Agricultural Credit Board generally endorsed the above recommendation and suggested that a beginning might be made towards implementing the recommendation from the year 1970-71. In pursuance of this recommendation, the land development banks were advised in December 1970 to float during 1970-71 one or more series of rural debentures for an amount aggregating at least 2-1/2 per cent of the approved ordinary debenture programme for the year. During the financial year ended March 31, 1971, the land development banks issued rural debentures for an aggregate amount of Rs. 4.39 crores, the Bank's contribution to these debentures being Rs. 0.18 crore. The Bank's total holding is of rural debentures as on March 31, 1971 were Rs. 8.59 crores.

Number of Co-operative Banks

336. As on June 30, 1971, there were 1,315 co-operative banks—29 State, 366 Central and 920 primary banks—coming under the purview of Banking Regulation Act 1949 as against 1,317 co-operative banks (28 State, 366 Central and 923 primary) at the beginning of the year. The decline in the number of banks during the year was mainly due to deletion of certain non-agricultural credit societies from the list of primary co-operative banks.

337. With a view to tightening the control on advances of State and Central co-operative banks against security of cotton

and kapas, selective control measures were taken during the year under review, as discussed on page 81.

Agricultural Refinance Corporation

Sanctions and Disbursements

338. During the year 1970-71, the Corporation sanctioned refinance in respect of 100 schemes@ of agricultural development relating to a wide range of irrigation and land development purposes. The total financial assistance involved in these schemes was of the order of Rs. 62.15 crores. The Corporation's commitment under these schemes was Rs. 53.92 crores.

339. Out of 100 schemes sanctioned during the year under review, 67 schemes are to be implemented through the central land development banks, the refinance provided in their case being in the form of contribution towards the special development debentures to be floated by the concerned banks. Six schemes are to be implemented through the State co-operative banks and the remaining 27 by the scheduled commercial banks, the refinance in their cases being in the form of loans.

340. The 100 schemes sanctioned, during the year under review, include 55 schemes for the development of minor irrigation works, 9 schemes for the development of land, 26 schemes of plantation and horticulture and 1 scheme of farm mechanisation. Of the remaining, 2 schemes are for the development of poultry farming, 2 for the development of fisheries, 3 for dairy development and 2 for the construction of godowns.

341. A noteworthy development during the year was the break-through achieved in regard to financing schemes for dairy development. The three dairy schemes sanctioned during this year involve financial assistance of the order of Rs. 142.25 lakhs for purchase of milch cattle by the cultivators engaged in mixed farming activities combining dairying with agriculture and also professional non-agriculturist milkmen of the co-operative milk societies. Yet another significant development was the refinance facilities provided by the Corporation for the first time to a State Agro-Industries Corporation through a scheduled commercial bank. The Agro-Industries Corporation will be providing services to cultivators for land-levelling by obtaining funds from the scheduled commercial bank which will be refinanced by the Corporation. Similarly, for the first time, the Corporation approved minor irrigation schemes for benefiting small farmers—one in Haryana through the Haryana Minor Irrigation Tubewells Corporation in Naraingarh tehsil of Ambala district for financial assistance of Rs. 161.50 lakhs for 170 deep tubewells and the other in West Bengal in the Hoogly district involving financial assistance of Rs. 18 lakhs for sinking 300 shallow tubewells. The two scheme areas fall under the Small Farmer's Development Agencies and the Corporation has provided 100 per cent refinance. More such schemes are under active consideration. The Corporation was also able to help cultivators to solve their storage problems in two more States, viz., Mysore and Haryana, by sanctioning one scheme each involving financial assistance of Rs. 71.10 lakhs in Mysore and Rs. 19.42 lakhs in Haryana. This is in addition to the earlier schemes of storage sanctioned by the Corporation in three States, viz., Gujarat, Punjab and Uttar Pradesh. The Corporation has made special efforts to promote more and more schemes for areas and States not fully developed and in this connection, has sent its officers for formulating schemes which could be sponsored by the concerned financing institutions and the State Governments. The Chairman of the Corporation had also discussions with the representatives of States in this regard which were followed up by the Managing Director and other officers of the Corporation. Special meetings were also held between the officials of the Government of India, the senior officials of the State Governments and of the Corporation to promote more schemes in these States.

342. During the year, the Corporation approved reduction in the financial assistance in respect of some schemes sanctioned earlier as also the rephrasing of some schemes so as

to extend the period of floatation of the special development debentures. Taking into consideration the changes in the outlay of some schemes sanctioned earlier as a result of rephrasing as also withdrawal of schemes sanctioned during the earlier years, etc., the total number of schemes sanctioned by the Corporation during the eight year of its working as on June 30, 1971 is 458, the total financial assistance and the Corporation's commitment thereunder being Rs.293.00 crores and Rs. 248.66 crores, respectively.

343. The disbursements made by the Corporation during the year amounted to Rs. 30.62 crores, raising the total disbursements as at the end of June 1971 to Rs. 89.71 crores. Out of the amount of Rs. 30.62 crores disbursed during the year, a sum of Rs. 26.65 crores was disbursed to the central land development banks, Rs. 1.19 crores to State co-operative banks and Rs. 2.78 crores to scheduled commercial banks. During the year, 8 scheduled commercial banks and 5 State co-operative banks made repayments of principal due, amounting to Rs. 31.12 lakhs and Rs. 26.57 lakhs, respectively.

Augmenting of Resources

344. During the year, the Corporation augmented its resources as under : (i) Rs. 22 crores by way of borrowings from the Government of India under Section 20(1)(c) of the Agricultural Refinance Corporation Act and (ii) about Rs. 8.53 crores from the open market by floating 5-3/4 per cent ARC Bonds 1982 (II Series). Further, the Corporation's short-term borrowings during the period from the Reserve Bank, under Section 20(1)(b) of the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963, aggregated Rs. 11.80 crores of which Rs. 4.28 crores were repaid to Reserve Bank of India in April 1971.

Policies and Procedures

345. The following policy and procedural changes were effected during the year under review : (a) The Corporation has raised its interest rate on its refinance to 6-1/2 per cent per annum in respect of schemes to be sanctioned on or after November 23, 1970.

(b) The special concession of 10 per cent contribution by State Governments to the special development debentures, floated by the Central land development banks in respect of minor irrigation schemes sanctioned by the Corporation was further extended upto June 30, 1972.

(c) The Corporation decided, as a special case, to provide 100 per cent refinance in respect of viable schemes, sponsored by Small Farmers Development Agencies through the eligible institutions and sanctioned by the Corporation, upto June 30, 1971. This concession, initially granted for one year, has now been further extended upto June 30, 1972.

(d) After the nationalisation of the 14 scheduled commercial banks, these banks as also the State Bank of India and its subsidiaries have been involved in a greater measure in advancing loans for agricultural development. The Corporation follow a flexible policy in regard to the extent of refinance provided to commercial banks. It provides refinance to such banks by taking into consideration their liquid resources position. During the year, the Corporation took various steps for simplification of procedure for refinancing commercial banks.

346. It was mentioned in the last year's Report that the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliate, the International Development Association, had approved three projects in financing capital investment for modernizing and increasing the productive capacity of agriculture. During the year under report, agreements were signed between the International Development Association, Government of India and the Corporation in respect of four more

@Excluding two schemes sanctioned but subsequently withdrawn.

projects for which IDA would provide financial assistance of Rs. 67.80 crores (\$90.40 million); out of this Rs. 61.67

crores will be made available through the Corporation as under :

	IDA Credit	Amount to be routed through A.R.C. (Rs. Crores)
Haryana Agricultural Credit Project	\$ 25 million Rs. 18.75 crores	18.75
Tamil Nadu Agricultural Credit Project	\$ 35 „ Rs. 26.25 crores	22.35
Andhra Pradesh Agricultural Credit Project	\$ 24.40 „ Rs. 18.30 crores	18.09
Agricultural Aviation Project	\$ 6.00 „ Rs. 4.50 crores	2.48

The Corporation is actively associated with the implementation of these projects both as the sole refinancing agency and as the agency which is to satisfy itself about the inherent soundness of the schemes from technical and economic aspects. During the year the Corporation's Regional Office at Kanpur was shifted to Lucknow.

V. DEVELOPMENT IN EXCHANGE CONTROL

Mauritius Travel Scheme, 1970

347. In the sphere of Exchange Control the process of liberalisation of the Rules relating to travel referred to in the last year's Report was further carried forward during the year under review. Under the Mauritius Travel Scheme, 1970, introduced with effect from August 7, 1970, passages may be booked by airline/steamer companies and travel agents for any person who is a resident of India for visiting Mauritius once in three years. Such persons travelling to Mauritius by Air India will be eligible for release of exchange for U.S. \$100. Any visits to Mauritius with grant of foreign exchange by the Reserve Bank of India for business, or other purposes or under 'P' form approval given by the Reserve Bank will be ignored for the purposes of this Scheme and any visits to countries other than Mauritius under the Foreign Travel Scheme, 1970 will not debar a person from availing of the Mauritius Travel Scheme. Similarly, a visit to Mauritius under the Mauritius Travel Scheme, 1970, will not debar a person from availing of the benefits of Foreign Scheme, 1970, if otherwise admissible.

Exchange Entitlement of U.S. \$100

348. The facility of release of exchange of U.S. \$100 or its equivalent admissible to persons travelling on flights/sailing of Air India/Shipping Corporation of India has since been extended to :—

- persons eligible to avail of the Foreign Travel Scheme, 1970 for visiting Afghanistan or Burma travelling by flights of Indian Airlines on round-trip tickets without any further ticket for travel to any other countries under the Scheme; and
- persons who hold non-endorseable round-trip tickets issued under the Foreign Travel Scheme, 1970 for travel on the vessels of the Scindia Steam Navigation Co., Ltd.

Sale of Foreign Currency Notes and Coins

349. Until March 1971, the Exchange bureaux of Authorised dealers in foreign exchange and licensed money-changers functioning at air ports and docks were permitted to sell foreign currency notes and coins subject to prescribed limits and procedural formalities to outgoing travellers from India except

- transit passengers, and
- passengers holding open-dated tickets (including return tickets) issued outside India.

This facility has been extended with effect from March 23, 1971 to all travellers of Indian nationality including those falling under the excepted categories (a) and (b) mentioned above. In other words, sale of foreign currency notes and coins would be permissible to a traveller who is an Indian national (i.e., a person holding an Indian passport, whether issued in India or abroad), irrespective of the currency in

which his ticket had been paid for and the place where the ticket had been issued.

Assistance to Refugees from East Bengal

350. As a measure of assistance to refugees from East Bengal, Authorised Dealers in foreign exchange have been permitted to open freely, without any exchange control formalities normally applicable to non-residents, current/savings/fixed deposit accounts in the names of persons who have come away from East Bengal and are temporarily resident in India. These accounts will be treated as resident accounts and operations thereon allowed freely.

Issue of Authorised Dealers' Licences

351. With a view to encouraging the smaller banks to participate in the foreign exchange business of the country, licences to deal in foreign exchange have recently been issued to the following banks: Benares State Bank Ltd., Varanasi, The New Bank of India Ltd., New Delhi, and Vijaya Bank Ltd., Bangalore.

352. The following table gives data relating to release of foreign exchange and number of 'P' Form applications approved for travel abroad for various purposes during the year ended June 1971.

Foreign Exchange permits and 'P' Form Approvals

I. Foreign Exchange Permits

Purpose of Travel	No. of Permits	Amount of Exchange Sanctioned (Rs. 000s)
Study/Training :		
(a) U.K. and Europe		
(i) Technical ..	501	35.18
(ii) Non-technical ..	625	28.45
(b) U.S.A. and Canada		
(i) Technical ..	2,366	5,78.38
(ii) Non-technical ..	1,182	2,58.44
(c) Other Countries		
(i) Technical ..	194	17.99
(ii) Non-technical ..	120	6.63
Business ..	10,892	6,58.72
Medical treatment ..	499	52.03
Study tour ..	850	33.43
Attending conferences ..	1,129	20.37
Miscellaneous ..	8,360	2,14.65
Total ..	26,718	19,04.27

II. 'P' Form

Purpose of Travel	No. of 'P' Forms Approved
Joining Head of Family	11,838
Visit to Relatives	8,797
Export Promotion	196
Employment Abroad	4,352
Emigration for Permanent Settlement	7,916
Students/Trainees	3,256
Miscellaneous	19,741
Total	56,096

VI. SURVEYS AND SEMINARS ORGANISED BY THE RESERVE BANK

353. At the instance of the Government of India, the Bank sponsored an All-India Survey to assess the extent, nature and structural characteristics of indebtedness of non-manual employee households in urban areas. The National Sample Survey Organisation carried out the field work of canvassing an appropriate schedule in about 9,000 urban blocks in their 25th Round during 1970-71.

354. The Bank is finalising the arrangements for conducting the decennial "All-India Debt, and Investment Survey, 1971-72" in collaboration with the National Sample Survey Organisation of the Government of India and the State Governments.

355. The Department of Statistics prepared a study based on the analysis of the accounts of 1,501 non-Government, non-financial medium and large public limited companies for 1967-68 in collaboration with the Economic Department and published it in the October 1970 issue of the Bank's Bulletin. The Survey of Industrial Situation relating to the period January-June 1970 was published in the January 1971 issue of the Bank's Bulletin.

356. A Special Study on the Branch Expansion Activities of commercial banks and the performance of new branches for the period July 1969 to September 1970 was conducted in the Credit Planning Cell of the Bank. The study showed that a pronounced thrust towards both special and functional spread of commercial banking has followed the nationalisation of 14 major commercial banks in July 1969. Findings of the study were published as a supplement to the November 1970 issue of the Bank's Bulletin. A Special booklet containing (i) Special Credit Schemes of Banks: Guidelines, (ii) Report of the Committee on Banks' Credit Schemes with reference to employment potential, (iii) Guarantee Schemes for Small loans to priority and neglected sectors, (iv) Guarantee Schemes for loans to Small-scale Industries and (v) Financing of Agriculture by Commercial Banks: Guidelines, was brought out by the Bank. This booklet was also published as a supplement to the February 1971 issue of the Bank's Bulletin. The Report of the Committee on Differential Interest Rates has also been published in a book form.

357. The last year's Report referred to the decision of placing on a continuing basis a survey, undertaken by the Division of International Finance, Economic Department, of unclassified receipts (*i.e.*, receipts in amounts below Rs. 10000 or its equivalent for which no purpose-wise details are required to be reported to the Exchange Control Department by authorised dealers). The results of the survey of unclassified receipts during the quarter October—December, 1969 were published in the March 1971 issue of the Bank's Bulletin. For the year 1970, the survey conducted covered the quarter July—September, the results of which are currently being processed. The survey for 1971, which covers the quarter April—June, is in progress. The survey of freight and passage fare payments and receipts relating to Indian and foreign shipping and airline companies continued to be undertaken by the Division of International Finance on an annual basis. The Division also continued to call for quarterly reports from branches of foreign companies and Indian joint-stock companies for the foreign investment survey. Based primarily on these reports, an article on "India's International Investment Position in 1967-68" was published in the March 1971 issue of the Bank's Bulletin. Besides presenting India's international investment position at the end of 1967-68, the article estimated broadly, on the basis of partial data, the position at the end of 1968-69. In addition, this study presented adjusted data on the country's overall balance of payments, taking into account the additional information derived from the foreign investment survey reports.

358. At the instance of the Agricultural Credit Department, the Division of Rural Surveys of the Economic Department undertook the Field Study of Savings Potential of Farmers in five selected districts in five States. The object of the study was to attempt an estimation of the savings potential of farmers resident in rural areas of the selected districts and to find out how and to what extent such deposit potential was being tapped by institutional agencies. The Division also conducted, jointly with the Agricultural Credit Department, another field study for the 'Assessment of Repaying Capacity and Valuation of Hypothec for Land Development Bank

Loans' in five districts in five States. The object of the survey was to evolve a suitable methodology for enabling Land Development Banks to conduct field studies with the purpose of shifting their lending policies from security basis to production basis. Further, the methods of valuation of hypothec followed by the Land Development Banks were also sought to be studied, as the current methods of valuation were neither satisfactory nor scientific and needed to be replaced by the method of capitalising income as suggested by the All-India Rural Credit Review Committee. Further, the Division finalised the Report on the field study into availability of Co-operative Credit to Small Farmers. This study was undertaken in eight selected districts from eight States with a view to (a) assessing the availability of credit from co-operatives to small farmers for their agricultural needs, (b) appraising the main factors that influence the availability of such credit, and (c) examining whether vested interests were operating within the co-operatives and, if so, whether they affected the availability of credit to small farmers.

359. Besides these *ad hoc* surveys, the Division was engaged in two relatively long-term surveys. The object of one survey was to study the extent to which co-operative credit was contributing towards agricultural production and helping borrowers to increase their productive capacity, and that of another was to study the credit and other related problems of small farmers in the context of different agro-economic environments in the country. The regular mailed questionnaire Survey of Co-operative Bank Advances and Deposits continued to be attended to. The Division also brought out a publication entitled 'Studies in Agricultural Credit.'

360. The results of Survey of Finances of Local Authorities, 1965-66 and 1966-67, carried out by the Division of Fiscal Analysis, Economic Department, were published in the September 1970 issue of the Bank's Bulletin; the data received for the Survey of Finances of Local Authorities for 1967-68 and 1968-69 are being processed. The Annual Survey of Ownership of Central and State Government Securities as on March 31, 1969 was published in the May 1971 issue of the Bank's Bulletin and the data received for the Survey as on March 31, 1970 are being processed.

VII. EDUCATION AND TRAINING

361. Prominent activities of the National Institute of Bank Management covering training, research and consultancy services to help the individual banks in improving their operational efficiency and performance during the year are indicated below:

362. During the year 1970, the NIBM conducted the following courses:

Courses

(1) Five one-week prototype field-workshops-*cum*-training programmes on Agricultural Finance for nearly 1,500 officers from banks, (2) Small-scale Industry Finance for training the Trainers in financing small-scale industry, (3) Instructors' Training Programmes primarily for one bank at a time; training was imparted to participants from Bank of Baroda and Central Bank of India in 1970, (4) Training Programmes for Staff Training Colleges for Branch Managers, (5) Executive Development Programme consisting (a) Senior Executive Course meant for persons at the Regional Manager's level and (b) Advance Management Seminar meant for Deputy General Manager's/Assistant General Manager's level, (6) Functional Management Programmes—a two-week Manpower Development Programme for 28 participants, two from each bank, (7) Sectoral Management Programme on Export Finance for participants of Commercial banks, IDBI, ECGC, ICICI and Ministry of External Affairs, (8) Training Management Programmes to train the Instructors of the staff training colleges of Eastern region banks held at Calcutta for instructors from United Bank, United Commercial Bank and Allahabad Bank and (9) Overseas Training Programme conducted at the request of Bank of Bumiputra, Malaysia by one of the NIBM faculty members in Malaysia on Agricultural Finance.

Research

363. With a view to developing a better understanding of problems as well as to resolve practical problems, the Institute initiated research projects on various aspects of banking

such as: environmental and management studies, credit and portfolio management, deposit mobilisation, credit research analysis, export potential development, integrated information and control system, management control system, manpower forecasting, industrial relations and communications, recruitment, etc.

Workshops

364. A Workshop on 'Recruitment and Selection' meant for Personnel Department Executives of Commercial Banks was held towards the end of December 1970. A Steering Group has been constituted for a high level workshop on 'Business Planning' to be held in mid-1971.

Teaching Material

365. In order to develop a more suitable training technology, the NIBM with the help of a few Staff Training College Instructors from the banks is preparing Programmed Learnings Texts on: (i) Remittances, (ii) Safe Deposit Vault, and is working on, (iii) Scrutiny of Cheques, (iv) Deposit Accounts and (v) Collection. The Institute has planned to launch a major programme of preparing a large number of such self-instructional material to cover most repetitive banking operations. Further, number of teaching cases were prepared by the Indian Institute of Management, Ahmedabad, for the use of the Senior Management Courses, which were organised during the year. The NIBM itself has collected a number of cases to add to this library. In addition, a number of business games and simulation exercises also have been prepared.

366. NIBM published reports on the 'workshops' organised by it on the following subjects:

Publication and Information Dissemination

(i) Financing Small-scale Industries, (ii) Financing Agriculture, (iii) Deposit Mobilisation (iv) Customer Service, (v) Management Development in Banking Industry and (vi) Financing Exports. Two more publications of NIBM were: (i) Review Committee on the Training Programmes of Commercial Banks and (ii) *Directory of Courses 1970-71*, containing details of training courses conducted by the various Staff Training Colleges of Commercial Banks and other Research and Management Institutions.

Consultancy

367. The Institute has provided consultancy services to the Bank of India, the Indian Bank, the Andhra Bank and the Indian Overseas Bank for the selection of direct recruitment using the battery of tests which have been developed. Again the Institute is working with the Andhra Bank and the Indian Bank on a Business Development Consultancy. The aims of the consultancy are (i) Business Development Plan over a period of three to five years, (ii) Organisational structure of the bank to suit its changing character, and (iii) Manpower planning and management development, including training, to meet the future needs. The Institute has agreed to help the Union Bank and the Central Bank of India in the formulation and implementation of the management development programme. Progress has been made in (i) devising personnel inventory, (ii) job description leading to an appraisal system, and (iii) manpower planning. Both banks have agreed to make this information available to other banks.

General

368. On the basis of the work done in 1969 and in 1970, the NIBM has proposed for the year 1971, a major programme of work in the following: (i) the training of higher banking personnel, (ii) development of new training and teaching material, especially the self-instructional texts, (iii) a large number of important research projects, and (iv) expanded consultancy services particularly in areas of recruitment and selection testing, credit risk analysis and business development.

Bankers Training College

369. The Bank continued to sponsor and organise the training courses for the supervisory staff of commercial

banks. During the period under review, the College conducted 4 Senior Courses, 3 Intermediate Courses, 2 courses each on Industrial Finance and Organisation and Methods and one course each on Foreign Exchange, and Personnel and Organisation. One course for supervisory inspection staff of commercial banks was also conducted. Two new courses introduced at the College during the period under review were: a course for legal officers of term-lending institutions and banks attending to term loan proposals, and a Credit Appraisal Course for the Officers of commercial banks in middle management level attending to appraisal of credit proposals for relatively large amounts. The total number of officials from banks and financial institutions who received training in the College during the period is 477 (including 3 officials from foreign countries). Since the inception of the College in 1954, 4,447 officials have received training in the different courses conducted by the College. The College proposes to institute soon a course on Project Appraisal (Financial) and a course on Market Analysis and Demand Projections for the officers of term-lending institutions as also for such officers of commercial banks who handle term loans. Recently, the College has also been assigned the task of conducting courses exclusively for the Bank's own officers. An inspection-oriented foreign exchange course for the officers of the DBO&D, and the first Central Banking Course I for the Staff Officers Grade I, were conducted during the period under review. The second Central Banking Course I is at present in session at the College.

Co-operative Bankers Training College, Poona

370. The Bank also continued to arrange courses on co-operative banking for the personnel of State, Central and urban co-operative banks and land development banks. During the period under review, two courses each for the managerial staff of State/central co-operative banks, urban co-operative banks and land development banks as also for branch agents of State/Central co-operative banks were held at the College. On agricultural finance, one course each for the senior personnel and for the middle level personnel of commercial banks was conducted during the period. A special course on agricultural finance was organised for the Bank's officers of the DBO&D with a view to equipping them with the knowledge of latest development in the sphere of agricultural credit, particularly in the context of the lending portfolio of commercial banks.

371. The new courses introduced at the College during the period under review were : (a) a course for the managerial staff of State/primary land development banks, (b) a course for the managers/deputy managers of central banks financing industrial co-operatives, (c) a refresher course for the managerial staff of State/central co-operative banks, and (d) a refresher course for the managerial staff of urban co-operative banks. While the course for managerial staff of State/primary and development banks was arranged four times, the other courses were conducted once each during the period under review.

372. The total number of officials from the co-operative, the land development and the commercial banks who received training in the College during the period is 509 (including two officials from foreign countries). Since the inception of

the College in 1969, 720 officials have received training in the different courses conducted by the College. The College also conducted a seminar for the staff teaching agricultural finance in colleges run by commercial banks. The Principal of the College has recently taken over the additional charge of the Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management with which the Bank entered into a collaboration agreement last year.

Staff Training College, Madras

373. The Staff Training College, Madras continued to conduct the General Course on central banking for Staff Officers Grade II and Assistants, and the Inspection-oriented Course for officers of the DBO&D and the ACD, on a regular basis. The total number of employees who have so far received training in the College is 2,947.

Zonal Training Centre

374. The Zonal Training Centres at Bombay, Madras and New Delhi continued to conduct courses for the junior and senior clerks of the Bank. The Zonal Training Centre, Calcutta could not be reopened as expected due to certain administrative exigencies. The total number of clerical staff who have received training so far in the various Zonal Training Centres is 6,210.

Deputation of Staff

375. Under the standing arrangements with the Administrative Staff College of India, Hyderabad, the Bank's officers were deputed to attend management development courses conducted by the College. Officers were also sent to participate in some of the courses conducted by the Bankers Training College for the officers of commercial banks and financial institutions as also to short-term courses on management development organised by the All-India Management and State level Association, Productivity Councils, Management Institutes and a few other similar institutes. During the period under review, the Bank also deputed its officers to participate in the 8th SEANZA Central Banking Course held in Manila, the Central Banking Course conducted by the Bank of England, and other courses of interest to the Bank organised by some foreign institutes. Officers were also deputed for study visits/training to banking and financial institutions in the U.K., Japan, West Germany, Australia, Indonesia, etc.

Promotion of Hindi in R.B.I.

376. During the year under review, the Bank brought out the Hindi version of the Annual Report on the Working of the Reserve Bank of India and Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1970 with annexures of selected statements in Hindi from the Report on Currency and Finance, 1969-70 and the Hindi version of important circulars issued by the Bank to scheduled commercial banks. The Bank continued to offer assistance to the Industrial Development Bank of India, Agricultural Refinance Corporation, Unit Trust of India and Deposit Insurance Corporation for Hindi translation and publication of their Annual Reports. The revised edition of the Functions and Working of the Reserve Bank of India and the non-statutory portion of the revised Exchange Control Manual (sixth edition) were translated into Hindi and the latter was furnished to Government. The Bank also brought out a Hindi version of the forms, to be supplied to the Registrars of Co-operative Societies in Hindi-speaking States, for collection of statistics relating to the Co-operative Movement in India.

377. In compliance with the provisions of the Official Languages Act, 1963, as amended in 1967, the Bank continu-

ed to issue Press Communiques/Notes/Releases/Summaries, Notices, Advertisements and Notifications simultaneously in English and Hindi. Letters and communications received in Hindi from the public, the Central Government and the State Governments were entertained and replied to in Hindi wherever necessary.

378. The Hindi classes continued to be conducted by the Bank under its own teaching scheme at various centres on voluntary basis for the benefit of the Bank's staff. The incentives provided for acquiring proficiency in Hindi were continued during the year under review. With a view to encouraging the typists of the Bank to learn Hindi typewriting, the incentive of honorarium has been offered for passing the Hindi Typewriting Examination.

VIII. ACCOUNTS AND OTHER MATTERS

379. During the accounting year ended June 30, 1971, the Bank's income after making statutory and other provisions amounted to Rs. 136.46 crores as against Rs. 105.45 crores in the previous year. The total expenditure for the year amounted to Rs. 36.46 crores as against Rs. 30.45 crores in the previous year. The net profit set aside for payment to Central Government was Rs. 100 crores as against Rs. 75 crores paid last year.

380. The contributions to the National Agricultural Credit (long-term Operations) Fund, the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund and the National Industrial Credit (Long-term Operations) Fund were Rs. 18 crores, Rs. 2 crores and Rs. 40 crores, respectively, as against Rs. 17 crores, Rs. 2 crores and Rs. 20 crores, respectively, during 1969-70.

381. The rise of Rs. 31.01 crores in the income during 1970-71 was mainly due to increased interest earned on investments in securities, loans and advances to State Governments, banks, etc., as also larger discount on Rupee Treasury Bills. The increase of Rs. 6.01 crores in the expenditure was mainly on account of establishment charges owing to the payment of (i) arrears of salary consequent on revision of pay scales of Staff in Classes II, III and IV and (ii) interim relief and *ad hoc* refixation of salaries of Officer Staff.

Auditors

382. The accounts of the Bank have been audited by M/s. A. F. Ferguson & Co., Bombay. M/s. Ray and Ray, Calcutta, M/s. Suri & Co., Madras and M/s. Thakur Vaidyanath Aiyar & Co., New Delhi who were appointed by the Government of India as auditors of Reserve Bank of India by the notification No. F. 3(50)-BC/69, dated the 28th April 1971 issued in exercise of the powers conferred by Section 50 of the Reserve Bank of India Act. With a view to ensuring a wider coverage of offices of the Bank by the Bank's statutory auditors, the books of the Kanpur, Nagpur and New Delhi offices have been audited by the auditors in addition to the traditional offices at Bombay, Calcutta and Madras. The remuneration of the auditors has been fixed at Rs. 15,000/- per office.

The Central Board

383. Sarvashri V. V. Chari and S. S. Shiralkar assumed charge as Deputy Governors with effect from the forenoon of 17th November 1970 and 18th December 1970, respectively, for a period of 5 years. Shri C. P. N. Singh and Prof. M. Mujeeb retired as Directors of the Central Board on expiry of their terms of appointment on 14th January 1971. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by the retired Directors.

334. Seven meetings of the Central Board were held during the year, four of which were held in Bombay, one each in Madras, Calcutta and New Delhi. The Committee of the Central Board held fifty-two meetings of which ten were held in New Delhi, two in Madras and the rest in Bombay.

385. Shri K. N. Mehta was appointed as Executive Director with effect from the close of business on 21st January 1971.

Local Boards

386. There was no change either in the composition or in the membership of the Local Boards during the year under review.

Opening and closing of Offices and Changes in Organisation and Management

387. An Office of the Exchange Control Department was set up at Cochin with effect from November 2, 1970. A full-fledged Public Debt Office was set up at Ahmedabad from May 1, 1971. Four offices of the Department of Banking Operations and Development were opened at Gauhati, Patna, Jammu and Jaipur on February 15, March 1, May 15 and June 15, 1971, respectively. The regional office of the Agricultural Credit Department located at Kanpur was shifted to Lucknow in May 1971. Another regional office of the Agricultural Credit Department at Chandigarh was upgraded with the jurisdiction of this office covering Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir.

Bank's Premises

Office Premises

388. The annexe building at Nagpur has been completed, while the construction of the main office building at Bangalore is in progress. The proposed office buildings at Hyderabad and in the compound of the Mint at Bombay as also the proposed office buildings and annexes at Bhubaneswar and New Delhi are in planning stage. In Jaipur progress of planning has been held up due to a dispute regarding the ownership of the land sold to the Bank by the Improvement Trust. Proposals for appointment of Architects for office buildings at Ahmedabad and Gauhati are under consideration.

389. A reference was made in the last year's Report about the proposals to take on lease buildings at Ahmedabad and Bhubaneswar for opening sub-offices of Issue Department and Sections of the Banking Department. The building at Ahmedabad has since been taken, while the one at Bhubaneswar is expected to be ready for occupation in the near future. In addition, accommodation has also been taken on lease for opening regional offices of the Department of Banking Operations and Development of Banking at Gauhati, Jaipur and Jammu.

Residential Quarters.—

390. The Bank is continuing its efforts to provide residential quarters, which are heavily subsidised, for the various categories of staff at all important centres. During the year under review, the construction of 11 flats for Staff Officers Grade I at Madras and a colony of 240 flats for clerical staff and 192 flats for subordinate staff at Bombay was completed. This will bring the total number of flats so far provided to 160 for Staff Officers Grade I, 366 for Staff Officers Grade II, 1,616 for clerical staff and 744 for subordinate staff at Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Nagpur, Patna and Kanpur, covering approximately 15 per cent of the total staff at these centres. Construction of 272 flats at New Delhi and 456 flats at Calcutta for clerical and subordinate staff is in progress, while construction work in respect of 56 flats at Bangalore for Staff Officers Grade I and II and 224 flats at Kanpur and 104 flats at Nagpur and 16 flats at Madras for clerical and subordinate staff has since commenced. Construction of 152 flats at Bombay for Staff Officers Grade I and II and 48 additional flats for clerical staff at New Delhi will commence shortly. Further construction of colonies for Staff Officers Grade I and II at New Delhi and Classes III and IV staff at Bhubaneswar, Madras, Bangalore

and Hyderabad is in the planning stage. Proposals for appointment of Architects for the proposed quarters for Staff Officers Grade I and II at Kanpur are under consideration.

391. Efforts are being made to secure suitable land for construction of quarters at Centres where no plot has been secured or where the number of quarters provided is inadequate.

392. The scheme of taking flats on Company Lease for staff officers continues, as there is no improvement in the housing situation in the cities where offices of the Bank are located. During the year under review, 227 flats were taken on lease, bringing the total number of flats taken since the introduction of the scheme in 1967 to 716.

Miscellaneous.—

393. The renovation of the old office building at Calcutta is nearing completion, while the renovation work of the old office building at Kanpur will commence shortly. The construction of community centres in the Sarojini Nagar and Kasturba Nagar colonies at New Delhi is in the planning stage.

Employer-Employee Relations

394. A reference was made in the previous year's Report to the negotiations with effect from June 1, 1970 between the management of the Reserve Bank of India and the All-India Reserve Bank Employees' Association representing the workmen employees in Classes II and III regarding revision of pay scales and allowances, etc. Since then settlements were reached between the management of the Bank, on the one hand, and the All India Reserve Bank Employees' Association and the All-India Reserve Bank Workers' Federation, on the other, in regard to revision of pay, allowances and certain other service conditions of workmen employees in Classes II, III and IV. The Agreements with the Association and Federation are binding on the parties till December 31, 1973. As the Agreements have not settled all the items included in the Charter of Demands of the two organisations, further meetings are being held with them for resolving the pending items also. Negotiations were held between unions of workmen employees of the commercial banks and the Indian Banks' Association on revision of pay structure for bank employees and a settlement was reached between them on October 12, 1970. The settlement would be in operation for 4 years from January 1, 1970.

Employees Housing Loan Scheme

395. During the year under review, Housing Loans were sanctioned as under:

	No. of Societies	Amount Rs.
A. New Co-operative Housing Societies	16	72,84,220
Additional loans to Co-operative Housing Societies already formed	7	3,29,585
Total		76,13,805
	No. of Employees	Amount Rs.
B. Individual members of staff		
New loans	145	27,44,798
Additional loans to employees who had already availed of loans earlier	2	2,850
Total		27,47,648

The total amount of 'Society' and 'Individual' loans sanctioned since the introduction of the scheme in 1971 amounts to Rs. 2,83,94,160 and Rs. 78,45,103, respectively. In all 1,716 employees have availed themselves of this facility.

Reserve Bank of India
BALANCE SHEET AS AT JUNE 30, 1971
ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES				ASSETS					
	Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.	P.	Rs.	P.
Notes held in the Banking Department	18,00,36,776.00				Gold Coin and Bullion:—				
					(a) Held in India	182,53,10,862.72			
Notes in circulation	4435,03,88,195.50				(b) Held outside India				
					Foreign Securities	278,41,99,950.06			
					Total			460,95,10,812.78	
Total Notes issued			4453,04,24,971.50		Rupree Coin			39,15,33,741.55	
					Government of India				
					Rupree Securities			3952,93,80,417.17	
					Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper	
Total Liabilities			4453,04,24,971.50		Total Assets			4453,04,24,971.50	

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES			ASSETS		
	Rs.	P.		Rs.	P.
Capital Paid-up	5,00,00,000.00		Notes	18,00,36,776.00	
Reserve Fund	150,00,00,000.00		Rupree Coin	92,062.00	
National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund	190,00,00,000.00		Small Coin	3,14,775.60	
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	39,00,00,000.00		Bills Purchased and Discounted—		
National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund	135,00,00,000.00		(a) Internal	10,02,29,513.79	
Deposits:—			(b) External		
(a) Government			(c) Government Treasury Bills	15,79,86,288.22	
(i) Central Government	54,98,95,012.38		Balances held Abroad*	94,12,01,406.55	
(ii) State Governments	86,63,13,936.17		Investments**	423,54,81,728.38	
(b) Banks			Loan and Advances to:—		
(i) Scheduled Commercial Banks	248,69,06,124.78		(i) Central Government		
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	18,83,72,356.57		(ii) State Governments†	55,77,00,000.00	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	83,62,402.90		Loans and Advances to:—		
(iv) Other Banks	1,02,07,228.20		(i) Scheduled Commercial Banks†	265,84,70,000.00	
(c) Others	162,56,14,761.21		(ii) State Co-operative Banks††	206,83,71,602.00	
Bills Payable	37,24,27,949.41		(iii) Others	13,78,60,000.00	
Other Liabilities	194,31,73,420.38		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long-Term Operations) and Fund		
			(a) Loans and Advances to:—		
			(i) State Governments		
			(ii) State Co-operative Banks	42,03,55,639.52	
			(iii) Central Land Mortgage Banks	24,31,43,271.66	
			(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	
			Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	10,14,98,135.00	
			Loans and Advances to State Co-operative Banks	13,66,14,587.00	
			Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund		
			(a) Loans and Advances to the Development Bank	55,04,21,044.00	
			(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
			Other Assets	75,14,96,362.28	
Total Liabilities	1324,12,73,192.00		Total Assets	1324,12,73,192.00	

Contingent liability on partly paid shares Rs. 8,99,992.80 (Sterling Investments of £ 50,000 converted @ Rs. 100 = £ 5.5556).

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** (i) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund.

(ii) Includes Rs. 5,31,09,367.80 (equivalent of £ 50,000 and \$U.S. 6,961,250) held abroad.

†Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund.

††Includes Rs. 171,91,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

†††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

J.S. NARULA,
 Chief Accountant,
 Dated the 28th July 1971,

S. JAGANNATHAN, Governor.
 P. N. DAMRY, Deputy Governor
 R. K. HAZARI, Deputy Governor
 V. V. CHARI, Deputy Governor
 S. S. SHIRALKAR, Deputy Governor

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1971

INCOME								Rs.	P.
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc. †								136,46,38,146.95	
EXPENDITURE									
Establishment								20,58,91,346.23	
Directors' and Local Board Members' Fees and Expenses								57,802.80	
Auditors' Fees								90,000.00	
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.								93,93,714.68	
Law Charges								39,151.82	
Postage and Telegraph Charges								11,32,016.41	
Remittance of Treasure								60,14,579.19	
Stationery, etc.								30,40,811.73	
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)								4,90,81,764.01	
Depreciation and Repairs to Bank Property								95,05,283.57	
Agency Charges								7,21,10,258.74	
Contributions to Staff and Superannuation Funds								7,32,000.00	
Miscellaneous Expenses								75,48,975.46	
Not available balance								100,00,00,442.31	
Total								136,46,38,146.95	
Surplus Payable to the Central Government								100,00,00,442.31	

RESERVE FUND ACCOUNT

By Balance on 30th June 1971								150,00,00,000.00	
By transfer from Profit and Loss Account								Nil	
Total								150,00,00,000.00	

†After making usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act.

J. S. NARULA,
Chief Accountant.

S. JAGANNATHAN, Governor.
P. N. DAMRY, Deputy Governor.
R. K. HAZARI, Deputy Governor.
V. V. CHARI, Deputy Governor.
S. S. SHIRALKAR, Deputy Governor.

REPORT OF THE AUDITORS

TO THE PRESIDENT OF INDIA,

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet and Accounts of the Bank as at 30th June, 1971.

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of the Central Office and of the Offices at Calcutta, Bombay, Madras, New Delhi, Kanpur, and Nagpur and with the Returns submitted and certified by the Managers of the other Offices and Branches, which Returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanations and information from the Central Board, such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in which the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder and is properly drawn up so as to exhibit a true and a correct view of the state of the Bank's affairs according to the best of our information and the explanations given to us, and as shown by the Books of the Bank.

RAY & RAY,
A. F. FERGUSON & CO.
THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO. } Auditors
SURI & CO.

Dated the 28th July, 1971.

[No. 3(9)-B. O. III/72]
R. RAJAMANI, Dy. Secy.

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 अगस्त 1972

(आयकर)

का.आ. 509:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अपनी अधिसूचना सं. 1 (फा. सं. 55/233/63-आई.टी.), तारीख, 18-5-1964 से उपायय समय-समय पर यथा संशोधित अनुसूची में एतद्वारा निम्नलिखित जोड़ता है।

उक्त अनुसूची में विद्यमान प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी:

1	2	3
67	विल्ली और बम्बई में स्थित आयकर अधिकारी ख-बोर्ड ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कार-जिला III (क) कलकत्ता पोरेशन के प्रवासी अधिकारी।	
4	5	6
आयकर सहायक आयुक्त (निरीक्षण) जिसे स्तंभ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी की बाबत आयकर सहायक आयुक्त (निरीक्षण) के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है।	आयकर सहायक आयुक्त (अपील) जिसमें स्तंभ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील चुनने की शक्तियां निहित की गई हैं।	आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल-1 कलकत्ता

यह अधिसूचना 17 अगस्त, 1972 से प्रभावी होगी।

[सं. 5/फा. सं. 187/12/71-आई.टी. (ए. आई.टी.)]

बी. माधवन, अवसर सचिव

(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 7th August, 1972

(INCOME-TAX)

S.O. 509.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax, 1961, (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following addition to the Schedule annexed to its Notification No. 1 (F.N. 55/233/63-IT) dated 18-5-1964 as amended from time to time.

In the said Schedule the following item shall be added below the existing entries:

1	2	3
67	Expatriate Officers of the British Overseas Airways Corporation stationed in Delhi and Bombay.	Income-tax Officer, B-Ward, District III-A, Calcutta.
4	5	6
I.A.C. of Income-tax, who has been appointed to perform the functions of I.A.C. of Income-tax in respect of Income-tax Officer referred to in column 3.	A.A.C. of Income-tax who has been invested with powers to hear appeals against the decisions of the Income-tax Officer referred to in column 3.	Commissioner of Income-tax, West Bengal I, Calcutta.

This notification will take effect from 17th August, 1972.

[No. 5 /F.No. 187/12/71-IT(AI)]

B. MADHAVAN, Under Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1973

स्टैपल तन्तु नियंत्रण आदेश, 1972, तारीख 6 दिसम्बर, 1972 का संशोधन

का. आ. 510.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, उक्त नियंत्रण आदेश में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

“नियंत्रण आदेश में जहां कहीं ‘स्टैपल तन्तु’ आया है उससे स्थान पर ‘विस्कास स्टैपल तन्तु’ पढ़ें।”

[सं. फा. 17013/1/72वस्त्र (एफ.)]

कै. किशोर, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 3rd February, 1973

Staple Fibre Control Order 1972 dated 6th December, 1972 Amendment thereof.

S.O. 510.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment to the said Control Order:—

“Viscose staple fibre may be read for staple fibre wherever it appears in the Control Order”.

[No. F. 17013/1/72/Tex(F)]

K. KISHORE, Jt. Secy.

(उप-मुख्य नियंत्रक, लोह और इस्पात आयात-निर्यात का कार्यालय)

फरीदाबाद, 6 दिसम्बर, 1972

आवृत्ति

का. आ. 511.—सर्वश्री इंडिया टिन बाक्स मैन को. सीक-50/82 राजा दरवाजा, वाराणसी को आयात लाइसेंस सं. पी/एस/8565830/सी/एक्स एक्स/42/डी/33.34 और पी/एस/8565831/आर/एम एल/डी/33.34/एम एल। दोनों का दिनांक 30-3-1972 क्रमशः 5000 रु. और 582 रु. के लिए सामान्य मुद्रा और यू. के. क्रेडिट के अधीन कलकत्ता परतन पर पंजीकरण की शर्त के साथ जारी किए गए थे। उन्होंने कथित लाइसेंसों की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों और सीमाशुल्क निकासी प्रतियों की अनुलिपियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां खो गईं/अस्थानस्थ हो गईं हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल लाइसेंस किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत नहीं कराए गए थे और उनका उपयोग शिक्कल नहीं किया था।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने दो शपथ पत्र दाखिल किए हैं। मैं संतुष्ट हूँ कि पूर्वाक्त लाइसेंसों की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां और सीमाशुल्क निकासी प्रतियां खो गईं/अस्थानस्थ हो गईं हैं और निवेदन देता हूँ कि विषयाधीन लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां और सीमाशुल्क निकासी प्रतियां को रद्द करके इनकी अनुलिपियां आवेदक को जारी की जानी चाहिए।

[सं. 162738]

कै. एन. कपूर, उप मुख्य नियंत्रक

(Dy. Chief Controller of Imports and Exports)
(Iron and Steel)Faridabad, 6th December, 1972
CANCELLATION ORDER

S.O. 511.—M/s India Tin Box Manufacturing Co., Ck-50/82 Raja Darwaja, Varanasi were granted import licence Nos. P[S]8565830[C]XA/42[D]33.34 and P[S]8565831[R]ML/42[D]33.34 MLI both dated 30-3-72 for Rs. 5,000 and Rs. 582 issued under G.C. and U.K. Credit respectively with part of registration as Calcutta. They have applied for duplicate Exchange Control and Custom Clearance Purpose copies of the said licences on the ground that the original E.C.P. and C.C.P. copies of the said licences have been lost/misplaced. It is further stated that the original licences were not registered with any custom authority and were not utilised at all.

In support of this contention the applicant has filed two affidavits. I am satisfied that the original E.C.P. and C.C.P. copies of the aforesaid licences have been lost/misplaced and direct that duplicate E.C.P. and C.C.P. copies should be issued to the applicant in cancellation of original E.C.P. and C.C.P. copies of the licences in question.

[No. 162738]

K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller.

(संयुक्त-मुख्य निबंधक आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर, 1972

आदेश

का. आ. 512.—सर्वश्री एयरो इंजी. वर्क्स, करीमपुरा रोड, लुधियाना को अप्रैल मार्च 1972 के लिए रेड बुक (वा. 2) की क्रम सं. ए. 151.2 के मद्दे कालम 4 में दिखाई गयी सूची के अनुसार मर्चें तथा दो विद्युत टाइपराइटर, दो विद्युत द्वारा परिचालित गणक मशीन, एक फोटो-कापी करने वाली मशीन तथा मद फोटो-कापी करने वाले कागज 1000 रुपये तक के आयात के लिए 38801 रु. का एक आयात लाइसेंस सं. पी/एल/2621262/सी/एक्स एक्स/40/डी/32-33 दिनांक 7-7-71 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस में शेष बचे 8770 रु. मूल्य के लिए अनुलिपि सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रती के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रती उपर्युक्त शेष बचे मूल्य का उपयोग किए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंस बम्बई सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत करवाया गया था।

अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रिया विधि हंडबुक 1972-73 की कंडिका 318(1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित एक शपथपत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रती खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है।

अद्यतन यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9(सी सी) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं लाइसेंस सं. पी/एल/2621262/सी/एक्स एक्स/40/डी/32-33 दिनांक 7-7-71 की मूल सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रती को रद्द करने का आदेश देता हूँ।

अब आवेदक को आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रिया-विधि, हंडबुक, 1972-73 की कंडिका 318(1) में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार लाइसेंस सं. पी/एल/2621262/सी/एक्स एक्स/40/डी/32-33 दिनांक 7-7-71 के शेष बचे मूल्य अर्थात् 8770 रु. के लिए तथा मर्चों की सूची के साथ अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रती जारी की जा रही है।

[सं. इंजी. 140/जे. एम 71/एस सी 1/सी एल ए]

ए. एल. भल्ला, उप मुख्य निबंधक,
कृत संयुक्त मुख्य निबंधक।(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)
(Central Licensing Area)

New Delhi, the 2nd October, 1972

SO. 512.—M/s. Aero Engineering Works, Karimpura Road, Ludhiana, were granted an import licence No. P[L]2621262[C]XX/40[D]32-33 dt. 7-7-71 for Rs. 38801 for Col. 4 items appeared against S. No. A. 152.2. to the Red Book for AM/72 (Volume-II) as per list and Two Electric Type-writer, Two Electric Operated calculators machine, One Photo copying Machine and item Photo-Copying Paper upto Rs. 1000. They have applied for issue of duplicate copy of the said licence for Customs purposes only for the unutilised balance of Rs. 8770 on the ground that the original Customs Purposes copy has been lost/misplaced without having been utilised the above balance amount. The licence was registered with Bombay Customs House.

The applicant have filed an affidavit in support of their above statement as required under para 318(1) of Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1972-73. I am satisfied that the original Customs Purposes copy of the said licence has been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under section 9(C) in the Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended upto date, I order the cancellation of the original Customs Purposes copy of licence No. P[L]2621262[C]XX/40[D]32-33 dt. 7-7-71.

The applicant is now being issued a duplicate Customs Purposes copy of licence No. P[L]2621262[C]XX/40[D]32-33 dt. 7-7-71 for the balance amount of Rs. 8770 of the licence alongwith its list of items in accordance with the provision of para 318(1) of Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1972-73.

[No. Engg. 140/JM/71/SC. I/CLA]

A. L. BHALLA, Dy Chief Controller
for Jt. Chief Controller

पेंट्रोलियम और स्लायन मंत्रालय

(पेंट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1973

का. आ. 513.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकोहित में यह आवश्यक है कि हील्व्या पोर्ट (जिला मिर्जापुर) और पश्चिम बंगाल राज्य में भारतीय तेल निगम (पाइपलाइन) के राजबन्ध वितरण केन्द्र (जिला बरदयान) के बीच पेंट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय तेल निगम (पाइपलाइन्स) द्वारा बिछायी जानी चाहिये और कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब, पेंट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप भारतीय तेल निगम लि. (पाइपलाइन्स) के कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी 14 ली रोड, कलकत्ता-20 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा। ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवायी व्यक्ति हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पुलिस स्टेशन हरियाल	जिला हुगली	(पश्चिमी बंगाल)		
मौजा नाम	प्लॉट संख्या	सीमा (क्षेत्र)	भूमि का	
		सड़कों में ए आर ई में विवरण		
कसिमपुर, जे. एल.	1296	0.04	1.62	उत्तर-पूर्व
संख्या 112				

[सं. 11/5/71-लेबर एण्ड लेजिस/4]

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS
(Department of Petroleum)

New Delhi, 7th February, 1973

S.O. 513.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Products between the Haldia Port (District Midnapore) and Rajbandh Delivery Point (District Burdwan) of India Oil Corporation Limited (Pipelines) in West Bengal State, pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited (Pipelines) and that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the said land may within 21 (twentyone) days from the date of this Notification object to the laying of pipelines under the land, to Competent Authority at 14, Lee Road, Calcutta-20, in the office of the Indian Oil Corporation Limited (Pipelines). Every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Name of Mouja	Plot No.	Extent (Area)		Description of land
		In acres	In ares	
Kasimerpur J.L. No. 112	1296	0.04	1.62	North-East

[No. 11/5/71-L&L/IV]

शुद्धिपत्र

का. आ. 514.—पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 (1) के अधीन दिनांक 25 मार्च, 1972 के भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड 3(2) के पृष्ठों 1181 से 1184 पर प्रकाशित दिनांक 7 जनवरी, 1972 की अधिसूचना संख्या का. आ. 807 में :—

- (1) 1183 पृष्ठ पर तीसरी लाइन में कालम 2 में "1292 मध्य" के स्थान पर "1298 मध्य" पढ़िये,
- (2) 1184 पृष्ठ पर 68 लाइन में कालम 2 और कालम 3 में क्रमशः "177 पूर्ण" और "02" के स्थान पर "171 पूर्ण" और "0.12" पढ़िये।

[सं. 11/5/71-लेबर एण्ड लेजिस/3]

ERRATUM

S.O. 514.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals, No. S.O. 897 dated, the 7th January, 1972, under section 3(i) of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), published at pages 1181 to 1184 of the Gazette of India, Part II, Sec. 3(ii), dated the 25th March, 1972.

(1) at page 1183 in column 2 in line 3, read "1298 middle" for "1292 middle";

(2) at page 1184 in column 2 and column 3 in line 68, read "171 Full" and "0.12" for "177 Full" and "0.02" respectively.

[No. 11/5/71-Lab. & Legis/III]

का० आ० 515—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 897 तिथि 7 जनवरी, 1972 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि हम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है और, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम में, सभी बन्धकों के मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

राज्य: पश्चिमी बंगाल जिला : हुगली पुलिस
स्टेशन/थाना हरियाल

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) तथा भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)	
		एकड़ों में	ए आर ई एस में
गाजा	135 मध्य	0.26	10.52
जे० एन० संख्या	137 पश्चिम	0.06	2.43
92	138 पूर्व	0.11	4.45
	139 पूर्ण	0.02	0.81
	140 पूर्ण	0.03	1.21
	141 पूर्व	0.01	0.40
	161 उत्तर पूर्व	0.005	0.20
	166 पूर्व	0.05	2.02
	167 पूर्व	0.07	2.83
	169 पूर्व	0.12	4.86
	170 मध्य	0.14	5.67
	171 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20

गाँव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) तथा भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)		गाँव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) तथा भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)	
		एकड़ों में	ए० आर० ई० एस० में			एकड़ों में	ए० आर० ई० एस० में
गाजा जे० एल० संख्या 92 (जारी)	176 पश्चिम	0.05	2.02	1200 उत्तर	0.07	2.83	
	177 पश्चिम	0.07	2.83	1201 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20	
	178 पश्चिम	0.10	4.05	1271 उत्तर-पूर्व	0.03	1.21	
	200 पश्चिम	0.05	2.02	1272 मध्य	0.07	2.83	
	205 दक्षिण-पश्चिम	0.02	0.81	1274 पश्चिम	0.08	3.24	
	207 पश्चिम	0.09	3.64	1275 दक्षिण	0.03	1.21	
	208 मध्य	0.20	8.09	1278 पूर्व	0.02	0.81	
	209 उत्तर-पूर्व	0.03	1.21	1279 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40	
	210 पश्चिम	0.07	2.83	1280 पूर्व	0.04	1.62	
	211 पूर्व	0.12	4.86	1281 पूर्व	0.09	3.64	
	220 पूर्व	0.19	7.69	1282 पूर्ण	0.09	3.64	
	304 उत्तर-पूर्व	0.16	5.67	1286 पश्चिम	0.04	1.62	
	316 दक्षिण-पश्चिम	0.02	0.81	1287 पश्चिम	0.08	3.24	
	317 पूर्व	0.09	3.64	1288 पूर्व	0.01	0.40	
	318 पूर्ण	0.06	1.62	1289 पूर्व	0.05	2.02	
	319 दक्षिण-पश्चिम	0.02	0.81	1290 मध्य	0.07	2.83	
	320 मध्य	0.20	8.09	1291 पश्चिम	0.04	1.62	
	332 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40	1292 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40	
	333 उत्तर	0.28	11.33	2168 दक्षिण	0.03	1.21	
	334 उत्तर-पूर्व	0.06	2.43	2197 पश्चिम	0.02	0.81	
	335 पश्चिम	0.16	6.48	2198 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20	
	355 पश्चिम	0.09	3.64	2199 पूर्ण	0.12	4.86	
	356 पश्चिम	0.39	15.79	2200 पश्चिम	0.05	2.02	
	358 उत्तर-पूर्व	0.05	2.02	2201 पूर्ण	0.06	2.43	
	359 पश्चिम	0.17	6.88	2202 पूर्व	0.05	2.02	
	1028 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40	2203 पूर्व	0.03	1.21	
	1029 पूर्व	0.02	0.81	2322 पूर्ण	0.03	1.21	
	1031 पूर्व	0.03	1.21	2323 पश्चिम	0.04	1.62	
	1032 मध्य	0.16	6.48	2326 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20	
	1034 पश्चिम	0.05	2.02	2327 दक्षिण-पश्चिम	0.04	1.62	
	1035 मध्य	0.19	7.69	2328 पूर्ण	0.06	2.43	
	1036 पश्चिम	0.005	0.20	2329 पश्चिम	0.17	6.88	
	1069 पश्चिम	0.05	2.02	2330 उत्तर-पूर्व	0.03	1.21	
	1077 मध्य	0.35	14.16	2344 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20	
	1078 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20	2345 पश्चिम	0.02	0.81	
	1080 पूर्व	0.06	2.43	2346 दक्षिण-पश्चिम	0.05	2.02	
दिलालपुर जे० एल० संख्या 111	1126 पश्चिम	0.02	0.81	2347 पूर्ण	0.01	0.40	
	1129 उत्तर-पूर्व	0.02	0.81	2348 उत्तर-पूर्व	0.02	0.81	
	1130 मध्य	0.09	3.64	2349 दक्षिण	0.06	2.43	
	1131 दक्षिण-पश्चिम	0.05	2.02	2354 उत्तर-पूर्व	0.12	4.86	
	1132 पश्चिम	0.10	4.05	2355 उत्तर	0.005	0.20	
	1178 दक्षिण-पश्चिम	0.17	6.88	2356 मध्य	0.05	2.02	
	1179 उत्तर-पूर्व	0.06	2.43	2364 दक्षिण	0.06	2.43	
	1182 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40	2365 दक्षिण	0.06	2.43	
	1183 मध्य	0.23	9.30	2369 दक्षिण-पश्चिम	0.04	1.62	
	1186 दक्षिण-पश्चिम	0.07	2.83	2810 पश्चिम	0.01	0.40	
	1198 दक्षिण-पश्चिम	0.04	1.62	2884 उत्तर-पूर्व	0.12	4.86	
	1199 मध्य	0.09	3.64	2908 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20	

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) तथा भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)		गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) तथा भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)	
		एकड़ों में	ए. आर. ई. एस. में			एकड़ों में	ए. आर. ई. एस. में
कसिमेरपुर	15 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20	कसिमेरपुर जे०	729 पूर्व	0.03	1.21
जे० एल० संख्या	16 मध्य	0.20	8.09	एल० संख्या 112	730 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40
112	17 मध्य	0.13	5.26	(जारी)	735 मध्य	0.36	14.57
	18 दक्षिण-पश्चिम	0.02	0.81		737 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20
	19 मध्य	0.13	5.26		738 पश्चिम	0.01	0.40
	21 पश्चिम	0.03	1.21		739 मध्य	0.16	6.48
	28 पश्चिम	0.22	8.90		742 उत्तर-पूर्व	0.07	2.83
	115 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40		761 पूर्व	0.17	6.88
	116 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40		762 मध्य	0.08	3.24
	117 मध्य	0.08	3.24		763 दक्षिण	0.02	0.81
	118 उत्तर-पूर्व	0.04	1.62		767 दक्षिण	0.04	1.62
	120 मध्य	0.14	5.67		768 मध्य	0.11	4.45
	121 मध्य	0.11	4.45		769 उत्तर-पूर्व	0.02	0.81
	122 पश्चिम	0.07	2.83		770 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20
	123 पश्चिम	0.06	2.43		771 मध्य	0.13	5.26
	125 पश्चिम	0.05	2.02		772 पश्चिम	0.06	2.43
	126 मध्य	0.09	3.64		773 उत्तर-पूर्व	0.05	2.02
	127 पूर्व	0.03	1.21		777 मध्य	0.03	1.21
	128 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40		1249 मध्य	0.09	3.64
	176 पूर्व	0.04	1.62		1250 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40
	179 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20		1298 मध्य	0.11	4.45
	190 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40		1302 पूर्व	0.04	1.62
	191 मध्य	0.12	4.86		1303 मध्य	0.10	4.05
	192 मध्य	0.38	15.38		1328 मध्य	0.03	1.21
	193 पश्चिम	0.08	3.24	बांदीपुर	2313 पूर्व	0.07	2.83
	199 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40	जे० एल० संख्या	2343 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40
	200 मध्य	0.09	3.64	113	2345 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40
	201 पूर्व	0.05	2.02		2346 मध्य	0.09	3.64
	205 पूर्व	0.005	0.20		2349 पश्चिम	0.06	2.43
	211 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20		2350 उत्तर-पूर्व	0.05	2.02
	212 पूर्व	0.05	2.02		2351 पश्चिम	0.03	1.21
	213 पश्चिम	0.26	10.52		2352 पश्चिम	0.05	2.02
	255 मध्य	0.19	7.69		2353 मध्य	0.06	2.43
	257 पश्चिम	0.10	4.05		2354 पूर्व	0.06	2.43
	258 पश्चिम	0.05	2.02		2355 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40
	260 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20		2362 उत्तर-पूर्व	0.03	1.21
	261 मध्य	0.05	2.02		2363 उत्तर	0.03	1.21
	262 मध्य	0.06	2.43		2364 उत्तर	0.04	1.62
	263 मध्य	0.04	1.62		2365 मध्य	0.06	2.43
	264 पश्चिम	0.08	3.24		3366 उत्तर-पूर्व	0.04	1.62
	265 पूर्ण	0.03	1.21		2367 दक्षिण-पश्चिम	0.12	4.86
	266 पूर्ण	0.01	0.40		2368 दक्षिण-पश्चिम	0.02	0.81
	267 पूर्ण	0.01	0.40		2389 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40
	268 मध्य	0.01	0.40		2390 पश्चिम	0.02	0.81
	269 पूर्व	0.01	0.40		2391 पश्चिम	0.15	6.07
	270 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20		2406 दक्षिण पश्चिम	0.09	3.64
	272 उत्तर-पूर्व	0.03	1.21		2407 उत्तर-पूर्व	0.13	5.26
	273 पूर्व	0.05	2.02		2408 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) तथा भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)		गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) तथा भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)	
		एकड़ों में ए आर ई एस में				एकड़ों में ए आर ई एस में	
बांदीपुर जे० एल० संख्या 113 (जारी)	2421 उत्तर-पूर्व	0.04	1.62	पूर्व गोपीनाथपुर जे० एल० संख्या 117 (जारी)	348 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20
	2422 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20		349 पूर्व	0.04	1.62
	2423 मध्य	0.44	17.81		350 पश्चिम	0.10	4.05
	2424 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20		352 मध्य	0.06	2.43
	2459 उत्तर-पूर्व	0.09	3.64		353 पश्चिम	0.04	1.62
	2465 उत्तर-पूर्व	0.07	2.83		356 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20
	2466 दक्षिण-पश्चिम	0.06	2.43		357 दक्षिण-पश्चिम	0.04	1.62
	2469 पश्चिम	0.11	4.45		358 उत्तर-पूर्व	0.05	2.02
	2470 उत्तर-पूर्व	0.09	3.64		366 पूर्व	0.06	2.43
	2471 दक्षिण-पश्चिम	0.03	1.21		368 उत्तर-पूर्व	0.04	1.62
	2477 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40		369 मध्य	0.03	1.21
	2416 मध्य	0.02	0.81		370 पूर्व	0.01	0.40
	2686 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20		371 पूर्व	0.05	2.02
	2690 मध्य	0.19	7.69		372 पश्चिम	0.11	4.45
	2691 दक्षिण-पश्चिम	0.05	2.02		373 पश्चिम	0.02	0.81
	2692 पूर्व	0.01	1.62		374 पश्चिम	0.03	1.21
	2693 उत्तर-पूर्व	0.05	2.02		382 दक्षिण-पश्चिम	0.02	0.81
	2695 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40		388 पश्चिम	0.14	5.67
	2696 मध्य	0.28	11.33		389 मध्य	0.16	6.48
	2697 दक्षिण-पश्चिम	0.04	1.62		390 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40
	2700 दक्षिण-पश्चिम	0.04	1.62		403 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40
	2701 मध्य	0.18	10.93		404 उत्तर-पूर्व	0.02	0.81
	2831 दक्षिण-पश्चिम	0.06	2.43		405 उत्तर-पूर्व	0.08	3.24
	2833 मध्य	0.08	3.24		406 पश्चिम	0.10	4.05
2834 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40	407 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40		
2835 मध्य	0.08	3.24	408 मध्य	0.10	4.05		
इस्लामपुर जे० एल० संख्या 114	1307 पश्चिम	0.17	6.83	409 उत्तर-पूर्व	0.03	1.21	
	1330 पश्चिम	0.34	13.76	411 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20	
	1343 मध्य	0.19	7.69	417 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40	
	1344 उत्तर	0.03	1.21	418 उत्तर	0.08	3.24	
	1498 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20	419 मध्य	0.10	4.05	
	1499 पश्चिम	0.03	1.21	420 दक्षिण	0.05	2.02	
पूर्व गोपीनाथपुर जे० एल० संख्या 117	16 उत्तर पूर्व	0.01	0.40	421 दक्षिण	0.02	0.81	
	17 मध्य	0.09	3.64	422 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20	
	21 दक्षिण-पश्चिम	0.10	4.05	425 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20	
	22 दक्षिण-पश्चिम	0.07	2.83	436 दक्षिण-पश्चिम	0.06	2.43	
	23 दक्षिण	0.07	2.83	437 उत्तर-पूर्व	0.80	3.24	
	24 पश्चिम	0.03	1.21	438 दक्षिण-पश्चिम	0.03	1.21	
	25 उत्तर	0.04	1.62	439 उत्तर-पूर्व	0.07	2.83	
	26 पश्चिम	0.13	4.25	441 पश्चिम	0.02	0.81	
	28 दक्षिण	0.03	1.21	442 पश्चिम	0.13	5.26	
	29 दक्षिण-पूर्व	0.11	4.45	444 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40	
	32 उत्तर	0.09	3.64	445 मध्य	0.24	11.33	
	33 उत्तर-पूर्व	0.03	1.21	449 उत्तर-पूर्व	0.18	7.29	
	35 उत्तर	0.09	3.64	450 दक्षिण-पश्चिम	0.14	5.67	
	342 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20	455 पश्चिम	0.01	0.40	
	345 मध्य	0.12	4.86	807 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20	
	346 मध्य	0.10		808 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20	
	347 मध्य	0.10	4.05	809 पश्चिम	0.06	2.43	

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या)	तथा भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)		गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या)	तथा भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)	
			एकड़ों में	ए० आर० ई० एस० में				एकड़ों में	ए० आर० ई० एस० में
पूर्व गोपीनाथपुर	810	मध्य	0.12	4.86	जादव बाटी जे०	524	उत्तर	0.08	3.24
जे० एल० संख्या	1203	दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20	एल० 119-जारी	525	उत्तर-पूर्व	0.03	1.21
117 (जारी)	1206	मध्य	0.21	8.49		526	उत्तर-पूर्व	0.07	2.83
	1207	मध्य	0.10	4.05		527	मध्य	0.08	3.24
	1208	पश्चिम	0.06	2.43		528	दक्षिण	0.05	2.02
	1211	दक्षिण-पश्चिम	0.07	2.83		529	दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40
	1212	पूर्व	0.05	2.02		531	दक्षिण	0.03	1.21
	1213	उत्तर-पूर्व	0.005	0.20		532	दक्षिण	0.02	0.81
	1214	पूर्व	0.04	1.62		533	दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20
	1241	पूर्व	0.16	6.48		534	मध्य	0.09	3.64
	1248	उत्तर-पूर्व	0.03	1.21		554	दक्षिण-पश्चिम	0.06	2.43
	1250	पूर्व	0.04	1.62		555	पश्चिम	0.08	3.24
	1251	पश्चिम	0.05	2.02		556	मध्य	0.16	6.48
	1252	पश्चिम	0.10	4.05		558	पूर्व	0.01	0.40
	1253	मध्य	0.11	4.45		1437	दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40
	1254	पूर्व	0.18	7.29		1438	मध्य	0.16	6.48
	1255	दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20		1439	पूर्व	0.07	2.83
	1319	दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40	ईनायतपुर	1	दक्षिण-पश्चिम	0.09	3.64
	1353	पश्चिम	0.04	1.62	जे० एल० संख्या	5	मध्य	0.17	6.88
हासिमपुर	50	दक्षिण-पश्चिम	0.05	2.02	नं० 148	7	दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20
जे० एल० संख्या	51	उत्तर-पूर्व	0.06	2.43		8	दक्षिण-पश्चिम	0.09	3.64
118	52	पूर्व	0.03	1.21		9	मध्य	0.13	5.26
	53	उत्तर-पूर्व	0.005	0.20		10	उत्तर-पूर्व	0.005	0.20
	56	मध्य	0.13	5.26		19	मध्य	0.15	6.07
	57	दक्षिण-पश्चिम	0.14	5.67		69	पश्चिम	0.01	0.40
	59	दक्षिण-पश्चिम	0.03	1.21		70	दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20
	137	पश्चिम	0.03	0.81		72	दक्षिण-पश्चिम	0.12	4.86
	139	दक्षिण-पश्चिम	0.17	6.88		73	मध्य	0.10	4.05
	142	मध्य	0.19	7.69		74	पूर्व	0.01	0.40
	144	दक्षिण	0.02	0.81		75	उत्तर-पूर्व	0.005	0.20
	145	मध्य]	0.51	20.63		76	मध्य	0.07	2.83
	148	पूर्व	0.005	0.20		82	उत्तर-पूर्व	0.10	4.05
	166	मध्य	0.16	6.48		111	मध्य	0.15	6.07
	167	उत्तर	0.13	5.26		112	पूर्व	0.10	4.05
	168	पूर्व	0.04	1.62		113	पश्चिम	0.04	1.62
	169	उत्तर-पूर्व	0.005	0.20		162	पश्चिम	0.02	0.81
	239	उत्तर-पूर्व	0.005	0.20		164	दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20
	240	दक्षिण	0.28	11.33		165	दक्षिण	0.04	1.62
	241	मध्य	0.03	1.21		166	दक्षिण-पश्चिम	0.11	4.45
	242	उत्तर	0.005	0.20		167	मध्य	0.07	2.83
	244	उत्तर	0.02	0.81		168	उत्तर-पूर्व	0.03	1.21
	464	पश्चिम	0.05	2.02		169	पूर्ण	0.06	2.43
जादव बाटी	509	उत्तर-पूर्व	0.01	0.40		170	उत्तर-पूर्व	0.03	1.21
जे० एल० 119	516	उत्तर-पूर्व	0.005	0.20		171	पूर्ण	0.12	4.86
	517	पूर्व	0.07	2.83		172	उत्तर-पूर्व	0.03	1.21
	520	पूर्व	0.07	2.83		177	पूर्व	0.05	2.02
	521	उत्तर-पूर्व	0.01	0.40		178	मध्य]	0.03	1.21
	522	उत्तर	0.04	1.62		181	पूर्व	0.03	1.21
	523	दक्षिण-पश्चिम	0.06	2.43		182	पूर्व	0.10	4.05

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) तथा भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)		गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) तथा भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)	
		एकड़ों में	ए० धार० ई० एस० में			एकड़ों में	ए० धार० ई० एस० में
ईनायतपुर	जे० 202 पूर्व	0.07	2.83	ईनायतपुर	जे० 1398 उत्तर-पूर्व	0.08	3.24
एल०	संख्या 245 पूर्व	0.005	0.20	एल०	संख्या 1401 उत्तर-पूर्व	0.04	1.62
148-जारी	246 मध्य	0.11	4.45	148-जारी	1402 पूर्व	0.03	1.21
	249 मध्य	0.05	2.02		1403 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20
	250 मध्य	0.13	5.26		1404 मध्य	0.10	4.05
	252 मध्य	0.13	5.26		1405 पूर्ण	0.07	2.83
	253 उत्तर-पूर्व	0.02	0.81		1406 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40
	255 मध्य	0.24	9.71		1414 पश्चिम	0.04	1.62
	256 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40		1415 मध्य	0.12	4.86
	263 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20		1415 पूर्व	0.06	2.83
	448 दक्षिण-पश्चिम	0.25	10.11		1417 दक्षिण-पश्चिम	0.04	1.62
	449 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40		1419 दक्षिण-पश्चिम	0.07	2.83
	452 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20		1420 पूर्व	0.09	3.64
	453 उत्तर-पूर्व	0.06	2.43		1421 मध्य	0.27	10.93
	454 पूर्ण	0.08	3.24		1426 पश्चिम	0.04	1.62
	455 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40		1427 मध्य	0.27	10.93
	456 पूर्ण	0.10	4.05		1428 पूर्व	0.12	4.86
	457 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20		1431 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40
	460 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40		1889 मध्य	0.08	3.24
	461 उत्तर-पूर्व	0.05	2.02		1906 पूर्व	0.07	2.83
	462 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20		1922 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40
	473 पूर्व	0.12	4.86				
	474 मध्य	0.10	4.05				
	475 दक्षिण-पश्चिम	0.01	0.40				
	476 मध्य	0.13	5.26				
	903 पूर्व	0.01	0.40				
	945 पूर्व	0.36	14.57				
	947 पश्चिम	0.16	4.48				
	948 दक्षिण-पश्चिम	0.02	0.81				
	976 दक्षिण	0.07	2.83				
	979 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20				
	980 मध्य	0.17	6.88				
	981 मध्य	0.13	5.26				
	982 मध्य	0.18	7.29				
	983 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40				
	987 पूर्व	0.06	2.43				
	988 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20				
	1034 पूर्व	0.34	13.76				
	1035 उत्तर-पूर्व	0.005	0.20				
	1037 उत्तर-पूर्व	0.10	4.05				
	1038 पश्चिम	0.14	5.67				
	1039 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20				
	1040 मध्य	0.21	8.49				
	1060 दक्षिण-पश्चिम	0.04	1.62				
	1061 मध्य	0.12	4.86				
	1062 उत्तर-पूर्व	0.01	0.40				
	1063 पश्चिम	0.27	10.93				
	1064 दक्षिण-पश्चिम	0.005	0.20				

[सं० 11/5/71-लेबर एण्ड लेजिस/2]

New Delhi, the 7th February, 1973

S.O. 515—Whereas by a Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals, S. O. No. 897 dated 7th Jan, 1972 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that Notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this Notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this Notification is hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State : West Bengal, District : Hooghly, Police Stn./Thana : HARIPAL

Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent (Area)	
		In acres	In ares
GAJA, . J. L. No. 92 . . .	135 Middle	0.26	10.52
	137 West	0.06	2.43
	138 East	0.11	4.45
	139 Full	0.02	0.81
	140 Full	0.03	1.21
	141 East	0.01	0.40
	161 North-East	0.005	0.20
	166 East	0.05	2.02
	167 East	0.07	2.83
	169 East	0.12	4.86
	170 Middle	0.14	5.67
	171 South-West	0.005	0.20
	176 West	0.05	2.02
	177 West	0.07	2.83
	178 West	0.10	4.05
	200 West	0.05	2.02
	205 South-West	0.02	0.81
	207 West	0.09	3.64
	208 Middle	0.20	8.09
	209 North-East	0.03	1.21
	210 West	0.07	2.83
	211 East	0.12	4.86
	220 East	0.19	7.69
	304 North-East	0.16	5.67
	316 South-West	0.02	0.81
	317 East	0.09	3.64
	318 Full	0.06	1.62
	319 South-West	0.02	0.81
	320 Middle	0.20	8.09
	332 South-West	0.01	0.40
	333 East	0.28	11.33
	334 North-East	0.06	2.43
	335 West	0.16	6.48
	355 West	0.09	3.64
	356 West	0.39	15.79
	358 North-East	0.05	2.02
	359 West	0.17	6.88
	1028 North-East	0.01	0.40
	1029 East	0.02	0.81
	1031 East	0.03	1.21
	1032 Middle	0.16	6.48
	1034 West	0.05	2.02
	1035 Middle	0.19	7.69
	1036 West	0.005	0.20
	1069 West	0.05	2.02
	1077 Middle	0.35	14.16
	1078 North-East	0.005	0.20
	1080 East	0.06	2.43
	1126 West	0.02	0.81
	1129 North-East	0.02	0.81
	1130 Middle	0.09	3.64
	1131 South-West	0.05	2.02
	1132 West	0.10	4.05
	1178 South-West	0.17	6.88
	1179 North-East	0.06	2.43
	1182 North-East	0.01	0.40
	1183 Middle	0.23	9.30
	1186 South-West	0.07	2.83
	1198 South-West	0.04	1.62
	1199 Middle	0.09	3.64
	1200 North	0.07	2.83
	1201 North-East	0.005	0.20
	1271 North-East	0.03	1.21
	1272 Middle	0.07	2.83
	1274 West	0.08	3.24
	1275 South	0.03	1.21
	1278 East	0.02	0.81
	1279 North-East	0.01	0.40
	1280 East	0.04	1.62
	1281 East	0.09	3.64
	1282 Full	0.09	3.64
	1286 West	0.04	1.62
	1287 West	0.08	3.24
	1288 East	0.01	0.40

DILALPUR, .
J. L. No. 111 .

Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent Area	
		In acres	In ares
DILALPUR,—Contd.	1289 East	0.05	2.02
	1290 Middle	0.07	2.83
	1291 West	0.04	1.62
	1292 South-West	0.01	0.40
	2168 South	0.03	1.21
	2197 West	0.02	0.81
	2198 South-West	0.005	0.20
	2199 Full	0.12	4.86
	2200 West	0.05	2.02
	2201 Full	0.06	2.43
	2202 East	0.05	2.02
	2203 East	0.03	1.21
	2322 Full	0.03	1.21
	2323 West	0.04	1.62
	2326 South-West	0.005	0.20
	2327 South-West	0.04	1.62
	2228 Full	0.06	2.43
	2329 West	0.17	6.88
	2330 North-East	0.03	1.21
	2344 North-East	0.005	0.20
	2345 West	0.02	0.81
	2346 South-West	0.05	2.02
	2347 Full	0.01	0.40
	2348 North-East	0.02	0.81
	2349 South	0.06	2.43
	2354 North-East	0.12	4.86
	2355 North	0.005	0.20
	2356 Middle	0.05	2.02
	2364 South	0.06	2.43
	2365 South	0.06	2.43
	2369 South-West	0.04	1.62
	2810 West	0.01	0.04
	2884 North-East	0.12	4.86
	2908 South-West	0.005	0.20
Kasimerpur, J. L. No. 112 . . .	15 North-East	0.005	0.20
	16 Middle	0.20	8.09
	17 Middle	0.13	5.26
	18 South-West	0.02	0.81
	19 Middle	0.13	5.26
	21 West	0.03	1.21
	28 West	0.22	8.90
	115 South-West	0.01	0.40
	116 South-West	0.01	0.40
	117 Middle	0.08	3.24
	118 North-East	0.04	1.62
	120 Middle	0.14	5.67
	121 Middle	0.11	4.45
	122 West	0.07	2.83
	123 West	0.06	2.43
	125 West	0.05	2.02
	126 Middle	0.09	3.64
	127 East	0.03	1.21
	128 North-East	0.01	0.40
	176 East	0.04	1.62
	179 North-East	0.005	0.20
	190 North-East	0.01	0.40
	191 Middle	0.12	4.86
	192 Middle	0.38	15.38
	193 West	0.08	3.24
	199 South-West	0.01	0.40
	200 Middle	0.09	3.64
	201 East	0.05	2.02
	205 East	0.005	0.20
	211 North-East	0.005	0.20
	212 East	0.05	2.02
	213 West	0.26	10.52
	255 Middle	0.19	7.69
	257 West	0.10	4.05
	258 West	0.05	2.02
	260 South-West	0.005	0.20
	261 Middle	0.05	2.02
	262 Middle	0.06	2.43
	263 Middle	0.04	1.62
	264 West	0.08	3.24
	265 Full	0.03	1.21
	266 Full	0.01	0.40
	267 Full	0.01	0.40
	268 Middle	0.01	0.40
	269 East	0.01	0.40

Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent Area		Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent Area	
		In acres	In ares			In acres	In ares
Kasimorpur— <i>contd.</i>	270 North-East	0.005	0.20	Islampur— <i>contd.</i>	1344 North	0.03	1.21
	272 North-East	0.03	1.21		1498 South-West	0.005	0.20
	273 East	0.05	2.02		1499 West	0.03	1.21
	729 East	0.03	1.21	Purbagopinathpur, J. L. No. 117	16 North-East	0.01	0.40
	730 North-East	0.01	0.40		17 Middle	0.09	3.64
	735 Middle	0.83	14.57		21 South-West	0.10	4.05
	737 South-West	0.005	0.20		22 South-West	0.07	2.83
	738 West	0.01	0.04		23 South	0.07	2.83
	739 Middle	0.16	6.48		24 West	0.03	1.21
	742 North-East	0.07	2.83		25 North	0.04	1.62
	761 East	0.17	6.88		26 West	0.13	4.25
	762 Middle	0.08	3.24		28 South	0.03	1.21
	763 South	0.02	0.81		29 South-East	0.11	4.45
	767 South	0.04	1.62		32 North	0.09	3.64
	768 Middle	0.11	4.45		33 North-East	0.03	1.21
	769 North-East	0.02	0.81		35 North	0.09	3.64
	770 North-East	0.005	0.20		342 North-East	0.005	0.20
	771 Middle	0.13	5.26		345 Middle	0.12	4.86
	772 West	0.06	2.43		346 Middle	0.10	4.05
	773 North-East	0.05	2.02		347 Middle	0.10	4.05
	777 Middle	0.03	1.21		348 North-East	0.005	0.20
	1249 Middle	0.09	3.64		349 East	0.04	1.62
	1250 South-West	0.01	0.40		350 West	0.10	4.05
	1298 Middle	0.11	4.45		352 Middle	0.06	2.43
	1302 East	0.04	1.62		353 West	0.04	1.62
	1303 Middle	0.10	4.05		356 South-West	0.005	0.20
	1328 Middle	0.03	1.21		357 South-West	0.04	1.62
Bandipur, J. L. No. 113	2313 East	0.07	2.83		358 North-East	0.05	2.02
	2343 North-East	0.01	0.40		366 East	0.06	2.43
	2345 North-East	0.01	0.40		368 North-East	0.04	1.62
	2346 Middle	0.09	3.64		369 Middle	0.03	1.21
	2349 West	0.06	2.43		370 East	0.01	0.40
	2350 North-East	0.05	2.02		371 East	0.05	2.02
	2351 West	0.03	1.21		372 West	0.11	4.45
	2352 West	0.05	2.02		373 West	0.02	0.81
	2353 Middle	0.06	2.43		374 West	0.03	1.21
	2354 East	0.06	2.43		382 South-West	0.02	0.81
	2355 North-East	0.01	0.40		388 West	0.14	5.67
	2362 North-East	0.03	1.21		389 Middle	0.16	6.48
	2363 North	0.03	1.21		390 North-East	0.01	0.40
	2364 North	0.04	1.62		403 North-East	0.01	0.40
	2365 Middle	0.06	2.43		404 North-East	0.02	0.81
	2366 North-East	0.04	1.62		405 North-East	0.08	3.24
	2367 South-West	0.12	4.86		406 West	0.10	4.05
	2368 South-West	0.02	0.81		407 South-West	0.01	0.40
	2389 South-West	0.01	0.40		408 Middle	0.10	4.05
	2390 West	0.02	0.81		409 North-East	0.03	1.21
	2391 West	0.15	6.07		411 North-East	0.005	0.20
	2406 South-West	0.09	3.64		417 North-East	0.01	0.40
	2407 North-East	0.13	5.26		418 North	0.08	3.24
	2408 North-East	0.01	0.40		419 Middle	0.10	4.05
	2421 North-East	0.04	1.62		420 South	0.05	2.02
	2422 South-West	0.005	0.20		421 South	0.02	0.81
	2423 Middle	0.44	17.81		422 South-West	0.005	0.20
	2424 North-East	0.005	0.20		425 South-West	0.005	0.20
	2459 North-East	0.09	3.64		436 South-West	0.06	2.43
	2465 North-East	0.07	2.83		437 North-East	0.08	3.24
	2466 South-West	0.06	2.43		438 South-West	0.03	1.21
	2469 West	0.11	4.45		439 North-East	0.07	2.83
	2470 North-East	0.09	3.64		441 West	0.02	0.81
	2471 South-West	0.03	1.21		442 West	0.13	5.26
	2477 South-West	0.01	0.40		444 North-East	0.01	0.40
	2416 Middle	0.02	0.81		445 Middle	0.24	11.33
	2686 South-West	0.005	0.20		449 North-East	0.18	7.29
	2690 Middle	0.19	7.69		450 South-West	0.14	5.67
	2691 South-West	0.05	2.02		455 West	0.01	0.40
	2692 East	0.04	1.62		807 South-West	0.005	0.20
	2693 North-East	0.05	2.02		808 South-West	0.005	0.20
	2695 North-East	0.01	0.40		809 West	0.06	2.43
	2696 Middle	0.28	11.33		810 Middle	0.12	4.86
	2697 South-West	0.04	1.62		1203 South-West	0.005	0.20
	2700 South-West	0.04	1.62		1206 Middle	0.21	8.49
	2701 Middle	0.18	10.93		1207 Middle	0.10	4.05
	2831 South-West	0.06	2.43		1208 West	0.06	2.43
	2833 Middle	0.08	3.24		1211 South-West	0.07	2.83
	2834 North-East	0.01	0.40		1212 East	0.05	2.02
	2835 Middle	0.08	3.24		1213 North-East	0.005	0.20
Islampur, J. L. No. 114	1307 West	0.17	6.83		1214 East	0.04	1.62
	1330 West	0.34	13.76		1241 East	0.16	6.48
	1343 Middle	0.19	7.69				

Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent Area		Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent Area	
		In acres	In ares			In acres	In ares
Purbagopinathpur J. L. No. 117	1248 North-East	0.03	1.21	167 Middle	0.07	2.83	
	1250 East	0.04	1.62	168 North-East	0.03	1.21	
	1251 West	0.05	2.02	169 Full	0.06	2.43	
	1252 West	0.10	4.05	170 North-East	0.03	1.21	
	1253 Middle	0.11	4.45	171 Full	0.012	4.86	
	1254 East	0.18	7.29	172 North-East	0.03	1.21	
	1255 South-West	0.005	0.20	177 East	0.05	2.02	
	1319 South-West	0.01	0.40	178 Middle	0.03	1.21	
Hasimpur, J. L. No. 118	1353 West	0.04	1.62	181 East	0.03	1.21	
	50 South-West	0.05	2.02	182 East	0.10	4.05	
	51 North-East	0.06	2.43	202 East	0.07	2.83	
	52 East	0.03	1.21	245 East	0.005	0.20	
	53 North-East	0.005	0.20	246 Middle	0.11	4.45	
	56 Middle	0.13	5.26	249 Middle	0.05	2.02	
	57 South-West	0.14	5.67	250 Middle	0.13	5.26	
	59 South-West	0.03	1.21	252 Middle	0.13	5.26	
	137 West	0.02	0.81	253 North-East	0.02	0.81	
	139 South-West	0.17	6.88	255 Middle	0.24	9.71	
	142 Middle	0.19	7.69	256 South-West	0.01	0.40	
	144 South	0.02	0.81	263 South-West	0.005	0.20	
	145 Middle	0.51	20.63	448 South-West	0.25	10.11	
	148 East	0.005	0.20	449 South-West	0.01	0.40	
	166 Middle	0.16	6.48	452 South-West	0.005	0.20	
	167 North	0.13	5.26	453 North-East	0.06	2.43	
	168 East	0.04	1.62	454 Full	0.08	3.24	
	169 North-East	0.005	0.20	455 North-East	0.01	0.40	
	239 North-East	0.005	0.20	456 Full	0.10	4.05	
	240 South	0.28	11.33	457 North-East	0.005	0.20	
	241 Middle	0.03	1.21	460 North-East	0.01	0.40	
	242 North	0.005	0.20	461 North-East	0.05	2.02	
	244 North	0.02	0.81	462 North-East	0.005	0.20	
	464 West	0.05	2.02	473 East	0.12	4.86	
Jadab Bati, J. L. No. 119	509 North-East	0.01	0.40	474 Middle	0.10	4.05	
	516 North-East	0.005	0.20	475 South-West	0.01	0.40	
	517 East	0.07	2.83	476 Middle	0.13	5.26	
	520 East	0.07	2.83	903 East	0.01	0.40	
	521 North-East	0.01	0.40	945 East	0.36	14.57	
	522 North	0.04	1.62	947 West	0.16	4.48	
	523 South-West	0.06	2.43	948 South-West	0.02	0.81	
	524 North	0.08	3.24	976 South	0.07	2.83	
	525 North-East	0.03	1.21	979 South-West	0.005	0.20	
	526 North-East	0.07	2.83	980 Middle	0.17	6.88	
	527 Middle	0.08	3.24	981 Middle	0.13	5.26	
	528 South	0.05	2.02	982 Middle	0.18	7.29	
	529 South-West	0.01	0.40	983 North-East	0.01	0.40	
	531 South	0.03	1.21	987 East	0.06	2.43	
	532 South	0.02	0.81	988 North-East	0.005	0.20	
	533 South-West	0.005	0.20	1034 East	0.34	13.76	
	534 Middle	0.09	3.64	1035 North-East	0.005	0.20	
	554 South-West	0.06	2.43	1037 North-East	0.10	4.05	
	555 West	0.08	3.24	1038 West	0.14	5.67	
	556 Middle	0.16	6.48	1039 South-West	0.005	0.20	
	558 East	0.01	0.40	1040 Middle	0.21	8.49	
	1437 South-West	0.01	0.40	1060 South-West	0.04	1.62	
	1438 Middle	0.16	6.48	1061 Middle	0.12	4.86	
	1439 East	0.07	2.83	1062 North-East	0.01	0.40	
Enayetpur, J. L. No. 148	1 South-West	0.09	3.64	1063 West	0.27	10.93	
	5 Middle	0.17	6.88	1064 South-West	0.005	0.20	
	7 South-West	0.005	0.20	1398 North-East	0.08	3.24	
	8 South-West	0.09	3.64	1401 North-East	0.04	1.62	
	9 Middle	0.13	5.26	1402 East	0.03	1.21	
	10 North-East	0.005	0.20	1403 North-East	0.005	0.20	
	19 Middle	0.15	6.07	1404 Middle	0.10	4.05	
	69 West	0.01	0.40	1405 Full	0.07	2.83	
	70 South-West	0.005	0.20	1406 South-West	0.01	0.40	
	72 South-West	0.12	4.86	1414 West	0.04	1.62	
	73 Middle	0.10	4.05	1415 Middle	0.12	4.86	
	74 East	0.01	0.40	1416 East	0.06	2.83	
	75 North-East	0.005	0.20	1417 South-West	0.04	1.62	
	76 Middle	0.07	2.83	1419 South-West	0.07	2.83	
	82 North-East	0.10	4.05	1420 East	0.09	3.64	
	111 Middle	0.15	6.07	1421 Middle	0.27	10.93	
	112 East	0.10	4.05	1426 West	0.04	1.62	
	113 West	0.04	1.62	1427 Middle	0.27	10.93	
	162 West	0.02	0.81	1428 East	0.12	4.86	
	164 South-West	0.005	0.20	1431 North-East	0.01	0.40	
	165 South	0.04	1.62	1889 Middle	0.08	3.24	
	166 South-West	0.11	4.45	1906 East	0.07	2.83	
				1922 North-East	0.01	0.40	

क्रा० प्रा० 516.—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अधिसूचना क्रा० प्रा० सं० 1596 तिथि 4 अप्रैल, 1972 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनों को बिहाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था :

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है :

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिहाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है और, उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में बहिष्कृत होने के बजाय भारतीय तेल निगम में, सभी बन्धकों के मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

राज्य : पश्चिमी बंगाल जिला : हुगली पुलिस स्टेशन/धाना: घनियाखली

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) और भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)	
		एकड़ों में	ए० आर० ई० एस० में
बागनाम	1008 मध्य	.17	6.88
जे० एल० 199-II	1009 मध्य	.14	5.67
	1010 पूर्व	.11	4.45
	1011 मध्य	.06	2.43
	1030 उत्तर-पूर्व	.01	.040
	1031 मध्य	.11	4.45
	1033 दक्षिण-पश्चिम	.01	0.40
	1034 मध्य	.15	6.07
	1036 दक्षिण-पश्चिम	.09	3.64
	1049 पश्चिम	.15	6.07
	1193 दक्षिण-पश्चिम	.02	0.81
	1194 दक्षिण-पश्चिम	.01	0.40
	1195 मध्य	.09	3.64
	1197 उत्तर-पूर्व	.05	0.20
	1199 उत्तर-पूर्व	.01	0.40
	1200 मध्य	.14	5.67
	1202 मध्य	.34	13.76
	1259 पूर्व	.10	4.05

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) और भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)	
		एकड़ों में	ए० आर० ई० एस० में
बागनाम जे० एल० 199-II—contd.	1260 मध्य	.04	1.62
	1261 पूर्व	.01	0.40
	1262 पूर्ण	.03	1.21
	1263 मध्य	.15	6.07
	1276 पश्चिम	.01	0.40
	1305 मध्य	.03	1.21
	1367 मध्य	.42	17.00
	1368 दक्षिण-पश्चिम	.005	0.20
	1376 पश्चिम	.09	3.64
	1377 पश्चिम	.03	1.21
	1378 पश्चिम	.02	0.81
	1379 दक्षिण-पश्चिम	.005	0.20
	1380 मध्य	.27	10.92
	1443 पूर्व	.16	6.48
	1444 पूर्व	.16	6.48
	1508 पूर्व	.04	1.62
	1509 पूर्व	.08	3.24
	1510 पूर्व	.09	3.64
	1511 मध्य	.04	1.62
	1512 मध्य	.19	7.69
	1547 पश्चिम	.01	0.40
	1548 मध्य	.04	1.62
	1550 पश्चिम	.02	0.81
	1551 पूर्ण	.03	1.21
	1552 पूर्ण	.04	1.62
	1553 पूर्व	.02	0.81
	1554 उत्तर-पूर्व	.005	0.20
	1558 पूर्व	.06	2.43
	1559 पूर्ण	.08	3.24
	1560 पूर्व	.22	8.90
	1561 पश्चिम	.05	2.02
	1568 पश्चिम	.005	0.20
	1569 पश्चिम	.09	3.64
	1570 पूर्व	.05	2.02
	1571 पूर्व	.05	2.02
	1572 पूर्ण	.10	4.05
	1573 पूर्व	.01	0.40
	1672 दक्षिण-पश्चिम	.01	0.40
	1690 उत्तर-पूर्व	.005	0.20
	1702 पश्चिम	.05	2.02
	1703 मध्य	.10	4.05
	1721 पश्चिम	.02	0.81
	1722 पश्चिम	.04	1.62
	1723 पश्चिम	.02	0.81
	1760 पूर्व	.005	0.20
	1706 पूर्व	.13	5.26
	1708 पूर्व	.09	3.64

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) और भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)	एकड़ों में ए०आर०ई० एस० में	गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) और भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)	एकड़ों में ए०आर०ई० एस० में
परमेश्वरपुर	18 पश्चिम	.08	3.24	276 पूर्व	.13	5.26	
जे० एल० 200	19 पश्चिम	.12	4.86	277 मध्य	.08	3.24	
	20 पूर्व	.01	0.40	278 पश्चिम	.02	0.81	
	21 मध्य	.34	13.76	290 पश्चिम	.03	1.21	
	22 पूर्व	.07	2.83	299 पश्चिम	.17	6.88	
	23 पश्चिम	.10	4.05	300 उत्तर-पूर्व	.01	0.40	
	26 मध्य	.12	4.86	301 मध्य	.17	6.88	
	27 पूर्व	.14	5.67	302 मध्य	.20	8.09	
	32 पश्चिम	.15	6.07	322 पूर्व	.24	9.71	
	33 पूर्व	.16	6.48	487 पूर्व	.09	3.64	
	34 पश्चिम	.03	1.21	488 मध्य	.21	8.49	
	35 पश्चिम	.02	0.81	490 पश्चिम	.04	1.62	
	36 पश्चिम	.02	0.81	491 मध्य	.05	2.02	
दक्षिण मलिकपुर	150 मध्य	.07	2.83	492 उत्तर-पूर्व	.005	0.20	
जे० एल० 202	151 पूर्व	.02	0.81	496 उत्तर-पूर्व	.03	1.21	
	152 पूर्व	.01	0.40	498 मध्य	.19	7.69	
	153 उत्तर-पूर्व	.005	.020	499 मध्य	.03	1.21	
	154 पूर्व	.03	1.21	500 दक्षिण-पश्चिम	.01	0.40	
	155 पूर्व	.04	1.62	501 मध्य	.11	4.45	
	319 पूर्व	.03	1.21	502 मध्य	.08	3.24	
	322 पूर्व	.12	4.86	513 मध्य	.27	10.92	
	323 उत्तर-पूर्व	.02	0.81	514 पूर्व	.09	3.64	
	324 मध्य	.18	7.29	515 दक्षिण-पश्चिम	.005	0.20	
	325 दक्षिण-पश्चिम	.02	0.81	521 पश्चिम	.06	2.43	
	326 मध्य	.18	7.29	522 पश्चिम	.07	2.83	
	334 पश्चिम	.09	3.64	523 पूर्व	.18	7.29	
	343 पश्चिम	.17	6.88	524 पूर्व	.05	2.02	
	347 पश्चिम	.05	2.02	525 पूर्व	.07	2.83	
	348 मध्य	.25	10.11	526 मध्य	.12	4.86	
	349 उत्तर-पूर्व	.06	2.43	527 उत्तर-पूर्व	.01	0.40	
	364 पूर्व	.02	0.81	528 पूर्व	.03	1.21	
	387 उत्तर पूर्व	.005	0.20	601 पूर्व	.07	2.83	
	388 पूर्व	.07	2.83	602 उत्तर-पूर्व	.005	0.20	
	389 मध्य	.26	10.52	605 उत्तर-पूर्व	.005	0.20	
	390 पश्चिम	.05	2.02	606 पूर्व	.005	0.20	
	410 उत्तर-पूर्व	.005	0.20	607 पश्चिम	.21	8.49	
पुरन्दरपुर	207 पूर्व	.03	1.21	608 मध्य	.19	7.69	
जे० एल० 208	204 पूर्व	.01	0.40	947 मध्य	.29	11.74	
	210 पश्चिम	.09	3.64	949 मध्य	.12	4.86	
	212 पश्चिम	.22	4.90	जोत माहेस	516 पश्चिम	.03	1.21
	214 पश्चिम	.05	2.02	जे० एल० 210	517 पश्चिम	.06	2.43
	215 पश्चिम	.09	3.64		521 पश्चिम	.10	4.05
	216 उत्तर-पूर्व	.01	0.40		523 पश्चिम	.01	0.40
	217 पूर्व	.09	3.64		524 मध्य	.19	7.69
	218 दक्षिण-पश्चिम	.005	0.20		525 पूर्व	.10	4.05
	268 पश्चिम	.11	4.45		526 पश्चिम	.12	4.86
	269 पूर्व	.11	4.45		557 पश्चिम	.06	2.43
	275 पूर्व	.13	5.26		558 पश्चिम	.01	0.40

गांव	सर्वेक्षण संख्या)	संख्या (प्लॉट और भूमि का विवरण)	सीमा (क्षेत्र)	गांव	सर्वेक्षण संख्या)	संख्या (प्लॉट और भूमि का विवरण)	सीमा (क्षेत्र)
		एकड़ों में ए०आर० ई० एस० में				एकड़ों में ए० आर० ई० एस० में	
जोत माहेस	567	मध्य	.38 15.38	1191	पश्चिम	.05 2.02	
जे० एल० 210	568	पूर्व	.16 6.48	1192	दक्षिण-पश्चिम	.01 0.40	
(जारी)	571	पूर्व	.17 6.488	1200	मध्य	.28 11.33	
	572	पूर्व	.12 4.86	1201	मध्य	.13 5.26	
	573	पूर्व	.05 2.02	1203	मध्य	.10 4.05	
	585	पूर्व	.12 4.86	1206	दक्षिण-पश्चिम	.01 0.40	
	586	पूर्व	.09 3.64	1207	पूर्व	.16 6.48	
	588	पूर्व	.04 1.62	1216	मध्य	.10 4.05	
	589	पश्चिम	.11 4.45	1217	मध्य	.12 4.86	
	590	पश्चिम	.22 8.90	1218	पूर्व	.01 0.40	
	650	उत्तर-पूर्व	.005 0.20	1219	मध्य	.11 4.45	
	653	पश्चिम	.02 0.81	1332	पश्चिम	.06 2.43	
पूर्व-केशवपुर	324	उत्तर-पूर्व	.03 1.21	1333	पश्चिम	.02 0.81	
जे० एल० 211				1335	मध्य	.07 2.83	
				1336	पूर्व	0.06 2.43	
बाजीतपुर जे०	997	मध्य	.07 2.83	1337	पूर्व	.16 6.48	
जे० एल० 212	1018	पूर्व	.10 4.05	1352	पूर्व	.09 3.64	
	1052	पूर्व	.005 0.20	1353	पूर्व	.20 8.09	
	1053	मध्य	.09 3.64	1362	पूर्व	.01 0.40	
	1054	मध्य	.11 4.45	1369	पूर्व	.07 2.83	
	1055	मध्य	.05 2.02	1370	उत्तर-पूर्व	.005 0.20	
	1056	पूर्व	.03 1.21	1371	पूर्व	.02 0.81	
	1057	पूर्व	.06 2.43	1372	पश्चिम	.16 6.48	
	1058	पूर्व	.09 3.64	1373	पश्चिम	.08 3.24	
	1060	पूर्व	.05 2.02	1392	पश्चिम	.08 3.24	
	1061	मध्य	.09 3.64	1393	पश्चिम	.01 0.40	
	1062	दक्षिण-पश्चिम	.10 4.05	1394	पश्चिम	.01 0.40	
	1074	मध्य	.07 4.83	1589	पश्चिम	.14 5.67	
	1075	दक्षिण पश्चिम	.01 0.40	1593	मध्य	.10 4.05	
	1076	पश्चिम	.005 0.20	1091	उत्तर-पूर्व	.02 0.81	
	1077	मध्य	.10 4.05	1092	मध्य	.09 3.64	
	1078	मध्य	.08 3.24	रुबरानी जे०	635	दक्षिण	.005 0.20
	1072	दक्षिण-पश्चिम	.005 0.20	एल० 189	636	मध्य	.01 0.40
	1079	दक्षिण-पश्चिम	0.04 1.62		637	मध्य	.07 2.83
	1081	पश्चिम	0.1 0.40		639	पूर्व	.06 2.43
	1082	मध्य	.10 4.05		1018	पूर्व	.05 2.02
	1083	पश्चिम	.05 2.02		1019	पश्चिम	.08 3.24
	1084	मध्य	.11 4.45		1034	पश्चिम	.07 2.83
	1085	पश्चिम	.08 3.24		1035	मध्य	.10 4.05
	1086	पूर्व	.04 1.62		1038	पूर्व	.05 2.02
	1088	उत्तर-पूर्व	.005 0.20		1040	पूर्व	.01 0.40
	1089	मध्य	.04 1.62		1041	पूर्ण	.03 1.21
	1090	पूर्व	.01 0.40		1042	उत्तर पश्चिम	.005 0.20
	1103	पूर्व	.07 2.83		1043	पूर्व	.17 6.88
	1104	पश्चिम	0.08 3.24		1050	पूर्व	.09 3.64
	1105	पूर्व	0.1 0.40		1051	पूर्व	.06 2.43
	1137	मध्य	.08 3.24		1052	पूर्व	.01 0.40
	1190	पूर्व	.02 0.81		1053	पूर्ण	.04 1.62

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या)	सीमा (क्षेत्र)	गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या)	सीमा (क्षेत्र)
	और भूमि का विवरण	एकड़ों में ए० आर० ई०एस०में		और भूमि का विवरण	एकड़ों में ए० आर० ई०एस० में
सवराली				196 उत्तर पूर्व	.005 0.20
जे० एल० 189	1054 पश्चिम	.08 3.24		202 पूर्व	.23 9.30
(जारी)	1064 पश्चिम	.16 6.48		203 पूर्व	.06 2.43
	1067 पूर्व	.03 1.21		204 पूर्व	.16 6.48
	1068 पूर्व	.03 1.21		205 पश्चिम	.11 4.45
	1092 पूर्व	.17 6.88		206 पश्चिम	.02 0.81
	1245 मध्य	.23 9.30		209 मध्य	.23 9.30
	1246 पूर्ण	.06 2.43		210 पूर्व	.13 5.26
	1247 पूर्ण	.03 1.21		283 उत्तर-पूर्व	.04 1.62
	1248 पश्चिम	.01 0.40		284 मध्य	.21 8.49
	1254 मध्य	.13 5.26		28 पश्चिम	.13 5.26
	1255 मध्य	.15 6.07		286 उत्तर-पूर्व	.005 0.20
	1256 मध्य	.12 4.86		287 पूर्व	.06 2.43
	1257 पश्चिम	.01 0.40		288 पश्चिम	.06 2.43
	1258 पूर्व	.08 3.24		316 पश्चिम	.04 1.62
	1804 पश्चिम	.06 2.43		319 पश्चिम	.04 1.62
	1805 पश्चिम	.08 3.24		320 पूर्व	.11 4.45
	1860 पूर्व	.08 3.21		322 पूर्व	.06 2.43
	1861 मध्य	.08 3.21		398 पूर्व	.01 0.40
	1870 पश्चिम	.04 1.62		399 उत्तर पूर्व	.01 0.40
	1872 पूर्व	.04 1.62		1084 मध्य	.31 12.54
छोटा खानपुर	14 पूर्व	.01 0.40	हरिहरपुर	242 पूर्व	.09 3.64
जे० एल०	15 पूर्व	.13 5.6	जे० ए० 201	246 पूर्व	.11 4.45
192	16 पश्चिम	.02 0.81		247 पूर्व	.04 1.62
	19 मध्य	.10 4.05		276 पूर्व	.01 0.40
	20 मध्य	.08 3.24		277 मध्य	.22 8.90
	22 उत्तर-पूर्व	.005 0.20		278 मध्य	.13 5.26
	23 मध्य	.08 3.24		279 मध्य	.06 2.43
	73 मध्य	.10 4.05		280 पूर्व	.07 2.83
	74 उत्तरपूर्व	.007 0.28		289 पश्चिम	.12 4.86
	75 उत्तर-पूर्व	.005 0.20		290 पूर्व	.01 0.40
	80 पूर्व	.03 1.21		292 पूर्व	.12 4.86
	81 मध्य	.25 10.11		293 मध्य	.17 6.88
	85 मध्य	.09 3.64		298 पश्चिम	.15 6.07
	184 मध्य	.02 0.81		300 मध्य	.10 4.05
	185 पश्चिम	.01 0.40		301 दक्षिण	.01 0.40
	189 पूर्व	.06 2.43		402 पूर्व	.02 0.81
	190 पूर्व	.07 2.83		411 पूर्व	.05 2.02
	191 पूर्व	.02 0.81		415 पूर्व	.07 2.83
	192 पश्चिम	.005 0.20		416 पूर्व	.09 3.64
	210 पश्चिम	.04 1.62		417 पश्चिम	.08 3.24
	212 पश्चिम	.06 2.43		418 पश्चिम	.02 0.81
	213 पश्चिम	.04 1.62		419 मध्य	.10 4.05
	564 दक्षिण-पश्चिम	.005 0.20		424 पश्चिम	.14 5.67
	565 पूर्ण	.01 0.40		425 मध्य	.23 9.30
	567 मध्य	.85 34.39		465 पूर्व	.10 4.05
न्योपारा	97 उत्तर पूर्व	.005 0.20		485 उत्तर पश्चिम	.06 2.43
जे० एल० 193	98 पश्चिम	.10 4.05		486 दक्षिण	.11 4.45

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) और भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)	गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट संख्या) और भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र)
		एकड़ों में ए. ई. एस. में			एकड़ों में ए. ई. एस. में
नाथिताजोल जे० एल० 214-II	490 पूर्व	.12 4.86	878 उत्तर-पूर्व	.01 0.40	
	498 दक्षिण-पश्चिम	.005 0.20	879 पूर्व	.04 1.62	
	11 पश्चिम	.03 1.21	880 पश्चिम	.04 1.62	
	12 पश्चिम	.06 2.43	884 पश्चिम	.09 3.64	
	16 दक्षिण-पश्चिम	.005 0.20	885 पूर्ण	.05 2.02	
	17 पश्चिम	.03 1.21	886 पूर्व	.01 0.40	
	21 पश्चिम	.14 5.677	887 पश्चिम	.09 3.64	
	22 उत्तर-पूर्व	.005 0.20	888 उत्तर-पूर्व	.01 0.40	
	23 मध्य	.13 5.26	889 मध्य	.16 6.48	
	30 दक्षिण-पश्चिम	.005 0.20	891 दक्षिण-पश्चिम	.005 0.20	
	36 पश्चिम	.02 0.81	892 पश्चिम	.01 0.40	
	37 पूर्व	.13 5.26	920 पश्चिम	.005 0.20	
	39 पूर्व	.04 1.62	922 पश्चिम	.04 1.62	
	40 पूर्व	.005 0.20	923 पश्चिम	.09 3.64	
	41 पूर्व	.01 0.40	924 पूर्ण	.04 1.62	
	45 पूर्व	.02 0.81	925 पूर्व	.05 2.02	
	46 पूर्ण	.12 4.86	926 पूर्व	.09 3.64	
	47 पूर्ण	.10 4.05	927 पूर्व	.10 4.05	
	48 मध्य	.05 2.02	1094 पूर्व	.10 4.05	
	49 मध्य	.02 0.81	1097 मध्य	.22 8.90	
	50 दक्षिण-पूर्व	.005 0.20	1099 पश्चिम	.14 5.67	
	52 दक्षिण-पश्चिम	.01 0.40	1112 पश्चिम	.11 4.45	
	569 पश्चिम	.02 0.81	1113 पश्चिम	.03 1.21	
	570 दक्षिण-पश्चिम	.01 0.40	1114 पश्चिम	.02 0.81	
	572 दक्षिण-पश्चिम	.005 0.20	1115 मध्य	.04 1.62	
	586 पश्चिम	.03 1.21	1116 पूर्व	.03 1.21	
	588 दक्षिण-पश्चिम	.01 0.40	1117 पूर्व	.04 1.62	
	589 पूर्ण	.06 2.43	1118 उत्तर-पूर्व	.01 0.40	
	590 पश्चिम	.01 0.40	1124 पूर्व	.20 8.09	
	591 मध्य	.08 3.24	1137 मध्य	.06 2.43	
	595 मध्य	.02 0.81	1138 पश्चिम	.04 1.62	
	596 पूर्ण	.08 3.24	1139 पूर्ण	.04 1.62	
	597 मध्य	.14 5.67	1140 पूर्व	.04 1.62	
	599 उत्तर-पूर्व	.03 1.21	1141 पूर्ण	.06 2.43	
	603 पूर्व	.06 2.43	1142 पूर्व	.09 3.64	
	610 उत्तर-पूर्व	.01 0.40	1149 उत्तर-पूर्व	.005 0.20	
	611 दक्षिण	.03 1.21	1150 मध्य	.22 8.90	
	612 मध्य	.15 6.07	1151 पश्चिम	.05 2.02	
	613 पश्चिम	.01 0.40	1164 दक्षिण-पश्चिम	.01 0.40	
	614 मध्य	.05 2.02	1165 उत्तर-पूर्व	.08 3.24	
	616 पश्चिम	.15 6.07	1166 दक्षिण-पश्चिम	.01 0.40	
	617 मध्य	.05 2.02	1169 दक्षिण	.01 0.40	
	762 मध्य	.08 3.24	1170 मध्य	.21 8.49	
	763 मध्य	.09 3.64	1554 पूर्व	.10 4.05	
	766 मध्य	.17 6.88			
	769 पूर्व	.09 3.64			
	770 पूर्व	.07 2.83			
	771 पूर्व	.06 2.43			

[सं० 11/5/71-सेक्टर एण्ड सेजिड/5]

S.O. 516.—Whereas by a Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals, S.O. No. 1596—dated 4th April, 1972 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right

[सं० 11/5/71-लेबर एण्ड लेजिस/5]

S.O. 516.—Whereas by a Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals, S.O. No. 1596—dated 4th April, 1972 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right

of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that Notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this Notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this Notification is hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State: West Bengal, District: Hooghly, Thana/Police Station: Dhaniakhali.

Village	Survey Nos.(Plot Nos.) and description of land		Extent (Area)	
			In acres	In ares
Bagnan J.L. 199-II	1008	Middle	.17	6.88
	1009	Middle	.14	5.67
	1010	East	.11	4.45
	1011	Middle	.06	2.43
	1030	North-East	.01	0.40
	1031	Middle	.11	4.45
	1033	South-West	.01	0.40
	1034	Middle	.15	6.07
	1036	South-West	.09	3.64
	1049	West	.15	6.07
	1193	South-West	.02	0.81
	1194	South-West	.01	0.40
	1195	Middle	.09	3.64
	1197	North-East	.005	0.20
	1199	North-East	.01	0.40
	1200	Middle	.14	5.67
	1202	Middle	.34	13.76
	1259	East	.10	4.05
	1260	Middle	.04	1.62
	1261	East	.01	0.40
	1262	Full	.03	1.21
	1263	Middle	.15	6.07
	1276	West	.01	0.40
	1305	Middle	.03	1.21
	1367	Middle	.42	17.00
	1368	South-West	.005	0.20
	1376	West	.09	3.64
	1377	West	.03	1.21
	1378	West	.02	0.81
	1379	South-West	.005	0.20
	1380	Middle	.27	10.92
	1443	East	.16	6.48
	1444	East	.16	6.48
	1508	East	.04	1.62
	1509	East	.08	3.24
	1510	East	.09	3.64
	1511	Middle	.04	1.62
	1512	Middle	.19	7.69
	1547	West	.01	0.40
	1548	Middle	.04	1.62
	1550	West	.02	0.81
	1551	Full	.03	1.21
	1552	Full	.04	1.62
	1553	East	.02	0.81
	1554	North-East	.005	0.20
	1558	East	.06	2.43
	1559	Full	.08	3.24
	1560	East	.22	8.90
	1561	West	.05	2.02

Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and Description of land		Extent (Area)	
			In acres	In ares
Bagnan J.L. 199-II—contd.	1568	West	.005	0.20
	1569	West	.09	3.64
	1570	East	.05	2.02
	1571	East	.05	2.02
	1572	Full	.10	4.05
	1573	East	.01	0.40
	1672	South-West	.01	0.40
	1690	North-East	.005	0.20
	1702	West	.05	2.02
	1703	Middle	.10	4.05
	1721	West	.02	0.81
	1722	West	.04	1.62
	1723	West	.02	0.81
	1760	East	.005	0.20
	1706	East	.13	5.26
	1708	East	.09	3.64
Parmeswarapore J.L. 200.	18	West	.08	3.24
	19	West	.12	4.86
	20	East	.01	0.40
	21	Middle	.34	13.76
	22	East	.07	2.83
	23	West	.10	4.05
	26	Middle	.12	4.86
	27	East	.14	5.67
	32	West	.15	6.07
	33	East	.16	6.48
	34	West	.03	1.21
	35	West	.02	0.81
	36	West	.02	0.81
	150	Middle	.07	2.83
	151	East	.02	0.81
	152	East	.01	0.40
Dakshinmalikpur J.L. 202.	153	North-East	.005	0.20
	154	Full	.03	1.21
	155	East	.04	1.62
	319	East	.03	1.21
	322	East	.12	4.86
	323	North-East	.02	0.81
	324	Middle	.18	7.29
	325	South-West	.02	0.81
	326	Middle	.18	7.29
	334	West	.09	3.64
	343	West	.17	6.88
	347	West	.05	2.02
	348	Middle	.25	10.11
	349	North-East	.06	2.43
	364	East	.02	0.81
	387	North-East	.005	0.20
	388	East	.07	2.83
	389	Middle	.26	10.52
	390	West	.05	2.02
	410	North-East	.005	0.20
Purandarapur J.L. 208.	207	East	.03	1.21
	208	East	.01	0.40
	210	West	.09	3.64
	212	West	.22	8.90
	214	West	.05	2.02
	215	West	.09	3.64
	216	North-East	.01	0.40
	217	East	.09	3.64
	218	South-West	.005	0.20
	268	West	.11	4.45
	269	East	.11	4.45
	275	East	.13	5.26
	276	East	.13	5.26
	277	Middle	.08	3.24
	278	West	.02	0.81
	290	West	.03	1.21
	299	West	.17	6.88
	300	North-East	.01	0.40
	301	Middle	.17	6.88
	302	Middle	.20	8.09
	322	East	.24	9.71
	487	East	.09	3.64
	488	Middle	.21	8.49
	490	West	.04	1.62
	491	Middle	.05	2.02
	492	North-East	.005	0.20
	496	North-East	.03	1.21
	498	Middle	.19	7.69
	499	Middle	.03	1.21

Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land		Extent (Area)		Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land		Extent (Area)	
			In acres	In ares				In acres	In ares
Purandarpur. J.L. 208—contd.	500	South-West	.01	0.40	Bajitpur J.L. 212—Contd.	1192	South-West	.01	0.40
	501	Middle	.11	4.45		1200	Middle	.28	11.33
	502	Middle	.08	3.24		1201	Middle	.13	5.26
	513	Middle	.27	10.92		1203	Middle	.10	4.05
	514	East	.09	3.64		1206	South-West	.01	0.40
	515	South-West	.005	0.20		1207	East	.16	6.48
	521	West	.06	2.43		1216	Middle	.10	4.05
	522	West	.07	2.83		1217	Middle	.12	4.86
	523	East	.18	7.29		1218	East	.01	0.40
	524	East	.05	2.02		1219	Middle	.11	4.45
	525	East	.07	2.83		1332	West	.06	2.43
	526	Middle	.12	4.86		1333	West	.02	0.81
	527	North-East	.01	0.40		1335	Middle	.07	2.83
	528	East	.03	1.21		1336	East	.06	2.43
	601	East	.07	2.83		1337	East	.16	6.48
	602	North-East	.005	0.20		1352	East	.09	3.64
	605	North-East	.005	0.20		1353	East	.20	8.09
	606	East	.005	0.20		1362	East	.01	0.40
	607	West	.21	8.49		1369	East	.07	2.83
	608	Middle	.19	7.69		1370	North-East	.005	0.20
	947	Middle	.29	11.74		1371	East	.02	0.81
	949	Middle	.12	4.86		1372	West	.16	6.48
Jot Mahes J.L. 210.	516	West	.03	1.21		1373	West	.08	3.24
	517	West	.06	2.43		1392	West	.08	3.24
	521	West	.10	4.05		1393	West	.01	0.40
	523	West	.01	0.40		1394	West	.01	0.40
	524	Middle	.19	7.69		1589	West	.14	5.67
	525	East	.10	4.05		1593	Middle	.10	4.05
	526	West	.12	4.86		1091	North-East	.02	0.81
	557	West	.06	2.43		1092	Middle	.09	3.64
	558	West	.01	0.40	Rudrani J.L. 189.	635	South-East	.005	0.20
	567	Middle	.38	15.38		636	Middle	.01	0.40
	568	East	.16	6.48		637	Middle	.07	2.83
	571	East	.17	6.88		639	East	.06	2.43
	572	East	.12	4.86		1018	East	.05	2.02
	573	East	.05	2.02		1019	West	.08	3.24
	585	East	.12	4.86		1034	West	.07	2.83
	586	East	.09	3.64		1035	Middle	.10	4.05
	588	East	.04	1.62		1038	East	.05	2.02
	589	West	.11	4.45		1040	East	.01	0.40
	590	West	.22	8.90		1041	Full	.03	1.21
	650	North-East	.005	0.20		1042	North-West	.005	0.20
	653	West	.02	0.81		1043	East	.17	6.68
Purba Keshabpur J.L. 211. Bajitpur J.L. 212.	324	North-East	.03	1.21		1050	East	.09	3.64
	997	Middle	.07	2.83		1051	East	.06	2.43
	1018	East	.10	4.05		1052	East	.01	0.40
	1052	Full	.005	0.20		1053	Full	.04	1.62
	1053	Middle	.09	3.64		1054	West	.08	3.24
	1054	Middle	.11	4.45		1064	West	.16	6.48
	1055	Middle	.05	2.02		1067	East	.03	1.21
	1056	East	.03	1.21		1068	East	.03	1.21
	1057	East	.06	2.43		1092	East	.17	6.88
	1058	East	.09	3.64		1245	Middle	.23	9.30
	1060	East	.05	2.02		1246	East	.06	2.43
	1061	Middle	.09	3.64		1247	Full	.03	1.21
	1062	South-West	.10	4.05		1248	West	.01	0.40
	1074	Middle	.07	4.83		1254	Middle	.13	5.26
	1075	South-West	.01	0.40		1255	Middle	.15	6.07
	1076	West	.005	0.20		1256	Middle	.12	4.86
	1077	Middle	.10	4.05		1257	West	.01	0.40
	1078	Middle	.08	3.24		1258	East	.08	3.24
	1079	South-West	.005	0.20		1804	West	.06	2.43
	1081	West	.01	0.40		1805	West	.08	3.24
	1082	Middle	.10	4.05		1860	East	.08	3.24
	1083	West	.05	2.02		1861	Middle	.08	3.24
	1084	Middle	.11	4.45		1870	West	.04	1.62
	1085	West	.08	3.24		1872	East	.04	1.62
	1086	East	.04	1.62	Chotokhanpur J.L. 192.	14	East	.01	0.40
	1088	North-East	.005	0.20		15	Full	.13	5.26
	1089	Middle	.04	1.62		16	West	.02	0.81
	1090	East	.01	0.40		19	Middle	.10	4.05
	1103	East	.07	2.83		20	Middle	.08	3.24
	1104	West	.08	3.24		22	North-East	.005	0.20
	1105	East	.01	0.40		23	Middle	.08	3.24
	1137	Middle	.08	3.24		73	Middle	.10	4.05
	1190	East	.02	0.81		74	North East	.007	0.28
	1191	West	.05	2.02		75	North-East	.005	0.20
						80	East	.03	1.21
						81	Middle	.25	10.11
						85	Middle	.09	3.64

Village	Survey Nos. (Plot.Nos.) and Description of land	Extent (Area)		Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent (Area)	
		In acres	In ares			In acres	In ares
Chotokhanpur J.L. 192—Contd.	184 Middle	.02	0.81	Nalitajole J.L. 214-II—Contd.	45 East	.02	0.81
	185 West	.01	0.40		46 Full	.12	4.86
	189 East	.06	2.43		47 Full	.10	4.05
	190 East	.07	2.83		48 Middle	.05	2.02
	191 East	.02	0.81		49 Middle	.02	0.81
	192 West	.005	0.20		50 South-East	.005	0.20
	210 West	.04	1.62		52 South-West	.01	0.40
	212 West	.06	2.43		569 West	.02	0.81
	213 West	.04	1.62		570 South-West	.01	0.40
	564 South-West	.005	0.20		572 South-West	.005	0.20
	565 Full	.01	0.40		586 West	.03	1.21
	567 Middle	.85	34.39		588 South-West	.01	0.40
					589 Full	.06	2.43
Noapara J.L. 193.	97 North-East	.005	0.20		590 West	.01	0.40
	98 West	.10	4.05		591 Middle	.08	3.24
	196 North-East	.005	0.20		595 Middle	.02	0.81
	202 East	.23	9.30		596 Full	.08	3.24
	203 East	.06	2.43		597 Middle	.14	5.67
	204 East	.16	6.48		599 North-East	.03	1.21
	205 West	.11	4.45		603 East	.06	2.43
	206 West	.02	0.81		610 North-East	.01	0.40
	209 Middle	.23	9.30		611 South	.03	1.21
	210 East	.13	5.26		612 Middle	.15	6.07
	283 North-East	.04	1.62		613 West	.01	0.40
	284 Middle	.21	8.49		614 Middle	.05	2.02
	285 West	.13	5.26		616 West	.15	6.07
	286 North-East	.005	0.20		617 Middle	.05	2.02
	287 East	.06	2.43				
	288 West	.06	2.43		762 Middle	.08	3.24
	316 West	.04	1.62		763 Middle	.09	3.64
	319 West	.04	1.62		766 Middle	.17	6.88
	320 East	.11	4.45		769 East	.09	3.64
	322 East	.06	2.43		770 East	.07	2.83
	398 East	.01	0.40		771 East	.06	2.43
	399 North-East	.01	0.40		878 North-East	.01	0.40
	1084 Middle	.31	12.54		879 East	.04	1.62
Hariharpur J.L. 201.	242 East	.09	3.64		880 West	.04	1.62
	246 East	.11	4.45		884 West	.09	3.64
	247 East	.04	1.62		885 Full	.05	2.02
	276 East	.01	0.40		886 East	.01	0.40
	277 Middle	.22	8.90		887 West	.09	3.64
	278 Middle	.13	5.26		888 North-East	.01	0.40
	279 Middle	.06	2.43		889 Middle	.16	6.48
	280 East	.07	2.83		891 South-West	.005	0.20
	289 West	.12	4.86		892 West	.01	0.40
	290 East	.01	0.40		920 West	.005	0.20
	292 East	.12	4.86		922 West	.04	1.62
	293 Middle	.17	6.88		923 West	.09	3.64
	298 West	.15	6.07		924 Full	.04	1.62
	300 Middle	.10	4.05		925 East	.05	2.02
	301 South	.01	0.40		926 East	.09	3.64
	402 East	.02	0.81		927 East	.10	4.05
	411 East	.05	2.02		1094 East	.10	4.05
	415 East	.07	2.83		1097 Middle	.22	8.90
	416 East	.09	3.64		1099 West	.14	5.67
	417 West	.08	3.24		1112 West	.11	4.45
	418 West	.02	0.81		1113 West	.03	1.21
	419 Middle	.10	4.05		1114 West	.02	0.81
	424 West	.14	5.67		1115 Middle	.04	1.62
	425 Middle	.23	9.30		1116 East	.03	1.21
	465 East	.10	4.05		1117 East	.04	1.62
	485 North-West	.06	2.43		1118 North-East	.01	0.40
	486 South	.11	4.45		1124 East	.20	8.09
	490 East	.12	4.86		1137 Middle	.06	2.43
	498 South-West	.005	0.20		1138 West	.04	1.62
Nalitajole J.L. 214-II.	11 West	.03	1.21		1139 Full	.04	1.62
	12 West	.06	2.43		1140 East	.04	1.62
	16 South-West	.005	0.20		1141 Full	.06	2.43
	17 West	.03	1.21		1142 East	.09	3.64
	21 West	.14	5.67		1149 North-East	.005	0.20
	22 North-East	.005	0.20		1150 Middle	.22	8.90
	23 Middle	.13	5.26				
	30 South-West	.005	0.20		1151 West	.05	2.02
	36 West	.02	0.81		1164 South-West	.01	0.40
	37 East	.13	5.26		1165 North-East	.08	3.24
	39 East	.04	1.62		1166 South-West	.01	0.40
	40 East	.005	0.20		1169 South-West	.01	0.40
	41 East	.01	0.40		1170 Middle	.21	8.49
					1554 East	.10	4.05

का० ग्रा० 517.—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का प्रजन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अधिसूचना का० ग्रा० सं० 896 तिथि 7 जनवरी, 1972 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है :

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार करने का विनिश्चय किया है ;

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है और, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम में सभी वस्तुओं के मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

राज्य; पश्चिमी बंगाल ; जिला हुगली ; पुलिस स्टेशन: धाना सिंहर

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट) संख्या	सीमा (क्षेत्र)
और भूमि का विवरण	एकड़ों में ए. आर. ई. एस. में	
भोला,	1437 मध्य	0.13 5.26
जे०एल०सं० 55	1440 उत्तर पूर्व	0.03 1.21
	1446 उत्तर पूर्व	0.005 0.20
	1447 पूर्व	0.02 0.81
	1449 पूर्व	0.04 1.62
	1450 मध्य	0.31 12.54
	1452 दक्षिण पश्चिम	0.005 0.20
	1468 दक्षिण पश्चिम	0.005 0.20
	1469 मध्य	0.11 4.45
	1470 पश्चिम	0.01 0.40
	1472 पूर्व	0.14 5.67
	1473 पूर्व	0.06 2.43
	1479 पूर्व	0.13 5.26
	1480 पश्चिम	0.01 0.40
	1483 पश्चिम	0.02 0.81
	1484 मध्य	0.11 4.45
	1485 पश्चिम	0.06 2.43
	1486 मध्य	0.13 5.26
	1487 पूर्व	0.05 0.02
	1489 पश्चिम	0.05 2.02
	1490 मध्य	0.11 4.45
	1491 उत्तर	0.03 1.21
	1509 पूर्व	0.06 2.43

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट सं०) और भूमि का विवरण	सीमा (क्षेत्र) एकड़ों में ए. आर. ई. एस. में
	1510 पूर्व	0.005 0.20
	1512 पूर्व	0.06 2.43
	1513 मध्य	0.10 4.05
	1514 पश्चिम	0.02 0.81
	1515 पूर्व	0.10 4.05
	1516 पश्चिम	0.14 5.67
	1518 पश्चिम	0.10 4.05
	1519 पूर्व	0.01 0.40
	1521 पूर्व	0.09 3.64
	1522 पश्चिम	0.14 5.67
	1523 दक्षिण पश्चिम	0.01 0.40
	1564 पश्चिम	0.05 2.02
	1732 पश्चिम	0.13 5.25
	1734 पश्चिम	0.13 5.26
	1738 मध्य	0.10 4.05
	1739 पूर्व	0.05 2.02
	1740 उत्तर पूर्व	0.01 0.40
मिलकी	229 पूर्व	0.20 8.09
जे०एल०-57	232 उत्तर-पूर्व	0.11 4.45
	234 पूर्व	0.005 0.20
	235 उत्तर पूर्व	0.05 2.02
	236 उत्तर	0.08 3.24
	237 उत्तर पूर्व	0.05 2.02
	238 दक्षिण	0.08 2.43
	239 दक्षिण पश्चिम	0.02 0.81
	298 दक्षिण पश्चिम	0.06 2.43
	299 दक्षिण पश्चिम	0.005 0.20
	301 दक्षिण पश्चिम	0.10 4.05
	302 दक्षिण पश्चिम	0.06 2.43
	313 दक्षिण पश्चिम	0.04 1.62
	314 मध्य	0.04 1.62
	315 मध्य	0.19 7.69
	316 उत्तर पूर्व	0.01 0.40
	317 उत्तर पूर्व	0.005 0.20
	333 उत्तर पूर्व	0.005 0.20
	334 मध्य	0.06 2.43
	335 दक्षिण पश्चिम	0.05 2.02
	336 पूर्व	0.07 2.83
	339 पूर्व	0.07 2.83
	341 पूर्व	0.08 3.24
	354 उत्तर पूर्व	0.005 0.20
	355 उत्तर पूर्व	0.07 2.83
	356 दक्षिण पश्चिम	0.06 2.43
	357 उत्तर	0.14 5.67
	358 पूर्व	0.05 2.02
	377 उत्तर पूर्व	0.005 0.20
	380 मध्य	0.23 9.30
	381 पश्चिम	0.005 0.20
	382 पश्चिम	0.005 0.20

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट नं०)	सीमा (क्षेत्र)	गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट नं०)	सीमा (क्षेत्र)
	और भूमि का विवरण	एकड़ों में ए.आर.ई.एस. में		और भूमि का विवरण	एकड़ों में ए.आर.ई.एस. में
सतगारा	350 उत्तर पूर्व	0.08 3.24		132 उत्तर पूर्व	0.03 1.21
	351 मध्य	0.08 3.24		201 उत्तर पूर्व	0.02 0.81
	352 उत्तर पूर्व	0.005 0.20		202 दक्षिण पश्चिम	0.05 2.02
संतोष बाटी	200 उत्तर पूर्व	0.03 1.21		203 दक्षिण पश्चिम	0.01 0.40
जे०एल०संख्या-59	201 मध्य	0.17 6.88		205 दक्षिण पश्चिम	0.02 0.81
	202 पूर्व	0.01 0.40		206 मध्य	0.15 6.07
	203 पूर्व	0.11 4.45		241 पूर्व	0.05 2.02
	207 उत्तर पूर्व	0.01 0.40		245 उत्तर पूर्व	0.01 0.40
	208 पूर्व	0.06 2.43		246 मध्य	0.11 4.45
	209 पश्चिम	0.03 1.21		247 पूर्व	0.03 1.21
	210 मध्य	0.09 3.64		249 उत्तर पूर्व	0.02 0.81
	211 पूर्व	0.05 2.02		250 मध्य	0.25 10.11
	212 पूर्व	0.11 4.45		259 पश्चिम	0.02 0.81
	213 दक्षिण-पश्चिम	0.01 0.40		260 मध्य	0.06 2.43
	221 उत्तर	0.02 0.81		261 मध्य	0.10 4.05
	224 पश्चिम	0.08 3.24		278 पश्चिम	0.06 2.43
	227 दक्षिण पश्चिम	0.05 0.20		2173 पूर्ण	0.03 1.21
	238 दक्षिण पश्चिम	0.05 2.02	मधु बाटी	9 पूर्व	0.10 4.08
	239 मध्य	0.10 4.05	जे०एल०नं० 65	10 दक्षिण पश्चिम	0.20 0.81
	240 पूर्व	0.17 6.88		11 पूर्व	0.06 2.43
	243 मध्य	0.04 1.62		12 दक्षिण पश्चिम	0.01 0.40
	244 उत्तर पूर्व	0.05 2.02		14 मध्य	0.07 2.83
	266 पूर्व	0.09 3.64		16 पूर्व	0.03 1.21
	267 मध्य	0.17 6.88		17 दक्षिण पश्चिम	0.10 4.05
	270 पश्चिम	0.05 2.02		18 पश्चिम	0.07 2.83
	271 दक्षिण पश्चिम	0.12 4.86		736 पूर्व	0.04 1.62
बालाराम बाटी	1 दक्षिण पश्चिम	0.005 0.20		744 मध्य	0.07 2.83
जे०एल०-60	7 दक्षिण पश्चिम	0.03 1.21		745 पश्चिम	0.005 0.20
	8 उत्तर पूर्व	0.11 4.45		746 पश्चिम	0.01 0.40
	9 दक्षिण पश्चिम	0.10 4.05	श्रीरामपुर	2524 पूर्व	0.03 1.21
	10 मध्य	0.23 9.30	जे०एल०-66	2525 उत्तर पूर्व	0.01 0.40
	15 पूर्व	0.07 2.83		2526 पश्चिम	0.03 1.21
	16 उत्तर पूर्व	0.05 2.03		2527 उत्तर पूर्व	0.09 3.64
	17 मध्य	0.08 3.24		2528 उत्तर पूर्व	0.01 0.40
	41 पश्चिम	0.13 5.25		2529 उत्तर पूर्व	0.01 0.40
	75 दक्षिण पश्चिम	0.005 0.20		2533 पूर्व	0.01 0.40
	76 दक्षिण पश्चिम	0.01 0.40		2534 पूर्व	0.06 2.43
	77 मध्य	0.22 8.90		2535 पूर्व	0.01 0.40
	78 पूर्व	0.11 4.45		2536 पूर्व	0.14 5.67
	85 मध्य	0.09 3.64		2537 मध्य	0.15 6.07
	86 पश्चिम	0.10 4.05		2538 मध्य	0.10 4.05
	124 दक्षिण पश्चिम	0.01 0.40		2539 दक्षिण पश्चिम	0.01 0.40
	125 मध्य	0.08 3.24		2540 पूर्व	0.06 2.43
	126 उत्तर पूर्व	0.02 0.81		2541 मध्य	0.05 2.02
	127 पूर्व	0.06 2.43		2589 पश्चिम	0.05 2.02
	128 मध्य	0.15 5.07		2593 पश्चिम	0.01 0.40
	130 दक्षिण पश्चिम	0.01 0.40		2594 पूर्व	0.08 3.24
	131 मध्य	0.19 7.69		2595 पूर्व	0.08 3.24

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट नं०)	सीमा (क्षेत्र)	गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट नं०)	सीमा (क्षेत्र)
	और भूमि का विवरण	एकड़ों में ए और ई एस में		और भूमि का विवरण	एकड़ों में ए और ई एस में
2596	पूर्व	0.06 2.43	3467	पश्चिम	0.12 4.86
2597	पूर्व	0.02 0.81	3468	मध्य	0.10 4.05
2646	मध्य	0.07 2.83	3469	मध्य	0.10 4.05
2647	मध्य	0.06 2.43	3470	दक्षिण पश्चिम	0.005 0.20
2648	मध्य	0.07 2.83	3471	पूर्ण	0.08 3.24
2692	उत्तर पूर्व	0.07 2.83	3472	पश्चिम	0.06 2.43
2699	पश्चिम	0.02 0.81	3473	पश्चिम	0.03 1.21
2701	पश्चिम	0.12 4.86	3474	पश्चिम	0.01 0.40
2702	मध्य	0.14 5.67	3475	दक्षिण पश्चिम	0.005 0.20
2703	पूर्व	0.20 8.09	श्री राम पुर 3544	पश्चिम	0.01 0.40
2704	उत्तर पूर्व	[0.01 0.40	जै०एल०संख्या-66 3545	पश्चिम	0.02 0.81
2711	उत्तर पूर्व	0.02 0.81	3547	पश्चिम	0.05 2.02
2712	पूर्व	[0.05 0.02	3549	पश्चिम	0.11 4.45
2713	पूर्व	0.08 3.24	3550	पूर्व	0.005 0.20
2714	पश्चिम	0.04 1.62	3553	पूर्व	0.12 4.86
2718	पश्चिम	0.01 1.40	3554	मध्य	0.17 6.88
2719	पश्चिम	0.40 1.62	3582	पूर्व	0.04 1.62
2720	पश्चिम	0.04 1.62	3883	पूर्व	0.04 1.62
2721	पूर्व	0.12 4.86	3584	मध्य	0.09 3.64
2722	मध्य	0.10 4.05	3591	उत्तर पूर्व	0.005 0.20
2723	उत्तर पूर्व	0.005 0.20	3592	पश्चिम	0.04 1.62
2724	पूर्व	0.05 2.02	3593	पूर्व	0.09 3.64
2725	मध्य	0.19 7.69	3594	पूर्व	0.08 3.34
2726	पूर्व	0.005 0.20	3601	पूर्व	0.04 1.62
2839	पूर्व	0.01 0.40	3603	मध्य	0.04 1.62
2840	पूर्व	0.08 3.24	3604	मध्य	0.04 1.62
2841	पश्चिम	0.05 2.02	3614	पूर्व	0.11 4.45
2844	मध्य	0.14 5.67	3615	मध्य	0.12 4.86
2845	पश्चिम	0.14 5.67	3616	पश्चिम	0.10 4.05
2846	पूर्व	0.07 2.83	3618	पश्चिम	0.01 0.40
2852	पूर्व	0.005 0.20	3619	मध्य	0.03 1.21
2853	पूर्व	0.05 2.02	3620	पश्चिम	0.06 6.48
2854	मध्य	0.09 3.64	3621	मध्य	0.05 2.02
2855	मध्य	0.11 4.45	3623	उत्तर पूर्व	0.01 0.40
2856	पश्चिम	0.10 4.05	3626	पूर्व	0.05 2.02
2863	पश्चिम	0.01 0.40	3627	मध्य	0.07 2.83
2864	पूर्व	0.16 6.48	3646	पश्चिम	0.07 2.83
3401	पूर्व	0.13 5.26	3648	पश्चिम	0.01 0.40
3402	उत्तर पूर्व	0.02 0.81	3649	पूर्व	0.18 7.29
3403	पूर्ण	0.07 2.83	3651	पश्चिम	0.07 2.83
3404	पूर्व	0.005 0.20	3663	पूर्व	0.05 2.02
3405	मध्य	0.06 2.43	बासूधारी 743	उत्तर पूर्व	0.11 4.45
3406	मध्य	0.10 4.05	जै०एल०संख्या-70 744	दक्षिण	0.04 1.62
3407	पश्चिम	0.01 0.40	748	पश्चिम	0.06 2.43
3408	पूर्व	0.23 9.30	750	मध्य	0.22 8.90
3409	पूर्ण	0.08 3.24	751	पूर्व	0.16 6.48
3410	पश्चिम	0.005 0.20	757	पश्चिम	0.14 5.67
3411	मध्य	0.15 6.07	758	पश्चिम	0.13 5.26
3412	पूर्व	0.24 9.71	759	मध्य	0.02 0.81
3422	पूर्व	0.11 4.45			
3423	पूर्व	0.005 0.20			

गाँव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट नं०)	सीमा (क्षेत्र)		गाँव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट नं०)	सीमा (क्षेत्र)	
	और भूमि का विवरण	एकड़ों में ए. आर. ई. एस. में			और भूमि का विवरण	एकड़ों में ए. आर. ई. एस. में	
	773 दक्षिण पश्चिम	0.02	0.81	219 पूर्व		0.03	1.21
	920 पश्चिम	0.18	7.29	220 दक्षिण पूर्व		0.005	0.20
	921 पश्चिम	0.20	8.09	221 पूर्व		0.07	2.83
	923 पश्चिम	0.16	6.48	222 पश्चिम		0.06	2.43
	924 मध्य	0.11	4.45	223 उत्तर पश्चिम		0.01	0.40
	925 पूर्व	0.09	3.64	224 पूर्व		0.06	2.43
	926 उत्तर पूर्व	0.01	0.40	225 उत्तर पूर्व		0.01	0.40
	938 दक्षिण पश्चिम	0.08	3.24	242 पूर्व		0.09	3.64
गोपालपोटा	243 पूर्व	0.02	0.31	273 पूर्व		0.005	0.20
जे०एल०नं०-71	246 पूर्व	0.06	2.43	274 पूर्व		0.13	5.26
	247 उत्तर	0.03	1.21	275 पूर्व		0.08	3.24
				295 मध्य		0.01	0.40
				296 मध्य		0.11	4.45
				297 मध्य		0.20	8.09
बिरोधवर बाटी	5 पश्चिम	0.01	0.40	309 पश्चिम		0.04	1.62
जे०एल०संख्या-72	6 पश्चिम	0.03	1.31	310 पश्चिम		0.11	4.45
	7 पूर्व	0.07	2.83	311 पूर्व		0.01	0.40
	9 पूर्व	0.08	3.24	313 मध्य		0.10	4.05
	10 मध्य	0.11	4.45	314 पश्चिम		0.12	4.96
	11 मध्य	0.06	2.43	315 पश्चिम		0.24	9.72
	12 दक्षिण पश्चिम	0.01	0.40	317 पश्चिम		0.02	0.81
	14 उत्तर पूर्व	0.04	1.62	318 पश्चिम		0.10	4.06
	15 मध्य	0.19	7.69	319 पश्चिम		0.06	2.43
	16 पश्चिम	0.08	3.24	330 पश्चिम		0.18	7.29
	149 पश्चिम	0.06	2.02	333 पश्चिम		0.21	8.49
	150 पूर्व	0.08	3.24	334 मध्य		0.22	8.90
	153 मध्य	0.06	2.02	335 पूर्व		0.04	1.62
	184 पूर्व	0.02	0.81	347 पूर्व		0.25	10.11
	185 पश्चिम	0.04	1.62	358 मध्य		0.07	2.83
	186 पश्चिम	0.06	2.02	374 दक्षिण पश्चिम		0.01	0.40
	189 पश्चिम	0.17	6.88	375 पश्चिम		0.01	0.40
	190 मध्य	0.19	7.69	377 पश्चिम		0.01	0.40
	191 पूर्व	0.14	5.67	378 पश्चिम		0.02	0.81
	193 मध्य	0.14	5.67	379 पश्चिम		0.05	2.02
	194 मध्य	0.06	2.43	382 पश्चिम		0.005	0.20
	195 पश्चिम	0.01	0.40	383 मध्य		0.10	4.06
	197 मध्य	0.13	5.26	384 उत्तर		0.005	0.20
	198 मध्य	0.07	2.83	385 मध्य		0.15	6.07
	199 उत्तर पश्चिम	0.01	0.40	386 पश्चिम		0.14	5.67
	201 पश्चिम	0.02	0.81	509 पश्चिम		0.09	3.64
	203 पश्चिम	0.01	0.40	559 मध्य		0.03	1.21
	208 उत्तर पश्चिम	0.005	0.20	574 पूर्व		0.01	0.40
	209 पश्चिम	0.02	0.81	575 मध्य		0.12	4.86
	214 दक्षिण पूर्व	0.005	0.20	578 पूर्व		0.02	0.81
	215 पश्चिम	0.11	4.45	579 पूर्व		0.005	0.20
	216 मध्य	0.08	3.24	582 मध्य		0.07	2.83
	217 दक्षिण	0.03	1.21	583 मध्य		0.07	2.83
	218 मध्य	0.15	6.07	584 मध्य		0.10	4.05

गांव	सर्वेक्षण संख्या (प्लॉट नं०)	सीमा (क्षेत्र)	Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent (Area)	
					In Acres	In Are
		एकड़ों में एभार ई एस में				
जगतनगर	1869	दक्षिण पश्चिम		1472 East	0.14	5.67
जे०एल०संख्या-73	1871	मध्य		1473 East	0.06	2.43
	1873	पूर्व		1479 East	0.13	5.26
	1875	उत्तर पूर्व		1480 West	0.01	0.40
	1877	पूर्व		1483 West	0.02	0.81
	2022	उत्तर पूर्व		1484 Middle	0.11	4.45
	2023	पूर्व		1485 West	0.06	2.43
	2024	मध्य		1486 Middle	0.13	5.26
	2025	पश्चिम		1487 East	0.05	2.02
	2032	मध्य		1489 West	0.05	2.02
	2033	उत्तर पूर्व		1490 Middle	0.11	4.45
	2034	उत्तर पूर्व		1491 North	0.03	1.21
	2035	मध्य		1509 East	0.06	2.43
	2036	पश्चिम		1510 East	0.005	0.20
	2037	पश्चिम		1512 East	0.06	2.43
	2230	पश्चिम		1513 Middle	0.10	4.05
				1514 West	0.02	0.81
				1515 East	0.10	4.05
				1516 West	0.14	5.67
				1518 West	0.10	4.05
				1519 East	0.01	0.40
				1521 East	0.09	3.64
				1522 West	0.14	5.67
				1523 South-West	0.01	0.40
				1564 West	0.05	2.02
				1732 West	0.13	5.26
				1734 West	0.13	5.26
				1738 Middle	0.10	4.05
				1739 East	0.05	2.02
				1740 North-East	0.01	0.40

[सं 11/5/71-लेबर एण्ड लजस/I]

भार०एल० चोपड़ा, भ्रवर सचिव,

Milki,
J. L. No. 57.

S.O. 517—Whereas by a Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals, S.O.No. 896 dated 7th January, 1972 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that Notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this Notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this Notification is hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State : West Bengal, District : Hooghly, Police Stn/Thana : Singur.

Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent (Area)	
		In Acres	In Area
Bhola, J. L. No. 55	1437 Middle	0.13	5.26
	1440 North-East	0.03	1.21
	1446 North-East	0.005	0.20
	1447 East	0.02	0.81
	1449 East	0.04	1.62
	1450 Middle	0.31	12.54
	1452 South-West	0.005	0.20
	1468 South-West	0.005	0.20
	1469 Middle	0.11	4.45
	1470 West	0.01	0.40

Satgara,
J. L. No. 58.Santosh Bati,
J. L. No. 59.

229 East	0.20	8.09
232 North-East	0.11	4.45
234 East	0.005	0.02
235 North-East	0.05	2.02
236 North	0.08	3.24
237 North-East	0.05	2.02
238 South	0.06	2.43
239 South-West	0.02	0.81
298 South-West	0.06	2.43
299 South-West	0.005	0.20
301 South-West	0.10	4.05
302 South-West	0.06	2.43
313 South-West	0.04	1.62
314 Middle	0.04	1.62
315 Middle	0.19	7.69
316 North-East	0.01	0.40
317 North-East	0.005	0.20
333 North-East	0.005	0.20
334 Middle	0.06	2.43
335 South-West	0.05	2.02
336 East	0.07	2.83
339 East	0.07	2.83
341 East	0.08	3.24
354 North-East	0.005	0.20
355 North-East	0.07	2.83
356 South-West	0.06	2.43
357 North	0.14	5.67
358 East	0.05	2.02
377 North-East	0.005	0.20
380 Middle	0.23	9.30
381 West	0.005	0.20
382 West	0.005	0.20
350 North-East	0.08	3.24
351 Middle	0.08	3.24
352 North-East	0.005	0.20
200 North-East	0.03	1.21
201 Middle	0.17	6.88
202 East	0.01	0.40
203 East	0.11	4.45
207 North-East	0.01	0.40
208 East	0.06	2.43
209 West	0.03	1.21
210 Middle	0.09	3.64
211 East	0.05	2.02
212 Full	0.11	4.45
213 South-West	0.01	0.40
221 North	0.02	0.81
224 West	0.08	3.24

Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent (Area)		Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent (Area)	
		In Acres	In Acre			In Acres	In Acre
Baram Bati, J. L. No. 60.	227 South-West	0.05	0.20	Srirampur, J. L. No. 66.	2589 West	0.05	2.02
	238 South-West	0.05	2.02		2593 West	0.01	0.40
	239 Middle	0.10	4.05		2594 Full	0.08	3.24
	240 East	0.17	6.88		2595 Full	0.08	3.24
	243 Middle	0.04	1.62		2596 East	0.06	2.43
	244 North-East	0.05	2.02		2597 East	0.02	0.81
	266 East	0.09	3.64		2646 Middle	0.07	2.83
	267 Middle	0.17	6.88		2647 Middle	0.06	2.43
	270 West	0.05	2.02		2648 Middle	0.07	2.83
	271 South-West	0.12	4.86		2692 North-East	0.07	2.83
	1 South-West	0.005	0.20		2699 West	0.02	0.81
	7 South-West	0.03	1.21		2701 West	0.12	4.86
	8 North-East	0.11	4.45		2702 Middle	0.14	5.67
	9 South-West	0.10	4.05		2703 East	0.20	8.09
	10 Middle	0.23	9.30		2704 North-East	0.01	0.40
	15 East	0.07	2.83		2711 North-East	0.02	0.81
	16 North-East	0.05	2.02		2712 East	0.05	2.02
	17 Middle	0.08	3.24		2713 East	0.08	3.24
	41 West	0.13	5.26		2714 West	0.04	1.62
	75 South-West	0.005	0.20		2718 West	0.01	0.40
	76 South-West	0.01	0.40		2719 West	0.04	1.62
	77 Middle	0.22	8.90		2720 West	0.04	1.62
	78 East	0.11	4.45		2721 East	0.12	4.86
	85 Middle	0.09	3.64		2722 Middle	0.10	4.05
	86 West	0.10	4.05		2723 North-East	0.005	0.20
	124 South-West	0.01	0.40		2724 East	0.05	2.02
Madhu Bati, J. L. No. 65.	125 Middle	0.08	3.24		2725 Middle	0.19	7.69
	126 North-East	0.02	0.81		2726 East	0.005	0.20
	127 East	0.06	2.43		2839 East	0.01	0.40
	128 Middle	0.15	6.07		2840 East	0.08	3.24
	130 South-West	0.01	0.40		2841 West	0.05	2.02
	131 Middle	0.19	7.69		2844 Middle	0.14	5.67
	132 North-East	0.03	1.21		2845 West	0.14	5.67
	201 North-East	0.02	0.81		2846 East	0.07	2.83
	202 South-West	0.05	2.02		2852 East	0.005	0.20
	203 South-West	0.10	4.05		2853 East	0.05	2.02
	205 South-West	0.02	0.81		2854 Middle	0.09	3.64
	206 Middle	0.15	6.07		2855 Middle	0.11	4.45
	241 East	0.05	2.02		2856 West	0.10	4.05
	245 North-East	0.01	0.40		2863 West	0.01	0.40
	246 Middle	0.11	4.45		2864 East	0.16	6.48
	247 East	0.03	1.21		3401 East	0.13	5.26
	249 North-East	0.02	0.81		3402 North-East	0.02	0.81
	250 Middle	0.25	10.11		3403 Full	0.07	2.83
	259 West	0.02	0.81		3404 East	0.005	0.20
	260 Middle	0.06	2.43		3405 Middle	0.06	2.43
	261 Middle	0.10	4.05		3406 Middle	0.10	4.05
	278 West	0.06	2.43		3407 West	0.01	0.40
	2173 Full	0.03	1.21		3408 East	0.23	9.30
Srirampur, J. L. No. 66.	9 East	0.10	4.05		3409 Full	0.08	3.24
	10 South-West	0.20	0.81		3410 West	0.005	0.20
	11 Full	0.06	2.43		3411 Middle	0.15	6.07
	12 South-West	0.01	0.40		3412 East	0.24	9.71
	14 Middle	0.07	2.83		3422 East	0.11	4.45
	16 East	0.03	1.21		3423 East	0.005	0.20
	17 South-West	0.10	4.05		3467 West	0.12	4.86
	18 West	0.07	2.83		3468 Middle	0.10	4.05
	736 East	0.04	1.62		3469 Middle	0.10	4.05
	744 Middle	0.07	2.83		3470 South-West	0.005	0.20
	745 West	0.005	0.20		3471 Full	0.80	3.24
	746 West	0.01	0.40		3472 West	0.06	2.43
	2524 East	0.03	1.21		3473 West	0.03	1.21
	2525 North-East	0.01	0.40	Srirampur, J. L. No. 66.	3474 West	0.01	0.40
	2526 West	0.03	1.21		3475 South-West	0.005	0.20
	2527 North-East	0.09	3.64		3544 West	0.01	0.40
	2528 North-East	0.01	0.40		3545 West	0.02	0.81
	2529 North-East	0.01	0.40		3547 West	0.05	2.02
	2533 East	0.01	0.40		3549 West	0.11	4.45
	2534 East	0.06	2.43		3550 East	0.005	0.20
	2535 Full	0.01	0.40		3553 East	0.12	4.86
	2536 East	0.14	5.67		3554 Middle	0.17	6.88
	2537 Middle	0.15	6.07		3582 East	0.04	1.62
	2538 Middle	0.10	4.05		3583 East	0.04	1.62
	2539 South-West	0.01	0.40		3584 Middle	0.09	3.64
	2540 Full	0.06	2.43		3591 North-East	0.005	0.20
	2541 Middle	0.05	2.02		3592 West	0.04	1.62
					3593 East	0.09	3.64

Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent (Area)		Village	Survey Nos. (Plot Nos.) and description of land	Extent (Area)	
		In Acres	In Areas			In acres	In area
Basubati, J. L. No. 70.	3594 East	0.08	3.24	Biseswar Bati J. L. No. 72. (contd.)	225 North-East	0.01	0.40
	3601 East	0.04	1.62		242 East	0.09	3.64
	3603 Middle	0.04	1.62		273 East	0.005	0.20
	3604 Middle	0.04	1.62		274 East	0.13	5.26
	3614 East	0.11	4.45		275 East	0.08	3.24
	3615 Middle	0.12	4.86		295 East	0.01	0.40
	3616 West	0.10	4.05		296 Middle	0.11	4.45
	3618 West	0.01	0.40		297 Middle	0.20	8.09
	3619 Middle	0.03	1.21		309 West	0.04	1.62
	3620 West	0.16	6.48		310 West	0.11	4.45
	3621 Middle	0.05	2.02		311 East	0.01	0.40
	3623 North-East	0.01	0.40		313 Middle	0.10	4.05
	3626 East	0.05	2.02		314 West	0.12	4.86
	3627 Middle	0.07	2.83		315 West	0.24	9.72
	3646 West	0.07	2.83		317 West	0.02	0.81
	3648 West	0.01	0.40		318 West	0.10	4.05
	3649 East	0.18	7.29		319 West	0.06	2.43
	3651 West	0.07	2.83		330 West	0.18	7.29
	3663 East	0.05	2.02		333 West	0.21	8.49
	743 North-East	0.11	4.45		334 Middle	0.22	8.90
	744 South	0.04	1.62		335 East	0.04	1.62
	748 West	0.06	2.43		347 East	0.25	10.11
	750 Middle	0.22	8.90		358 Middle	0.07	2.83
	751 East	0.16	6.48		374 South-West	0.01	0.40
	757 West	0.14	5.67		375 West	0.01	0.40
	758 West	0.13	5.26		377 West	0.01	0.40
	759 Middle	0.02	0.81		378 West	0.02	0.81
Gohailopta, J. L. No. 71	773 South-West	0.02	0.81		379 West	0.05	2.02
	920 West	0.18	7.29		382 West	0.005	0.20
	921 West	0.20	8.09		383 Middle	0.10	4.05
	923 West	0.16	6.48		384 North	0.005	0.20
	924 Middle	0.11	4.45		385 Middle	0.15	6.07
	925 East	0.09	3.64		386 West	0.14	5.67
	926 North-East	0.01	0.40		509 West	0.09	3.64
	938 South-West	0.08	3.24		559 Middle	0.03	1.21
	243 East	0.02	0.81		574 East	0.01	0.40
	246 East	0.06	2.43		575 Middle	0.12	4.86
Bisewar Bati J. L. No. 72	247 North	0.03	1.21		578 East	0.02	0.81
	5 West	0.01	0.40	Jagatnagar J. L. No. 73	579 East	0.005	0.20
	6 West	0.03	1.21		582 Middle	0.07	2.83
	7 East	0.07	2.83		583 Middle	0.07	2.83
	9 East	0.08	3.24		584 Middle	0.10	4.05
	10 Middle	0.11	4.45		1869 South-West	0.005	0.20
	11 Middle	0.06	2.43		1871 Middle	0.22	8.90
	12 South-West	0.01	0.40		1873 East	0.05	2.02
	14 North-East	0.04	1.62		1875 North-East	0.005	0.20
	15 Middle	0.19	7.69		1877 East	0.05	2.02
	16 West	0.08	3.24		2022 North-East	0.05	2.02
	149 West	0.05	2.02		2023 East	0.02	0.81
	150 East	0.08	3.24		2024 Middle	0.03	1.21
	153 Middle	0.05	2.02		2025 West	0.08	3.24
	184 East	0.02	0.81		2032 Middle	0.11	4.45
	185 West	0.04	1.62		2033 North-East	0.04	1.62
	188 West	0.05	2.02		2034 North-East	0.005	0.20
	189 West	0.17	6.88		2035 Middle	0.14	5.67
	190 Middle	0.19	7.69		2036 West	0.02	0.81
	191 East	0.14	5.67		2037 West	0.03	1.21
	193 Middle	0.14	5.67		2230 West	0.02	0.81
	194 Middle	0.06	2.43				
	195 West	0.01	0.40				
	197 Middle	0.13	5.26				
	198 Middle	0.07	2.83				
	199 North-West	0.01	0.40				
	201 West	0.02	0.81				
	203 West	0.01	0.40				
	208 North-West	0.005	0.20				
	209 West	0.02	0.81				
	214 South-East	0.005	0.20				
	215 West	0.11	4.45				
	216 Middle	0.08	3.24				
	217 South	0.03	1.21				
	218 Middle	0.15	6.07				
	219 East	0.03	1.21				
	220 South-East	0.005	0.20				
	221 East	0.07	2.83				
	222 West	0.06	2.43				
	223 North-West	0.01	0.40				
	224 East	0.06	2.43				

[No. 11/5/71—L & L/I]

R. N. CHOPRA, Under Secretary

वित्त विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1973

सार्वजनिक सूचना

का. आ. 518.—केंद्रीय सरकार जांन्स एफ-1 तथा एफ-7 (फ्रैंड्स कालोनी तथा आखला) के क्षेत्रीय विकास योजना में नीचे लिखे संशोधन करने का विचार कर रही हैं। उन्हें जनता की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है। इन संशोधनों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति और सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सचिव, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था

इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखकर भेज सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दे व अपना नाम तथा पता भी दें।

संशोधन

(ए) लगभग 1.12 हेक्टर (2.8 एकड़) का क्षेत्र जो उत्तर में फ्रेंड्स कालोनी, पूर्व मथुरा रोड़, दक्षिण में इन्स्टी-च्युशनल क्षेत्र तथा पश्चिम में रेलवे लाइन द्वारा घिरा हुआ है, जोन एफ-1 तथा एफ-7 (फ्रेंड्स कालोनी तथा ओखला) के संयुक्त क्षेत्रीय विकास योजना में यह क्षेत्र रेलवे स्टेशन तथा सरकूलेशन के लिये निर्दिष्ट किया गया था, इसे अब आवासीय उपयोग में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

(बी) लगभग 2.5 हेक्टर (6.2 एकड़) का क्षेत्र जो उत्तर में ईश्वर इन्डस्ट्रीज तथा गॉडरेज भूखण्डों, पूर्व में मथुरा रोड़, दक्षिण में ग्लैक्सो लैबोरेट्रीज तथा पश्चिम में रेलवे भूमि द्वारा घिरा हुआ है, जोन एफ-1 तथा एफ-7 (फ्रेंड्स कालोनी तथा ओखला) के क्षेत्रीय विकास योजना में सधु उद्योगों "लाइट मैन्युफैक्चरिंग" के लिये यह क्षेत्र निर्दिष्ट किया गया था, इसे अब "पार्किंग एवं सरकूलेशन" के उपयोग हेतु परिवर्तित किया जाना है।

शनिवार को छोड़कर और किसी भी कार्यशील दिन में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली-1 में उक्त अधीन में संशोधन के मानचित्रों का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं. एफ. 16(117)/71-एम. पी.]

हृदय नाथ फोतेदार, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 24th February, 1973

PUBLIC NOTICE

S.O. 518.—The following modifications which the central Government proposes to make in the zonal development plan for zones F-1 and F-7 (Friends colony and Okhla) is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objection or suggestions should also give his name and address.

Modifications

- An area measuring about 1.12 hec. (2.8 acres) surrounded by Friends colony in the north, Mathura Road in the east, institutional area in the south and railway line in the west, earmarked for Railway Station and circulation in the composite zonal development plan for zone F-1 and F-7 (Friends colony and Okhla) is proposed to be changed to residential use.
- An area measuring about 2.5 hec. (6.2 acres) surrounded by Ishwar Industries and Godrej plots in the north, Mathura Road in the east, Glaxo Laboratories in the south and Railway Land in the west, earmarked for "Light Manufacturing" in the zonal development plan for zone F-1 and F-7 (Friends colony and Okhla) is proposed to be changed for "Parking and Circulation".

The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays within the period referred to above.

H. N. FOTEDAR, Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1973

आदेश

का. आ. 519.—आई. डी. आर. ए.—उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एम्. विकास परिषद् (कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नीलिखित व्यक्तियों को विद्युत ऊर्जा का जनिमरण, पारंपरण और वितरण करने के लिए बिजली की मांटरो और मशीनों तथा उपकरणों के निर्माण अथवा उत्पादन रत अनुसूचित उद्योगों (घरेलू काम में आने वाले मोटरों तथा पैनल यंत्रों को छोड़ कर) की विकास परिषद् का, जिसे भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ./आई. डी. आर. ए/8/5 दिनांक 25 नवम्बर, 1972 के द्वारा पुनर्गठित और स्थापित किया गया था सदस्य नियुक्त करती हैं :—

- श्री एस. के. भाटिया, निदेशक, वैद्युत उद्योगों का अनुसंधान तथा विकास संगठन, पिपलानी, भोपाल।
- श्री एच. आर. कुलकर्णी, प्रबंधक, इण्डियन कंसोर्टियम फार पावर प्राजेक्ट्स (प्रा.) लि., चंद्र लोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली।
- श्री सारा सिंह वियोगी, एडवोकेट, श्रम शिविर, तानसेन मार्ग, बिड़ला नगर, ग्वालियर-4।
- श्री पी. बी. मथाई, अधीक्षक (वैद्युत), सी. ई. एण्ड डी. बी. एच. एस. एल. रांची।

केंद्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि उक्त आदेश में निम्नीलिखित संशोधन किया जाएगा :—

- श्री एस. एन. नरसिंह राव से संबंधित प्रविष्टि सं. 20 के पश्चात् निम्नीलिखित प्रविष्टियां निविष्ट की जाएंगी, अर्थात् :—
- श्री एस. के. भाटिया, निदेशक, वैद्युत उद्योगों का अनुसंधान तथा विकास संगठन पिपलानी, भोपाल।
- श्री एच. आर. कुलकर्णी, प्रबंधक, इण्डियन कंसोर्टियम फार पावर प्राजेक्ट्स (प्रा.) लि., चंद्र लोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली।
- श्री सारा सिंह वियोगी, श्रम शिविर, तानसेन मार्ग, बिड़ला नगर, ग्वालियर-4।
- श्री पी. बी. मथाई, अधीक्षक (वैद्युत), सी. ई. एण्ड डी. बी. एच. एस. एल., रांची।

[सं. ई. ई. आई-29(18)/72]

आर. कृष्णस्वामी, उप-सचिव

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 12th February, 1973

ORDER

S.O. 519.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industrial (Dev. & Reg.) Act, 1951 (65 of 1951) Read with Rules 2, 4 & 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the following persons to be members of

the Development Council for the scheduled industries engaged in the manufacture or production of electric motors and of machinery and equipment for the generation transmission and distribution of electric energy (excluding house service meters and panel instruments) which was reconstituted and established by Order No. S.O./IDRA/615, dated 25th November, 1972 of the Government of India, Ministry of Industrial Development:—

1. Shri S. K. Bhatia, Director, Research & Development Organisation for Electrical Industries, Piplani, Bhopal.
2. Shri H. R. Kulkarni, Manager, India Consortium for Power Projects (P) Ltd., Chanderlock Building, Janpath, New Delhi.
3. Shri Tara Singh Viyogi, Advocate, Shram Shivir, Tansen Marg, Birlanagar, Gwalior-4.
4. Shri P. V. Mathai, Superintendent (Electrical) CE & DB, HSL, Ranchi.

The Central Government also directs that the following amendments shall be made in the said order:—

- (1) After entry No. 20 relating to Shri S. N. Narasinga Rao, the following entries shall be inserted, namely:—
21. Shri S. K. Bhatia, Director, Research & Development Organisation for Electrical Industries, Piplani, Bhopal.
22. Shri H. R. Kulkarni, Manager, India Consortium for Power Projects (P) Ltd., Chanderlock Building Janpath, New Delhi.
23. Shri Tara Singh Viyogi, Advocate, Shram Shivir, Tansen Marg, Birlanagar, Gwalior-4.
24. Shri P. V. Mathai, Superintendent (Electrical), CE & DB, HSL, Ranchi.

[No. EEI-29(18)/72]

R. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1973

आदेश

का. आ. 520.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 27 मार्च, 1962 की अधिसूचना संख्या 16-15/61-वि-1 द्वारा केंद्रीय सरकार न निर्देश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिये 'लाइसेंस-सिआइएन-मीडिसिना सिरुर्गिया' यूनिवर्सिटी आव वेलेन्सिया (स्पेन) द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी,

और यतः डा. परेडा अर्टिज डे जारते अमालिया को जिसके पास उक्त अर्हता है धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल नजारथ अस्पताल, शिलांग असम के साथ संबंध है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केंद्रीय सरकार एतद् द्वारा—

- (1) 13 अक्टूबर, 1972 से दस वर्ष की अवधि

अथवा

- (2) उस अवधि को जब तक डा. परेडा अर्टिज डे जारते अमालिया नजारथ अस्पताल शिलांग (असम) के साथ संबंध रहती है, जो

भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा. मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[प. सं. बी 11016/26/72-एम.पी.टी.]

क. सत्यनारायण, उप सचिव।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (Department of Health)

New Delhi, the 5th February, 1973

ORDER

S.O. 520.—WHEREAS by notification of the Government of India in the former Ministry of Health No. 16-15/61-MI, dated the 27th March, 1962, the Central Government has directed that the medical qualification, "Licenciado en Medicina Cirugia" granted by the University of Valencia (Spain) shall be a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

AND WHEREAS Dr. Pereda Ortiz de Zarate Amalia, who possesses the said qualification is for the time being attached to the Nazareth Hospital, Shillong Assam) for the purposes of charitable work,

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

- (i) a period of two years with effect from the 13th October, 1972, or
- (ii) the period during which Dr. Pereda Ortiz de Zarate Amalia is attached to the said Nazareth Hospital, Shillong (Assam), whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/26/72-MPT]

K. SATYANARAYANA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1973

का. आ. 521.—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केंद्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (1940 का 23) की धारा 12 तथा 13 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात् बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धाराओं द्वारा यथा अपेक्षित उन सब व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

2. ऐसे किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व किसी व्यक्ति से प्रारूप के बारे में प्राप्त किये जायें, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

नियमों का प्रारूप:—

1. संक्षिप्त नाम:—

इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1973 होगा।

2. नये नियम, 134 का अन्तःस्थापन

औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,—

नियम 134 के पश्चात् निम्नीलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“134 के ऐसी प्रसाधन सामग्रियों के आयात का प्रतिषिद्ध होगा जिनमें हेक्साक्लोरोफीन अन्तर्निहित हो—

काँई ऐसी प्रसाधन सामग्री आयात नहीं की जायेगी जिसमें हेक्साक्लोरोफीन अन्तर्निहित हो ।”

3. नये नियम 144क का अन्तःस्थापन

उक्त नियम में नियम 144 के पश्चात् निम्नीलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“144 के ऐसी प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण का प्रतिषिद्ध होगा, जिनमें हेक्साक्लोरोफीन अन्तर्निहित हो—

काँई ऐसी प्रसाधन सामग्री विक्रय और वितरण के लिये विनिर्मित नहीं की जायेगी, जिसमें हेक्साक्लोरोफीन अन्तर्निहित हो ।”

[सं. एक्स 11014/5/72-डी]

रमेश बहादुर, अवर सचिव ।

New Delhi, the 16th February, 1973

S.O. 521.—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) is published, as required by the said sections for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of THREE months from the dated of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title :** These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 1973.

2. **Insertion of new rule 134A:** In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 (hereinafter referred to as the said rules),

after rule 134, the following rule shall be inserted namely :—

“134-A. Import of Cosmetics Containing Hexachlorophene Prohibited—

No cosmetic containing Hexachlorophene shall be imported.”

3. **Insertion of new rule 144-A :** In the said rules, after rule 144, the following rule shall be inserted, namely :—

“144-A. Prohibition of Manufacture of Cosmetics Containing Hexachlorophene—

No cosmetics containing Hexachlorophene shall be manufactured for sale and distribution.”

[No. X. 11014/5/72-D]

RAMESH BAHADUR, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1973

(व्यापार नौवहन)

का० आ० 522.— व्यापार नौवहन अधिनियम, 1958

(1958 का 44) की धारा 283 के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में तथा इस विषय में पूर्व समस्त घोषणाओं का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट देशों ने प्रत्येक देश के सामने स्तम्भ (2) में लिखी तारीखों से समुद्र में जीवन सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय संगमन, 1960 को स्वीकार कर लिया है :—

सारणी

उन देशों का नाम जिन्होंने समुद्र में जीवन सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय संगमन 1960 को स्वीकार किया/मान लिया है ।

(1)	(2)
1. हेटी	17 मार्च, 1961
2. नौरवे	23 अगस्त, 1961
3. फ्रांस	16 अक्टूबर, 1961
4. वियतनाम गणराज्य	8 जनवरी, 1962
5. घाना	22 मार्च, 1962
6. पेद	25 जुलाई, 1962
7. संघ राज्य भ्रमरीका	2 अगस्त, 1962
8. पेरटो रिको, गाम एण्ड विरजिन आइसलैण्ड्स	26 मई, 1965
9. मलागसी गणराज्य	13 सितम्बर, 1962
10. मोरोक्को	28 नवम्बर, 1962
11. स्पेन	22 जनवरी, 1963
12. ग्रीक	13 फरवरी, 1963
13. जापान	23 अप्रैल, 1963
14. ट्यूनिशिया	20 मई, 1963
15. न्यूवा	22 अगस्त, 1963
16. परागवे	11 सितम्बर, 1963
17. अलजीरिया	20 जनवरी, 1964
18. लाइबीरिया	26 मई, 1964
19. यू० के०	11 जून, 1964
20. हांग कांग	7 दिसम्बर, 1965
21. नीदरलैण्ड तथा नीदरलैण्ड एंटी-इलेस	16 अक्टूबर, 1964
22. डेनमार्क	1 दिसम्बर, 1964
23. आइसलैण्ड	11 दिसम्बर, 1964
24. युगोस्लाविया	23 फरवरी, 1965
25. चीन गणराज्य	23 फरवरी, 1965
26. मयूदी अरब	3 मई, 1965
27. फिनलैण्ड	11 मई, 1965
28. कुवैत	14 मई, 1965
29. कोरिया गणराज्य	21 मई, 1965
30. संघ राज्य जर्मेनी	25 मई, 1965
31. कनाडा	26 मई, 1965
32. बर्मा	12 जुलाई, 1965
33. साइप्रस	26 जुलाई, 1965
34. इजिप्ट	27 जुलाई, 1965

(1)	(2)
35. सोवियत समाजवादी गणतंत्र	
संघ	4 अगस्त, 1965
36. फिलीपिन्स	11 अगस्त, 1965
37. मलयेशिया	16 अगस्त, 1965
38. इसराईल	5 अक्टूबर, 1965
39. पनामा	12 अक्टूबर, 1965
40. ब्राइवरी कोस्ट	2 नवम्बर, 1965
41. नाइजीरिया	30 नवम्बर, 1965
42. स्वीडन	23 दिसम्बर, 1965
43. स्विट्जरलैण्ड	12 जनवरी, 1966
44. बेल्जियम	10 फरवरी, 1966
45. न्यूजीलैण्ड	14 फरवरी, 1966
46. पाकिस्तान	24 फरवरी, 1966
47. भारत	28 फरवरी, 1966
48. लेबनान	27 अप्रैल, 1966
49. अमेरिका	27 अप्रैल, 1966
50. पोलैण्ड	29 अप्रैल, 1966
51. इटली	26 मई, 1966
52. ईरान	31 मई, 1966
53. टर्की	2 जून, 1966
54. पुर्तगाल	14 जून, 1966
55. मैक्सिको	22 जून, 1966
56. ट्रिनिडाड एण्ड टोबैगो	6 सितम्बर, 1966
57. चिली	7 सितम्बर, 1966
58. इन्डोनेशिया	26 अक्टूबर, 1966
59. ब्राझिया	1 नवम्बर, 1966
60. रोमानिया	12 दिसम्बर, 1966
61. आयरलैण्ड	14 फरवरी, 1967
62. ब्राजील	8 मार्च, 1967
63. सोमालिया	30 मार्च, 1967
64. चैकोस्लावाकिया	5 जुलाई, 1967
65. निकारागुआ	9 अक्टूबर, 1967
66. बलगारिया	16 अक्टूबर, 1967
67. मोरोटानिया	4 दिसम्बर, 1967
68. दक्षिणी अफ्रीका	13 दिसम्बर, 1967
69. आस्ट्रेलिया	20 दिसम्बर, 1967
70. मालदीव	29 जनवरी, 1968
71. जामिका	22 फरवरी, 1968
72. जायरे	20 मई, 1968
73. गुइना	5 सितम्बर, 1968
74. उगंडा	19 सितम्बर, 1968
75. साइसिनधर गणतंत्र	24 दिसम्बर, 1968
76. वेनेजुएला	23 जनवरी, 1969
77. सिंगापुर	12 फरवरी, 1969
78. हीन्डुरस	18 फरवरी, 1969
79. यमन लोक जनवादी गणतंत्र	20 मई, 1969
80. नोरु	19 जनवरी, 1970
81. हंगरी	24 मार्च, 1970
82. मोनेको	25 मार्च, 1970
83. सेनेगल	9 अप्रैल, 1970

(1)	(2)
84. जाम्बिया	2 सितम्बर, 1970
85. खमेर गणतंत्र	24 नवम्बर, 1970
86. इन्डोनेशियल गुइना	3 मार्च, 1972

[फा० सं० 42-एम०ए० (6)/70]

वी० वी० सुब्राह्मण्यम, उप सचिव

Ministry of Shipping & Transport
New Delhi, the 19th January, 1973
(Transport Wing)
(MERCHANT SHIPPING)

S. O. 522.—In pursuance of the provisions of clause (a) of section 283 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and in supersession of all previous declarations on the subject the Central Government hereby declares that the countries specified in column (1) of the Table set out below have accepted the International Convention on Safety of Life at Sea, 1960, with effect from dates indicated against each country in column (2).

Table

Name of the country which has accepted/
acceded to the International Convention
on Safety of Life at Sea, 1960

1	2
1. Haiti	17 March, 1961
2. Norway	23 August, 1961
3. France	16 October, 1961
4. Vietnam Republic of	8 January, 1962
5. Ghana	22 March, 1962
6. Peru	25 July, 1962
7. United States of America	2 August, 1962
8. Puerto Rico, Guam and the Virgin Islands	26 May, 1965
9. Malagasy Republic	13 September, 1962
10. Morocco	28 November, 1962
11. Spain	22 January, 1963
12. Greece	13 February, 1963
13. Japan	23 April, 1963
14. Tunisia	20 May, 1963
15. Cuba	22 August, 1963
16. Paraguay	11 September, 1963
17. Algeria	20 January, 1964
18. Liberia	26 May, 1964
19. United Kingdom	11 June, 1964
20. Hong Kong	7 December, 1965
21. Netherlands and Netherlands Antilles	16 October, 1964
22. Denmark	1 December, 1964
23. Iceland	11 December, 1964
24. Yugoslavia	23 February, 1965
25. China Republic of	23 February, 1965
26. Saudi Arabia	3 May, 1965
27. Finland	11 May, 1965
28. Kuwait	14 May, 1965
29. Korea Republic of	21 May, 1965
30. Federal Republic of Germany	25 May, 1965
31. Canada	26 May, 1965
32. Burma	12 July, 1965
33. Cyprus	26 July, 1965
34. Egypt	27 July, 1965
35. Union of Soviet Socialist Republics	4 August, 1965
36. Philippines	11 August, 1965
37. Malaysia	16 August, 1965
38. Israel	5 October, 1965
39. Panama	12 October, 1965
40. Ivory Coast	2 November, 1965
41. Nigeria	30 November, 1965
42. Sweden	23 December, 1965
43. Switzerland	12 January, 1966
44. Belgium	10 February, 1966
45. New Zealand	14 February, 1966
46. Pakistan	24 February, 1966
47. India	28 February, 1966
48. Lebanon	27 April, 1966
49. Argentina	27 April, 1966

1	2
50. Poland	29 April 1966
51. Italy	26 May 1966
52. Iran	31 May 1966
53. Turkey	2 June 1966
54. Portugal	14 June 1966
55. Mexico	22 June 1966
56. Trinidad and Tobago	6 September 1966
57. Chile	7 September 1966
58. Indonesia	26 October 1966
59. Gambia	1 November 1966
60. Romania	12 December 1966
61. Ireland	14 February 1967
62. Brazil	8 March 1967
63. Somalia	30 March 1967
64. Czechoslovakia	5 July 1967
65. Nicaragua	9 October 1967
66. Bulgaria	16 October 1967
67. Mauritania	4 December 1967
68. South Africa	13 December 1967
69. Australia	20 December 1967
70. Maldives	29 January 1968
71. Jamaica	22 February 1968
72. Zaire	20 May 1968
73. Guinea	5 September 1968
74. Uruguay	19 September 1968
75. Syrian Arab Republic	24 December 1968
76. Venezuela	23 January 1969
77. Singapore	12 February 1969
78. Honduras	18 February 1969
79. People's Democratic Republic of Yemen	20 May 1969
80. Nauru	19 January 1970
81. Hungary	24 March 1970
82. Monaco	25 March 1970
83. Senegal	9 April 1970
84. Zambia	2 September 1970
85. Khmer Republic	24 November 1970
86. Equatorial Guinea	3 March 1972

[File No. 42-MA(6)/70]

V. V. SUBRAMANAYAM, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

(सम्पदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1973

का. आ. 523.—लोक परिसर, (अप्राधिकृत अधिभाषियों की बेइखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 20 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भूमि अर्जन अधिकारी, चण्डीगढ़ और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चण्डीगढ़ को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती हैं और भारत सरकार के निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय (निर्माण और आवास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 3921ए, तारीख 23 अक्टूबर, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, स्तम्भ 1 के मद 2 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“3. भूमि अर्जन अधिकारी ।

4. कार्यपालक मजिस्ट्रेट ।”

[सं. 21012(29)/72-सीति-3]

आर. बी. सक्सेना, उप सम्पदा निदेशक और पर्वन
अवर सचिवMINISTRY OF WORKS AND HOUSING
(Directorate of Estates)

New Delhi, the 9th February, 1973

S.O. 523.—In exercise of the powers conferred by section 3, read with section 20, of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the land Acquisition Officer, Chandigarh and the Executive Magistrate, Chandigarh to be estate officers for the purposes of the said Act and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Works, Housing and Supply, (Department of Works and Housing) No. S.O. 3921, dated the 23rd October, 1967, namely:—

In the said notification, in the Table, in column 1, after Item 2, the following items shall be inserted, namely:—

“3. The land Acquisition Officer.

4. The Executive Magistrate.”

[No. 21012(29)/72-Pol. III]

R. B. SAXENA, Dy. Director of Estates
and Ex-Officio Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1973

का. आ. 524.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने फिल्म प्रभाग, बम्बई में स्थानापन्न उप मुख्य प्रोड्यूसर श्री एन. एस. थापा को 24 जनवरी, 1973 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक, श्री प्रमोदपति के स्थान पर प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, बम्बई नियुक्त किया है ।

2. श्री प्रमोदपति ने 24 जनवरी, 1973 (पूर्वाह्न) को प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, बम्बई के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

राष्ट्रपति के नाम तथा उनके आदेशानुसार

[फा. सं. 2/3/73-एफ. सी.]

हरजीत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 1st February, 1973

S.O. 524.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952, the Central Government has been pleased to appoint Shri N. S. Thapa, officiating Deputy Chief Producer, Films Division, Bombay as Regional Officer, Central Board of Film Censors, Bombay vice Shri Pramod Pati with effect from 24th January, 1973 (forenoon) until further orders.

2. Shri Pramod Pati relinquished charge of the post of Regional Officer, Central Board of Film Censors, Bombay with effect from 24th January, 1973 (forenoon).

By order and in the name of the President.

[No. 2/3/73-FC]

HARJIT SINGH, Under Secy.

सिंचाई और विद्युत्, मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1973

आवेष

का. आ. 525.—जबकि 1965-66 से 1967-68 तक की अवधि में नई दिल्ली नगरपालिका को बिजली की सप्लाई करने के लिए दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान (जो कि विद्युत् के उत्पादन, प्रदाय तथा जनता में इसका वितरण करने के कार्य के लिए दिल्ली नगर निगम का एक स्कंध है) द्वारा ली जाने वाली दरों पर दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया है।

2. अतः अब दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 285 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् एतद्वारा यह फैसला करती है कि नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा क्रय की गई प्रभार्य ऊर्जा पर निम्नलिखित परिकल्पित प्रभाव लिए जाएंगे :—

वर्ष	प्रभार्य ऊर्जा की मात्रा (यूनिट)	प्रति यूनिट दर (पैसे)
1965-66	163,924,664	8.45
1966-67	185,816,483	9.08
1967-68	196,122,742	9.51

3. उपर्युक्त परिकल्पित दरें दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के 31 मार्च, 1968 तक समाप्त हुई अवधि के लेखों के सम्परीक्षित विवरणों पर आधारित हैं। इन परिकल्पित दरों में, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66वां) की धारा 113 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम के दाय कर सम्मिलित नहीं हैं।

[सं. बी. तीन-13(36)/67]

एल. जे. जान्सन, विशेष अधिकारी

MINISTRY OF IRRIGATION & POWER

New Delhi, 5th February, 1973

ORDER

S.O. 525.—Whereas a dispute has arisen between the Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Municipal Committee as to the rates to be charged by the Delhi Electric Supply Undertaking, (a wing of the Municipal Corporation of Delhi for the generation, supply and distribution of electricity to the public) for the supply of electricity to the New Delhi Municipal Committee during the period from 1965-66 to 1967-68.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to section 285 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), the Central Government, after taking all relevant facts into consideration, hereby decides that the chargeable quantum of energy purchased by the New Delhi Municipal Committee shall be charged at the computed rates as shown below:

Year	Quantum of chargeable energy (kwh)	Rate per kwh (Paise)
1965-66	163,924,664	8.45
1966-67	185,816,483	9.08
1967-68	197,122,742	9.51

3. The rates computed above are based on the audited statement of accounts of Delhi Electric Supply Undertaking upto the period ending with the 31st March, 1968. The rates computed above are exclusive of the taxes payable to the Municipal Corporation of Delhi under clause (d) of sub-section (2) of section 113 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957).

[No. EL. III 13(36)/67.]

L. J. JOHNSON, Officer on Special Duty.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1973

आवेष

का. आ. 526.—यतः कनारा बैंक, बंगलौर से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों ने, जिनका प्रतिनिधित्व कनारा बैंक कर्मचारी संघ, मद्रास करता है, संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया कि उक्त आवेदन में उपवीणित और उससे उपाबद्ध अनुसूची में उद्धृत विषय के बारे में औद्योगिक विवाद को, जो उनके बीच विद्यमान है, औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाए,

और, यतः, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त कनारा बैंक कर्मचारी संघ, मद्रास कर्मचारों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी थिरू जी. गोपीनाथ होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

क्या श्री एम. राम प्रसाद, विशेष सहायक का आधारीक वतन बैंक में उसकी नियुक्ति पर लीपकीय वतनमान के आरम्भ पर नियत करना ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस अनुसूचि का हकदार है?

[सं. एल. 12012/167/72 एल आर (3)]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION
(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 1st January, 1973

ORDER

S.O. 526.—Whereas the employers in relation to the Canara Bank, Bangalore and their workmen represented by Canara Bank Employees' Union, Madras, have jointly applied to the Central Government for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matter set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government is satisfied that the said Canara Bank Employees' Union, Madras represents the majority of the workmen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru

G. Gopinath shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute to the said Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Whether the fitment of the basic pay of Shri M. Ramprasad, Special Assistant, at the start of Clerical scale on his appointment in the Bank is in order? If not, to what relief is he entitled?

[No. L. 12012/167/72-LRIII]

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1973

आवृत्ति

का. आ. 527.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा-बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नेशनल कोल डेवलप-मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डाकघर कोर्बा, जिला बिलासपुर (मध्य-प्रदेश) के प्रबन्ध-तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है :

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है :

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोर्बा और मनीकपुर कोलियरीज, डाकघर कोर्बा, जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश) के कोयला खान उप-अधीक्षक का, श्री सरजू संख्या 3 और 4 कोर्बा से खाल संख्या 1 और 2 कोर्बा में स्थानान्तरित करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुपात का हकदार है?”

[सं. एल./22012/15/72 एल. आर. 2]

करनल सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd January, 1973

ORDER

S.O. 527.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of National Coal Development Corporation Limited, Post Office Korba, District Bilaspur (Madhya Pradesh), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the Deputy Superintendent of Collieries, Korba and Manikpur Collieries of National Coal Development Corporation Limited, Post Office Korba, District Bilaspur (Madhya Pradesh), is justified in transferring Shri Sarju Prasad Singh, Underground

Munshi, Incline No. 3 and 4 Korba to Incline No. 1 and 2, Korba, with effect from the 11th November, 1971? If not, to what relief is the workmen entitled?

[No. L/22012/15/72-LRII]

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1973

आवृत्ति

का. आ. 528.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा-बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि. की मूनीडीह परियोजना, डाकघर मूनीडीह, जिला धनबाद के प्रबन्ध-तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 2) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या मैसर्स राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड की मूनीडीह परियोजना, डाकघर मूनीडीह, जिला धनबाद के प्रबन्ध-तंत्र की, श्री डी. पी. मिश्र, कम्प्रेसर ऑपरेटर को 29 नवम्बर, 1971 से सेवा से बरखास्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुपात का हकदार है ?

[सं. एल./2012/68/72-एल. आर. 2]

करनल सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 24th January, 1973

ORDER

S.O. 528.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Moonidih Project of National Coal Development Corporation Limited, Post Office Moonidih, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Moonidih Project of Messrs. National Coal Development Corporation Limited, Post Office Moonidih, District Dhanbad, in dismissing Shri D. P. Misra, Compressor Operator from service with effect from the 29th November, 1971 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?

[No. L/2012/68/72-LRII]

New Delhi, the 9th February, 1973

S.O. 529.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Balihari Colliery, Post Office Kusunda, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd February, 1973.

[No. 2/248/68-LRII.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 76 of 1969

Present: Shri B. S. Tripathi,
Presiding Officer.

Parties: Employers in relation to the management of
Balihari Colliery, P.O. Kusunda, Distt. Dhanbad
AND

Their workmen represented by Hindustan Khan Mazdoor
Sangh, Dhanbad.

Appearances: For Employer—Shri B. Joshi, Advocate representing the Balihari Colliery Co. (P) Ltd., P.O. Kusunda, Dist. Dhanbad, Shri S. S. Mukherjee & Shri J. N. Sathi, Labour and Law Adviser, Bharat Coking Coal Ltd.—added as a party (vide) Order No. 19 dated 23-3-72).

For Workmen—Shri S. V. Achariar, General Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh, Dhanbad.

Industry: Coal.

State: Bihar

Dated, Dhanbad, the 30th January, 1973.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Department of Labour and Employment) being of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Balihari Colliery, P.O. Kusunda, Dist. Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the schedule of reference, by their Order No. 2/248/68-LRII dated the 18th October, 1969, referred the dispute in question under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 to this Tribunal for adjudication. The schedule of the reference is extracted below :—

SCHEDULE

"Whether the management of Balihari Colliery of M/s. Balihari Colliery Co. (P) Ltd., P.O. Kusunda, Dist. Dhanbad was justified in dismissing Shri Jageshwar Mahato, Mining Sardar and Shri S. N. Pandey, Munshi, with effect from the 7th August, 1968? If not, to what relief are these workmen entitled?"

2. The reference was received by this Tribunal on 27-10-69 and was registered as reference No. 76 of 1969. The industrial dispute in question was sponsored by Hindustan Khan Mazdoor Sangh, Dhanbad and the same union represented the workmen in the present proceeding. All the concerned parties, including Bharat Coking Coal Limited who were added as a party to the reference as per Order No. 19 dated 23-3-72, filed their written statements. The reference was ready for hearing, but in the meantime all the concerned parties amicably settled the dispute out of Court and filed compromise petition embodying therein the terms of settlement arrived at. The representatives of the parties verified the settlement and the terms thereof before me and made a prayer to pass an award accordingly.

3. I have carefully gone through the compromise petition and the terms of settlement mentioned therein, in the light of the reference and the cases of the parties contained in their respective written statements and I find that the terms of

settlement are just, fair and equitable and I see no reason as to why the settlement arrived at by the parties as per compromise petition said above, shall not be accepted and the reference be not disposed of accordingly. I accept the compromise petition containing the terms of settlement and make an award accordingly. The compromise petition will form part of the award and is marked as Annexure 'A' thereof.

4. Let the award be submitted to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

B. S. TRIPATHI, Presiding Officer

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
(NO. III) AT DHANBAD

In the matter of:

Reference No. 76 of 1969

Parties:

Employers in relation to Balihari Colliery
And
MEMORANDUM OF SETTLEMENT.

All the parties in the present proceedings have amicably settled the dispute involved in the present Reference on the terms hereinafter stated :—

- (1) That Sri S. N. Pandey (Munshi) one of the workmen concerned in the present Reference (who had been already since long employed in the Kustere Colliery) will have no claim for any back wages. However, the period intervening from the date of dismissal (which gave rise to the present Reference) till the date of resumption of duty at Kustere Colliery shall, for the purposes of continuity of services, be treated as leave without pay.
- (2) That Sri Jageshwar Mahato (Mining Sardar) the other workman concerned in the present Reference shall be re-instated on and from the 1st February, 1973 without any back wages, and he will be posted at Dhanbad Colliery. The period intervening from the date of dismissal (which gave rise to the present Reference) till the date of resumption of duty shall, for the purposes of continuity of services, be treated as leave without pay, but this workman concerned will be eligible to proportionate leave or quarterly bonus provided he puts in proportionate qualifying attendance during the remaining period of current year or the current quarter, as the case may be.
- (3) In the event of the failure of Shri Jageshwar Mahato (concerned workman) to report for work within a fortnight from the 1st February, 1973 the workman concerned shall have no right for re-employment etc. under this agreement.
- (4) The General Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh, will be paid a sum of Rs. 100.00 (Rupees One hundred only) as the cost of proceedings.
- (5) The above terms finally resolve the dispute between parties and, therefore, there is no subsisting dispute for adjudication in the present Reference.

It is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Settlement and to give its Award in terms thereof.

FOR THE EMPLOYERS:

Manager,
Balihari Colliery.

FOR THE WORKMEN:

General Secretary,
Hindustan Khan Mazdoor Sangh,
Dhanbad.

FOR BHARAT COKING COAL LTD.:

J. N. SAHI,
Labour and Law Adviser,
Bharat Coking Coal Ltd.

Dated the 27th January, 1973.

New Delhi, 9th February 1973

S.O. 530.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Madhuband Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post Office Nudkharkee, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th February, 1973.

[No. 2/20/69-LRII.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

**CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3,
DHANBAD.**

Reference No. 19 of 1969

Present :

Shri B. S. Tripathi—Presiding Officer.

Parties :

Employers in relation to the management of Madhuband Colliery of M/s. Oriental Coal Co. Ltd., P. O. Nudkharkee, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen represented by Mine Karamchari Sangh, Dhanbad.

Appearances :

For Employers—Shri S. S. Kapoor, Advocate representing M/s. Oriental Coal Co. Limited, Shri S. S. Mukherjee, Advocate and Shri J. N. P. Sahi representing Bharat Coking Coal Ltd.—added as a party vide Order No. 22 dated 23-3-72.

For Workmen—Shri Jagir Singh, General Secretary, Mine Karamchari Sangh.

Industry: Coal.

State: Coal.

Dhanbad, 29th January 1973.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Department of Labour & Employment) being of the opinion that an industrial dispute exists between the parties, named above, in respect of the matters specified in the schedule of reference, by their Order No. 2/20/69-LRII dated the 14th March, 1969 referred the said dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 to this Tribunal for adjudication. The schedule is extracted below:—

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Madhuband Colliery of M/s. Oriental Coal Co. Ltd., P. O. Nudkharkee, Dist. Dhanbad, in refusing work to Shri Ritu Mahato, Miner with effect from the 27th November, 1967 was justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. The reference was received in this Tribunal on 16-4-69 and was registered as reference No. 19 of 1969. The industrial dispute in question was sponsored by Mine Karamchari Sangh and the same union represented the workmen in the present proceeding. The union filed written statement on behalf of the workmen on 29-4-1969. The written statement of the employers, namely, M/s. Oriental Coal Company Limited was received in this Tribunal on 15-10-69. On behalf of the workmen a rejoinder to the written statement of the employers was filed on 4-11-69. During the pendency of the reference the colliery in question came into the possession of Bharat Coking Coal Limited under the provisions of Coking Coal Mines (Emergency Provisions)

Act, 1971. Thereafter, on behalf of the workmen a petition was filed to implead Bharat Coking Coal Limited in the present reference and after hearing the parties and also the representatives of Bharat Coking Coal Limited, the Bharat Coking Coal Limited were impleaded as party in the present reference as per Order No. 22 dated 23-3-72. The Bharat Coking Coal Limited filed written statement on 29-4-72 adopting the written statement filed by M/s. Oriental Coal Company Ltd., and alleging further that they are not responsible for the action of M/s. Oriental Coal Co. Ltd.

3. According to the reference Shri Ritu Mahato was working as a miner in Madhuband Colliery belonging to M/s. Oriental Coal Co. Ltd., and the management refused work to Shri Ritu Mahato with effect from the 27-11-67. The question for determination is as to the justification or otherwise of the said action of the management and if not justified, what relief the concerned workman is entitled to.

4. The case of the employers is that on 27-9-67 the concerned workman applied for leave from 4-10-67 to 28-10-67. Only 12 days Earned Leave was due to his credit. Accordingly he was allowed leave from 4-10-67 to 16-10-67 including one rest day (vide application for leave with orders thereon Ext. M-1). According to the usual practice in the colliery the application for leave was filed in duplicate and the workman was given one copy of the leave application along with the sanction order and at the time of giving such a copy to him, he was told the period of leave granted to him and when he was to resume his duty. The workman did not resume his duty on 17-10-67 after the expiry of leave granted to him nor he sent any application seeking extension of leave, already granted. He came on 28-10-1967. Since he overstayed for more than 8 days, after the expiry of the leave granted, he lost lien on his appointment under paragraph 11 (i) & (ii) of the Certified Standing Orders applicable to the colliery in question Ext. M-5. The management further issued a letter Ext. M-8 to the workmen on the same day i.e. 28-10-67 to explain his overstay without permission and to show cause as to why he should not lose lien on his appointment under the aforesaid Standing Order. The workman submitted his explanation Ext. M-2 which was not considered satisfactory and accordingly an enquiry was ordered. The enquiry was held on 3-11-67 in which the concerned workman participated and he was given full opportunity to cross-examine the witnesses of the management. The Enquiry Officer after completing enquiry submitted his report Ext. M-14 dated 8-11-67. The Enquiry Officer found the charge against the workman to have been established beyond doubt. The management accepted the finding of the Enquiry Officer and ordered that the workman lost his lien on his appointment and issued office order Ext. M-9 dated 19-11-67 accordingly. It is stated that since the management had no *malafide* intention, it allowed the workman to work from 3-11-67 subject to the final decision in the enquiry and he worked upto 26-11-67. The case of the management is that after the workman lost his lien on his appointment with effect from 17-10-67 he was kept in ‘badli’ list as per the Standing Order aforesaid and his work from 3-11-67 to 26-11-67 was considered as having been done as a badli worker. It is further stated that on 27-12-67 the workman put in a petition Ext. M-3 stating that he had been illegally stopped from work from 27-11-67 and the management promptly replied by their letter dated 31-12-67 Ext. M-10 denying the said allegation. On 10-1-68 the workman by his application Ext. M-4 reiterated that he was illegally locked out from work with effect from 27-11-67 which was denied by the management. It is said that on 13-1-69 the management issued the letter Ext. M-11 to the workman asking him to work as Loader in badli vacancy, but he did not go to work in compliance with the said letter. The case of the management is that the workman left his work from 27-11-67 and he was not refused work and when he came on 13-1-68 he was given the work of a Loader as a badli worker which he refused to join. The prayer of the management accordingly is that the workman is not entitled to any relief in this case. The management has also taken a formal plea in their written statement to the effect that the dispute in question is not an industrial dispute in as much as it is an individual dispute in the sense that the Union, Mine Karamchari Sangh, is an unregistered Union and it does not exist in the colliery in question. I may mention at this place that no evidence was adduced by the management in this regard and the Learned Advocate of the management at the time of hearing of the reference submitted that the management do not press the said plea.

5. According to the workmen Sri Ritu Mahato applied for leave from 4-10-67 to 27-10-67 and thereafter he came to join his duty after the expiry of leave on 28-10-67. He was neither given a copy of leave application with sanction order nor was he told verbally that he was granted leave only upto 16-10-67 and that he was to join on 17-10-67. It is stated that when he came to join on 28-10-67 he was not allowed to resume his duty and on the contrary he was given chargesheet for overstay to which he gave his reply on 29-10-67. The case of the workmen is that there was no enquiry regarding the charge issued to him and the allegation of the management in this regard is incorrect. It is said that he used to report daily from 28-10-67 to 3-11-67 and on 3-11-67 he was allowed to join duty only after taking his thumb marks on two papers, the contents of which the workman did not know. He worked till 26-11-67 and on 27-11-67 he was refused work and was not allowed to join his duty without assigning any reason for the same. The workman then protested the action of the management before the Labour Enforcement Officer, Bagmara by a written representation dated 1-12-67 Ext. W-4 and on 27-12-67 the workman submitted a written representation to the management to allow him to resume his duty whereupon the management as per its letter dated 31-12-67 agreed to take him back in the job provided he gave an assurance that he would not absent himself without permission and shall be regular in his work. The workman gave the assurance as required on 10-1-68 and on 13-1-68 the management issued a letter asking him to resume duty as a Loader in badli vacancy at 18A Seam. The workman made a protest to the said letter of the management by his letter Ext. W-5 dated 15-1-68 to the management asking the management to withdraw the letter dated 13-1-68. The workman never agreed to work in a badli vacancy in as much as he was a permanent workman. The prayer of the workmen accordingly is that the Tribunal should decide the refusal of the management to the workman concerned to work from 27-11-67 as unjustified and direct the management to allow him to resume his duty as a permanent employee with continuity of his service and with full back wages.

6. Both the parties have filed documents and have examined witnesses which will be discussed in course of the award, if and when the necessity for the same will arise. The only witness on behalf of the workmen is the concerned workman Sri Ritu Mahato (W-1). On behalf of the management 2 witnesses have been examined and they are Shri R. N. Thakur, the Leave Clerk (MW-1) and Sri N. K. P. Sinha, Administrative Officer (MW-2). The evidence of Sri N. K. P. Sinha is that he had conducted the enquiry regarding the overstay of the concerned workman after the expiry of leave granted to him. The witness states that during the enquiry held by him he examined Shri R. N. Thakur, Leave Clerk and the concerned workman Sri Ritu Mahato and submitted his report Ext. M-14, Ext. M-12 is the statement of Shri R. N. Thakur the Leave Clerk and Ext. M-13 is the statement of Shri Ritu Mahato recorded by Shri N. K. P. Sinha in the said enquiry.

7. The relevant provision relating to the overstay of a workman beyond the period of leave granted to him is in paragraph 11 of the Certified Standing Orders which runs as follows:—

"11. Any direct employee of the Company other than a miner or loader who desires to obtain leave of absence shall apply in writing to the head of the department or the Manager of the colliery. Employees who due to illiteracy do not apply in writing must apply verbally. If the employee remains absent beyond the period of leave originally granted or subsequently extended he shall lose his lien on his appointment unless :

- (i) he returns within 8 days of the expiry of the leave, and
- (ii) gives an explanation to the satisfaction of the Manager of his inability to return before the expiry of leave. In case the employee loses his lien on the appointment he shall be entitled to be kept on the 'badli' list. If leave is refused or postponed the fact of such refusal or postponement and the reasons therefor shall be recorded in writing in a leave register to be maintained

for this purpose and if the employee so desires, a copy of such entry in the register shall be supplied to him."

It is clear from the above provision that an employee of the company of the colliery in question loses his lien on his appointment if he remains absent beyond the period of leave already granted to him. This is, however, subject to the exception that in case such an employee returns within 8 days of the expiry of the leave granted to him and gives an explanation, to the satisfaction of the Manager of his inability to return before the expiry of leave, the said employee will not lose his lien on his appointment. Subject to the said exception, the loss of his lien to the appointment, in case of absence beyond the period of leave granted, is automatic. This is also the decision of their Lordships of the Supreme Court in the case of National Engineering Industries Limited and Hanuman, reported in 1967 (2) L.L.J. 883, in a case of similar provision in the Standing Order. Their Lordships held that when the Standing Order provides that a workman will lose his lien on his appointment in case he does not join his duty within 8 days of expiry of his leave, it obviously means that the services are automatically terminated on the happening of the contingency. A similar provision in the Standing Order of the company was also the subject matter of interpretation before their Lordships of the Patna High Court in the case of Pure Kustore Colliery and Khan Mazdoor Congress and others reported in 1969 (1) L.L.J. 133. The relevant Standing Order of the company in that case was exactly in the same language as in the Standing Order of the present case, already quoted above. Their Lordships relying upon the decision of the Supreme Court, said above, held as follows:—

"As Standing Order 11 stands, it is clear that the employee must lose his lien on his appointment, unless returns within 8 days of the leave and having returned within that time gives an explanation to the satisfaction of the Manager of his inability to return in time. The two requirements under Standing Order 11 are not disjunctive."

There is thus no doubt that in view of the Standing Order in question an employee of the company will lose lien on his appointment if he does not turn up after the expiry of his leave, subject of course to the exception, said above.

8. The admitted position in the present case is that the concerned workman Shri Ritu Mahato was working as miner in the colliery in question. He applied for leave from 4-10-67 to 28-10-67 and absented himself from duty from 4-10-67 as on leave. He presented himself for duty on 28-10-67, but he was refused to join and on the contrary a notice was issued to him on 28-10-67 saying that he was granted leave from 4-10-67 to 16-10-67 and as such he was to resume his duty on 17-10-67 and thus he overstayed for 10 days without permission and asking him to show cause as to why he will not lose his lien on his appointment under paragraph 11(i)(ii) of the Colliery's Standing Order (*vide* show cause notice Ext. M-8). From the leave application of the workman, Ext. M-1, it appears that he had applied for leave with effect from 4-10-67 to 28-10-67, both days inclusive, on the ground of urgent work at his home but he was granted leave for 12 days, the total period of leave due to him by that time, excluding one rest day, from 4-10-67 to 16-10-67. According to the workmen in their rejoinder to the written statement of the employers dated 4-11-69 he was granted leave for the entire period applied for. This is however belied by the order passed on the leave application by the competent authority. I may mention here that the leave application with orders thereon has been marked as exhibit in this case on admission of the workmen. Apparently, therefore, the leave granted to the concerned workman expired for 16-10-67 and as such he was to resume duty on 17-10-67 but he came to duty on 28-10-67. Sri Ritu Mahato, therefore, overstayed from 17-10-67 to 27-10-67 after the expiry of his leave.

9. The workmen have examined Shri Ritu Mahato as WW-1 to say that when the leave application came to the Leave Clerk Shri R. N. Thakur, Shri Thakur told him that he was entitled leave with pay for 12 days and for the remaining period his leave shall be without pay and he was directed to join duty after leave on 28-10-67. The order passed on the leave application, said above, does not show

that any leave was granted to Shri Ritu Mahato without pay from 17-10-67. I like to mention at this place that in the rejoinder dated 4-11-69 of the workmen, already referred to above, the statement is that the workman had applied for leave from 4-10-67 to 27-10-67 and similarly Sri Ritu Mahato WW-1 has been made to say that he had applied for leave upto 27-10-67. This is apparently incorrect in view of the admitted position contained in the leave application which shows that the leave applied for was upto 28-10-67, and not 27-10-67. The management has examined the leave clerk Sri R. N. Thakur as MW-1. From his evidence it appears that the second part of the leave application, which is a report as to the period of leave the workman was entitled to, was written by him. The witness states that he had explained to the concerned workman that he was granted leave for the period of 12 days only i.e. from 4-10-67 to 16-10-67 and that he must join duty after the leave expired. The witness has given the practice in the colliery office in this connection and it is this that a leave application is submitted in duplicate and when the leave is granted one copy is retained by the office and the other is returned to the applicant concerned and the applicant is told the period of leave sanctioned by the management and he is further told to join the duty after the expiry of the leave. The witness states that in this case also the practice was followed. He retained one copy of the leave application Ext. M-1 and gave the duplicate copy to Shri Ritu Mahato which contained the sanction order of leave for 12 days from 4-10-67 to 16-10-67. Sri Ritu Mahato WW-1 in cross-examination also admits to have received back one copy of the leave application with sanctioned order thereon. The witness states "I put my L.T.I. on two leave applications. One leave application was handed over to me after the leave was sanctioned and the other was kept with the management". The workmen do not produce the copy of the leave application containing the sanction order which was returned to Shri Ritu Mahato nor any explanation has been offered for not filing the same. It has been taken in the cross-examination of Shri R. N. Thakur (M.W. 1) that the copy of the leave application which is given back to the concerned workman, after sanction of the leave, is again returned by the workman after the expiry of the leave when he comes to join his duty. Shri Ritu Mahato does not say in his evidence that the copy of the leave application which was returned to him was made over by him to the management at any time. It is also not specifically suggested in the cross-examination of MW-1 that the said leave application was returned by the workman to the management at any time. There is thus no evidence worth the name to prove that the said copy of leave application was made over by the workman to the management when he came to join his duty. Assuming for the sake of argument that the workmen did return the same, steps should have been taken, if considered necessary, to call for the same from the management for the purpose of showing that leave without pay also was granted to the workman from 17-10-67 to 28-10-67 or to 27-10-67, as the case may be. No such step was taken. In consideration of the evidence and circumstances on record, discussed above, I do not accept the case of the workmen that Shri Ritu Mahato was granted leave without pay from 17-10-67 to 27-10-67 or 28-10-67, as the case may be, and I find that Ext. M-1 shows the true state of affairs so far as the sanction order is concerned and it is this that Sri Ritu Mahato was granted leave only from 4-10-67 to 16-10-67. I do not see any reason to disbelieve the statement of Shri R. N. Thakur that he did explain to Sri Ritu Mahato that he was granted leave only upto 16-10-67 and he was to join thereafter on 17-10-67. There is no evidence or circumstance to corroborate the oral testimony of Shri Ritu Mahato that Shri R. N. Thakur had told him that he was granted leave with pay from 4-10-67 to 16-10-67 and leave without pay from 17-10-67 to 27-10-67 or 28-10-67. In consideration of the evidence on record I am not prepared to believe the statement of Shri Ritu Mahato before the Tribunal that Shri R. N. Thakur had told him that he was granted leave without pay from 17-10-67 to 28-10-67 and I find accordingly.

10. There is another circumstance which goes to prove that the concerned workman Shri Ritu Mahato knew that he was granted leave only upto 16-10-67. The management in this case got Departmental Enquiry made when it was not satisfied with the cause shown by the workman in the matter of his overstay from 17-10-67 to 27-10-67. Ext. M-2 is the cause shown to the explanation called for as per

Manager's letter dated 28-10-67 to Shri Ritu Mahato Ext. M-8. The enquiry was held by Sri N. K. P. Sinha who at the relevant time was working as Administrative Officer in Madhuband Colliery. From his evidence it appears that in the enquiry he examined Sri R. N. Thakur, the Leave Clerk, and also recorded the statement of Sri Ritu Mahato. The witness states that Sri Ritu Mahato was present at the time of enquiry and participated in it. Ext. M-12 & M-13 are the statements of Sri R. N. Thakur and Sri Ritu Mahato respectively before Shri N. K. P. Sinha. The enquiry appears to have been held on 3-11-67. It appears that Shri Ritu Mahato put his L.T.I. on Ext. M-12 and also Ext. M-13 below his statement. Shri N. K. P. Sinha has testified that Shri Ritu Mahato has put his L.T.I. on those documents in his presence. Shri Ritu Mahato in cross-examination before the Tribunal admits to have put the said L.T.I. on the documents in question. His evidence, however, is that there was no enquiry whatsoever nor he was present at the time of any such enquiry nor he gave any statement before Shri N. K. P. Sinha and that taking advantage of his illiteracy and helpless position his L.T.I. was taken on the said two papers and that too forcibly. This fact is denied by the management. Shri N. K. P. Sinha has testified before the Tribunal that the enquiry was held by him in the presence of Shri Ritu Mahato and in his presence Shri R. N. Thakur was examined and he himself gave his statement and that he explained the statements recorded by him to Shri Ritu Mahato after which Shri Ritu Mahato put his L.T.I. The statement is corroborated by Shri R. N. Thakur. On careful consideration of the evidence on record I accept the evidence of Shri N. K. P. Sinha that in the enquiry conducted by him Shri Ritu Mahato was present and in his presence Shri R. N. Thakur was examined and he himself gave his statement and put his thumb mark below his statement after the statement so recorded was explained to him. I do not accept the statement of Shri Ritu Mahato to the contrary. The statement of Shri Ritu Mahato before Shri N. K. P. Sinha was that he had gone home after taking leave for 12 days but he could not return in time. He admitted to have committed mistake and promised not to commit any such mistake in future and begged for pardon. It is a case of clear admission on the part of workman that he knew that he was granted leave for 12 days only and he was not granted leave without pay or with pay thereafter.

11. I have thus no manner of doubt to hold that Sri Ritu Mahato was granted leave only upto 16-10-67 and was not granted leave thereafter. He came to join duty on 28-10-67 and thus he overstayed for 11 days. In view of the Standing Order, already discussed above, it is apparent that Shri Ritu Mahato lost his lien on his appointment on and from 17-10-67. It may be noted that in the departmental enquiry the report of the Enquiry Officer Ext. M-14 was also to that effect and after considering the materials before the Enquiry Officer the management agreed with the findings of the Enquiry Officer and ordered that Shri Ritu Mahato lost his lien on his appointment with effect from 17-10-67 (vide Office Order Ext. M 9 dated 19-11-69). It was ordered further that his name be kept in 'badli' list. I may mention here that the loss of lien under the circumstances being automatic and the period of overstay being more than 8 days from the date of expiry of leave, taking explanation from the concerned workman, when he turned up, was not at all necessary. However, an opportunity was given to the workman to explain the position but the management was not satisfied with it. Simply because there was an enquiry on the part of the management it cannot be said that the concerned workman continued to have lien over his appointment after the expiry of the period of leave, the simple reason being that the loss of lien was automatic under the Standing Order, referred to above, in the circumstances of this case.

12. It appears that the management did not allow the workman to join duty from 28-10-67 to 2-11-67 but he was allowed to resume duty on 3-11-67 and he continued to work till 26-11-67. The workman was allowed to do the work during this period as the enquiry aforesaid was pending against him. According to the Standing Order and also the order of the management Ext. M-9 the workman was kept in 'badli' list. The submission on behalf of the management accordingly is that Shri Ritu Mahato worked as 'badli' workman during the period from 3-11-67 to 26-11-67 and I accept the above submission as correct.

13. According to the reference the concerned workman Shri Ritu Mahato was refused work with effect from 27-11-67 and the question for determination is whether the said refusal

was justified. In view of my finding already recorded above that Shri Ritu Mahato had lost his lien on his appointment, the action of the management refusing work to Shri Ritu Mahato as miner cannot be said to be unjustified. My answer to the reference, accordingly, is that the action of the management of Madhuband Colliery of M/s. Oriental Coal Co. Ltd., P.O. Nudkurkee, Dist. Dhanbad in refusing work to Shri Ritu Mahato, Miner with effect from the 27th November, 1967 was justified. In that view of the matter the concerned workman is not entitled to any relief.

14. In view of what I have held above the question of any liability of the new management of the colliery i.e. Bharat Coking Coal Limited for the above action of M/s. Oriental Coal Company Limited does not arise.

15. This is my award. Let the award be submitted to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

B. S. TRIPATHI, Presiding Officer.

New Delhi, the 9th February, 1973

S.O. 531.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakar Coal Company Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th February, 1973.

[No. L/19012/149/71-LR.II]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL.
AT CALCUTTA

Reference No. 13 of 1972

Parties :

Employers in relation to the management of Bankola Colliery of Messrs. Burrakar Coal Company Ltd.,

AND

Their workmen.

Present :

Mr. S. N. Bagchi—Presiding Officer.

Appearances :

On behalf of Employers—Sri Monoj Kr. Mukherjee, Advocate.

On behalf of Workmen—Absent.

State : West Bengal.

Industry : Coal Mine.

AWARD

By Order No. L/19012/149/71-LR.II, dated 24th February, 1972, the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, referred the following dispute existing between the employers in relation to the management of Bankola Colliery of Messrs. Burrakar Coal Company Limited and their workmen, to this tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the management of Bankola Colliery of Messrs. Burrakar Coal Company Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan is justified in not paying Category IV wages to Sarvashri Siya Saran Prasad, Dalip Singh, Kaimuddin Khan, Sarif Thakur, Harendra Thakur, Sohan Mahato and Rama Shankar Gorh, Coal Cutting Machine Mazdoors with effect from the 1st January, 1971? If not, what relief are the said workmen entitled to?"

2. Today when the case was called on for hearing, the management is present through its learned Advocate and the workmen are not present. The union which sponsored the cause of the workmen is also absent. Mr. M. K. Mukherjee, learned Advocate for the management submitted an application stating that the management would not press the preliminary point as raised in the management's statement of case as to the maintainability of the reference in as much as no demand was raised with the management before agitating the matter with the Conciliatory authority.

3. In view of the circumstances stated above, the Tribunal presumes that there is no further dispute existing over the matter referred to for adjudication, between the parties, and as such a 'no dispute' award is rendered in the matter.

This is my award.

Dated,
January 30, 1973.

S. N. BAGCHI, Presiding Officer.

New Delhi, the 16th February, 1973

S.O. 532.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division I and II, Post Office Godavari Khani (Andhra Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th February, 1973.

[No. I-2112/32/71-LR.II]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD

Present :

Sri P. S. Ananth, B.Sc., B.L., Industrial Tribunal (Central) Hyderabad.

Industrial Dispute No. 87 of 1971

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited,
Kothagudem (Ramagundam Divisions I & II),
Andhra Pradesh. ...Petitioner.

AND

Management of Singareni Collieries Company Limited,
Kothagudem (Ramagundam Divisions I & II)
Andhra Pradesh. ...Respondent.

Appearances :

Sri A. Lakshmana Rao, Advocate—for Petitioner.

Sri M. Shyam Mohan, Personnel Officer and Sri Papa Rao, Divisional Personnel Officer—for Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour & Employment) by its Order No. L/2112/32/71-LR.II, dt. 3-12-1971 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act., 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for adjudication to this Tribunal, namely:—

"1. Is the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem (Ramagundam Divisions I and II) justified in employing Sarvasri Raja Moinuddin, Merngu Gattaiah, Bahdur Khan, Sardar Khan, D. Srihari, Md. Gaffar, Kunta Parvathalu, Elgam Rajam, Soula Laxmaiah, M. Iswari Das, Y. Hanu-manth Rao, Sardar Khan, Matta Kistaiah, Kedari Mallaiah, R. Bhadrach, E. Venkati, K. Mallaiah, Sk. Yacoob Ali and A. Durgaiah, Category III Pump Khalasis on more than one pump during the

week from the 23rd May, 1971 to the 29th May, 1971 and in refusing to pay them category IV wages for the said period? If not justified, to what relief are the said workmen entitled for the said period and also for the periods when they were employed on more than one pump?

2. Is the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem (Ramagundam I and II Divisions) justified in employing Sarvashri D. Radhakrishna, Kannam Rajanarsu, Kondalaxman, Dasi Posham, Janga Ch Posham, Thatikonda Rajesham, Nimmala Ramaswamy, K. Venkaty, Oddy Rayamallu and Kamuni Odelu, Category II Pump Khalasis on more than 35 H.P. Pumps during the week from the 23rd May, 1971 to the 29th May, 1971 and in refusing to pay them category III wages for the said period? If not justified, to what relief are the said workmen entitled for the said period and also for the periods when they were employed on more than one pump?
3. If the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem (Ramagundam I and II Divisions) justified in employing Sarvashri Purandla Ramulu, A. Veeraswamy, U. Rajamouli, Raja Mohammad, J. Samuel, S. Suryanarayana, Ghousuddin, Maddela Durgaiiah, L. Venkaty, G. Ramulu, Erabathula Muthaiah, Kendukuri Agaiah, and Elupula Ramulu, Category II Pump Khalasis on more than one pump and also on more than 35 H.P. Pumps during the week ending 23rd May, 1971 to the 29th May, 1971 and in refusing to pay them category IV wages? If not justified to what relief are the said workmen entitled for the said period and also for the periods when they were employed on more than one pump?

This reference was taken on file as Industrial Dispute No. 87 of 1971 and notices were issued to the parties. For the purpose of convenience, the claimants who are workmen of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Divisions I and II are referred to as the petitioners and the Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Divisions I and II is referred to as the respondent in the course of this award.

2. The petitioners are represented by Andhra Pradesh Singareni Collieries Mazdoor Sangh, Ramagundam (hereinafter referred to as the said Sangh) and the Vice President of the said Sangh filed the claims statement contending as follows:—The persons referred to in the schedule are the pump Khalasis. They are permanent employees. The workmen referred to in the first part of the schedule are in Category III. All these workmen are asked by the Management to operate more than one pump at the same time and they are operating more than one pump for the last few years. When the workmen demanded for payment of Category IV wages the Management refused to pay the same. The Central Wage Board for Coal Mining Industry recommended that a Pump Khalasi operating more than one pump will go to a higher category. The Management of Singareni Collieries Company Limited implemented the Wage Board recommendations with effect from 15-8-1967. But it refused to implement the Wage Board recommendations in the case of the Khalasis referred to in the first part of the schedule. Similarly the persons referred to in the second part of the schedule are deprived of category III wages which they are entitled to as of right as per the recommendations of the Wage Board. All these 10 workmen are placed in category III. They are asked to operate pumps of capacity of more than 35 horse power and they are operating pumps of more than 35 horse power for the last so many years. The workmen referred to in the third part of the schedule are placed in category II by the Management. All these workers are asked to operate more than one pump at the same time of the capacity of more than 35 H.P. and they are operating more than one pump of more than 35 H.P. since the last few years. As per the recommendations of the Wage Board these workmen are entitled to category IV wages. The stand taken by the Management that pump khalasis with less than five years of service are entitled for category II wages and those with more than 5 years are entitled to category III wages is not correct. There is no agreement to that effect between the

workmen and their employer. It is true that some discussion took place between the Unions and Management in the presence of the Sub-Committee of the Wage Board. While the discussions were still going on the Sub-Committee left and because of the divergent stands taken by the Union and the Management no agreement was entered into between the parties. Obviously the Wage Board might have been under the impression that some agreement might have been signed by the parties after the sub-committee left. Not even a single office bearer of any of the Unions has signed the so called minutes agreement referred to in paragraph 5 Chapter IX of Volume I of the Wage Board recommendations. The so called minutes agreement referred to is no agreement in the eye of law. The management virtually refused in the course of conciliation proceedings to place Category II Pump Khalasis in Category III which they are entitled to. Similarly in case of Category III pump khalasis operating more than one pump the Management has taken an unreasonable attitude that the maximum category they are entitled to is only category III. So the Management may be directed to pay the workmen referred to in the first part of the schedule category IV wages and the workmen referred to in the second part of the schedule category III wages and the workmen referred to in the third part of the schedule category IV wages with effect from 15-8-1967.

3. The respondent filed a counter contending as follows: The persons referred to in the schedule I are Pump Khalasis in category III. The reference is not maintainable as the said workmen are claiming for relief for one week from 23-5-1971 to 29-5-1971 and any such arrears comes under the purview of Section 33(c)(2) of the said Act and it cannot be the subject matter of the reference under section 10(1)(d) of the said Act. The workmen, who are asked by the Management to operate more than one pump under the practice obtaining in the Company since the implementation of the Mazumdar Award, have been allotted old Category IV to those who have put in above five years of service and old category III to those who have put in less than five years of service. It is agreed as a special case under the Wage Board recommendations that the pump drivers in Category III should be allotted category II and pump drivers in category IV should be allotted category III and that the Pump drivers in categories II and III shall be interchangeable on all pumps irrespective of Horse power and that in respect of promotions and recruitments after 15-8-1967 pump khalasis working on pumps upto 35 Horse Power under ground and on surface pumps shall be allotted new Category II and those working on pumps from 35 H.P. and above shall be allotted new category III and that the Management would be free to adopt the Bengal and Bihar pattern for the pump drivers to be promoted and recruited in future, that is, category to be fixed depends on the Horse Power of the pump operated by the workmen. The Khalasis had to oil the necessary machine bearings, start the pump mechanism and remain in attendance whilst the machine is in motion. It is patent that if pump khalasis operated two pumps of different H.P. he should be graded according to the largest pump he had to operate. All the pump khalasis referred to in the present dispute are in category III of the Wage Board recommendations and this is the maximum category for pump khalasis and so there is no question of giving extra category. The Government of India in their reference No. 7/18/69-LRII dated 21-4-1969 declined to refer a similar dispute raised in Bellampalli Division as there are no *mala fides* imputed. The workmen referred to in the third part of the schedule are rightly placed in category II. They do not and cannot operate more than one pump at the same time as it is physically impossible to do so. As laid down in job description and nomenclature, the Khalasi has to allow (evidently the word allow is a mistake for 'oil') the necessary machine bearings start up the pump mechanism and remain in attendance while the machinery is in motion. As such any workman attends to one pump only at a time and irrespective of H.P. they are interchangeable on all pumps but continue to get the higher category as between two categories. As per service, a pump khalasi with more than five years is entitled to category III as one of the service conditions which the pump khalasis were enjoying for several years and so it is not left for the claimants to say that there was no agreement. It is evident from the Wage Board recommendations that under Chapter IX and paragraphs 3, 4 and 5 that a specific agreement was recorded during discussions in respect of Pump Khalasis etc. It is therefore, baseless and incorrect to say that there was no agreement reached before the Sub-Committee and the Board agreement cannot be called into question at this stage especially when

the matter is seized in I. D. No. 30 of 1967. Having agreed to enjoy categories III and II to those persons who have put in more than five years of service and less than five years of service earlier to Wage Board implementation it is not for the workmen to ask a higher category. So the present relief sought for is not maintainable.

4. The dispute that is now referred to this Tribunal and which is shown in the schedule to the reference are in three parts and it is with reference to the pump khalasis and their claim for higher category is for the period from 23-3-1971 to 29-5-1971. The first part of the schedule relates to 19 workmen who are in new category III and they are claiming new category IV wages on the ground that they are operating more than one pump. The second part of the schedule relates to 10 workmen who are in new category II and they are claiming new category III wages on the ground that they are operating on more than 35 H.P. pumps. The third part of the schedule relates to 13 workmen who are in new category II and they are claiming new category IV wages on the ground that they are operating on more than one pump and also on more than 35 H.P. pumps. Now the reference is whether the respondent is justified in refusing the higher categories claimed by these workmen.

5. Though in the counter one of the contentions raised is that the reference itself is not maintainable and that since the claimants in the present case are asking for wages for one week they have to file only petition under section 33(c)(2) of the said Act as arrears comes under the purview of that particular section, in the course of the arguments the respondents' representative represented that the respondent is not pressing this objection. So it is not necessary to consider about this objection further.

6. It is also contended in the counter that the agreement reached before the Sub-Committee of the Wage Board cannot be called into question at this stage since the same matter is pending in I.D. No. 30 of 1967. Now it is contended by the respondents' representative that prior to the recommendations of the Wage Board the practice that was prevailing in Singareni Collieries Company Limited was that the pump khalasis who had put in less than five years of service were placed in old category III and that those pump khalasis who had put in more than five years of service were placed in old category IV and so it was agreed as a special case under the Wage Board recommendations that the pump drivers in old category III should be allotted new category II and pump drivers in old category IV should be allotted new category III and that the pump drivers in new categories II and III shall be interchangeable on all pumps irrespective of Horse Power and that in respect of promotion and recruitment after 15-8-1967 pump khalasis working on pumps on 35 H.P. under ground and on surface pump shall be allotted new category II and those working on pumps on 35 H.P. and above shall be allotted new category III and that this agreement was entered into before the Sub-Committee of the Wage Board and so the present claimants cannot claim any higher wages contrary to the agreement and that this agreement is also the subject matter of I.D. No. 30 of 1967 and so if any decision is given in the present case it would be only prejudging the issues in I.D. No. 30 of 1967 and so the present claim cannot be allowed. On the other hand it is contended by the learned counsel for the petitioners that I. D. No. 30 of 1967 has nothing to do with the present claim and that the agreement referred to was not signed by any of the office bearers of the Union and that no valid had been entered into and that there were only some discussions that had taken place and that whatever might have been the practice prior to the recommendations of the Wage Board the respondent is bound to implement the recommendations of the Wage Board, so far as pump khalasis are concerned, when once the respondent had implemented the recommendations of the Wage Board as regards the other workmen. If it is found that the agreement now referred to is also the subject matter of I.D. No. 30 of 1967 and that I.D. No. 30 of 1967 relates to pump khalasis also then it would not be proper to give any findings at this stage as regards the claim made by the claimants because it would be only prejudging the issues in I.D. No. 30 of 1967.

7. Before considering the question whether the present claim of the claimants is covered by I.D. No. 30 of 1967 the evidence let in in this case may be referred to to see whether the claimants are operating on more than one pump and on pumps of more than 35 H.P. W.W. 1 (P. Ramulu) is one of the claimants mentioned in the third part of the

schedule to the reference. He says that he is operating 75 H. P. pump that A. Veeraswamy and Rajamouli are also operating 75 H.P. pump, that S. Suryanarayana, Ghousuddin and J. Samuel operate 62 H.P. pump, that Maddela Burgian and Venkati operate 39.5 H.P. pump, that he knows Moinuddin and others (this Moinuddin is one of the claimants in the first part of the schedule to the reference) that Marugu Gattayya, Bahadur Khan operate two 85 H.P. pumps, that at the same time they operate both the pumps, that Sardar Khan, D. Srihari and Mod. Ghaffar operate three pumps and that those who are operating pumps of 35 H.P. are not given any extra category. Some names referred to by him are the other claimants in the first part of the schedule to the reference.

8. W.W. 2 (M. Eshwar Das) is one of the claimants mentioned in the first part of the schedule to the reference. He says that in each shift he operates two pumps of 75 H.P. each, that he knows all the workmen referred to in schedule No. 1 (reference is to the first part of the schedule to the reference) as items 11 to 17, that they and he are operating two pumps over 35 H.P. continuously. W.W. 3 (D. Seetaramaiah) is working in No. 3 Incline, Godavari Khani as Pump Khalasi. He says that Muthiah, Agiah and Ramulu mentioned under item 3 of the schedule to the reference (reference is to the third part of the schedule to the reference) are also working in No. 3 Incline, that Muthiah and Agiah are working on two pumps of 15 H.P. and 39 H.P. that Ramulu is working on two 75 H.P. pumps and that he and others are working on two pumps even at the time of Wage Board.

9. W.W. 4 (Shaikh Madhar Saheb) is one of the pump khalasis mentioned in the first part of the schedule to the reference. He says that there are two 54 H.P. pumps, one 37½ H.P. pump, one 20 H.P. pump and one 15 H.P. pump, that there are two more pump khalasis with him, that they attend to the maintenance of these pumps and they are not given one extra category for operating more than one pump and more than 35 H.P. pump. W.W. 5 (K. Devadatham) is working as pump khalasi, in No. 1 Incline at Godavari Khani. He says that the Management is paying Acting Allowance of Category III whenever pump khalasis in No. 1 Incline are looking after 35 H.P. pump, that those that are operating pumps more than 35 H.P. who are in category III are not given Acting Allowance of category IV, that he knows D. Radhakrishna, K. Rajanarasu, Konda Lakshman (referred to in the third part of the schedule to the reference) and that they and he were operating above 35 H.P. pumps. W.W. 6 (A. Papaiah) is working as Pump Khalasi in Ramagundam. He says that in his incline if they operate more than 35 H.P. or two pumps they are not given Acting Allowance of higher category. W.W. 7 (Das Posham) is one of the claimants mentioned in the second part of the schedule to the reference. He says that he and others are working on two pumps of 75 H.P. on 31 level at a time, that is himself, Ganga Chinn Posham (Evidently he means Janga Ch. Posham) and Thatukondal Rajam, that there are two pumps of 35 H.P. each in 31 level and Nimala Ramaswamy, K. Venkaty and Moora Posham are working on these two pumps, that they are not given extra category after the recommendations of the Wage Board though they are working on pumps of more than 35 H.P. and on more than one pump.

10. M.W. 1 (M. Satyanarayana) is working as Assistant Engineer. He says that he knows some of the Pump Khalasis mentioned in Item 1 of the schedule to the reference (reference is to the first part of the schedule to the reference). After mentioning some of the names of the Pump Khalasis known to him he says that they are working on 75 H.P. and 62.5 H.P. pumps, that during the week from 23-5-1971 to 29-5-1971 these persons worked on two pumps in three shifts two in each shift, that they worked on two pumps, that the practice in the Company is if category II man works on more than one pump he would be given allowance between category II and category III and that if category III person works on more than one pump he would not be given the allowance between category III and category IV because category III is the maximum category provided by the Wage Board for Pump Khalasis. He also says that the minimum Horse Power pump basis was not fixed for pump khalasis prior to Wage Board and that they had to work on all the pumps whenever they were asked to work, then there was interchange-

ability from pump to pump irrespective of the H.P. of the pumps. He also says that though they worked on two pumps during the week 23-5-1971 to 29-5-1971 they were not entitled to category IV allowance and that for other periods also they are not entitled to category IV allowance. He further says that out of the claimants mentioned in Item II of the schedule to the reference (reference is to the second part of the schedule to the reference), Vodda Rajamallu and Kamuni Odelu are working in G.D.K. No. 5 Incline and that the others are working in other inclines, that they worked on more than 35 H.P. pumps during the week from 23-5-1971 to 29-5-1971 that during the week from 23-5-1971 to 29-5-1971 though two persons referred to by him worked on the pumps more than 35 H.P., they were given only Category II because the H.P. is not taken into consideration in S. C. Co., Ltd. set up, that among the claimants in Item 3 to the schedule to the reference (reference is to the third part of the schedule to the reference) P. Ramulu, B. Rajamouli, Raja Mohammad, J. Samuel, S. Suryanarayana, Ghousuddin, Maddela Durgiah, L. Venkati are working in G.D. K. No. 5 Incline, that they worked on the pumps of more than 35 H.P. and also below 35 H.P. during the week from 23-5-1971 to 29-5-1971 and that they were not paid any difference in the allowance because they worked on only one pump and there is no relevancy of H.P.

11. M.W.2 (Sukhlal) is working as Under Manager in G.D.K. No. 7 and 7A Inclines. He says that out of the claimants in Item I (reference is to the first part of the schedule to the reference) E. Rajam, Kunta Parvathalu and Soula Lakshmaiah are working as Pump Khalasis in No. 7 and 7A inclines, that the pump khalasis working in No. 7 and 7A inclines given the maximum category III if they work on more than one pump or pumps of more than 35 H.P., that these three persons are working in No. 4 level in 7 Inclines and that that three claimants, whose names he mentioned operated more than one pump during the week from 23-5-1971 to 29-5-1971. M.W. 3 (Gangadhar Vanam) is working as Under Manager in G.D.K. No. 3 Incline. With reference to the workmen mentioned in the third part of the schedule to the reference he says that E. Muthiah, K. Agaiah and E. Ramulu are operating more than 35 H.P. pumps, that during the week from 23-5-1971 to 29-5-1971 they operated pumps of more than 35 H.P., that they did not operate on more than one pump during that week. At the same time he says that there are occasions when category II pump khalasis worked on more than one pump in No. 3 Incline and that if they work like that they are given Category III. M.W. 4 (Mohd. Abdul Jabbar) is working as Safety Officer in G.D.K. No. 1 Incline. With reference to the workmen mentioned in the second part of the schedule to the reference he says that only Radhakrishna, Karnam Rajanarasu and Konda Lakshman are working in G.D.K. No. 1 Incline as Pump Khalasis of Category II and that out of them only Konda Lakshman worked on 75 H.P. and 15 H.P. pumps during the period from 23-5-1971 to 29-5-1971, that out of the other two Radhakrishna worked on 25-5-1971 in the 3rd shift on 75 and 15 H.P. pumps in that week and that K. Rajanarasu worked on 25-5-1971, 26-5-1971 and 28-5-1971 on 40 H.P. and 15 H.P. pumps. He also says that even during the other periods other than the week from 23-5-1971 to 29-5-1971 they have been following the rule of giving category III Acting Allowance whenever the pump khalasis of Category II worked on more than one pump. In his cross examination he says that as per the Wage Board the pump khalasis operating pump of more than 35 H.P. is placed in category III and that if he operates pump of less than 35 H.P. he is placed in category II and that in respect of each category the Wage Board says that if he operates more than one pump he should be given higher category, that Radhakrishna and other referred to by him are working on pumps of more than 35 H.P. from 23-5-1971 and that they have also operated more than 75 and 15 H.P. pumps.

12. So from the evidence of all the witnesses taken together it is clear that some of the pump khalasis are operating more than one pump and that some are operating more than 35 H.P. pumps and that some are operating more than one pump of more than 35 H.P. and that in some cases whether the pump khalasis are in Category II are given Category III Acting Allowance and that those who are in category III are not given any higher category even

if they happened to work on more than one pump and the reason now given by the respondent, as seen from the evidence, is that the Wage Board has fixed only Category III as the maximum category for pump khalasis. Since there had been some printing mistake in the book containing the recommendations of the Wage Board some correction had been issued as seen from Ex. W1. The respondent has filed Ex. M1 to show that a similar dispute was raised by the pump khalasis at Bellampalli and that the Government of India had rejected their claim. Ex. M2 is filed to show that with reference to pump khalasis the Indian Mining Association sent a reply to the respondent and Ex. M2 is to the effect that the matter was discussed that the standing Coal Fields Committee meeting held on 4-9-1968 and that it was agreed that if khalasis operated in two pumps of different Horse Powers he should be graded according to the largest H.P. pump he had to operate. Now one of the contentions of the respondent is that an agreement had been entered into before the Sub-Committee of the Wage Board under which as a special case it was agreed that the pump drivers in old Category III should be allotted new Category II and that the pump drivers of old category IV should be allotted new category III and that pump drivers of Categories II and III shall be interchangeable on all pumps irrespective of the Horse Power and that this agreement is also a subject matter of I. D. No. 30 of 1967. It is seen from paragraph 4 of the claims statement that even the petitioners have stated about the discussions that took place before the Sub-Committee and now it is contended that since the agreement was not signed by any Office Bearer of the Union such an agreement cannot have any effect and that the respondent is bound to follow the recommendations of the Wage Board. Now it is seen from the relevant paragraph in the recommendations of the Wage Board viz. paragraph 5 in Chapter IX of Volume I of the Wage Board Recommendations that this is reference made about some agreement entered into between the parties. It is also now seen from the evidence that even though the present claim is only for higher wages claimed for one week, some of the pump khalasis are working on pumps of more than 35 H.P. and that some of the pump khalasis are working on more than one pump even subsequent to the period in question. So if any decision is given now in favour of the claimants the respondent has to comply with the present award in respect of the other periods also. As already stated if the present dispute is also covered by I.D. No. 30 of 1967 then any award that is now given would be prejudging the issues in I.D. No. 30 of 1967.

13. Now it has to be seen whether the present claim can be allowed or whether it should await the result of the decision in I.D. No. 30 of 1967. In order to appreciate the present contention of the respondent it would be useful to refer to the nature of the reference and the nature of the claim put forward in I.D. No. 30 of 1967 so far as Pump Khalasis are concerned. The reference which is the subject matter of I. D. No. 30 of 1967 is as follows:—

“Subject to the views expressed and recommendations made by the Central Wage Board for Coal Mining Industry, and the agreement between the management of Singareni Collieries Company Limited and their trade unions referred to, in paragraphs 3 to 6 of Chapter IX of the Wage Board's report, what further modifications and changes in the Categorisation and wage structure recommended by the said Wage Board for West Bengal and Bihar coal fields are necessary to make the said categorisation and wage structure applicable to the workmen of the Singareni Collieries Company Limited, having regard to the special conditions obtaining in the Andhra Pradesh Coal Fields”.

In that case the different Unions have filed their claims statements and those Unions are Singareni Collieries Mazdoor Sangh, Kothagudem Andhra Pradesh Singareni Collieries Mazdoor Sangh, Kothagudem, Mining Sirdars and Overmen's Association, Bellampalli Kothagudem, Singareni Collieries Workers Union, Kothagudem and Tandur Coal Mines Labour Union. These Unions have filed the claims statements almost on the same lines and so it is not necessary to refer to all the claims statements and reference may be made to the claims statement of one of the Unions. Now in the claims statement filed by the Singareni Collieries Mazdoor Sangh, Kothagudem, the claim put forward with reference to Pump Drivers is as follows:—

"Pump Drivers: Under the Mazumdar Award they were placed on category as under:—

Upto 35 H.P.	Category II
Upto 125 H.P.	Category III
Over 125 H.P.	Category IV.

The categorisation was based on H.P. and number of pumps handled. The Singareni Collieries while implementing the Mazumdar Award made a departure from this recommendation and prescribed only two categories III and IV. Above 5 years of service by a Pump Driver, would entitle him to be placed on Category IV. The categorisation on the basis of H.Ps. and number of pumps was not followed. As this mode has been found to be favourable and as favourable conditions are not contemplated to be altered by the directions of the Wage Board, the workmen demand that they should be paid the wages of Rs. 5.90—0.15—7.40 of new Category III and Rs. 6.90—0.20—8.90 of new Category IV prescribed by the Wage Board and on the basis of service with the minimum grade being Rs. 5.90—0.15—7.40 of new Category III.

14. The respondent while dealing with the claim of the pump khalasis in its counter in I. D. No. 30 of 1967 stated as follows:—

(6) **Pump Khalasis.**—Pump Khalasis are covered by job description No. 150. In Singareni the Pump Drivers are engaged on identical work. The Coal Award allotted the following categories for Pump Drivers or Pump Khalasis.

- (1) Pump Khalasis upto 35 H.P. Category II.
- (2) Pump Khalasis upto 125 H.P. Category III.
- (3) Pump Khalasis above 125 H. P. Category IV.

The same categories have been allotted under the Coal Award for Singareni vide Appendix XIII of the Coal Award. Although the Majumdar Tribunal allotted the same categories in Bengal and Bihar for pump drivers and although there were no special features in regard to job description or any other factor, the Union requested that instead of sticking up to H. P. which would make it difficult for the inter-changeability of pump drivers, pump drivers with 5 years service and under may be allotted category III and pump drivers with 5 years service and above may be allotted category IV. This request was agreed to during October, 1956, several months after the Coal Award was implemented and the conditions laid down do not recognise that there were any special features in regard to pump drivers in Singareni. It may be mentioned that not a single worker was allowed any category higher than what was recommended under the coal award viz.—Category III and category IV.

The Wage Board has recommended the following categories for pump drivers.

- (1) Those working on pumps upto 35 H. P. new category 2.
- (2) Those working on pumps of 35 H. P. and above New Category 3.

The Wage Board also prescribed that if a worker works on more than one pump he should be allowed one category higher. This feature was not recommended under The Coal Award. For the first time it was recommended under Sri Das Gupta's Arbitration Award. The same was incorporated in the Wage Board's recommendations, which is applicable to the entire industry. Although no special features exist in regard to job description etc., this issue was also discussed with the Unions in the presence of the Sub-Committee of the Wage Board during February, 1966 when it was agreed as under:—

"It was therefore agreed as a special case that the Pump Drivers in category III should be allotted the revised category II and the Pump Drivers in Category IV should be allotted the revised Category III. The workers who would be allotted the revised categories II and III would be interchangeable on all pumps irrespective of Horse Power. If however any of them is required to operate more than one pump, he will be given

one category Higher than the one in which he is now placed. In view of this arrangement the question of service will cease to have any bearing in the allotment of categories. The Management will be free to adopt the Bengal and Bihar pattern of categorisation for Pump Drivers to be promoted or recruited in future i.e. the category to be fixed would depend upon the Horse Power of the Pump operated by the worker".

The Management have accordingly implemented the new category 2 and 3 for Pump Khalasis and majority of the workers thus achieved the new category 3 in view of their past service and this is the highest category which is contemplated for Pump Khalasis under the Wage Board's recommendations.

The Unions have demanded that Pump Khalasis should be allowed the minimum of new category 3 and those with more than 5 years service should be allowed new category 4. As all the workers have completed more than 5 years service this demand would in practice mean that all the Pump Drivers should be allotted the new category 4 which is one category higher than the highest category recommended by the Wage Board, viz., category 3. There is absolutely no justification for this demand specially as there is no difference in job description for this category of workers and as under the Coal Award no worker in Singareni was allowed anything higher than what was given in Bengal and Bihar.

15. So from the claims statement filed in I. D. No. 30 of 1967 it is seen that the claim put forward is that the Pump Khalasis should be paid the wages of new Category III and the Wages of new Category IV prescribed by the Wage Board on the basis of minimum grade being new Category III, on the ground that the categorisation on the basis of H. Ps. and number of pumps is favourable. It is also seen from the counter filed by the respondent in I. D. No. 30 of 1967 that the respondent had stated that the recommendations of the Wage Board shown that if a worker works on more than one pump he should be allowed one category higher was also discussed with the Union in the presence of the sub-committee of the Wage Board and that it was agreed that as a special case the pump drivers in category III should be allotted the revised category II and that the Pump Drivers in category IV should be allotted the revised category III and that the workers who were allotted revised categories II and III would be interchangeable on all pumps irrespective of Horse Power and that if however any of them is required to operate more than one pump he would be given one category higher than the one in which he is now placed and that in view of this arrangement the question of service will cease to have any bearing in the allotment of categories. It is seen from paragraphs 4 and 5 of the Chapter IX of Volume I of the report of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry that in order to assist the parties in arriving at an agreed settlement, the Board deputed a Sub-Committee to discuss the matter with the representatives of the Management and that at that meeting it was generally accepted that the categorisation as recommended for all coal fields in India excluding Assam should be adopted in the Singareni Collieries Company Limited also and that the Management and the Unions held further discussions with a view to equate the designation and the job description and that specific agreement was recorded during those discussions in respect of pump Khalasis and others mentioned therein. Even though in the recommendations of the Wage Board it is mentioned that specific agreement was recorded in respect of pump Khalasis, now this fact is being disputed by the workmen both in the present case as well as in I. D. No. 30 of 1967. It is the contention of the petitioners that there was never any such agreement entered into before the Sub-Committee whereas the contention of the respondent is that the agreement was entered into and that it is only pursuant to that agreement as a special case the Pump khalasis were given new Categories II and III. So the question whether there was really any such agreement arrived at is a matter that has to be decided and this very same matter has to be considered in I. D. No. 30 of 1967 also.

16. Now the present claim of the claimants is that for the period from 23-5-1971 to 29-5-1971 the Pump Khalasis who are in new Category III and who worked on more than one pump should be given new category IV wages

and that the Pump Khalasis who are in new Category II and who worked on Pumps of more than 35 H. P. should be paid new Category III wages and that the Pump Khalasis who are in new Category II and who worked on more than 35 H.P. pumps and on more than one pump should be paid new Category IV Wages. Now this very same question has to be decided in I. D. No. 30 of 1967. So it would not be proper to give any finding at this stage in the present dispute because any such finding would only be prejudging the relevant issues in I. D. No. 30 of 1967 so far as Pump Khalasis are concerned. In I. D. No. 30 of 1967 relates to all the Pump Khalasis whereas the present claim is put forward only by some of the Pump Khalasis and that too for a period of one week. So the present claimants should await the result of the dispute in I. D. No. 30 of 1967. In this view of the matter I hold that though it is true that claimants in this case have operated during the week from 23-5-1971 to 29-5-1971 some on more than one pump and some on pumps of more than 35 H.P. and some of pumps of more than 35 H.P. and on more than one pump they are not entitled to any relief at this stage and that they should await the result of the claim put forwarded by all the Pump Khalasis in I. D. No. 30 of 1967.

17. For all the aforesaid reasons I hold on the dispute that is referred to for adjudication that though the 19 claimants mentioned in the first part of the schedule to the reference had operated on more than one pump and though the 10 claimants in the second part of the schedule to the reference have operated on more than 35 H.P. and though the 13 claimants in the third part of the schedule to the reference have operated on more than one pump and also on more than 35 H.P. pump, these claimants are not entitled to any relief at this stage because the question whether the action of the Management is not giving them higher category wages is justified or not cannot be decided in view of the question whether fixing of the categories is correct or not is itself in dispute in I. D. No. 30 of 1967 and since any finding now given would be only prejudging the relevant issues in I. D. No. 30 of 1967 wherein the dispute relates to all the Pump Khalasis working in all the mines whereas the present dispute is with reference only to some of the Pump Khalasis working in some of the Mines.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 28th day of December, 1972.

P. S. ANANTH, Presiding Officer.

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses Examined For Workmen.

- W.W. 1 P. Ramulu.
- W.W. 2 M. Eshwar Das.
- W.W. 3 D. Seetaramaiah.
- W.W. 4 Sheikh Yakooab ali.
- W.W. 5 K. Devadatham.
- W.W. 6 A. Papaiiah.
- W.W. 7 Das Posham.

Witnesses Examined For Employees.

- M.W. 1 M. Satyanarayana.
- M.W. 2 Sukhlal.
- M.W. 3 Gangadhar Vanam.
- M.W. 4 M. A. Jabbar.

Document's Exhibited For Workmen.

Ex. W. 1.—Copy of the letter dated 23-5-1970 of Government of India Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), New Delhi, addressed to the Labour Relations Adviser, Associated Cement Companies Limited, Bombay.

Documents Exhibited for Employers.

Ex. M. 1.—Copy of the letter dated 21-4-1969 of Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, (Department of Labour and Employment), New Delhi, addressed to the Agent,

Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli and the Vice-President, Singareni Collieries Workers' Union, Bellampalli.

Ex. M. 2.—Copy of the letter dated 1-7-1968 of the Secretary, of Indian Mines Association, Calcutta addressed to the General Manager, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.

Industrial Tribunal.

New Delhi, the 17th February, 1973

S.O. 533.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Tisra Colliery of Messrs Diamond Coal Company Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th February, 1973.

[No. L/2019/15/71-LR.II.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2) AT DHANBAD

PRESENT

Shri Nandagiri Venkata Rao, Presiding Officer

Reference No. 30 of 1971

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Parties:

Employers in relation to the management of Tisra Colliery of Messrs Diamond Coal Company Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad

AND

Their workmen.

Appearances:

On behalf of the employers in relation to the management of Tisra Colliery of Messrs Diamond Coal Company Private Ltd.—Shri P. K. Bose, Advocate.

On behalf of Bharat Coking Coal Ltd.—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri B. Lal, Advocate.

State: Bihar.

Industry: Coal.

Dhanbad, the 7th February, 1973

ORDER

The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Tisra Colliery of Messrs Diamond Coal Company Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen, by its order No. L/2012/15/71-LR. II dated 12-2-1971 referred to this Tribunal under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the schedule annexed thereto. The schedule is extracted below:

"Whether the action of the management of Tisra Colliery of Messrs Diamond Coal Company Private Limited, Post office Jharia, District Dhanbad in stopping the following workmen from work with effect from the 22nd September, 1970 is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

Sl. No.	Name of the workmen	Designation
1.	Prabhu Singh	Coal Cutter
2.	Saban Dusadh	—do—
3.	Ramadhhar Dusadh	—do—
4.	Makhan Ram Bilaspuri	—do—
5.	Sohbat Mia	—do—
6.	Deocharan Bilaspuri	—do—
7.	Harilal Bilaspuri	—do—
8.	Ramkishan Bilaspuri	—do—
9.	Sohanlal Yadav	—do—
10.	Dileram Bilaspuri	—do—
11.	Pardeshi Bilaspuri	—do—
12.	Sewak Ram Bilaspuri	—do—
13.	Rameswar Bilaspuri	—do—
14.	Ramdas Bilaspuri	—do—
15.	Binoy Singh	—do—
16.	Chintaram	—do—
17.	Ghasia	—do—
18.	Sarjoo Ram	—do—
19.	Babuchand Singh	—do—

2. Employers as well as the workmen filed their statement of demands.

3. The 19 affected workmen mentioned in the schedule of reference were coal cutters in Tisra colliery of the employers, M/s. Diamond Coal Co. (P) Ltd., P.O. Jharia, District Dhanbad. They were stopped from working with effect from 22-9-1970. These facts are not in dispute. According to the workmen, the affected workmen were permanent employees in the colliery and as such their services could not be terminated without notice. It is further stated in the written statement of the workmen that the employers were indulging in serious malpractice such as changing of names of workmen to deprive them of continuity of service, quarterly bonus, membership of the provident fund, annual leave and profit sharing bonus etc. against which the workmen have been protesting and the union, Koyala Ispat Mazdoor Panchayat has lodged complaints to authorities and in the lists so submitted names of the affected workmen were included. In the written statement the employers have taken at the outset an objection that neither the affected workmen themselves nor their union had raised any dispute before the employers and, as such the present one is not an industrial dispute. According to the employers all the affected workmen were temporary coal cutters having worked for less than 3 months and, as such their services were terminated without any written notice because their services were no more required. Pending the reference it had come to the notice of the Tribunal that the colliery was taken over by the Government of India and, as such the Tribunal deemed it necessary to implead the Bharat Coking Coal Ltd. as a party and gave notice to the Bharat Coking Coal Ltd. under S. 18 of the Industries Disputes Act, 1947. On behalf of the Bharat Coking Coal Ltd. written statement is filed adopting the written statement of the employers and further pleading that there did not exist any relationship of employer and employees between the Bharat Coking Coal Ltd. and the affected workmen, that there was no industrial dispute between Bharat Coking Coal Ltd. and the workmen and that the Bharat Coking Coal Ltd. is in no way liable or responsible for any act of the past management prior to the date of taking over of the colliery. The workmen were represented by Shri B. Lal, Advocate, the employers by Shri P. K. Bose, Advocate and the Bharat Coking Coal Ltd. by Shri S. S. Mukherjee, Advocate. On admission by the workmen. Exts. M1 to M3 were marked for the employers. On behalf of the employers 2 witnesses were examined and Ext. M4 was marked. On behalf of the workmen 3 witnesses were examined but no document was marked. No witness was examined and no document was marked for the Bharat Coking Coal Ltd.

4. The legal objection taken by the employers is that the dispute referred for adjudication was not an industrial dispute, inasmuch as before it was raised with the Assistant

Labour Commissioner no dispute was raised with the employers on the question of stoppage of work of the affected workmen. From the failure report accompanying the order of reference it appears that the Vice President, Koyala Ispat Mazdoor Panchayat Jharia had raised an industrial dispute with the Assistant Labour Commissioner over alleged illegal and wrongful stoppage of work of the affected workmen vide his letter dated 20-10-1971. The letter is admitted by the employers and it is Ext. M1. The Assistant Labour Commissioner sent a copy of the letter to the employers for comments and the comments submitted by the employers on 30-11-1970 are Ext. M3. Thereafter the dispute was admitted into conciliation on 31-12-1970. The Patna High Court in CWJC 1513 of 1969 dated 1-9-1971 in Managing Contractor v. the Presiding Officer and others has held that it is not necessary that the demand of the workmen should be made directly to the management and that when the Assistant Labour Commissioner sent a copy of the complaint of the workmen to the management and the management refuted it, the demand and refusal were there for the existence of an industrial dispute. In view of this decision I find no substance in the objection. The objection is over ruled.

5. Though it was stated by the workmen in their written statement that the affected workmen were employed as permanent workers in the colliery, it is admitted by the only affected workman examined, WW.1 that he was a temporary workman. According to WW. 2 the affected workmen were not members of Coal Mines Provident Fund and they were treated as temporary workmen. The substance of the evidence of WW.3 is also to the same effect, although he complains that the employers were manipulating records to deprive the affected workmen of the benefits of permanent workmen. MW.1, the then manager of the colliery has deposed that in the colliery model standing orders were being followed. Schedule I of the Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1946 contain the model standing orders. According to Rule 13 no temporary workman whether monthly rated, weekly rated or piece rated is entitled to any notice or pay in lieu thereof if his services are terminated. Hence, no notice was required to stop the affected workmen from work. According to Rule 2(c) a 'temporary' workman is a workman who has been engaged for work which is of an essentially temporary nature likely to be finished within a limited period. The manager, MW.1 has in his evidence that the 19 affected workmen along with some other temporary miners could not be provided with work as no work was available from 22-9-1970 and that they being temporary had gone away having finished their work. There is no rebuttal to this evidence. The only allegation made by WW.2 and spoken to by WW.3 is that though all the affected workmen had worked atleast for 4 or 5 years continuously in the colliery, the employers used to change their names in the B form register every 3 months to deprive them of the benefits of permanent workmen. This is a serious allegation made against the employers and as such it requires to be seen how far this could be correct. As I have stated earlier, only one of the affected workmen is examined and he is WW.1. He had not a word to speak about the allegation. WW.2 is working in the colliery from 1951 and he is a member of the Koyala Ispat Mazdoor Panchayat, the union which has raised the present dispute, from 1953-54. According to the Vice President of the union, WW.3, WW.2 is a prominent worker of the branch of the union at the colliery. WW.2 says that from the very beginning he knew that the employers were changing names of the affected workmen in the B form register every 3 months. But he does not seem to have made any complaint to the union at any stage during so many years till the affected workmen were stopped from work finally. The witness, WW. 2 was also aware that owing to this change of names the affected workmen suffered loss. He is also looking after the affairs of the union in the colliery. He says that when the affected workmen were made idle he had submitted a written report to the union regarding changing of names of the affected workmen every 3 months by the employers and on the basis of this report the union had raised the present dispute. The union had raised the present dispute through their letter, Ext. M1 addressed to the Assistant Labour Commissioner. The allegation was very serious and yet surprisingly, it finds no place in the letter, Ext. M1. Ext. M1 complains that the affected workmen were not paid their wages for three weeks and yet this serious allegation is not referred to. I find force in the contention of the employers that the allegation is the result

of an after thought on the part of the workmen. The workmen through their application submitted on 26-10-1971 had called for Form B registers from the employers and they were produced by the employers on 30-3-1972. The employers have also examined MW. 2 and proved the Form B register for 1969-70 and it is Ext. M4. But the workmen have not made use of any of the registers. All this apart, the Vice President of the union, WW3 has pointed out that the Coal Mines Provident Fund Organisation has field inspectors and one of their duties is to visit each colliery and inspect the records periodically. If there was any such malpractice on the part of the employers the field inspectors would have reported against it. On this material I find that there is no substance in the allegation. Obviously, the affected workmen were temporary and they were stopped from work when further work could not be provided for them.

6. I, therefore, find that the action of the management of Tisra Colliery of Messrs Diamond Coal Company Private Limited, Post office Jharia, District Dhanbad in stopping the 19 affected workmen from work with effect from 22nd September, 1970 was justified and, consequently they are not entitled to any relief. The award is made accordingly and submitted under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

N. VENKATA RAO, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1973

आदेश

का. आ. 534.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा-बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में प्रीमियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड/दि कनारा मोटर एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसूर से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करना वांछनाय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री नारायण राय कडूर होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करती है ।

अनुसूची

“क्या प्रीमियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसूर, जिसको बाद में दि न्यू प्रीमियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसूर लिमिटेड, मैसूर के रूप में बदल दिया गया के महाप्रबंधक की, जो कनारा मोटर एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसूर का भी प्रबंध निदेशक था, श्रीमति आर. एस. चूडामणि की सेवाओं को समाप्त करने की कारवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो, कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[फा सं. एल. 17011/15/71-एल. आर-1]

New Delhi, the 25th January, 1973

ORDER

S.O. 534.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Premier Insurance Company Limited/The Canara Motor and General Insurance Company Limited, Mysore and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Narayan Rai Kudoor shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the action of the General Manager of the Premier Insurance Company Limited, Mysore who was also the Managing Director of the Canara Motor and General Insurance Company Limited, Mysore and later converted as The New Premier Insurance Company Mysore Limited, Mysore in terminating the services of Smt. R. S. Choodamani, is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?”

[F. No. L 17011/15/71-LR. I.]

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1973

आदेश

का. आ. 535.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा-बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में एसोसिएटेड स्टोन इंडस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड, रामगंजमंडी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करती है ।

अनुसूची

“क्या एसोसिएटेड स्टोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधतंत्र की, श्री घासीलाल चौकीदार की 4 जुलाई, 1972 से सेवाओं को समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का, यदि कोई हो, हकदार है ।”

[सं. एल-29012/33/72-एल. आर.-4]

New Delhi, the 30th January, 1973

ORDER

S.O. 535.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Associated Stone Industries (Kotah) Limited, Ramgunjmandi and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Updesh Narain Mathur shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Associated Stone Industries Limited in terminating the services of Shri Ghasilal Chowkidar, with effect from 4th July, 1972 was justified ? If not, to what relief, if any, is the workman entitled ?”

[No. I-29012/33/72-LR. IV]

नई दिल्ली, 31 जनवरी 1973

New Delhi, 8th February, 1973

आदेश

का. आ. 536.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा-
बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एसोसिएटेड
स्टोन इन्डस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड की लक्ष्मीपुरा लाईम स्टोन क्वारी,
रामगंजमंडी (जिला कोटा) के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और
उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के
लिए निर्दिष्ट करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का
14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा एक
औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी
श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और
उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन
के लिए निर्दिष्ट करती है ।

अनुसूची

“क्या मैसर्स एसोसिएटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड की
लक्ष्मीपुरा लाईम स्टोन क्वारी, रामगंजमंडी (जिला कोटा)
के प्रबंधन की, महिला मजदूर, श्रीमती जॉरावर बाई
को 14 मार्च 1972 से काम न देने की कार्रवाई न्यायो-
चित थी ? यदि नहीं तो, वह किस अनुतोष का, यदि
कोई हो, हकदार है ?

[सं. एल. 29012/29/72-एल. आर. 4]

एस. एस. सहस्रनामन, अवर सचिव

New Delhi, the 31st January, 1973

ORDER

S.O. 536.—WHEREAS the Central Government is of opin-
ion that an industrial dispute exists between the employers in
relation to the management of Laxmipura Lime Stone Quarry
of Messrs. Associated Stone Industries (Kota) Limited, Ram-
gunjmandi (District Kota) and their workmen in respect of
the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

AND WHEREAS the Central Government considers it
desirable to refer the said dispute for adjudication ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred
by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal
with Shri Updesh Narain Mathur as Presiding Officer with
headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudi-
cation to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Laxmipura
Lime Stone Quarry of Messrs. Associated Stone
Industries (Kota) Limited, Ramgunjmandi (District
Kota) in refusing employment to Shrimati Zorawar
Bai, Female Mazdoor with effect from the 14th
March, 1972 was justified ? If not, to what relief,
if any, is she entitled ?”

[No. L-29012/29/72-LR. IV]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

S.O. 537.—In pursuance of section 17 of the Industrial
Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government
hereby publishes the following award of the Central Govern-
ment Industrial Tribunal, Bombay, in the industrial dispute
between the employers in relation to the management of
Messrs F.C.R. Machado and Sons, Stevedores, Vasco-da-Gama
(Goa), and their workmen, which was received by the
Central Government on the 27th January, 1973.

[No. L-36011/6/71-P&D]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL, BOMBAY.

Reference No. CGIT-10 of 1971

Parties :

Employers in relation to the management of Messrs.
F.C.R. Machado and Sons, Stevedores, Vasco-da-Gama.

AND

their workmen.

Present :

Shri A. T. Zambre, Presiding Officer.

Appearances :

For the employers:—Shri Ramesh Desai, Labour Adviser.

For the workmen:—Shri G. D. Badkamkar, General

Secretary.

State.—Maharashtra.

Industry.—Major Ports and Docks.

Bombay, 10th January, 1973.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Reha-
bilitation, Department of Labour and Employment, have by
their Order No. L-36011/6/71 R & D dated 1st November,
1971 referred to this Tribunal for adjudication an industrial
dispute existing between the employers in relation to the
management of Messrs. F.C.R. Machado and Sons, Steve-
dors, Vasco-da-Gama, and their workmen in respect of the
matters specified in the following schedule:—

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Messrs.
F.C.R. Machado and Sons, Stevedores, Vasco-da-
Gama, in placing Shri Vaman C. Prabhu, Super-
visor, in the pay scale of Rs. 150-4-170-5-195-6-225-
7-260 scale of pay of a tally clerk, while imple-
menting the recommendations of the Central Wage
Board for Port & Dock Workers at Major Ports is
justified? If not, to what relief is the workmen
entitled?”

2. The facts leading to the dispute may be stated in brief
as follows:—

The employers Messrs. F.C.R. Machado & Sons are a
firm registered under the partnership Act and have been
carrying on the business of stevedoring in the Mormugao
Harbour under a stevedoring licence issued by the Port.
They are also registered employers under the Dock Workers
Scheme. In addition to carrying on the stevedoring busi-
ness they are also shipping agents and commission agents.
In the year 1970 the said firm was converted into a private
limited company under the Indian Companies Act and the
assets and liabilities of the firm passed on to the private
limited company, namely Machado & Sons, agents of Steve-
dors Private Limited. The Stevedoring licence issued to
the firm was also changed to Machado & Sons Agents of
Stevedores Pvt. Ltd., and the employees of the outgoing
concern were continued by the company without any break

of service and on the same terms and conditions and there was no change in the business of the company. Everything was the same except the change in the name.

3. Shri Vaman Prabhu the workman concerned in this reference has been working with the management since the year 1967. He was working as supervisor at the jetty plot. Till the year 1970 the firm was handling the cargo of M.M.T.C. Subsequently after termination of the contract with M.M.T.C. the management transferred the services of Shri Vaman Prabhu to their stevedoring department where he started working as a member of the supervisory staff.

4. The Government of India by their resolution No. WB-21(7)/69 of 28th March, 1970 accepted the unanimous and majority recommendations of the Wage Board for Port and Dock workers with effect from 1-1-1969. The Wage Board had recommended scales of pay to the stevedoring staff and the employers had implemented the recommendations. While implementing the said recommendations the management fitted the claimant Shri Vaman Prabhu in the scale of Rs. 150-260 which was the scale recommended for tally clerks instead of fixing him in the scale of Rs. 200-550 recommended for foremen. The workman brought this fact to the notice of the management but did not get any favourable reply and hence he approached the management through his union the Mormugao Stevedores Staff Association of which he was a member. The association called upon the management to rectify the mistake in respect of the scale of Shri Vaman Prabhu but the management adopted a negative attitude. Hence the union raised a dispute before the Assistant Labour Commissioner (Central). The management did not take part in the conciliation proceedings and hence there was a failure report on which the Central Government referred the dispute to this Tribunal for adjudication.

5. The Mormugao Stevedores Staff Association has by its statement of claim and rejoinder contended that the workman Shri Vaman Prabhu was appointed as supervisor at the Jetty Plot in the year 1967. After the termination of the contract by the M.M.T.C. Shri Prabhu was transferred by the management to work on board the vessel in supervisory capacities under the Chief foreman. Shri Vaman Prabhu since then has been working as a foreman on board the vessel and has been supervising the loading and unloading operations by the workers subject to the directions issued by the Master of the Vessel. The association has denied the contention of the employers that Shri Prabhu was transferred in the same capacity to the stevedoring department and has contended that he in fact was performing the duties of a foreman on board the vessel since the inception of his transfer. It has been contended that the Central Wage Board for Port and Dock Workers have grouped the scales of pay under different designations. In respect of stevedoring supervisory staff the said Board had reduced the number of different categories in order to introduce a uniform pattern in respect of designations and scales and accordingly the supervisory staff and stevedoring staff was brought under three broad headings and Shri Vaman Prabhu should have been equated to the post of foreman. The conduct of the management in equating the so called supervisor working as foreman on board the vessel to that of tally clerk was unfair and unjust. It is alleged that the management has deprived the workman from getting his legitimate dues under the guise of different designations for the same work and the management should be directed to fix Shri Vaman Prabhu in the scale of Rs. 200-550 with effect from 1-1-1969 in addition to the other benefits such as D.A., C.C.A., H.R.A., and additional D.A., which also should be paid to him with effect from 1-1-1969.

6. The employers have by their reply statement admitted that they had transferred the business of the company to Messrs. Machado & Sons, Agent and Stevedores Pvt. Ltd. They have further admitted that the workman Shri Vaman Prabhu was working as a supervisor at the jetty plot but have contended that after the termination of the contract with M.M.T.C. they had to retrench certain staff and absorb some of them and Shri Vaman Prabhu was absorbed in the stevedoring department of the company and he was asked to work as a supervisor. They have contended that Shri Prabhu was working in the stevedoring department as a supervisor and not as a foreman. It has been further contended that in the port of Mormugao the designations given to the stevedoring staff were traditional and they

were not in conformity with designations found in other major ports. In the port of Mormugao each company in general used to have Chief foreman, Foreman Assistant or Junior Foreman, Tally clerk and supervisors and the supervisor known in the port of Mormugao used to be of a lower rank than even a tally clerk traditionally. The job of supervisor cannot be equated with that of foreman and the classification of Shri Vaman Prabhu on the basis of the existing practice and nature of work was fair and just and the scale of pay given to him was not only justified but also liberal since he was equated to the tally clerk.

7. In support of their contentions the association has examined Shri Vaman Prabhu the workman concerned Shri Padte and Shri S. M. D'souza a foreman of the company. They have also produced a number of documents such as appointment letters and daily loading form etc. The management has not examined any witness and the question is whether the action of the management in placing Shri Vaman Prabhu in the scale of tally clerk is justified.

8. It is not in dispute that while implementing the recommendations of the Central Wage Board the workman Shri Vaman Prabhu was placed in the Scale of Rs. 150-260 equating his job to that of a tally clerk. The employers have contended that Shri Prabhu was originally employed as a supervisor at the jetty plot and subsequently he was transferred to the stevedoring department in the harbour in the same capacity and hence he was placed in the scale of Rs. 150-260. Thus it is denied that Shri Prabhu was working as foreman after his transfer and it has been contended that his work after the transfer was the same as that of a supervisor working at the jetty plot.

9. It is not in dispute that Shri Prabhu was transferred from the jetty plot to the stevedoring department in the month of April 1970 and he started working at the harbour on the vessels from that time. He has stated in evidence that after his transfer he started going to the docks. He was directed to work at the jetty as supervisor. There was a difference in the work at the jetty and the docks. At the docks he was required to take the gangs and winchmen and check them while they were in their launch. He was to take them to the steamer and put them on the hatches. The work was allotted hatchwise. The gangs were to disembark on the barges and the winchmen were to take on board the vessel and there he was directing them and supervising their work. The gangs were to fill the net sling with ore with the help of shovels. The winchmen used to hoist the net sling and get the ore on board. The winchmen were to dump the material of the next sling in the hold and he used to supervise their work and if there was any dispute or quarrel he used to enquire and see that the work was going on smoothly and he was working as a foreman. He has further stated that the Manager of the company used to go to the docks and allot work to the supervisory staff. He has further added:—

"I shall be able to say the difference between the work of the foreman and supervisor. The work of both is the same but the difference is the officer on the deck of the steamer will speak only to the foreman and not to the supervisor."

The union has contended that these were the duties of a foreman and Shri Prabhu should have been placed in the scale of the foreman.

10. Witness, Shri Fadte who is also working with the management has supported the evidence of the workman and stated:—

"They told me that I was to work as foreman. The foreman has to do the work of supervising loading, unloading and to arrange for the storing of the cargo properly".

He has further stated:—

"In our company there are two categories of employees who go on board the vessel. They are foreman and supervisors. There is no difference between the duties of the two categories. But the pay is different."

He has further stated that on the boat they were required to take the shore labour i.e. winchmen and gangmen and distribute work to them. Thereafter they were required to go to the boat and supervise the work of unloading the barges.

1. Considering these duties it shall have to be held that the duties Shri Vaman Prabhu was performing after his transfer to the harbour are those of a foreman.

It is significant to note that the work of Shri Prabhu as supervisor at the jetty plot was of a simple nature. Shri Prabhu has stated:—

"I joined the company F.C.R. Machado & Sons before about five years as a supervisor and I was working on a plot at jetty where the wagons of ore are unloaded and I was supervising the unloading work."

The jetty portion is in the railway area (Southern Railway), and as a supervisor at the jetty he was required to see that the workers were unloading wagons properly near the railway line and giving necessary directions and to see that there was no obstruction for further unloading. He has stated that though he was transferred to the harbour the management was designating him as a supervisor. Thus it is clear that the duties at the harbour are quite different from those performed at the jetty. They carry higher responsibility. The duties of supervisor working at the jetty and the so-called supervisor working on the vessel are different. Clearly the duties of the so-called supervisor on the vessel are that of a foreman and the contention of the management that because Shri Prabhu was working as supervisor at the jetty they placed him in the scale of the tally clerk does not stand to reason.

12. The contention of the union that Shri Prabhu the supervisor working at the harbour works as a foreman will be also clear from the evidence of the witnesses in respect of the distribution of work by the employers among the supervisory staff. Witness Shri Fadte has stated:—

"As a result of the Wage Board recommendations the salaries of some employees were raised and so also mine. In our company there are two categories of employees who go on board the vessel. They are foremen and supervisors. There is no difference between the duties of the two categories. But the pay is different."

He has further stated that though there was no difference in duties of the foreman and the supervisor the management pays more to the foreman but he did not know why they paid the supervisors less.

13. The other witness D'souza who is also working as a foreman in the company has stated:—

"I am attached to the harbour office. When there is a ship allotment of work is done by the Manager. The ship works in three shifts. There is no fixed rule of allotment of work. When there is one ship the management sends two to four persons for one shift. Sometimes they even send one person when there is one ship. In the harbour staff there are three categories (1) foreman (2) assistant foreman and (3) supervisor. We are in all 12 attached to the harbour those who go on board the vessel. When there are more vessels 12 have to be split up. We are getting weekly off in rotation and when there are more vessels say two still the management sends us for weekly off. When there are two persons on weekly off the remaining ten are distributed in the two vessels. The persons returning from duty are again sent for work and are given overtime. The foreman, assistant foreman and supervisors constitute the group of 12."

Thus this evidence clearly shows that all the 12 employees who constitute the supervisory staff are employed on the work alike and are doing the same work irrespective of their designations.

14. Shri D'Souza had made the issue more clear and stated that out of the 12 employees two are foremen, two assistant foremen and the rest supervisors. He has further

stated that even the supervisor also manages the ship as a foreman.

15. The management had issued circulars about the work to be done by the supervisory staff. Shri D'souza produced them in all six pages exhibit W-4. The supervisors are also required to work according to this circular and this shows that in spite of the designations the duties performed by these 12 people are almost the same. Shri D'souza has stated that when there are three or four ships and the supervisor acts as a foreman the duties of the foreman as stated in the circular are done by the supervisor. In the circular issued there is a tally sheet which shows that the sheets are to be signed by particular employees but Shri D'souza has stated that they had no chief foreman and the line in the tally sheet in that respect is redundant. There is also a line regarding foreman and when the supervisor works as foreman he signs as foreman. It appears that there is no difference in respect of the responsibility of the employees. Shri O'souza has stated:—

"It is correct to say that the person signing as a foreman even if he be a supervisor is taken to task if there is some mistake in the hajri. When the vessel is complete then it is the supervisor who is working as foreman who has to obtain the signature of the chief officer on the statement."

and the evidence of Shri Prabhu and the witnesses leaves no doubt that all the members of the supervisory staff are performing the same duties and the so-called supervisor works at the harbour as foreman though he is designated as supervisor.

16. I have already discussed the duties of Shri Prabhu as Supervisor on the jetty and the mere fact that he was working there as supervisor will not justify the action of the management in placing him in the scale of tally clerk and the management ought to have considered the change in his duties after the transfer.

17. It is significant to note that even the Wage Board had equated the Assistant Supervisor to Assistant Foreman and had given them the same scale. The table on page 162 of the Report of the Wage Board states as follows:—

Category	Ports	New Scale
1. Tally/Sorting Clerks	All ports	Rs.150-4-170-5-195-6-225-7-260.
10. Assistant Supervisors	All ports.	} Rs.180-5-190-8-270-10-370
13. Assistant foreman.	Madras, Cochin Mormugao and Kandla.	

18. Thus it is clear that the Wage Board had equated assistant supervisors with assistant foremen. While formulating the proposals on scales the Wage Board had taken into consideration so many factors including the pay scales pattern existing at the Mormugao harbour and there is much substance in the contention raised by the union that Shri Vaman Prabhu who was designated as supervisor on board the vessel should have been placed in the scale of foreman.

19. The management had contended that at the Mormugao Port in general each company used to have a chief foreman, foreman, assistant or junior foreman tally clerk and supervisors and the supervisor was lower in rank than a tally clerk and the fitting of the supervisor in the scale of a tally clerk was fair and just. The employees have not examined any witness and there is absolutely no evidence to show that the management has all these categories of employees in their establishment. In fact all the 12 employees are doing the same work and the action of the management in fitting Shri Prabhu in the scale of tally clerk is not justified, and the further question is as to what relief the workman is entitled.

20. I have already observed that the Wage Board has by its report equated the post of Assistant Supervisors at all ports to the Assistant foremen. The workman Shri Prabhu has been designated as a supervisor on board the vessel after his transfer. It can not be denied that supervisor would carry higher scale than Asstt. Supervisors. The employers

have in their argument not suggested any scale to the workman doing the job on board the vessel and it will be reasonable that Shri Prabhu who is working as a supervisor should get the scale of a foreman the Scale of Rs. 200-10-300-15-550 which is recommended by the Wage Board.

21. The Union has contended that the Wage Board recommendations have been given effect to from 1-1-1969 and the workmen should get the benefit of the award from that date. However, it cannot be disputed that before the transfer of Shri Prabhu to the stevedoring department, Shri Prabhu was supervising the work at the jetty. However it is clear from the evidence that the duties performed at the jetty are of a different nature. The duties of a supervisor at the harbour carry heavy responsibility and the contention that the workman should get the scale from 1-1-69 can not be accepted. Shri Prabhu was transferred to the stevedoring department on 17-4-1970. It has come in evidence that the business of the firm was transferred to the private limited company of Messrs. Machado & Sons somewhere in the year 1971 and on taking over both the firm and the private limited company had issued letters to the employee. It appears that thereafter the dispute was raised and I do not think that the workman would be entitled to get the benefit of the award retrospectively. Considering the circumstances I think it just and proper to direct that the workman is entitled to get the scale of the foreman from the date of the reference i.e. from 1-11-1971.

22. From the nature of duties and responsibilities performed by Shri Prabhu, I have found that his duties merit the scale of a foreman i.e. Rs. 200-550. The management will fit him in the scale at the proper stage with effect from 1-11-1971 and also pay him other benefits such as DA, CA, HRA, etc., from that date. The reference is pending since more than a year. It is contested and the union will be entitled to get costs of Rs. 100/-.

Hence my award accordingly.

A. T. ZAMBRE, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1973

का. आ. 538.—डाक कर्मकार (नियोजन का विनियम) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री आर. श्रीनिवासन, अध्यक्ष, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट न्यास को, श्री एच. साम्बामूर्ति के स्थान पर 9 जनवरी, 1973 से विशाखापट्टनम के डाक श्रम बोर्ड में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य के रूप में नियुक्ति करती है और उन्हें उस बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत करती है तथा भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या 3582, दिनांक 28 सितम्बर, 1968 में निम्नीलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

जक्त अधिसूचना में :—

- (1) पहली प्रविष्टि 'श्री एच. साम्बामूर्ति' के लिए प्रविष्टि 'श्री आर. श्रीनिवासन' प्रतिस्थापित की जाएगी,
- (2) 'केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के स्तम्भ के अधीन क्रमांक (1) के सामने, 'श्री एच. साम्बामूर्ति, अध्यक्ष, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट न्यास, विशाखापट्टनम' प्रविष्टि के लिए प्रविष्टि 'श्री आर. श्रीनिवासन, अध्यक्ष, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट न्यास, विशाखापट्टनम' प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं. बी-15012/12/1/71-पी एण्ड डी, भाग 2]

वी. शंकरालिंगम, अवर सचिव।

New Delhi, the 12th February, 1973

S.O. 538.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri R. Srinivasan, Chairman, Visakhapatnam Port Trust as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board to represent the Central Government and nominates him as Chairman of that Board vice Shri H. Sambamurti, with effect from the 9th of January, 1973, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. 3582 dated the 28th September, 1968, namely :—

In the said notification :—

- (i) for the first entry "Shri H. Sambamurti", the entry "Shri R. Srinivasan" shall be substituted;
- (ii) for the entry "Shri H. Sambamurti, Chairman, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam" against S. No. (1) under column "Members representing the Central Government" the entry "Shri R. Srinivasan, Chairman, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam" shall be substituted.

[F. No. V-15012/1/71-P&D, Vol. II]

S.O. 539.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947, (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Commissioners, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st February 1973.

(AWARD)

[No.L-32011/14/71-P&D]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
AT CALCUTTA

Reference No. 5 of 1972

Parties:

Employers in relation to the management of Calcutta Port Commissioners, Calcutta,
AND
Their Workmen.

Present:

Sri S. N. Bagchi Presiding Officer

Appearances:

On behalf of Employers — Sri S. P. Naha Deputy Labour Advisor and Industrial Relation Officer.

On behalf of Workmen — Sri Nirmal Kumar Das Gupta, Secretary of National Union of Waterfront Workers.

State: West Bengal

Industry: Port

AWARD

By Order No. L-32011/14/71/P&D dated 20th January, 1972, the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment referred the following dispute existing between the employers in relation to the management of Calcutta Port Commissioners, Calcutta and the workmen to this Tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the demand of the staff of the Hi-Fix station, for being treated as Marine Staff, is justified? If so what benefits and amenities should they be entitled to?"

2. The scope of the reference on analysis is this: (a) The demand of the staff of the Hi-Fix station, (b) demand is for being treated as Marine staff. The issue referred to, does not specify which are the categories of workmen concerned in Hi-Fix staff and which are the categories of workmen the corresponding categories of workmen included in the benefits and amenities of the workmen of the categories included in the Hi-Fix staff could be justifiably compared with the corresponding categories of workmen included in the Marine staff. The issue referred to for adjudication does not specify what are the demands for the benefits/amenities, who are the workmen of the categories of the Hi-Fix staff that make the demands for specific benefits/amenities and what are such demands for benefits and amenities that could be compared with the benefits and amenities that are being enjoyed by specific categories of workmen in the Marine staff in order to decide the justification of the demands of the Hi-Fix staff.

3. The Commissioners of the Port of Calcutta is governed by the Calcutta Port Act, 1890. Section 30 of the Port Act reads as follows:

"30. Commissioners to prepare, and in meeting sanction, schedule of establishment.—

- (1) The Commissioners shall, from time to time, prepare, and in meeting sanction, a schedule of the staff of (employees) whom they shall deem it necessary and proper to maintain for the purposes of this act.
- (2) Such Schedule shall also set forth the amount and nature of the salaries, fees and allowances which the Commissioners in meeting sanction for each such (employee) :

Provided that artisans, porters and labourers, and sirdars of porters and labourers, shall not be deemed to be (employees) within the meaning of the section or of (section 32) of this Act."

In pursuance of the provisions of that section the Commissioners for the Port of Calcutta made and published the Establishment Schedule for the year 1971-72. Marine Department begins from page 381 of the Schedule and ends at page 644 of the schedule. "Marine staff"—the expression as used in the issue referred to for adjudication in the light of the Establishment Schedule is a very vague and confusing expression. The Marine Department beginning from page 381, starts with item No. 1 Director of Marine Department and ends at page 644 in item no. 141 Junior Electrical Engineer, Marine Department. So "Marine staff" the expression used in the issue referred to for adjudication would include any of the members of the staff of the Marine Department of the Commissioners of the Port of Calcutta within the categories 1 to 141 covered by pages 381 to 644 of the Establishment Schedule of the Commissioners of the Port of Calcutta. Now, page 645 of the Schedule relates to Hydraulic Study Department. The Head of the Department is Chief Hydraulic Engineer, in item no. 1. The Hydraulic Department covers pages 645 to 654 of the Establishment Schedule. Categories of staff in the Hydraulic Study Department fall within the numbers 1 to 24, within the pages 645 to 654 of the Schedule. In the Schedule there is nothing as "Hi-Fix Staff". At page 645 of the Schedule, Chief Hydraulic Engineer's office establishment—item No. 24 is Radio Technician, Item No. 25 is Instrument Supervisor, Item No. 26 is Instrument Supervisor and Item No. 27 is Instrument Technician. I do not find in the Statutory Establishment Schedule any post or any member of the staff in the Chief Hydraulic Engineer's office establishment with the designation 'Hi-Fix' staff. There is radio technician, instrument supervisor (Electronics), and Instrument technician. So, "Hi-Fix", the expression used in the reference is a much vague and confusing as the expression Marine Staff. In the Chief Hydraulic Engineer's office establishment there are 24 categories that are in the Schedule of the members of the staff and of whom, some are workmen as understood within the Industrial Disputes Act and some are not. Similarly in the Marine Department there are 141 categories of employees. Some of whom may be workmen under Industrial Disputes Act and some are not. The word 'staff' according to Webster's New World Dictionary, page 1384, Second College Ed., 1970, may denote a specific group of workers or employees, such as a teaching staff, a newspaper staff, main-

tenance staff. What is Hi-Fix staff? The schedule of Establishment does not specify any category of workers in Chief Hydraulic Engineer's office establishment with the designation 'Hi-Fix' staff. Under the Marine department, as I have already pointed out, there are several categories of employees some of whom may be workmen and some are not. So, within the expression "Marine Staff" and "Hi-Fix staff", what are the categories of workmen, as the expression 'workman' is understood under the Industrial Disputes Act that are to be included, cannot be determined from the constituents of the Order of reference, i.e. the issue referred to for adjudication. In the Schedule of Establishment, no category of staff under Chief Hydraulic Engineers' Department is so designated that it could be included within the expression 'Hi-Fix Staff'. Which category of workmen under the Chief Hydraulic Engineer's Department could be included within the expression "Hi-Fix Staff", the expression used in the order of reference, cannot be ascertained from the order of reference.

4. In the Schedule of Establishment at page 647 under Chief Hydraulic Engineer's office establishment, as I have already pointed out, there are item No. 24-Radio-Technician, item No. 25-Instrument Supervisor (Electronics), item No. 26-Instrument Supervisor (Electronics) and item No. 27-Instrument Supervisor. Under the heading "Note-Part II-Classification of Posts" in the Establishment Schedule 1971-72 there is the "Additional Notes—Payment of Overtime work. Clause C in material particulars reads as follows: "The following categories of Marine staff are eligible for payment of consolidated compensatory allowance for irregular hours of work, overtime work and ship keeping duty at the rates as shown hereunder" and it covers Marine Staff i.e. employees in clauses (a) (i), (ii), (iii), (b) (i), (ii), (c), D(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) and (h), of different categories. Pages 1 and 2 of the Schedule under the heading 'Additional Notes'—all those categories Marine staff covered under the 'Additional Notes' get certain rates of compensatory allowance for irregular hours of work, overtime work and ship keeping duty as shown under each category of Marine staff attached to Dredger, Despatch Vessels, Launches, Row Boats, River Survey Vessels, Pathfinder, Guide and crews of Pilot vessels, (ii) Staff attached to R.S.V. Haldia (iii) Staff attached to R.S.V. Triveni, (b) (1) Staff attached to Fire Float-cum-Tug 'Agnijoy', (ii) staff attached to Fire Float-cum-Tug 'Agnijit'. (c) Crews of Launches excluding those attached to Dredger & Despatch Service. Light vessels, Encroachment and Port Survey party, Semaphore staff, Sounding staff, Ganga Barrage Party, M. V. Parijat and Light House staff. Those categories of Marine staff attached to several vessels are entitled under the Resolutions of the Commissioners of the Port of Calcutta mentioned against each category varying rates of overtime allowance. Marine staff under clause C(a) and C(b) attached to different vessels are eligible for payment of consolidated overtime allowance. As regards their pay scale there is industrial dispute pending. Clause D(a) crews of Tugs & Launches under the Dock Master and Mooring Master, clause D(b) crews of crafts under the Harbour Master (P) other than those mentioned in clause D(a) and mooring crews, Dock lascars, Crews of Heave-up boats and Hawser boats, Jolly boats, Anchor vessels, clause D(c) crews attached to Port Divers Boat, clause D(d) 1st class Inland Master and Licensed Drivers-in-charge of vessels, clause D(e) Men of Kidderpore Dry Docks D(f) Serang Tucktaghat, clause D(g) Engineers of Port Dredging Crafts, clause D(h) Berthing Masters, Probationary Berthing Master, Asst. Dock Masters, Dy. Dock Masters Supdt. & Shipwright of Dry Docks, Supdt. Boat Registration, clause E—Crews of the vessels of Port dredging unit being Bucket Dredgers—Ajoy, Bulldog and Bully, suction Hopper Dredger—Daisy, Grab Dredgers No. 1 & No. 2, Hopper Barges No. 1 to 7 & 11 & 12 excluding Hopper Dr. Daisy or any other dredgers and Hopper Barges while they are utilised for work at Haldia under separate terms and conditions. So, for overtime work compensatory allowance, Marine staff means and includes those categories of employees as mentioned in Clauses C, D, E and sub-clauses thereunder and includes even Officers whose pay exceeds Rs. 550/- and workmen whose pay is above 110/- but below Rs. 500/- i.e. Class III posts and Class IV posts. (See Note Part II—Classification of Posts in the Schedule). Although in the body of the Schedule there is no mention of Hi-Fix staff but under the heading "Additional Notes—Payment of Overtime Work" as appearing in the Schedule Pages 1 to 4, the Port Commissioners classify Marine staff, and Hi-Fix staff, under the

Heading Chief Hydraulic Engineer. There are 5 classes of employees under the Chief Hydraulic Engineer—Crews of Research Vessel "Annusandhani", Men of the Upper Reaches Research Station Falta, and of M.V. "Investigator", Incumbents of one post of Instrument Supervisor (Electronics), The Incumbents of the posts of Sr. Laboratory Assistant, and Jr. Laboratory Assistant/Hydraulic Observer, Laboratory Attendant, the incumbents of the posts of Hi-fix Assistant operation, Hi-fix Assistant who are eligible for consolidated overtime allowance while they work at the following Hi-Fix stations viz., Mud Point, Sagour, Dadanpara and Frazergunj and Monitor. An allowance of Rs. 15/- per mensem as in-charge of the station i.e. Hi-Fix Station and Rs. 60/- per mensem as servant allowance of each station, vide Resolution No. 744 of 27-5-68. Rs. 25/- per month to the in-charge of each of the four Hi-Fix stations at Mud Point, Sagour, Dadanpara and Frazergunj under Reso. 581 of 29-4-68. Haldia, a separate unit under the Port Commissioners, relates to crews of S. L. Bharat, M. L. Zwan and Crews of M. L. Fleming. They are each entitled to consolidated overtime allowance at 50 per cent. Item 25 page 647 under Chief Hydraulic Engineer's office establishment in the schedule relates to Instrument Supervisor (Electronics). He gets conveyance allowance of Rs. 50/- per month and is eligible for Mess and away from base allowance for actual number of days he is required to work on the river either on Commissioner's craft or hired craft (Sanction under Resolution 744 of 27-5-68). Item 26—Instrument Supervisor (Electronics) 50 per cent consolidated overtime allowance while they work at the following Hi-fix station—Mud Point, Saugor, Frazergunj, Dadanpara and Monitor and an allowance of Rs. 15 per month to those holding R.T. Operation license (Reso-1204 of 30-8-71). Item 27—Instrument Technician—A special allowance to Shri S. B. Roy of Rs. 20 p.m. for attending the institute of Port Management (Reso. 1282 of 1966). So, from the Schedule it appears that Instrument Supervisor (Electronics) Item No. 25 and Instrument Supervisor (Electronics) Item No. 26, have been granted overtime allowance of 50 per cent consolidated, when they work either away from station or at the five Hi-Fix stations respectively. The additional note at page 4 of the Schedule, already mentioned, item 5 only covers the incumbents of the post of Hi-fix Assistant Operator. Hi-fix Assistants who are eligible to 50 per cent consolidated overtime allowance while they work at Hi-fix stations already mentioned. So, Hi-fix staff as the Schedule of Establishment shows may cover item 24—Radio Technician, item 25—Instrument Supervisor, item 26—Instrument Supervisor, item 27—Instrument Technician and Hi-fix Assistant Operator and Hi-fix Assistants and also those in-charge of Hi-fix stations at Mud Point, Saugor, Dadanpara and Frazergunj.

5. I mention here that the Commissioners of the Port of Calcutta are governed by the Calcutta Port Act 1890. Section 30 of the Act contains mandatory provisions calling upon the Commissioners to prepare from time to time and in meeting sanction the schedule of staff (employees) whom they shall deem it necessary and proper to maintain for the purpose of the Port Act. Such schedule shall set forth the amount and nature of salaries, fees and allowances which the Commissioners in meeting sanction for each such employee. Section 31 of the Port Act empowers the Commissioners in a meeting to frame rules covering clauses a to h(i) thereof relating to the terms and conditions of service of the employees of the Commissioners. So, the Schedule of Establishment framed under Section 30 of the Port Act is a Statutory Schedule wherein different categories of employees under the Commissioners of the Port of Calcutta have been designated holding a specific post carrying pay and wages for each of such posts. There are five Hi-fix stations as will appear from the Schedule, page 4 under heading Additional Notes—Chief Hydraulic Engineer. The categories of posts in the Hi-fix stations are Hi-fix Assistant Operator, Hi-fix Assistants, Hi-fix station in-charge, Radio Technicians, Instrument Supervisor (Electronics) and Instrument Technicians as per Schedule of Establishment mentioned above. Marine Staff who are entitled to special allowances or overtime compensatory allowance have been specifically mentioned in the Schedule of Establishment already discussed.

6. In finding out in terms of the order of reference relating to the dispute referred to for adjudication by this tribunal, the expression 'Hi-fix staff' and 'Marine staff' when read with the Schedule of Establishment, as I have read, bring out some sense. So, "the staff of the Hi-Fix station" as the expression has been used in the order of reference

and the expression "Marine Staff" as has been also used in the order of reference may be some what understood when read with reference to the Schedule of Establishment for the year 1971-72 from which I have elaborately quoted. But what was the demand of the staff of the Hi-fix station, or rather upon what factual basis the dispute or difference arose between the employer i.e. the Commissioners of the Port of Calcutta and the workmen i.e. "the staff of the Hi-fix station"? Industrial dispute, as Section 2(k) of the Act means, any dispute or difference between employers and workmen . . . which is connected with the employment or non-employment or terms of employment or with the conditions of labour, of any person. In the present reference, the expression 'demand' in the order of reference in relation to "the staff of the Hi-fix station", not of Hi-fix stations (when there are 5 Hi-fix stations as per Schedule of Establishment) must relate to the dispute or difference between the "the staff of the Hi-fix station" and the employer i.e. the Commissioners of the Port of Calcutta. The expression "the staff of the Hi-fix station" is again vague and confusing as used in the order of reference. There are five Hi-fix stations as per Schedule of Establishment. So, there should be staff not of the Hi-fix station, but of the Hi-fix stations. If the order of reference contained the words "The staff of the Hi-fix stations" then within those words the staff of the five Hi-fix stations could be included. But the order of reference positively uses the expression "the staff of the Hi-fix station" but not "the staff of the Hi-fix stations". The demand, as I have already pointed out, must relate to the dispute or difference that may arise only on factual basis. The workmen are to serve their charter of demand, containing specific items of their claim, based on specific facts to the authority of the management that may accede to or reject the demand i.e. the claim made by the workmen, based upon specific facts, relating to their terms of employment, as in the present case. The authority of the management receiving the charter of demand thus based upon specific facts relating to the workmen's terms of employment may or may not accede to such demand or may offer alternative terms of employment to which workmen may not agree. Then arises the dispute or the difference between the workmen and the employer relating to the terms of their employment. So, let us see the charter of demand of the workmen, only to find out a workable meaning of the expression "the demand of the Staff of the Hi-fix station", when the order of reference is silent as to what the demand had been.

7. The relevant demand of the Hi-fix staff is in clause 5 of the Annexure attached to the Strike notice Ext. W1, which reads as follows:

"The services of 'Hi-fix' staff are comparable with the services of other Marine staff based at shore. 'Hi-fix' stations are situated at different isolated places similar to the Marine Semaphore stations and the 'Hi-fix' staff have to work in the process of dredging, surveying and researching of the river under the similar circumstances to those of other Marine staff. Therefore 'Hi-fix' staff should be considered as Marine staff for all benefits and amenities of Marine staff."

Let me take the first sentence in the demand of Hi-fix staff, viz., services of Hi-fix staff are comparable with the services of other Marine staff based at the shore. The sentence is imprecise and vague "Hi-fix staff" as I have pointed out, is itself a vague and confusing expression as much as the expression "other Marine staff based at the shore". The next item in the demand clause 5 is that as Hi-fix stations are situated at different isolated places similar to the Marine Semaphore stations and as the Hi-fix staff have to work in the process of dredging, surveying and researching of the river in the similar circumstances to those of the Marine staff, the Hi-fix staff should be considered as Marine staff for all benefits and amenities of Marine staff. Hi-fix stations are under the Chief Hydraulic Engineer's control whereas the Marine staff is under the Marine department. Marine staff, according to clause 5 of the demand, are to work in the process of dredging, surveying and researching of the river and the Hi-fix staff, as the demand shows, have to work also in the process of dredging, surveying and researching of the river as much as the Marine staff are to work. Marine staff of specific categories of employees may be working in the process of dredging, surveying and researching of the river in view of the 'Additional Note—Payment of Overtime work in the Schedule under Clauses

C, D and E as already noted. Chief Hydraulic Engineer has under him the research vessel "Anusandhani", Upper Reaches Research station, Falta and M. V. Investigator and M. L. Investigator. So, there is only one research vessel, one M.V. and one M.L. under the Chief Hydraulic Engineer. The Hi-fix assistant Operators, Hi-fix assistant, Hi-fix Assistant-in-charge are posted at five stationary Hi-fix stations, *vide* item 5 of the Establishment Schedule under the Heading "Additional Notes—Payment for Overtime work" page 4. "Hi-fix station staff", whoever they may be, are stationary staff stationed at particular Hi-fix station at Mudpoint, Saugor, Dadanpara and Frezergunj and Mointor. Only Instrument Supervisor (Electronics) item 25 is required to work on the river either on Commissioner's craft or on hired craft. Instrument Supervisor (Electronics) item 26 works at Hi-fix station Mudpoint, Saugor, Frezergunj, Dadanpara and Mointor. So, Hi-fix assistant operator, Hi-fix assistant and Hi-fix station-in-charge of 4 Hi-fix stations Mudpoint, Saugor, Dadanpara and Frezergunj being posted at those Hi-fix stations are to work there at those stations. Only Instrument Supervisor (Electronics) item 25 is to work on the river either on Commissioner's craft or hired craft but Instrument Supervisor item 26 is to work at Hi-fix stations. So, only Instrument Supervisor (Electronics) item 25 is to work at time on the river but Instrument Supervisor (Electronics) item 26 and Hi-fix Assistant Operator, or Hi-fix assistant or Hi-fix station in-charge are not to work on the river but at "Hi-fix" fixed stations at the shore already named. There is only one research vessel "Anusandhani" under the Chief Hydraulic Engineer. There is one research station at the Upper Reaches Falta. There is the M.V. "Investigator" and M.L. "Investigator" under Chief Hydraulic Engineer. Employees of those craft and stations are described as crews of Research vessel "Anusandhani". Men of Upper Reaches Research Station, Falta and M.V. Investigator, crew of M.L. Investigator. So, under the Chief Hydraulic Engineer there is no research work except as done in the research vessel "Anusandhani". M.V. Investigator and M.L. Investigator may help in the research work but neither the vessel "Anusandhani" nor M.V. "Investigator" nor M.L. "Investigator" is a "Hi-fix" station. They are moving vessels in the river. Dredging, and surveying are the operations to be done by Marine staff but not by Hi-fix station staff. The demand in clause 5 of Ext. W.L. in the words "the Hi-fix staff have to work in the process of dredging, surveying and researching of the river, directly contradicts the Establishment Schedule, wherein the work of the Marine staff and the work of the staff under Chief Hydraulic Engineer have been specifically and separately detailed. I have already pointed out the vagueness in the expression "the staff of the Hi-fix station" and "Marine staff" in the order of reference. So, the demand as in clause 5 rests upon airy nothing and does not disclose factual basis upon which the demand is based.

8. The workmen represented by the National Union of Waterfront Workers filed its statement of case on 15-3-72. In paragraph 7 it is stated:

"That within the jurisdiction of the Port extending from the docks in the port area to sand heads these six Hi-fix stations are situated at (i) Sagar Island, (ii) Frezergunge, (iii) Dadanpara (iv) Mud point, (v) Falta and (vi) Calcutta named as (a) Mater station, (b) Slave III station (c) Slave I station (d) Slave II station (e) Base station and Headquarters respectively."

In paragraph 8, the workmen stated:

"That to cope with the work, Commissioners for the Port of Calcutta employ different categories of workmen in their Chief Hydraulic Engineer's department such as Driver (Diesel), Greaser, Serang, Tindal, Seacunny, Lascar, Leadsman, Butler, Cook, Masalchi, Servant, Bhandari including Instrument Supervisor (electronics) Hi-fix assistant (operator), Hi-fix Assistant (Radio) and Hi-fix Assistant (Diesel) those are covered under the present terms of reference."

In paragraph 8 of the statement of case, the workmen specify several categories of workmen as those that are said to be covered under the terms of the reference. But I have pointed out that in the reference the expressions used are "the staff of the Hi-fix station" and "Marine staff". If I take the

expression as used in the order of reference i.e. "the staff of the Hi-fix station" there is then the staff of the Hi-fix station, but not the staff of the 11 Hi-fix stations as stated in paragraph 7 of the statement of case filed by the workmen through the union. In the demand clause 5, Ext. W1, the expression used is "the services of Hi-fix staff" are comparable with the services of "other Marine staff based at shore". Who are the "other Marine staff based at the shore"—with whom which of "the staff of the Hi-fix station" are comparable in so far as their respective duties, responsibilities, amenities and benefits are concerned? Clause 5 of the demand, Ext. W1, is silent about this. In the statement of case, *vide* paragraph 8, several categories of workmen are said to be covered by the order of reference meaning that those categories of workmen mentioned in paragraph 8 of the statement of case filed by the workmen through the union concerned are covered by the order of reference in which the expression used is "the staff of the Hi-fix station". In clause 5 of the charter of demand, as I have pointed out, it was not stated that the services of those categories of Hi-fix staff as are mentioned in paragraph 8 of the statement of case, filed by the workmen are comparable with the services of the relevant corresponding categories of workmen of the Marine staff based at the shore. But in paragraph 8 of the statement of case, filed by the workmen, several categories of workmen are said to be covered by the expression "the staff of the Hi-fix station" as appearing in the order of reference. After making several statement of facts in several paragraph in the statement of case filed by the workmen, the workmen in paragraph 24 of the statement of case stated:

"That considering the place of work, nature of duties and responsibilities and existing service conditions of the staff of the Hi-fix station, they should be treated as Marine staff with effect from the date of strike Notice dated 29-6-1971 served by the union on the Chairman, Calcutta Port Commissioners over charter of demands in which demand No. 5 is connected with the present terms of reference".

I have already analysed the demand No. 5. The demand No. 5, as I have pointed out, is not based upon specific and precise facts relating to the claim of "the staff of the Hi-fix station" for the benefits and amenities as are comparable with specific categories of "Marine staff based at the shore". The services of the staff of the Hi-fix station as demand No. 5 says, are comparable with the services of "other Marine staff based at shore". Who are "the other marine staff based at the shore with whose services, the services of the staff of the Hi-fix station" are comparable is not appearing in clause 5 of the charter of demand. But in paragraph 8 of the statement of case filed by the union representing the workmen within the expression "the staff of the Hi-fix station" those that are included are the several categories of workmen in Chief Hydraulic Engineer's department such as, Driver (Diesel), Greaser, Serang, Tindal, Seacunny, Lascar, Leadsman, Butler, Cook, Masalchi, Servant, Bhandari including Instrument Supervisor (electronics) Hi-fix assistant (operator), Hi-fix Assistant (Radio) and Hi-Fix Assistant (Diesel). Those categories of "the staff of the Hi-fix station" were not mentioned in clause 5 of the charter of demand nor it was mentioned therein that the services of those categories of the staff of the Hi-fix station as mentioned in paragraph 8 of the statement of case filed by the workmen are comparable with which of the corresponding categories of staff of the "other Marine staff based at the shore". In the charter of demand services of "Hi-fix staff" are said to be comparable with the services of "other marine staff based at shore". But it is not stated in clause 5 who are in the categories of "other marine staff that are based at the shore" with whose services the services of which of the categories of Hi-fix staff are comparable. Thus by the statement made in paragraph 8 of the statement of case as I have pointed out, the workmen have brought about a total change in the identity of the demand as made before the employer and that as made before this tribunal. Let me now analyse each relevant paragraphs in the statement of case filed by the workmen. Paragraph 9 of the statement of case relates to Instrument Supervisor (Electronics), in-charge of Hi-fix station. In this paragraph how and on what specific factors the services of the Instrument Supervisor (Electronics) are comparable with "other marine staff based at the shore" is not disclosed. Paragraph 10 of the statement of case relates to the duties and responsibilities of Hi-fix assistant (Radio) but in this paragraph also it is not

stated as on which factors and how his services are comparable with "other marine staff based at shore" as stated in clause 5 of the charter of demand. Paragraph 11 in the statement of case relates to workmen attached to Research station at Falta. The workmen attached to River Research Parties, survey party and Semaphore at different shore stations are said to be treated as marine staff for all purposes. It is stated in paragraph 11 that discriminatory treatment is being done towards the workmen covered under the present terms of reference. But it is not stated how the services of the workmen, mentioned in paragraph 11 of the statement of case, said to be treated as marine staff, but not as marine staff based at the shore" are comparable with the services of workmen, whoever they may be under the terms of the reference, involved within the expression "the staff of the Hi-fix station", as used in the order of reference. It is needless to point out that clause 5 of the charter of demand opens with the work "The services of Hi-fix staff are comparable with the services of other marine staff based at the shore". But how the services of the workmen included within the expression "the staff of the Hi-fix station" as used in the order of reference are comparable with the services of the workmen mentioned in paragraph 8 and 11 of the statement of case has not been disclosed anywhere in the statement of case filed by the workmen. Paragraph 12 of the statement of case, it is stated that the services of Hi-fix staff are comparable with the services of "other marine staff based at the shore". Marine survey station, Semaphore and Research stations are situated at different isolated places as Hi-fix stations. It is further stated in paragraph 12 amongst other things, "and the concerned workmen have to work in the process of dredging, surveying and research of the river under the similar circumstances and conditions to those at other Marine Staff, but that statement carries no sense. Who are the workmen of "the other Marine staff" who have to work in the process of dredging, surveying and researching of the river and what are the conditions under which they are to serve have not been disclosed, but the expression 'similar circumstances and conditions' to those at the other marine staff does not present any comparable standard of services rendered respectively by the workmen of the Hi-fix station and by "of other marine staff". How a radio operator at the Hi-fix station is to work in the process of dredging, surveying and researching of river? Hi-fix stations are fixed stations but dredging and surveying vessels are moving in the river, but are anchored at the shore on completion of assigned duties. In paragraph 12 of the statement of case what is further stated is that the dredger, survey vessel and research vessel staff and the shore station staff of river survey after performing 8 hours duty stay at shore where public conveyance is available and they enjoy shore liberty and can meet their respective families. But four of the Hi-fix stations are situated in such isolated remote places where the public conveyance are not available and as such they are to remain throughout the year except while on leave. So the conditions of service of staff in the dredger, etc., mentioned in paragraph 12 are not *prima facie* comparable with the conditions of service at 4 Hi-fix stations evident from paragraph 12 itself. In paragraph 14 the expression used is "the concerned workmen covered under the present terms of reference are to depend on biweekly markets which are situated at least 3 or more miles away from their stations". It is further stated, "but the marine staff working under similar circumstances and better conditions that the concerned workmen are provided with free provisions at the following scale.....". In paragraph 15, it is stated that though the service condition of the concerned workmen are similar in some respects and more disadvantageous and hardships in many respects, they have been deprived of the benefit of the free provision which are unfair and unjustified. Again, the expressions "marine staff" and similar circumstances are there in paragraph 14. Facts are not stated upon which similarity exists, so also disadvantageous, as those were not also stated in the charter of demand, clause 5. The clause 5 of the charter of demand says that the services of Hi-fix staff are comparable with the services of other marine staff based at the shore. The expression "other marine staff based at the shore" excludes marine staff that are not based at the shore. Hi-fix stations are based at the shore. So, the services of the Hi-fix staff that are based at the shore, in view of clause 5 of the charter of demand, are to be compared with the services of "the other marine staff based at the shore". It is not stated in paragraph 14 of the statement of case what are the circumstances that are

similar, and the conditions better in the services of the marine staff, *vis-a-vis* the workmen, under the present term of reference, who they may be, that are based at the shore. If paragraph 14 of the statement of case would have referred to "other marine staff based at the shore" it would have some sense. The marine staff, when away on vessels in the river, work under conditions and circumstances, that cannot be similar to the working conditions and circumstances of staff of stationery Hi-fix stations. So, this paragraph 14 of the statement of case does not cover a case for comparing conditions of services of workmen of the stationery Hi-fix stations with those of the workmen of "the other marine staff based at the shore". Paragraph 15 of the statement of case, therefore, logically has no basis since it is with reference to paragraph 14. Paragraph 16 of the statement of case says the marine staff attached to the river survey and river research stations whose service conditions are comparable with Hi-fix staff are provided with uniform. But there is no statement of facts showing how the services of the marine staff, attached to river survey, and river research station, are comparable with the services of Hi-fix staff and if so, with which categories of Hi-fix staff and marine staff respectively. It is not stated in paragraph 16 of the statement of case that specific categories of marine staff attached to river survey or river research station are to do specified similar or same work under specified same or similar conditions to the specified categories of "the staff of the Hi-fix station." So, the remaining part of the statement of paragraph 16 of the statement of case is irrelevant. Paragraph 17 of the statement of case says about Butler, cook and servant attached to 2 officers of the river research station, but not to workmen. One cook is employed for two light house staff. How a Light house is comparable with any Hi-fix stations in any way? An officer is not comparable with a workman. In paragraph 17 it is said that no cook is provided for any of the Hi-fix stations, as a result of which the concerned workmen are to spend money to engage a cook in each Hi-fix station. Each Hi-fix station is provided with Rs. 60/- as servant allowance which is also inadequate to provide a whole time servant. But that is not the demand that was made in clause 5 of the charter of demand. Each Hi-fix station gets Rs. 60/- per mensem as servant allowance. If Hi-fix staff are workmen their services cannot be compared with the services of officers attached to river research station at Falta. A Light house is a unit which cannot be in itself comparable with any of the Hi-fix stations. The clause 5 of the charter of the demand, as I have pointed out, opens with the expression the services of the Hi-fix staff are comparable with other marine staff based at the shore". A light house is not based at the shore. Marine staff, as per the statement of case, field by the workmen are those who are to work in the moving vessels in the river. The reference used the expression "Marine staff" but not "other marine staff based at the shore as in cl. 5 of the charter". After completion of assigned duty, the moving vessels are moored at the shore and the men working in the vessels are then off duty. So, the amenities and benefits that are provided for to the marine staff, when working in the vessels, while on voyages, are not amenities or benefits that the marine staff working in the moving vessels get, while not on voyages, when the vessels are moored at the shore after completion of the assigned duty and the workmen are on off duty, evident from the statement of case, as made by the workmen. So, when working in the moving vessels in the river away from the shore, the marine staff are not then "based at the shore". The marine staff in the moving vessels work under conditions which cannot be either same or similar with the work of the workmen in any of the Hi-fix stations which is for all time based at the shore. A light house is not based at the shore. Officers of the river research station are not workmen. So there can be no comparison of services rendered by the officers of river research stations, and men of light house staff, I mean light house workmen. If Hi-fix staff means workmen working at the Hi-fix stations, no workmen of the "marine staff based at the shore" has been stated in the statement of case filed by the workmen to have been provided by the Commissioners of the Port of Calcutta with the amenities of having a free cook or a servant or food. In the moving vessels, plying in the river when the workmen of the marine staff are away from the shore but not based at the shore, there are certain amenities and benefits that are provided for to the marine staff in the moving vessels when they are thus away from the shore, but not "based at the shore". Nowhere in paragraph 17 of the statement of case, it has been stated that any workman within the expression "other marine staff based at the shore"

gets either free cook or free servant or free ration so that the services rendered by such a workman may be compared with the service rendered by the workmen of the Hi-fix stations. I think that the union representing the workmen of "the Hi-fix station" could not appreciate the basic distinction between the conditions of service of the workmen at the stationary Hi-fix station and the condition of service of the workmen of the marine staff in the moving vessels in the river. To make out an apparent similarity between stationary Hi-fix station staff and the moving marine staff, the union coined an ill thought expression "other marine staff based at the shore". When the workmen of the marine staff are working in the moving vessels while on voyages, the moving vessels with the working marine staff, are not "marine staff based at the shore". They are marine staff away from the shore. But when the workmen of the marine staff of the moving vessel finish their assigned duty and the vessels return to the shore, and are based at the shore, the workmen of the marine staff are not then based at the shore but are off duty at the shore. The vessels are then kept under the control and supervision of a skeleton staff when based at the shore till those vessels go out on duty along river. So, the expression "marine staff based at the shore" in clause 5 of the charter of demand suffers from confusion worst confounded. It is common sense that when the vessels are moving with the marine staff in the vessels away from the shore in the river or in the river estuary or in the high seas, the vessels are far away from the shore with the marine staff. Necessarily the conditions of service of the marine staff in the vessels while moving on duty can never be similar with the conditions of service of the Hi-fix staff of the Hi-fix stations which are for all time stationary posts. When moving vessels return to the shore, the marine staff are off duty except a skeleton staff as I have already observed, and are not provided with such amenities such as free cooks, free servants or free ration. Nowhere in the statement of case, it has been stated by the workmen that the marine staff of the vessels, when based at the shore, after completion of the assigned duty, and are off duty, get the amenities and benefits that are provided to the workmen of the marine staff while working in the vessels that are moving along in the river on duty. So, paragraphs 14, 15, 16 and 17 of the statement of case do not present specific facts and circumstances relating to the conditions of service of the workmen of the Hi-fix stations so as to make their conditions of service comparable with marine staff manning the moving vessels on duty in the river. I have pointed out that the expression "marine staff based at the shore" suffers from confusions of thought. Let me point out specifically paragraph 14. Marine staff but not "marine staff based at the shore" gets certain ration free. The reason is not far to seek. I have already pointed out that the marine staff working in the vessels, while moving on duty in the river and plying in the river, are necessarily to be provided with free ration stored in the vessel. But in paragraph 14 of the statement of case there is no assertion of facts that when the workmen of the marine staff working in the moving vessel finish their assigned duty in the vessel and are off duty, and the vessel is moored at the shore, the workmen who are then off duty are also provided for with such free ration as that stated in paragraph 14. The vessel when based at the shore, the workmen of the vessel are off duty, except the skeleton staff that are to keep the vessel in working order and maintain its working efficiency. So, how the conditions of working of the workmen of the marine staff in moving vessels can be comparable with the conditions of service of the workmen of the stationary Hi-fix station? Or, with those of the marine staff off duty, when the vessel is moored at the shore or based at the shore. Nowhere in the statement of case it has been stated that there are comparable conditions and circumstances between the services of the workmen of the Hi-fix stations and those of the workmen of the marine staff, when they are off duty from the moving vessels that are moored at the base i.e. shore. Therefore all those paragraphs are directly in conflict with the opening words of clause 5 of the charter of demand upon which the remaining portions of clause 5 of the charter of demand are inextricably connected. By logical syllogism paragraphs 14, 15, 16, 17 and 18 of the statement of case are inextricably interconnected. Paragraph 18 speaks of disparity in respect of sanction for a free cook for Hi-fix staff. A light house staff and river research officers get free cook or servant or butler. I have already made it clear that workmen are not comparable

with officers and the light house staff cannot be comparable with the staff of any of the fixed Hi-fix stations. Disparity or discrimination has got a constitution basis embodied in the principles laid down in Article 14 of the Constitution of India. If men are similarly circumstanced they are all entitled to the same or similar benefits and amenities and there cannot be any room for discrimination between man and man when they are similarly circumstanced. So, similarity in the conditions of service, between the workmen of the stationary Hi-fix stations, and the workmen of the "other marine staff based at the shore" meaning the marine staff, when off duty from moving vessels, that are moored at the shore awaiting next assigned voyage, are to be taken for comparison on the basis that there workmen are similarly circumstanced. If there is no positive and categorical statements of fact in the charter of demand identical with those in the statement of case filed for he workmen regarding similarity in the circumstances and the conditions of the service of the workmen of the Hi-fix stations with those of the workmen of the marine staff off duty from the moving vessels that are moored at the shore, i.e. "other marine staff based at the shore" the very basis of the charter of demand in clause 5 and of the demand relating to the issue referred to for adjudication as made in the statement of case filed for the workmen would be wanting to give rise to a dispute or a difference in relation to the terms and conditions of service of the workmen of Hi-fix stations that are not similar to those of Marine staff, so as to render such dispute or difference, an industrial dispute, within the meaning of Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in view of the principles of law laid down in the decision of Madras High Court in the case of Raju's Cafe, Coimbatore and Others vs. Industrial Tribunal, Coimbatore and another, 1951 1 LLJ p. 219, in the decision of the Supreme Court in the case of Sindhu Resettlement Corporation Ltd. and Industrial Tribunal Gujarat & Ors., 1968 1 LLJ p. 834 and in the decision of Delhi High Court in the case of Fedders Lloyed Corporation Private Ltd. and Lt. Governor, Delhi & Ors., F.L.R. 1970(20) p. 343. Paragraph 18 suffers from the same infirmity as that the other paragraphs, as I have pointed out, in the statement of case suffer. Paragraph 19 begins with the words "that the marine staff under the comparable service conditions are provided with 26 days special casual leave in lieu of weekly off days". All the words are vague. Who are the specific categories of workmen of "marine staff" whose services are comparable with the specific categories of workmen of the Hi-fix stations do not appear in the said paragraph of the statement of case. It has not been stated anywhere in paragraph 19, having regard to clause 5 of the charter of demand, as to how and what are the conditions of services of the workmen of the Hi-fix stations that are comparable with the "other marine staff based at the shore". The expression used in paragraph 19 of the statement of case "marine staff" but not "marine staff based at the shore". Comparison in clause 5 of the charter of demand may be made between the conditions of service of "the workmen of the Hi-fix station" and the workmen of "the other marine staff based at the shore" but not with "the marine staff" which means any of the categories of "marine staff" beginning from the Head of the Marine department down upto the Sweeper. So, the statement in paragraph 19 of the statement of case is irrelevant and inconsistent with the material particulars as set forth in clause 5 of the charter of demand. In paragraph 20 of the statement of case filed by the workmen it is stated "the Commissioners' employees are provided with medical benefit. In case of sickness of workmen attached to river survey and river research stations and vessels, Ambulance is provided to send them to C.P.C. Hospital, but the Port authority takes no initiative to hospitalise the Hi-fix staff. Even the light house staff get transport facilities upto C.P.C. Medical centre in case of their sickness but the concerned workmen are deprived from any sort of the said benefit. Our union thinks that the concerned workmen covered under the present terms of reference should be granted with Rs. 20/- per month as medical allowance". I again refer to the expression in clause 5 of the charter of demand "the services of Hi-fix staff are comparable with other marine staff based at shore" but the term of reference clearly indicates that the demand of the "staff of the Hi-fix station" for being treated as "marine staff" for the purposes of benefits and amenities should be considered, if justified or not. Therefore, the services as in clause 5 of the charter of demand of the workmen of the Hi-fix staff are necessarily to be compared

with the services of the other marine staff based at the shore. Paragraph 20 of the statement of case opens with a statement that the Commissioners employees are provided with medical benefits. It is undeniable. River survey and River research station workmen are hospitalised when ill, so also light house staff. But it is not stated that the Port authority takes no step to hospitalise the workmen of the Hi-fix staff. It is stated in paragraph 20 of the statement of case filed by the workmen that the Port authority takes no initiative to hospitalise the Hi-fix staff. The meaning of the expression 'initiative' must have been misunderstood by the workmen. The word 'initiative' means the action of taking the first step or move. Hi-fix stations are fitted with radio. It is not stated that if any information of illness of any workmen of any Hi-fix station is sent per radio message to the authority of the Commissioners of the Port of Calcutta the authority takes no action i.e. does not move in the action of taking the first step i.e. to remove the workman suffering from illness to C.P.C. hospital. If the authorities did not take "initiative" to remove the workmen who is reported to be ill from a Hi-fix station, will the claim for Rs. 20 as medical allowance remove the illness of the workman? It has not been stated in paragraph 20 of the statement of case that a workman of the "other marine staff based at the shore" if not hospitalised by the authority of the Port Commissioners, even if it gets information of such workman's illness, the workman concerned of "the other marine staff based at shore," has been provided for with Rs. 20 as medical allowance. Therefore paragraph 20 has no relevancy. Paragraphs 21 and 22 are inter-linked. Weekly off days enjoyed by workmen at the Hi-fix stations is spent at the station as no arrangement has been made by the Port authorities to bring the workmen to such places where public transport is available. So, the workmen practically loses their weekly off days. It is stated in paragraph 22 "our union thinks that the loss of weekly off days shall be compensated by making provision of 26 days special casual leave" I again refer to paragraph 19 of the statement of case. The marine staff mentioned in that paragraph is not "the marine staff based at the shore". "Marine staff" as paragraph 19 of the statement of case says, are provided with 26 days special casual leave in lieu of weekly off days. That is the demand in paragraph 22 of the statement of case. But clause 5 of the charter of demand, as I have repeatedly pointed out, excludes "marine staff" and includes only "the other marine staff based at the shore." Marine staff enjoys 26 days casual leave surrendering weekly off days, but clause 5 of the charter of demand opens with the expression "other marine staff based at shore". So the services of the workmen of the Hi-fix stations cannot be in terms of clause 5 of the charter of demand compared with the work of all marine staff, but only with the "other marine staff based at the shore". But it is nowhere stated either in paragraph 19 or in paragraph 21 or in paragraph 22 of the statement of case, that the "other marine staff based at the shore" enjoys 26 days casual leave surrendering weekly off days. Therefore, the demand in paragraphs 21 and 22 goes beyond the ambit of the clause 5 of charter of demand, and as such beyond the scope of the reference as well as the demands in other paragraphs of the statement of case which I have already discussed. Again, paragraph 23 of the statement of case has no relevancy and is beyond the ambit of clause 5 of the charter of demand. Paragraph 23 says amongst other things "considering active service performed by the concerned workmen at Hi-fix station going down the river and their permanent absence from home will be deemed to have worked 96 hours a week and should be paid consolidated compensatory allowance in lieu of overtime wages at 100 per cent of pay plus allowances including the money value of their free ration". This demand is beyond the scope of the demand as in clause 5 of the charter of demand which opens with the words "the services of Hi-fix staff are comparable with the services of "other marine staff based at shore". Only when the services of workmen of the Hi-fix stations are found comparable with the services of workmen of "other marine staff based at the shore", the workmen of the Hi-fix stations are then entitled to amenities and benefits that are enjoyed by workmen of other marine staff based at the shore but not otherwise. So, from this aspect, the paragraph 23 is irrelevant.

9. I have already pointed out that the place of work, nature of duties and responsibilities and existing service conditions of the staff of the Hi-fix station are to be considered to find if comparable with the place of work, nature

of duties, and responsibilities and the service conditions of the workmen of the "other marine staff based at the shore," the emphasis being on the expression "based at the shore", as used in clause 5 of the charter of demand. In paragraph 24 it is not said that the staff of the Hi-fix stations should be treated as "marine staff based at the shore" but they should be treated as "marine staff". This again is beyond the scope of the charter of demand as embodied in clause 5 of the charter of demand, Ext. W.1. In paragraph 25 the workmen said said. "That the discriminatory treatment is being done to the Hi-fix staff in respect of payment of consolidated allowances in lieu of overtime, grant of 26 days casual leave in lieu of weekly off day, supply of free provision, uniform and provision of cook or Bhandary and domestic servant to each station. The concerned workmen covered under the present terms of reference are entitled to said benefits/amenities from which very unjustifiably and unfairly they have been deprived from the date of their attachment with Hi-fix station". The workmen considered it to be discriminatory treatment on the following items viz. consolidated allowance in lieu of overtime, grant of 26 days casual leave in lieu of weekly off days, supply of free ration, supply of uniform, provision of cook or Bhandari and domestic servant to each station. The workmen claimed that they are entitled to the aforesaid benefits and amenities of which they have been unjustifiably and unfairly denied. Here again I refer to the charter of demand, clause 5. Unless the services of the staff of the Hi-fix stations are shown by specific statements of facts made, to be comparable with the services of "other marine staff based at the shore", the demands made, either in the clause 5 of the charter of demand or in the statement of case filed by the workmen before the tribunal would not give rise to a dispute which could be legally considered as an industrial dispute within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. The term of reference I have already quoted. Whatever vagueness and confusion might have been created by the expression "the staff of the Hi-fix station" and "marine staff" used in the order of reference, the workmen of the Hi-fix stations, as per first sentence in the clause 5 of the charter of demand, made this demand that their services are comparable with the services, not of the "marine staff", but with those of the "other marine staff based at the shore". So, the other part of the demand in clause 5 is dependent upon the first sentence in clause 5 of the charter of demand. If the services of the workmen of the Hi-fix stations are, upon positive facts stated, *prima-facie* comparable with the services of "other marine staff based at the shore", then and then only, there could be in terms of the demand in clause 5 of the charter of demand, a likely scope for a dispute or difference arising between the workmen and the employer although I have already pointed out that the charter of demand in clause 5 suffers from as much vagueness as vagueness could possibly be imagined since it contains no specific statement of positive facts upon which the demand in clause 5 could rest. The first part of the demand is that the services of the workmen of Hi-fix staff are comparable with the services of "the other marine staff based at the shore". That the demand in specific terms, based on positive facts must be lodged not only before the employer, but also before the Conciliation officer, and none the less, before this tribunal cannot be questioned. There must be identity of the demand all throughout so that the tribunal can, other conditions being satisfied, decide that the demand relating to the issues as are included in the order of reference covers an industrial dispute as understood within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. Judging from this aspect, there is no identity of demand as made in clause 5 of the charter of demand with that made in the several paragraphs of the statement of case filed by the union before this tribunal. I have analysed each and every paragraph of the statement of case filed by the workmen in relation to clause 5 of the charter of demand and I have pointed out the diametrical divergence between the charter of demand and the demand made in the statement of case filed by the workmen before this tribunal in several paragraphs. The broadest divergence is that neither in the charter of demand clause 5 nor in the statement of case filed by the workmen before this tribunal, it has been asserted by the workmen that their services or rather the services of the categories of workmen referred to in paragraph 8 of the statement of case filed by the workmen are comparable with the services of the "other marine staff based at the shore" as stated in the first line of the charter of demand clause 5. The other part of the charter of demand is inextricably connected with the first line in clause 5 of the charter of demand. Nowhere it is stated either in

the charter of demand clause 5 nor in the statement of case filed by the workmen that the services of the workmen of each of the categories as mentioned in paragraph 8 of the statement of case filed by the workmen are comparable with one or some of the categories of workmen included in the expression "the other marine staff based at the shore". Such statement must pivot on concrete facts which are to be specifically stated not only in the charter of demand but also in the statement of case filed before this tribunal, not to speak of in the statement of demand filed before the Conciliatory authority. I have already pointed out the confusion of thought from which workmen are suffering while using the expression "other marine staff based at the shore". There must be identity in the demand as laid in the charter of demand before the authority of the management, conciliatory authority and the adjudicatory authority in order that the demand relating to the dispute i.e., issue referred to for adjudication must be shown to be *prima facie* identical, in view of the decisions in the three cases already referred to in the earlier paragraph i.e. paragraph 8 of this award.

10. Judging from the factual and legal standpoint I find that the dispute referred to for adjudication is not an industrial dispute within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, even if I make a charitable allowance for the vagueness and impreciseness of the issue referred to for adjudication by this tribunal, for the reasons I have analysed thread bare. I assume that within the expression "the staff of the Hi-fix station" fall the workmen of the staff of Hi-fix stations as mentioned in the statement of case filed by the workmen. But the expression "marine staff" presents an insurmountable difficulty. Clause 5 of the charter of demand, as I have already pointed out, makes a specific demand that the services of Hi-fix staff meaning the services of workmen of the several Hi-fix stations are comparable with the "other marine staff based at the shore" but not with "marine staff". The issue in the order of reference does not cover the "other marine staff based at the shore" but the demand was that the services of the Hi-fix staff are comparable with the services, not of "marine staff", but of "other marine staff based at the shore". Therefore, I cannot include in the order of reference, within the expression "marine staff" the expression "other marine staff based at the shore". In the statement of case filed by the workmen no fact has been stated relating to the specific terms and conditions of services of workmen of Hi-fix stations that are comparable with the specific terms and conditions of services of workmen of the "other marine staff based at shore". Who are the workmen that come within the expression "other marine staff based at the shore" have not been specified either in clause 5 of the charter of demand or in any of the paragraphs of the statement of case filed by the workmen. So the basic foundation upon which the demand in clause 5 of the charter of demand is to rest is patently absent on the face of the record i.e., charter of demand and the statement of case filed by the workmen represented by the union. Moreover, there is clearly the basic divergence between the demand as made by the staff of the Hi-fix station before the employer, Commissioner of the Port of Calcutta and that as made by the workmen of the Hi-fix stations in the statement of case filed by them before this tribunal. Accordingly, the dispute referred to for adjudication may remain a dispute but it is not an industrial dispute within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act.

11. So, this tribunal has acquired no jurisdiction either to entertain the dispute under reference or to adjudicate upon it. In the result, the reference is rejected.

This is my award.

Dated, January 17, 1973.

S. N. BAGCHI, Presiding Officer.

गई दिल्ली, 8 फरवरी, 1973

का. सा. 540.—कर्मकारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-व द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और

रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 5302, तारीख 3 नवम्बर, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार, सिक्योरिटी पेपर मिल प्रोजेक्ट हॉशंगाबाद नामक स्थापन की, ऐसे क्षेत्र में, जिस में उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति का ध्यान में रखते हुए उक्त स्थापन को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्यमणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा छूट देती है।

[फा. सं. 601(47)/70-एच. आई.]

New Delhi, the 8th February, 1973

S.O. 540.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 5302, dated the 3rd November, 1971 the Central Government having regard to the location of the establishment, namely Security Paper Mill Project, Hoshangabad in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said establishment from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification.

[F. No. 601/47/70-HU]

का.सा. 541.—कर्मकारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-व द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाय्य अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को, उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्यमणीय नियोजक के विशेष अंशदान से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पूर्वी खादेश	धरनगांव	मैसर्स खादेश पेस्ट्रीटाइल्स।
2.	कोल्हापुर	भुरगुव	मैसर्स बावें एण्ड ग्रुबेय स्टोन क्रशर
3.	शोपापुर	सोरेगांव	मैसर्स भीमा रिवर स्कीम प्यूरीफिकेशन प्लांट
4.	धाना	पालाहार	मैसर्स एचर ग्रीन प्रोडक्ट्स कम्पनी।
5.	अमरावती	निमबोरा	मैसर्स विवर्भा काप्पारेडिब मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड

(1)	(2)	(3)	(4)
6. यवतमाल	यवतमाल	मैसर्स अलाप कैटल फील्ड मैनुफैक्चरिंग (प्रा०) लिमिटेड ।	
7. भंडारा	भंडारा	मैसर्स एस०एस०प्रार०टी० कारपोरेशन ।	
8. परभानी	मनवथ	मैसर्स जयकिसन गनेशालाल बंगव गिनिंग एण्ड दाल मिल्स ।	
9. परभानी	जिन्तूर	मैसर्स स्टेट ट्रान्सपोर्ट डिपो ।	

[सं० एस-38014(29)/72-एच 1]

S.O. 541.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Maharashtra in which the provisions of Chapters IV and V of the said act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those area, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of district	Name of Area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	East Khandesh	Dharangaon	Messrs. Khandesh Pesticides.
2.	Kolhapur	Murgud	Messrs. Barve and Albel Stone Crusher.
3.	Shopapur	Soregaon	Messrs. Bhima River Scheme Purification Plant.
4.	Thana	Palahar	Messrs. Ever Green Products Company.
5.	Amravati	Nimbora	Messrs. Vidarbha Cooperative Marketing Society Limited.
6.	Yeotmal	Yeotmal	Messrs. Alap Cattle Feed Manufacturing (Private) Limited.
7.	Bhandara	Bhandara	Messrs. M.S.R.T. Corporation.
8.	Parbhani	Manwath	Messrs. Jaikishan Ganeshlala Bangad Ginning and Dali Mills.
9.	Perbhani	Jintoor	Messrs. State Transport Depot.

[S-38014(29)/72-HI Pt.]

क्र०प्रा० 542.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-व द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त कारखानों की, उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उदाहरणीय नियोजक के विशेष अंशदान के संदाय से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या

तब तक के लिए जब तक उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गोवा (संघ क्षेत्र)	राज्य कोरलिम	मैसर्स एरिस्टो टाइल्स ।
2.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स गोवा पेंट्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स ।
3.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स मोदुलर टिम्ब्रलस ।
4.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स जोशी मेटल्स ।
5.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स फानेक्स टाइल्स ।
6.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स गोवा एक्जोटिक कैनर्स एण्ड फीजर्स ।
7.	-यथोक्त-	कुरचोरेम	मसर्स वीटा इण्डस्ट्रीज ।
8.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स एस० कान्तीलाल क० प्रा० लिमिटेड ।
9.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स दया टाइल्स ।
10.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स इण्डस्ट्रियल नेशनल डेटेलहास ।
11.	-यथोक्त-	बेगुईनिम	मैसर्स दी इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी ।
12.	-यथोक्त-	प्रोबोरिम	मैसर्स वासुदेवो एस० नायक ।
13.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स एमप्रेस टाइल्स इण्डस्ट्रियल जोइनकार ।
14.	-यथोक्त-	बोरिम	मैसर्स एजेन्सिया ई० सेकु-एरी ।
15.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स फैवरिल गैसोसा ।
16.	-यथोक्त-	सिरिगाओ	मैसर्स चोप्रोगुले एण्ड कम्पनी प्रा० लिमिटेड ।
17.	-यथोक्त-	कुर्टी	मैसर्स टायर सोल्स गोम्रा प्रा० लिमिटेड ।
18.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स लैन्कोप्लास्ट (इंडिया) ।
19.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स कुर्टी कैमिकल प्रा० लिमिटेड ।
20.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स कास्टर वालेख लिमिटेड ।
21.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स कोसमे फार्मा लैबोरेट्रीज ।
22.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स गवर्नमेंट डेरी ।
23.	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मैसर्स कोसमा फार्मा लैबोरेट्रीज ।

[एस-38014(29)/72-एच० 1]

S.O. 542.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the Union territory of Goa Daman and Diu in which the provisions of Chapter IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Goa (Union Territory)	Corlim	Messrs Aristo Tiles.
2.	do	do	Messrs. Goa Paints and Allied Products.
3.	do	do	Messrs. Modular Timbers.
4.	do	do	Messrs. Joshi Metals
5.	do	do	Messrs. Finex Tiles.
6.	do	do	Messrs. Exotic Canners and Freezers.
7.	do	Curchorem	Messrs. Vita Industries.
8.	do	do	Messrs. S. Kantilal Company Private Limited.
9.	do	do	Messrs. Daya Tiles.
10.	do	do	Messrs. Industrial National Detelhas.
11.	do	Baiguinim	Messrs. The Indian Hume pipe Company.
12.	do	Provorim	Messrs. Vasudeo S. Naik.
13.	do	do	Messrs. Empressa Industrial Chodankar.
14.	do	Borim	Messrs. Agencia E. Sequerra.
15.	do	do	Messrs. Fabril Gasosa.
16.	do	Sirigao	Messrs. Chowgule and Company Private Limited.
17.	do	Curti	Messrs. Tyresoles Goa Private Limited.
18.	do	do	Messrs. Lenkoplost (India) Private Limited.
19.	do	do	Messrs. Curti Chemical Private Limited.
20.	do	do	Messrs. Caster Wallace Limited.
21.	do	do	Messrs. Cosme Farma Laboratories.
22.	do	do	Messrs. Government Dairy.
23.	do	do	Messrs. Cosma Pharma Laboratories.

[S-38014/29/72-HI/Pl.]

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1973

का. आ. 543.—कर्मकारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 3घ की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4501 तारीख 10 दिसम्बर 1968 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री आर. आर. सहाय को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कर्तव्यों के निर्वहन में, सहायता करने के लिए सम्पूर्ण गुजरात राज्य के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 17(5)/67-पी. एफ. 1(1)]

New Delhi, the 9th February, 1973

S.O. 543.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5D of the Employees' Provident Funds, Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour, and Employment) No. S.O. 4501, dated the 10 December, 1968, the Central Government hereby appoints Shri R. R. Sahae as Regional Provident Fund Commissioner for the whole of the State of Gujarat to assist the Central Provident Fund Commissioner in the discharge of his duties, vice Shri A. V. Vyas.

[No. 17/5/67-PF.I(i)]

का. आ. 544.—कर्मकारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4502 तारीख 10 दिसम्बर 1968 को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री आर. आर. सहाय को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम और कटुम्ब पेंशन निधि स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके विभाग या शाखाएं एक से अधिक राज्यों में हों सम्पूर्ण गुजरात राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं. 17(5)/67-पी. एफ. 1(2)]

S.O. 544.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds, Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4502 dated 10th December, 1968 the Central Government hereby appoints Shri R. R. Sahae to be an Inspector for the whole of the State of Gujarat for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of, the Central Government, or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil-field or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[17/5/67-PF.I(ii)]

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1973

का. आ. 545.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अशोक टाकिज, रायगढ़, डाकघर रायगढ़, जिला कोरपुट, उड़ीसा नामक स्थापन से सम्बंधित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मकारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1967 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. 8/135/68-पी. एफ. 2]

New Delhi, the 19th February, 1973

S.O. 545.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Ashoka Talkies at Post Rayagada, District Koraput, Orissa have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1967.

[No. 8/135/69-PF. II]

का. आ. 546.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मॅसर्स प्रिन्ट्राइट, 67/69, मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के नवम्बर के 30 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35017(59)/71-पी. एफ. 21]

S.O. 546.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Printrite, 67/69, Mody Street, Fort, Bombay-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1971.

[No. S. 35017(59)/71-PF .II]

का. आ. 547.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मॅसर्स फ्रिंटीव वर्कशाप, ई-4 (आयॉनिक) (चौथी मंजिल) आफ आर्थर बंदर रोड, कोलाबा, बम्बई-5 नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के जून के 30 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35018(105)/72-पी. एफ. 2(1)]

S.O. 547.—Whereas it appears that the Central Government that the employer and the majority of the employees in the relation to the establishment known as Messrs. Creative Workshop, E-4, 'Ionic' (4th Floor), Off Arthur Bunder Road, Colaba, Bombay-5, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1972.

[No. S. 35018(105)/72-PF. II(i)]

का. आ. 548.—कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 8 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मॅसर्स फ्रिंटीव वर्कशाप, ई-4 (आयॉनिक) (चौथी मंजिल) आफ आर्थर बंदर रोड, कोलाबा, बम्बई-5 नामक स्थापन को 30 जून, 1972 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनियमित करती है ।

[सं. एस. 35018(105)/72-पी. एफ. 2 (2)]

S.O. 548.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 30th June, 1972 the establishment known as Messrs. Creative Workshop, E-4 'Ionic' (4th Floor) Off Arthur Bunder Road, Colaba, Bombay-5 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(105)/72-PF. II(ii)]

का. आ. 549.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मॅसर्स न्यू इंडिया एंजनीज, कूईलॉन नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के जनवरी के 31वें दिन को प्रवृत्त होगी ।

[सं. एस-35019(171)/72-पी. एफ-2 (1)]

S.O. 549.—Whereas it appears that the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. New India Agencies, Quilon have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the thirty-first day of January, 1973.

[No. S. 35019(171)/72-PF. II(i)]

का. आ. 550.—कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार संबन्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 जनवरी, 1973 से मैसर्स न्यू इन्डिया एंजनीज, कर्हलोन नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस-35019(171)/72-पी. एफ-2 (2)]

S.O. 550.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st January, 1973, the establishment known as Messrs. New India Agencies, Quilon for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(171)/72-PF. II(ii)]

का. आ. 551.—यतः केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इण्डो एरोपा इंजीनियरिंग वर्क्स, एफ-12 इण्डिस्ट्रियल एस्टेट, अम्बटूर, मद्रास-58 गामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस-35019(108)/72-पी. एफ.2]

S.O. 551.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Indo Eropa Engineering Works, F-12, Industrial Estate, Ambattur, Madras-58 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1972.

[No. S. 35019/108/72-PF. II]

का. आ. 552.—यतः केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम. एस. पी. नाडर कार्पोरेशन, पोस्ट बॉक्स सं. 42, मंगलूर नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस-35019(108)/72-पी. एफ-2 (1)]

S.O. 552.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. M.S.P. Nadar Corporation Post Box No. 42, Mangalore have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1972.

[No. S-35019/168/72-PF. II(i)]

का. आ. 553.—कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मैसर्स एम. एस. पी. नाडर कार्पोरेशन, पोस्ट बॉक्स सं. 42, मंगलूर नामक स्थापन को 1 जून, 1972 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस-35019/168/72-पी. एफ-2 (2)]

S.O. 553.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st June, 1972, the establishment known as Messrs. M.S.P. Nadar Corporation, Post Box No. 42, Mangalore for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019/168/72-PF. II(ii)]

का. आ. 554.—यतः केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सन. रे. इण्डस्ट्रीज, 434, करीमपुरा रोड, लुधियाना नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस-35018 (107)/72-पी. एफ-2 (1)]

S.O. 554.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sun Ray Industries, 434, Karimpura Road, Ludhiana, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1972.

[No. S-35018/107/72-PF. II(i)]

का. आ. 555.—कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मैसर्स सन रे, इण्डस्ट्रीज, 434 करीमपुरा रोड, लुधियाना नामक स्थापन को 1 मई, 1972 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस. 35018(107)/72-पी. एफ-2 (2)]

S.O. 555.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the 1st May, 1972 the establishment known as Messrs. Sun Ray Industries, 434, Karam-pura Road, Ludhiana for the purposes of the said provision.

[No. S-35018/107/72-PF. II(ii)]

का. आ. 556.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बासप्पा काब्यूर, बार लाइन्स रोड, दवंगेरी, मैसूर राज्य नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु-संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस-35019(177)/72-पी. एफ-2 (1)]

S.O. 556.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Basappa Kabbur, Bar Lines Road, Davangere, Mysore State have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1972.

[No. S-35019(177)/72-PF. II(i)]

का. आ. 557.—कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मैसर्स बासप्पा काब्यूर बार लाइन्स रोड, दवंगेरी, मैसूर राज्य नामक स्थापन को 1 नवम्बर, 1972 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस-35019(177)/72-पी एफ 2(2)]

S.O. 557.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st November, 1972

the establishment known as Messrs Basappa Kabbur, Bar Lines Road, Davangere, Mysore State for the purposes of the said proviso.

[No.S.35019(177)/72-PF.II(ii)]

का. आ. 558.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कल्याण अम्बरनाथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, न्यू म्यूनिसिपल बिल्डिंग, कल्याण, जिला थाना नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के मार्च के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस-35018(106)/72-पी. एफ-2]

S.O. 558.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kalyan Ambar-nath Manufacturers' Association, New Municipal Building, Kalyan, District Thana have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952(19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March 1971.

[No. S.35018(106)/72-PF.III]

का. आ. 559.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केसिरेड्डी अप्पासायामी, गुन्नाबथुला अचैय्या स्ट्रीट, विजयवाड़ा-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस-35019(180)/72-पी. एफ-2 (1)]

S.O. 559.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kesireddy Appala-swamy, Gunnabathula Achaiah Street, Vijayawada-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1972.

[No. S-35019/180/72-PF.II(i)]

का. आ. 560.—कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्द्वारा मैसर्स कैसीरेड्डी अप्पासास्वामी, गुन्नाबथुला अर्च्चया स्ट्रीट, विजयवाड़ा-1 नामक स्थापन को 1 अक्टूबर, 1972 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. एस-35019(180)/72-पी. एफ-2 (2)]

S.O. 560.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the 1st October, 1972 the establishment known as Messrs Kesireddy Appalaswamy, Gunnabathula Achaiah Street, Vijayawada-1 for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019/180/72-PF.II(ii)]

का. आ. 561.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुरथीयापेट बेनीफिट फण्ड संख्या 54, थम्बू चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस-35019(156)/72-पी. एफ. 2]

S.O. 561.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Murthialpet Benefit Fund No. 54, Thambu Chetty Street, Madras-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1972.

[No.S.35019(156)/72-PF.II]

का. आ. 562.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वाई वी ई इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कंपनी, 8, स्टीलमर्ड ईंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी ईस्ट बंछ-59 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें;

49 G of 1/72—30

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के फरवरी के 29 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35018(101)/72-पी-एफ-2]

S.O. 562.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Yve Industrial & Trading Company, 8, Steelmard Industrial Estate, Andheri East Bombay-59 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty Ninth day of February, 1972.

[No. S-35018,101/72-PF.II]

का. आ. 563.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मारोली आरुची एन्ड कम्पनी, बी-113, इन्डस्ट्रियल एस्टेट, बंगलोर-44 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के मार्च के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(175)/72-पी-एफ-2]

S.O. 563.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Maroli Aruchi and Company, B-113, Industrial Estate, Bangalore-44 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1972.

[No. S-35019/175/72-PF.II]

का. आ. 564.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डेटामेटिक्स कार्पोरेशन के, जी. रोड, बंगलोर-9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(176)/72-पी. एफ. 2]

S.O. 564.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Datamatics Corporation K.G. Road, Bangalore-9 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1972.

[No.-35019(176)/72-PF.II]

का. आ. 565.—यत्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मॅसर्स एवरब्राइट प्राडक्ट्स, सं. 81, पेराम्बर बैरक्स रोड मद्रास-7 नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. 35019(8)/72-पी. एफ. 2]

S.O. 565.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Everbright Products, No. 81, Perambur Barracks Road, Madras-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1971.

[No. S.35019(8)/72-PF.II]

का. आ. 566.—यत्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मॅसर्स ऑलिम्पिक सिनेमा, सत्तर रोड, शिवकाशी, रामनद जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस.-35019(148)/72-पी. एफ. 2]

S.O. 566.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Olympic Cinema Satter Road, Sivakasi, Kanyakumari District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1972.

[No. S-35019(148)/72-PF.II]

का. आ. 567.—यत्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मॅसर्स नामक्कल श्री वासवी कार्पोरेशन (प्रा.) लिमिटेड, नामक्कल, सालेम जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(185)/72-पी. एफ. 2]

S.O. 567.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Namakkal Sri Vasavi Corporation (P) Ltd., Namakkal, Salem District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1972.

[No.S.35019(185)/72-PF.II]

का. आ. 568.—यत्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मॅसर्स जी. शान्ति लाल ट्रांसपोर्ट कं., 3 सीमेंट चावल कथा बाजार, मुम्बई-9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के मार्च के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35018(100)/72-पी. एफ. 2]

S.O. 568.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. G. Shantilal Transon. Co., 3, Central Chawl Kaha Bazar, Bombay-9 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1972.

[No.S.35018(100)/72-PF.II]

का. आ. 569.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मॅसर्स शाहाबाद हवी इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव कैंटीन, शाहाबाद नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35019(178)/72-पी. एफ. 2 (1)]

S.O. 569.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Messrs. Shahabad Heavy Engineering Employees Consumers Co-operative Canteen, Shahabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1972.

[No.S-35019(178)/72-PF.II(i)]

का. आ. 570.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मॅसर्स शाहाबाद हवी इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव कैंटीन शाहाबाद नामक स्थापन को 1 जनवरी, 1972 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. एस. 35019(178)/72-पी. एफ. 2 (2)]

S.O. 570.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st January, 1972 the establishment known as Messrs Shahabad Heavy Engineering Employees Consumers Co-operative Canteen Shahabad for the purposes of the said proviso.

[No.S-35019(178)/72-PF.II(ii)]

का. आ. 571.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मॅसर्स परशुराम पेपर एण्ड बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के सितम्बर के तीसरे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35018(112)/72-पी. एफ. 2 (1)]

S.O. 571.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Parashuram Paper and Board Manufacturing Company Limited, Bombay, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1971.

[No.S.35018(112)/72-PF.II(i)]

का. आ. 572.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मॅसर्स परशुराम पेपर एण्ड बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई नामक स्थापन को 30 सितम्बर, 1971 से उक्त प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. एस. 35018(112)/72-पी. एफ. 2 (2)]

S.O. 572.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 30th September, 1971, the establishment known as Messrs. Parashuram Paper and Board Manufacturing Company Limited, Bombay, for the purposes of the said proviso.

[No.S.35018(112)/72-PF.II(ii)]

का. आ. 573.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मॅसर्स एस. जी. इण्डस्ट्रीज 13/14 गाला हाउसिंग, पाल एस्टेट डीपिंग रोड, मुल्तु (पश्चिमी) मुम्बई-80, जिसमें आक्रे (1) 225-संत तुकाराम रोड, मुम्बई-9 स्थित कार्यालय, और (2) उद्योग भवन, तीसरी मंजिल बालचन्द्र जिराचन्द माग वालाड एस्टेट मुम्बई-1 स्थित मुख्य कार्यालय भी सम्मिलित हैं, नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती हैं।

यह अधिसूचना 1972 के जून के तीसरे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35018(109)/72-पी. एफ. 2]

S.O. 573.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs S. G. Industries, 13/14, Gola Industrial Estate Dumping Road, Mulund (West) Bombay-80, including its offices at: (i) 225, Sant Tukaram Road, Bombay-9, and (ii) Head Office at Udyog Bhavan, 3rd Floor, Wachand Hirachang Marg, Ballard Estate, Bombay-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1972.

[No.S.35018(109)/72-PF.II]

का. आ. 574.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी इरोड को-ऑपरेटिव मोटर ट्रांसपोर्ट सोसाइटी फार हरिजनस लिमिटेड, इरोड-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहें ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती हैं।

यह अधिसूचना 1972 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(187)/72-पी. एफ. 2(1)]

S.O. 574.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Erode Co-operative Motor Transport Society for Harijans Limited, Erode-2 have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1972.

[No. S. 35019(187)/72-PF. II(i)]

का. आ. 575.—कर्मचारी और भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मैसर्स दी इरोड को-ऑपरेटिव मोटर ट्रांसपोर्ट, सोसायटी फार हरिजनस लिमिटेड, इरोड-2 नामक स्थापन को 1 नवम्बर, 1972 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती हैं।

[सं एस. 35019(187)/72-पी. एफ. 2(2)]

S.O. 575.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st November, 1972 the establishment known as Messrs. the Erode Co-operative Motor Transport Society for Harijans, Limited, Erode-2 for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35019 (187)/72-PF. II (ii)]

का. आ. 576.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है मैसर्स फेडरेशन आफ इण्डियन प्लाईवुड एण्ड पैनल इण्डस्ट्री, डी-21, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहें ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती हैं।

यह अधिसूचना 1971 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस-35019(174)/72-पी. एफ. 2 (1)]

S.O. 576.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Federation of Indian Plywood and Panel Industry, D-21, Defence Colony, New Delhi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first of January, 1971.

[No. S. 35019(174)/72-PF. II(i)]

का. आ. 577.—कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् प्रथम जनवरी, 1971 से मैसर्स फेडरेशन आफ इण्डियन प्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्री, डी-21 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती हैं।

[सं. एस-35019(174)/72-पी. एफ. 2 (2)]

S.O. 577.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st January, 1971, the establishment known as Messrs. Federation of Indian Plywood and Panel Industry, D-21, Defence Colony, New Delhi for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(174)/72-PF. II(ii)]

का. आ. 578.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विजय यूटेन्सिल्स कलपेट्टा डाकघर साउथ विनाड, केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 की जनवरी के 31वें दिन को प्रवृत्त होगी ।

[सं. 8/113/69-पी. एफ. 2 (1)]

S.O. 578.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Vijaya Utensils, Kalbetta P.O. South Wynad, Kerala have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the thirty-first day of January, 1973.

[No. 8/113/69-PF. II(i)]

का. आ. 579.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विजय एजेन्सीज, कलपेट्टा, डाकघर, साउथ विनाड, केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 की जनवरी के 31वें दिन को प्रवृत्त होगी ।

[सं. 8/113/69-पी. एफ. 2 (2)]

S.O. 579.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Vijaya Agencies, Kalpetta P.O., South Wynad, Kerala have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the thirty-first day of January, 1973.

[No. 8/113/69-PF. II(ii)]

का. आ. 580.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रंकज स्पाइस ट्रेडिंग कम्पनी कोचीन-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के दिसम्बर के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35019(170)/72-पी. एफ. 2]

दलजीत सिंह, अवर सचिव ।

S.O. 580.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Pankaj Spices Trading Company Cochin-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the thirty-first day of December, 1972.

[No. S. 35019(170)/72-PF. II]

DALJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1973

का. आ. 581.—कर्मकारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा फरवरी, 1973 के 18वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध उड़ीसा राज्य के निम्नीलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

गंजाम के जिले में, थाना और तहसील छत्रपुर में गंजाम, दामोदरपुर, भारपांडर, कल्याणपुर और कंचापुर राजस्व गांवों से मिलकर बना क्षेत्र ।

[फा. सं. एस-38013(19)/72-रज. आई]

डी. एस. निमि, संयुक्त सचिव ।

New Delhi, the 15th February, 1973

(Office of the Chief Labour Commissioner)
(Central)

New Delhi, the 29th January, 1973

ORDER

S.O. 581.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 18th day of February, 1973 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Orissa, namely :—

"Area comprising the Revenue Village of Ganjam, Damodarpur, Jharpodar, Kalyanapur and Kainchapur in Police Station, and Tehsil Chhatrapur in District of Ganjam."

[F. No. S-38013/19/72-HJ]

D. S. NIM, Jt. Secy.

(मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1973

आदेश

का. आ. 582.—यतः मैसर्स टी. नारायण स्वामी, एस. आर. मत्थु-स्वामी और कौ. सुब्रामनीयम जिप्सम माइनिंग कॉन्स्ट्रक्टर्स, (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के सम्बन्ध में 31-12-1972 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिये अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावीधि को बढ़ाने के लिये बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. डब्ल्यू. बी-20(42)/65 तारीख 28 अगस्त 1965 के साथ पीठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17-1-1973 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावीधि की अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय की अंतिम तारीख से 5 महीने (अर्थात् 31-1-1973 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता	स्थापन
-------------------------------	--------

सं/श्री टी. नारायण स्वामी रेडीयर, कौ. सुब्रामनीयम, जिप्सम माइनिंग कॉन्स्ट्रक्टर्स, गुरुदामगलम जिप्सम माइन, आफ डाल्मिया सीमेंट (बी) लि., गुरुदामगलम, थाया पादालुर, जि. त्रिची और श्री एस. आर. मत्थु स्वामी, जिप्सम माइनिंग कॉन्स्ट्रक्टर्स गुरुदामगलम जिप्सम माइनिंग शीरु कलापुर, कालाकुडुडी जिला मिची।	
--	--

[सं. बी. ए. 16(63)/72-एल. एस. 1]

S.O. 582.—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs. T. Narayan Swamy, S. R. Muthuswamy and K. Subramaniam, Gypsum Mining Contractors (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 31-12-1972.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. WB. 20 (42)/65 dated the 28th August, 1965, passed order on 17-1-73 extending the period for payment of the said bonus by the said employer by 5 months (i.e. up to 31-3-73) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

THE SCHEDULE

Name and address of the employer(s)	Establishment(s)
-------------------------------------	------------------

S/Sh. T. Narayanan Swamy Reddiar, K. Subramaniam, Gypsum Mining Contractor at Garudamangalam Gypsum Mine of M/s. Dalmia Cement (B) Ltd., Garudamangalam P. O. : Via Padalur, Dt. Trichy and Sh. S. R. Muthusawamy, Gypsum Mining Contractor at Garudamangalam Gypsum Mine, Sriukalappur P.O. Via Kallakudi, Trichy Dt.	
--	--

[No. BA. 16(63)/72. LS. 1]

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1973

का. आ. 583.—यतः मैसर्स कृष्ण माइनिंग कम्पनी (नियोजक) ने नीचे अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के सम्बन्ध में 31-3-72 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिये अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावीधि को बढ़ाने के लिये बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. डब्ल्यू. बी-20(42)/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पीठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19-1-1973 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावीधि की अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय की अंतिम तारीख से 1 महीने 10 दिनों (अर्थात् 10-1-1973 तक) बढ़ाने का आदेश दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता	स्थापना
मैसर्स कृष्ण माइनिंग कम्पनी गांगीनीनी पुरुष पोस्ट बॉक्स-13 गदरुनिलार, जिला आन्ध्र प्रदेश	साह मीका, पीली नदटा और तिला बान्दू माइन्स सयदा पुरम, गिलांर

[बी. ए. 16(55)/72-एल. एस. 1]

S.O. 583.—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs. Krishna Mining Company (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 31-3-72.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. WB. 20 (42)/65 dated the 28th August, 1965, passed order on 19-1-73 extending the period for payment of the said bonus by the employer by 1 month 10 days (i.e. up to 10-1-73) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

THE SCHEDULE

Name and address of the employer(s)	Establishment(s)
M/s. Krishna Mining Company Goginapuram, Post Box No. 13, GUDUR Nellore Dt. (A.P.).	Shah Mica, Pallimitta & Tallabodu Mines at Syda- puram, Nellore.

[No. BA. 16(55)/72-LS. I]

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1973

आदेश

क्र. आ. 584.—यतः मॅसर्स प्यारे जम्बाद कोलरीज प्राइवेट लि. (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के संबंध में 31-12-1971 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण हैं, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिनियमा सं. हक्यू बी-20(42)/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के माथ पीठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3-2-1973 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय की अंतिम तारीख से 5½ महीने (अर्थात् 15-2-1973 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों

स्थापन

का नाम और पता

प्यारे जम्बाद कोलरीज (प्रा.) लि. प्यारे जम्बाद कोलरीज (प्रा.) लि.
प्यारे जम्बाद कोलरीज प्रा. ऑफिस
कीजोरा ग्राम जिला बर्दवान

[सं. बी. ए. 16(26)/72-एल. एस. 1]

आर. जे. टी. डीमेलो, मुख्य श्रम आचर्यक केन्द्रीय।

New Delhi, the 8th February, 1973

ORDER

S.O. 584.—Whereas an application has been made under Section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs Pure Jambad Collieries Pvt. Ltd. (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 31-12-1971.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. WB.20(42)/65 dated the 28th August, 1965, passed order on 3-2-1973 extending the period for payment of the said bonus by the said employer by 5-1/2 months (i.e. up to 15-2-1973) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

THE SCHEDULE

Name and address of the employer (s)	Establishment(s)
M/s. Pure Jambad Collieries Pvt. Ltd., Pure Jambad Col- liery, P.O. Kajoragram, Distt. Burdwan.	Pure Jambad Collieries Pvt. Ltd.

[No. BA-16(26)/72-LS.I]

R. J. T. D'MELLO, Chief Labour Commissioner (C)

